ाचीन भारत के राजनैतिक सिद्धान्त्र

एवं संस्थाएँ

लेखकः

प्रो० हरिबिलास मिश्र, एम. ए. (इति॰), एम. ए. (राजनीति), एल एल. बी. अध्यच्न, राजनीति विभाग

ह्रँगर कॉ तेज, बीकानेर।



दो स्टूडेंगट्स बुक कम्पनी

जयपुर

जोधपुर

१६६२

मूल्य १०)

विषय-सूची

श्रध्याय

≫ c.	419	वृष्ठ
٤,	. अध्ययन-त्तेत्र एवं साधन (Scope and Sources)	
₹.	. राज्य का स्वरूप (Conception of State)	१ 8
₹.	राज्य की उत्पत्ति के सिद्धान्त (Theories about the origin of State)	28
٧.	राज्यों के प्रकार (Types of States)	३२
પ્.	गणराज्य-१ (Republics I)	४०
ξ,	गणराज्य-२ (Republics II)	५३
	राज्य के उद्देश्य श्रौर कर्त्तव्य (Aims & Functions of the State)	६४
	सम्राट्का पद (Kingship)	७४
ε.	श्रभिषेकोत्सव (Coronation Ceremony)	<u> ج</u> و
१०.	लोक्सभाएँ (Public Assemblies)	६५
११.	प्रशासन (१) मन्त्रिमण्डल (Administration-I-Ministry)	११८
१२.	प्रशासन (२) राजकीय संगठन (Administration-II-Governmental)	१३३
₹₹.	प्रशासन (३) स्थानीय सरकार (Administration-III-Local Self	
	Government)	१४२
8.	न्यायपालिका (Judiciary)	१५४
≀પ્.	कर-सिद्धान्त (Principles ot Taxation)	१६५
ξ.	ग्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध (Inter State Relations)	१७५
9.	diculture taxing suc their (Farence)	१५७
ς.	Made and a second	२०४
.3	अस्तिन मारत न तनाजनार (००००००००	२०ज
0.	प्राचीन भारत के राजनैतिक सिद्धान्तों का मूल्यांकन (An Estimate of the	
	Ancient Indian Political Thought)	२१७

प्राचीन भारत के राजनैतिक सिद्धान्त एवं संस्थाएं

(प्रो० हरिबिलास मिश्र)

प्रथम अध्याय

ग्रध्ययन-क्षेत्र एवं साधन

(Scope and Sources)

प्रस्तावना—ग्रारम्भ में दीर्घ काल तक पाश्चात्य विद्वानों तथा कुछ भारतीय विद्वानों की भीं यह मान्यता रही है कि प्राचीन हिन्दुग्रों के यहाँ राजनीति गंभीर ग्रध्ययन का विषय ही नहीं रहा । वस्तुतः यह भ्रम था ग्रीर इसके दो ग्राधार दृष्टिगत होते हैं । पहला, यह कि पूर्व स्थित ईरान साम्राज्य (Persian Empire के ग्रन्तर्गत कोई सामाजिक या राजनीतिक सिद्धान्त मान्यता प्राप्त नहीं थे ग्रीर यही विश्वास उनका भारत के प्रति रहा । दूसरा ग्राधार यह है कि पाश्चात्य विद्वान इतिहास एवं राजनीति के ग्रध्ययन के लिए यहाँ नहीं ग्राते थे । उनका मुख्य उद्देश्य संस्कृत का ग्रध्ययन होता था । ग्रतः उनके दृष्टिकोण में ही ग्रन्तर था । इन विद्वानों में मैक्सपूलरका नाम सबसे ग्रधिक विख्यात है, परन्तु वे भाषा-विज्ञान (Philology) की ग्रीर ग्रधिक उन्मुख थे । भारतीय ज्ञान के क्षेत्र में इन विद्वानों को निम्न तीन श्रीणयों में विभाजित किया जा सकता है!—-

- (१) शास्त्रीय संस्कृत साहित्य के ग्रध्येता (Students of classical Sanskrit literature)
- (२) धर्म, दर्शन एवं ग्राध्यात्म के ग्रध्येता (Religion, Philosophy & Metaphysics)
- (३) भाषा विज्ञान के ग्रध्येता (Students of Philology)

इंन लोगों की यह धारणा रही कि राजनैतिक विषय में भारत वर्ष की कोई प्रमुख देन नहीं है। चाएनय के अर्थशास्त्र की खोज व उसका प्रकाशन इनकी अनिभंजता दूर करने वाली, प्राची के ज्ञान सूर्य से प्रकट होने वाली प्रथम किरण थी। चाएनय का अर्थशास्त्र प्रामाण्यिक ग्रन्थ होते हुए भी उसके संबंध में दीर्घकाल तक ऐसी शंक।एँ वनी रहीं कि इसका लेखक चाएनय ही है यह कैसे सिद्ध हो सकता है, किस समय लिखा गया है आदि। श्रीनरेन्द्र नाथ ला ने अपनी पुस्तक Studies in Ancient Hindu Polity के प्राक्तथन में इस विषय का बहुत सुन्दर विवेचन करते हुए यह सिद्ध किया है कि प्राचीन भारत में भी राजनीति शास्त्र गम्भीर अध्ययन व शोध का विषय था तथा लगभग ३०० वर्ष ई० पू० का लिखा हुआ यह ग्रन्थ है। तत्पश्चात तो इसी प्रकार के अन्य ग्रन्थ भी प्रकाश में आने लगे और यह निविवाद एवं स्वयं सिद्ध हो गया कि भारत वर्ष श्रन्थ क्षेत्रों की भाति राजनैतिक ज्ञान के क्षेत्र में भी उन्नित के शिखर पर था।

साधन (Sources)—विस्तृत श्रध्ययन क्षेत्र होते हुए भी साधन कठिनाई से उप-लब्ध होते हैं। महाभारत के शांति पर्व में राजधर्म श्रध्याय इस क्षेत्र में सर्वोत्कृष्ट शांस्त्रीय स्रोत (Cangonial Text) है तथा प्राचीन भारतीय राजनैतिक ज्ञान में रुचि रखने वाले विद्यार्थी के लिए गंभीर ग्रध्ययन का विषय है। श्री प्रणीकर के विचार से महाभारत के साथ जो दूसरे सहायक ग्रन्थ है उनमें मनुस्मृति को प्रथम स्थान दिया जा सकता है। तत्प-रचात् समस्त पुराण् भी इसी श्रेणो में रवंबे जा सकते हैं। यद्यपि पुराणों में ग्रर्थ शास्त्र के सिद्धान्तों को भलक है, तथापि उनका ज्ञान वास्तविकता पर ग्राधारित प्रतीत होता है। सम्राटों व राजपरिवारों का वर्णन करते हुए यह प्रकट किया गया है कि राजनीति के सिद्धान्तों का कहाँ तक तथा किस प्रकार पालन किया जाता था। साहित्यिक साधनों में काव्य, नाटक एवं उपन्यास भी तात्कालिक सामाजिक तथा राजनैतिक सिद्धान्तों तथा उनके पालन का सफल चित्र उपस्थित करते हैं। इन ग्रन्थों में विशेष रूप से राजा; उनके न्यायालय तथा कार्य प्रणाली के ग्रुण तथा दोषों का सुन्दर तथा यथार्थ वर्णन है। कालिदास के कुछ ग्रन्थ प्रत्यक्ष रूप से सम्राटों के जीवन की ही भाँकी उपस्थित करते हैं जैसे शाकुन्तल, रघुवंश मालिवकाग्नि मित्र ग्रादि। इनका ग्रध्ययन उस समय की सामान्य राजनैतिक विचारधारा को समभने के लिए ग्रद्धितीय साधन है। कुछ ग्रन्थ ऐसे ग्रन्थ भी हैं जो विशेष सम्राट व साम्राज्यों के इतिहास के रूप में प्राप्य हैं तथा महत्व पूर्ण है। उदाहरणार्थ:—

- (१) कल्हरण कृत राजतरंगिरणी जो उसके विशद ज्ञान तथा वास्तविक प्रशासनीय अनुभूति के फलस्वरूप रची गई।
- (२) मंजु श्री मूल कल्प यह एक प्रकार से वौद्ध कालीन दृष्टि कोएा से लिखित भारतीय इतिहास है।
- (३) वारा द्वारा रिचत हर्ष चिरतसार—यह तत्कालीन राजनैतिक परिस्थितियों का यथार्थ चित्ररा है।

अन्य प्राचीन अन्थ (Ancient Treatizes)—सर्व प्रथम स्थान कौटित्य के अर्थ शास्त्र को देने के पश्चात् भी पर्याप्त ऐसे अन्य हैं, जो महत्वपूर्ण कहे जा सकते हैं। शुक्रनीतिसार, कामन्दकीय नीतिसार, पंचतन्त्र, हितोपदेश, राजनीति रत्नाकर, वीर मित्रोदय, कादम्बरी एवं दास बोध आदि ऐसे ही अन्य हैं। डा० काशीप्रसाद जायसवाल का विचार है कि हमारे अध्ययन के साधन मुख्य रूप से ४ भागों में विभाजित किए जा सकते हैं:—

- (१) वैदिक अर्थात् वेदों में निहित सामग्री।
- (२) शास्त्रीय एवं प्राकृत (Classical & Prakrit)
- (३) ऐतिहासिक लेख तथा मुद्रा सम्बन्धी प्रमाण (Inscriptional and numismatic records)
- (४) हिन्दू राजनीति पर तकनिक ग्रन्थ (पारिभाषिक कृतियां—Technical Treati zes on Hindu Politics)

इस प्रकार ग्राघुनिक काल में प्राचीन भारतीय राजनैतिक विचार का ग्रध्ययन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध साधन व ग्रन्भों की प्राप्यता ने सुगम तो बना दिया है, तथापि गंभीर शोध की ग्रतीव ग्रावश्यकता ग्रनुभव की जाती है । तत्कालीन ग्रध्ययन के कतिपय

^{1.} Dr. Jayaswal - Hindu Polity

इतने अधिक प्रचारित विषय हैं जिनका पठन पाठन सरलता से किया जा चुका है श्रिम्बोद्धः हिन्दू गराराज्य, हिन्दू सम्राट, जन-पद-पौर, हिन्दू मन्त्रि मण्डल, न्याय पालिका, कर-सिद्धान्तः (Taxation), प्राचीन साम्राज्य प्रणाली, सार्वभौम संस्थाएँ तथा स्थानीय स्वायत्त शासन की इकाइयाँ आदि ऐसे विषयों में मुख्य हैं।

ग्राधुनिक विद्वान वर्ग को, जो इस विषय के प्रमुख लेखक हैं, तीन श्रीिंग्यों में रक्खा जा सकता है। प्रथम वे जो केवल प्राचीन गुद्ध सिद्धान्त में रुचि रखते हैं जैसे श्री भण्डारकर, श्री घोषाल ग्रादि। द्वितीय, वे जो ग्रपनी ग्रपूर्व विद्वत्ता के साथ गहरी कल्पना का समन्वय करते हैं जैसे श्री विनय कुमार सरकार, श्री डा० जायसवाल, श्री डा० ग्रल्टेकर ग्रादि। तृतीय, वे जो राजकीय तथा प्रशासनीय संस्थाग्रों का प्राप्य प्रमाग्गों के ग्राधार पर ग्रध्ययन करते हैं जैसे श्री दीक्षीतार, प्रोफेसर वनर्जी तथा डा० वेनी प्रसाद ग्रादि। भारत की स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् इस क्षेत्र में जिस उत्साह से शोध कार्य होना चाहिए था वह गित ग्रभी ग्राना शेष है— जिसके द्वारा हमारा गौरवमय ग्रतीत ग्राधुनिक प्रकाश में विश्व को चमत्कृत करने की क्षमता प्रदर्शित कर सके।

नामात्रलि (संज्ञा) (Terminology --साधन व क्षेत्र के मार्ग में एक साधारएा सी कठिनाई हमारे इस ज्ञान की संज्ञा के विषय में अनुभव की जाती रही है। प्राचीन समय में ग्रनेक नाम प्रचलित रहे हैं जिनमें राजधर्म, राज्य शास्त्र, दण्डनीति, नीतिसार एवं ग्रर्थ-शास्त्र, मुख्य हैं। राजधर्म शब्द का प्रयोग ग्रधिकांश मनुस्मृति में तथा उससे प्रभावित ग्रन्य ग्रन्थों में किया गया है। इस का ग्रर्थ संभवतः "राजा के कत्त व्य" से था। राज्य शास्त्र का प्रयोग महाभारत में प्रचुरता से मिलता है। इसका अर्थ राज्य सम्बन्धी ज्ञान का शास्त्र ही समभा जा सकता है। इसी प्रकार दण्डनीति शब्द का प्रयोग भी मनुस्मृति में किया गया है। मनु की यह धारएा। थी कि राज्य का ग्राधार 'दण्ड' (Force) है। यदि इस दण्ड का उचित प्रयोग नहीं किया जाय तो मत्स्य-न्याय (Law of the fish or law of the jungle) की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। दण्ड ही सम्पूर्ण व्यवस्था की ग्राधार शिला है। ''जब ग्रन्य सब सुप्तावस्था में होते हैं तो दण्ड जागृत रहता है--नियम स्वयं भी दण्ड का ही स्वरूप है।" दण्ड का प्रयोग विशेषाधिकार युक्त ही होना चाहिए। अर्थशास्त्र में भी यही माना है कि यदि दण्ड का प्रयोग अधिक कठोरता से किया जाता है तो प्रजा को पीड़ा पहुँ-चती है, ग्रीर यदि ग्रधिक सरलता से प्रयुक्त हो तो सम्राट का प्रभाव नहीं रहता। यदि उचित ढंग से प्रयुक्त हो तो प्रजा प्रसन्न रहती है ग्रीर राज्य उन्नित की ग्रीर ग्रग्रसर होता है। यही भाव कामन्दक ने व्यक्त किए हैं कि तीथ्गा दण्ड से प्रजा उद्दे जित विरक्त)

⁽१) दण्डः शक्ति प्रजाः सर्वा दण्ड एवामिरक्षति ।

दण्डः सुप्तेषु जार्गात दण्डं धर्मं विदुर्बुधा : ।। [मनुस्मृति श्रव्याय ७ श्लोक १८]

मनु सप्तम श्रव्याय -१८ श्लोक से आगे समस्त वर्णन वड़ा रोचक तथा महत्व पूर्ण है
। पृष्ठ २८४)

⁽२) तीक्ष्णदण्डोहि भूताना मुद्धेजनीय: । मृदुनादण्डः परिभूयते । यथाई दण्डः पूज्यः । (ग्रर्थ गास्त्र से)

ही जाती है, मृदुदण्ड से राजा ही का तिरस्कार होने लगता है, इस कारण से राजा युक्त-वण्ड को विधान करे⁹। नीतिसार शब्द का प्रयोग भी अधिक लोक प्रिय रहा है। भन् हरि द्वारा लिखित ग्रन्थ का नाम 'नीति शतक'' इसी प्रकार का एक प्रयोग है। डा॰ अल्टेकर ने अपनी पुस्तक में यह स्पष्ट किया है कि ५ वीं सदी के बाद यह शब्द अत्यधिक प्रचारित रहा इसीलिए शुक्र नीतिसार, कामन्दकीय नीतिसार आदि सामने आएर। इति-हास के प्रकाण्ड पण्डित डाक्टर ग्रल्टेकर द्वारा तिथिवार वर्णन, किस समय क्या ग्रन्थ लिखे गए ग्रत्यन्त रिचिकर एवं गंभीर ज्ञान से युक्त है। उन्होंने नीति का ग्रर्थ उचित पथ-प्रदर्शन या संचालन से लिया है 3। ग्रर्थशास्त्र शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से चाराक्य द्वारा रचित ग्रन्थ 'ग्रर्थशास्त्र'के प्रकाश में ग्राने से ज्ञात हुगा । साधारए।तया 'ग्रर्थ'का भावसम्पत्तिया धन से होता है ग्रीर इसीलिए वक्त मान समय में Economics की ग्रर्थशास्त्र की संज्ञा दी गई है। परंतु कौटिल्य का मत है कि अर्थ का मतलब क्षेत्र या प्रदेश (Territory) से भी है ग्रतः ग्रयंशास्त्र का ग्रथं है वह शास्त्र, जो प्रादेशिक रक्षा, प्रशासन व्यवस्था ग्रादि विषयों का विवेचन करे । यद्यपि यह प्रयोग प्राकृतिक नहीं प्रतीत होता तथापि चाराक्य द्वारा इसका प्रयोग स्वयं सिद्ध तथा श्रकाट्य है। इसमें वर्णित श्रधिकांश विषय राजनीति शास्त्र से संबं-शित है इसलिए स्वभावतः यह विचार होता है कि पारचात्य देशों में लम्बे समय तक राज्य शास्त्र को (Political Economy) राजनैतिक ग्रर्थ व्यवस्था कहा जाता रहा, यहीं का प्रभाव हो सकता है। दूसरी संभावना यह मानी जा सकती है कि राजनीति शास्त्र की सम्पूर्ण सफलता, सफल अर्थ व्यवस्था पर ग्राधारित रहती है, इसीलिए प्राचीनकाल में इसकी प्राधान्यता के कारण राजनीति शास्त्र की ही ग्रर्थशास्त्र की संज्ञा दे दी गई हो। ग्राज भी यह कहा जाता है कि ब्रार्थिक स्वतन्त्रता रहित राजनैतिक स्वतंत्रता अर्थ हीन है। अतः अर्थशास्त्र का प्रयोग किया गया । वर्त्त मान में यह प्रयोग शुद्ध रूप से (Economics) ग्रर्थ सम्बन्धी ज्ञान के लिए होता है।

इस प्रकार हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि इस ज्ञान की संज्ञा क्रमशः परिवर्तित होती ग़ई—राजधर्म, दण्डनीति और अर्थशास्त्र सर्वाधिक प्रचलित शब्द रहे और इनका महत्व इनके प्रतिपादित ग्रन्थों से घटता व बढ़ता रहा है। पूर्व कथित विचार, कि प्राचीन भारत राजनैतिक ज्ञान शून्य था, पूर्ण रूपेण असत्य एवं आधार हीन सिद्ध करने में हमारी प्राचीन ग्रन्थावली सफलता पूर्वक समर्थ है।

⁽१) उद्वीजयित तीक्षेगान मृदुना परि भूयते । दण्डेन नृपित स्तस्माद्युक्त दण्डः प्रशस्यते । ३७ द्वितोय सर्ग ।। पृष्ठ २२ कामन्दकीय नीति॰

^(?) Dr. Altekar-State & Government in Ancient India

⁽३) उपरोक्त-Proper guidance or direction

द्रांड-नीति पर विशद् व्याख्याः—कौटित्य के मतानुसार दण्डनीति प्रवित्र विज्ञान (Science of Government) चार प्रमुख विज्ञानों में से एक था तीन विज्ञान इस प्रकार है :—

- (१) ग्रान्वीक्षकी (तर्क शास्त्र)
- (२) त्रयों (वेदत्रय की विद्या)
- (३) वार्ता (कृषि, पशुपालन एवं वारिएज्य)। शुक्रनीति के अनुसार इन चारों विद्याओं में दण्डनीति प्रधान हैं क्योंकि शेष तीन विद्याएँ दण्डनीति पर ही ग्राधारित है। इसलिए दण्डनीति का ग्रर्थ हमें ग्रीर ग्रधिक स्पष्ट रूप से समभना ग्रावश्यक हो जाता है। साधारए। ग्रर्थ में दण्डनीति का ग्रर्थ है प्रशासन की विद्या व कला । इसी शास्त्र की बाद में ग्रन्य संज्ञाएँ, जैसे अर्थ शास्त्र, राजधर्म, राजनीति ग्रीर नीति शास्त्र भी दी गई। परन्तु वाद में इन नामों में भेद उत्पन्न हो गया। श्री घोषाल ने ग्रर्थ शास्त्र व दण्डनीति का भेद वहत ही स्पष्ट लिखा हैं । उनके मतानुसार दण्डनीति का ग्रर्थ है प्रशासन एवं दण्ड व्यवस्था की कला परन्तु मर्थ शास्त्र का मर्थ है प्रमुख रूप से व्यवस्था। दण्ड का विधान इस रूप में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। परन्तु कौटिल्य ने ग्रर्थशास्त्र की व्यापक व्याख्या द्वारा यह स्पष्ट कर दिया है कि मानवता अर्थ पर ग्राधारित है ग्रीर अर्थ का मूल आधार भूमि है जहाँ मानव सम्मिलित रूप में निवास करता है। इसी भूमि को प्राप्त करने व सुरक्षित रखने के लिए अर्थशास्त्र का ज्ञान अनिवार्य है। परन्तु अन्य तीन विद्याएँ, आन्वीक्षकी, वेदत्रयी तथा वार्ता की उन्नति ग्रीर विकास उस विद्या पर ग्राधारित है जिसे दण्डनीति कहते हैं। ग्रर्थात् पूर्ण सामाजिक ग्रायिक व नैतिक विकास के लिए दण्ड नीति ग्रनिवार्य विद्या है। कौटिल्य तो यह भी कहता है कि सम्पूर्ण विश्व की समृद्धि ग्रीर उन्नति इस दण्डनीति पर ही ग्राधारित है³। कामन्दक के मतानुसार दण्डनीति ग्रीर वार्ता यह जो दो विद्या हैं यह लोक के ,प्रधान मर्थ की साधक बृहस्पित के शिष्यों द्वारा प्रचारित की गई है । ग्रीर दण्डनीति उशनस ग्रर्थात् शुक्राचार्य की विद्या है, इसमें सब विद्याग्रों का ग्रारम्भ कहा गया है । ग्रान्वीक्षकी से म्रात्मा का विज्ञान होता है म्रीर त्रयी विद्या में धर्म म्रधर्म की व्यवस्था है, वार्ता में म्रर्थ ग्रनर्थ का ज्ञान व दण्डनीति में नीति ग्रनीति स्थित है।

"दमो दण्ड इति ख्यातस्तात्स्थ्या द्ण्डो महीपतिः। तस्य नीतिर्दण्डनीतिर्नयनान्नीति रुच्यते ॥ १५ ॥ (कामन्दक)

भ्रथीत् दम (संयम) या दमन करने का नाम दण्ड है वह दण्ड शासक (राजा) में स्थित है, उसकी नीति दण्ड नीति है, नयन भ्रथीत् सम्यक रीति से सुमार्ग में चलाने से इसको नीति कहते हैं। नीति शब्द स्वयं भी 'नी' धातु से उत्पन्न है जिसका भ्रथ है नेतृत्व

⁽१) कामन्दक-पृष्ठ १४...

^(?) Goshal-Hnidu Political Theories-Page 78.

⁽३) प्रर्थ शास्त्र - चतुर्थ मध्याय-पृष्ठ, ८. (Eng. Edi.)

⁽४) कामन्दक-पृष्ठ १६, १७.

अर्थात् जो जनता का उचित मार्ग पर नेतृत्व या पथ प्रदर्शन करे। इसी प्रकार मनु के मता-नुसार सम्पूर्ण विश्व दण्ड के ग्राधीन है। बिना भय के संसार के व्यवहार पवित्र नहीं रह सकते। दण्ड के भय द्वारा ही विश्व उपभोग के योग्य है। इसलिए राज्य को चाहिए कि दण्डनीति द्वारा अपनी रक्षा करे तथा दूसरी विद्याओं की रक्षा करे।

नीति ग्रीर दण्डनीति का क्या सम्बन्ध है, इस विषय पर कुछ विचार किया जा सकता है। गुक्राचार्य के मतानुसार नीतिशास्त्र का उद्देश्य सामाजिक कल्याए। है ग्रीर विश्व कल्याए। या मानव मात्र का हित इसका चरम लक्ष्य है। धर्म ग्रर्थ ग्रीर काम का मुख्य स्रोत व ग्राधार नीति-शास्त्र ही माना जाता है। इसिलए राजा के लिए नीति शास्त्र का ज्ञान ग्रानिवार्य माना गया था। इसी शास्त्र के ज्ञान द्वारा, जो सुरक्षा, न्याय व शाँति की स्थापना, सामाजिक कल्याए। की व्यवस्था ग्रादि स्थापित करता था, सामाजिक विकास संभव होता था। नीति विहीन राज्य फूटे हुए जहाज की भाँति माना जाता था। नीति के ग्रनुसार चलने वाले राज्य की कीर्ति ग्रंथों में गाई जाती है ग्रीर स्वेच्छाच।री राजा की निन्दा होती है। इसिलए राजा को नीति का ग्रनुसरए। करते हुए स्वयं की, राज्य की तथा मानव मात्र की उन्नति ग्रीर समृद्धि बढ़ानी चाहिए।

बृहस्पति के श्रनुसार दण्डनीति वह विद्या है जिसका पालन न करने वाला राजा उसी प्रकार संकट ग्रस्त हो जाता है जैसे अबोध शलभ दीप शिखा पर भस्म हो जाता है। इसलिए भारतवर्ष में दण्डनीति का विशेष स्थान है स्रोर हिन्दुसों के चारों वर्णी द्वारा इसका ग्रध्ययन किया जाना चाहिए। इस दण्डनीति का ग्रध्ययन युगानुसार न्यूनाधिक किया जायगा। कृत युग में बुद्धिमान व्यक्ति अधिक संख्या में इसका अध्ययन करेंगे, त्रेता युग में कर्मशील पुरुष, द्वापरमें तांत्रित तथा तिष्य (किल) युग में सर्व साधारए। इसका ग्रध्ययन करेंगे। इसके पश्चात मानव ग्रधार्मिक हो जायगा ग्रीर दण्डनीति के सिद्धान्त जुत हो जायेंगे। मनुस्मृति के भनुसार "दण्ड ही प्रजा का शासन करता है तथा सब की रक्षा करता है। दण्ड ही उस समय जागृत रह कर सब की रक्षा करता है जब सब सी जाते हैं इसलिए विद्वान लोग दण्ड को ही धर्म कहते हैं।" इस प्रकार दण्ड राज्य के लिए ग्रनिवार्य तत्व है। दण्ड का चित्र भी इसी लिए ऐसा उपस्थित किया गया है जिसमें श्याम वर्गा, रक्त नेत्र, ग्रथमियों के नाश का व्रत तथा निरुखल लोगों की रक्षा का उत्तर दायित्व लेते हुए देवता से तुलना की जा रही है। जहां दण्ड किया शील रहता है वहां जनता को कोई कष्ट नहीं होता। ग्रीर सम्राट भी ग्रपने पद का पूर्ण उपयोग करता है। दण्ड का भय बड़ा विकट माना गया है। इसके भय के कारण ही देव, असुर, गांधर्व, राक्षस आदि उचित ढंग से अपने कार्य संपादित करते हैं। यहां तक भी माना है कि दण्ड के भय के कारण हो अग्नि प्रज्ज्वलित होती है, सूर्य प्रकाशित होता है तथा ग्रन्य समस्त ग्रह ग्रपना ग्रपना कार्य करते है। यदि दण्ड नहीं है तो समाज और राज की भी संभायना नहीं हो सकती !! इसलिए प्रत्येक कार्य के लिए दण्ड का नेतृत्व ग्रनिवार्य है। दण्ड ही वास्तविक सम्राट,

^(?) No Danda, no society, no danda, no state.

वास्तविक नेता तथा वास्तविक रक्षक है। इसलिए राज्य के कर्तब्य, राज्य क ात तथा राज्य का सामान्य हित ही दण्डनीति कहे जाते थे।

दण्ड की व्याख्या करते हुए कॉटिल्थ ने तीन प्रकार के दण्ड माने हैं:-

- (१) तीच्या द्यड (Cruel) इससे प्रजा उद्घे जित (विरक्त) हो जाती है।
- (२) मृदु द्राड (Mild) इससे राजा का ही तिरस्कार होने लगता है।
- (३) यथा त्रिधि द्रण्ड (Just) इससे राजा त्रिवर्ग (धर्म, ग्रर्थ, काम) वृद्धि को प्राप्त होता है। तथा जो अयुक्त शासन करता है देश तो क्या वन के लोगों को भी कुपित करता है ।

पुरागों के अनुसार दण्डनीति की उत्पत्ति ब्रह्मा द्वारा किया जाना स्वीकार किया जाता है। महाभारत के शांति पूर्व के अनुसार ब्रह्मदेव ने वर्ग (अर्थात् धर्म, अर्थ, काम) की रचना की जिसमें १ लाख अध्याय के करीब थे। परन्तु उसमें दण्डनीति का कार्य बहुत भारी प्रतीत हुआ इसलिए विशालाक्ष द्वारा केवल दस हजार अध्याय के रूप में संक्षिप्त बनाया गया, फिर इन्द्र ने इसे केवल पांच हजार अध्याय में हो संक्षिप्त बना दिया। फिर बृहस्पित ने ३ हजार तथा उशनाज ने क्रमशः केवल १००० अध्याय में संक्षिप्त बना दिया तत्पश्चात ज्यों ज्यों मनुष्यों की अवस्था छोटी होती गई इस बात की आवश्यकता होने लगी कि दण्ड नीति पर ऐसी पुस्तक हो जो सरलता से इस छोटे से जीवन में पढ़ा व समभी जा सके। और तब से यह दण्डनीति आसान बन गई। इस प्रकार यह दण्डनीति की उत्पत्ति का दैविक सिद्धान्त माना गया है।

मानव के द्वारा दण्डनीति की उत्पत्ति के संबंव में काफी सामग्री प्राप्त है। महाभारत में दण्डनीति का निर्माण ब्राठ ऋषियों द्वारा किया जाना बताय। गया है। फिर उन्होंने यह पुस्तक स्वीकृति हेतु भगवान नारायण के समन्न उपस्थित की जिसे देख वे बहुत प्रसन्न हुए और कहा कि यह मौलिक कृति बहुत वर्षों तक उपयोग में ब्रायगी। स्वायम्भुव मनु का यही पुस्तक पथ प्रदर्शन करेगी ग्रीर जिसके द्वारा वह सम्पूर्ण विश्व में धर्म के सिद्धान्तों का प्रचार करेगा। बृहस्पति श्रीर शुक्र के लिए भी यह बहुत मूल्यवान सामग्री सिद्ध होगी।

इस प्रकार दण्डनीति शास्त्र प्राचीन भारत का अनुपम विज्ञान था। उत्पत्ति चाहे दैवी हो या मानुषी परन्तु यह एक स्वीकृत उपयोगी ज्ञान था। इसका उद्देश्य विश्व को प्रसन्न व समृद्ध बनाना था। इन्हीं सिद्धान्तों के द्वारा समाज में शांति स्थापित की जाती थी। इसी के भय से समस्त प्राणी वर्ग धर्म को जीवन व्यतीत करते थे और सम्पूर्ण सामाजिक व्यवस्था संतुलित रहती थी। दण्डनीति को त्रिवर्ग विद्या भी कहा गया है। अर्थात् धर्म अर्थ काम को प्राप्त कराने वाला ज्ञान । हिन्दू समाज शास्त्र के अनुसार यही त्रिवर्ग विद्या (मोह को छोड़कर) पुरुषार्थ कहलातो है। राजधर्म इन्हीं पुरुषार्थों की प्राप्ति के लिए

⁽१) कामन्दक-पृष्ठ २२ " उद्घे जयित तीक्ष्णेन, म्टदुना परिभूयते । "दण्डेन न्टपतिस्तस्मांस्क्रक दण्डः प्रशस्यते" ॥३७॥ द्वि. सर्ग ॥

यत्न करता है। दण्डनीति चारों वर्णों के व्यक्तियों के लिए ग्रहव की लगाम ग्रथवा हाथों के ग्रंकुश की भांति है जो उन्हें धर्म पर ग्रारुढ़ रखती है। इसी के द्वारा हिन्दुग्रों की सामाजिक व्यवस्था, चारों ग्राश्रम ग्रादि की रक्षा को जाती थी। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि प्राचीन भारत में दण्डनीति को प्रमुख स्थान दिया गया था। यह कहा जाता है कि ''जब राज धर्म निर्जीव ही जाता है तो तीनों वेद जुप्त हो जाते हैं ग्रीर समस्त धर्म, जो सभ्यता के ग्राधार हैं, चाहे कितने ही विकसित हों, नष्ट हो जाते हैं। जब राज्य के ग्राधार भूत प्राचीन सिद्धान्तों को त्याग दिया जाता है तो सामाजिक जीवन अव्यवस्थित हो जाता है। समस्त त्याग राजधर्म में ही ग्रनुभव किए जा सकते हैं, सारी दीक्षाएँ राजनीति में ही संभव हैं, सारी विद्याएँ राजधर्म के ग्रन्तर्गत ही प्राप्त की जा सकती है ग्रीर सारे लोक भी राज धर्म के ग्रन्तर्गत ही प्रविष्ठ होते हैं १। ग्रतः दण्डनीति ग्रथवा राज धर्म प्राचीन भारत की ग्रत्यन्त उन्नत तथा प्रमुख चार विद्याग्रों में से एक थी तथा इसका स्थान बहुत ऊंचा माना गया था। इसलिए प्रारंभ में दिया गया प्रसंग कि पाश्चात्य विद्यान यह समस्ते रहे कि भारत केवल दार्शनिक विचारों में ग्रग्रणी था, राजनैतिक विचारों से ग्रन-भिक्ष, पूर्णतः निराधार एवं ग्रसत्य सिद्ध हो जाता है।

(१) मज्जेत्त्रयी दण्डनीतौ हतायां सर्वे धर्माः प्रक्षपेयुविवृद्धाः । सर्वे धर्माश्राश्रमाणां हताः स्युः क्षात्रे त्यक्ते राजधर्मे पुराणे ॥ सर्वे त्यागा राजधर्मेषु हण्टा सर्वा दीक्षा राजधर्मेषु युक्ता । सर्वा विद्या राजधर्मेषु चोक्ताः सर्वे लोका राजधर्मे प्रविष्टा ।

म० भा० शा० ६३, २८, २६

When Polities becomes life less, the triple Veda sinks, all the dharmas [i.e. the bases of Civilization] (howsoever) developed, completely decay. When traditional State-Ethics are departed from, all the bases of the divisions of individual life are Shattered.

"In Politics are realized all the forms of renunciation, in Politics are united all the sacraments in Politics are combined all knowledge: in Politics are centred all the worlds."

Mahabharat, Santi. 63, 28, 29. as quoted by Dr. Jayaswal.

अध्ययन चेत्र (Scope of study):—भारत के प्रचीन विचारक राजनीति विज्ञान की बहुत महत्व देते थे। उनका कहना था कि "अन्य सब धर्म राजधर्म के अन्तर्गत होते हैं।" ग्राचार्य शुक्र दण्डनीति या राजनीति शास्त्र को ही एकमात्र विद्या मानते थे। उनको सम्मति में अन्य समस्त विद्याभ्रों का श्रस्तित्व भ्रीर सत्ता राजनैतिक विज्ञान (दण्ड गीति) पर ही ग्राधारित था। ग्राचार्य चाएाक्य के अनुसार भी ग्रन्य समस्त विद्याग्रों के विकास के लिए मानव समाज में जो योगक्षेम चाहिए, वह दण्ड सर्थात् व्यवस्था, शासक-शसित भाव, द्वारा ही प्रस्थापित हो सकता है। ग्रत: दण्डनीति का क्षेत्र स्वतः ही व्यापक ग्रीर विस्तृत हो जाता था। वर्तामान यूग की भांति प्राचीन काल में भी राजनीति शास्त्र का क्षेत्र व्यापक था। सर्वप्रथम यह कहा जा सकता है कि मानव जीवन के प्रन्य सभी महत्वपूर्ण पक्षों का व्यवस्थित ग्रौर विकसित होना राजनीति शास्त्र पर निर्भर करता है। इसलिए सामाजिक, म्रायिक, धार्मिक तथा व्यक्तिगत जीवन के क्षेत्र प्रभावित रहते थे मौर राजनीतिक पक्ष पूर्ण रूप से ग्रध्ययन का विषय था। प्राचीन प्रचलित भावनामों के भ्रनुसार यह मान्यता सर्वया ग्रसंगत है कि तत्कालीन समय में रुढ़ियां प्रधान होती थी और समाज क्रांतिकारी नहीं था। यदि सुक्ष्म हिष्ट से देखें तो यह बहुत स्पष्ट सिद्ध होता है कि हिन्दू , समाज भीर जाति ने राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में, राज्य पढ़ितयों एवं प्रशासकीय तंत्रों से संबंधित स्रनेक प्रयोग किए थे स्रीर उनका क्रमिक विकास इस वात का प्रमाण है कि ये प्रयोग केवल विशेष काल और परिस्थितियों में ही नहीं किए गए, किन्तु इस दिशा में हिन्दू जाति की, निरन्तर समुन्नत एवं अग्रसर होते रहने की, प्रवृति के कारण, सदैव जागरूक श्रीर सचेष्ट रहने का प्रतिफल था। इस रूप में प्राचीन काल में लोक सभाम्रों का क्रमिक विकास हुमा। निर्वाचन प्रणालियों के प्रयोग हुए। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के संगठन हुए। राज्यों का स्वरूप सदैव विकासशील रहा जिसमें राजतंत्र, प्रजातंत्र एवं साम्राज्यों की स्थापनाएं हुई । गराराज्यों एवं संघ राज्यों का प्रयोग हुआ । जनता जनार्दन की मृदु-भावनाम्रों के म्र तर्गत राज्य व्यवस्था चलाने के हेतु जनपद म्रीर पौर संस्थाम्रों का जन्म हुमा। लोकप्रिय तंत्र की स्थापना के लिए मंत्रिमण्डल. मंत्रिपरिषद् श्रीर अन्य अनेक प्रकार की उत्तरदायी संस्थायों का श्रीगरोश हुया। श्रात्मिन र्शय के सिद्धान्त को पूर्ण मान्यता देने के लिए 'कर-सिद्धान्त' निर्धारित किए गए। अंतर्राष्ट्रीय संवंधों का ऐसा स्वरूप उस समय उत्पन्न हुम्रा जो म्राज बीसवीं सदी में भी मध्ययन का रोचक विषय है। विदेश नीति एवं कूटनीति के सिद्धान्त उत्तम दृष्टान्तों सहित प्रतिपादित किए गए । तत्कालीन तंत्र के प्रत्येक भंग, जैसे नागरिक, शासक, दूत, व्यासारी, कर्मचारी, जनसेवक तथा मंत्री, सचिव, पुरोहित म्रादि सब लोगों की योग्यताएं, चरित्र, कर्तव्य तथा नियुक्तियों के लिए लगभग सर्वकालीन सिद्धान्त स्वीकृत किए गए थे। व्यापार के क्या उपयुक्त सिद्धान्त हैं, गुप्त सूचना प्राप्त करने के साधन क्या हो सकते हैं ब्रादि समस्त प्रकार का ब्रध्ययन तत्कालीन राजशास्त्र का विषय था। यही नहीं, मानव के व्यक्तिगत जीवन को छोटो से छोटी बात लेकर राजा और सम्राट के निजी जीवन की दिनचर्या तक, स्थानीय घटना से लेकर अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र की महत्वपूर्ण घटना तक तथा भूतकाल से लेकर भविष्यकाल की संभावनाध्रों तक राजनीति

शास्त्र का क्षेत्र फैला हुग्रा था। जिस प्रकार ग्राजकल कुछ विद्वानों की यह धारणा बन गई है कि वर्तमान समय में प्रत्येक राज्य, चाहे किसो भी पढ़ित का ग्रनुसरण करता हो, सर्व-ग्राही (Totalitarian State) राज्य होता है ग्रीर नागरिक के समस्त जीवन की प्रत्येक किया ग्रीर कार्य पर नियंत्रण रखता है, प्राचीन काल में भी राजनीति शास्त्र वास्त्रव में व्यापक शास्त्र था। इसका ग्रध्ययन क्षेत्र मानव जीवन पर पूर्ण रूप से व्याप्त था। इसलिए यह निष्कर्ष निकालना ग्रत्यन्त प्राकृतिक है कि प्राचीन काल में दण्डनीति ग्रथवा राजनीति शास्त्र का क्षेत्र बहुत व्यापक था ग्रीर राज्य की कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका युग युग में ग्रंपनी स्थिति के ग्रनुसार मानव के राजनीतिक, सामाजिक, ग्राथिक एवं धार्मिक ग्रादि लगभग सभी क्षेत्रों में पूर्ण क्रियाशील रही। यह ग्रवस्थ स्वीकार करना चाहिए कि कुछ ग्रपवादों के ग्रतिरिक्त प्राचीन काल में सम्पूर्ण व्यवस्था का उद्देश्य "सर्वभूतिहतेरता" होता था ग्रीर लोकराज्य की भांति साधारण जनता के कल्याण के लिए शासन यंत्र संचालित होता था। इसलिए ग्रध्ययन क्षेत्र की सीमाएं बहुत विस्तृत एवं व्यापक थीं, यह सत्य है।

राजनीति शास्त्र का क्रसिक विकास — डा. ग्रल्टेकर के मतानुसार राजनीति शास्त्र का व्यवस्थित साहित्यं लगभग ५०० ई. पू. से प्राप्त होता है। इससे पूर्व वैदिक साहित्य में यदा कदा कहीं स्पष्ट ग्रीर कहीं ग्रस्पष्ट प्रसंग ग्रवश्य मिलते हैं किन्तु वह सामग्री बहुत ही अलप है। किन्तु अथर्ववेद में 'राजा' से संबंधित प्रसंग कुछ अधिक हैं। वैदिक काल के बहुत बाद लगभग = वी शताब्दी से विशेषज्ञता (Specialization) का युग यारंभ होता है और उसी समय राज्यशास्त्र (Politics) का समारंभ मान सकते हैं। फिर भी वास्तविक रूप में इस ज्ञान का प्रकाश "महाभारत" ग्रीर "ग्रर्थशास्त्र" के द्वारा ही प्रकट होना स्वीकार किया जाता है। "महाभारत" का ग्रंथ यों तो ग्रह -ऐतिहासिक एवं ग्रह -पौरािएक माना जाता है ग्रौर उसी के वर्णन के ग्रनुसार ''राजशास्त्र'' की रचना आरंभ में ब्रह्मा के द्वारा उस समय की गई थी जब धराजकता को दूर करके सामाजिक व्यवस्था स्थापित की थी। उसके बाद शिव, इन्द्र, बृहस्पति तथा शुक्र ने उसे क्रमशः संक्षिप्त वनाया। ग्रीर ग्रंत में मनु तथा भारद्वाज ग्रादि द्वारा भी "राजधर्म" का संक्षिप्त वर्णान करना उल्लिखित है। मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पाराश्चर स्मृति तथा शुक्रनीति आदि से यह भी प्रकट है कि उस समय लेखक अपना नाम प्रकाशित नहीं करना चाहते थे भीर अपनी कृतियों को किसी देवता की समिपित करते हुए कृति की संज्ञा (नाम) निर्धारित करते थे। कौटिल्य के ग्रर्थशास्त्र में इस प्रकार के ग्रनेक ग्रंथों का प्रसंग मिलता है जिनमें बृहस्पति, शुक्र, मनु, पाराशर, कनिक, कात्यायन ग्रादि मुख्य हैं। ग्रन्य दूसरे विज्ञानों की भाति, राजनीति शास्त्र के ज्ञान की भी कई शाखाएँ थीं ग्रीर उपरोक्त ग्रनेक ऋषि लोग ही प्रत्येक के संस्थापक माने जाते थे। कुछ लोग मानव सुष्टिकत्ती "मनु" को ग्रपना संस्थापक स्वीकार करते थे, कुछ अन्य लोग, देवताओं के गुरू, "वृहस्पति" को तथा शेप अन्य लोग "शुक्र" को संस्थापक मानते थे। इनके ग्रतिरिक्त ब्रह्मा, विष्णु भीर महेश के साथ ग्रपना

³ Dr. Altekar State & Govt. in Ancient India Page 4 & 5.

संबंध सिद्ध करने वाले भी विद्यमान थे। ये लोग पर्याप्त मनन के पश्चात् कुछ लिखते थे. ग्रीर उसी के विस्तार का ग्राकार बाद में बृहद् ग्रंथ हो जाता था। इन कृतियों को देवतां ग्री ग्रयवा सस्यापकों के नाम से प्रकाशित करते थे। परन्तु ग्राजकल ये उगलव्ध नहीं हैं। महा-भारत तथा ग्रथंशास्त्र, जो उसी समय की ग्रथवा समीप की कृतियां हैं, उनमें ऐसे ग्रंथों के असंग मिलते हैं। यह भी संभव है कि महाभारत ग्रीर ग्रथंशास्त्र जैसी सर्वोत्तम पुस्तकों की रचना के कारण ग्रन्थ कृतियां प्रभावहीन होकर नष्ट हो गई हों।

सर्व प्रथम जब किसी विषय का अध्ययन आरंभ होता है तब लेखकों का ध्यान उसकी महत्ता सिद्ध करने की ग्रोर श्रधिक होता है। वे चाहते हैं कि समाज में उस विषय को प्रतिष्ठा प्राप्त हो। संभवतः राजशास्त्र के संबंध में भी यही धारणा श्रधिक क्रियाशील रही है। तत्कालोन कई लेखकों ने यह लिखा है कि केवल राजनीति शास्त्र ही अध्ययन योग्य विषय है, राजनीति शास्त्र में सम्पूर्ण ज्ञान निहित है, सर्वोत्तम ज्ञान राज्य विज्ञान है म्रादि । तत्कालीन राजनीति शास्त्र में, नुपतंत्र, नुप का शिक्षणा, म्रादर्श प्रशासक के गूण. मित्रयों की योग्यताएं ग्रीर कर्तव्य, कूटनीति के सिद्धान्त ग्रीर साधन, कर-सिद्धान्त, स्थानीय स्वशासन, नियम की धारएगा, दण्ड विधान ग्रादि का वर्रान किया जाता था। इस संबंध में महाभारत सर्वाधिक महत्व का साधन है। शांतिपर्व में राजधर्म का वर्शन विस्तार से किया गया है। राजधर्म का अर्थ, जैसा हम पहले देख चुके हैं, प्रशासन तथा शासक के कर्च व्य से होता है। इसी में राज्य विज्ञान का महत्व तथा विभिन्न सिद्धान्तों की व्याख्या की गई है। राजा की उत्पत्ति के सिद्धान्त, मंत्रि-परिषद, कर-सिद्धान्त, गृह-प्रशासन के सिद्धान्त. स्थानीय स्वशासन का महत्व आदि विशद रूप में विश्वत हैं । शांति, युद्ध, विदेशी संबंधों के विभिन्न ग्राधार भूत सिद्धान्त, ग्रनेक हण्टान्त ग्रीर उपमाग्रों के द्वारा ग्रत्यन्त रोचक वन गए हैं। अर्थशास्त्र आदि अन्य गंथों की अपेक्षा महाभारत एक पूर्ण एवं समुन्तत कृति प्रतीत होती है। महाभारत का समय सुगमता पूर्वक संक्रम एकाल माना जा सकता है जिसमें "करो या मरो" के सिद्धान्त का प्रभाव प्रतीत होता है। इसलिए महाभारत में ग्रन्य विभिन्न स्थलों पर भी राज्य विज्ञान संबंधी वर्णन मिल जाते हैं। कुछ विशेष परिस्थितियों में संकट-कालीन कूटनीति, मेकेयावलीवाद और ग्रादर्श प्रशासन का भी ग्रच्छा वर्णन है। "

कौटित्य द्वारा रिचत 'ग्रर्थशास्त्र' दूसरा प्रमुख स्रोत है। यह ग्रंथ भो पौरा-िण्य है ग्रीर इसमें जितने विषयों का वर्णन है वह पूर्ण ग्रीर पर्याप्त है। विशेष रूप से प्रशासकीय व्यवस्था का वर्णन वहुत ही सुन्दर है। राज्य की प्रकृतियां. विभिन्न प्रकार के नियम, राजा को उत्पत्ति के सिद्धान्त, विदेश नीति के सिद्धान्त (मण्डल सिद्धान्त, ग्रादि) ग्रमेक महत्वपूर्ण विषयों का प्रशस्त वर्णन अर्थशास्त्र में ग्रनूठा है। इस प्रकार राजनीति शास्त्र के प्राचीन ज्ञान का ग्रखण्ड भण्डार इन ग्रंथों में है। ङा० ग्रन्टिकर की सम्मित में ग्रर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, ग्रथवा प्रशासनीय मौलिक सिद्धान्तों की विवेचना का दार्शनिक

[?] Dr. Altekar-State & Govt. in Ancient India-page 9.

ग्रंथ होने की ग्रपेक्षा, प्रशासक के लिए नियमाविल ग्रधिक है। वास्तव से अर्थशास्त्र में प्रशासन के व्यावहारिक रूप और समस्याओं का ही ग्रधिक वर्णन है। ऐसे ग्रंथों का सचमुच ग्रभाव है जिनमें प्रशासन, राज्य के कत्त व्य, शक्तियों ग्रादि का ऐसा विशद विवरण हो।

अर्थशास्त्र का समय (Date of Arthasastra,: — अर्थशास्त्र के रचना-काल पर बहुत समय तक लम्बा विवाद चलता रहा है। कुछ प्रमुख भारतीय तथा विदेशी विद्वानों की तो यह मान्यता रही है कि यह कृति, विख्यात सम्राट चन्द्रगुप्त मौर्य के सुयोग्य सचिव चारावय द्वारा लिखित है। इस श्रेणी में सर्वश्री श्यामा शास्त्री, गरापति शास्त्री, नरेन्द्रनाथ लॉ, स्मिय, पलीट, जायसवाल आदि आते हैं। अन्य दूसरे विद्वानों की धारणा है कि यह कृति बहुत समय बाद ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में लिखी हुई है। इस श्रेणी में सर्वश्री भण्डारकर, कीथ , जॉली, विन्टरनीज आदि हैं। वास्तविक स्थिति का ज्ञान अभी तक इसलिए दुर्लभ रहा कि बीच बीच में यही कृति संशोधित होती चली गई और विषय और भी गंभीर बन गया। दोनों वर्ग अपनी अपनी मान्यताओं के संबंध में विभिन्न वाद प्रस्तुत करते हैं इसलिए यह उचित है कि हम पहले दोनों पक्षों से परिचित हो जायं।

प्रथम पक्ष के विद्वान पं. क्यामा शास्त्री विद्या डा० जायसवाल म्रादि यह प्रस्तुत करते हैं कि ग्रंथ के अन्त (Colophan) में यह स्पष्ट ग्रं कित है कि इस ग्रंथ की रचना कीटिल्य द्वारा की गई है जिसने देश की नन्द राजाओं से रक्षा की थी। दूसरे, चक्रवर्ती राजा के क्षेत्र का वर्णन करते हुए उसमें लिखा गया है कि हिमालय से लेकर समुद्र तक विस्तृत है। यही तत्कालीन साम्राज्य की वास्तविक सीमाएं थी तीसरे, इस पुस्तक में उन्हीं संस्थाओं एवं संगठनों का वर्णन है जो तत्कालीन सामान्य जीवन में प्रचलित थे। इसलिए विशेष परिस्थितियों का तथा सम्पूर्ण प्रकार की विभिन्नताओं का समावेश करने की प्रावश्यकता या संभावना नहीं समभी गई थी। चौथी, तत्कालीन समय में तथा बाद में भी

[?] The "Arthasastra is more a manual for the administrator than a theoritical work on polity discussing the philosophy and fundamental principles of administration or of the political science".

⁻Dr. Altekar-(State & Govt. in Ancient India page 10.)

Royal P. A.B. Keith A Jorunal of the R.A.S; 1916—We cannot yet say, save as a more hypothesis that the Arthasastra represents the work of a writer of 300 B.C. (P. 131) & that it may be assigned to the first century B.C., which its matter very probably is older by good deal than that P. 137.

३ अर्थशास्त्र की 'पाण्डुलिपि', जिससे श्यामा शास्त्री ने प्रथम संस्करण सन् १६०६ में प्रका-शित किया, तामिल प्रदेश से प्राप्त हुई प्रतीत होती है। डा० ऑपर्ट की संस्कृत पाण्डुलिपियों की यंथ सूची जो दिल्ला भारत के निजी पुस्तकालयों से संबंधित थी, में भी कौटिल्य के अर्थशास्त्र की पाण्डु-लिपि का उल्लेख है जो कुम्भकोनम के नरसिंहाचार्य के अधिकार में था। पं. महादेव शास्त्री, जो मैसर के पुस्तकालय के अध्यद्य थे, ने बताया कि अर्थशास्त्र की पाण्डुलिपि कंजीवरम के निकट एक आम निवासी श्री अर्थ्युनी राधवाचार्य से प्राप्त हुई थी (प्रथम प्रकाशन यहीं से शास्त्री द्वारा ही कराया गया था अत: संभवतः डा० ऑपर्ट द्वारा भी इसी कृति का उल्लेख किया गया है)।

बहुत दीर्घ काल तक यह एक स्वीकृत भारतीय परम्परा रही है कि लेखक स्वयं अपने नाम का उल्लेख नहीं करता था। ऐसे अनिवार्य स्थलों पर जहां स्वयं का नाम आवश्यक हो सर्वनाम में प्रथम पुरुष के स्थान पर अन्य पुरुष का प्रयोग किया जाता था। मैं या हम के स्थान पर उस या वह का प्रयोग क की प्रथा सी थी। इसीलिए कौटिल्य ने भी इसी प्रथा का अनुसरण किया है। इस प्रकार अर्थशास्त्र के रचियता कौटिल्य ही थे, इसमें सन्देह का स्थान नहीं है।

दूसरे पक्ष के विद्वानों का यह कथन है कि यह ग्रंथ कौटिल्य द्वारा नहीं लिखा गया। प्रथम, तो इसलिए कि मौर्यकाल में उपस्थित होते हुए भी उसने मीर्यकालोन प्रशासन की सारी विशेषताओं का वर्णन नहीं किया। ऐसी अनेक प्रधान वातें हैं जिनका उल्लेख हमें अन्य स्रोतों जैसे यूनानी आदि में मिलता है और स्वयं कौटिल्य के अपने इस ग्रंथ में वे उपलब्ध नहीं है। दूसरे, विदेशियों के प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए था, सिद्धान्त किस प्रकार के थे, उनकी रक्षा का भार राज्य पर था या नहीं, ऐसा महत्वपूर्ण वर्णन अर्थशास्त्र में नहीं है। तीसरे, यह ग्रंथ यदि स्वयं कौटिल्य द्वारा लिखित होता तो वह स्वयं अपने लिए सर्वनाम के उत्तम पुरुष का प्रयोग वयों करता ? इस प्रकार यह सिद्ध होता है, कि अर्थशास्त्र के रचियता कौटिल्य नहीं थे।

डा० अल्टेकर के मतानुमार ''कीटिल्य' नाम अच्छा नहीं है; परन्तु केवल इसीलिए हम अर्थशास्त्र की ऐतिहासिकता पर संदेह नहीं कर सकते क्यों कि इसी प्रकार के शुष्क श्रथवा स्पष्ट नाम उनसे पूर्व भी प्रचारित रहे थे जैसे वात्व्याधि, कोएगानदांत ग्रादि । साथ यह भी नहीं कहा जा सकता कि यह भास के बाद की कृति है क्योंकि ग्रथंशास्त्र के कई उद्धरण भास की कृति में ज्यों के त्यों उपलब्धं है क्योंकि कौटिल्य ने अपने पूर्व के समस्त स्रोत स्पष्ट रूप से स्वीकार किए हैं ग्रीर भास उनमें नहीं है। यह कहना कि मेगास्यनीज ने ग्रपने संस्मरणों में कौटिल्य का नाम नहीं लिखा, एक उचित बात हो सकती थी, पन्तू वे भी हमें, पूरे रूप में प्राप्त नहीं हैं। इसी प्रकार पातंजिल द्वारा कौटिल्य का उल्लेख न करना भी इसकी ऐतिहासिकता के विरुद्ध नहीं माना जा सकता, क्योंकि संभव है ऐसा प्रसंग ही न ग्रा पाया हो। ग्रशोक ग्रौर विदुसार का उल्लेख भी तो वहां नहीं है। इसलिए यह वाद भी उपयक्त नहीं हो सकता। इसके विपरीत समर्थन में अनेक वातों पर विचार किया जा सकता है। प्रथम, कौटिल्य ने उस समाज का वर्शन किया है जिसमें विधवा पूर्नीववाह, विवाह-विच्छेद, तथा वयस्क विवाह ग्रादि प्रचलित थे ग्रीर यह ग्रवस्था मीर्यकाल में उपस्थित थी । दूसरे, उस समय बौद्ध धर्मावलम्बियों के प्रति सम्मान का ग्रभाव था ग्रीर परिवार की उचितं व्यवस्था किए विना साधु वनना अनुचित माना जाता था। ऐसी स्थिति इस बात की द्योतक है कि बृद्ध-धर्म उस समय तक दृढ़ नहीं था। यह भी मोर्यकाल को परिस्थितियों में

१ इसी प्रकार प्राचीन काल में ऐसे अनेक नाम थे जैसे कुत्स (despisedone) जो सप्तऋषियों में से एक हैं, शुनरोफ (Dog's tail), दिनोदशा (Time-Server), चर्मीसर Leather-Head) आदि जिनका तात्पर्य शाब्दिक अर्थ के अनुसार लगाया जाय तो अनर्थ हो जाय जो जपर इंगतिश में लिखे गए हैं।

माता है। तीसरे, राज्य कर्म बारियों के लिए 'युक्त' शब्द का प्रयोग होता था, यह भी मोर्यकाल की ही बात है। चौथे, खन्मोज, मल्ल, लिच्छिवि ग्रादि गणराज्यों का वर्णन ग्रयंशास्त्र में होना, यह प्रमाणित करता है कि यह पुस्तक प्रारंभिक मौर्यकाल की रचना हैं जब ये गराराज्य पूर्ण विकसित और उन्नत थे। पाँचनें, पाणिनी की व्याकरण का प्रयोग भी कौटिल्य ने नहीं किया, इसलिए यह कहा जा सका है कि उस समय तक यह व्याकरण ग्रधिक लोकत्रिय नहीं हुई थी। इसलिए ग्रर्थशास्त्र का रचना-काल ईसा से पूर्व चतुर्थ शताब्दी होनी चाहिए, ईसा से परचात् चतुर्थ शताब्दी नहीं। छठा, मेगास्थनीज तथा की टिल्य के बहुत से वर्रान एक रूप में है, जैसे शिकार तथा धार्मिक जुलूस, जुलूसों के समय राजकीय व्यवस्था, सिचाई की नहर प्रणाली, राजा की दूत प्रणाली ग्रादि । विदेशियों के लिए सुविधा ग्रादि संबंधों नियमों का उल्लेख भी समान रूप से प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त प्रर्थशास्त्र में उल्लिखित 'गोप' एवं 'अध्यक्ष' मेगास्थनीज द्वारा विश्वित कर्मचारियों के समान है। इसलिए कौटिल्य प्रौर मेगास्यनोज का समकालीन होना प्रमासित होता है।

उपरोक्त सब प्रकार का वर्णन ध्यान में रखते हुए यदि निर्णय किया जाय तो यह सिंद होना है कि कौटिल्य का ग्रर्थशास्त्र पूर्ण रूपेए। उसी की कृति सिंद्ध करने के मार्ग में कई ग्रभाव हैं जो सन्देह उत्पन्न करने में समर्थ हैं। परन्तु उन ग्रभावों को दोप, नहीं कहा जा सकता । अपनी रुचि के अनुसार विषयों का विवेचन सदैव श्रीष्ठ माना गया है । इसलिए एक वर्णन की कमी अथवा एक विषय के संबंध में विविध वर्णन, उनकी रुचिका प्रतीक मान लिया जाना चाहिए। श्रीर फिर ग्रर्थशास्त्र की रवना-तिथि एवं लेखक के संबंध में तो श्रनेक अकाट्य प्रमासा भी उपलब्ध हैं। कौटिल्य विख्यात राजनीतिज्ञ और कुशल प्रशासक ही नहीं था वरन राजनीति विचारधारा का संस्थापक भी था। इसीलिए उसके बाद के युग में वह बहुत प्रतिष्ठित रहा और उसका ग्रंथ ग्रीर नाम बहुत महत्वपूर्ण तथा ग्रादर्श रहे। वारा और दिण्डिन ने ग्रंथ का ग्रध्ययन राजपुत्रों के लिए प्रस्तावित किया। जैन साहित्य में अर्थशास्त्र को रामायण महाभारत आदि पौराणिक ग्रंथों की श्रेणी में खला गया और दक्षिए। में ग्रन्छे कूटनीतिज्ञ शासकों को विब्तुगुद्त (कौटिल्य) का रूप बताया गया।

ग्रतः हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि 'ग्रर्थशास्त्र, वास्तव में सम्राट चन्द्रगुप्त मौर्य के समय में उपस्थित कौटिल्य द्वारा ही लिखा गया था और यह इतना पूर्ण और प्रशस्त ग्रंथ था कि सदियों तक इसकी वरावरी में कोई ग्रन्य ग्रंथ प्रशस्त नहीं हो सका भौर वत्त मान समय तक यही कृति प्राचीन राजनीतिक सिद्धान्त और व्यवहार पर अनुपम ज्ञान प्रदान करती है। संस्कृत में एक "बृहस्पत्य-प्रर्थशास्त्र" श्रीर प्राप्य है; किन्तु यह बहुत बाद के समय की रचना है (लगभग १२ वीं सदी)। तथा इसमें राजनीति शास्त्र संबंधी मीलिकता गथवा विलक्षणता का पूर्ण ग्रभाव है। संभव है किसी साधारण व्यक्ति ने लिखकर, प्राचीन परम्परा के यनुसार 'बृहस्पति' का नाम जोड़ दिया है। कीटिल्य का 'अर्थशास्त्र' ग्राज भी

१ डा० अल्टेकर — State & Govt, in Ancient India, Pages 11-13. १ अर्थशास्त्र — अनियोगय अर्थेषु आगन्त्नां, अन्यत्र सम्योपकारिन्सः । १ए८ ६= । १ Kautilya states that the alphabet consists of sixety three letters: (अनारादयो वर्णाः त्रिपप्टिः) पृष्ठ ७१.

राजनीतिक व्यवस्था तथा सिद्धान्तों के विषय में ग्रमूल्य एवं महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो चन्द्रगुष्त मौर्य के समय में रचा गर्या था।

टिप्प ग्याँ

प्राचीन भारत के राजनैतिक सिद्धान्तों एवं संस्थाओं का अध्ययन करने के लिए सम्पूर्ण साधनों को संक्षेप में निम्न बिन्दुओं द्वारा निर्धारित किया जा सकता है जो संस्कृत, पाली तथा प्राकृत ग्रादि भाषाओं में उपलब्ध हैं।—

- (१) ऋग्वेद ग्रीर ग्रथ ववेद के संबंधित प्रमंग।
- (२) सतपथ्, म्रात्रेय, तंतरीय तवा पंचिवश ब्राह्मणों में संबंधित उद्धरण ।
- (३) धर्मसूत्र तथा स्मृतियां (मनु, नारद, पाराशर ग्रादि)।
- (४) पुराण ग्रीर उपनिपद (पुराण ग्रधिकांश स्मृतियों के विचारों को संक्षित बनाकर वर्णन करते हैं, ग्रत: ग्रधिक महत्वपूर्ण नहीं है)।
 - (५) नीति प्रंथ [शुक्रनीति सार (कौटिल्य के बाद की महत्वपूर्ण कृति), कामन्दकीय नीतिसार (लगभग ४०० वर्ष ईस्वी पश्चात् गुप्तकाल में रिवत), नीति वाक्यां मृत (लगभग ६६० वर्ष ईस्वी पश्चात् सोमदेव सुरी, जैन लेखक द्वारा) ग्रिभलाय हितार्थ चिन्तामिए। (सोमेश्वरकृत), युक्ति-कल्पद्रुम (भोज, सन् १०१५ ई०), राजनीति कल्पद्रुम (लक्ष्माधर सन् ११२५ ई.), राजनीतिकाण्ड (देवन भट्ट, सन् १३०० ई. में) राजनीति रत्नाकर (चन्देश्वर, सन् १३२५ ई.), नीति मयूल (नीलकण्ठ, सन् १६२५ ई.), राजनीति प्रकाश (मित्र मिश्र,सन् १६५० ई.) श्रादि।
- ं(६) प्रस्तर लेख तथा ताम्रपत्र (ताम्र लेख)। (Epigraphic records)
- (७) यूनानी तथा ग्रन्य विदेशी यात्री एवं इतिहासकारों के लेख एवं संस्मरएा।
- (५) मुद्रा विज्ञान (Numismatics or the science of coins)।
- (६) ग्रन्य साहित्यिक सामग्री (रघुवंश, मालविकाग्निमित्र, पंचतंत्र, हितोपदेश, कादम्बरो, हर्पचरितसार, दशकुमारचरित, राजतरंगिणी, ग्रचरंग सूत्र, दीघनिकाय, चुल्लवग्ग, दिव्यावधान, जातक ग्रंथ ग्रादि)

कोटिल्य का विशेष परिचय—भारतीय परम्पराग्रों में कौटिल्य एक नहीं ग्रनेक नामों से विख्यात है जिनमें से कुछ नाम ग्रधिक लोकप्रिय हैं ग्रौर कुछ नाम साहित्य में विशेष प्रयोग में ग्राए हैं। जैन-साधु हेमचन्द्र कृत (सन् १०८८-११७२ ई.) ''ग्रभिधान चितामिण'' में निम्न पंक्तियां कौटिल्य के विभिन्न प्रचित्त नामों की सूची का परिचय देती हैं:—

वात्स्यायनेमल्लनागः कौटिल्य चएाकात्मजः।

द्रामिलः पक्षिलस्स्वामी विष्णुगुप्तो गुलश्च सः ॥ (पृष्ठ ३४, पंक्ति =५३ व =५४) इसी प्रकार यादव प्रकाश (सन् १५०० ईस्वी) कृत "वैजयन्ती" में निम्न पंवितया है:--

वात्स्यायनस्तु कौटिल्यो विष्णुगुप्तो वराणकः।

द्रामिलः पक्षिलस्स्वामी मल्लनागोऽङ्गुलोऽविच । (पृष्ठ ६६)

इन विभिन्न नामों के प्रचलित होने के साथ ही प्रत्येक नाम की कुछ य तर्कथाएं भी प्रचलित हैं जो प्राचीन साहित्य में मिलती हैं। उनमें से कुछ का वर्णन हिनकर होने के कारण यहां करते हैं। 'चाएगक्य'नाम के संबंध में विकाखदत्त इत मुद्राराक्षस की 'पूर्व पीठिका' में यह व्याख्या की गई है कि 'विष्णुगुप्त' अर्थात् कीटित्य अपने माता-पिता के साथ नन्द राजाओं द्वारा एक कीठरी में बंदी बना दिए गए थे और वहां भोजन के लिए उन्हें केवल 'चएक' (चने) दिए गए, इसलिए इसका नाम चाएाक्य प्रचलित हो गया। एक दूसरे प्रसंगानुसार डा॰ राजेन्द्रलाल मित्रा ने यह लिखा है कि कीटित्य, चएक का पुत्र था, इसलिए चाएाक्य नाम से पुकारा गया। इस प्रकार यह नाम पिता के नाम से लिया गया है।

कौटिल्य नाम का विश्लेषण निम्न प्रकार से किया जाता है । कुछ लोग 'कुटिल' (Crooked) शब्द से कौटिल्य का संबंध जोड़ते हैं, " परंतु यह उपयुक्त नहीं है । यदि कृटिल शब्द से कौटिल्य का नाम लिया जाता तो स्वयं कौटिल्य इम शब्द का ग्रधिक प्रयोग नदीं करता । मुद्राराक्षम में "कौटिल्य: कुटिलमित: स एवयेन कौधानी प्रसममदाहि नन्द वंश: ।।" कहा गया है किन्तु यह उचित नहीं जान पड़ता । स्वयं कौटिल्य ने 'इति कौटिल्य:" तथा 'नेति कौटिल्य: का प्रयोग ग्रयंशास्त्र में ग्रनेक वार किया है । एक विचार यह भी है कि से कुछ शब्द जैसे 'बहुल' से 'बाहुल्य', 'प्रवल' से 'प्रावल्य' वनते हैं उसी प्रकार 'कोटि' से कौटिल्य वना हो जिसका ग्रथं था उच्च कोटि का व्यक्ति, जिसमें कोटि के ग्रुणों का भंडार था । यह उसके शेष जीवन के वृत्तान्त से पूर्ण रूपेण सिद्ध भी होता है । प्राचीन उक्ति 'यथा नाम तथा ग्रुणा:' के ग्रनुसार यह संभव है कि यह नाम उसे वाद में ही मिला हो; किन्तु इसका ग्रथं (Derogatory) हीन भावना युक्त नहीं हो सकता । जिसने नीति का प्रयोग कर साम्राज्य बदल दिए ग्रीर शासन व्यवस्था ग्रादर्श रूप में सम्मादित की वह "कौटिल्य" ग्रयोन ('कोटि का व्यक्ति', श्रेष्ठ व्यक्ति कहा जा सकता था।

पक्षिलस्वामी भी कौटिल्य को कहा गया है। प्रखर बुद्धि वाला श्रम्येता होने के कारण, एक बार श्रवण किया हुपा ज्ञान एक पक्ष तक स्मरण रखता था इसिलए 'पिक्षल स्वामी' कहा गया था। 'द्रामिल' उसे इसिलए कहा गया कि वह द्रामिल भयात तामिल प्रदेश का निवासी था। अतः इस प्रकार उसके समस्त नाम सार्थक थे और उनका चाणक्य के किसी महत्वपूर्ण गुण की और संकेत होता था। प्रसिद्ध 'काम-सूत्र' का रचियता तथा गौतम के न्यायमूत्र की प्राचीनतम मीमांसा का लेखक वात्सायन भी यहो कीटिल्य था।

अर्थशास्त्र में कुछ प्रमुख प्रसंग ऐसे हैं जिनका उसके जीवन से स्पष्ट संबंध सिद्ध होता है। निम्न उद्धरण इसी श्रेणी के हैं:—

^{2.} Dr Rajendra lal Mitra-Jaurnal of the Bengal Asiatic Society-Vol.52(1883) P. 268.

२ मुद्राराजक-पृष्ठ ६१।

[?] Dr. Keith-Suggests that the name Kautilya is suspicious for it means falsehood, and that "that it seems a curious name for him to bear in his own work."

४ तारनाथ-"वानस्पत्य" तथा टा० मित्रा (उपरोक्त) पुष्ठ २६२ ।

(१) सर्व शास्त्राण्यनुक्रम्य प्रयोगमुपलभ्यच।

कौटिल्येननरेन्द्राथें शासनस्य विधि: कृतः। (फुळ ७५) ग्रर्थात् शासन की विभिन्न विधियां जो नरेशों के लिए ग्रावश्यक थीं, समस्त शास्त्रानुसार तथा प्रयोग क्रम (रीति रिवाजों के ग्रनुसार) के ग्रनुसार उपलब्ध बनादीं।

(२) येन शास्त्रंच शस्त्रंच नंदराज गता च भू:।

अमर्षेणों द्वृतान्याशु तेन शास्त्र मिदं कृत्रम।। (पृष्ठ ४२६) अर्थात् यह कृति उस व्यक्ति की रचना है जिसने बलपूर्वक ज्ञान, सैनिक शक्ति तथा नन्द राजामों द्वारा शासित भूमि शोधता से प्राप्त करली थी। आदि।

प्रथंशास्त्र की एतिहासिकता के कुछ अन्य प्रमाण विभिन्न कृतियों में उपलब्ध प्रसंगों के रूप में शाप्त होते हैं। दण्डिन का 'दशकुमारचरित' (पृष्ठ ५१-५) तथा वाग की 'कादम्वरी' (पृष्ठ १०६) बहुत उपयोगी प्रसंग हैं। पंचतंत्र में कौटिल्य से संबंधित कम से कम तीन चार स्पष्ट प्रसंग उपलब्ध हैं। सातवीं या आठवीं शताब्दी में मेधातिथि कृत ''मनु स्मृति'' की मीमांसा में कौटिल्य का प्रसंग है (पृष्ठ ७७४)। इसी प्रकार क्षीरस्वामी द्वारा लिखित ''टीका सर्वस्व'' दिनकर मिश्र द्वारा लिखित 'रघुवंश' (कालीदास कृत) की मीमांसा, चरित्रवद्धन द्वारा लिखित 'रघुवंश' की मीमांसा, मिललनाथ कृत 'रघुवंश की मीमांसा, 'कुमार संभव' पर गणपित शास्त्री द्वारा प्रकाशित मीमांसा, जीमूतवाहन कृत 'व्यवहार-मात्रिका'' आदि सभी ग्रंथों में कौटिल्य संबंधी बहुत उपयोगी प्रसंग हैं, 'किन्तु पुस्तक विस्तार के भय से यहां उद्धृत करना संभव नहीं है। ग्रतः ऐसी ग्रनन्य कृति वास्तव में उसी कौटिल्य द्वारा लिखी हुई है जिसने नन्द वंशियों का नाश किया तथा मौर्यवंश को स्थापित किया।

कोटिल्य एवं मेकेयावली — पूर्व में कौटिल्य ग्रौर पिश्चम में मेकेयावली क्रमशः प्राचीन भारतीय राजनैतिक सिद्धान्त एवं ग्राधुनिक राजनैतिक सिद्धान्तों के प्रमुख प्रवर्त्त कराने जाते हैं। मेकेयावली द्वारा लिखित राजकुमार (Prince) में जो सिद्धान्त प्रतिपादित किए गए हैं वे कौटिल्य द्वारा स्थापित ग्रर्थशास्त्र में विणित सिद्धान्तों से पर्याप्त रूप में मिलते हैं। मेकेयावली के ग्रादर्श राजकुमार (Ideal Prince की ग्रर्हताएं प्रमुख रूप से वही हैं जो कौटिल्य एक शासक के लिए वांछनीय समक्षता था। इस प्रकार दोनों सहमत हैं कि शासक का प्रथम कर्ता व्य राज्य की सुरक्षा है। शासक को उन सब व्यसन एवं सुराइयों से बचना चाहिए जो कभी प्रशासन को क्षति पहुँचा सकें। शासक को सिंह ग्रौर लोमड़ी दोनों होना चाहिए। शासक को वास्तव में न हो तो भी दयालु, स्वामिभवत एवं धार्मिक प्रतीत होना चाहिए। उसे ग्रपनी प्रजा के सम्पत्त संबंधी ग्रधिकारों में ग्रनावश्यक रूप में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि मानव उसके पिता की हत्या को तो फिर भी शीघ्र ही क्षमा कर देगा किन्तु पैतृक-सम्पत्ति की हानि को कभी नहीं भूलेगा। शासक को किसी में प्रतिशय विश्वास रखकर निर्वचत नहीं वन जाना चाहिए ग्रीर न ग्रतिशय संदेह द्वारा शासन को

[?] Sir Subrahmanya Aiyar Lecture, 1914—Some Aspects of Ancient Indian polity:—(इस पुस्तक के परिशिष्ट (Appendix) यह सम्पूर्ण वर्णन बहुत विदत्तापूर्ण हंग से दिया गया है जो विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी है)

कठोर वना देना चाहिए। जहां देश की सुरक्षा का प्रश्न हो, वहां न्याय, दया, वैभव या अन्य भावनाओं को महत्व नहीं देना चाहिए। परन्तु दोनों में प्रधान अन्तर यह है कि कौटिल्य भी मेनेयावलों की भांति राजधर्म (दण्डनीति) को नीतिशास्त्र और धर्म से अलग समभता है और पृथक ज्ञान के रूप में व्याख्या करता है, किन्तु फिर भी विश्व की स्थायी नैतिक-व्यवस्था में कौटिल्य का हढ़ विश्वास है। संभवत: इसको रक्षा करना वह शामक का कर्ता व्य स्वीकार करता है। संकटकालीन स्थिति में अवश्य वह राजधर्म की प्रधानता स्वीकार करता है। इस हिन्द से यह कहा जा सकता है कि भारतवर्ष के वर्तमान नवीन संविधान में भी राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार कौटिल्य के मान्यताओं के अनुसार ही प्रतीत होते हैं और साधारण स्थिति में वहीं नीति और धर्म के स्वतंत्रताओं के साथ दण्डनीति का प्रयोग होता रहेगा। इस प्रकार प्राचीन और अर्वाचीन सिद्धान्तों का नवीन युग में सुन्दर समन्वय उपस्थित होता है।

दूसरा ग्रध्थाय

राज्य का स्वरूप

(Conception of State)

प्रस्तावना—डा० भण्डारकर ने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के भाषणा-क्रम में इस विषय पर प्रकाश डालते हुए पूर्वकथित विचार की पुष्टि की थी कि यदि भारत में कोई राजनैतिक सिद्धान्त और विचार नहीं ये तब तो प्राचीन राज्य के स्वरूप पर कुछ कहने का प्रश्न हां उपस्थित नहीं होता। परन्तु वर्तमान समय में अर्थशास्त्र, कामन्दकीय नीति सार, मनुस्मृति, शुक्त-नीतिसार तथा महाभारत आदि ग्रंथ राजनैतिक विषयों पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं।

व्याख्या—राज्य के संबंध में सप्तांग-सिद्धान्त (Doctrine of seven limbs) वहुत प्रसिद्ध है। इस सिद्धान्त के अनुसार राज्य के सात अंग या प्रकृति अयवा भाग होते हैं। वे इस कम से हैं:—

(१) स्वामी (Sovereign) (२) ब्रामात्य (Minister) (३) राष्ट्र या जनपद (Territory) (४) कोष (Finance or Treasury) (५) हुर्ग (Fortress) (६) वल (Army) (७) मित्र (Ally)।

इन सात अंगों द्वारा राज्य का निर्माण माना जाता है। कामन्दक ने अपने चतुर्थ सर्ग के प्रथम इलोक में ही इसका वर्णन किया है—

''स्वाम्यमात्यश्च राष्ट्रञ्च दुर्ग' कोशो बर्ल सुहृत्।

परस्परोपकारोदं सतांगं राज्य मुच्यते।।१।। प्रथात् स्वामी, मंत्री, राज्य (भूभाग), दुर्ग, कोष, सेना एवं मित्रवर्ग यह परस्पर उपकारी होने से राज्य के सात ग्रंग कहे जाते हैं। एक ग्रंग के भी विकल होने से राज्य में गड़वड़ होती है इसलिए राजा को परीक्षा पूर्वक इनकी सम्पूर्णता रखना उचित है। इन तत्वों को राज्य की प्रकृति के रूप में विणित किया गया है। परंतु इसका ग्रंथ यहां स्वभाव (Nature) से नहीं लिया जा सकता। वास्तविक ग्रंथ राज्य के स्वाभाविक तत्व के रूप में लिया जा सकता है, जो उचित है। यह शंका भी की जा सकती है कि राज्य का ग्रंथ राज्यानी, सरकार या प्रदेश कुछ भी हो सकता है। परंतु यहां राज्य के अतिरिक्त कोई ग्रंथ उपयुक्त नहीं है क्योंकि उपयुक्त सातों ग्रंग ग्रीर किसी भी तरह की ग्रन्य मान्यता के साथ संवंधित नहीं हो सकते।

अर्थशास्त्र तथा कामन्दकीय नीतिसार में उपर्युक्त समस्त तत्वों का विपद, विस्तृत तथा रुचिकर वर्णन मिलता है। अपने अध्ययन के लिए इन तत्वों का अर्थ तया महत्व समभ लेना पर्याप्त होगा।

१ Some aspects of Ancient Indian Polity—D. R. Bhandarkar (B.H.U. 1929) २ वामन्दकीय नीतिसार, श्लोक २, पृष्ठ २२.

- (१) स्वामी—इतका ग्रर्थ सार्वभीम तथा सर्वेसर्वा से लिया जाता है। यह एक या अनेक भी हो सकते हैं। अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने साधारणतः एकतंत्र (Monarchy या राजतंत्र) ही राज्य का सामान्य रूप माना है। राज्य के एक से ग्रधिक स्वामी की घारणा को प्रियकर नहीं माना गया है। स्वामी के लिए चार मुख्य अर्हताएं (Qualifications) आवश्यक समभी जाती थी ?:—
- (अ) अभिगमिका (Inviting nature)—स्वभाव से आकर्षक होना तथा जनता का अपना मार्ग अनुसरण करने तथा सम्पर्क पाने के लिए प्रेरित करने की क्षमता होना।
- (ग्रा) प्रज्ञा (Understanding)—सामान्य बुद्धि तथा साधारणतः प्रत्येक स्थिति की बीघ्र समक लेने की समर्थता।
- (इ) उत्साह (Energy)—व्यक्तिगत रूप से शारीरिक, मानसिक शक्ति सम्पन्नता।
- (ई ग्रात्म संपद (Self possession)—चरित्र तथा साहस का ग्रहितीय ग्राद्धी। इसी के साथ स्वामी के ग्रुएों या तत्वों (attributes) पर भी प्रकाश डाला गया है। स्वामी में तीन मुख्य ग्रुए। ग्रावश्यक हैं:—
 - (म्र) शक्य सामन्त--जो ग्रपने पड़ीसियों पर नियंत्रण करने में समर्थ हो।
 - (मा) म्रसुद्र परिशतक जिसके परामर्श के लिए विख्यात मंत्रियों की सभा हो।
- (इ) दीर्घदर्शी—- उचित समय व अवसर को दीर्घकाल पूर्व जानने वाला। कामन्दक ने ये तीन गुए त्याग, सत्य बोलना और शूरता वताए हैं। इनसे युक्त राजा सम्पूर्ण गुएों को प्राप्त होता है। उस समय स्वामी एक कुशल, कुलीन व समर्थ शासक होता था। केवल साधारए। सामन्त या राज्याध्यक्ष की कल्पना नहीं थी वरन वास्तविक सार्वभौम तथा सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न व्यक्ति ही स्वामी माना जाता था।
- (२) श्रामात्य साधारणतया इसका तात्पर्य मंत्री से होता है। अर्थशास्त्र में आमात्य का अर्थ है राज्य की सेवा में कोई भी उच्च अधिकारी। इसीलिए कौटित्य ने आदर्श आमात्य के लिए केवल दो गुणों की आवश्यकता स्वीकार की हैं—— १. जनपद अर्थात राज्य का स्थायी निवासी हो। और २. हदभक्ति अर्थात् कर्ता व्यपरायणता में पूर्ण विश्वास तथा आवरण करता हो। कामन्दक ने मंत्रियों के गुणों का वर्णन करते हुए लिखा है कि स्मृति अर्थात् कर्ता व्या कमीं का स्मरण रखना, योग्यता से धनादि

दीर्घदरित्वमुत्साहः ग्रुचिता स्थल लद्यता।
विनीतता थार्मिकता ग्रुणाः साध्याभिगामिकाः ।।=॥ [कामन्दकीय नीतिसार पृष्ठ ३३]
त्रिर्धाद —दीर्घदरी होना, उत्साह, पवित्र रहना, स्थलता से ही लच्य को जान लेना, विनय सम्पन्न होना, धर्मात्मा होना, साध्य वस्तु के सिद्ध करने के ग्रुण रखना—इन ग्रुणों से युक्त स्वामी लोक प्रिय होता है।

२. त्यागः सत्यश्च शौर्थ्यश्च त्रये एते महागुणाः। प्राप्तोति हि गुणान्सर्वा नेतेयु कतो नराधिषाः ॥२४॥ [कामन्दक-पृष्ठ ३६[

उपार्जन करने में तत्परता, तर्क रहितता, ज्ञान में निश्चय, हढ़ता ग्रौर मंत्र का गुप्त रखना यह मंत्री की सम्पद है। वास्तव में ये गुरा राज्य के प्रत्येक उच्च ग्रधिकारी के लिए भी ग्रावश्यक हैं।

(३) जनपद्—राष्ट्र या देश इस तत्व के सम्बन्ध में कौटिल्य ने बहुत विस्तार में वर्णन किया है। जनपद की विशेषताम्रों (Character stics) में यह जरूरी है कि वह पंक, चट्टान, ग्रसम, कण्टक तथा जंगली जानवरों ग्रादि ये रहित हो ग्रीर उर्वरा भूमि, भवन निर्माण योग्य काष्ठ (Timber) तथा हस्तियों से युक्त (भू-प्रदेश) हो। फिर जनपद के संबंध में चार ग्रावश्यक बातें लिखी हैं:—

ध-शत्रुद्धे षी-शत्रु से द्वेष करने वाला

म्रा-शक्य सामन्त-म्रपने पड़ोसियों पर नियन्त्रण करने में समर्थ।

इ---कर्मशील कृषक--कृषि करने योग्य व्यक्तियों द्वारा निवासित हो ।

ई-भक्त शुचि मनुष्य-पवित्र व कक्त व्य परायरा जनता से यूक्त हो।

उपर्युक्त तस्वों के संबंध के विस्तृत वर्णन से यह शंका स्वाभाविक है कि जनपद या राष्ट्र का श्रर्थ भू-भाग (Territory) से है अथवा जनसंख्या (Population) से है अथवा दोनों से। पहली विशेषताएँ तो निश्चित का से भू-भाग में ही हो सकती हैं परंतु दूसरी आवश्यक वार्ते निवासियों के चित्र एवं व्यवहार के प्रति अपेक्षाएँ (Expectations) हैं। इस संबंध में विद्वानों के मत भिन्न हैं। साधारण विचार से जनपद का शाव्दिक ग्रर्थ इसका सरल उत्तर देता है। जन अर्थात् मनुष्य या नागरिक जिनके चार ग्रुण आवश्यक बताए गए हैं और पद ग्रर्थात स्थान या भू-भाग जिसके लिए यह अपेक्षा की गई है कि वह कीचड़, पत्थर, कण्टक ग्रादि रुकावटों से रहित तथा उर्वरा भूमि श्रादि से युक्त हो—इस प्रकार जनपद का अर्थ, जनता व भू-भाग दोनों का सम्मिलित होना सिद्ध होता है। कामन्दक ने ग्रन्न, खनिज, उर्वरा भूमि ग्रादि से युक्त; कंकर पत्थर, सर्प ग्रादि से रहित तथा शिल्पी, चित्रकार, विशिक ग्रादि से सम्पन्न जनपद की अपेक्षा की है।

- ४. दुरी—सम्राट के लिए यह ग्रावश्यक था कि वह ग्रपने राज्य सीमाग्रों पर चारों दिशाग्रों में ऐसे दुर्गों का निर्माण कराए जो युद्ध उपयुक्त हो कौटिल्य दुर्गों का नर्गीकरण चार प्रमुख श्रेणियों में करता है:—
- (i) जल दुगें (Water Fort) (ii) पर्वत दुर्ग (Hill Fort) (iii) मरुस्थलीय दुर्ग (Desert Fort) (iv) वन्य दुर्ग (Forest Fort)। पिछले दोनों प्रकार के दुर्गों को श्रतावी दुर्ग (Wild Fort) माना जाता था तथा इनकी गराना प्रच्छे दुर्गों में होती थी। जल दुर्ग को भी श्रच्छा तथा पर्वत दुर्ग को श्रेष्ठ माना जाता था। दुर्ग वनाने के लिए स्थान का चुनाव, खाइयों की व्यवस्था, पानी का स्थायी प्रवन्य, ऊंची मीनारें, दीवारें ग्रादि के सम्बन्ध में धर्थशास्त्र में विस्तार पूर्वक वर्रान मिलता है। कुछ विद्वानों ने दुर्ग के

स्मृतिस्तत्परतार्थेषु वितर्को ज्ञान निश्चयः ।
 दृद्ध भक्तिरकत्तां च वैराणां सचितो भवेत् ॥२०॥ [कामन्दक पृष्ठ २७]

२. कामन्दक (५१ से लेकर ५५ तक के श्लोक का सारांश) पृष्ठ ४१

स्थान पर 'पुर' शब्द का भी प्रयोग किया है परन्तु इनका अर्थ समान ही है। मनु ने राज्य के सप्तांग सिद्धान्त में दुर्ग के स्थान पर 'पुर' का ही प्रयोग किया है। कामन्दक ने लिखा है कि विशाल सीमा वाला, गहरी खाई, ऊँची चाहर दीवारी तथा छज्जों से सम्पन्न पुर के समीप, पर्वत नदी और धने वन के समीप, जल, धन-धान्य से भरा पूरा, समय को सहने वाला बड़ा हढ़ दुर्ग राजा को बनाना चाहिए। दुर्ग रहित राजा पवन से प्रेरित मेघों के दुकड़ों के समान छिन्न-भिन्न हो जाता है।

४ कोष — कोटिल्य के मतानुसार श्रीष्ठ कोष वह ही सकता है जो स्वर्श, रजत, स्वर्ण मुद्रायों एवं रत्नों से सम्पन्न हो। परिपूर्ण कोप की सहायता वास्तव में दीर्घ तथा कठिन ग्रापत्तियों का सामना करने के लिए होती है। ये ग्रापत्तियों ग्राठ प्रकार की मानी जाती हैं। (१) ग्राम्न, (२) वाढ़, (३) ग्रकाल, (४) चूहे, (५) महामारी, (६) राक्षस ग्रादि। सम्पत्ति का उपार्जन भी पवित्रता तथा सवाई से किया जाना चाहिए। सम्पत्ति संग्रह के कई साधन होते थे। मुख्य ये हैं:—

- (१) प्रचार समृद्धि (Opulence of Industry Department run by the State)-राज्य द्वारा संचालित उद्योग की आय ।
 - (२) शस्य सम्पत Abundance of harvest)-म्रच्छी उपन ।
 - (३) पन्य बाहुल्य (Prospreity of Commerce) -न्यापार-समृद्धि ।

उपरोक्त तीनों साधनों को कीटिल्य ने 'वार्ता' को संज्ञा दी है। उसका विश्वास था कि कोष व सेना वास्तव में वार्ता पर ही आधारित होती है। सम्पन्न कोष की आवश्यकता राज्य प्रशासन एवं दढ़ सुरक्षा के लिए होती है। रिक्त कोष राजा के लिए कठिन समस्या तथा पूर्ण कोष वरदान माना जाता है। यह स्थिति आज भी सत्य है।

- ६. बल-मेना (Army) का महत्त्व राज्य की स्थापना तथा अस्तित्व के लिए सदा से महत्त्वपूर्ण रहा है। आंतरीय प्रशासन एवं वाह्य शत्रुओं के दमन के लिए सुदृढ़ एवं संगठित सेना अनिवार्य है। कीटिल्य ने इसे राज्य का छटकाँ तत्त्व माना है। सेना का वर्णन करते हुए उसने ६ प्रकार के सेनिक संगठन बताए हैं:—
 - (१) मूल (Hereditary Forces)
 - (३) भतक (Hired Troops)
 - (३) श्रेणी (Soldiers of fighting corporations)
 - (४) मित्र सेना (Troops belonging to an ally)
 - (४) शत्रु सेना (Troops belonging to an enemy)
 - (६) प्रतानी-बल (Soldiers of wild Tribes)

वर्णाश्रम के श्राघार पर भी सेनाश्रों की विशेषता का वर्णन किया गया है। ब्राह्मण, क्षित्रय, बैश्य तथा शूद्र चारों वर्णों की सेनाश्रों में श्रीष्ठ सेना ब्राह्मणों की थी परन्तु ब्राह्मण सेना की कमजीरी भी उसने वताई है, कि यदि कोई ब्राह्मण की साष्ट्रांक्स दण्डवत् करले तो ब्राह्मण की दया श्राजाती है। इसलिए क्षत्रिय सेना ही श्रीष्ठ है।

१. कामन्द्रकीय नीतिसार एलोक ५७, ५८ एष्ठ ४२।

9. मित्र—दो प्रकार के मित्र माने गए हैं, सहज श्रीर कृतिम। सहज मित्र वे होते हैं जिनसे पूर्वजों के समय से ही मित्रता चली ग्रा रही है तथा जो निकट के पड़ौसो शत्रु के समीप निवासित हैं। कृत्रिम मित्र वह होता है जिससे जीवन श्रीर सम्पत्ति की रक्षा हेतु मित्रता स्थापित की गई है। ये मित्र भी श्रेष्ठ (Superior) श्रीर हीन Inferior) दो प्रकार के होते हैं। मित्र का स्थान राज्य के तत्त्वों में माना गया है, यह प्राचीन भारतीय राज-नैतिक विचार की विलक्षणता है।

विवेचन-राज्य के उपरोक्त सात ग्रङ्ग माने जाते थे। इनके समन्वय के सभाव में राज्य की कल्पना संभव नहीं थी। यदि इस घारणा की तुलना स्रावृतिक राज्य की धारणा से की जाय तो यह निर्णय हो सकता है कि श्रेष्ठ तथा पूर्ण घारणा प्राचीन है ग्रथवा ग्रर्जा-चीन । म्राधुनिक राजनीतिक विचारकों में गेटेल, गिलकाइस्ट, गार्नर म्रादि की लिया जा सकता है। इनके विचारानुसार राज्य में चार प्रमुख तत्त्व होते हैं-(१ भू-भाग, (२) जन-संख्या, (३) सरकार एवं (४) सार्वभौमिकता। यह विचार प्राचीन राज्य की कल्पना के सम्मुख श्रधूरा प्रतीत होता है। प्रथम दोनों तत्त्वों की, प्राचीन राज्य का तीसरा स्रकेला तत्त्व जनपद या राष्ट्र पूरा कर देता है। चौथा तत्त्व सार्वभौमिकता, स्वामी के समान है तथा तृतीय तत्त्व सरकार प्राचीन राज्य का दूसरा तत्त्व पूरा कर देता है। तत्पश्चात् दुर्ग, कांप एवं वल ऐसे तत्त्व वच जाते हैं जो प्राचीन राज्य की घारए। को पूर्णता प्रदान करते हैं ग्रीर ग्राधुनिक धारणा को ग्रभाव युक्त । कामन्दक इन तत्वों को राज्य के निर्माण तत्त्व कहता है ग्रीर सिद्ध करता है कि राज्य वास्तव में एक प्राणी की तरह है जिसमें इन समस्त तत्वों का महत्व है। शंकराचार्य ने राज्य की तुलना रथ (Chariot) से की है जिस्में प्रत्येक ग्रह्म का ग्रस्तित्व महत्वपूर्ण है - जब सारे तत्व उचित ग्रनुपात से कार्य करते हैं तभी रथ का संचालन सरलता से संभव है। प्राचीन धारणा के श्रनुसार राज्य एक श्रात्मा वाला प्राणी माना गयां है जिसमें शरीर एवं प्रात्मा विद्यमान है। जो विकासमय तथा उन्नतिशील है। स्वामी इसका प्रारा है ग्रीर ग्रन्य तत्व शरीर। इस प्रकार राज्य की श्रेष्ठ कल्पना प्राचीन भारतीय विचारधारा में उपस्थित की गई है।

निष्कर्ष — उपरोक्त वर्णन से यह सिद्ध होता है कि प्राचीन भारतीय विचारकों ने राज्य की प्रकृति स्वरूप एवं स्वभाव का वर्णन किया है जब कि ग्राधुनिक पाश्चात्य विद्वान राज्य को केवल परिभाषा मात्र देते हैं। राज्य का वास्तिवक स्वरूप क्या है यह प्रकट करने में वे ग्रसमर्थ रहे हैं। भू-भाग एवं जनसंख्या तो राज्य के तत्व हैं ही; किन्तु सरकार की उत्पत्ति तो राज्य के बाद होती है। ग्रतः यह राज्य की विशेषताग्रों में ही ग्राता है. तत्वों में नहीं। ये चारों तत्व राज्य की परिभाषा बनाते हैं, राज्य का वास्तिवक स्वरूप नहीं प्रकट कर पाते। जब कि प्राचीन हिन्दू राज्य-ग्रपने तत्वों के द्वारा भपना पूर्ण परिचय देता है। एक ग्रीर मुख्य ग्रन्तर प्राचीन व ग्रवांचीन घारणाग्रों में यह प्रकट होता है कि ग्राधुनिक घारणा राज्य के गतिहीन संगठन (Statical state) के रूप में मान्यता देती है ग्रीर प्राचीन घारणा इसे गतिमय जीवनयुक्त संगठन का स्वरूप प्रदान करती है। प्राचीन राज्य ग्रपने पूर्णत्व की विशेषताग्रों से युक्त है जहां मित्र भी उसका ग्रपना ग्रह है तथा कोप की ग्रनिवार्थता भी ग्रावश्यक मानी गई है। ग्राधुनिक राज्य में ऐसी कल्पना का नितान्त ग्रभाव है। ग्रतः राज्य का प्राचीन स्वरूप पूर्ण एवं प्रभावशाली सफल संगठन है।

तृतीय ग्रध्याय

राज्य की उत्पत्ति के सिद्धान्त

(Theories about the origin of State)

प्रस्तावना—प्राचीन काल में हिन्दुयों के विचार में राज्य की धारणा क्या थी यह हम पिछले ग्रन्थाय में देख चुके हैं। ग्रव इस विषय पर विचार करेंगे कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में किस प्रकार के सिद्धान्त मान्य रहे हैं। डा० ग्रन्टेकर का विश्वास है कि हमारे पास तत्कालीन कोई प्रमाण नहीं है जिससे राज्य की उत्पत्ति को निश्चित रूप से सिद्ध किया जा सके। केवल पुराणों एवं ग्रन्थ प्राचीन ग्रंथों में विणात सामग्री से हो निष्कर्ण निकाल सकते हैं। प्राप्य साधनों से यह तो सिद्ध है कि प्राचीन काल में "राजा ही राज्य है" (King is the state) यह सिद्धान्त बहुत प्रचलित था ग्रीर राजतंत्र (Monarchy) राज्य का सामान्य स्वरूप माना जाता था। राजा ही राज्य की ग्रात्मा माना जाता था। ग्रतः राज्य की उत्पत्ति के सिद्धान्त वास्तव में राजा की उत्पत्ति के सिद्धान्त हैं। कौटित्य ने मी राज्य के कार्य एवं शासन का ही वर्णन किया है, सिद्धान्तों के संबंध में केवल कहीं कहीं ग्रीर वह भी ग्रत्यत्प रूप में लिखा है। ग्रतः इस संबंध में हमें वेद, उपनिपद, स्मृतियां, बौद्ध धर्म, ग्रंथ ग्रादि साधनों पर हा निर्भर रहना पड़ता है। महाभारत में इस विषय में सबसे मधिक भौर भनेक रूपों में विस्तारपूर्वक वर्णन मिलते हैं। इन ग्रनेक प्रकार के विचारों ग्रीर सिद्धान्तों में से मुख्य मुख्य वर्णन संक्षेत्र में इस प्रकार हैं: —

(१) वैदिक सिद्धान्त (Vedic Theory)—(म्र) मानेय नाह्मण में माये प्रसंगानुसार इस वात की पुष्टि की जाती है कि प्रारंभ में देवतामों में कोई सम्राट नहीं था। मुसुरों के साथ संघर्ष भी हीतें रहते थे जिनमें देवता सदैव परास्त होते थे। निरन्तर परास्त होने के कारणों पर विचार करने के पश्चात् वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि प्रमुरों की विजय इसिलए होती है कि उनके नेतृत्व के लिए सम्राट को व्यवस्था की गई है। मतः देवतामों ने भी निश्चय किया कि यही प्रयोग हम भी करें और सम्राट के निर्वाचन के लिए सब सहमत हो गये। यही सब की सम्मित से राजा के निर्वाचन की प्रया का श्रीगणेश माना गया है। डा॰ जायसवाल के मतानुसार उक्त विवरण ऐतिहासिक प्रसंग में भी ठीक उतारा जा सकता है। जब भारतवर्ष में शार्य लोग (Tribal Stage) मादि काल से गुजर रहे थे तब द्रविड लोगों से यह साम्राज्ञीय संस्था (Institution of Kingship) प्रयनायी गई भीर राजा का पद निर्वाचन से निर्धारत होना स्वीकार किया गया। र राज्य की उत्पत्ति का यह विवरण 'देवासुर संमाम सिद्धान्त' के नाम से प्रयन्ति है तथा इसका विवरण अनेक पुराणों में मलग मलग हंग से किया गया है।

(व) इसी सिद्धान्त को याचेय याह्मण में इन्द्र के महाभिषेक उत्सव के साथ मी उपस्थित किया गया है। इन्द्र की सार्वभौमिकता (Sovereignly of Indra) की भांति

^{3.} Altekar State & Govt. in Ancient India.

२. डा॰ वायसगल-दिन्द्र पालिटी

'ही मानव-समाज में भी सार्वभौमिकता की स्थापना का अनुमान किया जा सकता है। कुछ सीमा तक यह उचित है कि देवतायां की कल्पना भी मानव अपनी हो ब्राकृति के अनुरूप करता है और इसीलिए यह संभव है कि मानव की सार्वभौमिकता, देवतायों के ग्रादर्श पर ही ग्रपनायों गई हो। तदनुसार इन्द्र के महाभिषेक उत्सव में यह इंगित किया गया है कि देवतायों के सम्मेलन में, प्रजापित अध्यक्ष थे और वहां परस्पर वार्तालाप के पश्चात् इन्द्र की ग्रोर संकेत करते हुए यह कहा गया कि 'देवतायों में सर्वाधिक शक्तिमय, ग्रत्यन्त बलवान, पराक्रमी तथा सर्वथा पूर्ण यही है जो प्रत्येक कार्य को भली प्रकार सम्पन्न कर सकता है, ग्रतः इसी को सम्राट के पद पर ग्रासीन करना चाहिए"। कित्वश्चात् सर्व सम्मित से इन्द्र के ग्रभिषेकोत्सव की स्वीकृति की गई ग्रीर इस प्रकार उसकी सार्वभौमिकता स्थापित हुई। इस सिद्धान्त में पश्चिमी विद्धानों द्वारा प्रचारित सामाजिक समभौते के सिद्धान्त से कुछ साम्य प्रतीत होता है। उदाहरएए। इन्द्र ने ग्रपनी सार्वभौमिकता देवतायों के चुनाव द्वारा प्राप्त की तथा देवतायों ने ग्रपने में से ही एक को ग्रधिकार दिए। इस प्रकार यह सिद्धान्त सामाजिक-समभौते के सिद्धान्त के समीप प्रतीत होता है।

(स) तैत्तरीय ब्राह्मण में भी राजा की उत्पत्ति का सिद्धान्त दिया गया है, किन्तु थोड़े परिवर्तन के साथ। प्रजापित ने इन्द्र को युवक होने के कारण सब देवताओं के राजा के रूप में उपस्थित किया और उससे कहा कि तुम जाओ और इन देवताओं पर राज्य करो। परंतु जब दन्द्र देवलोक पहुँचे, तब देवताओं ने प्रश्न किया 'तुम कौन हो ?'' हम तो स्वयं देवता हैं। यह सुन इन्द्र वापस प्रजापित के पास पहुँचे। प्रजापित उस समय सौर-चक्र (Luster of the sun) से मुक्त थे। इन्द्र ने कहा—''यह (luster) ग्राप मुफे दें ताकि मैं उन पर जासन कर सकू'।'' प्रजापित से सौर चक्र प्राप्त कर इन्द्र देवताओं के ज्ञासक बने। इस प्रकार यह सिद्धान्त ईश्वरीय सिद्धान्त के ग्राधक समीप सिद्ध होता है।

उपर्युक्त तीनों प्रकार के सिद्धान्त वेदों के आधार पर प्रतिपादित हैं। इससे यह तो सिद्ध है कि राज्य की उत्पत्ति के सिद्धान्त ब्राह्मरण काल से उपलब्ध हैं। इससे पूर्व का ज्ञान आज भी अलभ्य है।

(२) बौद्ध धर्म का मत—बौद्ध धर्म-संबंधी साहित्य में राजनीतिक विचार कम हैं तथा वे भी अधिकांश सांसारिकता से दूर अध्यात्म के विकास की ओर संकेत करते हैं। "राज्य की उत्पत्ति सामाजिक समभौते के फलस्वरूप हुई" यह मान्यता लगभग ब्रह्मा, चीन, लंका, तिब्बत आदि स्थानों में भी प्रचलित है। 'दीघ्ध निकाय' में भी यही वर्णन है। इस सामाजिक समभौते की व्याख्या इस प्रकार की गई है:—आदि काल में सभी व्यक्ति संतुष्ट थे। उनका शांतिमय जीवन था। काल क्रमानुसार पतन प्रारम्भ हुआ और रंग, सम्पत्ति, लिंग आदि के भेद उत्पन्न हो गए। लालच, स्वार्थ, मद आदि विचारों से मन उद्धिग्न होने लगे। तब समस्त जन सनुदाय ने एकत्र होकर यह विचार किया कि ऐसा व्यक्ति चुना जाय जो दोषी को दण्ड दे, वनवास के योग्य व्यक्ति को बनवास दे, अपराध करने

R This one is among gods the most vigorous, most strong, most valient, most perfect." Let us install him (to the Kingship over us)—Bhandarker.

वाले को अपराधा घोषित करे, और इस प्रकार एक अत्यंत सुन्दर, प्रतिष्ठावान तथा शिक्त शाला व्यक्ति द्वन लिया और उससे निवेदन किया "महात्मन, आइये और जो जिसके योग्य है उसे उसी प्रकार दण्डनीय, बनवासी तथा अपराधी ठहराइये और दण्डित कीजिए। हम अपनी उपज का निश्चित अनुपात आपको सेवा में उपस्थित करेंगे।" वह सहमत हो गया और ऐसा ही करने लगा। इसीलिए उसे "महा सम्मत" या "महाजना-सम्मत" का नाम दिया गया। राजा अथवा क्षत्रिय भी उसी को कहा जाने लगा। यह समभौता राजा एवं प्रजा में हुया। राज्य की स्थापना के पूर्व की प्राकृतिक अवस्था (State of nature) तथा समाज को स्थित (State of Society) का सुन्दर वर्णन इसमें मिनता है और पाश्चात्य विद्वाना के सिद्धान्त के समकक्ष सिद्ध होता है। हर प्रकार से तुलना योग्य बौद्ध धर्मानुकूल यह सिद्धान्त सामाजिक समभौते की पूर्णता लिए हुए हैं।

रे) सनु-संहिता— राजा की उत्पत्ति का अत्यन्त संक्षिप्त सिद्धान्त मनु संहिता में विणात है। तदनुसार जब राजा की अनुपिस्थिति में प्राणी मात्र सर्वत्र मारे मारे फिरने लगे तब परमात्मा (Lord) ने समस्त चराचर की रक्षा के हेनु सम्राट का सजन किया। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने इन्द्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, जल, चन्द्र तथा कुवेर आदि के स्थायो तत्व लिए और उनसे राजा की रचना की। इस विचार से राजा इन्द्र की मांति सर्वत्र धन जन का रक्षक व पालक, वायु की भांति सर्वत्र विचरण करने वाला तथा पशस्वी हो, यम की मांति कठोर दण्ड देने योग्य हो, सूर्य की मांति अन्धकार-विदारक तथा प्रकाश करने वाला, अग्नि की भांति सर्वनाश करने योग्य, तथा शुद्धिकारक, जल की मांति औदार्य (generosity) तथा कुवेर को भांति सम्पत्तिशाली होना चाहिए। इस प्रकार के राजा की कल्पना वास्तव में (Semi-divine being) अर्द्ध देवत्वमय प्रतीत होती है। सम्राट ईश्वर के द्वारा नियुक्त किया गया है। किसी प्रकार का समभौता नहीं है और न राजा का शासन ही किसी प्रकार के समभौते पर आधारित है।

परन्तु स्थानाभाव के कारण यहां हम केवल दो तीन प्रमुख विचारों का ही ग्रन्थयन करेंगे। सर्वश्रथम उस सिद्धान्त पर विचार करते हैं जो भीष्म द्वारा विणित है।

्य) प्रारंभ में जब मानव समाज में कोई राजा नहीं था तो ग्रागे जाकर मत्स्य न्याय की स्थिति पैदा हो गई। वलवान निर्वल को खाने लगे-सताने लगे। तब सब लोगों ने एकत्र होकर बुछ समय (Compacts) निर्धारित किए जिससे परस्पर विस्वास उत्पन्न हुगा ग्रीर कुछ समय तक इस प्रकार काम चलता रहा; परंतु ग्रागे चलकर यह व्यवस्था भी पर्याप्त सिद्ध नहीं हुई। तब सब ब्रह्मा के पास पहुँचे ग्रीर प्रार्थना को ''मगवन ! राजा के विना हमारा नाश हो रहा है, ग्रतः किसी को हमारा सम्राट बना दोजिए, हम सब उसका

^{3.} They selected most beautiful, gracious, powerful and addressed him "Come now, good being, do punish, revile or exile those who well deserve to be punished, reviled or exiled, we shall contribute to you a proportion of our rice." (Bhandarkar)

^{2.} The great elect or chosen by the whole people. (Bhandarker)

सम्मान करेंगे और वह हमारी रक्षा करेगा"। उनकी विनय सुनकर ब्रह्माजी ने मनु की ग्रीर संकेत किया। मनु ने कहा "मैं सहमत नहीं हूं क्योंकि मैं सब पाप कर्मों से भयभीत रहता हूं। वास्तव में किसी राजधानी का नियंत्रए। ग्रत्यन्त किठन होता है। ग्रीर वह भी मानवों में, जो स्वभाव से ही ग्रसत्य-परायण, व्यवहार में कठोर एवं संदेहपूर्ण होते हैं।" मानवों ने विश्वास दिलाते हुए निवेदन किया "मनु! डरो मत! मानव जो पाप करता है उसका भागी स्वयं मानव होता है। ग्रीर इस सब कार्य के लिए हम द्रव्य (Precious metal) का ५० वां भाग ग्रन्त का १० वां भाग एवं ग्राय का चतुर्थ भाग ग्रापके कीप संग्रह के लिए देंगे। इस कीप द्वारा हढ़ बनकर ग्राप हमारी उसी प्रकार रक्षा कीजिए जैसे देवताग्रों की रक्षा इन्द्र करते हैं। तब मनु सहमत होगए।। उन्होंने समस्त विश्व का भ्रमण करके, पाप कर्मों को नष्ट किया ग्रीर मानव मात्र को कर्त्त व्यनिष्ठ बनाया। इस प्रकार यह विश्वास किया जाता है कि जो व्यक्ति इस घरती पर हैं ग्रीर समृद्धि चाहते हैं उन्हें सर्व प्रथम एक राजा का चुनाव करना चाहिए कि वह सब की रक्षा करता रहे। इस सिद्धान्त में भी सामाजिक समभौते के लगभग सभी तत्व निहित हैं। प्राकृतिक स्थिति, संघर्ष का युग (State of war), सामाजिक समभौता ग्रादि तथा यह सिद्धान्त हाटस (Hobbes) के सिद्धान्त के ग्राधक समीप ज्ञात होता है।

(ब) दूसरा सिद्धान्त उस व्यक्ति से सम्बन्धित है जो पुरागों में प्रथम शासक या राजा माना जाता है। वह वैणु का पुत्र पृथु है। शांति-पर्व के अनुसार युधिष्ठिर ने भीष्म से ग्रनेक प्रका किए है उनमें एक प्रका यह भी है कि राजा की उपाधि (title) किस प्रकार श्रांस्तित्व में आई ? इसके उत्तर में राजा की उत्पत्ति का पूर्ण सिद्धान्त वर्णन किया गया है। भीष्म ने वतलाया है कि प्रारंभ में मानव धर्म एवं पवित्रता के साथ निवास करते थे। धीरे-धीरे उनमें काम, क्रोध, मद, लोभ का संचार हुन्ना (Self-indulgence, wrath, intoxication and greed) जिसके कारण विश्व में ग्रशांति होने लगी। देवताग्रों को चिन्ता हुई और वे ब्रह्मा के पास पहुंचे । उन्होंने सबके लिए एक वृहद् ग्रंथ की रचना की जिसमें १०० ग्रध्याय थे तथा जिसमें जीवन के चारों उद्देश-धर्म, ग्रर्थ, काम, मोक्ष, का सुन्दर वर्णन किया था। इसे द्रग्डनीति कहा । शिव तथा इन्द्र देवताग्रों ने ग्रीर वृहस्पति तया शुक्र ऋषियों ने उसके संक्षिप्त रूप (Summaries) लिखे । तत्पश्चात् देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे ग्रीर प्रार्थना की कि किसी भी सुयोग्य व्यक्ति को मर्त्यलोक का राजा (Highest Place, श्रेष्ठ्यम) चुन दीजिए। भगवान ने अपने अंश से एक पुरुप की उत्पत्ति की ग्रीर उसे राजा संज्ञा दी। (डॉ॰ ग्रल्टेकर के मतानुसार इसका नाम 'विराज' था) इस राजा ने राज्य को पूर्ण रूपेए। न्यास (Trust) की तरह माना ग्रीर ग्रच्छा शासन किया; परन्तु उसके बाद वेरा का समय आया जो घोर अत्याचारी शासक था। क्रुड ऋषिथों ने उसे नव्ट कर दिया और उसकी दाहिनी भूजा का मर्दन किया जिससे एक सुन्दर व्यक्ति

R. Oh Divine God? without a King we are going to destruction. Appoint some one as our King. All of us shall worship him and he shall protect us. (Mahabharat)

उत्पन्न हुआ——जिसका नाम पृथु रखा गया। ऋषियों एवं देवताग्रों ने उसे ग्राज्ञा दी कि तुम ग्रपनी वासनाग्रों को वश में रखकर भय तथा पक्षपात रहित होकर धर्मानुसार शासन करो। देवताग्रों ने उसे प्रतिज्ञा भी कराई—"मैं मन, वचन, कर्म से निरन्तर पृथ्वी की रक्षा करूं गा; मैं दण्डनीति में निर्देशित नियमों का पालन करूं गा; मैं कभी स्वेच्छाचारिता से कार्य नहीं करूं गा; मेरे शासन में द्विज दण्डित नहीं होंगे ग्रौर मैं विश्व की ग्रन्तर्जातीय मिश्रण से रक्षा करूं गा।'' तत्पश्चात् ऋषियों, ब्राह्मणों तथा स्वयं विष्णु भगवान ने पृथु का राजतिलक किया ग्रौर उसे राजा (ग्रयात् सबको प्रसन्न करने वाला) की संज्ञा दी। क्योंकि स्वयं भगवान विष्णु के द्वारा राजा की स्थापना की गई इसलिए समस्त विश्व ने राजा या सम्राट् की महत्ता स्वीकार को। इस प्रकार इस सिद्धान्त में देवी एवं सामाजिक-समभौते के सिद्धान्त बड़े सुन्दर ढंग से सिम्मलित हुए हैं।

४. मत्स्यन्याय का सिद्धान्त Doctaine of Matsya Nyaya (Logic of the fish)—हिन्दू विचारकों ने राज्य को समभने के लिए ग्रराज्य (non-state) से भिन्नता प्रकट करने का प्रयत्न किया है। इस विषय में उनकी पढ़ित ताकिक एवं ऐतिहा-सिक रही है (Logical as well as historical) ग्रयांत् यह सिद्ध किया है कि अराज्य में से किस प्रकार राज्य का विकास हुआ और इसका उत्तर उन्हें इसी 'मतस्य-न्याय' के सिद्धान्त में प्राप्त हो गया। हिन्दू विचारकों के अनुसार अराज्य की धारणा बड़ी विलक्षण प्रतीत होती है। परन्तु फिर भी यूरोपियन विद्वानों की प्राकृतिक ग्रवस्था (State of nature) से अधिक दूर नहीं है। हुकर (Hooker), हान्स (Hobbes) तथा स्पीनीजा (Spinoza) के मतानुसार प्राकृतिक अवस्था वहीं संघर्ष, अव्यवस्था तथा अनिश्चितता की स्थिति थी। प्राचीन भारत में भी श्रराज्य की यही धारएगा थी, जहां 'प्रत्येक का प्रत्येक से संघर्ष, पक्षियों और पशुस्रों की स्रराजकता स्रथवा गिद्ध सीर वानरों की व्यवस्था' स्थापित हो। चीन में भी प्राकृतिक अवस्था के मंबंध में इसी प्रकार की धारणाएं प्राप्त होती हैं। महाभारत में भी अराज्य का वर्णन इसी प्रकार तथा और अधिक सुन्दर ढंग से किया गया है। "यदि पृथ्वी पर कोई दण्डधारी शासक न रहे तो जल में मछलियों की भांति, बलवान निर्वल का भक्षण कर जायँगे' पिछले समय में जनता, इसी प्रकार सार्वभौम राहित्य तथा ग्रव्यवस्था के कारण सर्वनाश को प्राप्त हुई थी-यह कहा जाता है। मनुस्मृति में इसी विचार की पृष्टि की गई है कि यदि वापस अराजकता हो जाय तो पुनः शक्तिशाली निर्वलों का भक्षण करने लग जायेंगे, जैसे मछलियों में होता है। रामायण में भी यही विचार प्रकट किए गए हैं। मत्स्य पुरासा में अराज्य का वर्सान ग्राधिक रोचक ढंग से किया गया है कि

^{1.} The sages also proposed him an oath (प्रतिज्ञा) in following terms:
"I will constantly protect the earth in thought, word & deed; I will carry on the laws in accordance with Dand Niti; I will never act arbitrarily; on the laws in accordance with Dand Niti; I will never act arbitrarily; Twict born classes will not be punished; & world will be saved from inter-mixture of classes." (Bhandarkar)

^{2.} Political Institution and theories of Hindus—B. K. Sarkar.

वालक, वृद्ध, रुग्ण, साधु, पुजारी (पण्डित), महिला तथा विधवा सब का शोषण होगा, जब तक दण्ड उचित समय पर कार्यान्वित नहीं किया जायगा। अर्थशास्त्र में भी लिखा है (Powerful swallows the powerless) कि शक्तिशाली शक्तिहीन को निगल जाता है। कामन्दक के विचार में दण्ड की अनुपस्थित में सर्वनाश अथवा धातक मत्स्यन्याय कार्याविन्त होता है (The destruction or the ruinous logic of the fish operates)। इस प्रकार अराज्य (non-state) की मुख्य र विशेषताएं निम्नांकित हैं:—

(१) यह ग्रराजकता की स्थिति है।

- (२) ऐसी स्थिति है जिसमें ग्रत्याचार, डकैतियां ग्रीर स्वेच्छाचारिता चलती है।
- (३) जहां न्याय की भलक भी नहीं दृष्टिगत होती।
- (Y) जहां मानव मानव का भक्षक वन जाता है।
- (५) जहां सम्पत्ति तथा पारिवारिक जीवन का उपभोग श्रसम्भव होता है।
- (६) जहां केवल डाकू और लुटेरे प्रसन्न रहते हैं और उनकी प्रसन्नता भी क्षिणिक ही हो सकती है क्योंकि एक को दो और दो को चार हरा सकते हैं।
- (७) जहां स्वतंत्र व्यक्ति दास और स्त्रियां दासियां बनाई जाती हैं। इन कारणों से मत्स्यन्याय से संसार भयभीत रहा है। इसकी पुनरावृत्ति रोकने के लिए l) cotrine of Dand अर्थात् दण्डसिद्धान्त की पुष्टि की गई है।

दएडसिद्धान्त-(Doctrine of Dand) दण्ड का साधारए। प्रर्थ सज् (Punishment) शनित प्रयोग (Coercion) ग्रथना ग्रधिकार (Sanction) से लिया जाता है। परन्तु प्राचीन भारतीय विचारों में इसका ग्राधार गंभीर है। राज्य के हिन्दू सिद्धान्तों में दो ग्रभिन्न तिद्धान्त महत्वपूर्ण माने जाते हैं। प्रथम तो ममत्त्र का सिद्धान्त (Doctrine of mineness) अयंत्रा स्वत्त्र का सिद्धान्त (Doctrine of one's ownness) जिसमें अपनी सम्पत्ति, परिवार या ग्रन्य किसी ऐसी वस्तु का ध्यान रहता है जो विलग न की जा सके और दूसरा धर्म-सिद्धान्त (Doctrine of Dharma) जिसमें नियम, न्याय ग्रथवा कर्ताव्य को प्रधानता दी जाती है। परन्तु उपरोक्त दोनों सिद्धान्त पंगु रहते हैं जब तक दण्ड सिद्धान्त इनकी रक्षा में सहायक नहीं होता। इसी सिद्धान्त की स्राधारशिला पर ये दोनों, जीवन के परमावश्यक सिद्धान्त, स्थिर तथा सफल होते हैं। ग्रतः दण्ड सिद्धान्त का महत्व ग्रीर भी बढ़ जाता है। जुछ हिन्दू विचारकों का मत है कि राज्य इसलिए राज्य है कि वह बल-प्रयोग, बन्धन तथा अनिवार्यता को कार्यान्वित कर सकता है (Coercion. restrain & compulsion)। वास्तव में राज्यों के सम्बन्धों की बुनियाद दण्ड पर ही ग्राधारित है। यदि दण्ड नहीं तो राज्य नहीं रह सकता (No Danda, no State) दण्डिवहीन राज्य की कल्पना एक ग्रसम्भव-कल्पना है। जहां दण्ड का ग्रस्तित्व न हो, वहां मत्स्यन्याय, प्राकृतिक अवस्था अथवा धर्मविहीन, सम्पत्तिविहोन स्थिति माननी चाहिए; क्योंकि ये सब बात राज्य में ही विद्यमान हो सकती हैं ग्रीर राज्य वहीं हो सकता है जहां दण्ड है। ग्रतः हम इस निष्कर्प पर पहुँचते है कि दण्ड नहीं तो राज्य नहीं ग्रीर राज्य नहीं ता न धर्म ग्रीर न सम्पत्ति ही रह सकतों है।

निष्कर्ष-अपर विश्वात सिद्धान्तों में राजा की उत्पत्ति के संबंध में देवी सिद्धान्त पर्याप्त महत्व का है। यहां तक कि कीटिल्य ने भी अनेक देवताओं के तत्वों से कर्ताच्य पर प्रकाश डालकर कुछ देवत्व स्वीकार किया है। मनु ने ती स्पष्ट देवताश्रों के कर्तव्य-ज्ञान की म्रोर इंगित किया है। शांतिपर्व में भीष्म ने यह सिद्ध किया है कि राजा को ईश्वर क्यों मानते हैं। प्रो॰ प्रमथनाथ बनर्जी के मतानुसार केवल सचाई से कार्य करने वाला शासक ही ईश्वर का स्वरूप माना जाता था। प्रो. डी. आर. भण्डारकर के विवार से सम्राट 'नर-देवता' होता है परन्तु अपने शुद्ध कर्तव्यों से गिर जाने पर इसे नर देवता नहीं कह सकते। इस प्रकार देवी सिद्धान्त की मान्यता सर्वव्यापी सी रही है।

सामाजिक समभौते के सिद्धान्त पर भी यदि तुलनात्मक दृष्टि से विचार कर लिया जाय तो विषय स्पष्ट ही होगा। साधारण हिष्ट से भारतीय सिद्धान्तानुसार समभौते द्वारा भी सम्राट जनता का सेवक ही रहता है जबकि पाश्चात्य विचारकों में समभौता (irrevocable) प्रविच्छेद्य माना गया है। भ्राजकल तो सामाजिक समभौते का सिद्धान्त (Bad history and worse logic) दूषित इतिहास व हीन-तर्क माना जाता है । किन्तु फिर भी प्राचीन भारतीय विचारों वाले सम्भौता-सिद्धान्त की तुलना यूरोपियन विचार के सम-भौता सिद्धान्त से कर लेना स्वाभाविक सा लगता है।

पाइचात्य विद्वान हाब्स के विचार से तुलनाः-हान्स (Hobbes)

१. प्राकृतिक अवस्था में प्रत्येक का प्रत्येक से संघर्ष था।

२. इस स्थिति से ऊव कर लोग ग्रपनी समस्त शक्तियां शासक को समर्पित करने के लिए प्रस्तुत हो गए और

३. यह समभौता केवल जनता में ही हुम्रा, शासक पार्टी नहीं या। शासक को अमर्यादित इसलिए म्रधिकार मिले।

४. शासक पर कोई उत्तरदायित्व नहीं था, न जनता की विद्रोह का अधिकार था। पूर्ण सार्वभीम शक्ति शासक के हाथ थी।

हिन्दू विचार (Hindus) १. प्राकृतिक अवस्था मत्स्य न्याय युक्त

थी जिसमें ग्रस्तित्व को रक्षा कठिन थी। २. समभौता तो हुग्रा किन्तु सिर्फ जनता

पर ही भार नहीं रहा, शासक ने भी उत्तरदायित्व को संभाला।

३. शासक स्पष्ट रूप से पार्टी था ग्रीर उसे केवल सीमित अधिकार ही प्राप्त हुए।

४. शासक जनता का सेवक बना ग्रीर शास्त्र, जो ब्रह्मदेव ने रचा था, उसके अनुसार शासन चलाना कर्ता व्य था। सार्वभीम सत्ता सदैव जनता की बनी रही।

लॉक के विचारों से तुलना

१. प्राकृतिक ग्रवस्था दोनों विचारकों के ग्रनुसार समान सी है। जब जनता का जीवन सुखमय था और समाज का अस्तित्व नहीं था। प्राचीन भारतीय विचार के अनुसार यह युग पौराणिक काल का स्वर्ण-युग कहा जा सकता है।

- २. हिन्दू विचारकों में यह मान्यता है कि वाद में वातावरण दूपित हुग्रा ग्रीर समाज पतित हुग्रा। तब सामाजिक समभौता हुग्रा। लॉक का मत इसी विचार का रूपान्तर है।
- ३. समभौते के फलस्वरूप लॉक-शासक को कुछ शर्तों पर सीमित सत्ता देना स्वीकार करता है। हिन्दू विचारक भी शास्त्रीय नियमों द्वारा शासक के ग्रिधकार मर्यादित होना स्वीकार करते हैं।

पाश्चात्य विद्वानों के विचार, प्राचीन भारतीय विद्वानों के विचारों की ग्रपेक्षा वास्तविकता ग्रीर यथार्थता की ग्रीर कम, किन्तु भौतिकवाद की ग्रीर ग्रधिक ग्राकपित प्रतीत होते हैं। डॉ॰ ग्रल्टेकर की राय में पाश्चात्य विद्वानों का दृष्टिकोण लौकिक था, जविक हिन्दू विचारकों का ग्रद्ध-धार्मिक तथा ग्रर्ध-सामाजिक था। — भारत में सर्वध्येष्ठ स्थिति, यह थी कि जनता ग्राज्ञापालन एवं कर-ग्रुक्क ग्रादि ग्रपनी रक्षा एवं सेवा के फलस्वरूप ग्रपित करती थी तथा कर्त्त व्य से च्युत होने की ग्रवस्था में ग्रत्याचारी शासक को ग्रपदस्थ करने ग्रयवा जीवनमुक्त करने के ग्रधिकारों से भी युक्त थो। पाश्चात्य देशों में यह भावना ग्राप्तिक युग में स्वीकार की जाने लगी है। प्रइस प्रकार भारतीय समभौते का सिद्धान्त ग्रधिकतर ग्रंशों में पूर्णता एवं यथार्थता से ग्रुक्त है।

⁺ Dr. Altekar— Westerns looked at the problem from a purely secular point of view, while Ancient Indian writers looked at the problem from a semi-religious & somi-sociological point of view. (State Govt. Anc. India) × उपश्र⁴नत Dr. Altekar.

चतुर्थ ग्रध्याय

राज्यों के प्रकार

(Types of States)

प्रस्तावता—प्राचीन भारतीय राजनैतिक विचार में राज्यों के कई प्रकार दृष्टिगत होते हैं, किन्तु उनका प्रसंग जिस दक्ष से प्राप्य है वह इस बात पर प्रकाश डालता है कि उस समय राज्यों का प्रकार महत्वपूर्ण विषय नहीं था। साधारणतया राजतंत्र (Monarchy) हो राज्य का स्वरूप होता था और इसी रूप में ग्रनेक प्रकार समयानुकूल प्रचलित हुए। डॉ० ग्रल्टेकर के मतानुसार प्राचीन विद्वानों ने इसीलिए इस विषय का विवेचन नहीं किया है, नयोंकि राजतंत्र ही राज्य का मुख्य रूप था। परन्तु ग्रन्य प्रकार के राज्य भी विद्यमान सवस्य थे और उनका महत्त्व ग्रपना ग्रलग था।

सर्व प्रथम राज्य का लोकप्रिय रूप राजतन्त्र ही था और वैदिक काल से लेकर अन्त समय तक इसी रूप के विभिन्न प्रकार समाज के सामने आते गए। राजतन्त्र की शक्ति व प्रतिष्ठा के अनुसार ही राजाओं के पद (Designations) भी निर्धारित किए जाते थे। जैसे—राजा (king), महाराजा (A great king), समरत (an emperor) आदि। इन्हीं में से कुछ स्वराज तथा भोज भी कहलाते थे परन्तु इनका क्या अर्थ था—यह आज भी स्पष्ट नहीं किया जा सका है।

उस समय में विभिन्न उपाधियों एवं सम्मानार्थक विशेषणों की सहायता से शासकों में भेद किया जाता था । उदाहरणार्थ, परमभट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर ग्रादि से उन्हें सम्वोधित किया जाता था, जो सार्वभौम (Supreme) शासक होते थे तथा समाधिगत, पंचमहाशब्द, महासामन्ताधिपति ग्रादि उन्हें कहा जाता था जो सामन्तिक (Feudatory) शासक होते थे। ये उपाधियाँ भी समय ग्रीर स्थिति के ग्रनुसार परिवर्तनशील रहती थीं। शुक्ल यजुर्वेद में ऐसे पांच मंत्र हैं, जिनमें एक ही देवता का पांच प्रकार से सम्बोधन किया गया है। तदनुसार इस प्रकार वर्गीकरण किया जा सकता है:—

- १. राजन-पूर्व दिशा में -वसुग्रों के साथ
- २. विरत दक्षिण दिशा में छ्द्रों के साथ
- ३. समरत-पश्चिम दिशा में -- ग्रादित्यों के साथ
- ४. स्वरत-उत्तर दिशा में-मारुतों के साथ
- थ. ऋधिपति ऊपर की दिशा में विश्वेदेवता स्रो के साथ र

^{1.} State & Govt. in Ancient India-Dr-Altekar.

^{2.} Sukla yajurveda. (शुक्ल यजुर्वेद)

इसी प्रकार का वर्गीकरण कुछ परिवर्तन के साथ इन्द्र के ग्रिभिषेक के ग्रवसर पर 'ग्रात्रेय बाह्मण्' में भी वर्णन किया गया है। इससे साधारणतया यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि समराज, भोज, स्वराज, विराज व राजन एक ही प्रकार व सम्मान वाले शासकों की विभिन्न उपाधियाँ थों। ये ग्रनेक प्रकार के राजाग्रों के नाम नहीं थे। 'ग्रात्रेय बाह्मण्' में एक ग्रीर स्थान पर विजेताग्रों की चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है जिनमें पहले दो की ग्रपेक्षा तृतीय-ग्रधिष्ठाता (Overlord) तथा चतुर्थ समन्तपर्ययो को अधिक महत्व दिया गया है। (Universal Ruler ग्रयात् सार्वभौम शासक) इस प्रकार वैदिक कालीन राजतन्त्र (Monarchy) में तीन मुख्य वर्गीकरण स्वीकार किए गए थे, जो निम्नांकित हैं:—

- (१) सामन्तिक प्रधान (Feudatory chieftain)
- (२) अधिष्ठाता (The Overlord or अधीश्वर)
- (३) सार्वभौम शासक (The Universal Monarch) ग्रमरकोष में यह वर्गीकरण दूसरे रूप में दिया गया है-तदनुसार—
 - (१) चक्रवर्ती (Fendatory chief) जो राजसूय यज्ञ करलेता हो।
 - (२) ऋधीश्वर (Suzerain) जो अनेक राजाओं का स्वामी हो।
- (३) मंडलेश्वर (Universal Monarch) जो एक मण्डल का स्वामी हो। शुक्रनीतिसार में राज्यों कावर्गीकरण उनकी आय के अनुसार किया गया है, जो इस प्रकार है:—
 - (१) सामन्त-जिसकी म्राय १ लाख से ३ लाख तक रजत मुद्रा प्रतिवर्ष हो। (Silver Karshas)
 - (२) माएडलिक ग्राय ४ लाख से १० लाख प्रतिवर्ष तक
 - (३) राजन-ग्राय ११ लाख से २० लाख प्रति वर्ष तक
 - (४) महाराज-ग्राय २१ लाख से ५० लाख वार्षिक तक
 - (५) स्वराज-गाय ५१ लाख से १ करोड़ वार्षिक तक
 - (६) तमराज-प्राय १ करोड़ से १० करोड़ वार्षिक तक
 - (७) विराज-ग्राय ११ करोड़ से ५० करोड़ वार्षिक तक
 - (८) सार्वभौम ग्राय ५१ करोड़ से ग्रधिक वार्षिक तक

परंतु ये भी राजतन्त्र (Monarchy) के ही अनेक प्रकार तथा विभिन्न श्रीणियां हैं।

जैन ग्रन्थों में निपेधात्मक रूप से ये ग्रादेश मिलते हैं कि जैन साधुग्रों को उन राज्यों में प्रवेश नहीं करना चाहिए, जहां द्विराज (Duarchy) हो ग्रर्थात् जहां दो राजा राज्य करते हों। इससे यह तो स्पष्ट ही है कि दिराज होते थे। इनका रूप क्या था, इस पर विद्वान् एक मत नहीं हैं। संभवत: ये दिराज तीन प्रकार के होते थे—प्रथम, जहां पिता य पुत्र

मिलकर शासन चलाते हों। द्वितीय, जहां दो बन्धु सहयोग के ग्राधार पर राज्य संचालित करते हों ग्रीर तृतीय जहां दो विभिन्न बंश या कुल के राजा मिलकर शासन-प्रबन्ध करते हों। कुछ भी हो इस प्रकार का शासन ग्रादर्श तो हो ही नहीं सकता था—ग्रीर न शांति एवं सुरक्षा के लिए ही हितकर माना जाता था। कौटिल्य ने भी इसके प्रसंग में यही लिखा है कि द्विराज, पारस्परिक विद्वेष, पक्षपात तथा प्रतियोगिता से स्वयं ही नष्ट हो जाता है। प्राचीन कहावतें — 'एक म्यान में दो तलवार नहीं रहती" तथा "एक जंगल में दो सिंह नहीं रहते", इसी स्थित को स्पष्ट करती हैं। द्विराज के सम्बन्ध में डा. ग्रल्टेकर ने लिखा है कि यदि दोनों शासक मिलकर शासन चलावें तब तो "द्विराज" है, ग्रन्थथा यह "विरुद्ध राज्य" है। प्रती मुख्य कारण हा सकता है जिससे जैन साधुगों का ऐसे राज्यों में प्रवेश निषद्ध माना गया है।

अर्थशास्त्र में राजतन्त्र का एक तीसरा प्रकार भी विश्वत है। जिसे विद्वान ''कुलराज'' की संज्ञा देते हैं। मौर्थ-काल में मगध का राज्य नन्द तथा उसके पुत्रों द्वारा शासित था और वे सिम्मिलित रूप में हो शासन संचालित करते थे। नन्द के पुत्रों की संख्या ग्राठ थी ग्रीर वे सब शासन में भाग लेते थे। इस प्रकार पूरा कुल शासन चलाता था—इसे ''कुलराज'' कहते थे। यह एक प्रकार से संघ राज्य की तरह माना जाता था। ग्रर्थशास्त्र की पंक्ति निम्न प्रकार से यह भाव व्यक्त करती है: —"राज्यम कुला संधीहि दुर्जयह ं' इस प्रकार राजतन्त्र के तीन मुख्य प्रकार थे—एकराज, द्विराज एवं कुलराज।

गरा-राज्य:—दूसरा राज्य का मुख्य रूप 'गराराज्य' था। पाणिती के मतानुसार कई राज्यों के नाम क्षत्रिय जाति के नाम के अनुसार थे। तथा विभिन्न उद्देशों से बनाए हुए संघ भी विद्यमान थे। साधारणतः निम्न प्रकार के संघ प्रचलित थे:—

- (१) धार्मिक संघ (Religious Sangha) जैसे बौद्ध संघ ग्रादि ।
 - (२) व्यापारिक संघ (Commercial Sangha) जैसे श्रेणी मादि।
 - (३) आयुध जीवी संघ (पाणिनी) शस्त्रों के सहारे जीवन व्यतीत करने वाले व्यवितयों का संगठन
 - (४) शस्त्रीवजीवी संघ (कौटिल्य) उपयुक्त ।

परन्तु उनत संघों में कोई राजनैतिक विशेषताएं नहीं थीं घीरे घीरे जब जीवन के अन्य क्षेत्रों में संघ प्रणाली सफल हुई तब राजनैतिक क्षेत्र में भी इसे अपनाया गया और यह बहुत लोकप्रिय हुई। कीटिल्य ने अनेक प्रकार के राजनैतिक संघों का उल्लेख किया है जैसे लिच्छिवि, वृज्जिक, मल्ल, मद्रक, कुरु, पांचाल आदि। इससे यह स्पष्ट होता है कि नृपतंत्र या राजतंत्र (Monarchy) के समर्थक कीटिल्य द्वारा गण्रराज्यों की आलोचना न करना इन संघों की लोकप्रियता का प्रमाण है। कुछ विद्वान तो यह मानते हैं कि भारतीय

न कोटिल्य "Such a state perishes through mutual hatred, partiality and rivalry." (Translation by Shama Shastry)

[×] If both rule in harmony, it is (two king state) विराज, if pulling in opposite direction (self fighting state) विरुद्ध-राज्य। (Dr. Altekar)

राजनीति का प्रारम्भ ही प्रजातन्त्र राज्यों की स्थापना के साथ हुआ था। प्रारंभ कैसे हुआ था इस प्रश्न को छोड़ दें तो भी प्रजातन्त्र की विद्यमानता तो स्पष्ट स्वीकार की जाती है। परन्तु प्रजातन्त्र जैसा साधारण लोग सोचते हैं—राजतन्त्र (Monarchy) अथवा कुलीन-तंत्र (Aristocracy) आदि पढ़ितयों के विष्ण्व नहीं था। राजा सदैव प्रजा का हित्वितक माना जाता था। परम्पराएं बलवान थीं, राज्य न्यास (Trust) की भांति रहता था, राजा का निर्वाचन, उसे पदस्थ. अपदस्थ करना, निष्कासन, वनवास, पुनर्स्थापन आदि लोक विख्यात प्राचीन परम्पराएं हैं जिनका प्रयोग जनता मुक्त रूप से करती थी। इसी के अनुसार यह मान्यता महत्व पाई कि भारतीय राजनीति सदैव प्रजातन्त्रात्मक बनी रही। विचार करने से एक ही साथ एक से अधिक प्रकार के राज्यों का अस्तित्व सरल प्रतीत नहीं होता किन्तु इंगलेण्ड का उदाहरण इसकी सम्भावना सिद्ध करता है देश की प्रमुख सत्ता चाहे वंशानुगत सम्राट के हाथ हो अथवा सम्पत्तिशाली या कुलीन जनों के हाथ में, परन्तु यदि उस राजा को जनता को समानता, स्वतंत्रता, न्याय आदि आवश्यक तत्व उपलब्ध है, स्वयं द्वारा निर्मत विधान है और विधान के अनुसार शासन चलता है तो उसे प्रजातंत्र ही कहा जायगा। ऐसी अवस्था में ही प्रजातंत्र अन्य प्रकार की राज्य व्यवस्थाओं में भी हिन्दगत हो सकता है।

उपरोक्त वर्णन से यह निष्कर्ष निकलता है कि प्राचीन भारत में राज्यों का मुख्य प्रचलित प्रकार राजतंत्र या नृपतंत्र (Monarchy) था और इसी के अनेक भेद प्रचलित थे। द्विराज या कुलराज भी नृपतंत्र के ही भेद माने गए हैं। संघों के अनेक प्रकार थे यह ऐतिहासिक आधार पर प्रमाणित माना जा चुका है। विभिन्न युगों में इनका क्या स्वरूप रहा और कैसी उन्नत अवस्था में संघ रहे—इसका विचार अलग अध्याय में पूर्णरूप से किया जाना आवश्यक है। प्रजातंत्र राज्य मुख्य रूप से एक शासन पद्धति थी, जो राज्य के स्वरूप पर अधिक आधारित न होकर शासन प्रगाली से अधिक सम्वंधित थी। वर्त्त मान समय में इंगलैंग्ड की शासन प्रगाली इस विषय में सर्वोत्कृष्ट उदाहरण उपस्थित करती है।

प्राचीन भारतीय राजनीति की प्रजातन्त्रात्मक प्रणालियों के प्रघ्ययन से यह ता सिद्ध है कि भारत में दण्डनीति का उद्देश्य लोकहित था ग्रीर मानव का सर्वा गीए विकास चरम लक्ष्य था। इसकी प्राप्ति एवं यनुकूल परिस्थितियों का स्रजन राज्य का उद्देश्य होता था। फिर भी यह पक्ष रह ही जाता है कि प्रजातन्त्रात्मक भावना की उत्पत्ति का इतिहास रोम व यूनान के नगर राज्यों के साथ प्रारम्भ हुग्रा माने ग्रथवा उससे भी पूर्व इस भावना का जन्म भारत में होना स्वीकार करें। श्री यदुनन्दन कपूर ने यह स्पष्ट प्रकट किया है कि यूनान के नार्गारक जीवन के दर्शन के साथ प्रजातंत्र की भावना का जन्म हुग्रा। सुकरात, प्लेटो तथा ग्रस्तू ने इस भावना को प्रस्फुटित भी किया; परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं कि यूनान में उत्पन्न यह विचारधारा विश्व की प्रजातंत्र सम्वन्धी प्राचीनतम विचारधारा हो। भारत में प्रजातंत्र की भावनाए सम्यता के प्रारम्भ से हो उपस्थित मानी जा सकती हैं . यद्यपि निश्चित प्रमाण ग्रभी तक पूर्ण रूपेण उपलब्ध नहीं हैं तथापि वेदों के तत्संवर्धा प्रसंग इस भावना की प्राचीनता सिद्ध करने में समर्थ हैं। साधारणतः मेगास्थनीज के वर्णन

[🕂] धर्म निरपेत्त प्राचीन भारत की प्रजातन्त्रात्मक परम्पराएं-यदु० कपूर एष्ठ ४४

के ग्राधार पर यह विचार प्रचलित है कि नृतंत्र के उपरान्त भारत में प्रजातंत्र स्थापित हुए×। परंतु इसका ग्राधार एक भारतीय दन्त कथा ही है। महाभारत में नृपतंत्र के पूर्व ग्रराजक राज्य ग्रथवा मत्स्य न्याय की स्थिति थी यह स्वीकार किया गया है। परन्तु यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाय तो भारत का सर्व प्रथम संगठन प्रजातन्त्रात्मक भावनाग्रों से ग्रारम्भ हुग्रा प्रतीत होता है। उस समय राज्य ग्रवश्य छोटे होंगे परन्तु सिद्धान्त वही स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के स्थापित किए गए। क्रिमक विकास के फलस्वरूप जब व्यक्ति स्वार्थ-प्रिय ग्रीर संकुचित वृत्ति का बनता गया तब समाज में दोष उत्पन्न हुए ग्रीर परिणामतः दूसरे प्रकार के संगठन ग्रपनाए जाने लगे। इस प्रकार यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि विश्व का प्राचीनतम प्रजातन्त्र भारत में ही स्थापित हुग्रा ग्रीर उसका समय उत्तर वैदिक काल (लगभग ३००० वर्ष ई पू०) ग्रनुमान किया जा सकता है।

वस्तुतः वर्ता मान समय में साम्यवादी, सर्वोदयवादी, गांधीवादी म्रादि जिस वर्गहीन समाज की स्थापना का लक्ष्य सामने रखकर श्रादर्श जन-राज्य का चित्र म्र कित किया जाता है वही प्राचीन मारत का वर्गहोन-राज्य प्रजातन्त्र का सच्चा म्रादर्श रहा था। ऐतेरेय ब्राह्मण् इस विचार की पुष्टि बड़ी सफलता से करता है। उसमें विणित देवताम्रों व दानवों के संघर्ष में सदैव देवता ही परास्त होते रहे थे। परन्तु एकत्र होकर विचार-विमर्श करने पर जब वे इस निर्णय पर पहुँ चे कि उनकी ग्रराजक-प्रणाली ही पराजय का मुख्य कारण है तब उन्होंने भी ग्रपना शासक चुना ग्रौर इस प्रकार प्रथम प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था राजतंत्र में परिवर्तित हुई। इनका पतन विशेषकर पारस्परिक संघर्ष एवं युद्धों के कारण हुमा। ग्रतः ग्राज की नवीनतम विचारधाराएं भारत की प्राचीनतम प्रणालियों की पंक्ति में ग्राती हैं यह हमारे देश के गौरव की वृद्धि में विशेष सहायक तत्त्व स्वीकार किया जाना चाहिए।

राज्यों के प्रकार के संबंध में विचार करते समय हमें युक्त का यह कथन स्मरण रखना चाहिए कि राजसत्ता राजा के शरीर में नहीं, उसके हस्ताक्षरित ग्रीर मुद्रांकित शासन में निवास करती है। ज्ञे श्र्यांत् राजा का स्वयं व्यक्ति के रूप में शासन क्षेत्र में वह महत्व नहीं है जो साधारणतया समभा जाता है। वह वास्तव में वैधानिक शासन है इसलिए राज-सत्ता का निवास उस शासन में है जो राजा के हस्ताक्षर व मुद्रा द्वारा संचालित किया गया हो। महाभारत में भी इसी प्रकार का प्रसंग है कि राजा कभी स्वतंत्र नहीं है, सदैव मंत्रियों के वशीभूत है। गर्याद मंत्रिवर्ग प्रभावहीन हो तो वे भो केवल दर्शनी मूर्ति ही रह जाते हैं। शुक्र नीतिसार में ऐसे मंत्रियों की तुलना महिलाग्रों के ग्रामूपणों से की गई है। क्षे ग्रतः राजतंत्र या नृपतंत्र ग्राज के ग्रयं में केवल Monarchy ग्रयवा निरंकुश राजतंत्र नहीं था। नृपतंत्र का ग्रयं साधारणतः (Limited ग्रयवा Constitutional Monarchy) मर्यादित या वैधानिक राजतंत्र ही लिया जाता था। उस समय की राजनैतिक चेतना तथा

[×] Ancient India as described by Megasthnese-Mackrindh Page 38-40.

⁺ ऐतिरेय ब्रह्मण १/१४ - नृप संचिन्हितं लेख्यं नृपस्तन्न नृपो नृप । शुक्रनीतिसार २।२६२

प्रजातंत्रात्मक पद्धतियों की विद्यमानता ही राजनैतिक क्षेत्र में इस प्रकार की संस्थायों की स्थापना के लिए उत्तरदायी तत्व माने गए हैं। इन परिस्थितियों में हम यह घारगा स्वीकार करना उचित समभते हैं कि प्राचीनकाल में शासन पद्धतियां समयानुकूल विकसित, परिवर्तित भीर परिविद्धत होती रहती थीं। प्राचीन साहित्य में ऐसे उदाहरएों का प्राचुर्य है जहां विना किसी भीषए। क्रांति अथवा ऊहापोह के शासन-पद्धतियां संशोधित हो गईं। आज के यूग में इंगलैण्ड की शासन पद्धति का स्वरूप अथवा क्रीमक विकास विश्व में आश्चर्य की वस्तु बनी हुई है, परन्तु प्राचीन भारतीय-ज्ञान ही उनका यह पथ प्रदर्शन कर रहा है यह ग्राज भी ग्रनेक भारतीयों के लिए एक नवीन बात होगी। इस संबंध में सर्वप्रथम उदाहरण ऐतेरेय बाह्मण से ही लिया जा सकता है जहां कुरु व पांचाल को नृपतंत्र या राजतंत्र विश्वत किया गया है। 🗙 जबिक कौटिल्य ने ये ही कुरु व पांचाल प्रजातंत्र के रूप में लिखे हैं। + इसी प्रकार 'विदेह' का उदाहरण भी दिया जाता है जो प्रमाणों के झाधार पर पूरी तरह सिद्ध होता है । इसके विपरीत प्रजातंत्र भी स्थित के अनुसार राजतंत्र या नृपतंत्र में परिवर्तित हो जाते थे। जब कभी एक शासन पद्धति ग्रसफल होने लगी-दूसरी पद्धति को स्थापित करना पड़ता था। फिर भी प्रजातंत्र से नुपतंत्र में परिवर्तन सरल था और इसके विपरीत कठिन भी । परंतु ये हेर फेर होते अवश्य थे । इससे यह भी सिद्ध होता है कि जनता राज-नैतिक क्षेत्र में जागरुक थी और इसीलिये ये परिवर्तन संभव थे। ऐसी दृढ़ प्रजातंत्रात्मक भित्ति पर प्राचीन भारत की शासन पद्धति संगठित थी जो सिदयों तक मिडिंग रही । म्राज उसके अवशेष खोजः करने पर प्राप्त होते हैं परंतु प्रत्यक्ष रूप से उसकी आत्मा का प्रकाश हमें भारतीय सहिष्णुता, समानता एवं उदारता में ब्राज भी दिष्टगत होता है। ब्रतः प्राचीन भारत की शासन पद्धतियों के प्रकार किसी सीमा में नहीं वांधे जा सकते।

प्राचीन प्रमाणों के ग्राधार पर ऊपर विणित राज्यों के प्रकार से कुछ साम्य तथा कुछ वैभिनन्य रखते हुए ग्रौर भी वर्णन मिलते हैं जिनका संक्षेप में उल्लेख करना ग्रावश्यक प्रतीत होता है । अछरंग सूत्र में निम्न प्रकार के विधान विशित किए गए हैं:-

- (१) ग्ररायिश
- (२) जुवरायिए
- (३) दोरज्जिएा
- (४) वैरज्जिए
- (५) विरुद्धरज्जिएा
- (६) गणरायिण
- (१) श्ररायणि का धर्थ साधारणतः ग्रराजकता से लिया जाता है। जहां व्यक्ति विशेष का शासन न होकर, समस्त जनता का राज्य हो उसे अरायिंग कहा जाता होगा। जहां "Rule of Law" अथवा "विधि का शासन" हो, किसी वर्ग विशेष अथवा

[×] ऐतेरेय बाह्यण =/१४ "कुरुपांचालानां राजानः......." + श्रथंशास्त्र-कोटिल्य-

[÷] श्रारायणि वा गणरायणि वा जुबरायणि वा दोरङ्जणि वा वेरङ्जणि वा विरुद्धरङ्जणि वा / श्रवरंग सूत्र २/३/१/१०१

व्यक्ति विशेष का प्राधान्य नहीं हो, उसे ग्ररायिए कहा जाता था। जैसे प्रत्येक व्यक्ति का कार्य किसी व्यक्ति का कार्य नहीं होता× उसी प्रकार ऐसे राज्य में यह दोप रहा होगा कि उत्तरदायित्व का निश्चयोकरण नहीं किया जा सकता होगा ग्रीर यही इसकी ग्रसफलता का कारण बनता होगा।

- (२) जुलरायिण का संबंध युवराज से लिया जा सकता है। साधारणतया युवराज का स्थान मंत्रिमण्डल में तो होता ही था। यदि अचानक पिता के देहावसान के कारण वयस्क होने से पूर्व ही राज्य का भार संभालना ग्रावश्यक हो जाय तो ऐसी स्थित में Court of Wards अथवा (Regency) संरक्षक मण्डल आदि के द्वारा युवराज के नाम पर शासन चलाया जाता था-इस ग्राधार पर इसे युवराज का शासन या जुवरायिए। कहा जाता था। वयस्क होने पर नियमानुसार शासन व्यवस्था युवराज को सींप दी जाती थी ग्रीर व्यवस्था का नाम परिवर्तित हो जाता था। ऐमे उदाहरण ग्रनेक हैं। खारवेल के शिलालेख में यह अवस्था २४ वर्ष म कित है+। जैन साहित्य में यह प्रसंग आया है कि विक्रम को २५ वें वर्ष में राज्यासीन किया गया था । अशोक का राज्याभिषेक पिता की मृत्य के चार वर्ष बाद हुग्रा। इन चार वर्षों में वहां जुवरायिए शासन पढ़ित रही थी।
- (३) दोर्डजिशा—इसका अर्थ दोराज लिया जाता है। प्राचीनकाल में यह पद्धति प्रचलित थी। रोम और यूनान में भी दो शासक (Duarchy) अथवा Two Consuls की प्रणाली बहुत समय तक रही है। कौटिल्य ने भी विराज, द्विराज का वर्णन किया है 🕂। थीर जैन सूत्रों में तो जैन सांधुयों को द्विराज में न जाने के लिए स्पष्ट रूप से ही सावधान किया गया है। डा० ग्रंटिकर ने द्विराज के सम्बन्ध में लिखा है कि जैसे "एक म्यान में दो तलवार" संभव नहीं है उसी प्रकार द्विराज ब्रावर्श राज्य नहीं हो सकता। ‡ इसी प्रकार दोरज्जिए का अर्थ दो शासकों के शासन हैं, जो अधिक समय के लिए आदर्श व्यवस्था न बनकर—स्थिति विशेष के लिए प्रचलित प्रया रही है जैसे कुछ विद्वान इसे दो भाई, पिता-पुत्र भ्रयवा दो वंशों का राज्य मानते हैं उसी प्रकार कुछ लेखकों ने इस व्यवस्था में शक्ति-विभा-जन के सिद्धान्त को भी देखने का प्रयत्न किया है। परंतु यह सही नहीं प्रतीत होता।
- (৪) बैरज्जिशा—यह उपयुक्त वैराज्य का ही पर्यायी है। जिसका अर्थ नि:स्वार्थ विराज से भी लिया जा सकता है ग्रर्थात् जहां समस्त जनता का शासन हो। कीटिल्य ने चैराज्य का वर्णन किया है भ्रीर वह इसे अपूर्ण व्यवस्था मानता है। संभव है कि कौटिल्य ने राजतंत्र का समर्थक होने के कारण इस व्यवस्था को सफल न समभा हो। ग्रधिक ज्ञान इस पद्धति का प्राप्य नहीं है।
 - (४) विरुद्धरज्जिणि-ऐसी शासन व्यवस्था जी विरुद्ध लीगों के हाथ में हो। इसते

[×] Everybody's work is nobody's work. + I Hindu Polity-Page 230.—II योवराजन् पसासितम् - यदु० कपूर पृष्ठ १३६.

^{*} Hindu Polity-Page 230.

[÷] अर्थशास्त्र—कौटिल्य

¹ State & Govt. in Ancient India-Dr Altekar.

प्रजातंत्र की ग्रोर लक्ष्य होता है। जहां सभी वर्ग, विश्वास, स्वार्थ तथा प्रकार के लोग व्यवस्था करते हों उसे विरुद्धरज्जिए कहा जाता है जैसे ग्राजकल के शुद्ध प्रजातंत्र। चुनावों हारा सब धर्म, दल, विश्वास, स्वार्थ मादि के लोग निर्वाचित हो जाते हैं भौर निश्चित काल तक ग्रपने स्थान पर वने रहते हैं। परस्पर विरोध रहता है, लोग एक दूसरे की ग्रालोचना करते हैं ग्रोर व्यवस्था के प्रति जागरुक रहते हैं। ग्रतः विरुद्धरज्जिए प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था वहां थी जहां जनता का शासन था।

(६) गण्रायणि – गण्राज्य की व्यवस्था से तात्पर्य है। गणों के संबंध में अगले अध्याय में विशेष रूप से वर्णन किया जायगा यहां इतना समक्त लेना पर्याप्त है कि गण्रायणि का ग्रर्थ है राज्य की गण के रूप में व्यवस्था। ये प्राचीनकाल में बहुत संख्या में विद्यमान थे।

इस प्रकार राज्यों के प्रकार प्राचीनकाल में समय समय पर बदलते रहे। इससे सिद्ध होता है कि भारत राजनैतिक क्षेत्र में सदैव प्रगतिशील रहा है। समय और ग्रावश्यकतानुसार शासन पद्धतियां बदली — ग्रनुभव का लाभ उठाकर उसमें ग्रावर्तन-परिवर्तन किये गये— प्रजातंत्रात्मक क्षेत्र में ग्रनेक प्रयोग हुये तथा ग्राज की सर्वश्रेष्ठ कही जाने वाली प्रणालियों का पूर्ण रूपेण लाभ उठाकर उन कटु परन्तु शाश्वत तत्वों का ज्ञान प्राप्त किया गया जिनकी खोज में ग्राधुनिक सभ्य और विकसित कहे जाने वाले राष्ट्र ग्राज भी प्रयत्नशील हैं।

पाँचवां ग्रध्याय

गणराज्य-१

(Republics)

पिछले अध्याय में राज्यों के प्रकार का वर्णन करते हुए गराराज्य का प्रसंग ग्राया है। गराराज्यों का ग्रस्तित्व प्राचीनकाल में या यह तो एक ग्रटल सत्य है ही। साथ ही यह भी सिद्ध है कि वीच के युग में राज्य का यह रूप लोकप्रिय भी रहा है। तरकालीन भ्रात्मशासन की प्रवृत्तियों का भी यह एक स्पष्ट प्रमाण है। यद्यपि गणराज्यों के प्रारंभ का निरुचय करना कुछ कठिन प्रतीत होता है तथापि प्राप्त प्रसंग यह सिद्ध करने में समर्थ हैं कि गराराज्य उत्तर-वैदिककाल में ही प्रचलित ग्रौर लोकप्रिय बने। वेदों में तो राज्यों का वर्णान साधारणतया राजतंत्र (Monarchy) के ही रूप में हुमा है। उसके पश्चात् विकास द्वारा गणतंत्रों की रचना हुई। मेगास्थनीज ने यही विचार व्यक्त किया है कि अनेक स्थानों पर राजतंत्र भंग होगए ग्रीर प्रजातंत्रात्मक सरकारें स्थापित होने लगी+। महाभारत ग्रादि ग्रन्य ग्रंथों से भी इसी विचार की पुष्टि होती है। ग्रतः इस बात को निविवाद रूप में स्वीकार किया गया है कि राज्यों का प्रथम स्वरूप राजतंत्र था। उसके दीर्घकाल पश्चात् गराराज्यों का युग ब्रारम्भ हुन्ना भ्रीर बहुत, समय तक सफलतापूर्वक प्रचलित रहा । हिन्दू जाति के इतिहास में गणराज्य अपना स्वतंत्र एवं महत्वपूर्ण स्थान तो रखते ही हैं, वंधानिक राजर्नतिक क्षेत्र में भी उनकी प्रगति चरम सीमा पर पहुँची हुई थी, यह म्राज के भारत के लिए ब्रत्यन्त गर्व ग्रीर गौरव का भी विषय है। प्रत्येक क्षेत्र में प्राचीन भारतीय गए।राज्य म्राज के गणराज्यों से कहीं मागे वढ़े हुए थे, यह मगले पृष्ठों का मध्ययन भली भांति सिद्ध कर सकेगा।

प्राचीन शब्दावली (Ancient Terminology for Republics)—
प्राचीनकाल में गएराज्य (Republic) के लिए साधारएतया 'गए।' शब्द ही प्रयोग में
प्राता था, परन्तु साथ साथ 'संघ' शब्द का प्रयोग भी प्रचलित था। वैसे संघ शब्द का प्रयं
प्रमेक राज्यों के संगठन के रूप में लिया जाता था, परन्तु वृहद् प्रथं में गएएराज्य भी इस
शब्द की सीमा में लिए जाते थे। साधारएा भाषा में गए। का ग्रर्थ संख्या (number) से
लिया जाता है ग्रर्थात् गएएराज्य वह व्यवस्था है जहां संख्या से कार्य संचालन किया जाय।
इस सम्बन्ध में सबसे बड़ी श्रापत्ति उस समय उपस्थित हुई जब डाक्टर जायसवाल ने यह
शोध की कि गए। का मर्थ गएएराज्य होता है×। उस समय तक पाश्चात्य विद्वान् ''गए।' का
भर्थ गएएराज्य न लेकर ग्रपनी ग्रपनी सुविधानुसार भनेक प्रकार से किया करते थे।

⁺ McCrindle-Megasthnese pp. 38-40. "Sovereignty (Kingship) was dissolved and democratic governments set up."

[×] Hindu Polity-Dr. Jayaswal pp.-21

श्री पलीट तथा ग्रन्य विद्वान् 'गए।' का ग्रर्थ 'जाति' (Tribe) समभते थे, जबिक श्री बूलर के विचारानुसार गए। का ग्रर्थ ''व्यापारी वर्ग ग्रयवा श्रमिकों का निगम'' होता था । ये सारे ग्नर्थ डा॰ जायसवाल ने भ्रामक सिद्ध किए हैं। + उनका मत है कि गए का ग्नर्थ यदि पारचात्य विद्वानों के विचारानुसार मानें तो हम एक कदम भी श्रागे नहीं वढ़ सकते । बौद्ध ग्रंथों में ये शब्द ग्रधिक प्रयुक्त हुए हैं । उनके प्रसंग देखते हुए यह प्रमाणित होता है कि गए। का प्रयोग गए। राज्य के लिए ही हुआ है। जैसे शलाका (Voting Tickets) गए।-पूरक× (Quorum) म्रादि पारिभाषिक शन्दों (Technical Terms) का प्रयोग गराराज्य के संबंध में ग्रधिक उपयुक्त होता है। दूसरी बात यह भी है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में गराराज्यों के लिए ऐसे कई प्रसंग हैं, जहां उनकी स्थापना स्रोर उनके विनाश के कारण तथा लुत होने का वर्णन म्राता है। इसलिए 'गण' का मर्थ 'जाति' (Tribe) तो हो ही नहीं सकता । हिन्दू पॉलिटी में डा॰ जायसवाल स्वयं लिखते हैं कि इंगलैंड में 'गरा' का ग्रर्थ जाति लिया जा रहा था, परंतु उनके इस नए ग्रर्थ के प्रकाशित होने पर जब इंगर्लैंड के श्री डा॰ एफ॰ डबल्यू॰ थोमस ने, जो भारतीय राजनीति के सर्वश्रीष्ठ विद्वान् (Indianist Scholar) थे, यह विचार व्यक्त किया कि गए। का अर्थ ''जाति'' अब त्याग रे देना चाहिए—तव डा० पलीट ने अपने अर्थ पर स्थिर रहना चाहा। परन्तु डा० थोमस ने चुनीती दे दी कि किसी भी संस्कृत ग्रंथ से वे यह ग्रर्थ सिद्ध नहीं कर सकते। ग्रन्तत: डा॰ जायसवाल का मर्थ (Interpretation) ही मान्य हुमा *।

दूसरा शब्द 'संघ' किसी सीमा तक गए। का पर्यायवाची है ही-प्राचीन भारतीय ग्रंथों में उसका प्रयोग समानार्थी रूप में ही हुन्ना भी है। पािशानि ने दोनों का प्रयोग एक ही मर्थ में किया है। संघ की श्रेणों में उसने मद्र, वृष्ण्जि ग्रादि राज्यों को लिया है, जो गए। राज्य भी थे। ग्रार्थशास्त्र में कौटिल्य भी राजतंत्र के साथ प्रजातंत्र राज्यों के वर्णन में 'संघ' शब्द का प्रयोग करता है ग्रीर यही बात बौद्ध-ग्रन्थों में भी प्रकट होती है, ग्रतः हम यह मानते हैं कि साधारण रूप में ये दोनों शब्द "गए। ग्रीर 'संघ' समानार्थी ही थे। परन्तु विशेषतः इनमें भेद था ग्रीर गहरा भेद था। जैसे ग्राज साधारण नागिरकों के लिए राज्य ग्रीर सरकार (State & Govt.) में विशेष भेद नहीं है, उसी प्रकार संघ ग्रीर गए। की स्थित भी श्री। वस्तुतः पारिभाषिकता की हिष्ट से इनमें गंभीर ग्रन्तर है। 'गए।' का ग्रर्थ था शासन के रूप से ग्रीर 'संघ' का तात्पर्य था राज्य के संगठन ग्रयवा स्वरूप से। जैसे सरकार, राज्य के भीतरी संचालन का ग्रंग होती है, परिवर्तनशील होती है, परन्तु फिर भी राज्य की पर्यायवानी नहीं होती। इसी प्रकार गए। ग्रीर राज्य की स्थिति थी। पातंजिल की संघ-विषयक

⁺ Hindu Polity—Dr. Jayaswal " PP-21.

^{ं ×} गरापूरको वा भविस्सामौति - महावाग्ग III 6.6;

^{*} Hindu Polity-. PP. 26.

व्याख्या से भी इसी बात की पुष्टि होती है +

गणराज्यों के संबंध में विशेष विवरण — प्राचीन भारतीय ग्रंथों के संबंधित प्रस्नों ना विश्लेषण किया जाय तो यह स्वतः सिद्ध हो जाता है कि गण का ग्रर्थ प्रजा-तन्त्रात्मक ज्ञासन व्यवस्था वाला राज्य था ग्रोर संघ भो इसका समानार्थी था। पाणिनि ने यह लिखा है—'नए गण स्थित किये गए थे। × जातक ग्रन्थों में ''गण बन्धन'' शब्द का प्रयोग हुग्रा है। + इसका ग्रर्थ है गण ऐसा संगठन था जिसमें कुछ बन्धन होते थे। जैसे ग्राजकल किसो सभा, समुदाय या समूह में होते हैं। महाभारत में तो ग्रत्यधिक स्पष्ट शब्दों में गण की व्याख्या कर दी गई है। - इस समय गणराज्य ग्रपनी कुछ विशेषताग्रों के लिए ख्यातिप्राप्त थे। जनमें से मुख्य ये थीं:—

(१) सफल विदेश नीति (२) परिपूर्ण कीष (३) सन्नद्ध सेना (४) उनका युद्ध-कौशल (५) न्यायपूर्ण नियम (६) ग्रादर्श ग्रनुशासन ।

स्रवदान-शतक में गण-शासन-व्यवस्था को राजतंत्र-व्यवस्था से विरुद्ध बताया है। डा० जायमवाल ने एक घटना का वर्णन किया है कि कुछ उत्तर भारत के व्यापारी बुद्ध के शासनकाल में दक्षिण भारत में गए थे। जब वहां के सम्राट् ने उनसे प्रश्न किया कि तुम्हारे सम्राट् कौन हैं ? तो उन्होंने उत्तर दिया—''श्रीमान् कुछ देश गणराज्य के श्रधीन हैं तथा कुछ सम्राट् के"। — तारार्थ यह कि उस समय गण 'राज्य' के ही अर्थ में प्रयोग होता था और भारत में गणराज्य स्थापित थे। जैन ग्रंथों में गण का ग्रर्थ मस्तिष्क वाले संगठन से लिया गया है ग्रयीत् जो समूह चैतन्य हो ग्रीर ग्रपना कार्य स्वयं करता हो। वास्तविक संघ वही है जो वैधानिक व्यक्तित्व (Corporate body) के साथ विद्यमान हो। इस प्रकार उपयुक्त वर्णन से गण का ग्रर्थ उस शासन-व्यवस्था से लिया जाता था. जिसमें संगठन होता था तथा जनता द्वारा व्यवस्था की जाती थी ग्रीर जहां कोई सम्राट् या स्थायी ग्रिधिटाता नहीं होता था।

(१) संघ के संबंध में पाणिनि के विचार (500 B.C.) — अपने समय के हिन्दू गणाराज्यों के संबंध में पाणिनि द्वारा अत्यधिक महत्वपूर्ण वर्णन किया गया है।

⁺ महाभाष्य-पातंजलि ४/१/४६.

[×] Hindu Polity-Jayaswal PP. 26. "New ganas were founded."

⁺ Jataka I 422 & II 45.

[÷] Ch. 107, Mahabharat.

^{+ &}quot;Your Majesty, some countries are under ganas & some are under Kings"-Hindu Polity PP. 28. or अवदानशातक "देव केचिद्देशा गणाधीनाः केचिद्राजाधीना" पृष्ठ १०३.

ढा० जायसवाल ने यह समय ५०० वर्ष ई० पू० माना है। ⋉ पाणिनि भारतवर्ष के प्रमुख व्याकरणाचार्य थे। उन्होंने यह लिखा है कि भारतवर्ष का कितना भाग उनके समय में संघों द्वारा संगठित था। पाणिनि के लिए 'संघ' एक तकनीकी शब्द था, जिसका अर्थ राजनैतिक संघ प्रथवा गएा या Republic होता था। उस समय धर्मसंघ नहीं होते थे प्रथवा यह कहना चाहिए कि इतने विख्यात नहीं हुए थे। परंतु जातियों का महत्व संघों में प्रवश्य रहता था। कुछ ऐसे नियम भी थे, जिनकी सहायता से यह ज्ञात हो सकता था कि संघ ब्राह्मणों का है, क्षत्रियों का अथवा अन्य किसी वर्ण का। इस प्रकार संव एक सम्य समाज की संस्या प्रतीत होती है, पिछड़े हुए या ग्रद्ध विकसित समाज की नहीं। कात्यायन ने पाणिनि की समालोचना में यह व्यक्त किया है कि यह नियम केवल एक सीमा में हो कार्यान्वित होता है, सर्वत्र नहीं। संघ किसी एक जाति के होते थे-यह व्यावहारिक नहीं जान पड़ता। संघ तो समाज की रचना पर ग्राधारित होता था, इसलिए सभी जाति के लोगों का सहयोग भ्रपेक्षित रहता था। पाणिनि ने संघों के निम्नांकित उदाहरण दिये हैं:-

१. वृक २ दामनि ३. यौधेय श्रीर ४. पार्व

पािंगिन ने संघों को ''ग्रायुधजीवी'' कहा है। परंतु कौटिल्य ने इनका नाम ''शास्त्रोपजीवी" रक्ला है तथा ''राजशब्दोपजीवी' संघों से इनकी तुल्ना की है। राजशब्दोपजीवी का अर्थ है वे संघ, जिनके शासक 'राजा' शब्द की उपाधि धारेण करते हैं भीर इसी प्रकार ''ग्रायुधजीवी'' का ग्रर्थ है, वह संघ. जहां ग्रायुध के ग्राधार पर जीवन श्राधारित हो अर्थात् जहां का विधान यह श्रादेश करता हो कि प्रत्येक संघ का सदस्य सैनिक शिक्षरायुक्त देशसेवक होना चाहिए। पािरानि ने इन शौर्यपूर्ण संघों के ग्रतिरिक्त दूसरे संघों का वर्णन भी किया है। जैसे मद्र, वृज्य, राजन्य ग्रन्धक, वृष्णि, महाराज एवं भर्ग म्रादि। + कुछ संघ जैसे वृष्णि के लिए यह लिखा है कि ये (Kingless) राजा-विहीन होते थे। मुद्रा में संघ या गए। का नाम होता था ग्रीर ये स्वतंत्र होते थे। इसी तरह "राजन्य" शब्द का भी संवैधानिक महत्त्व है इसका अर्थ उस परिवार के संचालकों से होता था, जो शासन की व्यवस्था करते थे। महाभारत में ऐसे प्रसंग बहुत ग्राए हैं। वृिष्ण-ग्रन्थक संघ का एक संयुक्त संघीय विधान था ग्रीर कार्यपालिका शक्ति दो राजाग्री में निहित होती थी, जो दोनों प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते थे। कात्यायन ने भी प्राचीन साहित्य के ग्राधार पर "अक़ूर वर्ग'' ग्रौर ''वासुदेव वर्ग'' का उल्लेख किया है। ग्रक़ूर भ्रन्थक नेता था और संघीय परिषद् के दी ग्रध्यक्षों में से एक ग्रध्यक्ष स्वयं था। महाभारत में इसीलिए कृष्ण भगवान् कहते हैं कि उनका ऐश्वर्य (authority) केवल प्राधा है ('ग्रद्ध'भोक्ता') । ये दो दो के दल भी समय समय पर बदलते रहते थे । कभी वासुदेव-उग्रसेन, कभी म्रक्र र-वासुदेव मौर कभी सिनी-वासुदेव-इससे यह ज्ञात होता है कि इनका निर्वाचन होता था। सिक्कों पर गए। व राज्य दोनों के संयुक्त नाम मंकित किये जाते थे।

[×] Hindu Polity-PP. 30. + महाभारत-सभापर्व

पाणिनि के मतानुसार संघ का 'शं क' ग्रीर 'लक्षण' होता था। लक्षण का अर्थ संभवतः राज्य की स्थायी मुहर (Seal) से होता था, जिसका उपयोग राज्य के भाजा-पत्रों तथा पताका ग्रादि में किया जाता था। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में "लक्षणाध्यक्ष" (Mint-Master or Director of Lakshanas) उस व्यक्ति को कहा है, जो चांदी ग्रीर तांबे के सिक्के बनाने के कार्य का निरीक्षण ग्रीर संचालन करता है। डा० जायसवाल का मत है कि राज्य की मुद्रा पर राज्य की मुहर (लक्षण) लगती थी, इसलिए उसका नाम 'लक्षणाध्यक्ष' कहा जाने लगा। × ग्रंक का अर्थ डा० जायसवाल के मत में सरकार के प्रतीक से हैं, जो सरकार के परिवर्तन के साथ परिवर्तित होता रहता था। वीर मित्रोदय + में 'हस्तांक' शब्द का प्रयोग हस्ताक्षर के ग्रंथ में किया गया है। कालिदास ने 'नोत्रांक' शब्द का प्रयोग किया है ग्रीर इसी प्रकार कौटिल्य ने 'राज्यांक' शब्द का। इप्तलिए 'ग्रंक' का अर्थ 'व्यक्ति का चिन्ह' अथवा विशेष ग्रंक से ही लिया जा सकता है। यहां तक कि पूरा सिद्धान्त या ग्रादर्श जो सत्ता हारा स्वीकृत किया जाता था, वह भी 'ग्रंक' में सम्मिलित किया जा सकता है यत: चित्र (figure) को लक्षण तथा सिद्धान्त (Motto or legend) को ग्रंक मान सकते हैं।

पारिणित ने संघों के दो प्रकार माने हैं:—(१) एकसदनीय (अनुत्तराधर्म) और (२) दिसदनीय। पहली प्रकार के संघ को वह 'काय' अथवा 'निकाय' अर्थात् 'एक अंग' का नाम भी देता है और निम्न तीन राजनैतिक निकायों का उदाहरण देता है:—

- (i) सपिण्डी निकाय (Sapindi-Nikaya)
- (ii) मुण्डी निकाय (Maundi-Nikaya)
- (iii) चिनकली निकाय (Chikkali-Nikaya)। इस प्रकार 'संघ' ग्रथना 'Republics' का वर्णन पाणिनि ने अपने अनुभव के आधार पर वैज्ञानिक ढंग पर किया है, जो अत्यन्त महत्वपूर्ण है।
- क्षित्र व्याप्त का निर्मा का निर्मा (500-400 B.C.)

ईसा के ५०० वर्ष पूर्व से लेकर ४०० वर्ष पूर्व तक साधारणतया इन संघों का समय अनुमान किया जाता है। बुद्धकालीन संघों की स्थापना राजनैतिक संघों का अनुकरण करके की गई थी। बुद्ध स्वयं एक गणराज्य में उत्पन्न हुए थे और उनके पड़ौसी राज्य भी सब गणराज्य थे। इसीलिए उन्होंने भी अपने संगठन का नाम "भिक्षु संघ" रक्खा और इसी प्रकार धर्म संघों की स्थापना में भी राजनैतिक संघों के आदर्शों से सहायता ली। पाली सूत्रों में दिया हुआ बुद्ध का वह उत्तर जो उन्होंने मगध चांसलर को दिया था यह

[×] Hindu Polity (Page 39)

⁺ वीर मित्रोदय एष्ठ १६५

स्पष्ट सिद्ध करता है कि "वज्जी" गएराज्य था और वहां पूर्ण स्वतंत्रता स्थापित था। + गएराज्यों की इस स्वायत्तता के मूल कारणों की वृद्ध ने व्याख्या भा की है, जिनके विद्यमान होते गए। राज्य का कभी पतन नहीं हो सकता था। डा॰ जायसवाल के मतानु-सार बुद्ध संघ की उत्पत्ति का इतिहास वास्तव में विश्व में (Monastic Order) के जन्म का इतिहास है। इसके द्वारा बुद्ध के धार्मिक भ्रातृत्व का विकास समस्त विश्व के लिए अध्ययन का विषय वन गया है।

बुद्धकाल के मुख्य प्रामाशिक गराराज्यों में नीचे लिखे सिम्मलित हैं:--

- १. शाक्य गरा राज्य-राजधानी किपलवस्तु २. जिच्छिव गरा राज्य--राजधानी वैशाली
- ३. विदेह गणराज्य--राजधानी मिथिला ४. मल्ल गणराज्य--राजधानी कुशीनगर

उक्त गणराज्यों में अधिकांश प्रशासन प्रणाली एक ही प्रकार की थी, किंतु कुछ साधारण भेद अवस्य थे। इनमें प्रशासन तथा न्याय व्यवस्था जनता की उस विधान सभा द्वारा संचालित होती थी जो सभाभवन (संस्थागार Mote Hall) में विचार करती थी तथा जहाँ युवक व वृद्ध समान रूप से उपस्थित रहते थे। ×विधान सभाके अधिवेशन चलते रहते थे और विदेशी यात्री तथा आगन्तुक भी अधिवेशन को देख सकते थे। + अधिवेशन का कार्य संचालित करने के लिए एक अध्यक्ष (Speaker) चुना जाता था जो अधिवेशन चलते समय राज्य की अध्यक्षता करता था। इसे राजा कहा जाता था।

जातक प्रन्थों में लिच्छ वि विधानः—इसका वर्णन सबसे अच्छा किया गया है। लिच्छ वि शासकों को उसमें गए। शासक कहा गया है। उस समय राज्य में तीन प्रधान अधिकारी होते थे, जिन्हें क्रमशः राजा, जपराजा तथा सेनापित कहा जाता था। × एक चौथा अधिकारी और होता था, जिसे भएडगारिका कहते थे। इन्हीं चारों अधिकारियों का दल समस्त शासन संचालित करता था। यद्यपि सार्वभीम कित्त जनता में निहित रहती थी, तथापि उसका प्रयोग उनके प्रतिनिधि ही करते थे, जो सभा के रूप में रहते थे। वैशाली में ऐसे प्रतिनिधियों के निर्वाचकों की संस्था७७० वताई गई है, जो स्वयं भी शासक बनने योग्य होते थे। जो शासक चुने जाते थे, उन्हें पद प्रहण करने का उत्सव मनाना होता था। सभाकी बैठक प्रारंभ होने के लिए घण्टा Toesin बजाया जाता था और तब वैशाली निवासी अपनी संसद में

⁺ Dialogues of the Buddha-Part II Page 79-85-यही वर्णन डा॰ जायसवाल ने अपनी पुस्तक Hindu Polity में वहुत अच्छा किया है । एन्ठ ४२-४३.

[×] Jataka I Page 504—"राजानी होंति तत्तका; येव उपराजानी तत्तका, सेनापतिनी तत्तका, तत्तका, मंडगारिका,"

उपस्थित होते थे । यहाँ राजनैतिक, सैनिक हो नहीं बल्कि कृषि तथा व्यापारिक विषय पर भी बहुत विचार-विमर्श होता था । एक बुद्धिस्ट पुस्तक में यह प्रसंग ग्राया है कि गण-राज्य में सब सदस्य समान प्रधिकारों का उपभोग करते थे, चाहे कोई ऊँचा हो या नीचा हो वयो वृद्ध हो ग्रथवा युवक ग्रोर प्रत्येक ग्रपने को स्वतन्त्र राजा समभता था + कोई एक दूसरे का ग्रनुसरण नहीं करता था । भाषण व मतदान के ग्रधिकार साधारणत: समान होते थे, उनमें से प्रत्येक राष्ट्राति बनने के लिए उत्सुक रहता था।

लिच्छवि विधान द्वारा नागरिकों की स्वतन्त्रता बड़ी सतर्कता से सुरक्षित रखी गई थी - गणराज्य का अध्यक्ष न्यायविभाग का सर्वोच्च ग्रधिकारी होता था। न्याय मन्त्री का पद मलग होता था, जिस पर वही व्यक्ति मा सकता था जो न्यायविज्ञ हो, वह विदेशी भी हो सकता था और वैतनिक भी। किसी भी नागरिक को उसी स्थिति में अपराधी माना जा सकता था, जब सेनापति, उपराजा और राजा द्वारा अलग अलग निविवाद रूप से उसे दोषी मान लिया गया हो । * तत्कालीन निर्णयों को सुरक्षित रखा जाता या । इस प्रकार के रिकार्ड्स के लिए रजिस्टर रक्ले जाते थे, जिन्हें ''पावनी पहुका'' कहा जाता था। इसमें अपराध की किस्म, दिया हुआ दएड, साक्षी आदि तथा निर्णय सुरक्षित रक्ले जाते थे। न्यायालय भी कई प्रकार के होते थे-(१) साधारण ग्रपराधों के लिए-साधारण न्यायालय जिनके न्यायाधीशों को विनिच्चय-महामत्त कहते थे। (२) इससे ऊपर ग्रपील का न्यायालय होता था जिसके त्यायाधीश "व्योहारिक" (Lawyer-Judges) कहलाते थे ग्रीर (३) उससे ऊपर उच्च न्यायालय (High Court) होता था जिसके न्यायाधीश सूत्रधार (Doctor of Law) कहलाते थे। इसके बाद फिर (४) ग्रन्तिम प्रार्थना के लिए परिषद् (Council of final appeal) होती थी; जिसमें साधारणतया ब्राठ सदस्य होते थे। इसी को 'ग्रब्टकुल' भी कहा जाता था। उपयुक्त शृंखला में किसी भी एक से नागरिक को निरपराध घोषित करके मुक्त किया जा सकता था और निरन्तर अपराधी मानने पर फिर के बोनेंट (मंत्रिपरिषद्) द्वारा निर्णय लिया जाना ग्रनिवार्य था। महाभारत में यह सिद्धान्त स्वीकार किया गया है कि फौजदारी न्याय विशेषज्ञों द्वारा होना ग्रावश्यक है।×

एक और मुख्य विशेषता (लिच्छवि विधान की) यह थी कि विदेह गएराज्य के साथ संघ की स्थापना की हुई थी और दोनों को संयुक्त रूप से 'समविज्जी' कहा जाता था। इसी प्रकार पहले 'मल्ल गएराज्य' के साथ भी ये संघ स्थापना कर चुके थे। + संघीय परिषद (Federal Council, में १८ सदस्य होते थे, ग्राधे लिच्छिव तथा ग्राधे मल्ल ग्रीर 'गएगराजा' कहे जाते थे। संघों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य बड़ी शक्तियों से ग्रपना बचाव

^{*} Lalita Vistar Page 21 — नौच्चमध्य वृद्धज्येष्ठानुपालिता, एकेक एव मन्यते, अहं राजी प्रहाराजीति।

⁺ Hindu Polity - Jayaswal Page 49.

[×] वीरमित्रोदय--एष्ठ 19

⁺ कल्पस्त्र, 128.

करना था। संघों में सब राज्य समानता के ग्राधार पर मिलते थे तथा समान मताधिकार का प्रयोग करते थे । वहां बड़े-छोटे या निर्वल-बलवान का भेद नहीं किया जाता था। उस समय संघ की स्थापना का प्रचार ग्रधिक था।

३. श्रर्थशास्त्र में रंघों का वर्णन (325-300 B.C)—म्रर्थशास्त्र में संघों का म्रधिकांश वर्णान उनकी विशेषताम्रों तथा साम्राज्यवादी नीति के साथ सम्बन्धों के क्रम में प्राप्त होता है। मुख्यरूप से कौटिल्य ने संघों को दो श्रेणियों में रखा है। एक तो वे जहां शासक 'राजा' की पदवी से विभूपित होते थे ग्रौर दूसरे वे जो 'राजा' नहीं कहलाते थे। कीटिल्य राजतंत्र या नृपतंत्र का प्रशंसक था, परन्त् वह स्वीकार करता है कि राजतन्त्र से गणाराज्य बनते रहते हैं। महाभारत, पुराण तथा अन्य अन्यों के अनुसार प्रारम्भिक में 'कु ह' काल राजतन्त्रात्मक राज्य के अन्तर्गत थे और बाद में 'गए। राज्य' बन गए। इसके समय का अनुमान बुद्ध के बाद ग्रीर कीटिल्य से पूर्व का किया जाता है ग्रयीत् लगभग ३२५ ई० पूर् से ३०० वर्ष ई० पू० तक। इसी प्रकार 'विदेह' भी पहले 'राजतन्त्र' ग्रीर 'गर्णराज्य' परिवर्तित हो गए थे। पांचाल भी गराराज्य के रूप में हो था—कोटिल्य यह मानता है। डा० जायसवाल का मत है कि भारतीय गणुराज्यों की यह सामान्य विशेषता रही है कि जब ने राजनैतिक शक्तिविहीन हो जाते थे, तब भी न्यापारिक कौशल वनाए रखते थे श्रीर व्यापारिक बन जाते थे 🗴 पांचाल व कुरु कुछ कुछ इसी श्रेग्गी में ग्रा सकते हैं।

दूसरी श्रेणी ने गण राज्य ने थे, जहां राजा की पदनी नहीं होती थी परन्तु सारा राष्ट्रःसैनिक कौशल युक्त (Nation-in-arms) होता था । इस श्रेणी में कम्भोज, सौराष्ट्र क्षत्रिए तथा श्रेणी म्रादि म्राते हैं। 🕂 ये राज्य म्राने नागरिकों पर सैनिक योग्यता प्राप्त करने पर बल देते थे, साथ हो उद्योग एवं कृषि म्रादि व्यवसायों की म्रोर भी यथेष्ट ध्यान दिया जाता था | इसलिए ये शक्तिशाली और समृद्ध दोनों होते थे इस प्रकार कौटिल्य के समय में गणराज्य प्रचलित भी थे ग्रीर प्रभावशाली भी।

४. यूनानी लेखकों द्वारा संघों का वर्श्यन (325 B.C.) — यूनानी लेखक साधार एतिया गांवों को स्वतन्त्र इकाइयां समभते थे परन्तु ग्राम पञ्चायत से वे गए। राज्य ग्रर्थ नहीं लेते थे। जिन वर्गों से उनकी भेंट हुई, उन्हें वे राज्य ही समभते थे, उनसे यूनानियों ने युद्ध किए, संधियां की ग्रीर उनकी वैधानिक विशेषताओं को लेख-बद्ध किया। युनानियों के वर्णन पूर्ण विश्वसनीय हैं। मेगास्थनीज, चन्द्रगुष्त मौर्य के राज्यकाल में यूनान को राज-दूत था, उसकी कोई भी बात संदिग्ध व ग्रस्पष्ट नहीं है। वह यहाँ पर स्थायी राजदूत था इसलिए उसका वर्णान सत्य है। उसने देश में दो प्रकार के राज्य बताए हैं-१.राजतन्त्र भौर २. गए। राज्य । जहां सम्राट् है, वहां प्रत्येक स्थिति सम्राट् के सामने प्रकट की जाती थी; तथा ग्रात्मशासित जनता में वस्तुस्थिति का ज्ञान मिजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित किया

[×] Hindu Polity—Jayaswal (Page 54). + काम्भोज-सुराष्ट्र-चत्रिएश्र एयादयो वार्ता शस्त्रोपजीविनः (श्रर्थशास्त्र Page 376)

जाता था। - यूनानी लेखकों द्वारा कई गणराज्यों का उल्लेख किया गया है। जैसे (१) कथाइबन (लाहौर, धमृतसर म्रादि), यह गणराज्य साहस तथा युद्धकौशल के लिए विख्यात था। यहां स्त्री-पुरुष स्वेच्छा से विवाह करते थे तथा सती प्रधा भी प्रचलित थी और सर्वश्रीदर सुन्दर व्यक्ति को ही सम्राट् बनाया जाता था । * इसके ग्रतिरिक्त ग्रन्य कई गए।राज्यों का वर्शन आता है। रावी के तट पर अनेक सार्वभीम गए।राज्यों का सामना सिकन्दर कर चुका था, जिनमें ग्रह स्टाइ, सीभूति ग्रादि मुख्य थे। इन गराराज्यों में उच्च कोटि की प्रशासन व्यवस्था थी, सर्वोत्तम नियमों द्वारा शासन संचालित होता था तथा सींदर्य की समाज में सर्वोत्कृष्ट स्थान तथा अत्यधिक सम्मान दिया जाता था। इन राज्यों के नागरिकों को भी दूसरे राज्यों के नागरिकों की अपेक्षा श्रीष्ठ माना जाता था । सींदर्य को स्थान समाज में ऊँचा होता था, इसोलिए विवाह के लिए उच्चकूलीन-सम्बन्ध की ग्रपेक्षा ग्राकर्षक सीन्दर्य को ही प्रधानता दी जाती थी, क्योंकि वच्चों का सुन्दर होना गर्व की वस्तु मानी गई थी। 'मिकिण्डल' ने तो यह भी लिखा है कि बच्चों का पालन माता-पिताग्रों की इच्छानुसार नहीं होता था, बल्कि राज्य के स्वास्थ्य-ग्रधिकारियों द्वारा निर्णय लिया जाता था कि बालक स्वस्य है ग्रीर नागरिक वनने योग्य है, तब पालन होता था ग्रन्यथा उसे समाप्त कर दिया जाता था | ÷ एरियन (Arrian) ने भी व्यास नदी के किनार के दो गए। राज्यों का उल्लेख किया है जो बहुत उपजाऊ, युद्ध-कुशन तथा श्रेष्ठ शासन-व्यवस्था से सुशोभित थे।

सिकन्दर ने वापस जाते समय भी ग्रनेक गराराज्यों को पार किया, जो सिंधु नदी के किनारे से विल्विस्तान तक फैले हुए थे, जिनमें धुद्रक व मालव प्रसिद्ध थे। यूनानियों ने इन्हें क्रमशः ग्रावसीड्रकाई (Oxydrakai) तथा मलोई (Malloi) नाम दिया है। यूनानी इतिहास तो यह प्रकट करता है कि सिकन्दर महान ने इन दोनों गणराज्यों को नष्ट कर दिया था, परन्तु पातंजिल के अनुसार 'क्षुद्रकोजितम्' क्षुद्रक विजयी रहते थे। मैसेडोनिया के लेखकों ने भी युद्ध के पश्चात् इन गणराज्यों को महत्ता स्वीकार करते हुए यह लिखा हैं कि ये गराराज्य सौ के करीव राजवूत भेजते थे, जो रथ पर सवारी करते ये तथा प्रसाधारण प्रतिष्ठावान् होते थे। उनकी वेशभूषा सोने व जरी के काम सहित रेशमी वस्त्रों की होती थीं। स्वतन्त्रता पर वे गर्व करते थे और ईश्वर से भयभीत न होकर, उसमें ग्रहट श्रद्धा व विश्वास रखते थे। इसलिए सिकन्दर महान् ने जो साधारणता विरोधियों की पीड़ित करता था, यहां समस्त राज़दूतों का सम्मान किया तथा प्रीतिभोज का आयोजन किया।

युनानियों ने 'सम्बसथास' गणाराज्य का वर्णन भी किया है, जिसे सम्बस्ताई (Sambastai) श्रीर श्रवस्तनोई लिखा गया है, जो संख्या तथा यक्ति में भारतवर्ष में किसी

⁺ Mc Crindle-Megasthnese. Page 212.

[.] Mc Crindle-Invasion of India by Alaxander the Great-Page 219.

से भी कम नहीं थे (Second to none) वहां प्रजातन्त्रात्मक सरकार संगठित थी ग्रीर उनकी सेना में ६०,००० पैदल. ६००० घुड़सवार ग्रीर ५०० रथ थे। +इसी प्रकार उस्साङ्ग्रोइ (Ossadioi), स्यूजिकनी (Musicani) ज्ञचमनोई (Brachmanoi) तथा पटाला (Patala) ग्रादि का भी वर्णन मिलता है। इनमें से पटाला को हैदराबाद सिध से मिलाया जाता है, जिसे प्राचीन पोटलपुरी नाम द्वारा श्रव भी स्वीकार किया जाता है। ग्रन्य स्थानों का निश्चय ग्रभी तक नहीं हो पाया है। ग्रतः यह निष्कर्ष निकलता है कि यूनानियों के वर्णनानुसार पंजाव व सिध का लगभग समस्च भाग गणराज्यों से युक्त था।

यूनानी विद्वानों द्वारा हिन्दू गराराज्यों की वैधानिक स्थिति:-उपरोक्त वर्णन से यह ज्ञात होता है कि यूनानी विद्वानों के मतानुसार भारतवर्ष में गए। राज्यों के भी विभिन्न संविधान थे स्रोर प्रत्येक की कुछ गुल्य विशेषताएं भी थीं। वास्तव में विधान जनता की म्रावश्यकताएं तथा देश-काल मौर स्थिति की मनुकूलता की ध्यान में रखकर बनाये जाते थे। कुछ गराराज्यों में द्विसदनात्मक प्रणाली थी, जहां दूसरे सदन में निर्वाचित प्रौढ़ व्यक्ति होते थे ग्रीर निर्वाचन में समाज के प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्यक्ष मताधिकार प्राप्त होता था। इस प्रकार की स्थिति श्रम्बसथास प्रजातन्त्र राज्य में थी। क्षुद्रक तथा मालव ग्राराज्यों में स्यिति दूसरे प्रकार की थी। वहां राज्य की सत्ता एक व्यक्ति में निहित नहीं होती थी, न किसी छोटी संस्था में, बल्कि समस्त प्रजा में निहित होती थी ग्रौर १०० या १५० प्रति-निधियों द्वारा राज्य के महत्त्वपूर्ण काम करवाये जाते थे। * कथाइयन गणराज्य में निर्वा-चित शासक की प्रया थी। परन्तु यह निर्वाचित शासक सैनिक नेतृत्व नहीं करता था। लिच्छवि गराराज्य में सैनिक अध्यक्ष का पद भिन्न था, जिसे सेनापति कहते ये। पाटल गणराज्य में शासन भार "मन्त्रिमण्डल" (Council of Elders) पर या ग्रीर शासक भंत्रिमण्डल के प्रति उत्तरदायी रहते थे। यह राजतन्त्र व कुलतन्त्र का सुन्दर सुयोग था, जहां सत्ता का ब्रन्तिम स्थान गए। व संघ ही था कुछ गए। राज्यों में प्रशासकीय या कार्य-पालिका शक्ति दितीय सदन में रहती थी-ग्रीर कुछ में संसद् के हाथ में। गएाराज्यों में, महाभारत के प्रनुसार, गोपनीयता का प्रश्न हमेशा चिन्ताजनक माना जाता था, क्योंकि व्यक्तियों की संख्या प्रधिक होने तथा विचार-विमर्श के कारण सब विषय प्रकट हो सकते थे. इसलिए मन्त्र-सम्बन्धी (Policy-matters) विषय कुछ ही व्यक्तियों के हाथ में रक्खे जाते थे। इन्हीं लोगों की कार्यकारिएरो वनती थी और शेष प्रौढ़ व्यक्तियों की सभा द्वितीय सदन की भांति कार्य करती थी।

यूनानी विद्वानों ने कुछ ऐसे गणराज्यों का वर्णन भी किया है, जहां कार्यपालिका शक्ति कुछ परिवारों के हाथ में थी। उस समय उत्तराधिकार के नियमों का पालन किया जाता था, फिर भी गणराज्य कायम थे। ऐसे राज्यों को उन्होंने कुलतंत्रात्मक प्रजातन्त्र

⁺ Curtius (Bk. Ix, Ch. 8, Mc Crindle, Alaxander, P. 252

^{*} Hindu Polity-Jayaswal, Page. 73

(Aristocratic Dem cracy) का नाम दिया है। इन गए। राज्यों में बृहदाकार संसदें भी होती थीं। क्षुद्रक ग्रादि लोग उच्चकोटि के दार्शनिक भी माने जाते थे। उनकी 'प्रत्युत्पन्न कुशाग्रमति'' (Sharp-witted) प्रशंसनीय थी। दूसरे गए।राज्य वेद व उपनिषदों की विद्वता में निपुण थे, जिनके नाम ग्राज तक चले ग्राते हैं जैसे ''कठ''। स्वतंत्र गसाराज्यों का मुक्त वातावरसा ही इतने ऊ चे दर्शन को जन्म देने का कारसा माना जा सकता है। सङ्गीत का स्थान भी स्पृह्णीय था। एरियन ने भारतीयों को "नृत्य व सङ्गीत के प्रेमी" बताया है। + केवल कलह (Disputes), विद्या (Science) तथा शिल्प (Art) का ग्रधिक प्रचार ही गए। राज्यों की प्रमुख कमजोरी मानी जाती थी। × परन्तु फिर भी बुद्ध ने लिच्छविगरा की तुलना ''देवताग्रों की मण्डली'' से की है। → इस प्रकार गगाराज्यों की ग्रनेक वैधानिक तथा दूसरी सामान्य विशेषताग्रों का उल्लेख यूनानी विद्वानों ने किया है, जो महत्त्वपूर्ण है।

४. महाभारत में गणराज्यों का वर्णन--शांति पर्व के ५०७ वें प्रध्याय में गण-राज्यों की विशेषताएं वताई गई हैं। उनमें मुख्य ये हैं:—पहली, यह कि गए।राज्य किसी-शासक के प्रति स्वामिभक्त नहीं थे। दूसरी, गराराज्य का धर्थ समस्त जनता से होता है केवल शासक वर्ग से नहीं। तीसरी, शासक वर्ग (Governingbody) में सिर्फ गरामुख्य तथा प्रधान हो सम्मिलित होते थे चौथी, सभा में सदस्य संख्या वड़ी होने के कारण महत्त्व-पूर्ण नीति के विषयों की गोपनीयता कठिन होती थी। पांचवीं, गराराज्य अधिकांश अपने संय (Confederations) बना लेते थे। छठीं, लोभ व होप दो मुख्य कारण थे, जिनके द्वारा गराराज्यों में परस्पर वैमनस्य उत्पन्न होता था। सातवीं, गराराज्यों में परस्पर छल, भेद, वल, समभौता, प्रपंच, पड्यन्त्र म्रादि का प्रयोग किया जाता या ग्रीर ऐसे गणराज्य का अवश्य विनाश होता था।

गराराज्यों के कुछ विशेष गुरा भी होते थे। श्रच्छे गराराज्य में बुद्धिवृद्ध नागरिक - परस्पर मिलकर चलने का भाव प्रोत्साहित करते थे। शुद्ध नियम व न्यायव्यवस्था के कारण तथा एक दूसरे के प्रति सद्व्यवहार द्वारा गणराज्य हर प्रकार से प्रसन्न रहते थे। अच्छे गराराज्य अपने बच्चों व सन्तान को निरन्तर अच्छा शिक्षण देने में संलग्न रहते थे। गरा-राज्यों का सर्वाङ्गीए। विकास होता था। इसीलिये ये लोकप्रिय बन गये थे।

किन्तु गुरा के साथ अवगुरा का होना अनिवार्य सा है। गराराज्यों में कुछ भयद्भर अवगुरा थे, जैसे - क्रोध, विभाजन, सेना का प्रयोग आदि । वास्तव में गणराज्यों में भीतरी

^{+ &}quot;Lovers of Dance and Song". Mc Crindle-Page 136

[×] Hindu Poltiy-Page 78

^{÷ &}quot;Company of Tavatimsa Gods." Footnote-Hindu Polity-Page 78

खतरा ही ग्रधिक समभा जाता था और संघ-निर्माण उसकी बहुत बड़ी रोक ग्रौर सुरक्षा का साधन माना गया था।

- ६. मीं यंकाल में गणराज्यों का वर्णन मीर्य साम्राज्य में कुछ गणराज्य के क्षेत्र भी थे। यूनानी लेखकों ने लिखा है कि चन्द्रगुप्त ने ग्रराकोसिया तथा एरिया के गणराज्य सिल्यूकस से जीते थे। मीर्य साम्राज्य की नीति यह थी कि हढ़ गणराज्यों को स्वतन्त्र सा ही छोड़ दिया जाय क्यों कि उनका जीतना या जीतकर वश में रखना कठिन होता है। ग्रशोक की नीति भी गणराज्यों की ग्रोर इसी तरह की थी। जनरल किन्चम (स्वर्गीय) द्वारा तक्षशिला में प्राप्त कुछ सिक्के एकत्र किए गए हैं और उनके ग्राधार पर यह सिद्ध होता है कि गणराज्यों के भ्रपने सिक्के चलते थे। इस प्रकार मीर्यकाल में भी गणराज्य थे ग्रीर राजतन्त्र (Monarchy) के साथ मिलकर चलते थे। यह एक विशेष प्रकार के संबंध से चलते थे। इस समय के गणराज्यों के सिक्के तथा अन्य ऐतिहासिक प्रमाण प्रचुर मात्रा में मिलते हैं।
- ७. गण्राज्यों का लोप -गुप्त-काल के ग्रारंभ से मण्राज्यों का लोप प्रारंभ होता है। गुप्त-काक्ति का साम्राज्य के रूप में प्रादुर्भाव लिच्छिव गण्राज्य की मित्रता से होता है, क्योंकि उस समय तक लिच्छिव गण्राज्य ही शक्तिशाली प्रधान गण्राज्य रह गया या ग्रन्य गण्राज्य शक्ति व प्रभाव में ग्रस्त हो चुके थे। या एक विशेषता है जो ऐतिहासिक तथ्यों पर ग्राधारित है कि जिन गण्राज्यों को सहायता से गुप्त-शक्ति प्रभावशाली वनी, उन्हीं गण्राज्यों का लोप गुप्त-शक्ति द्वारा किया ग्रीर मन्त में फिर गुप्त-शक्ति की नींव एक गण्राज्य द्वारा ही हिला दी गई। ये गण्राज्य थे मित्र-त्रय (Three Friendly Republics), जिनके नाम क्रमशः पुष्यमित्र-पद्मित्र थे। इनका स्थान मालवा था।

ऊपर का समस्त वर्णन गणराज्यों का ऐतिहासिक परिचय कहा जा सकता है! इनकी कार्यपद्धित तथा अन्य वैधानिक रोति-रिवाजों पर अलग से वर्णन करना सर्वथा उचित व आवश्यक है। यहां केवल यह उल्लेख कर देना पर्याप्त है कि गणराज्य विभिन्न युगों में रहे और उनकी अपनी मुख्य विशेषताएं थीं। सामान्य विशेषताएं तो थीं ही और उनके प्रमाण पर्याप्त रूप में विद्यमान हैं। इस आधार पर यह मानना उचित है कि प्राचीन भारत में प्रजातन्त्रात्मक प्रवृत्तियां वहुत गहरे रूप में जमी हुई थीं तथा सामाजिक व आर्थिक क्षेत्रों के अतिरिक्त राजनैतिक क्षेत्र में भी जनता की स्वतन्त्रता और आत्मशासन के सिद्धान्त कार्यान्वित किये जाते थे।

१ V. Smith-Early History of India-Page 149-151

गहाराज्य-परिशिष्ट

तकन की हिन्दू संविधान (१००० ई० पू०) (Technical Hindu Constitution)—डा॰ जायसवाल के मतानुसार संघ राज्यों के दो भाग, 'गएा' ग्रीर 'कुल' होते थे ग्रीर इनमें कई प्रकार के संवैधानिक तकनीकी (Technical) भेद होते थे जिनमें निम्नलिखित मुख्य हैं:—

- (१) भोज संविधान (जहां वंश परम्परा द्वारा उत्तराधिकार मिलता रहता हो)
- (२) स्वराज्य संविधान (जहां योग्यता के ग्राधार पर ग्रध्यक्ष का चुनाव होता हो) ।
- (३) वैराज्य संविधान (जहां का विधान राष्ट्रीयता जिए हुए हो) (Kingless-cess)
- (४) राष्ट्रिक संविधान (Non-monarchical Community—जहां जनता में अराजतन्त्रीय शासन हो)।
- (५) द्वौराज्य संविधान : The rule of the two—जहां दो व्यक्ति शासन चलाते हों)।
- (६) ग्रराजक (The ion-ruler State)—जहां नियम का शासन हो, व्यक्ति का नहीं)। +

जैन सूत्र में निम्न ६ प्रंकार के गएराज्य विश्त हैं:--

- (१) श्रराजक राज्य (Non-ruler States)
- (२) ग्एातन्त्रात्मक राज्य (Gana-ruled States)
- (३) युवराज शासित राज्य (Yuvaraj-ruled States)
- (४) द्विशासित राज्य (Two-ruled States)
- (५) वैराज्यीय राज्य (Vairajiya States)
- (६) विरुद्ध-रज्जनी राज्य (States ruled by Parties)

उपरोक्त गणराज्यों का शासक वर्ग सदैव प्रतिज्ञावद्ध होता था और यह (Cerem ny of Consecration) अभिषेक की औपचारिकता अनिवार्य होती थी। इसके विना राज्य का विधिपूर्वक अस्तित्व ही नहीं माना जाता था। शासक अच्छा और निष्पक्ष तथा न्यायपूर्ण शासन चलाने की शपथ ग्रहण करते थे। लिच्छिव शासकों के यहां प्रभिषेक की प्रया थी। मल्ल शासकों के यहां तो एक निश्चित स्थान था, वहों यह "मुक्ता-बंधन" (Coronation) उत्सव सम्पन्न किया जाता था। हिन्दू राजनीतिक विचार में विना ग्रिभिक ग्रथवा राजितलक हुए शासक (Un-anointed ruler) घुणा की दृष्टि से देखा जाता था और उसे नियमविष्द्ध शासक (Unlawful ruler) माना जाता था। इस प्रकार गणराज्यों की विधि-परायणता तथा वैधानिकता अपूर्व और ग्रहितीय थो जो ग्राज भी नवोदित गणतन्त्रात्मक राज्यों के लिए ग्रादर्श रूप में उपस्थित है।

⁺ Hindu Polity-Dr. Jayaswal, Chapt. X.

छठा ग्रध्याय

गणराज्य

(ii) Republics

हिन्दू गणराज्यों में विचार-विमर्श तथा विधि-निर्माण-पद्धति

(Procedure of Deliberations & lawmaking in Hindu Republics)

प्रस्तावनाः—प्राचीन गणराज्यों के विषय में हमारी जानकारी उस समय तक पूर्ण नहीं मानी जा सकती, जब तक हम उनके विचार करने की प्रणाली तथा विधि-निर्माण पढ़ित से परिचय प्राप्त नहीं कर लेते । यद्यपि पूर्ण ग्रधिकृत वर्णान प्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध नहीं है, तथापि प्राप्त सामग्री उस समय की स्पष्ट भलक देने में समर्थ हैं । प्राचीन काल के बौढ़ संघ, राजनैतिक संघों के अनुरूप ही स्थापित हुए थे तथा उनकी प्रक्रियाए लगभग समान रूप में ही संचालित होती थीं । कौशलनरेश विख्डक द्वारा शाक्यों पर आक्रमण्या की घटना बहुत प्रसिद्ध है । उस समय शाक्य-सभा का अधिवेशन बुलाया गया था । प्रश्न यह था कि शाक्य ग्राप्त-समर्पण करने के विषय में एकमत नहीं थे । एकमत न होने से बहुमत शांत करना आवश्यक हो गया और सदस्यों के मत लिये गए । बहुमत ने द्वार खोलने का निश्चय किया और किपलवस्तु के द्वार खोल दिए गए । ४ इसी प्रकार की ग्रन्य कई घटनाए हैं जिनसे संघों के विचार-विमर्श की प्रणाली का परिचय होता है । इनमें मल्लसंघ का अधिवेशन, पाली साहित्य में पावा के मल्लों द्वारा निर्मित उभटक नामक नवीन सभा-भवन का बुद्ध द्वारा उद्घाटन, शाक्यों के नवीन सभा-भवन का उद्घाटन (यह भी बुद्ध द्वारा ही किया गया था) ग्रादि मुख्य हैं । इस प्रकार के अध्ययन से संघों की कार्य पद्धित का ग्रनुमान लगाया जाता है ।

१. स्थान(Seats) — कपिलवस्तु की उपरोक्त घटना के वर्णन से ज्ञात होता है कि सभाग्रों के ग्रधिवेशन एक निश्चित भवन में होते थे जिसे ''संस्थागार'' कहा जाता था । इस भवन में बैठने का प्रवन्ध करने के लिए एक ग्रधिकारी नियुक्त होता था, जिसे ''ग्रासन पंचापक'' या ''ग्रासन प्रजन्यक'' (Seat regulator) कहते थे ।
...

[×] रोंकहिल-लाइफ ऑफ दी बुद्ध ।

[÷] चुल्लवगग-१२/२/६

- २. गण्पूरक (Quorum)—साधारणतया समस्त सदस्यों से उपस्थित होने की आशा की जाती थी परन्तु सब सदस्य उपस्थित नहीं हो पाते थे। इसलिए गण्णृरक की प्रया थी। बीद्धसंघ में गण्पूर्ति के लिए कम से कम २० भिक्षुग्रों की उपस्थित ग्रनिवार्य थी। राजनैतिक संघों में भी गण्पूर्ति ग्रनिवार्य थी, परन्तु उनकी संख्या क्या थी इसका पता नहीं चलता है। प्रत्येक नियमित कार्यवाही के लिए गण्णूप्रक ग्रनिवार्य था तथा इसके विपरीत किया हुग्रा कार्य सच्चा कार्य नहीं माना जाता था। अ गण्णूर्ति के लिए एक सदस्य को उत्तरदायी बना दिया जाता था वही इस के लिए प्रयत्न करता था, उसे गण्णूरक ग्रधिकारी कहते थे। ग्राजकल जो कार्य (Whip) सचेतक का माना जाता है, वही कार्य इस ग्रधिकारी वा था। परन्तु यह केवल एक बैठक के लिए हीता था, जब कि ग्राज के राजनैतिक दलों के सचेतक (Party Whip) सभा के पूरे कार्य-काल के लिए होते हैं।
- ३ श्रध्यत्त (Speaker)—बौद्ध संघ के अधिवेशन का अध्यक्ष 'विनयधर' कह लाता था। राजनैतिक संघों में सभा की अध्यक्षता राजा या गएामुख्य करता था। अधिवेशन के अवसर पर निश्चित कार्य-क्रम (Agenda) का संचालन, अनुशासन की स्थापना तथा मन्त्रए। पर नियन्त्रए। करना आदि अध्यक्ष के मुख्य कार्य थे। अध्यक्ष से पूर्ण निष्पक्ष रहने की आशा की जाती थी। विवादग्रस्त विषयों पर उसका निर्णय अन्तिम होता था यह नहीं कहा जा सकता परन्तु उसके पक्षपात करने पर कड़ी अलोचना की जाती थी।
 - 8. प्रस्ताव (Motion)—विचार विमर्श के लिए प्रत्येक विषय 'प्रस्ताव' या 'जिंदा' के रूप में ग्रारंभ होता था। इसके बाद वह प्रस्ताव दुवारा नियमित रूप से (Resulution) निश्चित रूप में उपस्थित किया जाता था। इस ग्रवसर पर मत लिए जाते थे ग्रीर विवाद का ग्रवसर मिलता था। मतदान (Voice-Vote) वाणी द्वारा प्रकट किया जाता था परन्तु सर्वसम्मित होने की स्थिति में मतदान नहीं होता था। विरोध होने की स्थिति में प्रस्ताव के पूरे तीन वाचन होते थे ग्रीर पूर्ण निष्पक्षता व नियमानुसार पारित होने पर ही उसे युद्ध स्वीकृत प्रस्ताव माना जाता था। जिसे ''कर्मवाचा'' कहते थे। मतदान के समय समर्थकों को मीन तथा विरोधियों को वागी द्वारा विरोध व्यक्त करने को कहा जाता था। मवादिवयाद के समय सदस्यों में मण्डन, कलह तथा विवाद उठ खड़ा होता था। × निरर्थक लम्बे भागण देते रहने को प्रथा भी प्रचलित थी। ÷ यह भी प्रतीत होता है कि राजनेतिक-दल होते होंगे जिनके कारण कभी-कभी कदुता वढ़ जाती थी ग्रीर सत्ता प्राप्ति के प्रयत्न

^{× &}quot;अधम्मेन न भिक्रवधे वन्ग कन्म अकन्म न न करणीवं ॥ महावन्ग IX. ३२.

⁺ महावारग

[÷] चुल्लवागा

चलते रहते थे। महाभारत में पिएत अन्धक-वृष्णि संघ की सभा में आहुक और अकरूर ऐसे ही दलों के नेता थे। * आज के प्रजातन्त्रात्मक गर्णराज्यों को भांति प्राचीन काल के गर्ण-राज्यों में भी दलवन्दी रहती थी तथा सदस्यों को स्वतंत्रतापूर्वक आलोचना—प्रत्यालोचना करने का पूर्ण अधिकार होता था। भाषर्णों के विषय में कुछ नियमों का पालन अनिवार्य था। चुल्लवागा के अनुसार, पूर्व-निर्णीत प्रश्न दुवारा उपस्थित नहीं किये जा सकते थे, एक ही प्रश्न पर दो बार विचार व्यक्त नहीं किए जा सकते थे, तथा इन नियमों का उल्लंघन दण्डनीय माना जाता था।

- ४. सर्वसम्मित (unauimity) प्रत्येक प्रश्न पर सर्व-सम्मित प्राप्त करना श्रेष्ठ माना जाता था। इसलिए मत-भेद को दूर करने के लिए कुछ साधन भी अपनाए जाते थे जिनमें से मुख्य-मुख्य निम्नलिखित हैं:—
- १. सम्बन्धित प्रश्न को दलीय बैठकों में निपटाने का प्रयास किया जाता था जिसे 'तिन्वत्यारक' युक्ति कहते थे।
- २. परंस्पर विचारभेद दूर न होने की स्थिति में किसी दूसरे संघ के निर्णय के लिए भेज देते थे तथा उस निर्णय को स्वीकार करना ग्रनिवार्य था।
- ३. सम्बन्धित प्रश्न विचारार्थ एक उप-समिति के सुपुर्द किया जा सकता था जिसमें बहुत योग्य सदस्य होते थे। इसे उद्वाहिका सभा भी कहते थे। संभवतः इस समिति का निर्वाचन सभा द्वारा होता था तथा इसमें एक प्रधान व एक मंत्री भी होता था। इस समिति का निर्ण्य सर्वमान्य होता था। दल-यद्धित के कारण यह भी होता होना कि समिति में सदस्यों का प्रमुपत दल के प्राधार पर रखा जाता हो।
- ६. सतदान तथा मतसंग्रह की विधियां—(Vating & Vote-Collecting Systems) सर्वसम्मित के अभाव में मत लिये जाते थे जिसकी एक विशेष प्रणाली थी। बौद्ध-संघ में इसे येव्भुय्यस्सिकेन (बहुमत से कार्य करना) कहा जाता था। मत के लिए 'छन्द' शब्द प्रयोग में याता था जिसका भाव ''स्वच्छन्दता'' से लिया जाता है। मतदान से पूर्व एक अधिकारी नियुक्त होता था जिसें (Teller) 'शलाका ग्राहक' कहते थे। मतदान शवाकाओं द्वारा होता था जो विभिन्न रंगों की होती थी। चीनी साहित्य द्वारा यह भी

[÷] चुल्लवाग्ग ४/१३

[×] शांतिपर्व =१/१०

सिद्ध होता है कि शलाकाएँ लकड़ी की बनी होती थीं। + शलाका ग्राहक रंगों का महत्व समभता या ग्रीर उचित उपगोग की प्रार्थना करता था मतदान गोपनीय होता था। मत-संग्रह की कुल तीन विधियां थीं, जो इस प्रकार हैं:—

- (१) गूल्हकम (गुप्त विधि)
- (२) सकण्एा-जप्पकर्म (कान में घीरे से कह कर)
- (३) विवटकमं (स्पेन्ट रूप से)

ज्ञाला का ग्रहण के पश्चात् बहुमत के ग्राधार पर निर्णय घोषित कर दिया नाता था प्राचीन भारत में भी ग्रनुपिस्थित सदस्यों के मत एकत्र किए जाते थे ग्रीर मत ग्रामा के साथ इन्हें गिना जाता था। ऐसे मत केवल उपस्थित की ग्रसमर्थता या रुग्णावस्था के कारण लिए जाते थे, परन्तु विरोध होने पर इन्हें भो रह कर दिया जाता था।

मतदान तथा शलका का कार्य बहुत उत्तरदायित्व का माना गया था तथा शलाका ग्राहक को भी इस सम्बन्ध में बहुत ग्रधिकार थे। यदि उसे यह सन्देह हो जाय कि इस निर्णय में सदस्य समभ कर मत न दे सके या निर्णय से संघ या धर्म को क्षिति पहुँचेगी तो वह निर्णय को स्थगित ग्रथवा उसका निर्णय कर सकता था × मतदान में ग्रधर्म (Irregularity), सदस्यों से ग्रसमान व्यवहार, मतदाता की इच्छा के विरुद्ध मतदान प्रथवा किसी प्रभाव का प्रयोग करना ग्रादि मतदान को ग्रवैध घोषित करने के लिए पर्याप्त कारण थे। ग्रन्थथा बहुमत का निर्णय मान्य होता था। इसे बहुतर (Greater number) कहा जाता था।

• प्रतिनिधित्व का सिद्धान्त (Principle of Representation) जव संघ स्वयं सर्वसम्मित से निर्णय करने में असमर्थ रहता था तो प्रतिनिधि सभाग्रों की नियुक्ति भी (Delegation Committees) की जाती थी। इस सभा के समक्ष विभिन्न दल उपस्थित हो सकते थे। इस सभा में सदस्यों की संख्या पूरी न होकर ३,५ या ७ होती थी, जिससे निर्णय सरलता से लिया जा सके। मनुस्मृति तथा प्रर्थशास्त्र भी इस भी पृष्टि करते हैं, (Arthasastra, 61)। वौद्ध ग्रन्थ के श्रनुसार इस सभा में 'धम्म', 'विनय' तथा विशेष व्यक्ति उपस्थित होने चाहिए। इस प्रकार शुद्ध न्याय की स्थापना के लिए प्रतिनिधित्य का सिद्धान्त माना गया था।

द. श्रान्तिम निर्णय (Res Judicata) एक वार नियमित प्रणाली के ग्रमुसार निर्णय हो जाने के पश्चात् वही प्रश्न दुवारा विचार के लिए उपस्थित नहीं किया जा सकता था। जो निर्णय हो जाता था वही श्रान्तिम माना जाता था ÷ यदि कोई सदस्य

⁺ Hindu Polity foot note (Page 95)

[×] हिन्दू सम्पल-पो० मुकर्जी ए० २१०

[÷] Hindu Polity-Page 98. "Having been once settled, it is settled for good."

सभा में अपना भाषण देते हुए मर्यादा का उल्लंघन करता था अथवा नियम एवं परम्पराओं के विरुद्ध व्यवहार करता था अथवा इसी प्रकार कोई अशोभनीय ढंग अपनाता था तो उसकी निन्दा की जाती थी और उसे खेदजनक घोषित करने की पद्धति भी प्रचलित थी। इस तरह निर्णात प्रश्न को पुनः प्रस्तुत करना अपराध माना गया था।

- (ह) सभा के लिपिक (Clerks of the House):— इन सभात्रों में लिपिक भी होते थे, जो निरन्तर सभा की कार्यवाही को लेखबद्ध करने में व्यस्त रहते थे। इस प्रकार सभा में जो भी प्रस्ताव, विवाद एवं विचार-विनिमय प्रस्तुत होते थे सभी लिखे जाते थे। एक बौद्ध प्रंथ में ऐसा वर्णन मिलता है कि देवतात्रों की सभा हो रही थी उसमें चारों कोनों पर चार लिपिकों का उल्लेख भी है। ये लिपिक अपने निर्दिष्ट स्थान पर अप्रांतीन होते थे और सभा की प्रत्येक कार्यवाही को लेखबद्ध करते थे। अ यह देवतात्रों की सभा का वर्णन है; परन्तु जैसा डा० जायसवाल का मत है, मनुष्य अपनी सब संस्थात्रों की देविक रूप में समभते थे, यह वर्णन भी मानव संस्थात्रों का ही है। बुद्धकालीन युग में भारत की संसद् के भवनों में थे लिपिक होते थे और इनके बाद दर्शकों को प्रवेश के लिए आजा लेनी होती थी। यह निष्कर्ष उपयुक्त ही है। चारों कोनों में चार लिपिक रहने का अर्थ यह है कि सभा बड़ी होती थी और एक—दो लिपिकों से कार्य ठीक नहीं हो सकता था। सभासद् अपने स्थानों से ही मात्रण देते थे इसलिए समीप का लिपिक ही वह भाषण सुविधापूर्वक लेखबद्ध कर सकता था। इस प्रकार लिपिक का स्थान प्रतिष्ठित होता था और इन्हें (Great king) महाराजा कहा जाता था।
- (१०) पारिभाषिक शब्दावली तथा कार्य प्रणाली का ऐतिहासिक महत्व (Historical Significance of the Terms & Procedure)—उपर्युक्त कार्य प्रणाली तथा पारिमाषिक शब्दावली यह सिद्ध करती है कि प्राचीन भारतीय गणराज्य राजनैतिक च्रेत्र में विकास के बहुत ऊ चे स्तर पर पहुँचे हुए थे। उनकी कार्य पद्धति में तकनीकीपन (Technicality), वाणी विन्यास, भाषा की श्रीपचारिकता, नियमों का पालन तथा वैधानिकता की सर्वोच्च सीमा प्रकट होती है। ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह स्थिति सिद्यों के निरन्तर श्रम्यास के फलस्वरूप प्राप्त हुई थी। जिन्त, प्रतिज्ञा, गणपूर्ति, शलाका, बहुमत निर्णय पद्धति, श्रांतम निर्णय (Res Judlicata), समा की कार्यचाही को लेखबद्ध रखना श्रादि पूर्ण विकसित तथा जाग्रत समाज में ही रह सकते हैं श्रीर इसी-लिए बुद्ध ने इनकी परिभाषा या परिचय भी नहीं दिया; क्योंकि यह समस्त शब्दावली पूर्ण रूप से प्रचलित थी जातक ग्रंथ में तो सम्राट का चुनाव भी 'नागर' Citizens of the Capital) सथा मंत्रियों के एकमत हो जाने के कारण होना वर्णित है। जिसे पूर्ण नगर का जनमत (Referendum) कह सकते हैं। जातक ग्रंथ में ही दूसरा प्रसंग यह भी है कि प्रस्ताव के तीन वाचन की प्रणाली बुद्ध से पूर्व भी थी श्रीर यह पद्धति एक हास्यमय कहानी द्वारा वतायी गई है। उस कहानी में एक पद्धी ने राजा के चुनाव के लिए प्रस्ताव दुवारा प्रस्तत

ĭ

सं

[×] दीच निकाय XIX, 14; as quoted by Dr. Jayaswal (Hindu Polity) P. 99.

किया। दो बार प्रस्ताव किया श्रीर दो ही बार विरोध हुआ श्रीर कहा-"प्रतीचा कीजिए।" विरोधियों ने भाषण के लिए समय मांगा जो इस शर्त पर मिला कि वे राजनीतिक सिद्धान्तों श्रीर नियमों का स्पष्टीकरण करेंगे। विरोध, अन्त में हुआ श्रीर यह कहा गया कि प्रस्तावित शासक की उपस्थित श्रुभ नहीं होती (यह पच्ची उल्लू था)। इस ह्ष्टान्त द्वारा केवल सोंदर्थ या उपस्थित के निर्वाचन के सिद्धान्त का मांग्रील उड़ाया गया है। यह प्रणाली पहले लोकिक तथा बाद में बुद्ध कालीन बन गई है।

(११) नागरिकता तथा मताधिकार (Franchise & Citizenship) — साधारणतया गणराज्यों में नागरिकता का श्राधार प्रतिवार होता था। महाभारत में यह प्रसंग स्त्राता है कि गणराज्य में 'कुल' व 'चन्म' के अनुसार समानता स्वीकार की गई है। डा॰ जायसवाल ने इसका श्रर्थ यह लगाया है कि राजनैतिक उद्देश्यों के लिए सब परिवार समान थे। पाली प्रथा में भी मताधिकार 'कुल' के अनुसार ही स्वीकार किया जाना माना गया है। गणराज्य में बड़े बड़े पद जैसे शासक, राष्ट्रिक, पेत्तनिक, सेनापति, गाम-गमनिका (नगरपति या President of Township), पूग गमनिका (श्रीद्यों—गमनिका (नगरपति या President of Township), पूग गमनिका (श्रीद्यों—भाषा ही इस प्रकार की है कि यह "कुलों की ही मिलते थे। कात्यायन ने तो गणराज्य की परि-भाषा ही इस प्रकार की है कि यह "कुलों की स्था" (Assembly of Kulas) है। अत: कुल ही नागरिकता का श्राधार था यह स्वीकार किया जाता है।

गणराज्यों में विदेशी लोगों को भी नागरिकता प्रदान की जाती थी। पाणिनि ने इस अकार के नियम बताए हैं जिनके द्वारा व्यक्ति का स्थायी निवास (श्रिभजनश्च), वर्तमान निवास (सोऽस्य निवास:) तथा भिक्त (Allegiance) आदि प्रकट किए जाते थे और श्रपनी भक्ति के श्रवुसार उन्हें पुकारा जाता था। जैसे श्राव भी निवास के श्रवुसार व्यक्तियों का तिरवय आसानी से किया जाता है और निवास के अनुसार ही अधि-कांश नागरिकता प्राप्त करना आसान होता है, वही हिथति प्राचीन काल में भी दिव्यात होती है। अफ़ीका के निवासी नागरिकता प्राप्त करने पर अफ़ीकन किंतु भारत की नागरि-कता रखते हुए अफ़ीका में रहने पर भी भारतीय ही कहलाते हैं। प्राचीन काल में मद . राज्य भक्ति वाले नाग्रिक मद्रक तथा दृज्य राज्य की भक्ति अर्थात् दृज्ञि की नागरिकता प्राप्त व्यक्ति वृज्ञिक करे जाते थे । भिक्त या Allegiance का श्रर्थ राजनैतिक स्वामिभिक्त या राज्य के प्रति कर्त्ताच्य की भागना का प्राधान्य था। प्राचीन काल में कृत्रिम नागरिकता प्राप्त करने के उदाहरणों का समाव नहीं है। इस्रिक् गणराज्यों की नागरिकता का प्रसार बहुत होता था। कुछ विचारकी ने भिक्त का अर्थ धार्मिक तन्मयता से लिया है किंतु यह सदी नहीं है। पाणिति ने स्वयं इसका प्रयोग राजनैतिक तथा संवैधानिक अर्थ में किया है। साथ ही बन्पद, महाराबा सादि के साथ धार्मिक मिल को योग कहीं मी उचित जात नहीं होगा। स्मिन-दन (स्पायी निवास) तथा निवास (अस्थायी निवास) आदि का संबंध ती स्पष्ट रूप

⁺ Hindu Polity-Dr. Jayaswal-Poge 102

से नागरिकता के साथ ही सुन्दर छोरे सार्थ क प्रतीत होता है। प्राचीन काल के गणराज्यों में पूर्ण वयस्क मताधिकार नहीं था (Universal Adult Franchise) न सत्ता ही समस्त जनता में निहित थी।

(१२) नियम व न्याय व्यवस्था (Laws & Judicial System in Republics)—प्राचीन काल में कुलराज्य तथा गणराज्य दोनों के ही नियम प्रचलित थे और कुल न्यायालयों की अध्यक्ता भी कुलिक अर्थात् कुल के अज्ञ लोगों द्वारा की नाती थी। 'वीर मित्रोदय' में यह भी मिलता है कि फीजदारी अपराध व अभियोगों की सुनवाई के लिए ''अष्ट-कुलक न्यायालय'' (Board of the Eight Kulikas) था और कुल न्यायालय की अपील गण न्यायालय में की नाती थी। न्याय का उत्तरदायित्व राज्य के अध्यक् का माना नाता था; इसीलिए न्याय सम्पादन गण के अध्यक्त के नाम पर ही होता था। इन्हीं गणराज्यों में उद्योग-संगठन भी होते थे जिन्हें पूग (Puga of Gulids) कहा नाता था, इन्हें भी कुछ न्यायिक अधिकार होते थे; परन्तु इनके निर्णयों की अपील कुल न्यायालय या गण न्यायालय में हो सकती थी। सत्ता परिवर्त न के अवसर पर इन न्यायालय या गण न्यायालय में हो सकती थी। सत्ता परिवर्त न के अवसर पर इन न्यायालय या गण न्यायालय में हो सकती थी।

प्राचीन हिन्दू न्याय व नियम शास्त्रों से यह प्रकट है कि इन गणराज्यों के नियम अलग व भिन्न भिन्न होते थे और उनकी मान्यता थी। यूनानी लेखकों ने तो हिन्दू गणराज्यों के नियमों की बड़ी प्रशंसा की है। महाभारत में भी इनका यश वर्णन किया गया है। लिच्छवियों के यहाँ तो कानूनी नजीरों का पूर्ण लेखा मौजूद था (Book of Legal Precedents)। नारद व बृहस्पित ने इन नियमों को "समय" का नाम दिया है। अर्थात् सम + इ=समान होना। सभा में सब लोग सहमत होकर ये नियम बनाते थे।

हिन्दू गणराज्य पद्धित का मृल्यांकन—गणराज्यों का विशद अध्ययन करने के बाद यह स्वाभाविक सा जगता है कि उनका उचित मृल्यांकन भी किया जाय। न्याय और ज्यवस्था के ज्ञेत्र में हमारे हिन्दू गणराज्य बहुत क चे स्तर पर पहुँचे हुए थे, जिसका प्रमाण महाभारत में तो विद्यमान है ही, यूनानी लेखकों ने भी उसकी पुष्टि की है। अधिकांश गणराज्य अपने राजकीय लेख सुरिच्चित रखते थे। निर्णय नजीरों (Precedents) के रूप में कार्यान्वित होते थे। अर्थशास्त्र का रचियता व राजतंत्र का समर्थक कोटिज्य भी यह स्वीकार करता है कि गणराज्यों में न्याय ज्यवस्था उत्तम थी। + अनुशासन के ज्ञेत्र में भी गणराज्यों का आदर्श क चा था। अनुशासन की स्थापना के लिए इद्ध जन उत्तरदायी होते थे। अनुशासन छोटे-बड़े सभी के लिए अनिवार्य था। मन-वचन-कर्म तीनों का अनुशासन अपेन्तित होता था। महाभारत में वह प्रतंग बहुत महत्व रखता है जहाँ कृष्ण ने अपने मित्र नारद से अपने संघ की कुछ कठिनाहर्यों प्रकट की छोर उसके

⁺ ऋर्थशास्त्र Page 379-"न्यायवृत्तिहितः प्रियः"

फलस्वरूप कृष्ण की नारद से यह धुनना पड़ा कि अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। संघ की प्रतिष्ठा व धुरचा के लिए ये गुण वास्तव में आवश्यक थे। वीरता भी गणराज्यों की एक विशेषता थी। वे थुद्ध के लिए सदैन तैयार रहते थे और पराक्रम का प्रदर्शन प्रत्येक नागरिक के लिए गौरव का विषय होता था। स्वदेश सेवा में तन-मन-धन अर्पण करने को किटचढ़ रहना लोकप्रिय आदर्श था। समानता सार गणराज्य में व्याप्त रहती थी। प्रजातंत्रात्मक संस्थाओं में समानता ही सबसे अधिक प्रिय आदर्श है। यह बड़ी सफलता-पूर्वक गणराज्यों में सुरिचत था। प्रशासन के चेत्र में गणराज्य सदैव सफल रहे हैं। महा-भारत में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, जहाँ गणराज्यों को बड़ी किटन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा; किन्तु शासन की कुशलता के कारण वे सदैव सफल रहे। विशेषकर आर्थिक या धन की व्यवस्था में विशेष पटु थे। गणराज्यों के परिपूर्ण कोष लोकोित वन गए थे।

सैनिक दृष्टि से सुसंगिठत होना गणराज्यों के लिए अभय वरदान था। आज की माँति सदैव ही सैनिक संगठन राजनैतिक व्यवस्था का मूल आधार रहा है । गणराज्य में सैनिक शिक्षण लगभग अनिवार्य साथा। डा॰ जायसवाल ने गणराज्यों को सैनिक राष्ट्र (Nation-in-arms) ही कह दिया है। × इसलिए गणराज्य किसी भी तूसरे प्रकार के राज्य अथवा सैनिक दृष्टि से निर्वल नहीं रहते थे। कौटिल्य ने इसीलिए गणराज्यों को "अजेय" (Invincible) माना है। गणराज्यों के सुदृढ़ बनने का दूसरा कारण था उनकी संघ-स्थापना की भावना। वे अधिकांश संघ बनाकर रहते थे जिससे उनकी शिक्ष और भी बढ़ जाती थी। ऐसे संघों के अनेक उदाहरण हैं—जैसे लुद्रक-मालव संघ, अधक-वृष्टिण संघ आदि-आदि। संघ-गणराज्यों को पराजित करना एक असम्भावना मानी जाती थी।

श्रीश्रोगिक च्रेत्र में भी गणराज्य पीछे नहीं थे । उनकी सम्पन्नता श्रीर समृद्धि के सम्बन्ध में यूनानी लेखकों ने बहुत कुछ लिखा है । महाभारत में तो इसका वर्णन है ही । प्रत्येक नागरिक का यह श्रादर्श होता था कि वह समाज में श्राग्णी बने । यदि राजनैतिक च्रेत्र में सफल न हो तो श्रार्थिक च्रेत्र में श्रवश्य ही उसे सफल होना चाहिए । वाणिज्य के लिए गणराज्य सदैव यह चाहते थे कि उनके शत्र श्रों की संख्या कम हो श्रीर मित्र बढ़ें तािक परस्पर समृद्धि श्रीर सुख में सहयोग दे सकें । इस प्रकार वे सर्वतोसुखी प्रतिमाणील नागरिकों से श्रक्त उन्नत गणराज्य थे । कौटिल्य ने लिखा है कि वे एक साथ ही योद्धा श्रीर उद्योगपित थे, उनके नियम ऐसे थे जो उन्हें उद्योगपित श्रीर योद्धा बनने के लिए मजबूर करते थे । इस प्रकार कृषि व व्यापार पर ध्यान देने से उनके कोप सदैव पूर्ण रहते थे । यूनानी लेखकों ने यह स्पष्ट लिखा है कि गणराज्यों के नागरिक कृषक भी थे श्रीर उच कोटि के सैनिक भी । डा॰ जायसवाल ने लिखा है कि जो हाथ श्रद में कुशलतापूर्वक तलवार का प्रयोग करते थे, वही हाथ समान सुगमता से दर्शती (Soythe) का प्रयोग

[×] Hindu Polity-Page 170.

करने में भी अभ्यस्त थे। + अर्थशास्त्र तथा बौद्ध ग्रन्थों से भी इसी विचार की पुष्टि

प्रशासनीय च्रेत्र में राजनीति के अत्यन्त विचारपूर्ण सिद्धान्तों के प्रयोग करते रहना भी गणराज्यों की विशेषता थी। शिक्तयों के पृथक्करण का सिद्धान्त भी गणराज्यों में अपनाया गया था। न्यायपालिका लगभग स्वतंत्र और नियमादि के च्रेत्र में पूर्ण शिक्तशाली थीं । कार्यपालिका को च्रेत्र में व्यवस्थापिका समाए पूर्ण शिक्तशाली थीं। कार्यपालिका का च्रेत्र अपने ही कार्यच्रेत्र तक सीमित था—न्यायपालिका और व्यवस्थापिका पर अनुचित प्रभाव डालने की च्रमता कार्यपालिका में नहीं थी। साथ ही इतनी किठन पृथक्ता भी नहीं होती थी कि एक दूसरे के सहयोग से वंचित रहकर कार्य में ही बाधा आने लगे। सभी गणराज्यों द्वरा शिक्तयों के विलगाव का सिद्धान्त अपनाया हुआ था। कई गणराज्यों में सेना-पित का पद निर्वाचित किया जाता था। लिच्छिव गणराज्यों में न्यायपालिका, सेना संचालन तथा कार्यपालिका के कार्य भिन्न भिन्न थे। यूनानी लेखकों ने इसकी पृष्टि की है। अतः यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि ये गणराज्य राजनैतिक च्रेत्र में बहुत कुशल तथा वैधानिक अनुभव से पूर्ण थे।

हा॰ जायसवाल का मत है कि गणराज्यों का इतना अध्ययन करने पर ध्यान होता है कि उनसे संबंधित कुछ पुस्तकें भी प्राप्त होनी चाहिए । यह सब वर्णन महाभारत, अर्थशास्त्र, बौद्ध ग्रन्थ आदि से प्राप्त करते हैं जो अधिकांश राजतंत्रीय काल के ग्रन्थ हैं । ऐसे ग्रन्थों के अभाव में भी यह तो स्वीकार किया जाना चाहिए कि गणतन्त्रात्मक पद्धित की एक सुदृढ़ दार्शनिक पृष्ठभूमि होगी, उसके बिना इतने उच्चकोटि के तन्त्र की व्यवस्था असंभव-सी लगती है । अचानक ऐसी संस्थाएँ जन्म नहीं ले सकतीं । साथ ही सहसा उत्पन्न तंत्र या संस्था दीर्घकाल तक प्रभावपूर्ण ढंग से सफलतापूर्वक चलतो रहें, यह तो असम्भव ही है । इसके अतिरिक्त किपल और कठ के देश में, जिन्होंने राज्य से कहीं अधिक किन दार्शनिक समस्याओं के सफल इल निकाले, गणराज्यों के दर्शन का नितान्त अभाव रहा हो यह तो स्वीकार ही नहीं किया जा सकता । अतः यह आशा की जाती है कि भविष्य में स्वतंत्र भारत के शोधकर्ता ऐसे प्रामाणिक ग्रन्थों की खोज करके इस कमी की पूर्ति का प्रयत्न करेंगे ताकि गणराज्यों का अध्ययन सुदृढ़ आधार पर किया जा सके । गणतंत्रात्मक सिद्धान्त के अनुसार निर्वाचित शासकरण राज्य का सेवक या दास माना जाता

गणतंत्रात्मक सिद्धान्त के अनुसार निर्वाचित शासकगणराज्य का सेवक या दास माना जाता था। महामहोपाध्याय श्री हरप्रसाद शास्त्री द्वारा प्राप्त आर्यदेव की पुस्तक "चतुरशितका" द्वारा यह प्रामाणित किया जाता है कि वह गणराज्य का निर्वाचित शासक ''गणदास'' कहलाता था। महाभारत में भी कृष्ण ने यही घोषित किया था कि शासक के नाम पर सुके वास्तव में सेवक का कार्य करना पड़ता है। ऐसे गणराज्यों में नागरिक का व्यक्तित्व भी महत्त्वपूर्ण माना जाता है। कुछ गणराज्य अवश्य ऐसे थे जहाँ राज्य से पृथक व्यक्ति

^{+ &}quot;The hand which weilded the sword successfully was accustomed to use the scythe with equal facility" Hindu Polity Page 171.

का महत्व नहीं था, परन्तु अधिकांश गणराज्यों में व्यक्तिवाद का सिद्धान्त स्वीकार किया गया था। अराजकवाद का सिद्धान्त व्यक्तिवाद की ही चरम सीमा है, जिस पर प्राचीन लेखकों ने विचार व्यक्त किए हैं और उन्हें महत्ता दी है। वास्तव में शासन तो नियमों द्वारा होता था व्यक्ति द्वारा नहीं। और कोई व्यक्ति अपनी सार्वभौमिकता किसी व्यक्तिविशेष या समूह-विशेष पर नहीं थोपता था। इस प्रकार व्यक्ति गत स्वतंत्रताए अरिच्त रहती थीं। गण-राज्य की संगठन सामाजिक समभौते के सिद्धान्त पर आधारित रहता था और उनके संबी की स्थापना तो स्पष्ट रूप से इन्हीं समभौतों के आधार पर होती थीं। यह सामाजिक समभौते का सिद्धान्त भारतवर्ष में अतिपाचीन माना गया है। डा॰ जायसवाल के मतान समभौते का सिद्धान्त भारतवर्ष में अतिपाचीन माना गया है।

किसी भी राज्य की सफलता का प्रमाण उसका दीर्घ-जीवन ही हो सकता है। इस हिन्द से भारत के प्राचीन गणराज्य बहुत सफल रहे हैं। सतवत भीज गणराज्य लगभग १००० वर्ष रहा और उत्तर मद्रास १३०० वर्ष । इसी प्रकार राजस्थान में भालव गणराज्य लगभग १००० वर्ष रहा। लिच्छेंवि गणराज्य पूरे १००० वर्ष रहा।

हिन्दू गणराज्यों के दोप-उपर्युक्त गुणों और विशेषताओं के होते हुए इन गणराज्यों में कुछ ऐसी कमियाँ भी थीं जिनके कारण ये चिरद्यायी नहीं वन सके । पहली बात, ये गणराज्य छोड़े छोटे भूमिमाग होते थे, जिसके कारण ये ब्राह्मिनिर्भर नहीं हो पाते थे । कुछ गंगाराज्य अवश्य बड़े थे; किन्तु अधिकांश आकार-प्रकार तथा साधन एवं संग-ठन की हिन्दि से छोटे ही होते थे । इसलिए जन कभी बड़े राज्य साम्राज्य ननाने को लिप्सा या छोटे राज्यों के हड़िप जाने के लोभ का संवरण नहीं कर पाते थे, उसी समय इनका जीवनं समाप्त हो जाता या । महाभारत में यह वर्णन मिलता है कि जब अराजक राज्यी तथा दसरों हड राज्यों में मूठमेड़ होती थी तो अराजक राज्य सूखी लकड़ी की तरह नष्ट ही जाते थे। यही जात श्रन्य प्रजातंत्रात्मक गणराज्यों के लिए सत्य प्रतीत होती है। दूसरी कमजोरी ईन गणराज्यों में पारस्परिक होये व पड्यन्त्रों की थी जो स्रधिकांश लोभ स्त्रीर प्रतियोगिता के कारण उत्पन्न होते रहते थे । कीटिल्य ने यह लिखा है कि ये गंणराज्य पार-स्परिक विरोध व संघूर्ण पैदा करने के लिए उपयुक्त थे । + प्रस्पर द्वेप उत्पन्न करके ही गए। राज्यों की ध्वंस किया जा सकता था। कभी शत्रुद्धारा विरोध उत्पन्न कराया जाता था श्रीर कभी सभाश्रों में भाषण श्रादि के अवसर पर स्वयं उत्पन्न हो जाया करता था। महा-मारत में कृष्ण कहते हैं कि भीषण भाषण छुनते छुनते मेरा हृदय तप गया। इसी प्रकार राजनैतिक दल पद्धति के कारण भी गुड़ वन जाते थे । ऐसे अवसर पर कृष्ण की दूसरी उक्ति बहुत सुन्दर है जब कि आहुक व अफरूर की दीनों दलों के बीच में यह चुनना पड़े कि क्सिका साथ दें ग्रीर किसका नहीं। वे कड़ते हैं 'दोनों के बीच मेरी स्थिति उन दी बुशारियों की मां के समान है जो एक दूसरे के विरुद्ध दाव लगा रहे ही, श्रीर वह एक

⁺ Arthusustra-Kautilya "Fit soil for sowing the seeds of dissension."

की विजय ऋौर दूसरे की पराजय के लिए कामना नहीं कर सकती हो।"+ महाभारत में यही कहा है कि गणराज्यों के लिए ये आन्तरिक कलह ऋौर विवाद ही वास्तविक आपित्याँ थीं। इनकी तुलना में बाहरी आपित्याँ कुछ भी नहीं थीं। इन्हीं के कारण गणराज्य स्तव्यस्त होते रहते थे।

निष्फर्प-गणराज्यों के गुणों, विशेषताश्रों ग्रीर दोषों का लेखा जोखा-करने के उपरान्त यह कहा जा सकता है कि प्राचीन भारत के गणराज्य प्रजातंत्रात्मक रूप में अत्यन्त वैधानिक श्रीर विकसित राज्य थे, जहाँ उन सब प्रक्रियाश्रों को स्थान मिला था जो श्राज बीसवीं सदी में भी कई तथाकथित गणराज्यों में विद्यमान नहीं है। वास्तव में उनका स्वरूप, कार्य प्रणाली, सिद्धान्त श्रादि श्राज भी विश्व के लिए श्रीर विशेष रूप में भारत के लिए श्राज करणाय हैं। राज्य को न्यास (Trust) समक्तना श्रीर शासक में जनता के दास बनने की भावना बहुत ही सुन्दर है। विदेशों का इतिहास ऐसी परम्पराश्रों से रिक्त है, जबिक भारत का श्रातीत ऐसी परम्पराश्रों से पूर्ण रूप से सम्पन्न है। श्राधुनिक भारत के लिए भी, प्राचीन काल की श्रन्य कई श्रानुकरणीय बातों के स्थाय ये परम्पराए भी श्रपना विशेष महत्व रखती हैं। जन-मत (Referendum) श्रादि की पद्धित, जो श्राज शुद्ध रूप में केवल स्विट्जरलण्ड में प्रचलित है, वह प्राचीन भारत में थी। श्राज भी श्रन्य राष्ट्र उस पद्धित को श्रपनाने का साहस नहीं कर रहे। बड़े गर्व की वस्तु है।

प्रश्न

- 1. Describe the peculiarities of the Hindu republican constitutions as noticed by the Greek writers who came with Alexander.
- 2. What do you know of the procedure of work in the sessions of ancient Hindu republics?
- 3. What are the causes of the fall of republics according to the Mahabharat?
- 4. Describe the judicial procedure in a republic in ancient India.
 - 5. Enumerate the different forms of republics obtaining in ancient India and give their chief characteristics.
- 6. Trace the history of Buddhist influence on political thought and institutions in ancient India?
 - 7. Describe and comment upon the procedure of deliberation in the Hindu Republics.

⁺ Hindu Polity-Jayaswal-"Between the two, I am like a mother of two gamblers, staking against each other, who can not wish for the Victory of one and the defeat of the other." (Page 176.)

सातवाँ ग्रघ्याय

राज्य के उद्देश्य और कत्त्व्य

(Aims & Functions of the State)

प्रस्तावना — प्राचीन भारत में राज्य का ख्रादर्श क्या रहा है यह स्पष्ट रूप से एक ही स्थान पर उपलब्ध नहीं होता । वैदिक साहित्य में इसका उन्लेख ख्रीर भी अधिक ख्रस्पट है; परन्तु यन तत्र जो प्रसंग प्राप्त होते हैं उनके ख्राधार पर राज्य के मुख्य उद्देशों का निश्चय किया जा सकता है। राज्य में शान्ति ख्रीर व्यवस्था बनाए रखना तथा मुरज्ञा व न्याय की स्थापना करना सबसे प्रधान कर्ता व्य समम्मे जाते थे। राज्य में सम्राट्या शासक को सर्वोच्च स्थान प्राप्त होता था ख्रीर वही राज्य का प्रतीक समभा जाता था। वरुण देवता की भाँति दुष्टों का नाश तथा सज्जनों का पालन करना उसका मुख्य उद्देश्य होता था। इस प्रकार भौतिक व्यवस्था के साथ साथ नैतिक प्रगति ख्रीर सामान्य कल्याण की ख्रोर भी राज्य का ध्यान ब्राक्षित रहता था। राजा परीचित् का राज्य इसीलिए विख्यात था कि वहाँ दूध और घी की सरिताए बहती थीं और जनता की भौतिक तथा नैतिक उन्नति राज्य का मुख्य जच्य था। यह समय वैदिक तथा उपनिषद्काल तक (600 B. C.) माना जा सकता है, जब राज्यों का मुख्य उद्देश्य जनहित—समाजकल्याण था। क्रमशः राजन नैतिक साहित्य के विकास के साथ साथ राजनैतिक विचार भी उन्नत और विस्तृत हुए और राज्य के चार मुख्य उद्देश्य माने जाने लगे—धर्म, द्र्यं, काम ख्रीर मोच । चारों उद्देश्यों का भिन्न अर्थ इस प्रकार लिया जाता था:—

(१) धर्म — प्राचीन भारत में धर्म का ऋर्थ बड़ा व्यापक था। संप्रदाय या पंथ के रूप में संकीर्ण ऋर्थ नहीं लिया जाता था। धर्म का तात्पर्य था धार्मिक पिनत्र वातावरण की रचना करते हुए, मानवीय स्वाभाविक गुणों का विकास करना, परस्पर सहायता द्वारा चिकित्सा छादि की व्यवस्था करना, सदाव्रत बंदवाना, समस्त धार्मिक संस्थाओं की सहायता करना, धार्मिक साहित्य और विज्ञान को संरच्या देना और सिहप्णुता तथा समन्वय का पाठ सिखाना—यह राज्य का धर्मसंबंधी उद्देश्य माना जाता था। किसी एक धर्म का पक्ष लेकर दूसरे धर्म की छालोचना करना या एक धर्म की ज्ञित पहुँचाकर दूसरे धर्म की उन्नित करना, कल्पनातीत विचार थे। उपर्श्वक्त व्यापक छार्थ में धर्म राज्य का प्रथम मुख्य उद्देश्य था।

- (२) अर्थ कृषि, उद्योग एवं व्यापार को उन्नत करना, अविकसित राष्ट्रीय साधनों का विकास करना, नई भूमि कृषि योग्य बनाना, बांध बनाकर नहरें निकाल कर नई नई योजनाओं द्वारा कृषि को वर्षा से स्वतंत्र बनाना, खनिज पदार्थों का अधिक विकास करना आदि अनेक साधनों से राज्य की अर्थ व्यवस्था सुदृढ़ बनाना राज्य का दूसरा मुख्य उद्देश्य था। अर्थ-व्यवस्था राज्य की आधारिशला होती है। इसके दृढ़ रहते राज्य के लिए कोई संकट भयानक नहीं हो सकता। इसी कारण यह राज्य का महत्वपूर्ण उद्देश्य स्वीकार किया गया था
- (३) काम प्राचीन भारत में 'काम' का अर्थ भी न्यापक रूप में लिया जाता था। जब राज्य में शांति और सुरक्षा स्थापित हो जाती थी तो जनता का जीवन वैभवपूर्ण बनाने की ओर भी ध्यान दिया जाता था। संगीत, तृत्यं, चित्रकारी ओदि लिलत केलाएँ तथा वास्तुकला का विकास भी ऐसे ही समय में होता था। इन सब साधनों से जनता का जीवन ऐक्वर्यशाली बनाया जाता था। पारिवारिक जीवन सुखपूर्ण तथा कलामय व्यतीत होता था। यही 'काम' के अन्तर्गत राज्य के मुख्य उहे एय थे, जिनके द्वारा प्रत्येक नागरिक को जीवन का कलामय उपभोग उपलब्ध होता था।
- (x) मोत्त-यह राज्य के उद्देश्यों में चरम लच्य था। जीवन के अनेक पत्तों में यह अंतिमं श्रीरं श्रत्यन्त त्रावश्यक समका जाता था। वैसे वंशिश्रमं धर्म का प्राधान्य भार-तीय जीवन में सदा से रहा है । इनमें सन्यांस आश्रम अ तिम और महत्वपूर्ण रहा है। परन्तु चारों ही श्रांश्रम सही श्रंर्थ श्रीर उचित हैं। से श्राचरण करने पर मौज्ञदायक माने गए हैं। एहस्थाश्रम सर्वोत्कृष्ट माना गया है, परन्तु उसपे त्याग की श्रपेत्ता श्रधिक की जाती है। फिर वानपस्थ श्रीर सन्यास क्रमशः सरल माने गए हैं। इन श्राश्रमों के द्वारा सबसे श्राधिक कार्य यह होता था कि वानप्रस्थ के समय व्यक्ति की समाज की नि:स्वार्थ सेवा करनी पड़ती थी श्रीर सन्यास के समय वह केवल नैतिक सेवा में संलग्न हो जाता था। वर्त्तमान समय की समस्याएँ वेरोजगारी, श्रीधक श्राबादी, निवास की कठिनाई, श्रर्थ-व्यवस्था की असमानता आदि उस समय दृष्टिगत नहीं होती थी। इस प्रकार जीवनकाल में तथा जीवन के बाद भी हर प्रकार से मोज्ञदायक व्यवस्था राज्य के उद्देश्यों में समिमिलित की गई थी। समाज की यह निष्काम सेवा एक वरदान होती है श्रीर धर्म उसमें श्रलीकिकता ला देता है। इस प्रकार भारतीय विचारकों ने राज्य का बहुत ऊँचा त्रादर्श सामने रखा है। व्यक्ति के सर्वागीण विकास द्वारा समाज का पूर्ण विकास करते हुए कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना प्रमुख उद्देश्य होता था। धर्म, अर्थ, काम और मोच्-इसके ऐसे अच्क साधन थे जो राज्य की सफलता के लिए अनिवाय भी थे। व्यापक और पर्याप्त भी।

कुछ लेखकों ने वर्णाश्रम धर्म को लेकर प्राचीन भारतीय व्यवस्था की कटु श्राली-चना की है। उनका विचार है कि इन मान्यताश्रों के श्राधार पर बाह्मणों को उन्चा श्रीर श्रूढ़ों को हर बात में नीचा बना दिया गया था। श्रूढ़ों को छदैव के लिए बाह्मणों का दास गान लिया गया था श्रीर हर प्रकार के उन्चें श्रीधकारों से वे वंचित रखे गये राज्य ने भी

उसका प्रतिपादन किया। इस विचार की अभिन्यिति मुख्य रूप से श्री अ जरिया ने अपनी पुस्तक 'The nature and Ground of Political Obligation in Hindu State' में की है। डा॰ ग्रल्टेकर ने यह विचार ग्रस्वीकार किया है। + उनका मत है कि उपर्युक्त बात उचित नहीं है। प्राचीन भारतीय परम्परात्रों तथा शास्त्रादि के अध्ययन से यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि यहाँ किसी भी धर्म या व्यवस्था द्वारा किसी दूसरे का पतन या शोषण नहीं किया गया। इसलिए यह मानना कि वर्णाश्रम के द्वारा एक वर्ण ने दूसरे का शोषण किया और यह शोषण राज्य ने मौन स्वीकृति द्वारा मान्य ठहराया, निराघार है। श्राधुनिक थुग की भाँति वह युग व्यवस्थापिकाश्रों में प्रचार या बोबणाश्रों द्वारा किसी नियम को मान्यता नहीं देता था। पहले हर परम्परा को सामाजिक स्वीकृति प्राप्त होती थी और बाद में राज्य द्वारा उसे अपनाया जाता था। डा॰ अल्टेकर ने ऐसे अनेक उदाहरण दिए हैं। उनमें से मुख्य निम्नलिखित हैं-(१) अंतर्जातीय विवाह एवं भोज-प्रचलित तो थे परंतु पहले समाज ने स्वीकार किये तत्पश्चात् राज्य ने भी उन्हें उचित माना । (२) विधवा स्त्री को उत्तराधिकार-पहले नहीं था परन्तु स्रावश्यकतानुसार बाद में स्वीकार किया गया। (३) साथ ही नियोग (Levirate) पहले मान्य था किन्तु बाद में निषिद्ध घोषितः किया गया। इस प्रकार समय और स्थिति के अनुसार नियमादि परिवर्त्त नशील रहते थे और राज्य सदैव जागरूक रहता था । आवश्यक नियमों को अपनाना तथा सारहीन अथवा घातक नियमों को निरस्त करना राज्य का ही कार्य था । मध्ययुग में हिन्दू समाज में कुछ संकीर्णताएँ बढ़ीं श्रीर उनसे सामाजिक जीवन में भी सीमाएँ श्रीर प्रतिवन्ध बढ़े; किन्तु यह सब सामा-जिक संकुचित मनोवृत्तियों का फल था, राज्य के प्रयत्नों का फल नहीं । ऐसे उदाहरण भी हैं जहाँ राज्य के प्रयत्न बहुत समय तक समाज में कार्यान्वित नहीं हो सके। शारदा एक्ट उनमें से एक है। नियम बन जाने पर भी जनता ने वर्गों तक उसका पालन नहीं किया। अतः यह सत्य है कि राज्य ने ये असमानताएँ न स्थापित की, न धर्म का अनुचित अर्थ लगाया । केवल सामाजिक मनोवृत्तियों के परिणामस्वरूप यह रिथति बनी । राज्य के उद्देश्य सदैव क चे श्रीर जन-हित तथा कल्याण के लिए अग्रसर रहे।

प्राचीत भारतीय राज्यों का स्वभाव — प्राचीत भारतीय राज्यों के उद्देश्यों में धर्म का स्थात होने के कारण अधिकांश यह शंका की जाती है कि ये धर्मराज्य (Theocracy) तो नहीं थे। इस शंका को और अधिक बल इस बात से मिलता है कि इन राज्यों में भी बासणों का महत्त्व अधिक था। परन्तु धर्मराज्य की विशेषताएँ दूसरी हैं। धर्मराज्य में धर्म का अध्यक्त ही राज्य का सम्राट् होता है। जैसे इस्लामी राज्यों में खलीफा, या वेटीकन राज्य में पोप (पादरी) होता है अधवा शासक गिरजाधर के एजेन्ट या सहायक के रूप में काम करता है; जैसे प्रवीं और ६वीं सदी में यूरोप में था। ऐसे राज्य में धर्माध्यक्त, नियमानुसार शासन न चलाने पर शासक को दिएडत कर सकता है। धर्माध्यक्त की आजाएँ शासक या सम्राट की आजाओं की अपेका अधिक बलवती एवं प्रभावशाली होती हैं।

⁺ State and Government in Ancient India-Page 45

प्राचीन भारत में ऐसा धर्मराज्य नहीं था । इस विवाद में शंका का आधार यह है कि कुछ स्थानों पर 'पुरोहित' को सम्राट् के दण्ड से परे माना गया है । + कहीं यह मान्यता है कि यदि राजा के पाम सुयोग्य ब्राह्मण पुरोहित नहीं है तो देवता श्रौर पितर उसके द्वारा किया हुआ तर्पण या उदक् स्वीकार नहीं करेंगे।× राज्यामिषेक उत्सव में भी ब्राह्मण का महत्व-पूर्ण स्थान था। यह भी मान्यता थी कि जो सम्राट् अपने पुरोहित को आदरपूर्वक प्रसन्न रखता है वह सरलता से अपनी जनता का स्वामी बन जाता है और अपने शतुओं पर विजय प्राप्त करता है । 🕂 इन उदाहरणों से यह लिचत होता है कि ब्राह्म एकाल (1: 00 B. C.) तक राजा पर पुरोहितों का प्रभाव रहा श्रीर इसके द्वारा राज्य पर भी अधिकार बना रहा। बाद में नित्रय और बाह्मणों में समसौता हो गया और दोनों एक दूसरे को अपने लिए सहारद बनाने लगे । ग्रेगरी सप्तम ने इसीलिए यह माना कि शासकत्व श्रीर धर्माध्यव्यत्व दोनों दैविक हैं श्रीर दोनों मानव की दोनों श्रांखों के समान हैं जो नितान्त त्रावश्यक हैं । भारतवर्ष में पुरोहित का स्थान तो उँचा था ही, उसे निय-मादि के संबंध में भी व्यापक अधिकार थे। वर्णाश्रम धर्म भी वह संशोधित कर सकता था। कर तथा अन्य दण्ड से वह मुक्त था। मीर्यकाल में ''धर्ममहामात्रा'' तथा गुप्तकाल में ''विनय स्थितिस्थापक" की नियुक्तियाँ धर्म नियंत्रण तथा पथ-प्रदर्शनिए के लिये ही होती थीं। इससे भारतीय राज्यों को धर्मराज्य समक्तने का भ्रम हो सकता है। परन्तु यह विचार बहुत बढ़ाकर स्त्रतिशयोक्ति कर दिया गया है । वास्तव में शासक ही ब्राह्मण पर शासन चलाता था। अक्ष सम्राट् ब्राह्मण को निष्कासित (Expel) भी कर सकता है। श्रतः यह मानना भ्रान्तिपूर्ण होगा कि वैदिक काल में सम्राट्या राज्य, ब्राह्मणों के हाथ में थे श्रीर इस कारण धर्मराज्य कहे जा सकते हैं। राज्य तो वास्तव में जनता की इच्छ का सामाजिक प्रयोग था। अत: प्राचीन भारत में "धर्मराज्य" नहीं थे, केवल वैसे प्रतीत होते थे, क्योंकि ब्राह्मणों को कुछ विशेष अधिकार जैसे कर या मृत्युदण्ड से मुक्ति आदि प्राप्त थें । फिर भी वास्तविक स्थिति इन सैद्धान्तिक विचारों से दूर थी श्रीर ब्राह्मणों का प्रभाव क्रमशः न्यून होता जा रहा था । विशेषकर ही॰ ई॰ पू॰ चतुर्थ शताब्दी में धर्म का यह प्रभाव श्रीर भी कम हो गया । वैदिक कालीन बिलदान स्वयं घ्यास्पद बनते गए श्रीर राजनीति एक विज्ञान के रूप में विकसित होने लगी। शासक वर्ग ने वेद श्रीर उपनिपदों की श्रपेद्धा राजनीति का अध्ययन श्रारम्भ किया श्रीर कमशः धर्म का स्थान गीए। बनता गया । ईसाई युग के श्रारंभ में राज्य का धार्मिक पत्त कमज़ीर हो गया। सम्राट्या शासक का मुख्य कर्ज व्य समस्त जनता को समान अधिकार देना माना जाने लगा और धर्म के त्तेत्र में किया जाने वाला कार्य राज्य के

⁺ गौतम धर्मस्त्र (500 B. C.) "राजा वै सर्वस्येष्ठे नहारावर्जन्"

[×] आत्रेय बाह्मण-"न ने अपुरोहितस्य देवा बलिमश्तुवन्ति ।"

[÷] ऋग्वेद — "तस्मिन्वशः स्वयमेवानमन्त यस्मिन्वतः राजनि पूर्वेमेति । 507-9 स इन्द्राजा प्रति जन्यानि विश्वा शुष्मेंग तस्यौ अभि वीर्येगः ।

^{*} यदा वै राजा कामयते अथ नाहाण जिनाति" III 9-14

श्रधिकारियों द्वारा होने लगा । राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं होता था । उसके लिए सब धर्म समान थे । इसलिए यह स्पष्ट निर्णय किया जाता है कि भारतवर्ष में धर्मराज्य नहीं था।

कत्त व्य (Functions)—प्राचीन भारत में राज्य के उद्देश्यों पर विचार करने के परचात, कर्त व्य पर विचार करना शेष रहता है। आधुनिक काल में राज्य के कर्त व्य दो भागों में बाँटे जाते हैं-अनिवार्थ और। ऐच्छिक । अनिवार्थ कर्त व्य दो हैं जो राज्य का अस्तित्व बनाए रखने के लिए अति आवश्यक हैं; जैसे-पुरत्ता, विदेशी संबंध, शांति-व्यवस्था आदि। ऐच्छिक कर्त व्य, वे हैं जिन्हें करने से जनता का अधिक कल्याण हो सकता है, समृद्धि बढ़ सकती है; जैसे-शित्ता, स्वच्छता, व्यापार संचालन, यातायात के साधन, वनों व खनिज पदार्थों का विकास आदि। प्राचीन भारतीय प्राप्त सामग्रों के आधार पर यह कहा जाता है कि दीर्घकाल तक भारतीय राज्य केवल अनिवार्थ कार्य ही करते रहे। ने वैदिक काल के राज्य शांति स्थापना, विदेशी आक्रमणों से नागरिकों की सुरत्ता, नियमों का पालन आदि कार्य करते थे। उसके परचात् राज्यों का कार्यच्चेत्र व्यापार बना । महा-भारत और अर्थशास्त्र आदि राजनैतिक ग्रन्थों के द्वारा यह बताया जाता है कि वैदिक काल तथा मीर्यकाल के मध्य में ही यह विकास हुआ। इस विकास का क्रम अभी तक स्पष्ट रूप से जात नहीं है।

उपर्युक्त साधनों के आधार पर यह सिद्ध किया गया है कि राज्य का कार्यक्ति व्यापक था। मानव जीवन से सम्बन्धित सभी क्षेत्रों में राज्य का अधिकार था श्रीर कर्त व्य-पालन किया जाता था। सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक जीवन के पक्त भी राज्यान्तर्गत ये। व्यक्तिवादी सिद्धान्त (Laissez Faire) की भाँति राज्य को श्रीनवार्य दोप नहीं माना जाता था, जिसके द्वारा राज्य का क्षेत्र भी श्रत्यन्त सीमित बनाने का दम्भ किया जाता है। प्राचीन काल के राज्य मानव जीवन के प्रत्येक पक्त की व्यवस्था करना चाहते थे। इसीलिए सब धमों को समान सुविधाएँ देना, नैतिकता, पवित्रता और सहित्युता का वातावरण बनाना, सामाजिक व्यवस्था करना, शिक्ता, कला व विद्वत्ता को प्रोत्साहित करना, विद्यालय, पाठ-शालाएँ तथा श्रन्य शिक्ता संस्थाएँ स्थापित करना श्रादि राज्य के सुख्य कर्तां व्य माने गए थे। इस प्रकार पाचीन भारतीय राज्य 'पुलिस राज्य' (Police State) न होकर एक वास्तविक कल्याग्रकारी राज्य (Welfare State) थे। जातक श्रीर पुराण भी इसी विचार की पुष्टि करते हैं। इसलिए जनता के लोक व प्रश्लोक का हित साधन गरना, समस्त मानव मात्र की मलाई का प्रयत्न करना, किसी प्रकार का वर्ग, जाति श्रीर धर्ममेद न मानवा तत्कालीन राज्य की प्रमुख विशेषताएँ थीं।

वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए प्राचीन राज्यों के कर्तव्यों को कीटिल्य के मतानुसार इम निग्नांकित भागों में बॉट सकते हैं:—

⁺ State & Govt. in Ancient India-Altekar-Page 53

- (१) आधिक कत्त वय (Economic Functions)
- (२) सामाजिक कत्त व्य (Social Functions)
 - (३) सांस्कृतिक कत्त व्य (Cultural Functions)
 - (४) शिचा सम्बन्धी कत्त व्य (Educational Functions)
 - (४) परोपकारी कत ब्य (Philanthropic Functions)
 - (६) श्रन्य कृत्त व्य (Miscellaneous Functions)
- 🗼 : (१) त्र्यार्थिक कत्त्रेव्य-- त्र्यर्थशास्त्र राजनैतिक जीवन का त्र्याधार माना जाता था। . त्राज भी ऋर्थव्यवस्था ही राज्य का प्राण समक्ती जाती है। राजनीति ऋौर ऋर्थव्यवस्था के घनिष्ठ सबंघ के कार्ण ही कौटिन्य ने ध्रुत्रपनी राजनीति की पुस्तक का नाम भी अर्थशास्त्र ही रखा था। कौटिल्य के मतानुसार जनता के सम्पूर्ण आर्थिक जीवन की व्यवस्था कराना राज्य का प्रमुख कर्ताच्य था। सुमस्त सम्भव साधनों द्वारा जनता की समृद्धि करना राज्य का उत्तरदायित्व था। राज्य के कृषक समुदाय को समस्त राज्य में समान रूप से निवासित करना चाहिए था। इसलिए अधिक आबादी वाले भागों से उन्हें हुटाना तथा कम अवादी वाले भागों में आमन्त्रित करना और आवश्यकतानुसार नए ग्राम स्थापित करना भी राज्य का कर्त व्य होता था। इसके अतिरिक्त "अध्यत्-प्रचार" नामक पुस्तक में कर्मचारियों के दो प्रकार के कर्ताच्य बताए गए हैं। प्रथम-राज्य का प्रशासन और द्वितीय-राज्य की स्रोर से उद्योग व व्यापार की व्यवस्था करना। इस प्रकार राज्य के उद्योग-धन्धों की व्यवस्था ख्रौर उचित नीति निर्घारित करना राज्य का ही कत्त व्यथा। कुषि के ज्ञेत्र में जो अधीत्तक (Superintendent) होता था, वह अन्य कार्यों के साथ राज्य की भूमि (Crown Lands) में खेती करवाने की व्यवस्था भी करता था। इसके लिए राज्य अपने अलग यंत्र अरि साधन जैसे वैल आदि भी रखता था। अकाल के समय ये ही राज्य भंडार खोल दिए जाते थे, जहाँ प्रतिवर्ष की उपज सुरचित रखी जाती थी।

उद्योग (Industries) भी राज्य द्वारा नियंत्रित होते थे। खनिज का स्वामित्त्र राज्य का ही माना जाता था श्रीर उनकी उन्नति करना राज्य का ही कर्त ज्य था। परंतु उनकी कार्य प्रणाली दूसरे प्रकार की थी। साधारणतः जनता द्वारा उनका उपयोग होता था। कीटिल्य कहता है—'राज्य' जनता को खानों के लिए श्राज्ञापत्र (Licence) दे देता था किन्तु फिर खानों में नियमविरुद्ध काय करने वालों को बेगार (Forced labour) का दण्ड मिलता था। श्रिधकांश व्यापार केन्द्र के श्रधीन था श्रीर कुछ प्रदाशों के व्यापार में राज्य श्रपना एकाधिकार रखता था; जैसे नमक श्रादि। जन का उपयोग भी राज्य स्वयं ही करता था। इसकी व्यवस्था के लिए पूरा प्रजन्य किया जाता था। व्यापार के चेत्र में, मृत्य निर्धारण तथा लाभांश राज्य द्वारा निश्चित किया जाता था। स्थानीय वस्तुत्रों में निर्धारित मृत्य पर ५ प्रतिशत तथा बाह्य उत्पादित वस्तुत्रों पर १० प्रतिशत लाभ स्वीकृत किया जाता था। इस व्यवस्था के विरुद्ध मृत्यवृद्धि या लाभवृद्धि करने को श्रपराध माना जाता था। चाहे वह किचित्मात्र ही क्यों न हो। इसके लिए ५ से लेकर २०० पाणा (तरकालीन मुद्रा)

तक अर्थदण्ड दिया जा सकता था। व्यापारिक चेत्र में भी पुरचा का भार राज्य का या और व्यापार में किसी भी प्रकार की चित राज्य द्वारा पूरी की जाती थी। इस प्रकार राज्य एक बीमा कम्पनी की तरह कार्य करता था। × अिमकों की पुरचा का भार भी राज्य पर था। उन्हें चिति पहुंचाने वाले पर १००० पाणा तक अर्थदण्ड की व्यवस्था थी। तेल, खाँड आदि का व्यवसाय राज्य के अधीचकों के मुपुर्द था तथा भीलों व तालावों में मछली, नौका, सब्जी आदि का व्यवसाय भी सम्राट् के ही अधीन था। आर्थिक चेत्र में राज्य पूर्ण रूप से कर्च व्यपालन करता था और कोई सीमा या बन्धन राज्य के अधिकारों पर नहीं था। राज्य की समृद्धि और जनता के जीवन की संतुलित अर्थव्यवस्था रखना-मुख्य लच्च था।

- (२) सामाजिक कर्त व्य-राज्य के सामाजिक जीवन में कई महत्वपूर्ण कार्य सरकार द्वारा किये जाते थे। समाज की व्यवस्था साधारण नियमानुसार होती थी। नियमों का
 उल्लंघन अपराध माना जाता था। समाज का नैतिक स्तर बनाए रखना भी राज्य का
 कर्त व्य था। इसलिए संतान व माता-पिता के संबंध, पित-पत्नी के संबंध ठीक रहना
 आवश्यक था। सामाजिक दुर्णुणों पर राज्य नियंत्रण रखता था। शराव घर, वेश्यागृह,
 जुआघर (Gambling House) तथा अन्य ऐसे स्थानों के अधीक्षण के लिए "नैतिक
 अधीक्तक" (Superintendents of Morality) रक्खे जाते थे। जुमावरों की जीत का
 ध प्रतिशत राज्य को मिलता था। इस प्रकार सामाजिक कर्त्त व्य का चेत्र व्यापक था। परन्त
 इसका यह अर्थ नहीं लिया जाना चाहिए कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता सीमित थी। जैसे आधुनिका
 काल में भी सर्वोच्च प्रजातंत्रात्मक राज्यों में जनहित और समाजकल्याण के लिए हर प्रकार
 के नियम और प्रतिबन्ध लगाए जाते हैं। वही स्थिति प्राचीन भारत में थी।
- (३) सांस्कृतिक कर्त वय प्राचीन भारत का राज्य संस्कृतिप्रधान संस्था थी। उस समय जनता की संस्कृति को समुन्नत करते रहना भी राज्य का कर्त व्य था। इसलिए वर्णाश्रम धर्म तथा श्रन्य सांस्कृतिक कार्यों पर राज्य नियंत्रण रखता था। कौटित्य के मतानुसार राज्य का कर्त व्य था कि धर्म पर कुछ प्रतिकृष्ध लगाए जावें; जैसे साधू बनने के लिए निश्चित श्रवस्था श्रीर स्थिति निर्धारित की जाय। इसी प्रकार पारिवारिक वातावरण उपयुक्त बनाए रखने के लिए यह श्रावश्यक रखा जाय कि भाई-बहिन, चाचा-भतीजे, पिता-पुत्र पर स्पर एक दूसरे की धोखा न हैं, न सूठ बोलें। स्त्रियों की सुरत्ता का विशेष प्रवन्ध करना राज्य का कर्त व्य था। महिलामान्न का सम्मान करना व प्रतिष्ठा की रत्ता का भार राज्य पर प्राना गया था। किशोर बालिकाश्रों की सुरत्ता, प्रीमयों के संबंध, संबंधविच्छेद या विवाह-श्रादि की व्यवस्था भी राज्य द्वारा की जाती थी। जनता में सांस्कृतिक चेतना बनाए रखने के लिए सब प्रकार की कलाश्रों का विकास हो, यह च्यान रखा जाता था। उत्य कला, संगीत कला, नाट्य कला श्रादि इसीलिए बहुत उन्नत थी। मनो-रंजन तथा विनीद श्रादि की व्यवस्था भी राज्य करता था। वेश्यावृत्ति की प्रथा यद्यि बुरी मानी

^{× &}quot;State thus played the role of a modern Insurance Company".

जाती है परन्तु प्राचीन भारत में यह भी राज्य द्वारा पूर्ण रूप से नियंत्रित थी। इस प्रकार राज्य सांस्कृतिक च्रेत्र में अपने कर्ता व्यपालन में सच्चे थे।

- (४) शिचा संबंधी कर्त वय—शिचा के चेत्र में राज्य सदैत से उदार रहता श्राया है। शिचा को प्रोत्साहित करने के लिए बड़ी बड़ी शिचा संस्थाश्रों प्रोर अकादिमयों की स्थापना की जाती थी। उच्चकोटि के विद्वानों और कलाकारों को राज्य द्वारा संस्कृण दिया जाता था। अच्छे साहित्य, काव्य अथवा शास्त्रों की रचनाएँ पुरस्कृत की जाती थीं। गुरु का स्थान सर्वत्र ऊँचा और आदरणीय माना जाता था। इस प्रकार अत्यन्त उदार दृत्ति से शिचा संबंधी कार्य करते हुए भी तत्कालीन राज्य इन शिच्एण संस्थाओं पर अपना नियन्त्रण नहीं रखता था। आजकल भी भाँति शिचा संचालक और उसके अधीनस्थ कर्मचारियों के समूह द्वारा राज्य इन संस्थाओं को नियंत्रण में नहीं रखता था। ।
- (४) परोपकारी कर्त व्य—राज्य की स्रोर से परोपकार के त्रेत्र में कई कार्य किये जाते थे। विश्रामग्रहों की स्थापना, सदाव्रत की व्यवस्था, चिकित्सालय खोलना, प्राकृतिक संकट के समय सहायता ×, स्रनाथालय खोलना, गर्भवती स्त्रियों के लिए सहायता, बृद्ध व स्रसहायों की व्यवस्था तथा दुखी और पीड़ित लोगों की सहायता के लिए व्यवस्था करना राज्य का कर्त व्य होता था। जनता की धार्मिक संस्थाओं को सहायता देना तथा धर्म की प्रवृत्तियों का प्रोत्साहित करना भी राज्य का कर्त व्य था। परन्तु सब धर्म समान समके जाते थे।
- (६) श्रान्य कर्त व्य—उपर्युक्त कर्त व्यों के श्रातिरिक्त मुख्य प्रशासनीय कर्त व्य प्रधान थे। जहां व्यवस्थापिका श्रीर कार्यपालिका श्रीर त्यायसंबंधी कर्त व्य राज्य हर प्रकार ध्यान से करता था श्रीर इन कर्तव्यों का पालन ही राज्य को सफल श्रीर श्रासफल बनाता था। इन कार्यों का सम्पादन राज्य स्वयं न करके श्रपने श्राधीनस्य श्रानेक श्रांगों द्वारा संचा-लित करवाता था। जिनका वर्णन श्रागे यथोचित स्थान पर किया जायगा (श्रध्याय-प्रशासन)।

राज्य के ऊपरिवर्णित कर्तां थों का अध्ययन करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि राज्य का स्तेत्र व्यापक था। परन्तुं पिर भी विकेन्द्रीकरण का सिद्धान्त अपनायां गया था। स्थानीय संस्थाएँ; जैसे पंचायत, अंगी, पूग आदि को अपने चेत्र में पूर्ण स्वाधीनताएँ प्राप्त थीं। इन संस्थाओं के सहयोग द्वारा ही राज्य केवल वे कर्तां व्या करता था जो समाज के लिए आव-श्यक तथा कल्याणकारी थे। व्यक्ति की स्वतंत्रता भी पूर्ण रूप से सुरक्ति थी। डा॰ अल्टेकर का मत है कि प्राचीन भारत में राज्य का स्तेत्र इसलिए व्यापक था कि जनता, राज्य द्वारा

⁺ डा॰ श्रत्टेकर-State & Govt. in Ancient India-Page-55

x संबंद कई प्रकार के माने गए हैं; जैसे-महामारी, बाद, टिट्डी, श्रकाल, भूकरप, वर्षाधिक्य, श्राप्ति श्रादि ।

अपने हितों की सुरजा में अधिक विश्वास करती थी, व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं के प्रति राज्य की स्रोर से उसे कोई चिन्ता नहीं थी।+

त्राधितिक काल में कुछ भारतीय विद्वानों ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि प्राचीन भारत में "राज्य-समाजवाद" अथवा (State Socialism) था, जहाँ उत्पादन के साधन तथा वितरण राज्याधीन था। परन्तु यह विचार उचित नहीं है। प्राचीन भारत में सीमित व्यवसायों में राष्ट्रीयकरण के प्रयोग तो किये गए थे और वितरण में भी सिद्धान्त रूप में समानता को उचित माना था। किन्तु केवल इसी आधार पर पूरी व्यवस्था की "राज्य-समाजवाद बताना तो सत्य से दूर हो जाता है। डा० वेनीप्रसाद के मतानुसार" हिन्दू राज्य केवल सांस्कृतिक राज्य ही नहीं था वरन् पूर्ण रूप से व्यापक नैतिक और आध्यात्मिक समुदाय था। सबसे अधिक गौग्व का विषय तो यह था कि धार्मिक तत्परता के होते हुए भी, जिसके कारण यह अनेक अवसरों पर प्रभावित हुआ, साधारणतया यह सब प्रकार के धार्मिक विश्वासों के प्रति सहिष्णु था। श्री वन्द्योपाध्याय के मतानुसार अर्थशास्त्र में वर्णित सरकार एक विशेष प्रकार का प्रशासनीय पितृवाद है जो वर्ग संबंध निर्धारित करता है और अपने साधनों का उपयोग समाज के बल्याण के लिए करता है। इस प्रकार राज्य के कर्ता व्यापक के कर्ता व्यापक करते हुए यह कहा। जा सकता है कि प्राचीन भारतीय राज्य एक आदर्श कल्याणकारी राज्य था।

सन् १६५५ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल ने जो समाजवादी सामाजिक योजना का प्रस्ताव स्वीकार किया, वह हमारी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर ही आधारित है। प्राचीन राजनैतिक साहित्य में कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक अनुपम और अधिकृत प्रथ है। उसमें वर्णित प्रशासनीय आयोजन व्यावहारिकता पर आधारित है, केवल सैद्धान्तिक नहीं। इस-लिए हमारी राष्ट्रीय सरकार द्वारा अपनायी नीति व योजना, पाश्चात्य देशों से ली हुई नहीं वताई जा सकती, बल्क जाज्वल्यमान ऐतिहासिक प्रम्पराओं से प्राप्त की हुई सिद्ध होती है। भारत के विख्यात इतिहासक और कटनीतिविशारद सरदार पनिक्कर ने इस संबंध में कहा है कि भारत ने अपने राजनैतिक विचार और सिद्धान्त अपने देश की परम्पराओं से उत्तराधिकार में प्राप्त किए जो उसी प्रकार मौलिक हैं जैसे पश्चिम का कोई भी मौलिक विचार, और समस्त मूलभूत प्रश्नों और समस्याओं का विवेचन और विचार-विमर्श उसी

^{🕂 🏻} डा॰ श्रहदेवारे—State & Govt. in Ancient India—Page. 55.

Dr. Beni Prasad-State in Ancient India. "Hindu state was not merely a culture state but an all pervasive moral and spiritual association. The glory of the situation was that inspite of the missionary zeal which moved its spirits at several epochs, it was generally tolerant of all forms of religious belief."

^{*} N. C. Bandyopadhyaya—"All that we can do is to describe the Arthasastia government as a peculiar type of administrative paternalism which regulated the relation of classes, and spent its resources for the welfare of the community."

स्वतंत्रता, निर्भयता तथा गहराई से किया जाता है जैसे पश्चिप में । इसके अतिरिक्त राज्य के प्रशासनीय और आर्थिक कर्ताच्य पर इस प्रकार विशेष बल दिया गया है, जैसा यूरोप के १६वीं सदी के पूर्व के लेखकों को ज्ञान भी नहीं था। + अतः हमारा स्वतंत्र किशोर भारत गणराज्य वृद्ध यूरोप प्रजातंत्र राज्यों से किसी प्रकार कम नहीं है।

प्रश्न

- 1. "The state in ancient India was regarded as the centre of society and the chief instrument of its welfare." Explain and amplify the above statement.
- 2. Discuss the functions of the state as derived from the Arthashastra.

⁺ Panikkar—"India has inherited a tradition in political thought which is at least as original as anything in the West, which discusses freely, frankly and with deep insight all the fundamental problems relating to political communities and further emphasizes the administrative & economic functions of a state in a manner generally unknown to European writers before the 19th century.

ग्राठवां ग्रध्याय

ं सम्राट्का पद

(Kingship)

प्रस्तावना—यद्यपि प्राचीन भारत में राज्य के अनेक रूप विकसित होते रहे हैं, तथापि राजतंत्र या उपतंत्र (Monarchy) का बहुत अधिक प्रचलित रूप रहा है। उप या सम्राट् के संबंध में बहुत ऊ चे ऊ चे आदर्श वर्णित हैं। अतः सम्राट् का पद क्या था, किस प्रकार इसका उपयोग होता था, कीन कीन से कार्य इस पद से संबंधित थे, आदि बड़े रोचक प्रश्न हैं, जिनका उत्तर प्राचीन भारतीय अंथों में पर्याप्त संतोषजनक ढंग से मिलता हैं। उन्हीं का अध्ययन इस अध्याय में किया जायगा।

विकास - सर्वप्रथम यह प्रश्न उपस्थित होता है कि सम्राट् के पद की रचना किस प्रकार हुई ? यद्यपि राज्यों की उत्पत्ति का वर्रान करते हुए कुछ सिद्धान्तों का अध्ययन हम कर चुके हैं; परन्तु सम्राट् के पद की रचना का प्रश्न किर भी अलग से लिया जा सकता है। वैदिक साहित्य में यह रचना तीन प्रकार से बताई गई है। एक तो यह कि देवता और असुरी के बीच निरन्तर होने वाले युद्धों में देवता ही सदैव पराजित होते रहते थे। इस पराजय का कारण, उन्होंने सम्राट् या नेतृत्व का श्रभाव निश्चित किया श्रीर सोम चन्द्रमा) को श्रपना अध्यक्त (King) बनाया। दूसरे स्थान पर यह प्रसंग मिलता है कि देवताओं ने इन्द्र की अपना सम्राट् बनाया; क्योंकि वह सबमें अधिक योग्य और युवक था। तीसरे स्थान पर वरुण की सम्राट् वनने की श्रिभिलाषा का प्रसंग मिलता है जो प्रजापित से गुरुमंत्र लेकर देवतात्रों का मान्य सम्राट्चना । उपर्युक्त प्रसंगों से यह प्रकट होता है कि सम्राट का पद सैनिक नेतृत्व की त्र्यावश्यकता के कारण त्र्यस्तित्व में त्र्याया । इसीलिए राजा को सैनिक अध्यत्त माना गया। शक्ति के आधार पर शासन होने के कारण ही सम्राट् स्वयं भी शक्ति-शाली आदर्श पुरुष होता था और योग्य संतान होने पर वही पद उत्तराधिकार द्वारा भी हस्तांतरित होता था । प्राचीनकाल में राज्याभिषेकः या बाजपेय यज्ञ के बाद रथ की दौड़ होती थी स्त्रीर उसमें सम्राट् ही प्रथम स्त्राता था-यह सम्राट् के लिए प्रतीकात्मक ही था। कुछ विचारकों का मत है कि वैदिक काल में भारतीय समाज पितृप्रधान था और इसी का विक्रसित रूप अर्थात् कुलों के योग से वंशा ग्रीर वंशों के योग से जाति (Tribe) नन

कर, राज्य वन गया जहाँ कुलपित और जनपित ही अध्यत्त होते थे । वे भी रथ दौड़ आदि में भाग लेते थे और इसी का अ तिम रूप अध्यत्त, सम्राट् या राजा कहलाया । वैदिक साहित्य धार्मिकता लिये हुए है किन्तु फिर भी सम्राट् का पद धर्म से संबंधित नहीं बताया गया है। वैदिक काल में जाति प्रथा पुष्ट नहीं हुई थी, इसलिए तत्कालीन राजाओं की जाति के संबंध में कोई प्रसंग नहीं है । बाद में जब जातियाँ पूर्ण विकसित व व्यवस्थित हो गई तब राजा चित्रय जाति के ही होने लगे जो सैनिक कोशल और युद्धविद्या के विशारद होते थे। बाद में चित्रय, बाह्मण, वश्य, सूद्ध तथा अनार्य भी राजा बनने लगे। सीथियन, पारिथयनस, हुण आदि के राज्य अनार्य राज्यों के प्रमाण हैं। राजा शब्द धीरे धीरे सभी शासकों के लिए प्रयोग में आने लगा।

सम्राट की नियुक्ति के प्रकार—इस विषय के लेखकों में सम्राट् की नियुक्ति के विषय में गहरा मतमेद है । यह पद निर्वाचन द्वारा नियुक्त होता था अथवा उत्तराधिकार द्वारा श्रीर किस प्रकार के नियमों द्वारा ये प्रकार कार्यान्वित होते थे, इस पर लोगों के विचार मिन्न मिन्न हैं। फिर भी प्राप्त प्रसंगों के आधार पर यह सिद्ध होता है कि कुछ स्थानों पर. यह पद निर्वाचन द्वारा ही निश्चित किया जाता था । प्रारंभिक वैदिक काल में निर्वाचन प्रया प्रचलित थी । ऋग्वेद में यह प्रसंग त्राता है कि "जनता सम्राट को चुनती थी।" + किन्तु डा॰ श्रुंक्टेकर का मत है कि यद्यपि यह प्रसंग स्पष्ट वर्णन करता है कि जनता सम्राट्का, निवीचन करती है किन्तु फिर भी इसकी महत्ता इसलिए कम हो जाती है कि निर्वाचक जनता इस अवसर पर भयभीत बताई गई है। यदि सम्राट् जनता के मत द्वारा निर्वाचित होता था तो जनता को सम्राट् से डरने की क्या त्रावश्यकता थी। 🗙 इस प्रकार यह सम्राट के निर्वाचन को एक श्रीपचारिकता का रूप ही प्रदर्शित करता है । दूसरा प्रसंग अथर्ववेद में है जिसका तात्पर्य है कि राज्याभिषेक के योग्य व्यक्ति जनता द्वारा निर्वाचित होना चाहिए। : तीसरा प्रसंग शतपथ बाहा ए में इस प्रकार है कि शासक वही बन सकता है, जिसका नेतृत्व दूसरे सम्राटी द्वारा स्वीकार कर लिया जाय । क्षेत्र अर्थात् –शासक का निर्वाचन एक प्रथा थी । यह संभव है कि समय और युग के अनुसार इसका महत्व न्यूनाधिक होता रहा हो। निर्वाचक मगडल भी परिवर्त नशील रहा है। कभी संपूर्ण जनता और कभी चुने हुए कुछ सामन्त वर्ग के लोग, तो कभी कुछ सामन्त श्रीर जनता के मुख्य प्रतिनिधि लोग इसमें भाग लेते रहे हैं। कालान्तर में यह निर्वाचन एक श्रीपचारिकता मात्र रह गई होगी जिसमें मतदाता शासक से प्रभावित होने के कारण भय का अनुभव करते दिखाए गए हैं। यह निर्वाचन कई स्थानों पर शुद्ध रूप में भी रहा होगा, परन्तु एक अपवाद के रूप में; साधारण लोकप्रिय प्रथा के रूप में नहीं । प्रारंभिक वैदिक काल में ही यह प्रथा एक प्रकार से पुरानी पड़

⁺ ता ई विशो न राजानां षृणाना वीभत्सवो अप वृत्रादित्य्वन् । X 124. 8.

[×] State & Government in Ancient India-Foot Note-Page 75-Dr. Altekar

[÷] त्वां विशो वृणतां राज्याय । III 4. 2.

^{*} यस्मै वै राजानो राज्यमनुमन्यन्ते स राजा भवति न स यस्मै न । रात्रस्य नागाग, IX. 3. 4 5.

गई थी। फिर भी सम्राट को निष्कासित करना, अपदस्थ करना अथवा निष्कासित सम्राट को पुन: निर्वाचित करना—य जनता के मान्य अधिकार ये और जनता या जनता की प्रति-निधि सभाए पूर्ण रूप से इनका प्रयोग करती थीं । एक प्रसंग भी है जहाँ राजतंत्र या सम्राट् का पद उत्तराधिकार के द्वारा प्राप्त होता था । पिता के पश्चात पुत्र को ही राज्य का सम्राज्ञीय पद प्राप्त होता था। पुरु राजाओं में चार-पाँच सदियों तक यह प्रथा चली श्रीर लगभग चार सदी तक त्रित्सस राजात्रों के यहाँ भी यही प्रथा रही। त्रात्रेय बाहाण का यह प्रसंग कि ''राजानं राजपुत्रं'' अर्थात् नया राजा स्वयं राजा का ही पुत्र था । इस प्रकार सम्राट या राजा का पद पारंभ में निर्वाचित और उसके पश्चात् उत्तराधिकार द्वारा निर्धारित होता रहा है। डा॰ श्रार॰ सी॰ मजूमदार श्रीर डा॰ जायसवाल ने यह स्वीकार किया है कि राजा का पद प्रधान रूप से वैदिक काल में तो निर्वाचित ही होता था; परन्तु डा० अल्टेकर इस विचार से सहमत नहीं है। + उत्तराधिकार की प्रथा भी निश्चित नियमों द्वारा संचालित होती थी। साधारणतया ज्येष्ठ पुत्र का ग्राधिकार मान्य होता था ग्रीर इसमें भी जनता की स्पट्ट या मौन स्वीकृति आवश्यक होती थी । सम्राट् प्रतीप और य्याति का उदाहरण स्पष्ट है । उन दोनों ने अपने छोटे पुत्रों क्रमशः शान्तनु और पुर को राज्याधिकार देने के विचार से मुकुट पहनाना चाहा और उनसे बड़े पुत्रों का अधिकार रह कर दिया। तब जनता ने राजप्रासाद में एकत्र होकर इस विषय में प्रश्न किया कि ऐसा क्यों हो रहा है ? राजा भतीप ने उत्तर दिया कि शान्तन के बड़े भाई कोड के रोग से पीड़ित हैं, इसलिए उन्हें सम्राट् का पद नहीं दिया जा सकता था । ययाति ने उत्तर दिया कि मेरे श्रन्य समस्त पुत्रों ने श्रपनी युवावस्था की मेरी वृद्धावस्था से परिवर्तित करना श्रस्वीकार कर दिया है, इसलिए में उन्हें सम्राट्का पद नहीं देना चाहता। इस प्रकार संतीयजनक उत्तर सुनकर जनता संतुष्ट हो गई। इन उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि जनता के कुछ अधिकार तो थे परन्तु ने अधिकांश केवल औपचारिक रूप में थे और सम्राट् के पद के लिए साधारणतः ज्येष्ठता का नियम (Law of Primogeniture) पालन होता था । इन्नाकु राजाक्री के परिवार का वंशवृद्ध भी यह सिद्ध करता है कि उत्तराधिकार इसी नियम द्वारा संचालित होता था एवं जनता की निर्वाचन का कोई श्राधिकार नहीं था । डा॰ मजूमदार ने यह विचार न्यक्त किया है कि ईसा के १३० वर्ष बाद रुद्रदमन, ईसा के पश्चात ६०६ में हर्षवर्द्धन तथा× ई॰ प॰ ७५० में गोपाल को जनता के चुनाव द्वारा ही राजा का पद प्राप्त हुआ था। डा॰ अल्टेकर ने भी यह स्वीकार किया है कि रुद्र दमन और गोपाल को जनता ने ही निर्वाचित किया था । परन्तु इस वर्णन की गंभीरता में उनका विश्वास नहीं है; क्योंकि जुनागढ़ के शिलालेख में यह भी अ कित है कि उद्रदमन अपने पराक्रम के बल

⁺ State & Govt. in Ancient India-Dr. Altekar-Page 76 [Dr. R.C. Majumdar's book-corporate & Dr. Jayaswal's-Hindu Polity deserves study in this connection]

[×] Corporate life-Majumdar R. C. (Page 112)

[.] Gopala-was the founder of Pal Dynasty in Bengal.

पर सम्राट् बना । में यदि कोई उत्तराधिकारी नहीं होता था तो सम्राट् के उच्च श्रिधिकारी, मंत्रिगण श्रादि उसी सम्राट् के संबंधियों में से किसी योग्य व्यक्ति को इस पद के लिए निर्वाचित करते थे। परन्तु ६०० वर्ष ईसा के परचात् से तो उत्तराधिकार का सिद्धान्त ही कार्यान्वित होता रहा श्रीर १२वीं सदी के इतिहासकारों को तो सम्राट् का पद निर्वाचित होने की बात बड़ी श्राश्चर्यजनक श्रमुभव हुई। × उत्तराधिकार के संबंध में कुछ श्रीर भी स्पष्ट श्रीर स्वीकृत परिभाषाएँ थीं। ज्येष्ठ पुत्र के सम्राट् बन जाने के बाद दूसरे भाइयों को भी गवर्नर श्रादि के पदों पर उसी जगह नियुक्त कर दिया जाता था। जातक श्रन्थों में ऐसे श्रमें उत्तराधिकार के योग्य नहीं माना जाता था। घृतराष्ट्र तथा देवायी इसी नियम के श्रांतर्गत राज्याधिकार के योग्य नहीं माना जाता था। घृतराष्ट्र तथा देवायी इसी नियम के श्रांतर्गत राज्याधिकार से वंचित रहे थे। कभी इन्हीं कारणों से राज्य के भीतर भाई माई में संघर्ष भी हो जाया करते थे, जिनका वर्णन लोकसाहित्य तथा कहानियों में बहुतायत से मिलता है।

उत्तराधिकारी के प्रशिच् का भी विशेष ध्यान रखा जाता था। तच्शिला श्रादि की भाँति विख्यात शिचानेन्द्रों में, साधारण लोगों के साथ उसे श्रध्ययन करना पड़ता था। प्रारंभ में दर्शन श्रोर वेदों का निशेष श्रध्ययन किया जाता था; - परन्तु समय के साथ श्रध्यास्त्र श्रोर राजनीति ही शिच् के मुख्य विषय रह गए थे। अ इन विषयों का श्रध्ययन इतना गम्भीर श्रोर प्रशस्त होता था कि श्रन्य शास्त्रों के श्रध्ययन की श्रावश्यकता नहीं समभी जाती थी। महाभारत में तो यह भाव इस प्रकार व्यक्त किया गया है कि समाज की व्यवस्था श्रोर उन्नति पूर्ण रूप से कुशल प्रशासन पर निर्भर करती है। + इसलिए राजा का प्रशिच्तित होना श्रत्यन्त श्रावश्यक है। राजा की शिच्चा सद्धान्तिक होने के साथ ही व्यावहारिक भी होती थी जिसमें प्रशासनीय, सैनिक व युद्धकीशल सम्बन्धी शिच्चा मुख्य थी। घुड़सवारी, हित-संचालन तथा धनुर्विद्या की शिच्चा श्रानिवार्य रूप से दी जाती थी। वह शिच्या प्राप्त कर लेने तथा वयस्क हो जाने पर राजकुमार की नियमानुसार प्रशासक (Heir-apparent) के रूप में नियुक्ति कर दी जाती थी, जहाँ वह पिता की सम्मति से शासन चलाता था।

⁺ Dr. Altekar-State & Govt. in Ancient India-Page 78-Foot note-Junagarh Inscription-"स्वयमधिगतमहास्त्रप-नाम्ना रुद्रदाम्ना '

[×] राजतरंगिणी-VII-773. FF.

[÷] श्रर्थशास्त्र Chap. 2. मनुस्मृति VII. 43.

^{*} कामन्दकीय नीतिसार-II.

⁺ महाभारत ६३, २६, २६-"सर्वा विधा राजधर्मेषु युवताः सर्वे लोका राजधर्मे प्रतिष्ठाः । सर्वे धर्मा राजधर्माप्रधानाः।

उत्तराधिकार के नियम - यदि उत्तराधिकार के समय राजकुमार अल्पायु (Minor) होता था तो प्रशासन, संरक्षक-मण्डल द्वारा (Council of Regency) संचितित होता था। साधारणतया स्वर्गीय सम्राट की पत्नी इस मण्डल की प्रधान होती थी। जातक चतुर्थ के वर्णनानुसार जई काशीनरेश साधु इन गए तो वहाँ की जनता ने उनकी पत्नी से राजकाज सँमालने की पार्थना की। + इसी प्रकार कीशाम्बी के सम्राट उदयन के वन्दी हो जाने पर, राज्य का शासन-प्रवन्ध उसकी माता ने संमाला था। ऐसे मारतवर्ष में अनेक उदाहरेण हैं। ईसा से १४० वर्ष पूर्व नयनिका तथा ३६० ई० में प्रमा-वती गुप्त ने अपने पुत्रों की अल्पायु के समय बड़े विस्तृत राज्यों का शासनप्रवन्ध पूर्ण सफलता के साथ संचालित किया।

महाभारत के ऋतुमार, हिन्दू नियम इस बात की ऋहा नहीं देता कि सम्राट की इकलौती पुत्री सम्राज्ञी के रूप में उत्तराधिकार प्राप्त करे। केवल उस रिथित में, जब कि सम्राट युद्ध में काम आए हों श्रीर उत्तराधिकार के लिए कोई पुत्र न हों, तब पुत्री का भी राज्यामिषेक हो सकता था। 🗙 परेन्तु यह सामीन्य नियम नहीं था। केवल विशेष परि-स्थितियों में ही इस नियम की सहायता ली जीती थी। प्राकृतिक मंयदि। श्रों के कारण महिला वर्ग शासन के लिए अधिक उपगुक्त नहीं माना जाता था। कत्याओं के उत्तराधिकार के अव-सर पर श्रिधिकांश उनके पति ही शासन के प्रति उत्तरसंगी बन जाते थे। परन्त वह कत्या श्रपने उत्तराधिकार के कार्रण स्वाधिकारिणी सम्राज्ञी (Regnant queens) होती थी । उदाहरणार्थ, चन्द्रगुप्त प्रथम तथा लिच्छ्यी सम्राज्ञी कुमारा देवी की संयुक्त सुंदा से यह प्रकट होता है - कुमारा देवी अपने ही उत्तराधिकार के बल पर सम्राज्ञी बनी रही। किन्तु यह अपवाद माना जा सकता है। साधारणतया उत्तराधिकारिगी पुत्री अपने पतिदेव की ही राज्य का कार्य-भार सँभेलाकर स्वयं उसकी रानी कहलाती थी। डी॰ श्रेस्टेकर के मतानुसार दिल्ए भारत में विशेषकर चालुक्य तथा राष्ट्रकटों के समय में राजपरानों की कुमारियाँ महत्वपूर्ण प्रशा-सनीय पदी पर नियुक्त की जाती थीं। ऋमीववराह की पुत्री इर्रागंग की धर्मपरनी रेवका-निम्दी सन् ८५० ई० में इदातोर नामक महत्वपूर्ण जिले की राज्यपाल थी तथा जयसिंह नृतीय की अग्रजा, अक्कादेवी सन् १०२२ में किंग्रुकुड़ा जिले का शासन करती थीं। परंतु उत्तर भारत में ऐसे उदाहरण नहीं मिलते। ÷

इ स प्रकार यह निर्णय किया जा सकता है कि प्राचीन हिन्दू नियम उत्तराधिकार के संबंध में आदर्श रूप में थे। न अधिक कठोर थे और न अधिक उदार । कन्याओं को उत्तराधिकार से वंचित भी नहीं किया गया था तो उन्हें पूर्ण रूप से उत्तराधिकारी स्वीकार भी नहीं किया गया था, जिससे वे अपने पिता के राज्य में पड्यन्त्र करने के लिए सोचने लगे।

⁺ जातक IV-Page 105, 487.

[×] कुमारी नास्ति येपाँ च कन्यास्त्रवामिषेचय । महामारत १२/३२,२३//

⁻ State & Govt. in Ancient India-Page. 81, 82. Dr. Altekar

राजकुमारियों की सैनिक, प्रशासनिक शिक्षा की भी व्यवस्था होती थी, जिससे वे अवसर आने पर केवल रमणी ही न रिद्ध हों, बब्कि थोग्य प्रशासक के रूप में आगे बहुकर राज्य का कार्यसंचालन भी कर सकें।

समाट के पद वा महत्त - शांति पर्व के अनुसार यह त्राज्ञा दी गई है कि इस संसार में जो समृद्धि चाहते हैं, उन्हें सर्वप्रथम सबकी रचा के हेत समाट का चुनान कर उसकी मुकुट धारण करा देना चाहिए अन्यथा प्रत्येक व्यक्ति का जीवन और सम्पत्ति सदैव ही संबट में रहेगी। बलवान् निर्हल का भद्रण करेंगे; विवाह स्पवन्ध आदि के नियम शिथिल हो जायंगे; कृषि व व्यापार अस्तुव्यस्त हो जायंगे; नैतिवता नष्ट हो जायगी; वेद लुप्त हो जायंगे; अन्याय, अवाल और दर्णारं बरता बढ़ जायगी; इसलिए प्रथम सम्राट का जुनाव करें, फिर धर्मपत्नी का चुनाव करें और उसके पश्चात् सम्पत्ति अर्जित करें। इस प्रकार सम्पत्ति और पारिवारिक मुख के पहले समाट का स्थान निर्धारित किया गया था। सम्राजीय कार्य वास्तव में देवी कार्य था। अन्य कार्य स्म्राट स्वयं करता था। इसलिए सम्राट का महत्त्व सदैव बना रहा । श्राधुनिक पाश्चात्य विद्वानीं में, लॉक, जॉन स्टुश्रर्ट मिल तथा गिडिंग्स श्रोदि के मतानुसार समाट वा प्राधान्य इसलिए माना है कि वह मानवमात्र का हित साधन करता है। अपरस्तू ने कहा था कि राज्य व राजा की आवश्यकता इसलिए है कि जीवन पूर्ण व श्रात्मनिर्भर बन सके । + इसलिए भारतवर्ष में सम्राटको साधारण सांसारिक व्यक्ति नहीं माना जाता था। वह मानव के रूप में देवता समका जाता था । जो अपने पुराय चीए। हो जाने के कारण पृथ्वी पर अवतरित होता है। प्राचीन हिन्दू विचार में सम्रोट अनेक रूप वाला होता था। ब्रावश्यकतानुसार वह धर्म, यम, इन्द्र ब्रादि के रूप में जनता के सामने आता था। अञ्छे कार्य करने वालों को पुरस्कार तथा बुरे काम करने वालों के लिए दण्ड की व्यवस्था यही करता था। महाभारत में इसीलिए सम्राट की जनता का हृद्य, जनता की शरण, जनता का गौरव तथा जनता के हर्ष का प्रतीक कहा गया है 🗙 तथा उसकी आज्ञा मानने वालों के लिए इस लोक वा सुख और दूसरे लोक के सुख की अभि-लांघा पूर्ण होना, सम्भव माना जाता था ।

इसके अविरिक्त समार् का महत्व इसलिए भी माना जाता था कि वह युग-निर्माता था। जब वह पूर्ण रूप से 'द्राह' अर्थात् राजनीतिक सिद्धान्तों द्वारा शासन चलाता है तो सर्वश्रे कर युग सत्तसुग (कृतसुग भी कहते हैं) आरम्भ होता है और सर्वत्र पवित्रता और ईमानदारी का प्राधान्य होता है। जब समार् जारों उद्देश्यों (धर्म, अर्थ काम, मोज) में से केवल तीन का पालन कर पाता है तो जे तासुग आरम्भ होता है। जब नेवल दो उद्देश्यों का पालन होता है तो द्वापर सुग होता है तथा जहाँ विज्ञान का प्रभाव होने पर मानवता से दूर होकर अत्याचार आरम्भ होते हैं, उसे कलियुग कहते हैं। अतः सम्राट् या राजा हो

⁺ Aristotle said-"a perfect and self-sufficing life.

^{× &}quot;The King is the heart of people; he is their great refuge, he is their glory; and he is their highest happiness." महाभारत—शांति पूर्व

:

युग-प्रवर्तक अथवा युग-निर्माता कहा जाता था। आज भी जहाँ सम्राट हैं, वहाँ आधुनिकतम फैशन तथा अन्य अनुकरणीय बातों के लिए सम्राट् को ही मुख्य आदर्श माना जाता है। ताल्पर्य यह कि सम्राट् के पद का सामाजिक तथा राजनैतिक महत्व अत्यधिक माना गयां था।

सम्राट् की स्थिति (Position of the King)—सम्राट् के पद की स्थिति विभिन्न युगों में परिवर्त्त नशील रही है । पूर्व ऐतिहासिक काल में सम्राट ग्रपनी परापर्श दात्री परिषद् का केवल एक वरिष्ठ सदस्य माना जाता था और उसकी निर्वाचन द्वारा यह स्थान मिलता था। प्रशासनीय कार्यों में अधिकांशतः लोकप्रिय मगडल या परिषद् का उत्तर-दायित्व स्रोर सम्बन्ध रहता था । 'इसलिए सम्राट् का पद स्थायी नहीं था । वर्तमान काल में अविश्वास के प्रस्ताव द्वागा सुख्य मंत्री या महामियोग के द्वारा राज्यों के अध्यद्धों को हटाया जा सकता है, उसी प्रकार उस समय भी सम्राट को कुछ आधारों पर पदच्युत किया जा सकता था । कर आदि जनता विशेष अवसरों पर देती थी, नियमित रूप से नहीं। इस प्रकार प्रारम्भिक काल में सम्रट् का स्थान अरित्त, अनिश्चित तथा मर्यादित होता था ग्रीर सुन्यवस्थित शासन प्रबन्ध के लिए उसे ग्रन्य सहयोगियों पर निर्मर रहना

पूर्व तथा प्रारम्भिक वैदिक काल में सम्राट् की स्थित कुछ इड वन गई थी। राज्यों का आकार बढ़ने के कारण उत्तरदायित्व तो बढ़ा ही, साथ ही सहयोगी एवं सिमितियों के पड़ता था। ग्रिधिकार सीमित बनते गए । सम्राट् की इच्छानुसार प्रशासनीय निर्णय होने लगे । इसी समय में सम्राटों की स्थिति सुधरी स्रोर शिक्तयाँ बढ़ गईं। ऋग्वेद में कई प्रकार के सम्राटों का प्रसंग ज्ञाता है-जैसे स्वरत, एकरत, अधिराज, समरत इत्यादि । ये प्रकार निश्चित रूप से उनकी स्थिति और शिक्तयों के ग्रन्तर के आधार पर ही रहे होंगे। शुद्ध वैदिक काल में सम्राट की स्थिति और भी अच्छी हो गई। यह पद पूर्ण ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा और वैभव से युक्त हो गया। व्यक्तिगत स्वामित्व का सिद्धान्त लागू होने लगा। भूमि, सम्पति, कोष आदि ह्यितिगत वैभव के लच्या स्वीकार किए गए। अयर्ववेद के अनुसार सम्पति का स्वामी, जनता का अध्यच श्रीर योद्धाश्रों का मुख्य नायक, सम्राट ही होता था। ब्राह्मण, चत्रिय, नेश्य और शद सन सम्राट की समृद्धि के लिए प्रार्थना करते थे, कर देते थे और हर प्रकार के सहयोग के लिए तत्पर रहते थे। सम्राट के अधिकार कमरा: बहुत विस्तृत, व्यापक छोर चलशाली बन गए इसलिए उसके कीप से जनता मयमीत रहने लगी। × इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि वैदिक काल में सम्राट समस्त शासन का ग्राधिष्ठाता था, राज्य की सम्पूर्ण ध्यवस्या, न्याय-परिषद् उसकी इच्छानुसार संचालित होती थी ग्रीर सम्राट का पद ग्रात्यन्त होमवपूर्ण, समृद्धियाली एवं जनता के एकमात्र रक्क का स्थान बन गया था।

सम्राट और देवत्त्रः—प्रारम्भ में भारतवर्ष में सम्राट का पद गुह लीकिक संस्था (Secular institution) के रूप में माना गया था। ऋग्वेद में केवल राजा पुरुक्तत की केवल एक स्थान पर श्रद्ध दैव (Semi-divine) कहा गया है श्रीर इसी प्रकार श्रियाँचे ने वेद में राजा परीचित् को मानवीं के मध्य देवता बताया गया है। 🗙 परन्तु ये प्रसंग श्रीर वर्णन श्रपवाद हैं। सम्राट के प्रशंसक उसे ऊ चा उठाने के लिए श्रयवा श्रपने लिए सम्राट की कृपा प्राप्त करने लिए, उसके पद में कल्पना से देवच्व का प्रवेश कर लेते होंगे। ब्राह्मण-काल में यह देवत्व अधिक प्रभावशाली हुआ। यह समय धर्म के विकास तथा धर्मपरायणता को माना जाता है। इसलिए सम्राट मी, जो जनता की रचा करता था, समृद्धि लाता था, युद्ध में विजय प्राप्त करता था, संकट निवारण करता था, वह देवत्व से संयुक्त माना जाने लगा श्रीर उसके कार्यों की देवताश्रों के कार्यों से वुलना होने लगी। राज्यामिषेक के समय समाट की देवत्व प्राप्त कराने के हेतु अनेक प्रकार के यहाँ की प्रथाएँ चलीं तथा देवताओं को प्रसन्न करके उनकी कृपा के लिए प्रार्थनाएँ की जाने लगीं। वास्तव में यह देवत्व ब्राह्मणों से ख्रारंभ होता है जो स्वय ख्रपने ख्रापको पृथ्वी के देवता (भूदेव) कहते ये । उनका देवत्व राजा की अद्धा व प्रसन्नता पर निर्भर करता था। इसलिए वही देवत्व वे सम्राट के लिए भी स्वीकार करने लगे। इस प्रकार उत्तर-वैदिक काल की सब परिस्थितियाँ सम्राट की देवत्व देने के लिए श्रनुकुल बन गईं श्रीर सम्राट का पद दैविक माना गया। ईसाः की पहली सदी के आरंभ में कुशन वंश की स्थापना ने सम्राट का देवत्व श्रौर भी स्पष्ट रूप से स्वीकृत और स्थायी बना दिया । सम्राट देवपुत्र कहलाने लगे । सम्राटों द्वारा अपने पूर्वजों के मंदिर बनाए गए श्रीर उनकी पूजा श्रारंभ हो गई। भारत स्वतंत्र होने के पूर्व तक देशी राज्यों में राजा देवता का प्रतीक समभा जाता था और जिस अोर वह जाता था वहाँ उसके दर्शनों के लिए अपार बनता एकत्रित होती थी। समर्थ नागरिक भेंट भी (नजर) करते थे। कुछ स्मृतियाँ और पुराण भी राजा के देवत्व के सिद्धान्त को स्वीकार करते हैं। उनमें मनुस्मृति, विष्णुपुराण, श्रीमद्भागवंत त्रादि मुख्य हैं। भागवत में ती राजा वेरा के शरीर पर, विष्णु की भाँति शंख, चक्र, गदा, पंच की कल्पना भी कर ली गई है। परन्तु यह वास्तविकता से दूर की कल्पना है। कुछ स्मृतिकारों ने सम्राट के पद की, देव-तात्रों के पद की भौति मानकर केवल कार्य-समानता (Functional resemblance) की स्रोर ध्यान स्राक्षित किया है। जैसे सम्राट, सर्य की भाँति पालक, स्राप्त की भाँति घातक, कुनेर की भाँति समृद्धिदाता है। महाभारत, शुक्रनीति, नारदस्पृति आदि इस संबंध में मुख्य हैं। इन विचारकों का दिन्दिकीण बहुत महत्व का है। इन मंथों से यह सिद्ध होता है कि सम्राट स्वयं देवता नहीं है पर सम्राट का पद देवत्व से युक्त है; क्योंकि उसके कार्य उसी प्रकार के हैं; जैसे देवताओं के । अतः हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि सम्राट के देवतन का सिद्धान्त जो ईसा की प्रथम दस शतान्दियों तक भारतदर्ध में बहुत लोकप्रिय रहा, वैदिक काल में उसका श्रस्तित्व ही नहीं था।

सम्राट के देवत्व की छुलना पाश्चात्य देशों के सिद्धान्तों से भी की जाती है। रोम के सम्राटों को देवता माना जाता था। उनकी मृत्यु के बाद उनके मंदिर बनाए गए श्रीर

x "यो देवो मर्त्य अधि"

पूजा आरंभ हुई। ईसाई धर्म के अनुसार पादरी में वास्तिवक देवत्व स्वीवार किया गया शा और यह मान्यता थी कि राज्याभिषेक के समय पादरी यह देवत्व समाट को भी हस्तांतरित कर सकता है। किन्तु बाद में राज्य और गिर्जा के संघर्षों ने राजा और पादरी दोनों के देवत्व को केवल कर्षमा सिद्ध कर दिया। भारतवर्ष में जो सिद्धान्त थे उनके द्वारा देवत्व केवल अन्छे समाटों को ही दिया जाता था, नीच व अत्याचारी राजाओं को राज्य मान कर समाप्त कर दिया जाता था। राजा वेग्न की कथा इस संबंध में बहुत उपयुक्त है। मिस्र तथा वेबीलोन, असीरिया आदि की सम्यताओं में भी समाट के देवत्व को स्वीकार किया गया है। परन्तु १०वीं सदी के परचात समाटों का देवत्व जीगा होने लगा और सर्वत्र उनका विरोध आरंभ हो गया। इस प्रकार समाट और देवत्व का सिद्धान्त अन्य देशों को अमेजा भारतवर्ष में मध्य दुग में आया, किन्तु ऐसे मर्यादित रूप में जो अन्यत्र हिन्योचर नहीं होता और बाद में पूर्ण लोकमय बन गया।

सम्राट के कत्त व्य (Functions of the King)—प्राचीन भारतवर्ष में सम्राट के अनेक कर्ताव्य माने गए थे।

- ाः । (१) ं सुरत्ता काः उनः सम्में प्रमुखःस्थानः हैः। महाभारतः के श्रातुसारः यदिःसम्राद्यः सरेला स्वभावः का वनः ज्ञाताः है तो प्रत्येकः स्यक्ति । उसकीः श्रयन् हेलना करने लगता है, यदि नि इंदर बन जाता है तो जनता कव्ट पाती है। इसलिए उसे दोनों प्रकार का स्वभाव अवना चाहिए। सूर्य की भाँति न तो अधिक शीतल रहे अभीर न अधिक गरम । जनता की रचा करते हुए यदि सम्राट् संकट में भी पड़ जाता है तो यश प्राप्त करता है अभीर कर्तव्यपरायणता के द्वारा वह अपना पारली किक जीवन बनाता है। अदि एक दिन भी सम्राट सुरचा के कार्य में भयशिक्षिल हो जाता है तो इतन। पाप जगता है कि १००० वर्ष तक भी नरक से छुटकारा नहीं मिलता । साथ ही कर्त छ। पालन करने वाले समाट को बहु चर्याश्रम, गृहस्थाश्रम तथा; बान्मस्थाश्रम का सारा कल स्वतः मिल जाता है । यदि समाद सुरचा नहीं करता तो वह जिना दूध की गाय, या वन्ध्या पतनी की भावि होता है। महाभारत में ऐसे सम्राटों की उपमाएँ बहुत सन्दर रूप में दी गई हैं। जो सम्राट मुजा की रचा न कर सके अथवा बाह्यण जिसे वेदों का जान न हो, वे काष्ट के हाथी, चर्म के हिरण, सम्पत्तिहीन पुरुष, शिखण्डी पुरुष, या वन्ध्या भूमि की भाँति होते हैं । दूसरा प्रसंग चेतावनी के रूप में है कि इन इ प्रकार के पुरुषों का साथ ऐसे ही छोड़ देना चाहिए; जैसे समुद्र के बीच फूटी नौका का: —(१) मीन दार्शनिक, (२) निरचर (पंडित) पुरोहित, (३) रचा न कर सकने वाला सम्राट, (४) श्राप्रयमायक पत्नी, (५) गाँव में घूमने वाला गहरिया और (६) सन्यास ग्रहण करने वाला नाई। अर्थात जनता की सरका का कर्तव्य सम्राट के लिए सर्वप्रथम तथा अत्यन्त महत्व का था।
- (२) सद्चार की बुद्धिः सम्राट का दूसरा मुख्य कर्त व्य है शासन का इस प्रकार संचालन जिससे सदाचार की बुद्धि हो। सदाचार की बढ़ाने बाला शासन सम्राट को देवत्व के पद पर पहुँचा देता है; क्योंकि समस्त जनता सदाचार पसन्द करती है अपीर सदाचार सम्राट के शासन पर निर्भर करता है। इसलिए वास्तविक सम्राट वही माना गया था जो

न्यायिप्रय तथी धर्मीनुकूल शासनकर्ता हो । इसके विपरीत शासन कभी सफल नहीं हो सकता और न अधिक समय चल सकता है। इसलिए धर्मप्रधान शासन अनिवार्य होता था। ब्राह्मणों द्वारा इसीलिए धर्म निर्धारित कियों जाता था कि जिससे समस्त प्राणी निर्भयता से रहते हुए अपना विकास और उन्नति करें। राजा को इसीलिए हमारे धर्मप्र थ धर्मानुकूल शासन चलाने की आजाएँ देते हैं। इसके विपरीत शीसन में सम्पत्ति का नाश, व्यवस्था में गड़बड़ तथा सर्वत्र भय व्याप्त हो जाता है। सम्राट को सारे राज्य का रचियता और नाशक कहा जाता था। यदि धर्म के अनुसार शासन करता था तो स्वामाविक रूप से रचियता हो जाता था और विपरीत शासन चलाने पर नाशक सिद्ध होता था।

- (३) जनता का सामान्य हित-सम्राट का पद एक न्यास (Trust) की भाँति समभा जाता था, इसलिए समस्त जनता का सामान्य हित करना सम्राट का अनिवार्य कर्त व्य समका जीती थीं महामारत में यह कहा है कि सम्राट श्रीर जनता का वही सम्बन्ध होना चाहिए जो एक माता का अपने पुत्र के साथ होता है। इस्लिए सम्राट् को सदैव अपनी प्रना के सुख और भनाई का ध्यान रहना चाहिए । सन्नाट का पद सुमन-शय्या नहीं थी वरने कर्त व्यों के बीम के कारण एक कठोर श्रीर कांटों का मुकुट था। इस कर्तिय के अन्तर्गत सम्राट से अपेका की जाती थी कि वह मिद्रालय, वेश्यालय, यूत-एह, नाट्यशालाएँ तथा इस प्रकार के अन्य स्थानों पर नियंत्रण रक्षे । राज्य को निवास-योग्य स्थल बनाने के लिए सब प्रकार के आवश्यक कार्य क्रांना उसका उत्तरदायित्व माना गया थी। जैसे कृषियोग्ये भूमि प्राप्ते करना श्रीर उसे उपजान बनाने का प्रयस्त, कृषि को पूरी तरह से वर्षा पर निर्भर न रेखिनी, भीलें व तालावों का निर्माण, अग्नि, सर्प आदि के संकट निवारण के लिए उचित व्यवस्था, जनता में आरोग्यता बनाये रखने के साधन, सङ्कों व राज-पर्थी की निर्माण, उचित स्थानी पर दूर्कीने तथा प्याउश्री की व्यवस्था करना, चोर-डाकुश्रों का निवारण श्रीदि मुख्यें केत्तव्य थे। श्रीधिनिक काल में जी लोक-कर्त्याण-कारी राज्य (Welfare State) का नारा लिंगाया जाता है प्रीचीन भारत में वही ब्राइश सम्राट के कर्त व्य के संस्थित्ध में स्वीकार किया गर्या था । सुधा, रोग, निरस्रेती, निर्धनता श्रीर वेरोजगारी ये पाँच मानव समाज के मुख्य शत्रु माने जाते हैं। प्राचीन भारतीय सम्राट् इन्हें दूर करने के लिए कटिबंद रहता थी। वह जनता के पिता की माति सर्व-कच्ट निवारण हेतु तरंपर रहता था।
- (४) प्रशासनीय श्रिथं-व्यवस्था प्रत्येक राज्य के शासन की नीव वहाँ की श्रिधं-व्यवस्था पर निर्भर करती है। प्राचीन भारत में भी श्रर्थ व्यवस्था दृढ़ श्राधिक सिद्धान्तों पर स्थापित की गई थी ि सम्राट् का यह श्रिधिकार था कि वह उपने का छुठा भाग, श्रपराधियों पर श्राधिक द्रएंड तथा व्यापारियों से उनके लाम की निश्चित भीग, धर्मप्रत्यों में बताए निर्थमों के श्रनुसार लेकर श्रपनी कीच पूर्ण करे। यह राजा की जनतों की रची करने के फलस्वरूप मिलता था। इसलिए कर-सिद्धान्त पूर्ण स्प से उचित ठहरती था। सम्राट् की श्रन्य भारी कर लगाने की श्रावश्यकता नहीं रहती थी। कर प्राप्त करने के लिए महाभारत में बेड़ी सुन्दर उपमाए श्रीर उक्तियाँ कही गई ई कि, सम्राट् की मधुमिन्सी की

तरह द्रव्य एकत्र करना चाहिए, घेनुदोहन की भाँति मर्यादित प्रयतन होना चाहिए; किन्तु मूपक की भाँति श्रहितकर व्यवहार नहीं करना चाहिए, समय, स्थान व मात्रा बड़ी बुद्धिमानी से निर्धारित करनी चाहिए आदि अनेक सिद्धान्त हैं। इनका विशद वर्णन हम आगे कर-सिद्धान्त के अध्याय में करेंगे का कार्या कि किया है। कार्या कार्या कार्या कर

क्ष(४) व्यक्तिगतः जीवनं का नियमन—राज्य की व्यवस्था उचित रूप से चलाने के लिए सम्राट् के जीवन में संयम व नियम श्रावश्यक माने गये थे श्रीर ये भी सम्राट् के कर्ता व्या में सम्मिलित थे। कौटिल्य ने तो सम्राट् के कर्ता व्यों के साथ ही उसके व्यक्तिगत दैनिक जीवनक्रम भी निश्चित कर दिये हैं। नकार राव कर को निर्देश राज्य विकास का जाविक रहे ।

दिन

६.०० बजे प्रातः से ७.३० प्रातः — श्राय श्रीर व्ययं का निरीच् ए
७.३० बजे प्रातः से ६.०० प्रातः — जनता व नागरिकों के कार्य
६.०० बजे प्रातः से १०.३० प्रातः — स्नान, संध्या व भोजन
१०.३० बजे प्रातः से १२.०० मध्यान्ह— राज्य के कर्मचारियों के कार्य
१२.०० बजे मध्यान्ह से १.३० श्रपरान्ह— मंत्रियों तथा विश्वासपात्र व्यक्तियों से भेंट

१.३० वजे अपरान्ह से ३.०० अपरान्ह—विश्राम तथा विनोद

३.०० बजे अपरान्ह से ४.३० अपरान्ह—सेना का निरीचण

४.३० बजे अपरान्ह से ६.०० सायं —शत्रु हिथति तथा सैनिक कार्यवाहियों से सम्बन्धित कार्य .

रात्र ६.०० सायं से ७.३० रात्रि—गुप्तचर तथा श्रन्य गुप्त स्चना श्रधिकारियों से भेंट ७.३० सार्य से ६.०० रात्रि — स्नान, भोजन, (वन्दना) संध्या ६.०० साय से १.३० प्रातः—संगीत-व श्रायन.

रे. ३० प्रातः से ३. ० प्रातः पुनः संगीत तथा भविष्य का विचार

३.०० प्रांतः से ४.३० प्रांतः — राज्य के ब्रान्य विचारणीय अश्न, व कार्यः कार्यः कार्यः

४.३० प्रातः से ६.०० प्रातः — पुरोहित या कुलपण्डित से आशीर्वादः ।

इस कम से सम्राट् का जीवन यंत्रवत् चलता था । संयमः श्रीर समस्तः कार्योः का निरीच्यण इस प्रणाली से सरतता से हो जाता था । इसके अतिरिक्ति सम्राट छुछ अन्य कार्य

(६) अन्य कार्य उपयुक्त कत्त व्यों के अतिरिक्त कुछ विशेष कार्य थे, जिन्हें सम्राट व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के कार्य सम्भता था । जैसे मंदिर, नास्तिक, महिलाएँ, चौपाए, तीर्थस्थान, युवक, बृद्धा, रुग्ण तथा निस्सहाय से सम्बन्धित कार्य इस अ णी में त्राते थे। इन्से अधिक महत्व का कार्य था—हरूही का अगण है है आप अगण है है है

न्याय-सम्पादन-सामाजिक प्रतिष्ठा ः तथा , त्रान्य ः तत्वी ः की महत्व ्दिए जिना निष्यत्तं न्यायं करना, सम्राट् का महत्वपूर्णः कत्तं व्यामाना गया था । जनता को प्रसन्न व

सुखी बनाए रखने के लिए निष्पुच न्याय श्रानिवार्य माना गया था । इसके श्रातिरिक्त श्राव-श्यकतानुसार सभी प्रकार के कर्च व्य सम्राट् से श्रापेचित किये जाते थे जो समय और स्थिति से उत्पन्न हो जाये ।

सम्राट् के गुण कीटिल्य के मतानुसार सम्राट् में कुछ त्रावश्यक गुण होने चाहिये, जिनके बल पर वह उपर्युक्त कठिन कर्त ज्यों का पालन कर सके। अर्थशास्त्र के अनुसार सम्राट् में निम्नांकित गुणों की अपेद्या की गई है:—

- (१) उच कुल में उत्पन्न होना, बुद्धि, शौर्य, कहणा, सहदयता, श्रतुभवी व्यक्तियों से परामर्श करना, कृतज्ञता की भावना, उदारता, शक्तिमत्ता, श्रतुशासन, दृढ़ निश्चय श्रादि:
- (२) चतुराई व बुद्धि से सम्बन्धित ऐसे गुग्-जैसे जिज्ञासा, स्मृति, ज्ञान, पर्यवेक्षण, विशेष प्रतिभा तथा सत्य के प्रति प्रगाढ़ निष्ठा आदि;
- (३) कर्त व्यशीलता के गुगा-जैसे साहस, गर्व, स्फूर्ति श्रीर कौशल श्रादि;
- (४) व्यक्तित्व के गुण-जैसे प्रज्ञा या चातुरी, प्रखर स्मरणशक्ति, विलच्चण बुद्धि, आत्मितियंत्रण, अन्यान्य कलाओं पर प्रभुत्व, निष्पच्च न्याय, दूरदर्शिता, विरोधी की कमजोरियाँ समभ लेने की योग्यता, भावनाओं पर नियंत्रण, आवेश से मुक्त रहना, लोभ, धमण्ड, आलस्य, उतावली तथा निर्दयता से दूर रहना आदि।

उपर्युक्त गुण एक त्रादर्श सम्राट् के लिए त्रावश्यक हैं। परन्तु सभी गुणों को प्रत्येक सम्राट् में लोज करना भूल या दुराशामात्र ही हो सकती है। फिर भी सधारणतः सम्राट् में अधिकांश गुण होते थे। कुछ तो परिस्थितियों के कारण त्रीर कुछ जन्म से ही सम्राट् को प्राप्त हो जाते थे।

सम्राट पर प्रतिबन्ध-प्राचीन भारत में जनता का हित प्रधान लच्य माना गया था। इसलिए सम्राट पर अनेक कर्त व्यों का भार रख देने पर भी मर्यादाएँ रक्खी गई थीं, जिससे कभी कोई सम्राट यह कल्पना न करने लगे कि वह सर्वेसर्वा अथवा निरंकुश है। धर्मप्र थीं के अनुसार यदि सम्राट अपनी जनता या प्रजा को पापवृत्ति से नहीं रोकता है तो पाप का चौथा भाग सम्राट को भी मिलता है। यदि निष्पत्त न्याय नहीं करता तो उसका यश और परलोक नष्ट हो जाता है। इस प्रकार की मान्यताओं के आधार पर सम्राट पर अनेक प्रति-बन्ध लगाए गए थे, जिनमें अधिकांश धार्मिक तथा नैतिक थे और शेष संवैधानिक और ध्यावहारिक।

महाभारत में तथा नारद-रमृति में निरंकुश राजतंत्र को प्रतिपादित किया गया है। चाहे सम्राट किसी भी प्रकार पतित या श्रयोग्य हो उसे हटाने या घृणा करने का श्रधिकार जनता का नहीं माना गया है। परन्तु साथ ही वहाँ श्रादर्श संम्राट की रूपरेखा में समस्त प्रतिबन्ध भी श्रा गए हैं। श्रादर्श सम्राट वह है जिसका जीवन जनता की सेवा श्रीर हित के लिए समर्पित हैं। जो एक इस्टी की गाँति कार्य करता है। उसे जनता के सेवक के रूप में

सेवा करनी चीहिए । श्रेंत्याचारी, दुश्चरित्र सम्राट के शासन से जनता को बचाने के लिए श्रेनेक सीवन स्वीकार किए गए थे जो महाभारत के अनुसार निम्न प्रकार है:—

(१) जो सम्राट अपने सदाचार व सुरचा के कर्च व्य को भूल जाता है वह जनता से श्राज्ञापालन कराने के अधिकार से च्युत हो जाता है। महाभारत में श्रत्याचार से मुक होने का प्रजा का श्रिधिकार स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है। ऐसा श्रत्याचारी संश्राट जो दुष्टों की सलाह पर चलकर सदाचार श्रीर सुन्यवस्था को नष्ट करता है, वह सपरिवार प्रजा द्वारा नष्ट कर दिये जाने के योग्य है। राजा वेण की कथा इसका स्पष्ट उदाहरण है। कुछ लेखकों का विचार है कि पाचीन भारत में "विद्रोह की अधिकार" स्पष्ट नहीं माना है, यह सत्य नहीं है। अत्याचारी सम्राट की पदच्युत करने अथवा मौत के बाट उतारने का अधि-कार इससे अधिक और किस स्पष्टता से स्वीकार किया, जा सकता है। कुछ अन्य लेखक इसे संविधानिक अधिकार भी नहीं मानना चाहते हैं। वे इसे अधिवधानिक उपाय मानते हैं। परन्त वास्तव में यह सर्वमान्य नियम या । इसकी परीक्षी यही थी कि अत्याचारी सम्राट का विरोध खुले रूप से होना चोहिए थीं। उस समिय में शांतिमय सीधन भी काम में स्नाते थे। पुरोहित, में त्रिगण तथा श्रन्य श्रेनुभवी व्यक्ति श्रपने प्रभवि से श्रेरवाचारी संबाद की उचित मार्ग पर लीने की येरने करते थे स्त्रीर इसे प्रयत्न के असफल होने पर ननता विद्रोह करके सम्रोट की वैध कर देती थी । कुँछ विद्वानों के मतानुसार केवल विद्रोह ही एकमात्र उपायं थीं, यह सत्य नहीं जान पड़ता। यह भी संभावना की जाती है कि यदि विद्रोह असफल हो जाता तो श्चित्याचारी श्चीर श्रधिक पीड़ा पहुँचा एकता था। परन्तु यह शंका भी निम् लाहे । समस्त जनता के विद्रोह की दंशने के लिए, जैसे उन्नीसवीं और श्रीसबीं: सदी के भारत के स्वतंत्रता-संग्रीमी की कुँचलने के लिए इंगलैड और विदेशों से सेना और पुलिस खुंलाई जाना समव नहीं था; इसी प्रकार एक अत्याचारी सम्राट की समाप्ति ंके वाद वंदि पुन: कोई ा श्रात्याचारी - सम्राट् ् बन् जाता था हो । वहीं ाउसे नमीतः के धाट उतारना उसका उपचार था। मागवत में वेण की कथा में यह प्रसंग स्पष्ट ही कर दिया गया है। वेण के बाद कब एक श्यामवर्ण, रक्तनेत्र, नाटा कद तथा ऋत्याचारी शासक उत्पन्न हुआ तो ऋषियों ने उसे भी मार दिया । अतः जनता का विद्रोह-अधिकार स्पष्ट और विस्तृत था, लो सम्राट के लिए तबसे अधिक प्रभावशाली प्रतिबन्ध था।

(२) धार्मिक व आध्यात्मक प्रतिबन्ध छोर भी छाधक प्रभावशाली ये। प्राचीन भारतीय लेखको ने धर्म का प्रयोग बहुत बुद्धिमानी से सब चेत्री में किया है। सम्राट के कर्च व्य-पालन न करने पर उसे नरक का भय दिखाया गया था और यह बहुत शिक्षिशाली प्रतिबन्ध सिद्ध हुआ है। छानुचित कर लगाने पर, सम्राट स्वयं दगड रूप में उस राशि से तीस गुनी शिशा वरुण को मेंट चढ़ाता था इत्यादि छानेक प्रतिबन्ध स्वीकार किये गए ये। सम्राट के छात्याचार के विकद्ध समस्त समान भी सत्याग्रह करता था (Passive-resistence)। इसका ढंग यह था कि विना मोजन किए हुए, मीसम की चिन्ता न करते हुए किसी महत्वपूर्ण बनस्थल (Public Place) पर इस्ते समय तक लम बाते थे, ववं तक राजा

उनकी माँग स्वीकार न करें । इसके अतिरिक्त अधिक अत्याचारी राजा के राज्य को जनता छोड़कर चली जाती थी ताकि राजा अकेला रहकर सुधरं जाय । प्राचीन भारत में बुद्धिमान नागरिकों का यह कर्त व्यामाना जाता था कि जब राजा न सुधरे तो उन्हें वह स्थान छोड़ देना चाहिए । यह नैतिक प्रतिबन्ध था ।

- (३) देशधर्म—सम्राट की निरंकुशता पर परम्पराश्रों का प्रतिबन्ध भी स्वीकार किया गया था। समान की परम्पराश्रों को किसी भी देश-काल में सरलता से नहीं अलाया जा सकता। शुक्रनीतिसार के श्रमुसार परम्परा या देशधर्म वह प्रथा है जो चाहे वेदों पर श्राधारित न हो परन्तु जिसका पालन जनता द्वारा विभिन्न समय में सदैव किया गया है। इसलिए स्थानीय परम्पराएँ श्रीर देशधर्म का खण्डन या उल्लंधन हमेशा बहुत भयंकर होता है। यह सम्राट की शक्तियों पर एक सफल प्रतिबन्ध था।
- (४) नियम (धर्म)—प्राचीन हिन्दू दर्शन में धर्म या नियम का स्थान बहुत ऊँचा और पवित्र माना गया है। नियम सम्राटों का सम्राट × है तथा सब प्राणिमात्र की रच्चा करता है। धर्म या नियम से ऊपर कोई नहीं है, धर्म सर्वोपरि है। यह मान्यता विद्यमान थी— को सम्राट पर बहुत बड़े नियंत्रण का काम करती थी।
- (४) स्त्रन्य विशेष प्रतिबन्ध-केवल नरक, नियम, धर्म स्त्रीर जनमत ऐसे प्रतिबन्ध नहीं थे जिनसे एक अत्याचारी शासक ठीक रास्ते पर आ जाय। इसलिए कुछ दूसरे प्रतिबन्ध जो विशेष स्थितियों में काम में आते ये, उनका अध्ययन भी किया जा सकता है। सर्वप्रथम ऐसे अत्याचारी के विरुद्ध उसी के परिवार में प्रड्यंत्रकारी पदा होकर उसे समाप्त कर सकते थे, ताकि जन-विद्रोह की आवश्यकता ही न हो और दूसरा व्यक्ति सम्राट के पद के लिए लड़ा हो सकता था अथवा पड़ीसी राज्य के सम्राट द्वारा, ऐसे राज्य पर श्राक्रमण का भय भी एक प्रतिजन्ध होता था या बलशाली पड़ौसी के सीमाविस्तार की आकांचा को सीमित बनाए रखने के लिए शासक कभी अत्याचारी नहीं हो संकता था, विल्क जनता की सेवा द्वारा सम्पूर्ण प्रजा को संतुष्ट रखने की चेष्टा करता था । इसके श्रतिरिक्त साधु श्रीर सन्यासी भी उस समय के राजनैतिक जीवन में महत्वपूर्ण तत्व माने जाते थे । शिवाजी का पथ-प्रदर्शन गुरु रामदास तथा चन्द्रगुप्त का पथप्रदर्शन चाणक्य द्वारा किया नाना सर्वविदित है । ये लोग निष्पत्त तथा स्पष्टवक्ता होते ये तथा शुद्ध बुद्धि होने के कारण इनकी आजाए शाप और वरदान के रूप में मानी जाती थीं। इनसे भी सम्राट प्रतिबन्धित रहते थे। जनमत का प्रमाव भी सम्राट पर श्रिधिक पड़ता था। रामचन्द्रजी ने अपनी पत्नी सीता को केवल जनमत के आधार पर छोड़ दिया, अन्यथा उन्हें स्वयं सीताजी पर अपीर विश्वास था और वे अनिपरीचा में उत्तीर्ण भी हो चुकी थीं। अपूर्वि राज्य के चेत्र में सम्राट के व्यक्तिगत विचार उतना महत्व नहीं रखते थे जितना लोकमत । सम्राट की शपथ-जो वह राज्यामिषेक के समय गहरा करता था, सदैव सचेतक के रूप में उस पर प्रतिबन्ध का कार्य करती थी ख्रीर इतिहास में ऐसे अनेक उदा-

[×] महाभारत—"King of kings"

हरण हैं, जब विभिन्न सम्राट अपनी शापथ के सहारे पथ्रअंग्ट होने से बचे हैं। राजाओं के पदच्युत करने के उदाहरण इतिहास में बहुत हैं। वेश (महाभारत) मगधनरेश नाग-दशक (महावंश), राजा पालक (मृच्छकटिक), रामगुप्त (देवीचन्द्रगुप्तम्) × तथा मौर्य सम्राट बृहद्रथं + ऐसे ही राजा हैं।

इस प्रकार प्राचीन भारतीय सम्राट के पद की जितनी प्रशस्ति लिखी जाय, वह कम है जिह एक ट्रस्ट (न्यास) समक्ता जाता था। जनता के सेवक का पद माना जाता था। कभी निर्वाचित श्रीर कभी उत्तराधिकार द्वारा यह पद प्राप्त होता था। श्रनेक महत्वपूर्ण कर्त व्य इस पद के साथ ये श्रीर उनके साथ श्रधिकांश नैतिक तथा कुछ व्यावहारिक प्रतिवन्धों द्वारा इस पद की पिन्त्रता श्रीर सुरक्षा स्वीकार की गई थी। प्राचीन भारतीय राजनीति की इन सुदृद्ध परम्पराश्रों से राजतंत्र (Monarchy) के श्र तर्गत ही उसके व्यावहारिक प्रजातंत्रात्मक रूप का स्पष्ट परिचय प्राप्त हो जाता है श्रीर यह भी सिद्ध हो जाता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास उस राजनैतिक पद्धति का सुन्दर चित्र है, जहाँ शासक श्रपना व्यक्तित्व जनता के साथ, श्रीर श्रपने सुख तथा हित जनता के सुख व हित के साथ सम्मिलित कर लेते थे —

प्रस्त का अग्रेगीच अहंगी प्रस्त

- 1. Discuss the powers & functions of a Hindu King & show that though in theory he was autocret, in practice he was a constitutional head of the state.
 - 2. Was hindu monarchy theocracy? Dicuss:
- 3. Trace the evolution of monarchy in ancient India & show how the power of monarch was kept in proper check.
- 4. Examine the position of the King & his relationship to the Purohita in the age of the Rigveda.

THE REPORT OF A STATE OF THE PARTY OF THE PA

mingray of granding managagagam in this fall following

[×] देवीचन्द्रगुप्तम्-विशाखद्त्त रचित नाटक है जो श्रप्राप्य है, किंतु इसके छुद्र श्रांश नाट्य दर्भेण ग्रांथ में उद्ध त है जिसके प्रणेता रामचन्द्र और गुणचन्द्र है।

⁺ नाया ने बहद्रथ को पदच्युत किए जाने का कारण उसका "प्रतिज्ञा-दुर्वल' होना माना है।

[÷] प्रजा सुखे सुखे राझः प्रजानाञ्च हिते हितम् । नात्य प्रियं हितं राझः प्रजानां तु प्रियं हितम् ॥ अर्थशास्त्र १/१६/१६

क सबैलोकहितेन (असोक-शिलामिनेख ६) (सबैभू तहिते रताः-गीता ।

नवौ ग्रध्यायः

अभिषेकोत्सव

(Coronation Ceremony)

प्रस्तावना-प्राचीन भारत की अनेक परम्पराओं और संस्थाओं में अभिषे-कोत्सव का एक प्रधान एवं महत्वपूर्ण स्थान है । अन्य संस्थाएँ चाहे रही हो अथवा नहीं किन्तु इस अभिषेकीत्सव के सम्बन्ध में तो यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि यह परम्पर्रा, भारतवर्ष के स्वतंत्र होने की तिथि तक और उसके पश्चात भी राज्यों के एकी-करण तक, भारत के प्राचीन देशी राज्यों में बराबर चलती रही । राजवरानों में तो शायद श्राज भी इस परम्परा का पालन होता है। किन्तु महत्व की दृष्टि से श्रंब इस परम्परा की कोई प्रधानता नहीं । यों तो हम यह भी कह सकते हैं कि आधुनिक काल में नवोदित प्रजातंत्र राज्यों में जो शपथ प्रहरा का नियम है यह निश्चित रूप से अभिषेकोत्सव का ही श्रवशेष एवं परिवर्तित रूप है। इस प्रकार वैदिक काल से प्रारम्भ होने वाले इस उत्सव की महत्ता क्या थी, किस प्रकार इसे सम्पन्न किया जाता था, इसके प्रमान क्या होते ये श्रीर जीवन भर इसका क्या महत्व रहता था, प्राचीन भारत की राजनीति का श्रध्ययन करने वाले विद्यार्थी के लिए, यह सचमुच एक रोचक विषय है। वास्तव में ब्राह्मणे साहित्य के युग में यह श्रिभिषेकोत्सव बहुत विशाल (Elaborate), परम्परामय (Ritualistic) तथा तकनीकी (Technical) बन गया था श्रीर एक निश्चित धार्मिक उत्सव तथा पद्धति के रूप में स्वीकार कर लिया गया या । राजधरानों के लिए इस पद्धति की मान्यता दे दो गई थी। उसी समय से प्रत्येक हिन्दू राजा श्रीरं सम्राट् ने निरन्तर इसका पालन किया है। नंए राजा को अपने पद का पूर्ण अधिकार प्राप्त करने के लिए अभिषेकोत्सव श्रानिवार्य माना गया था। इस उत्सव के तिनां कोई व्यक्ति सम्राट् नहीं जन सकता था। हमारा सम्बन्ध अधिकांश इस उत्सव की संवैधानिक महत्ता से है-केवल रीति-रिवाज श्रीर श्रीम-षेकोत्सव की परम्परा से नहीं। परन्तु अध्ययन थोड़ा बहुत समी परम्पराओं का करना अतिवार्य हो जाता है ।

अभिषेक्तकोसन का नर्णन — नेदों में समान के अध्यक्तों के अभिषेक के लिए तीन उत्सनों का नर्णन किया गया है । सर्वप्रथम राजसूय अर्थात् सन्नाट् का कार्य प्रारम्म (Inauguration of a King) । दूसरा नाजपेय अर्थात् राजा का नास्तनिक संस्कार (Consecrating of a King) और तीसरा सर्वमेध अर्थात् विश्वराज्य के लिए 'बलि-दान) यत्र करना। × इनमें से दूसरा तो राजनैतिक दोन का उत्सव नहीं था, केवल खेलों आदि के उद्घाटन में प्रयोग में माता था और यही नाद में राजपरानों और धार्मिक उत्सवों में भी अपना लिया गया था। तीसरा सर्वमेध तो एक विशेष उत्सव था, इसे सम्राट् करता था जो पहले से ही शासक होता था। किन्तु प्रथम "राजस्य" अर्थाव राजा के लिए वास्तविक परम्परा थी। शततथ ब्राह्मण में उल्लेख है—"सज्ज एव राजस्थम" अर्थात् राजा के लिए वास्तविक परम्परा थी। शततथ ब्राह्मण में उल्लेख है—"सज्ज एव राजस्थम" अर्थात् राजा के लिए वास्तविक परम्परा 'राजस्य" की है। इसी के द्वारा वह सम्राट् बनता है। आगे जाकर "वाजपेय" को 'राजस्य" के पहले की परम्परा माना जाने लगा था। "राजस्य" को भी मुख्य तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है—(१) प्रारम्भिक-यज्ञ (Preliminary Sacrifices), (२) अभिवेकनीय (Sprinkling or Anointing) एवं (३) उत्तर-अभिवेकनीय परम्पराए (Post-anointing Ceremonies)। इन तीनों में मध्य भाग अर्थात् अभिवेकनीय सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसी उत्सव के पश्चात् वह व्यक्ति सम्राट् कहलाता था, इससे पूर्व वह साधारण नागरिक रहता था।

ः(१) प्रारंभिक यज्ञ के अ तर्गत स्थारह भेटें (एकादश रत्नानि) राज्य के विभिन्न ग्यारह प्रधान अधिकारियों को दी जाती थीं। ये लोग सेनानी, पुरोहित, महिषी (Queen), सत् (Court Minstrel) ग्राम्णी, चत्री (The Chamberlain) संग्रहीत्री या संनि-भाती (Master of the Treasury), भागद्वा (Collector of Revenue:) समाहर्त्रि, अञ्चलाप (Controller of Gambling), गोविकतृ (Master of forest or Distroyer of Beast) त्रौर पालागला (The Courier) इन्हें 'रितन' कहा जाता था। इनमें से प्रत्येक राज्य के लिए महत्वपूर्ण सेवाए अपित करता था। पालागला (The Courier) शुद्र जाति का होता था । अतिम दोनों के नाम मैत्रायणी संहिता में तज्ञाः (Carpenter) श्रीर रथकार (Chari of-builder) नताए गए हैं। + वास्तव में प्राचीन काल में "पलाश-मिएं" में हुनी जाती थी और ये 'रितन इसी मिए से संबंधित ये। ये लोग "राजकृतः" (Kirg-makers) भी बहलाते थे । राज्य के स्तम्भ होते । श श्रीर सम्राट इन पर विश्वास करता था। इसीलिए इस श्रीसी में वे सब लोग थे जिनका सहयोग कुशल व्यवस्था और चंद्रस् प्रशासनं के लिए अनिवाय माना जाता था। यजुर्वेद की संहिता के अनुसार रथकार और तदा भी रतिन में सम्मिलत किए जा सकते हैं, क्योंकि इनकी स्वामिमिकि पर राजा की सुरचा और यात्रा की निरापदता निर्भर करती थी। जितना बड़ा राज्य-- उतना ही विभिन्न कार्यचेत्र का विस्तार । इन रितन के चुनाव में संभवतः वर्ग और जातियों का ध्यान रखा जाता था। शुद्र जाति के प्रतिनिधि से लेकर उच्चकुलीन पुरोहित तक इसी श्रेणी में थे। इन्हें रामायण में भी 'राजकत्तीरः' कहा गया है। जैसे आधुनिक समय में केविनेट सदस्यों का महत्व होता है उसी प्रकार आचीन काल में ताज़तंत्र होते हुए भी

प्रकार अक्षतंपथ मोहार्या, श्रद्धाय १३, मिलिक विकास के विकास के कि कि कि कि

[#]M. S. II. 6. 5. As quoted by Dr. Jayaswal-Hindu Polity-Page 203.

ये "रितन" वास्तव में (King-makers) राजकृत: ये जो राजा की अपने पद पर मुशोभित रखने में कुशल होते थे और सम्पूर्ण शासन में पूर्ण सहयोग देकर सफल जनाते थे।

डॉ॰ जायसवाल की मत है कि ये 'रितन' मीलिक रूप से समिति के अंग ये और सम्राट के पूर्व भी स्वतंत्र रूप से विद्यमान थे। यही कारण है कि बाद में भी इनका स्थान ''सम्राट-रचियता के रूप में माना जाता रहा। इनके महत्व के कारण ही इन्हें प्रत्येक अभि- पेकीत्सव के पूर्व सम्राट द्वारा सम्मानित किया जाता था। यही नहीं, सम्राट के अभिषेकीत्सव के अंतर्गत समस्त संबंधित महत्वपूर्ण संस्थाओं और व्यक्तियों का समर्थन प्राप्त किया जाता था और सम्राट अत्यन्त नम्रतापूर्वक प्रशासन के उत्तरदायित्व को जीवन पर्यन्त वहन करने के लिए स्वीकार करता था। धरती माँ की ''श्रंनुमिति'' भी प्राप्त की जाती थी। — इसके बाद सोम और रुद्र को पेय चढ़ाया जाता था, जिसका अर्थ था कि दैविक शिक्त भी सहायक वनी रहे।

(२) श्रिभिषेक्रनीय (Sprinkling Ceremony)—उत्सव का यह भाग उस समय श्रारंभ होता था जब प्रारंभिक यह समाप्त हो जाते थे श्रीर देवताश्री से श्राशीवीद होने के लिए कार्य आरंभ होता था। देवताओं से कुछ शक्तियों और गुंगों की याचना की जाती थी जिससे सम्राट पूर्ण रूपेण योग्य और कुशल बन जाय । सविता (सूर्य) से शिक्त, सोम से वनीं की रचा, गुरु से वाणी, इन्दु से शासन, रह से पशुरचा, मित्र से सत्य तथा वर्रण से विधि की सरदा के लिए प्रार्थना की जाती थी। तत्पश्चात् अनेक जल-स्थानों से एकत्रित जल द्वारा श्रभिषेक किया जाता है। समुद्र, भील, तालाव, कुश्रों, पुष्करिणी श्रादि सभी स्थानों से इसलिए जल एकत्रित किया जाता था कि जल स्वतंत्र है, राष्ट्र को जीवन देने वाले हैं। इनकी कृपा भी भावी सम्राट के लिए अपेद्धित है। शतपथ बाह्मण में लिखा है "स्वराजस्थ राष्ट्रदा राष्ट्रमनुष्मै दत्त" श्रेशीत् श्रेपने स्वमीव के श्रनुसार मुक्ते भी स्वतंत्र राष्ट्र प्रदान करें। इसमें यह भी भावना है कि सब स्थानों का महत्व मानते हुए उनकी महत्ता बताई है श्रीर उनके सहयोग की प्रार्थना की है। इसके बादः श्रिभिषेक की दंसरा भाग श्रारम्भ होता था जन सिंहासनालढ़ होने से पूर्व सम्राट् के ललाट पर पुरोहित द्वारा तिलक किया जाता था और वह विछी हुई केहरिछाला पर खड़ा हो जाता था । यहाँ चार व्यक्ति-माहाण, कुलबन्धु, राजन्य और वैश्य उसका अभिषेक करते थे । इन चारों व्यक्तियां को चारों वर्णों का प्रतिनिधि बताया गया है । तालर्थ यह कि बाहाण, च्विय, वैश्य तथा शूद्ध चारों प्रकार के प्रतिनिधि अभिषेकोत्सव में भाग लेते थे। बाद के प्रन्थों में तो शूद की उपस्थिति सदैव स्वीकार की गई है। तत्पचात् सम्राट् पवित्र वस्त्रं, श्रीर मुकुट (किरीट) धारण करता था श्रीर पुरोहित उसे एक दृढ़ धनुष एवं तीन बाण यह कामना करता हुआ प्रदान करता था-"रद्धा करो" और फिर अनेक प्रकार से देवताओं के नाम आहि

[÷] शतपथ नाहाय में अनुमति प्राप्त करने का सुन्दर वर्यन है। तदनुसार पीछे न देखते हुए वापस आते हैं और मटकी के आठ गोल इकड़ों (संगवतः धरती मों के आकार से सान्य रखने के लिए) पर रोटी रक्खे हुए अनुमति प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं। (Dr. Jáyaswal-Hindu Polity 205)

लेकर घोषणाएँ की जाती थीं । यह सब प्रतीकात्मक (Symbolical) अधिक था और इस पद की वैधानिक स्थिति को अधिक स्पष्ट करता था।

इससे अधिक महत्वपूर्ण कार्य था शपथ ग्रहण, जिसे उस समय "धृतवत" कहा जाता था । तैतिरीय बाहाण में 'सत्यसव', 'सत्यधर्म', 'सत्यस्वा', शब्दों का प्रयोग भी हुआ है, परन्तु इनका अर्थ स्पष्ट नहीं है। शपथ ग्रहण सम्राट् द्वारा की जाती थी उसे प्रतिशा भी कहा जाता था । इसमें कोई देवी तत्व को प्रधानता नहीं दी गई थी । शुद्ध मानव व्यवहार ही इसे माना जा सकता है। पुरोहित, जो समाज का प्रतिनिधि भी माना जाता था और सम्राट् के कुल का ग्रुक होता था, उसी के समन्न यह शपथ ग्रहण होती थी। इसके बाद सम्राट् काष्ठ आसन पर आसीन होता था। × जिस पर केहरिछाला किछो होती थी। यहाँ चारों प्रतिनिधियों को सम्राट् की रज्ञा का भार दिया जाता था। यह सम्राट् की स्थित को पूर्ण रूपेण संवैधानिक (Constitutional) बना देता है। अर्थात् प्रजा द्वारा सुरज्ञित सम्राट् प्रशासन संचालित करता था। प्राचीन हिन्दू दण्डनीति का यह केसा सुन्दर सिद्धान्त था। राजतंत्रात्मक प्रजातंत्र का यह स्वरूप आज के इंगलैंड के प्रजातंत्र से कहीं बढ़कर सिद्ध होता है।

सिंहासनालड़ होने से पूर्व सम्राट एक स्वर्णपात्र पर चरण रखता है और पुरोहित द्वारा १०० या ६० छिद्र वाली स्वर्ण चलनी में होकर सम्राट पर जल का अभिषेक किया जाता था। उस समय विभिन्न श्लोक और मन्त्रों का उच्चारण किया जाता था। उस समय पुरोहित सभी देवताओं की स्तृति करता हुआ सम्राट के लिए उनकी कृपा की कामना करता था। तब तीन चरण काष्ठ सिंहासन पर आगे बढ़ने के बाद सम्राट की संबोधन करते हुए यह कहा जाता था कि:—

"इयं ते.राट् ।""" "यन्तासि समनो ध्रुवीसि ध्रुक्णः । व्यवकार के विकास

कृष्ये त्वा चेमाय त्वा रस्ये त्वा पोषायत्वा" ॥ शतपथ न्नाहाण । अर्थात् यह राष्ट्र तुम्हें दिया गया है । अन तुम्हों इसके संचालक और व्यवस्थापक हो, तुम्हों इस राष्ट्र को घुवरूप से धारण करोगे । कृषि, कल्याण, समृद्धि और विकास के लिए यह राष्ट्र तुम्हें दिया गया है । नित्त सम्राट् सिंहासन पर वैठता था । इसके बाद ही सम्राट् को शिक्त (सत्ता) प्राप्त होती थी । राज्य कोई दान, दिचिणा या मेंट नहीं था वरन न्याम (Trust) था । जिसकी रक्षा करना सन सम्मन्धित व्यक्तियों का परम धर्म था और सम्राट् उनका अध्यक्ष होता था । इस प्रकार अभिषेकोत्सव द्वारा यह मानवीय संस्था शुद्ध रूप से लोकसंस्था सिद्ध होती है । सम्राट् का चुनाव, मनुष्यों द्वारा मनुष्यों में से होता था । देवताओं से उसके और लोक के कल्याण की पार्थना की जाती थी और उत्तरदायित्व अभिषेक-प्रतिज्ञा

[×] हाथीदाँत और स्वर्ण के सिंहासन होते गुण भी इस जत्सव के अवसर पर काष्ठ आसन का ही उपयोग किया जाता था और उसी पर यह प्रथा सम्पन्न होती थी। भारत के काष्ठ सिंहासन का स्वरूप तो पुराणों में असिंख माना गया है।

⁺ रातपथ हाल्य-Volume 2.1. 25 (As quoted by Dr. Jayaswal-Hindu Polity-P. 215.)

द्वारा सम्राट् पर भी रक्ता जाता श्रीर समर्थन द्वारा जनता का सहयोग भी श्राश्वस्त होता था।

(३) उत्तर-अभिषेकनीय परम्पराएँ (Post-anointing Ceremonies)-वास्तविक श्रभिषेकोत्सव के सम्पन्न हो जाने के पश्चात् कुछ श्रीर भी रूढ़ियाँ सम्पन्न होती थीं। उनका भी अपना-अपना प्रतीकात्मक (Symbolical) अर्थ होता था । शपथ महरण करने वाला सम्राट् फिर सिहासन से उत्तर कर वराह-चर्म की जूतियाँ धारण करता था और चार घोड़ों के रथ पर चढ़कर सवारी के लिए जाता था । रामायण-काल में यही राज्याभिषेकोत्सव से सम्बन्धित जुलूस के रूप में परिवर्तित हो गया । पुनः वापस त्राने पर सम्राट् सिंहासन पर बैठता था और फिर पुरोहित आशीर्वाद देता था। सम्राट्को पीछे से एक दग्ड द्वारा भी स्पर्श किया जाता था । इसका प्रतीकात्मक अर्थ यही था कि दण्डनीति द्वारा ही इस सिंहासन की रचा हो सकती है और इसी को हम 'राजदण्ड' का प्रतीक भी मान सकते हैं। कुछ ग्रंथकारों ने इसका ऋर्थ यह लगाया है कि राजा की 'दराड-वध' से सुरिचत बनाने के लिए यह दण्डस्पर्श किया जाता था। परन्तु यह उचित नहीं प्रतीत होता । इसके बाद सम्राट् को सम्मानपूर्वक प्रतिष्ठित स्वीकार किया जाता था। सारे उचा-धिकारी उसके समन्न कुछ नीचे आसनों पर सुशोभित होते थे; जिनमें ब्राह्मण, न्विय, ब्रामणी आदि सभी सभी होते थे । इस प्रकार सम्राट्ट वास्तव में सबका राजा अर्थात् नायक, स्रीर संरचक बन जाता था, तत्र पुरोहित सम्राट् को खड्ग मेंट करता था। यह भी दण्ड का ही प्रतीक थी, जो जनता की रचा के हेतु उसे अर्पित की जाती थी । सम्राट् इसी खड़ग को फिर सब अधिकारियों के पास हस्तान्तरित करता था अर्थात् वह सबका सहयोग चाहता था। इसके बाद जुत्रा का खेल होता था। जैसे खेल में साथी स्त्रीर सहयोगी चाहिए उसी प्रकार राज्य संचालन सहयोग विना सम्भव नहीं इसीलिए 'रितन' के साथ यह खेल जमाया जाता था। गाय की बाजी लगाई जाती थी जो समाज के साधारण सदस्य द्वारा स्वेच्छा से ही जाती थी। ये सभी क्रियाएँ प्रतीकात्मक अर्थ से युक्त थीं श्रीर सबका ध्येय एक ऐसी जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापित करना था जो सहयोग पर आधारित हो श्रीर जनहिंत स्त्रौर जनसमृद्धि से प्रेरित हो ।

श्रीभेषेकोत्सव का महत्व तो सदैव से चला श्राया है श्रीर उसकी कुछ बात तो इतनी महत्वपूर्ण हैं कि श्रांक भी इस विषय के विद्यार्थी की श्राहचर्यान्वित किए विना नहीं रहतीं। उस प्राचीन युग में इतनी उन्नत श्रीर संवैधानिक संस्थाएँ भारतवर्ष में सफलता-पूर्वक विद्यमान थीं। इस पर विचार करने से श्रमेकों महत्वपूर्ण पन्न हमारे सामने श्राते हैं। धर्मिष्रय देश होते हुए भी प्राचीन काल में श्रिभिकोत्सव पूर्ण रूपेण लोकोपचार के रूप में ही रहा-इसमें किसी देवी या ईश्वरीय तत्व प्रवेश नहीं कर पाया देवताश्रों से प्रार्थनाएँ श्रीर कृपा की श्राकांचा की जाती थी किन्तु इससे सारा लोकोपचार कुछ पवित्रता की श्रीर श्राग बढ़ा, देवल की श्रोर नहीं। दूसरे, श्रभिषेकोत्सव यह प्रमाणित करता है कि सम्राट् का पद वंशानुगत नहीं था। समस्त पना द्वारा, श्रनेकों चार, श्रनेकों ढंग से, विभिन्न

प्रतिनिधियों द्वारा उसके सिहासनारूढ़ होने के लिए अनुमति लेनी पड़ती थी और कई लोकोपचारों में उसी व्यक्ति के अभिषेक की पुष्टि की जाती थी । यह प्रथा वास्तव में निर्वाचन की अपेत्ता भी अधिक अच्छी और लोकप्रियता पर आधारित थी। समस्त जनता प्रत्यच या अप्रत्यच रूप में सहयोग करती थी। कई मंत्र और घोषणाएँ यह भी आभास देती हैं कि यह लोकोपचार, समभौते की माँति, राजा और प्रजा में, एक दूसरे के प्रति कर्त व्यनिष्ट श्रीर धर्मपरायण बनाने में भी सहायक होता था । श्रन्य उच्च श्रिषकारियों की उपस्थिति. उनका सम्मान श्रीर सहमति तथा बाद में उन्हीं श्रिधिकारियों द्वारा सम्राट् की प्रतिष्ठा करना श्रीर राज्य शासन के उत्तरदायित्व में हरे प्रकार की सहायता का श्राश्वासन देना, यह सिद्ध करता है कि सम्राट् का पद व्यक्तिगत सम्पत्ति नहीं था, बल्क राज्य की संस्था के रूप में था और वह सभी अधिकारियों (रितन) के सहयोग से संचालित होना चाहिए था । हिन्दू राजनीति में राष्ट्र एक न्यास (Trust) माना जाता था श्रीर लोकसमृद्धि श्रीर जन कल्याण के हेतु इसकी रचना की गई थी । व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति तो कल्पना से परे थी ही; किन्तु राष्ट्र का यथावत् रहना भी ऋसहा था । निरन्तर प्रगतिशील ऋौर विकासोन्मुख बनाए रखना समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों का मुख्य उत्तरदायित्व था। सम्बन्ध के सम्बन्ध में यह तो स्वप्न में भी नहीं सोचा जा सकता कि वह स्वेच्छाचारी बन सकता था। प्रत्येक चरण पर उसकी नमता, कर्ताच्य श्रीर सबका सहयोग इस बात का छोतक है कि वह अकेला असमर्थ है और भवते साथ ही वह राजकार्य में सफल होने का श्रभिलाषी है । नियमों का स्थान सर्वोच्च था। सम्राट् विधि के श्रनुसार ही चलता था। श्रभिषेकोत्सव नियम की महानता श्रीर उच्चता को सिद्ध करता है। प्रचीन भारतीय राज-नीति में सम्राट्का पद वास्तव में राष्ट्रीय संस्था थी, देशीय अथवा प्रान्तीय नहीं। हमारे पूर्वजों ने जिस वैधानिक तंत्र की कल्पना कर व्यावदारिक रूप दिया, वह वास्तव में अद्भुत **श्रीर श्रलीकिक है।** कार का उन्हर्स है के कार का अंदिल अवने कार्य प्राप्त के स्थान

पद्च्युत सम्राट — शुक्त यजुर्वेद श्रीर कृष्ण यजुर्वेद में पद्च्युत सम्राट के लिए भी एक यज्ञ का विधान है, जिसे सीत्रामिण यज्ञ (Sautramani Sacrifice) कहते हैं। इससे गह सिद्ध होता है कि सिंहासनारूढ़ करने के समान ही सिंहासनच्युत करने की प्रथा भी प्रचलित थी। वैदिक काल में राजाश्रों का जीवन पूर्यन्त श्रपने पद पर रहना उस तरह निश्चित नहीं था; जैसा वाद में राजतंत्रात्मक व्यवस्था के समय के लिए सोचा जाने लगा था। पीछे जाकर इस प्रधा का प्रचलित होना वैदिक काल के श्रनुभव श्रीर प्रसंगों के श्राधार पर सत्य प्रमाणित होता है।

उत्तर-वैदिक काल में राज्याभिषेक उत्सव का महत्व-भारतवर्ष की प्रत्येक संस्था में सदैव से समय के साथ चलने की विलक्षण प्रतिमा रही है। राज्याभिषेक उत्सव भी इसका अपवाद नहीं है। ज्या ज्या समय आगे बढ़ता गया और परिस्थितियाँ परिवर्तित होती गई इस उत्सव की प्रथा में भी साधारण परिवर्त्त न होते गए। महाभारत में लिखा है- ''ग्रचियता सभासदः" X अर्थात् सभासदों की अर्चना की गई। प्राचीन काल में को 'रितन' ये उनके स्थान पर महाभारतकाल में सभासद पूज्य बन गए। यह स्पष्ट है कि ये सभासद वास्तव में मंत्रिपरिषद् (Cabinet) के सदस्य होते ये। रामायणकाल में पीर अर्थार जानपद को महत्व दिया गया और स्थकारी तथा तज्ञा के स्थान पर व्यापारी वर्ग को प्रतिनिधित्व मिला। इसी काल में महिला वर्ग की उपस्थित भी नवीन तत्व था। ग्राभिषकोत्सव में कुमारी कन्याएँ भी भाग लेती थीं। श्री नीलक्ष्यठकृत ''नीतिमयूल'' के अनुसार मुख्य चार श्रमात्यों (ब्राह्मण, च्रिय, वैश्य एवं श्रूद्र) द्वारा राजा का श्रमिषेक किया जाता था। न इसके पश्चात् श्रम्य व्यक्तियों तथा प्रतिनिधियों द्वारा ग्रमिषेक होता था। तब सम्रट व्यापारी वर्ग तथा मंत्रियों के मध्य में बैठता था। उसके पश्चात् जुल्स निकलता था और उत्सव समाप्त हो जाता था। यह भी वर्णन मिलता है कि बाद में सम्राट् हाथी पर सवार होकर राजधानी का निरीच्ला करता हुन्ना पुनः राजप्रसाद में प्रवेश करता था। इसके पश्चात् बाह्मणों श्रीर समाज के प्रतिनिधियों की धर्मपत्नियों को सम्राट् नमस्कार करता था श्रीर वे सब सम्राट् को आशीर्वाद देते थे।

हस प्रकार वैदिक काल के लोकोपचार और उसके बाद की रीति में विशेष अन्तर नहीं है परन्तु उसमें क्रमिक विकास अवश्य हुआ है। महिला वर्ग का प्रदेश, प्रतिनिधित्व पर बल तथा अधिकारियों के परिजनों का सम्मिलित होना उत्सव की अधिक लोकप्रियता पर प्रकाश डालता है। इस उत्सव में दूसरा महत्व "शपथ ग्रहण" का है। बाद में इसे "प्रतिज्ञा" "अ ति" आदि नामों से भी पुकारा गया है किन्तु इसके वैधानिक महत्व में समय के साथ और भी दृद्धि हुई। जब सम्राट् प्रतिज्ञा करता था तो जनता "एवमस्तु" कहती थी अर्थात् ऐसा ही हो। इस प्रकार प्रतिज्ञा माननीय रही और जनता उसकी साची जनी। यह प्रथा इस रूप में अन्यत्र दुर्लभ है। यही नहीं, इस शपथ ग्रहण का प्रभाव समय समय पर बड़ा महत्वपूर्ण सिद्ध होता था। अपनी प्रतिज्ञा पूरी न कर सकने वाले सम्राट्या राजा को "असत्वप्रतिज्ञ" और "असत्यस्वप्रच्य" आदि नाम दिये जाते थे और उसे राज्यसिंहासन पर रहने का अधिकार भी नहीं रहता था। आवश्यकता आने पर सम्राट् बड़े गर्ब से अपनी शपथ दुहराया करते थे। इद्दर्भन ने अपने लेख में यह उत्लेख किया है कि वह "सत्य-प्रतिज्ञ" था। क्योंकि उसने शास्त्रों के विरुद्ध कोई कर नहीं लगाया। चित्राया। कार रहने साम राज्यसिंहास पर रहने का अधिकार मी नहीं रहता था। कार वेश से बाहर रखने में दुर्चल रहा, बाण ने "प्रतिज्ञादुर्जल" कहा है। महामारत में ऐसे व्यक्ति को 'विध्यमी' कहा है। अतः हम इस निक्क पर पहुंचते है कि उत्तर-वैदिक काल में राज्यभिषेक उत्सव का महत्व बढ़ता गया और समाज के जीवन में अधिक उपयोगी सिद्ध होने लगा।

[×] संभापन, श्रध्याय १३-४/२६/२६.

⁺ Dr. Jayaswal-Hindu Polity-Page. 223.

[÷] Dr. Jayaswal-Hindu Polity-Page. 228

मध्ययुग श्रीर उसके पश्चात्—दां जायसवाल का मत है कि मुस्लिम काल तक भी यह एक श्रावश्यक संस्कार के रूप में चलता रहा है। बाद में राज्याभिषेक के लिए राज-कुमार की श्रवस्था के सम्बन्ध में कुछ भिन्न भिन्न मत प्रकट हुए हैं। सम्राट खारवेल के लेख से तो यह प्रमाणित होता है कि २४ वर्ष की श्रवस्था से पूर्व राज्याभिषेक संभव नहीं था। जैनग्रन्थों से यह पता चलता है कि विक्रम का राज्याभिषेक उसकी २५ वर्ष की श्रवस्था में हुश्रा था। श्रशोक का राज्याभिषेक ४ वर्ष तक इसीलिए एका था कि वह उस समय केवल २० वर्ष का था। तात्पर्य यह है कि श्रवस्था एक श्रावश्यक तत्व था श्रीर श्राश्रम व्यवस्था के श्राधार पर भी २५ वर्ष की श्राधु हमारे यहाँ द्रथम श्राश्रम की पूर्णता के लिए श्रविवार्य थी। इस युग में भी यह उत्सव साधारण परिवर्त नों के साथ उसी रूप में चलता गया। हम राजस्थान के लोग तो इस परम्परा से मेलोमाँति परिचित हैं। यहाँ राज्याभिषेक परिवर्त कहीं राजतिलक तत्काल भी किया जाता था। परन्तु शासनाधिकार सदैव ही पूर्ण वयस्क श्रवस्था में प्राप्त हुश्रा करते थे। श्रतः बाद में भी राज्याभिषेक उत्सव मनाया जाता रहा।

उपर्युक्त वर्णन यह स्पष्ट करता है कि इस उत्सव का संवैधानिक महत्व बहुत था श्रीर श्रुन्तिम समय तक बना रहा । राजा श्रीर प्रजा के पवित्र सम्बन्ध श्रीर पारस्परिक सहयोग की उच्च भावना इसमें निहित थी ने इन्हीं कारणों से कौटिल्य जैसे राजनीतिज्ञों ने राजतंत्र के गुरा गाए हैं। इसी प्रथा के साथ राजा की संस्था का संवैधानिक स्वरूप बन जानी इसकी विशेषता है। नैतिक हिष्ट से इस समय का प्रतिज्ञानद सम्राट अधिनक समय के लिखित और कठोर संविधानों से अधिक प्रतिविधान रहता था । शापथग्रहण की प्रथा तो श्राज के प्रजातन्त्रों में भी श्रिपनाई जाती हैं। परन्तु श्राज का नैतिक श्राधार उतना हुड़ नहीं है। राष्ट्रीय विकास, एकता और दृढ़ता के लिए यह आवश्यक है भी। राज्य के कर्मचारियों को जो शायथ ग्रहण कराई जाती है, यदि वे सच्चे अर्थ में उसका पालन कर तो वर्त्त मान भ्रष्टाचार श्रीर दिलाई रह नहीं सकती। समय पर कार्यालय न जाना, जाकर कार्य न करना, कार्य न करते हुए असंतीष बताना आदि केवल कर्ताव्य-विमूद्ता के परिचायक हैं। प्राचीन भारत के आदर्श से यदि प्रत्येक भारतीय अपने को जरा सी सुस्ती में असत्यपतिज्ञ, प्रतिज्ञा दुर्वल आदि कह सकने का साहस कर सके तो क्या भारत संसार का अध्या नहीं बन सकता ! त्राज भारत में प्रत्येक राजा है और प्रत्येक राजा के लिए अपनी शपथ प्रहण और राज्या-भिषेक की आवश्यकता है। साथ ही आवश्यकता है अपनी शपथ को पूरा करते हुए सर्य-प्रतिज्ञ सिद्ध करने की। सम्राट खारवेल का लेख प्रत्येक व्यक्ति का आदर्श बन जाना चाहिए। जातक-यन्थों के विद्यम्बन काच्य में कही उक्ति आज सत्य सिद्ध हो रही है । उस समय प्रजातंत्र राज्यों में लोग कहते थे-

"ग्रहं राजा ग्रहं राजन्येति" ग्रर्थात् प्रत्येक ग्रादमी ग्रपने को राजा कहता था ग्रीर राजा का कहीं पता नहीं था । उस समय भी गणराज्यों की स्थिति थी ग्रीर ग्राज भी हम गणराज्य के नागरिक हैं । ग्रतः प्राचीन काल का राज्याभिषेक 'उत्सव ग्रपने ऐतिहासिक महत्व के साथ ग्रपना दूसरा महत्व भी रखता है जो ग्राधुनिक भारत का पथपदर्शन करने में समर्थ है ।

प्रश्त

1. Explain the constitutional significance of the Coronation Ceremony in the Hindu Polity

दसवाँ ग्रध्याय

लोकसभाएँ

(Public Assemblies)

प्रस्तावना—प्राचीन भारत का लोक-जीवन राजनीतिक दृष्टि से बहुत उन्नत स्त्रीर विक्रिस्त रहा है। उस समय जन-जीवन तथा राष्ट्रीय प्रवृत्तियाँ विद्यमान तो थीं ही किन्तु उनकी स्त्रभिव्यिक्त के साधन भी संगठित तथा मान्य रूप में प्रस्तुत थे। वेदों का स्रध्ययन करने से ऐसे प्रसंग स्रनेक प्राप्त होते हैं। प्राचीन काल के राष्ट्रिय जीवन स्त्रीर राष्ट्रिय गति-विधियों पर तत्कालीन लोकप्रिय संस्थास्रों स्त्रीर समितियों के द्वारा पूर्ण प्रकाश पड़ता है। इस श्रीणी में समिति, सभा, विद्य, श्रीणी, पूग, निगम स्त्रादि कई संस्थाएँ स्त्राती हैं। परन्तु इन सबका संगठन, शिक्तयाँ, महत्व, समय तथा कार्य भिन्न भिन्न रहे हैं। इनका स्रध्ययन बहुत ही रोचक है तथा स्त्राधुनिक प्रजातंत्र की लोकप्रिय निर्वाचित संस्थास्रों की त्रलना के लिए उपयुक्त भी। स्रतः हम इन संस्थास्रों का क्रमशः स्रध्ययन करेंगे।

(१) समिति—उपर्युक्त अनेक प्रकार की संस्थाओं में, समिति सबसे बड़ी संस्था थी जो वैदिक काल में हमारे पूर्वजों ने स्थापित की। इस समिति में समस्त जनता की उपस्थित अपेित्तत होती थी क्योंकि यही संस्था राष्ट्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर निर्णय करती थी। राजा का निर्वाचन, पुनर्निर्वाचन आदि विषय इसी समिति के समच उपस्थित होते थे। ''सिनिति'' का शाब्दिक अर्थ भी यही है—सम + इति अर्थात् सिमिलित होना। दूसरे शब्दों में सम्मेलन अथवा सभा में सिम्मिलित होना। इस प्रकार के प्रसंग अप्रवेद तथा अथवंदि में हैं जहाँ समस्त जनता की उपस्थिति की प्रार्थना की गई है। १ इस संस्था के अर्नेक कर्ता यों में मुख्य राजा का निर्वाचन था। यही संस्था निष्कासित राजा का पुनर्निर्वाचन कर सकती थी। इस प्रकार संवैधानिक हिन्द से यह सार्वभीम संस्था थी। इसके अतिरिक्त इस संस्था से संबंधित प्रार्थनाओं में यह प्रसंग आता है कि सब सदस्य एकता तथा सर्वसम्मित चाहते थे ताकि राष्ट्र की नीति (मन्त्र or Policy) सुचार रूप से स्वीकृत व संचालित हो सके। र

१ "विशस्त्वा सर्वा वान्छन्तु" ऋग्वेद X 173.

^{&#}x27;'त्वां विशो वृणतां राज्याय'' श्रथवंवेद III 4. 2. यहाँ विशः का श्रथे हैं समस्त जनता। डॉ॰ जायसवाल (Hindu Polity-Page 12) के मतानुसार वैश्य शब्द की उत्पत्ति इसी से हुई है। 'जिसका श्रथे हैं साधारण नागरिक।'

२ समानो मन्त्रः समितिः समानी' समानं वृतः सहचित्तमेषाम्'' (ऋग्वेद VI. 64.)

राज्य के सभी महत्वपूर्ण कार्य जैसे राज्य की नीति का निर्धारण, राजा का निर्वाचन, राष्ट्रिय जीवन की व्यवस्था त्रादि यही संस्था करती थी। राजा के निर्वाचन व पुनर्निर्वाचन के अधिकार से यह भी अनुमान किया जा सकता है कि इस संस्था और सम्राट या राजा के क्या संबंध थे १ कुछ प्रसंगों से यह भी प्रकट होता है कि राजा के लिए सिमिति की बैठक में उपस्थित होना अनिवार्य कर्ताच्य था।३ उपस्थित न होने पर राजा असत्य माना जाता था। छांदोग्य उपनिषद् का प्रसंग भी यह समर्थन करता है कि जब श्वेतकेतु श्रारुपय गौतम, पांचालों की समिति को देखने गया तो वहाँ के राजा प्रवाहन जैवाल समिति में उपस्थित थे। ४ इस प्रकार राजा नैतिक बन्धनानुसार समिति का सेवक था। इस संस्था में ऐसे भाषण दिए जाते थे जो साधारणतया सभी सदस्यों को रुचिकर अनुमव हों। वक्ता यह सिद्ध करने के लिए उत्मुक रहते थे कि उनकी कही नात, दिया हुआ भाषण अथवा प्रस्ताव समिति में अद्वितीय है। अपने विपित्त्यों श्रंथवा विरोधियों को वक्तृश्रों या वाद-विवादों में परास्त करना श्रभीष्ट माना जाता था स्रोर इसके लिए प्रार्थना की जाती थी । इन्द्र से यह कामना की जाती थी कि हमें विरोधियों से श्राधिक श्रन्छा भाषरण देने की चमता दीजिए, तथा विवाद में विजय प्रदान कीजिए। इसके अतिरिक्त सिमिति राजनैतिक, शैच्चिएक, आर्थिक आदि अन्य चेत्रों में भी कार्य करती थी । छांदोग्य उपनिषद् में श्वेतकेतु का प्रसंग आता है । ५ श्वेतकेतु केवल चौबीस वर्ष की त्रायु में शिचा समाप्त कर चुका था त्रीर यह गर्व करता था कि उसने समस्त धार्मिक व दार्शनिक यंथों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। जब वह पांचाल समिति के समज्ञ उपस्थित हुआ। तो चित्रिय राजा :प्रवाहन जैवाल ने उससे पांच दार्शनिक प्रश्न पूछे । क्रुमार श्वेतकेतु एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका। तो यह भाव व्यक्त किया गया कि "इन विषयों का ज्ञान प्राप्त किए विना कैसे कोई शिच्चित कहला सकता है।" ४ इस प्रकार समिति एक राष्ट्रिय श्रकादमी की भाँति कार्य करती थी।

समिति का कार्य संचालन करते के लिए एक अध्यक्त होता था जिसे ईशान या सभा-पति (President) कहते थे। इस पद पर विलक्षण प्रतिभा स्रोर प्र खरबुद्धि वाला व्यक्ति ही श्रासीन होता था। ६ समिति का संगठन तो समस्त नागरिकों से ही होता था। परन्तु विशिष्ट कार्यों के लिए छोटी छोटी विशेष कमेटियाँ बनाई जाती थीं जिससे राष्ट्रकार्य सुचार रूप से संचालित हो सके। यह धारणा, कि समस्त राष्ट्र इन समितियों में उपस्थित होता था; इसलिए सारे काम समस्त समिति द्वारा किए जाते थे, अञ्यावहारिक प्रतीत होती है। जैसे ग्राधुनिक विधान समाग्रों का ग्राधिकांश कार्य विभिन्न समितियाँ करती हैं, उसी प्रकार पाचीन भारत में भी यही प्रथा थी। श्वेतकेत से प्रश्नोत्तर करने का प्रसंग अवस्य ऐसी ही

१ राजा न सत्यः समितोरियानः ॥ = ऋग्वेद IX 92. 6.

छांदोग्य उपनिषद-V. 3.

४ पञ्चालानां समितिमेयाय, पञ्चालानां परिषदमाजगाम । ६ श्रस्य पर्पद देशानः सहसा सुदुष्टरो जन इति । पार० गृ० स्० ॥।. 13.4

छोटी समिति का है जिसमें कुछ विशेषज्ञ (Experts) थे। इसी में स्वेतकेत का साजा-त्कार (Interview) किया गया था। वैसे भी, प्रतिनिधित्व का सिद्धान्त प्राचीन कार में लोकप्रिय रहा था। गाँवों का प्रतिनिधित्व 'ग्रामणी' द्वारा किया जाता था, व्यापारिव संस्थाओं के प्रतिनिधि भी सम्राट के श्रिभिषेक उत्सव में सम्मिलित होते ये श्रीर दूसरे वगों को भी प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त द्वारा ही उपस्थिति का अधिकार दिया गया था। विशेपकर ग्रामों का अधिक मूल्य था। समस्त गांव एक इकाई होता था और सिमिति में अनेक ग्रामों वे प्रतिनिधि सम्मिलित होते थे, यह विश्वास किया जाता है। ग्रामों का श्रस्तित्व तो नियमानुसा भी इकाई के रूप में ही माना जाता था, इसलिए कभी कभी सारे ग्राम को दण्डित किया गया या ग्राम श्रमियुक्त या श्रमियोगी रहा, ऐसे प्रसंग भी मिलते हैं। समिति के संगठन का श्रापार हम गाँवों को ही मानते हैं और उनके प्रतिनिधियों द्वारा समिति का निर्माण होता था। डा॰ श्रब्टेकर के मतानुसार ऋग्वैदिक राज्य यूनानी नगर राज्यों की भाँति बहुत छोटे होते थे। एक रानधानी होती थी। गांवों स्वायत्त संस्थाएँ होती थीं जिसे सभा कहते थे श्रीर केन्द्र की संस्था को समिति कहते ये 10 समिति एक पूर्ण विकसित समाज की संस्था थी जहां वाद-विवाद, मुक्त भाष्य, तथा प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त व्यवहार में लाये जाते ये। यह रियति अविकसित अथवा अद्ध विकसित समाज में कभी नहीं आ सकती। इसलिए यूरोप की जनसभाओं (Folk-Assembly) प्राचीन भारतीय समिति के समज्ञ नहीं ठहर सकतीं। इसके अतिरिक्त ऐतिहासिक दृष्टि से भी यह संस्था शाश्वत मानी गई थी। इसे "प्रजापति की सुता" कहा है जो विश्व के रचियता हैं। ऋग्वेद तथा श्रथर्ववेद के प्रसंग यह सिद्ध करने में समर्थ हैं कि समिति बहुत प्राचीन संस्था थी। वैदिक काल में यह संस्था निरन्तर वनी रही परन्तु साम्राज्यों के विकसित होने के पूर्व ही यह लुप्त हो गई। जातकप्र थों के समय (६००वर्ष ईसा पूर्व) से पूर्व सिमिति का ऋरितत्व मिट चुका था। इस प्रकार वैदिक काल से लेकर ७०० वर्ष ईसा से पूर्व तक, लगभग १००० वर्ष समिति के निरन्तर बने रहने का समय माना जा सकता है। डॉ॰ जायसवाल के शब्दों में, "इसी समिति की राख में से दूसरी जानपद व पीर स्त्रादि की संस्थाएँ विकसित हुई थीं "६ बहुत उपयुक्त है। यही समिति का संचिप्त इतिहास है।

(२) सभा—दूसरी लोकप्रिय एवं प्रसिद्ध संस्था सभा कहलाती थी। यह संस्था समिति की समकालीन थी। अथर्ववेद में सभा एवं समिति की विहेने बताया गया है। १० यह सम्बन्ध इस बात को सिद्ध करता है कि सभा और सिमिति का संगठन, कार्य और शिक्षयों कुछ समानता लिए हुई थीं। सभा की प्रार्थना में

v Dr. Altekar-The State & Govt. in Ancient India-Page-129. 130

^{= &}quot;a daughter of Prajapati"-Atharva Veda VII 12

[€] Hindu Polity-Page 17.

र॰ समा च मां समितिस्वावतां प्रजापतेद्व दितरीं संविदाने । A. V. VII 12, 1.-As quoted by Dr. Jayaswal-Page 19 (Hindu Polity)

सिमिति की भाँति सहयोग के लिए याचना की जाती थी और विवाद एवं अन्य किसी भी प्रकार का विग्रह अशुभ समभा जाता था। सुमित और सहयोग तथा मिलकर आगे बढ़ने की प्रवृत्ति प्रशंसनीय समभी जाती थी। यह सभा समय समय पर अनेक प्रकार के प्रस्ताव भी पास किया करती थी। ऐसे निर्णय न तोड़े जा सकते थे और न उनका उल्लंघन ही संभव था। इसी विशेषता के कारण इन्हें 'नरिष्टा' की संज्ञा दी गई थी। प्रत्येक सदस्य वक्ता यह अभिलाषा लेकर आगे बढ़ता था कि समस्त उपस्थित सदस्य उसका सहयोग करेंगे! सभा में असहयोग-विरोध करने का पूर्ण अधिकार और अवसर होता था। एक बार निर्णय ले लेने पर सभा के निर्णय नियम का रूप धारण कर लेते थे और तंत्पश्चात् वे नियम सबके लिए मान्य हो जाते थे। उनका उल्लंघन किसी भी प्रकार संभव नहीं था इस तरह अध्ययन करने से हम इस निर्णय पर पहुँचते हैं कि सिमिति की भाँति ही सभा भी बहुत महत्वपूर्ण और शिक्तयुक्त संस्या थी।

ढाँ॰ जायसवाल के मतानुसार सभा श्रीर समिति पहले ही भली माँति संबंधित थीं परन्तु उनका संबंध किस प्रकार का था यह जात नहीं है। ११ साधारणतया 'सभा' का साहित्यिक श्रर्थ ऐसी संस्था से है जिसमें सब लोग योग्य हों श्रीर मिलकर प्रकाशित हों। १२ श्रयोत् वे लोग जो सभा के सदस्य बनते थे, वे इस प्रकाश से युक्त हो जाते थे। समाज में तथा राज्य में उनका सम्मान होता था। इस दृष्टि से ऐसा प्रतीत होता है कि सभासद् श्राज के विधान सभायी श्रथवा संसद सदस्यों के समान प्रतिष्ठित होते थे श्रीर लोक-जीवन का नेतृत्व उनके हाथ में होता था। यही कारण है कि उन्हें प्रकाश—युक्त श्रीर वैभवपूर्ण कहा गया है। सभा के संगठन के विषय में भी कुछ ऐसे प्रसंग प्राप्त हैं जिनके श्राधार पर हम श्रनुमानतः यह निर्णय ले सकते हैं कि इस सभा का एक श्रध्यत्त होता था श्रीर उसे सभापति कहा जाता था। श्रुक्ल यजुर्वेद में एक पंक्ति इस प्रकार है:—"नमः सभाभ्यः सभापति कहा जाता था। श्रुक्ल यजुर्वेद में एक पंक्ति इस प्रकार है:—"नमः सभाभ्यः सभापति के प्रतिनिधि तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति ही चुने जाते थे जो स्वाभाविक रूप से ही प्रजा के सम्मान के श्रिकारी होते थे। प्राचीन काल की श्रन्य श्रनेक संस्थाओं में भी इस प्रकार चृद्ध-जनों के हाथ में सत्ता रखी जाती थी श्रीर वे सम्मानपूर्वक उस श्रिधकार का समाज के हित में प्रयोग करते थे। सायण ने भी इस मत की पुष्टि की है। उसके श्रमुसार—

हे पितर: पालका: ""पितृभूता वा हे सभासदो जना: । ग्रर्थात् सभासद् लोग पिता की भाँति पालन करने वाले होते थे, पूर्वजों की भाँति शुभिचन्तक ग्रीर सत्कार्य के किए सम्बोधन योग्य होते थे । कम श्रायु, श्रनुभव श्रीर योग्यता वाले व्यक्तियों की उपस्थिति भी संभावना भी इस संस्था में नहीं की जा सकती थी। इस प्रकार कुशल नीतिज्ञ, श्रनुभव-

११ Dr. Jayaswal-Hindu Polity-Page 19.

१२ सहधर्मेण सद्भिनो भातीति सभा । पारस्करगृह्य-As quoted by Dr. Jayaswal.

१३ शक्ल यज्ञवेंद-XVI-24

युक्त वयोष्ट्रह्म तथा समाज के सम्माननीय व्यक्तियों द्वारा ही समा का निर्माण व संगठन किया

सभा के कार्य - प्राचीन काल की संस्थाओं के संगठन तथा कार्यप्रणाली ब्रादि का श्राध्ययन करने पर यह तो स्पष्ट ही हो जाता है कि प्रजातंत्र राज्यों की समाएँ प्रतिनिधि संस्थाएँ होती थीं और राज्य की प्रशासनीय समस्त सत्ता इन्हीं संगठनों में हाथ में रहती थी। परनत फिर भी इन सभात्रों के स्पष्ट कार्यों की सूची नहीं बनाई जा सकती। केवल विभिन्न प्रसंगों के आधार पर तथा विशेष विवरणों द्वारा यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अमुक कार्य तो अवश्य ही यह संस्था संपादित करती थी, । साधारणतया राजनीतिक, श्रार्थिक, सामाजिक, धार्मिक तथा अन्य उल्के हुए प्रश्नों पर पूर्णतया विचार करना एवं निर्णिय करना इन्हीं संस्थाओं के अधिकार में था । विरुद्धक के आक्रमण के समय शावय-सभा द्वारा कपिलवस्तु के द्वार खोलने की गंभीर समस्या पर विचार-विमर्श करना तथा मतदान के पश्चात् बहुमत द्वारा द्वार खोल देने का निर्णय करना इसका एक देवलन्त उदाहरेंगा है।१४ इस घटना से सभा के राजनीतिक अधिकारी का तेत्र स्पष्ट रूप से सिद्ध हो जाता है । सामाजिक चोत्र में भी सभा के अधिकार व्यापक ये िकौशल-नरेश प्रसेन जित् के विवाहसम्बन्धी प्रस्ताय पर भी शाक्य सभा ने विचार किया था । प्रसेन जित् ने शाक्यकुमारी से विवाह करने का प्रस्ताव किया था १५ और इसी पर विचार करते के लिए शाक्य सभा आमंत्रित की गई थी। इस घटना की तुलना इंगलैंड की उस आधुनिक घटना से की जा सकती है जिसके अनुसार सम्राट् एडवर्ड अध्यम की अपनी राजगद्दी छोड़नी पड़ी और संसद् ने अपनी परम्पराओं को अन्तरण बनाए रखा । इस प्रकार प्राचीन भारत में सभा के अधिकार एवं कार्य माजिक क्षेत्र में भी व्यापक रूप से प्रचलित थे, यह सिद्ध होता है। घार्मिक जीवन के चेत्र में भी सभाश्रों को श्रिधिकार प्राप्त थे । बुद्ध की मृत्यु के पश्चात् पावा की मल्ल समा का ग्राधवेशन बुलाया गया था ग्रीर उसमें केवल इस प्रश्न पर विचार किया गया कि उनका ब्रान्तिम संस्कार किस प्रकार किया जाय । यो तो भारतीय राजनीति सदैव ही धर्म से स्रोत-पोत रही है । सब धर्मों के प्रति एक सा व्यवहार स्रीर संरच्या प्रधान लच्य समभा जाता था; परन्तु फिर भी लोक-कल्याय तथा जन-हित की हिंद से महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, सामाजिक व राजनीतिक व्यवस्था संतुलित बनाए रखने के उद्देश्य से, समय समय पर आवश्यक दिलचरपी ली जाती भी है। इस प्रकार धार्मिक चेत्र में भी समा निरपेच नहीं कही जा सकती वरन् आवश्यक कार्य संपादित करती हुई सिद्ध होती है क्रीर वह भी प्रभावपूर्ण ढंग से । इस सम्बन्ध में कुछ लोग यह शंका कर संकते हैं कि सभा का यह कार्य समाज के घार्मिक जीवन में राज्य द्वारा अनावस्यक हस्तचेप है । परन्तु वस्तु-स्थिति इसके विपरीत है । सूक्ष दृष्टि से देखा जाय तो सभा का यह कार्य सिद्ध करता है कि भारतीय राजनीति का समाज के जीवन के प्रति बहुत उदार एवं व्यापक दृष्टिकीए था।

²⁸ Rockhill-Life of the Buddha-Page 1/119...

²⁴ Rhys Davis-Budhist India-Page-11.

इस दृष्टान्त से हमारी प्राचीन राजनीतिक संकीर्णता प्रकट नहीं होती, वरन् उसकी उदार एव व्यापक वृत्ति की पुष्टि होती है।

राजनीतिक चेत्र में इन्हीं अधिकारों को और भी अधिक स्पष्ट रूप से समभाने के लिए तीन भागों में बाँटा जा सकता है-व्यवस्थापिका सम्बन्धी, कार्यकारिणी सम्बन्धी तथा न्यायपालिका सम्बन्धी । व्यवस्थापिका सम्बन्धी अधिकारों में समा पूर्ण शिक्तशाली थी। राज्य के लिए नियम निर्माण करना, राज्य की निर्धारित नीति को मान्यता देना तथा पूर्ण कार्यविधि के ऋनुसार प्रत्येक प्रस्ताव पारित या रहः करना इसके मुख्य कार्य थे। महाभारत में भीष्म ने प्रजातन्त्र राज्यों के दोषों की व्याख्या करते हुए इसी तथ्य पर प्रकाश डाला है कि सदस्यों की अधिक संख्या के कारण गोपनीयता नहीं रक्ली जा सकती। १६ फिर भी सभा द्वारा स्वीकृत नीति के प्रतिकृल कार्य करना अथवा उन्हें टालना किसी भी स्थिति में सम्भव नहीं था । महात्मा बुद्ध के शब्दों में यह सत्य इस प्रकार प्रकट हुआ है कि लिन्छ वियों का भविष्य उसी समय तक उज्ज्वल है जब तक वे बिना नियम बनाए कोई श्राज्ञा में वित नहीं करते, बने हुए नियम का उल्लंघन नहीं करते श्रीर प्राचीन परम्पराश्री तथा नियमों के अनुसार कार्य करते रहते हैं। १७ इस प्रसंग से यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि समायों को व्यवस्थापिका के चेत्र में ब्रत्यधिक व्यापक तथा हु अधिकार प्राप्त थे श्रीर उनकी अवहेलना असम्भव थी। कार्यकारिएी सम्बन्धी चेत्र में भी सभा पूर्ण शक्तिशाली थी । वास्तव में नीति निर्धारण श्रीर नियम निर्माण की पूर्ण सफलता कार्यकारिणी पर ही निर्भर करती है। इस च्रेत्र के अ तर्गत नियुक्ति सम्बन्धी अधिकार सभा की प्राप्त थे। प्रजातंत्र में श्रीर विशेषकर गणतंत्र में स्वयं गण के अध्यत्त की नियुक्ति सभा द्वारी की जाती थी श्रीर श्रन्य मुख्य श्रिधंकारियों की नियुक्ति भी सभा द्वारा ही की जाती थी। इस प्रकार सभा के रूप में प्रजा के प्रतिनिधियों का प्रशासन पर पूरा अधिकार रहता या। राष्ट्रपति, समाध्येत्त, मुख्य मंत्री आदि की नियुक्तियाँ इनमें मुख्य हैं। इसके अतिरिक्त दैनिक प्रशासन संचालन, वर्तामान की भाति शासन सम्बन्धी जानकारी प्राप्त करना, आर्थिक स्वीकृति देना, वैदेशिक कूटनीतिक तथा व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करना, सन्धि-विमह का निर्णय करना आदि इसी प्रकार के अन्य कार्य थे, जो समा बरती थी।

न्याय के त्रेत्र में सभा के कार्य श्रीर भी श्रधिक स्पष्ट थे। सभा राष्ट्रिय न्यायालय के रूप में भी कार्य करती थीं, इसीलिए सभा की "कृष्ट" श्रीर 'पीड़ा" भी कहा जाता था। १८ यह बात श्राजकल की प्रथा से मिलती जुलती है, जहाँ न्यायालयों के नाम उनके काम

१६ मन्त्रगुप्तिः प्रधानेषु चारस्चामित्र-कर्षण ।

न गर्याः इत्रस्नशी मन्त्र श्रोतुमहन्ति भारत ॥ शान्तिपर्व १०७, २४

१७ दीव्यनिकाय, महापरिनिच्याया सुत्त, डायलाग्सः श्रॉफ दी मुद्ध रीस टेविस, भाग २, पुष्ठ ७६–द⊻ ।

१= पारस्कर गृहा-III,१३.

के अनुसार रमखे जाते हैं या जनता जिनका प्रयोग करती है। जैसे फीजदारी न्यायत्त्रय, दीवानी या माल का न्यायालय आदि । जिनके नाम से ही उनके काम के चेत्र का परिचय प्राप्त हो जाय। इसी कारण सभा में से सफलतापूर्वक स्त्राने वाले के मित्र, नाती स्त्रीर सम्बन्धी प्रसन्न बताए जाते थे श्रीर स्वयं तथाकथित श्रपराधी पूर्ण रूप से कलकमुक्त माना जाता था। इस प्रकार समा के अधिकार न्यायत्तेत्र में भी व्याप्त थे। इसी सम्बन्ध में जातक-मंथीं में अन्य ऐसे प्रसंग भी हैं जो सभा की इस चेत्र की व्यापक कार्यवाही को और अधिक सुरपष्ट करते हैं। उदाहरणार्थ-"जिस समा में संत व्यक्ति नहीं है, वह समा नहीं है," "जो धर्म (न्याय) का उच्चारण नहीं कर सकते, वे सज्जन नहीं हैं," "जो व्यक्तिगत भावकतात्रीं को दूर रख कर न्याय का पक्ष ले सकें, वे सर्वजन हैं। १६ इन वाक्यों द्वारा यह सिद्ध होता है कि सभा का न्यायपंच श्रौर सभासदों की न्यायप्रियता प्रशंसनीय मानी जाती थी श्रौर इसके अभाव या अनुपरियति में सभा को सभा ही नहीं माना जाता था।

इस प्रकार सभा बहुत महत्वपूर्ण, सर्व शक्तिसम्पन तथा सार्वभौम शक्ति से युक एक प्रनिनिधि सस्था थी । वैदिक साहित्य में समा शब्द का प्रयोग कभी भवन, कज, न्यायालय त्रादि के लिए भी प्रयुक्त किया गया है । परन्तु प्रतिनिधि संगठित सभा के लप में भी यह संस्था बहुत प्राचीन काल से विद्यमान थी और सभा और समिति समकालीन थी-यह ऋग्वेद के सम्बन्धित प्रसंग सिद्ध करते हैं । डॉ॰ जायसवाल के मतानुसार इसी लोक॰ प्रिय सभा के अवशेष, न्याय सभा के रूप में, शाही एवं साम्राज्यवादी केंद्रियकरण के काल तक बने रहे श्रीर न्याय व्यवस्था के चेत्र में महत्वपूर्ण कार्य भी किये जाते रहे । २०

सभा श्रीर समिति के सम्बन्ध में इतना जान लेने पर भी यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि इनका वास्तविक और शाश्वत अर्थ क्या था। यह संभव हो सकता है कि इन्हीं संस्थाओं का तात्पर्य भिन्न भिन्न युगों में स्त्रीर परिस्थितियों में भिन्न भिन्न माना जाता रहा हो । त्र्राधुनिक विद्वानों में भी इनके त्रर्थ के सम्बन्ध में मतैक्य नहीं है । उदा-हरणार्थ: पाश्चात्य विद्वान् लद्विग (Ludwig) की धारणा है कि सभा तो उच्च भवन था जिसमें धनी, पण्डित श्रीर ऊँची प्रतिष्ठा के व्यक्तियों के प्रतिनिधि होते थे श्रीर सिमिति कनिष्ठ भवन की भाँति था जिसमें जन-साधारण के प्रतिनिधि होते थे। श्री जिमर (Zimmer) के मतानुमार सभा एक ग्राम संस्था थी और समिति समस्त नीति की केन्द्रिय विधान समा । श्री हिलब्रागड (Hillebrandt) का विचार श्रीर ही है । उनकी हिंद में समा ग्रीर समिति कुछ कुछ समान ही थीं, जिसमें समिति तो संस्था थी ग्रीर समा उसका सम्मेलन स्थल । डॉ॰ जायसवाल के विचार अधिक उपयुक्त प्रतीत होते हैं जिनके द्वारा

Dr. Jayaswal-Hindu Polity (Page. 21)

न सा समा यत्य न संति संतो न ते संतो ये न भणन्त धम्मं। रागं च दोसं च पहाय मोहं धम्मं भणन्ता व मवन्ति संतो ॥ As quoted by Dr. Jayas wal-Hindu Polity-Page 21.

सिमिति एक राष्ट्रिय संसद् ग्रीर समा उसकी कार्यकारिणी के रूप में हो सकती है। तात्पर्य यह है कि इनका वास्तविक सम्बन्ध त्राज तक एक विचारणीय विषय ही बना हुन्ना है। इस सम्बन्ध में कोई ग्रन्तिम निर्णय प्राप्त सामग्री के त्राधार पर लिया जाना सम्भव नहीं है। स्वतन्त्र भारत के शोध कर्जा सम्भव है इस प्रश्न पर कुछ प्रकाश डाल सकें।

(३) बिद्थ—सभा और सिनित के अतिरिक्त एक और संस्था थी जिसे 'विद्य' कहते थे। समाज के धार्मिक जीवन का संगठन इस संस्था द्वारा किया जाता था। अपनेद में अनि को विद्य के रूप में वर्षित किया गया है। जिमर (Zimmer) के विचारानुसार विद्य सिनित का ही एक छोटा सा अग था। परन्तु डॉ॰ जायसवाल के मतानुसार विद्य ऐसी संस्था हो सकती है जो सिनित के भी पहले से विद्यमान थी। ऐसा भी प्रतीत होता है कि विदय एक प्रारंभिक लोकसमा (Parent folk—assembly) थी जिसमें से आगे जाकर सभा, सिनित, सेना आदि प्रकट हुई। क्यों विदय प्रशासनिक (Civil) सैनिक तथा धार्मिक कर्त व्यों से संबंधित थी। २१ डॉ॰ अल्टेकर के मतानुसार 'विद्य' शब्द की उत्पत्ति विद्ध धातु से हुई है जिसका अर्थ होता है धार्मिक सम्मेलन आदि, जहां सर्वोच्च ज्ञान की अपेद्रा की जाती है। उत्पर से यह संस्था ऐसी लगती थी जैसे किसी पूरी जाति (Tribe) का प्रतिनिधित्य करती हो।

इस प्रकार के प्रसंग भी प्राप्त हैं जिनसे यह प्रकट होता है कि विद्य के कार्य में भी िस्त्रयां भाग लेती थीं। वैसे तो वैदिक काल में महिलाओं का स्थान लगभग पुरुप के समान ही था ग्रीर वे सभी महत्वपूर्ण कार्यों में पुरुष का सहयोग करती थीं; किन्तु विद्य में िस्त्रयों का स्थान प्रधानता लिए हुए था। सम्राट भी विद्य में उपस्थित होते थे। श्री एस. ग्रार. शर्मा के मतानुसार विद्य द्वारा सैनिक कार्य भी किए जाते थे। २२ ऋग्वेद के अनुसार विद्य का संबंध राज्य के प्रशासनिक, (Civil) सैनिक (Military) एवं धार्मिक कार्यों से था। २३ परन्तु यह सब होते हुए भी विस्तारपूर्वक विद्य के संबंध में या उसकी विशेषतात्रों पर ग्राधिक प्रकाश डालना संभव नहीं है। ग्रान्य संस्थाश्रों की भाँति विद्य भी एक संस्था थी ग्रीर कुछ समय के लिए समाज से इसका भी ग्रापना महत्व रहा है यह कहा जा सकता है।

(४) सेना (Army)—-डॉ॰ जायसवाल के मतानुसार प्रारंभ में सेना एक संगठन के रूप में थी श्रीर समस्त देश ही सैनिक हिंदर से एक इंकाई समक्ता जाता था। इसकी संवैधानिक स्थिति भी स्त्रतंत्र थी। श्रिधिक विवरण इस संस्था के विषय में उपलब्ध नहीं है। कौटिल्य के समय में सेना राज्य के सात भागों में से एक श्रिनवार्य श्रांग वन गई, जो हम पड़ चुके हैं।

२१ Dr. Jayaswal-Hindu Polity (Page. 21)

³² Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society. 1952. PP. 429.

२३ "विद्यस्य धीभिः चत्रं राजानो प्रदिवो द्धाये," ऋग्वेद III 38. 5;

इस प्रकार उत्तर वैदिक काल की प्रवृत्तियाँ इन स्वतंत्र एवं स्वायत्त संस्थाओं के अनेक रूपों में प्रकट होती थीं। यही नहीं, आर्थिक त्तेत्र में भी समाज का जीवन इसी पद्धित पर वैज्ञानिक ढंग से उन्नत हो रहा था। श्रेणी, पूग, निगम आदि उस समय के आर्थिक जीवन के स्तम्भ थे जिनमें व्यापारी वर्ग, श्रमिक वर्ग तथा अन्य प्रकार की सहयोगी बृत्तियाँ संगठित होकर समाज कल्याण एवं आत्मकल्याण के कार्य में संलग्न होते थे। जातक-अंथ तथा धर्म सूत्रों में इस प्रकार के प्रसंगों का बाहुल्य है। अतः यह कहा जा सकता है कि वैदिक काल का राष्ट्रीय जीवन इन संस्थाओं के द्वारा संचालित होता था। इन्हीं संस्थाओं की पर म्पराएँ आगे चलती गईं। पौर-जनपद सभाएं इन्हीं संस्थाओं के अवशेष माने जाते हैं।

(४) पोर-जनपद्—इन संस्थाओं के संबंध में सबसे अच्छा और अधिकृत वर्णन डॉ॰ जायसवाल ने किया है। उनकी धारणा है कि इन संस्थाओं का समय लगभग ६०० वर्ष ई० प० ते लेकर ६०० वर्ष ई० प० तक निर्धारित किया जा सकता है। यह भारतवर्ष में ऐसा समय था जब अराष्ट्रिय तथा चेत्रीय राजतन्त्रों का विकास हो रहा था। और साथ ही राज्यों का विभाजन भी 'राजधानी' और 'समस्त राज्य' के रूप में होने लगा था। राजधानी को ''पुर'', २४ 'नगर', २५ या 'दुर्ग' २६ कहते थे और शेष समस्त राज्य को 'राष्ट्र', देश अथवा जनपद कहा जाता था। कौटिल्य ने राजनगरी के लिए नगर तथा दुर्ग शब्दों का प्रयोग किया है। पाणिनि तथा पातञ्जलि ने भी राजनगरी के लिए 'नगर' तथा 'पुर' शब्दों का प्रयोग किया है। अशोक के शिलालेख तथा अभिलेखों में भी नगर शब्द का राजधानी के लिए प्रयोग किया है। मनु ने भी राजधानी के लिए 'दुर्ग' शब्द का प्रयोग किया है। राजधानी के आतिरिक्त शेष राज्य के लिए आम शब्द का प्रयोग किया जाता था। बीर मित्रोदय, कौटिल्य, पाणिनि तथा पातञ्जलि ने भी यह प्रयोग स्वीकार किया है। प्रत्येक राज्य में राजधानी के अतिरिक्त शेष भाग अर्थात् आमों के समूह को सामूहिक रूप से जनपद, राष्ट्र तथा देश कहा जाता था। इसकी पुष्टि विभिन्न प्रसंगों से स्पष्टतः हो जाती है। मनु ने जाति, जनपद तथा देश कहा जाता था। इसकी पुष्टि विभिन्न प्रसंगों से स्पष्टतः हो जाती है। मनु ने जाति, जनपद तथा देश कहा जाता था। इसकी पुष्टि विभिन्न प्रसंगों से स्पष्टतः हो जाती है।

"बातिबानपद्गन्धर्मान्श्रेणीधर्मादच धर्मवित्।

समीच्य कुलधमीं श्चं स्वधमीं प्रतिपाद्येत् ॥ मनुसमृति ५।४१

हसी प्रकार दूसरे स्थल पर देश, कुल तथा जाति का उल्लेख भी किया है। जिससे देश तथा जनपद पर्यायवाची होना सिद्ध होता है। व्यास ने जनपद एवं देश की समानार्थी माना है श्रीर जनपद के श्रध्यक्त को ही देशाध्यक् कहा गया है। २७ जनपद तथा राष्ट्र भी

२४ "पुरं मुख्यनगरम्" - वीरं मित्रोदय, १५ ११।

देश "नगर राजधानी"—शर्यसास्त्र, पृष्ठ ४६।

२६ अर्थशास्त्र में दुर्ग भी राज्य का शावस्यक शह माना गया है। यहाँ दुर्ग का श्रामिप्राय उस रशान से है जहां समाद निवास करता है। वहीं से राज्य कार्य के चालित होता था और सम्रोट की प्रतिष्ठा व रहा की व्यवस्था की जाती थी, इसलिए इस राजनगरी या राजधानी कहते थे।

२७ देसाध्यकादिना लेख्यं यत्र जानपदम् कृतम् ॥ याद्यत्त्वय रष्टति २१६२ (Hindu Polity-19, 243)

पर्यायवाची थे। इसका दशकुमारचित द्वारा समर्थन होता है। इसके अनुसार एक एक ही व्यक्ति की राष्ट्र-मुख्य तथा जनपद-महत्तर कहा गया था। २८ इन दोनों शब्दों, मुख्य एवं महत्तर का अर्थ प्रधान से है। अतः यह सिद्ध है कि जनपद, राष्ट्र तथा देश का प्रयोग प्राचीन भारत में एक ही अर्थ में होता था। इस प्रकार यह निर्णय सही है कि 'पुर' ने तात्पर्य राजधानी से था और 'जनपद' से तात्पर्य राजधानी के अतिरिक्त साम्राज्य या राष्ट्र के रोष भाग से।

पोर तथा जनपद संस्थाओं का चेत्र:—उपर्युक्त वर्णन से यह सिद्ध है कि 'पोर' त्रीर 'जनपद' क्रमश: राजधानी तथा राज्य के शेष माग की संस्थाएँ थीं। इसिलए यह भी निश्चत रूप से वहा जा सकता है कि इन संस्थाओं के सदस्यों का निर्वाचन भी इन्हीं चेत्रों से होता होगा। १७० वर्ष ई० पू० के खारवेल लेख द्वारा यह पुष्टिं हो चुकी है कि जनपद् महत्वपूर्ण संस्था थी ह्रोर सम्राट द्वारा जनपद को विशेष द्राधिकार प्रदान किए जाते थे। रामान्यण के ह्रायोध्याकाएड में भी यह स्पष्ट वर्णन मिलता है कि जनपद् राजतिलंक की प्रतीद्वा कर रहा था ह्रीर जनपद पहले ही सर्वसम्मित से यह निर्णय कर चुका था कि राजतिलंक हो जाना चाहिए। यह निर्णय जनपद ने पौर के साथ संयुक्त सम्मेलन में लिया था ह्रीर सब की एक सम्मित थी। २६ मनुस्मृति में लिखा है:—

जाति जानपदान्धममीङश्रेणीधममीं श्च धममीवत् ।

समीद्य कुलधमां रेच स्वधमं प्रतिपाद्येत् ॥ श्रयांत् जाति, जनपद श्रीर श्रेणियों के नियमों (धर्म) का प्रतिपादन किया जाता था। ३० याज्ञवल्क्यस्मृति के श्रनुसार जनपद, गणं, श्रेणी तथा जातियां हर प्रकार से इकाइयां होती थीं श्रीर उनके लिए स्वधमं का श्रनुसरण करना श्रनिवार्य माना जाता था। ३१ गण श्रीर श्रेणी के साथ इस स्मृति में 'कुल' का प्रयोग भी किया गया है श्र्यांत् 'कुल' भी इसी प्रकार की एक संस्था थी, यह सिद्ध होता है। वृहस्पति ने भी श्रेणी, पूग श्रादि के साथ जनपद का प्रयोग किया है। 'देश,' 'संय' तथा 'जनपद' एक ही श्र्यं में प्रयुक्त हुए हैं जिसका श्रयं था राजधानी रहित सम्पूर्ण राज्य की संस्था। इन संस्थाश्रों की विद्यमानता की पुष्टि नालन्दा में प्राप्त मुहरों से श्रीर भी श्रच्छी तरह हो गई है। ये मुहरें सिद्ध करती हैं कि जनपद तथा पीर पूर्ण रूप से संगठित संस्थाएँ थीं। इन मुहरों पर लिखा है:-''पौरिका ग्रामजनपदस्थाः''। श्राजकल जैसे ग्राम-पंचायत, विधानसभा श्रादि की मुहरें होती हैं। उसी प्रकार की ये मुहरें भी शीं।

२म 'दशंकुमारचरित-अध्याय ३.

२६ रामायण अयोध्याकारह. पंक्ति २०-२२ (अध्याय २)

३० मनुस्मृति-अध्याय दा४१.

३१ व्यवहारान्स्वयं पश्येत्सभ्येः परिवृतोऽन्यहम् । कुलानिजातिश्रे णीरच गणाव्जानपदानिष ॥ स्त्रपर्माञ्चलितान्राजा विनीय स्थापयेत्पथि । ज्ञामश्रे णि गणानाव्च संकेतः समयकिया ॥ याज्ञवत्क्य, प्रथम ३६०, ३६१॥

पोर—राजधानी की विधानसभा 'पौर' साधारणतया देश की विधानसभा, जनपढ़ के साथ ही प्रयोग में त्राती रही है इसीलिए डॉ॰ जायसवाल ने भी पौर—जनपढ़ दोनों का प्रयोग एक साथ ही किया है। इससे यह भी प्रकट होता है कि ये दोनों संस्थाएँ युग्म बहनों की भांति (Twin Sisters) अथवा एक जोड़ी (Pair) की तरह ही समाज में रही हैं। इसीलिए कभी कभी एक संस्था के नाम के साथ ही दूसरी संस्था को समक्क लिया जाता रहा है। पौर का अर्थ यह तो नहीं है कि राज्य के प्रत्येक नगर की संस्था समक्का जाय। कुछ विद्वानों ने प्रारम्भ में ऐसा अर्थ लगाने का प्रयत्न किया है किन्तु अब यह भ्रामक माना जाता है। 'पुर' और 'नगर' का अर्थ तो अवश्य राजधानी होता था और प्राचीन हिन्दू लेखकों ने ऐसा ही माना है। अब इसके कर्ज व्यों पर विचार करना है।

कत्त व्य - पौर के कर्त व्य प्रधान रूप से राजधानी की सीमात्रों तक ही प्रभावशाली थे। नगरपालिका के समान राजधानी का पूर्ण नागरिक प्रशासन इस संस्था के हाथ में था। परन्तु इस कर्ज्ज के अतिरिक्त वैधानिक अधिकार और कर्ज्ज्यों का प्रयोग भी यह संस्था करती थी । सर्वप्रथम हमें नागरिक कर्त्त व्यों पर विचार करना चाहिए । पौर की स्त्रप्यच्या राजधानी के सुप्रसिद्ध नागरिक द्वारा की जाती थी, जो साधारणतया धनी श्रयवा मुख्य व्यापारी महाजन होता था। उसे 'श्रेष्ठी' कहा जाता था। वह पौर का सभापति या श्रध्यक्त होता था श्रीर नगर की न्यवस्था के सब कार्य व निर्णय यहाँ लिये जाते थे। नए नियम वनाना तथा अनावश्यक नियम रद्द यहीं किये जाते थे। रामायण के अनुसार पौर में आंतरीय ॰ क्रीर बाह्य दो वर्ग होते थे । क्रांतरीय वर्ग क्राधुनिक केबिनेट की माँति होता था जो कार्यकारिणी की तरह सम्पूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करता था। इसे नगरवृद्ध (Council of elders) समिति कहते थे। इसमें शूद भी हो सकता था। भूतपूर्व सदस्यों की समान में प्रतिष्ठा की जाती थी । मुख्य मुख्य पर्वो ग्रीर उत्सवीं पर उनका सम्पान, किया, जाता था । वे इस सम्मान के ग्राधिकारी माने जाते थे। इससे यह सिद्ध होता है कि इन संस्थाओं के संगठन का स्राधार लोकप्रियता तथा निर्वाचन होता खा प्रीर के कार्यालय में लेखसूची (Register) रखी जाती थी, जिसमें लौकिक-लेखाः (Popular documents) एवं राजकीय लेख (Government documents) का पूरा विवरण रक्या जाता था। इस प्रकार के लेखों का प्रमाण अकाट्य माना जाता था।

पीर के अन्य कार्यों में अ-राजनीतिक कार्य भी महत्वपूर्ण थे। सम्राट की ओर से उन्हें यह अधिकार प्रदान किया जाता था कि अविशिष्ट सम्पत्ति (गृतकों द्वारा छोड़ी हुई सम्पत्ति—Estates) का प्रबंध पीर ही करें। इसिलए इस कार्य को अविशिष्ट ही कहा जाता था। इसी प्रकार के कार्य और थे जो कमशः पौष्टिक, शान्तिक, 'न्याथिक' एवं 'देविक' कहे जाते थे। 'पौष्टिक' का अर्थ था ऐसे कार्य जिन्हें करने से नागरिकों के कल्याण की वृद्धि हो, वे आर्थिक तथा सामाजिक हिष्ट से मजबूत बनें। शान्तिक के अंतर्गत ऐसे कार्य किए जाते ये जिनसे राजधानों में शांति सुनिश्चित बनी रहे। पुलिस की व्यवस्था इसी के अन्तर्गत मानी जा सकती है। यह भी तीन प्रकार की व्यवस्था होती थी—साधारण, विशेष और गुप्त

(Discretionary)। न्यायिक के अंतर्गत पौर अपने न्यायालय द्वारा निर्णयों की व्यवस्था करता था जिसमें फीजदारी नियमों का महत्वपूर्ण स्थान था। साहस (Violence) के अभियोग उपस्थित होते थे और उनका न्याय पौर न्यायालयों में किया जाता था। 'दैविक' के यां तर्गत पौर पवित्र स्थान, मंदिर आदि तथा जनता के लिए विनोदस्थलों का प्रवन्ध करता था। उनकी मरम्मत करवाना, देखरेख की व्यवस्था करना पौर के मुख्य कार्य थे। इस चेत्र में भी पौर बड़ा सजग था। सभा (Assembly), प्रपा (प्याक्त), तथक (तालाव), आराम (विआन्तिएह), देवएह (मंदिर) आदि की व्यवस्था पौर द्वारा ही की जाती थी। इस संवंध में पाटलिपुत्र की व्यवस्था आदर्श मानी जा सकती है जिसका वर्णन हम आगे प्रशासन के यां तर्गत करेंगे।

ः पौर तथा निगम:--प्राचीन साहित्य में कई स्थानों पर पौर तथा निगम का प्रयोग एक ही ऋर्थ में हुआ प्रतीत होता है। इस साधन से पीर के सम्बन्ध में कुछ और वातों का ज्ञान भी होता है। संस्कृत में पौर-जनपद का प्रयोग हुआ है श्रोर जातक शंथों में निगम-जनपद का । ३२ पाली साहित्य भी इसी का समर्थन करता है । ३३ वीर मित्रोदय में लिखा हैं:--''नैगमाः पौराः,'' ''नैगमः पौरतमृहः'' ३४ अर्थात् निगम और पौर समान थे। निगम का ऋर्थ राजधानी के उद्योगपति, ज्यापारी तथा शिल्पियों का संगठन है जिसमें सब सम्बन्धित श्रे णियों का प्रतिनिधित्व हो । वीर मित्रोदय में भी पूर के विणकों की सभा की निगम बताया है। ३५ नांसिक गुफालेखंभी यह प्रमाणित करता है कि 'निगम' राजधानी के प्रमुख व्यापारियों की ही सामृहिक प्रतिनिधि संस्था थी । इस लेख के अनुसार एक दानी ने गोवर्धन की निश्चित श्रेणियों के पास कुछ धन जमा किया था ।३६ उसका उद्देश्य था कि उसके ज्याज को निश्चित दान में ज्यय किया जाय। यह कार्य उसने निगम सभा में लेख-त्रद्ध (Registered) करा दिया था। इस लेख 'से यह प्रकट होता है कि निगम सभा अपने अन्तर्गत विभिन्न औ िएयों के कार्यों का भी निरोक्षण करती थी और यह अधिकार निगम को इसलिए प्राप्त था कि वह समस्त श्री शियों की प्रतिनिधि संस्था थी। ऐसा न होने की अवस्था में इसं सारी कार्यवाही का कोई अर्थ ही नहीं होता। इसलिए उक्त स्थिति में सन्देह को स्थान नहीं है । इसी प्रसंग में यह भी ज्ञात होता है कि प्राचीन भारत में विभिन्न व्यापारियों, शिल्पकारों एवं अमजीवियों के संगठनों को श्रेणी तथा पूरा कहा जाता था श्रीर निगम इन सबकी प्रतिनिधि संस्था थी । यहाँ श्राकर हम यह निस्संकोच मान सकते हैं कि निगम सभा के लिए पूग एवं श्रेणी के सदस्य निर्वाचित होते थे '

३२ सब्बे नैगमजानपदे-जातक १ ५० १४६.

३३ नेगमा च एव जानपदा च ते भवं राजा आमन्तयतं । दीवनिकाय ।

३४ वीरमित्रोदय (चएडेश्वर) पृ० १७७ तथा १८०।

३५ नैगमा: पीरवाणिजः-वीर मित्रोदय (मित्रमिश्र) पृ० १२०।

रद "गोवर्धन-वाथवासुश्रे शिसु कोलीकनिकाये २००० वृधिपडिकरात एते च सर्वेक्षावित निगम सभाव निवध च फलकवारे चरित्रतेति" Nasik cave incliption. E. I. VIII, 82. Txst.

त्रथवा श्रेणी तथा पूर्ग के निर्वाचित ग्रध्यत्त ही निर्मासमा के पदेन (Ex-officio) सदस्य रहते होंगे। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि निर्मा का उद्देश्य राजधानी के हितोंका ग्रार्थिक दृष्टि से संरत्त्रण श्रीर उनका विकास करना था।

पौर श्रीर निगम के घनिष्ठ सम्बन्ध के कारण यही स्थित हम पौर के सम्बन्ध में भी समक्त करें । निगम की माँति ही पौर के सदस्य भी पूग तथा श्रेणी के रूप में विभिन्न हितों के श्रध्यच्च रहते होंगे । रामायण में प्राप्त प्रसंग इस बात की पुष्टि करते हैं कि पौर में श्रमेक श्रध्यच्च उपस्थित रहते थे । ३७ पौर तथा निगम की निकटता के कारण यह भी श्रमान किया जा सकता है कि प्रारंभ में ये दोनों नाम एक ही संस्था के हों श्रीर कार्य के श्रमुसार विभिन्न नामों से पुकारी जाती हो । श्राधुनिक काल में जैसे कलक्टर एवं जिलाधीश श्रथवा जिला एवं सेशन्स न्यायालय का प्रयोग होता है उसी प्रकार यह संभव समक्ता जा सकता है । जब वह व्यावसायिक हित सम्बन्धी काम करती हो तो निगम श्रीर जब प्रशासन सम्बन्धी कार्य करती हो तो पौर कहा जाता हो । दशकुमारचरित में एक पौर-मुख्य का प्रसंग श्राता है जो विदेशी व्यापार से सम्बन्धित श्रेणी का श्रध्यच्च था श्रीर यही श्राशा है कि पौर के श्रन्य सदस्य भी किसी न किसी संस्था के श्रध्यच्च होते थे । निगमा ध्यच्च की माँति पौर का भी श्रध्यच्च होता था श्रीर उसे 'श्रेष्टी' कहा (जाता था; किन्तु निग्रोध जातक (४४४) में राजगहसेटी तथा साधारणसेटी में एकट श्रन्तर किया गया है । राजधानी के पौर के श्रध्यच्च राजग्रहश्रेष्ठी कहलाते ये श्रीर दूसरी संस्थाश्रों के श्रध्यच्च केवल श्रेष्ठी । पंजाब के सेठी लोग संभव है इसी श्रेष्ठी शब्द से सम्बन्धित हों।

कार्ल मार्क्स ने समाज के आर्थिक आधार का सिद्धान्त अपनाया है। संभवतः प्राचीन भारत के लोग इससे पूर्णक्षेण परिचित थे। 'पौर' और 'निगम' की सहचारिता इस ओर स्पष्ट इंगित करती है। वैदिक काल से ही भारत में वाणिज्य, शिल्पकला और श्रम की उचित स्थान प्राप्त था। रथकार, कम्मार आदि के रूप में इनके प्रतिनिधि वैदिक सिनित के सदस्य भी होते थे। वर्त्त मान समय में जैसे व्यापारी संघ, चेम्बर ऑफ कामर्स तथा विश्व विद्यालयों आदि के विशेष प्रतिनिधि विधान सभाओं में स्थान पाते हैं। उसी प्रकार उस समय भी भारत में इन व्यापारियों एवं श्रमजीवियों को देश की राजनीति एवं व्यवस्थापना में उचित एवं महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त रहता था। इसी स्थिति से प्रोत्साहन पाकर देश का शिल्प और व्यवसाय भी उन्नत और विकसित होता था। प्राचीन भारत की समृद्धि का मूल कारण यही था और ये श्रीणयाँ तथा पुग उसके प्राण्य । अतः हम यह कह सकते हैं कि प्राचीन भारत की सुहढ़ और संगठित अर्थ-व्यवस्था ही राजनीतिक व्यवस्था का रतम्म थी और पौर केवल एक आर्थिक अर्ग ही नहीं वरन एक सुव्यवस्थित लोक-प्रिय सामाजिक तथा राजनीतिक संरथा भी श्री जो दीर्घ काल तक विद्यमान रही।

पोर तथा जातियाँ: —सामान्यतः पौर संस्था में जातिभेद नहीं था । प्रतिनिधि तो विभिन्न श्रेणी एवं संगठनों से त्राते थे किन्तु जाति को कोई महत्व नहीं दिया जाता था।

३७. मुख्या ये निगमस्य च-अयोध्याकारङ १४/५/२. पौरजानपदश्र ध्ठा-अयोध्याकारङ १४/५/४०.

चाहे कोई निम्न जाति का हो अथवा उच्च जाति का, पोर का सदस्य बनने के पश्चात् समस्त समाज उसे श्रद्धा और सम्मान अपित करता था। उस समय जातिगत उच्चता या नीचता को कोई स्थान नहीं था। गौतम धर्मसूत्र में आये प्रसंगानुसार ब्राह्मए को एक श्रद्ध पौर सदस्य का भी खड़े होकर सम्मान करना चाहिए, चाहे वह अस्ती वर्ष से कम अवस्था का हो। ३०० अर्थात् पौर सदस्य श्र्द्ध तो सम्मान का अधिकारी है ही; परन्तु पौर का भृतपूर्व श्र्द्धों सदस्य भी सम्मान प्राप्त करने का अधिकारी है। साथ ही यह भी स्पष्ट है श्र्द्धों की श्री शियाँ भी होती थीं और उनके प्रतिनिधि भी पौर में स्थान पाते थे। ऐसी समाज व्यवस्था प्राचीन भारत में विद्यमान थी यह जानकर किस भारतीय की गर्व नहीं होगा। इस प्रकार पौर जातिभेद रहित किन्तु आर्थिक व्यवस्था पर आधारित एक लोकतंत्रात्मक संस्था थी जिसके सदस्यों का निवांचन अप्रत्यक् रूप से इन श्रेणी, पूर्ण आदि संस्थाओं के सदस्यों से होता था और इन संस्थाओं के सदस्य सम्बन्धित जनता द्वारा निर्वाचित होते थे। इस प्रकार समस्त प्रजा प्रत्यक् रूप में अपनी संस्था तथा अप्रत्यक् रूप में पौर के निर्वाचनों में भाग लेती थीं।

पीर या निगम मुद्राएँ (Paur or Nigema Coins'-अर्थशास्त्र (पृष्ठ न्ह) के अनुसार पीर की स्वर्णमुद्राएँ होती थीं जो राजकीय मुद्रालय (Royal Mint) में निर्मित होती थीं । डा० जायसवाल के मतानुसार यह पीर का एक विधायी कार्य हो सकता है जिसके द्वारा राजकीय मुद्रालय के अनुचित मुद्रानिर्माण पर प्रतिवन्ध रखा जा सके अथवा यह एक शुद्ध आर्थिक कर्त व्य के रूप में ही रहा हो ।३६ पीर और निगम का प्रयोग हैं, साथ साथ और समान अर्थ में होता ही था यह हम ऊपर देख चुके हैं । अत: पीर का यह महत्वपूर्ण अर्थ-कार्य था और अर्थशास्त्र के अनुसार ये मुद्राएँ पीर अथवा राजधानी के व्यवसायियों के प्रयोग के लिए राजकीय मुद्रालय द्वारा निर्मित होती थीं। ४० उन पर राजधानी का नाम अंकित किया जाता था । इसी कारण उन्हें पीर की मुद्राएँ कहा जा सकता है । इस प्रकार निगम और पीर का साहचर्य सिद्ध होने पर ही पीर का पर्याप्त जान हो पाता है । फिर भी पूरा पूरा विवरण इसे नहीं कहा जा सकता।

जनपद — पौर की भाँति जनपद भी, राजधानी के ऋतिरिक्त, शेष समस्त राज्य की प्रतिनिधि संस्था थी। राजधानी की भाँति शेष राज्य भी सम्भव श्रेणी तथा पूग ऋादि संस्थाओं से ऋच्छादित था छोर ये संस्थाएँ समस्त जनता की प्रतिनिधि संस्थाएँ थी। प्रत्येक गाँव में भी इन संस्थाओं के ऋध्यन्त थे और इन्हीं ऋध्यन्तों में से जनपद के सदस्यों का

ऋत्विक्शवशुरिषतृत्यमातुलानां तु यवीयसां प्रत्युत्थानमनभिवाद्याः ॥
 तथान्यः-पूर्वः पौराऽशीतिकावरः शङ्गोऽप्यपत्यसमेन ॥
 प्रवरोऽप्यार्यः ग्रुद्दे ॥ गौतमधर्मसृत्र ६/६/११

३६ Dr. Jayaswal-Hindu Polity-Page 252.

४० सौवर्शिकः पौरजानपदानां रूप्यनुवर्णमावेशनिभिः कार्येत् । श्रर्थं शास्त्र-पृष्ट 🗠 ।

चुनाव होता था। जनपद का इस प्रकार ग्राम—चुनाव चेत्रों के त्राधार पर संगठन होता था त्रीर ग्रामों की व्यवस्था जनपद के त्राधीन होती थी। दशकुमारचरित में एक जगह है कि जनपद के त्राध्यच से एक शासक, ग्रामणी के सताने संबंधी प्रार्थना करता है। इससे यह निष्कर्ष जाता है कि जनपद संस्था ग्रामणी के कार्यों का निरीच् ण भी करती थी। वैसे वैदिक काल में तो ग्रामणी समिति का भी सदस्य होता था। पौर की भाँति जनपद का भी एक ग्रध्यच होता था। वह जनपद संस्था का कार्यालय भी राजधानी में ही रहता था त्रीर त्रावश्यकतानुसार राज्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार-विमर्श के लिए पौर तथा जनपद संस्था जा नपद संस्था का कार्यालय विमर्श के लिए पौर तथा जनपद संस्था जा संयुक्त सम्मेलन भी होता रहता था।

जनपद का संगठन—प्राचीन भारत के विशाल राज्यों में असंख्य गाँवों और उनकी श्रीणियों तथा पूर्गों में निर्वाचन की ज्यवस्था कैसे होती होगी, यह एक किन प्रक्त है। परन्तु किर भी प्राप्त सामग्री के आधार पर यह तो सत्य है कि यह निर्वाचन होता अवश्य था। नालन्दा से प्राप्त छठी या सातवीं शताब्दी की मुहरों के आधार पर यह सिद्ध है कि ग्रामों में भी जनपद संस्थाएँ स्थापित थीं। जैसा ऊपर कहा जा चुका है, मुहर पर अंकित है :— ''पुरिका ग्राम जनपदस्थाः''। इसलिए यह निष्कर्ष उचित है कि राज्य के प्रशासनीय भागों के आधार पर अनेकों ग्रामों से चेत्रीय जनपद संस्थाओं के सदस्यों का निर्वाचन होता था और किर इसी प्रकार अन्त में केन्द्रिय जनपद संस्था के सदस्य, चेत्रीय जनपद के सदस्यों से होता था। बहुत संभव है कि चेत्रीय संस्थाओं के अध्यच्च ही केन्द्रिय संस्था के सदस्य होते थे।

जनपद के कार्य – जैसा पहले कहा जा जुका है, विभिन्न प्रसंगों से ही हम यह जात कर पाते हैं कि जनपद के क्या क्या कार्य सम्भव थे। मुख्य रूप से हम इन कार्यों को आर्थिक, संवैधानिक, राजनैतिक एवं विशेष, चार भागों में विभाजित कर सकते हैं। आर्थिक कार्य के चित्र में जनपद बहुत शिक्षशाली संस्था प्रतीत होती है 'पौर की माँति जनपद भी राजकीय मुद्रालयाध्यच् द्वारा अपनी मुद्राएँ बनवाते थे। यह आर्थिक कार्य था। इसके द्वारा जनपद यह देखरेख रखता था कि राज्य में विनिमय के लिए मुद्राएँ पर्याप्त मात्रा में हैं या नहीं, भार एवं शुद्ध धातु का प्रयोग ठीक ठीक है या नहीं, तथा मुद्राओं के पुराने हो जाने के कारण जनता की विनिमय में कोई कब्द तो नहीं होता है आदि। एक-दो बार जन साधारण द्वारा इस प्रकार की आपत्तियाँ भी की गई थीं इसी चेत्र में दूसरा आर्थिक कार्य था कर संबंधी (Taxation) साधारणतया सामान्य नियमों (Common Law) द्वारा कर निर्धारित किये लाते थे, परन्तु कभी सम्राट को विशेष आवश्यकताएँ भी होती थीं और राजा विशेष आवेदन करता था। इसे 'प्रणय' कहा जाता था। ऐसे प्रस्ताव सर्वप्रथम पौर-जनपद से समच्च ही उपस्थित किये जाते थे। अर्थशास्त्र के अनुसार राजा को पौर-जनपद से ही ये कर मांगने पड़ते थे। ४२ और जनपद समाओं में राजा के करों के आधिक्य की चर्चा तो साधारणतया हुआ ही करती थी। युद्धकाल तथा अन्य प्रकार के संक्रमणकाल में नथे तो साधारणतया हुआ ही करती थी। युद्धकाल तथा अन्य प्रकार के संक्रमणकाल में नथे

४१ दशंकुमारचरित-अध्याय ३.

४२ एतेन प्रदेशेन राजा पौरजानपदान् भिन्नते । अर्थशास्त्र-भाग ५, अध्याय २, पृष्ठ ६०

कर लगाने की चेष्टा तथा जनपद द्वारा उसका त्रिरोध करने के प्रसंग तो बहुत मिलते हैं। सम्राट द्वारा प्रत्येक व्यय भी जनपद द्वारा स्वीकृत होता था और जनपद स्वीकृत या अस्वीकृत करने में पूर्ण रूप से स्वतंत्र था। कद्रदमन द्वारा सुदर्शन भील की मरम्मत का उदाहरण बहुत प्रसिद्ध है। मंत्रिमण्डल द्वारा अस्वीकार करने पर कद्रदमन ने निजी सम्पत्ति से यह कार्य करनाया और जनपद को कष्ट नहीं दिया। इस प्रकार जनपद जनता के कोष का संरच्छ सिद्ध होता है। पूर्ण अर्थव्यवस्था में जनपद की स्वीकृति अनिवार्य होती थी। नये कर लगाना, कम करना आदि सारे कार्य जनपद की स्पष्ट स्वीकृति से होते थे। इस प्रकार आर्थिक कार्य के चेत्र में जनपद शिकशाली संस्था थी।

संवैधानिक कार्य के दोत्र में भी जनपद महत्वपूर्ण संस्था थी। इस दोत्र में साधारण-तया पौर ऋौर जनपद साथ साथ आती थीं। युवराज की नियुक्ति इस प्रकार के कार्य में मुख्य था। जनपद के विचार-विमर्श व तिर्गाय के पश्चात् सम्राट से युवराज के राजतिलक के लिए कहा जाता था। वे कहते थे कि इस युवराज को ''हम चाहते हैं।'' रामायण में राम के राज-तिलक का प्रसंग बड़ा रोचक श्रीर महत्वपूर्ण है। दशरथ यह प्रश्न करते हैं कि मैं धर्म के त्रानुसार शासन कर रहा हू^{*}, फिर भी श्राप लोग राम को युवराज के पद पर अत्यधिक शिक्तयों के साथ नियुक्त करना चाहते हैं, इसका क्या कारण है। इस पर जनंपद के सदस्य उसे कारण सहित समकाते हैं कि राम इच्चाकु वंश के रत्न हैं स्त्रीर श्रनेक स्रद्भुत शासनीय गुणों से युक्त है। तब सम्राट सहमत होता है। यहां यह स्पष्ट प्रमाण मिलता है कि जनपद युवराज की नियुक्ति का कार्य करता था । अभिषेकोत्सव में जनपद के प्रतिनिधि एक लोकतंत्रात्मक संस्था के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेते थे। उत्तराधिकार के संबंध में भी जनपद सार्वभीम संस्था थी। श्रनुचित होने पर उत्तराधिकार को रोकने की सामर्थ्य भी जनपद में थी। राज्याभिषेक के पश्चात् सम्राट श्री णियों के ऋष्यन्नों की धर्मपतिनयों को आर्शार्वाद लेने के लिए प्रणाम करता था। इससे उनके महत्व का ज्ञान होता है। अन्य सम्राज्ञीय उत्सवों में भी जनपद के प्रतिनिधि सम्मिलित होते थे। इनके अतिरिक्त राजाओं और सम्राटों की पद्च्युत करने का श्रधिकार भी जनपद की प्राप्त था। धर्मविषद्ध शासन चलाने वाले राजा की पदच्यत करना तथा उसके भाई श्रथवा उस वंश से बाहर श्रन्य धर्मानुकूल शासन चलाने वाले न्यिक को सिंहासन दे देना जनपद के ऋधिकार में था। पदच्युत सम्राट की वनवास देना भी जनपद के अधिकार में था। जनपद के विश्वासपात्र व्यक्ति को ही सम्राट, मंत्र (Policy) दएड (Government) मंत्रित (Premier) आदि के अधिकार देता था। इस प्रकार संवैधानिक सरकार का सा रूप बन जाता था। राज्य-नीति भी जनपद् द्वारा स्वीकृत होती घी श्रीर उनकी सम्मति पर ही मंत्रिमण्डल के सदस्यों की कार्यविधि निर्भर थी। स्कन्दगुप्त के राज्यपाल चक्रपालित ने एक लेख में यह घोषित किया है कि उसने श्राहप काल में ही पीर-जनपद श्रादि लोकप्रिय संस्थात्रों का विश्वास प्राप्त कर लिया है और यह प्रार्थना करता है कि भविष्य में राजधानी समृद्धिशाली बने श्रीर पौर के प्रति स्वामिभक रहे। ४३ प्रांतों के

४३ नगरमि च भूयादृ द्धिमत्पौरजुष्टम् । जूनागदृ-लेख--४५७-५= ई० प०

मुख्य नगरों (Head Quarters) में भी ये संस्थाएँ थीं परन्त वहां पौर का नाम ही अधिक त्राता है। दिव्यावधान में वर्णित उत्तरपथ की राजधानी तच्चशिला के पोर की कांति भी नहुत रोचक तथा महत्वपूर्ण है। सम्राट अशोक ने जब अपने पुत्र कुणाल को शांति स्थापना के लिए मेजा तो पौर ने संबोधन किया कि हम राजकुमार या सम्राट के विरुद्ध नहीं है किन्तु उन दुष्ट निरंकुश मंत्रियों के विरुद्ध हैं जो हमारा अपमान करते हैं। ४४ अतः यह सिद्ध होता है कि शासन के चेत्र में जनपद पूर्ण संबैधानिक शिक्तियों से युक्त होता था। सम्राट आवश्यकतानुसार जनपद के समज्ञ सम्भाषण देता था और अपनी आवश्यकताओं को उप-स्थित करता थां।४५ धन के लिये भी याचना करता था कि संकट की स्थित आ जाने से धन चाहता हूं इस स्थिति के हट जाने पर वापिस लौटा दूँगा, इस प्रकार मध्र सम्यतापूर्वक भाषण द्वारा धन दान की प्रार्थना करता था। भवत् (Honourable) भवद्भिः संगतैः (Your Honourable Assembly) आदि संगोधन के शब्द राजा द्वारा प्रयुक्त किए जाते थे।

साथ ही पौर तथा जनपद को सम्राट द्वारा विशेष अनुग्रह (Privileges) प्रदान किए जाते थे। खारवेल लेख में यह उल्लेख है कि एक वर्ष पौर को तथा जनपद की बहुत से अनुगह प्रदान किए गए। कीटिस्य ने भी यह लिखा है कि शत्रु देश में गुप्तचरी द्वारा वहां के जनपद के नेताओं को अधिक अनुग्रह प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना चाहिए अरि जन वहीं दुर्भिच आदि आपित्यों हो तब और भी अधिक । याजवल्क्य के अनुसार जनपद की चोरी की चतिपूर्ति राजा को करनी चाहिए।४६ इस प्रकार प्रशासनीय चेत्र में भी जन-पद शिक्तशाली था। क्योंकि शासन की त्रुटियों के लिए सम्राट उत्तरदायी था श्रीर जनपद च्तिपूर्ति करवाने का श्रिधिकारी समका गया था। जैसे नये कर के लिए जनपद की स्वीकृति श्रनिवार्य थी, इसी प्रकार बड़े यज आदि कार्यों के लिए राजा को स्वीकृति लेनी होती थी और जनपद अपनी अनुमति देकर राजा को मुखी बनाता था। इस प्रकार राजा और जनपद दीनों परस्पर एक दूसरे से अनुग्रह और सहयोग प्राप्त करते हुए चलते थे। अमेरिका की प्रतिबन्ध श्रीर संतुलन पद्धति(Checks & Balance System) का यह सुन्दर उदाहरण प्राचीन भारत की प्रजातंत्रात्मक पद्धित में प्राप्त होता है । इतना सुन्देर समन्वय आधुनिक काल में दुर्लभ है। राजा और जनपद का यह सबैध यदा-कदा ही नहीं था किन्तु प्रतिदिन यह आव-श्यकथा। अर्थशास्त्र में दिए हुए सम्राट के कार्यक्रम और दिनचर्या में नित्यपति पीर-जन-पद के साथ कुछ समय व्यतीत करना लिखा है। इसलिए सिद्ध होता है कि आर्थिक, राज-नैतिक तथा प्रशासनीय सब प्रकार के कार्यों का निपटारा इने संस्थाओं के सहयोग से किया जाता था । यहाँ तक कि सै निक समस्यां भी इनके सामने अति थी।

् वार्मिक च्रेत्र में भी जनपद हस्तच्चेप करता था। अशोक ने अपने नथे धर्म की चर्चा जनपद के समस् की थी और उसकी अनुमति के बाद ही अशोक ने नया धर्म घोषित किया। ४४ ैं दिन्यानिधान पृष्ठ ४०७-०= ।

²⁴ Dr. Jayaswal - Hindu Polity. PP. 264-267 Quotation From Mahabharat. देथं चौर-इतं द्रन्यं राशा जानपदाय तु । याश्चलक्य II ३६

इस प्रकार श्रन्य विशेष विषयों के संबंध में भी जनपद शिक्तशाली संस्था थी। यदि न्याया-लय द्वारा कोई वास्तविक श्रपराधी छोड़ दिया जाता था तो भी जनपद उसे दण्ड देने योग्य था-ऐसा मुच्छुकंटिक में उल्लेख है। परन्तु इसकी सत्यता एवं वास्तविकता में विश्वास नहीं किया जा सकता। सम्राट एवं युनराज इन सभाश्रों में उपस्थित होते थे, क्योंकि ये संस्थाएं प्रशासन को स्थापित श्रोर विस्थापित करने के योग्य होती थीं। पौर-जनपद श्रपने श्रपने चेत्र में सहायता कार्य भी करती थीं। निर्धन श्रोर निस्सहाय व्यक्तियों की सुरचा का कार्य बड़ी तत्परता से किया जाता था। महाभारत में जिल्हा है कि पौर-जनपदा यस्य भूतेषु च दयालव:। सधना धान्यवन्तश्च दृदमूलः सं पार्थिव:॥४७ श्रर्थात् यदि पौर जनपद जनता प्रति दयालु रहें श्रीर धनधान्य उनके पास हो तो राज्य बहुत मजबूत रहेगा। विरोधी होने पर पौर-जनपद समाट को च्रितपूर्ति की समस्या द्वारा ही संकट में डाल सकते हैं।

पौर-जनपद को नियम बनाने के अधिकार भी ये और ये कार्य इन संस्थाओं द्वारा किये जाते थे। इनके प्रमाण हिन्दू न्यायशास्त्रों में उपलब्ध हैं। इन संस्थाओं द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव नियम की भाँति प्रभावशाली होते थे और न्यायालय सदस्य अपराधियों की जाँच करने में नियम की भाँति उनका उपयोग करते थे। इन्हें 'समय' कहा जाता था। मनु और याज्ञव्ह्म ने इन्हें धर्म का नाम दिया है। ''स्थिति'' या ''देशस्थित'' (Fixed Laws) दूसरे प्रकार के प्रस्ताव थे, जो सब लोगों के विरुद्ध कार्य में लाय जाते थे। ये समभौते या ''समविद्'' कहे जाते थे और ''समविद् पत्र'' में शपथपूर्वक अ कित किए जाते थे। कभी कभी ये सम्भाट के विरुद्ध भी होते थे, कितु न्यायालय ऐसे समभौतों को प्रभावित करने के लिए बाध्य नहीं थे।

इस प्रकार पौर ख़ौर जनपद ऐसी संस्थाएँ थीं, जो सम्राट पर प्रतिवन्ध थीं, जनता की संरचक थीं ख़ौर प्रजातंत्रात्मक न्यवस्था की प्राण थीं। प्राचीन भारत में ऐसी संस्थाओं की विद्यमानता ख्राज के भारतवर्ष के लिए गौरवमय ख्रादर्श के रूप में स्वीकार की जा सकती है। भारतवर्ष की जनसंख्या, चेत्रफल तथा स्थानीय समस्याख्रों को दृष्टि में रखते हुए वही प्राचीन ख्रादर्श इस समय भी सम्बल हो। सकता है।

श्रालोचनाः—श्रुटिकर के मतानुसार पौर श्रौर जनपद जैसी संस्थाएँ जिनका विशद वर्णन डॉ॰ जायसवाल ने भी किया है, कभी नहीं रहों। इस धारणा के पज्ञ में उन्होंने निम्ना-क्कित बातें कहीं हैं:—(१) पौर-जनपद की श्राभिव्यक्ति कभी भी दिवचन के श्रार्थ में नहीं हुई। रामायण में वर्णित प्रसंगानुसार भी पौर-जनपद कभी प्रभावशाली नहीं रहा। (२) खारवेल के हाथी गुफालेख में उल्लिखित श्रानुग्रह का श्रार्थ विशेषाधिकार नहीं हो सकते, क्योंकि वे सेंकड़ों श्रौर हजारों नहीं हो सकते। उन पर व्यय की हुई धनराशि सहस्रों में हो सकती है तथा खारवेल का प्रशासन तथा नीति कभी किसी लोकप्रिय नगर संस्था के वशी-भूत नहीं रहा। यह स्वयं संधि श्रथवा युद्ध कर सकता था। (३) स्मृतियों में पौर-जनपद के प्रसंग से जनपद की संस्था का श्रान नहीं होता। जनपद-धर्म का प्रयोग केवल देश की प्रधा

अथवा सामाजिक नियमों या रीति-रिवाजों के लिये हुआ है, किन्तु लोकप्रिय संस्थाओं के द्वारा स्वीकृत नियमों के अर्थ में नहीं। देशधर्म भी इसी प्रकार स्थानीय नियमों के अर्थ में स्राये हैं को देश के प्रत्येक भाग में भिन्न भिन्न होते थे। विवाह, भोजन तथा व्यवसाय की मान्यताएँ भी देश के अनुसार भिन्न भिन्न होती थीं। (४) देश एवं ग्राम के 'समय' का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पौर-जनपद के नियमों का उल्लंघन करने वाले नहीं माने जा सकते। (५) डॉ॰ जायसवाल द्वारा प्रतिपादित यह निर्णय स्मृतियों द्वारा समर्थित नहीं है कि पौर के विरोधी को न्यायालय द्वारा भी सहायता नहीं दी जा सकती। (६) पौर सभा के पूर्व सदस्य को सम्मान का अधिकारी माना जाता था चाहे शूद्र ही हो, यह धारणा, गलत अर्थ लगाने के कारण हुई है। वास्तव में प्राचीन भारत में तो वयोद्य लोगों को सम्मान देने की साधारण प्रथा थी ही। पौर का अर्थ नगर का निवासो है न कि नगरसभा का सदस्य। (७) पोर-जनपद की वैधानिक शिक्तयाँ भी एक अममात्र हैं। रामायण से उद्घृत पंक्तियाँ जिनमें उत्तराधिकारी की नियुक्ति आदि का अशुद्ध है अर्थ लगाया है। यह सर्वविदित है कि राम की भविष्य जनपद ने नहीं बल्कि राजमहलों के षड्यन्त्र द्वारा निश्चित किया गया था। इसी प्रकार राजा को पदच्युत करने का अधिकार भी असत्य है। विभिन्न कर लगाने का अधिकार डॉ॰ जायसवाल द्वारा गलत समभा गया है। महाभारत में दिया गया प्रसंग राजा का संभाष्ट्र नहीं है किन्तु युक्ति है, जिसका प्रयोग सम्राट को जनता की स्राश्वस्त करने के लिए, करना चाहिए। इसी प्रकार पौर-जनपद द्वारा सम्राट को चितिपूर्ति के लिए बाध्य करने का अधिकार भी नहीं है। पीड़ित नागरिक (जनपद) की च्तिपूर्ति का सिद्धान्त तो याज्ञवल्क्य ने भी लिखा है, परन्तु ऐसी लोकप्रिय संस्था का वर्णन नहीं है। इस प्रकार डॉ॰ जयसवाल के सारे प्रसंग वास्तव में साहित्यिक प्रमाणमात्र हैं; ठोस सामग्री नहीं है।

६० वर्ष ई० पू० से ६०० वर्ष ई० प० तक जो समय इन संस्थाश्रां का माना है उस समय के अन्य किसी भी लेख आदि में इनका उल्लेख ही नहीं है। मेगास्थनीज के वर्णन में कई महत्वपूर्ण सूचनाएँ हैं किन्तु पौर-जनपद की संस्थाश्रों का कोई वर्णन ही नहीं है। न राज्य सप्तांग सिद्धान्त में ही यह सम्मिलित है। नालन्दा की प्राप्त मुहर्रे भी पंचायत की मुहरें हैं न कि किसी लोकप्रिय संस्थाश्रों की। अन्य तत्कालीन ताम्रपत्रों में भी कोई प्रसंग प्राप्त नहीं है। कल्हणकृत राजतरंगिणी में भी, जो कश्मीर के जीवन और प्रशासन का पूर्ण चित्र उपस्थित करती है, इसका कोई उल्लेख नहीं है। अतः यह सारा पौर-जनपद का वर्णन एक क्योल-कल्पना है। ४०

उपयुक्त वर्णन श्रीर श्रालोचना दोनों दो प्रमुख विद्वानों के ऐसे विचार हैं जो (Extreme) विरोध की चरम सीमा पर हैं। इनका श्रध्ययन श्रीर मनन करने पर यह स्वष्ट हो जाता है कि ये संस्थाएँ थीं श्रीर इनके वर्णित कर्ज व्य भी महत्वपूर्ण ये। यशिप इनका स्पष्ट वर्णन किसी एक स्थल पर प्राप्त नहीं हैं, किन्तु डॉ॰ जायसवाल की शोध का श्राधार इतना गलत नहीं ठहराया जा सकता, जितना डा॰ श्रल्टेकर ने बताया है।

v= Dr. Alteker-State & Govt. Ancient India-PP. 136 to 146.

कुछ उदाहरण तो डॉ॰ जायसवाल के द्वारा दिए हुए ऐसे अकाट्य हैं, जो पौर-जनपद की विद्यमानता तथा कार्यों की स्पष्ट पुष्टि करते हैं, जैसे अर्थशास्त्र की पंकिन "एतेन प्रदेशेन राजा पौरजानपदान भिद्मते" आदि। प्राचीन भारत की परम्पराओं और प्रजातांत्रिक प्रवृत्तियों की अभिन्यिक्तयां अनुपम तो थी ही परन्तु उनका उल्लेख एक स्थान पर नहीं मिलता। डॉ॰ जायसवाल के निष्कर्ष और शोध वास्तव में अयस्कर हैं। बहुत अधिक सद्म हिन्द से देखने पर कुछ अभाव प्रतीत हो सकते हैं किन्दु नई शोध द्वारा उनकी पूर्ति की आशा की जा सकती है; उनके उनमूलन की नहीं।

इस प्रकार प्राचीन भारत की ये लोकसभाएँ वैदिक काल से लेकर ही किसी न किसी रूप में चलती रहीं श्रोर प्रजातंत्रात्मक प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करती रहीं। कभी विकसित, कभी श्रद्ध विकसित श्रोर कभी सुप्त श्रवस्था में इन संस्थाश्रों का उत्थान-पतन चलता रहा। एक संस्था के पश्चात् दूसरी श्रोर दूसरी के श्रवशेष के रूप में तीसरी संस्था उद्भृत होती गई। इन सब प्रसंगों से एकमात्र निर्णय लिया जा सकता है कि लोकप्रिय संस्थाएँ प्राचीन भारत में सदैव विद्यमान रहीं श्रोर श्रपनी महत्वपूर्ण परम्पराश्रों का पालन करने में संलग्न रहीं।

प्रश्त

- 1. Discuss the importance of Paura and Janapada as representative institutions of the people and indicate their place in the administration of the Country.
- 2. Distinguish between the SABHA and SAMITI of Vedic times and elucidate their composition and functions.

ग्यारहर्वी ग्रध्याय

प्रशासन (१) मन्त्रिमगडल

('Administration-I-Ministry)

प्रस्ताचना - त्राधुनिक युग में जैसे प्रत्येक प्रजातंत्र राज्य का शासन मंत्रिपरिषद् के द्वारा संचालित होता है उसी प्रकार प्राचीन भारत में भी मंत्रिपरिपद् विद्यमान थी। डॉ॰ नायसवान के मतानुमार यह मंत्रिपरिषद् ऐसी संस्था थी जो वैदिककालीन पौराणिक राष्ट्रीय महासभा से उत्पन्न हुई थी। प्राचीन प्रन्थों के विभिन्न प्रसंगों से यह प्रकट होता है कि राज-कृत (King-makers) जो बाद में राज्य के उच कर्मचारियों के रूप में प्रकट होते हैं, वे मंत्रिपरिषद् के ही सदस्य थे । महासेनाध्यत्त्, भाण्डागारिक श्राद्-उनमें सम्मिलित होते ये श्रीर नव निर्वाचित सम्राट अपने राज्याभिषेक के अवसर पर सम्मानपूर्वक उन्हें प्रणाम करते तथा अर्चना करते थे। इस प्रकार अरयन्त अद्धापूर्वक यह सम्मान उन्हें दो रूपों में भेंट किया जाता था, प्रथम राज्य के उचाधिकारियों के रूप में तथा दूसरे समाज के प्रतिनिधियों के रूप में । इससे यह प्रकट होता है कि ये अधिकारी जनता के सब्चे प्रतिनिधि और सेवक होते थे और इसी कारण भावी सम्राट ग्रापने सिहासनारुढ़ होने से पूर्व इन सदस्यों की स्वीकृति के ग्राम-लायी होते थे। इस प्रकार मंत्रिपरिपद् के सदस्य राज्य के कर्मचारी होते थे परन्तु सम्राट के कीतदास अथवा उसके अधीन नहीं होते थे। समाज का प्रतिनिधित्व करने के कारण वे सम्बाट के परामर्शदाता होते थे । मंत्रिपरिषद् की उत्पत्ति के संबंध में यह कहा जा सकता है कि समस्त सदस्य एक सामृहिक संस्था के रूप में समके और पुकार जाते थे। इसलिए उन्हें मं त्रिपरिपद् की संज्ञा दी गई थी। किर भी विभिन्न प्रत्थीं में उनका प्रयंग एक रूप में नहीं मिलता । केवल यह निश्चय है की मंत्रिपरिषद् प्रत्येक प्रचार्तन राज्य में रहता था और राज्य के प्रशासन में प्रभावपूर्ण सहयोग रखता था। उस समय का मंत्रिपरिपद् श्राद के मंत्रि-मण्डली से कहीं अधिक सम्मानित और शक्तिशाली होता था।

नामावली: - अर्थशास्त्र में मंत्रियों की संस्था के लिए 'परिपद' शब्द का प्रयोग हुआ है, और जातक-प्रन्यों तथा अशोक के पुस्तक लेखों में 'परिपा' शब्द प्रयुक्त हुआ है। बृहदारम्यक उपनिषद में मंत्रिवरिषद और समितिपन्पिद् का मेद स्वष्ट करते हुए यह निद्ध किया गया है कि 'परिषद' शब्द ऐसो संस्था के लिए आता था जो मंत्रुक उत्तरदापित की पद्धति का अनुगरण करती हो। अशोक में मंत्रियों के लिए भी विशेष श्कार के सब्दी का प्रयोग किया है 18 जिससे यही प्रकट होता है कि राज्य की वास्तविक सत्ता उन्हीं लोगों के हाथ में होती थी जो मंत्रिपरिषद् के सदस्य होते थे । पाली स्त्रों में तथा रामायण आदि प्रन्थों में मंत्रियों के लिए 'राज्यकर्ता' शब्द का प्रयोग हुआ है । प्रति मोत्त्स्त्र के अनुसार मंत्रियों को राजा की संज्ञा दी गई है । वहां 'राजानो' शब्द का प्रयोग हुआ है । जिसका आर्थ है 'राजाओं' इस प्रकार विभिन्न शब्द जैसे—परिषा, परिषद्, राज्जा आदि कुछ मंत्रियों के लिए तथा अधिक मंत्रिमण्डल के लिए व्यवहार में आते थे और यह संस्था प्राचीन भारत में लगभग निरन्तर रही और इसका नाम बहुधा 'परिषद्' ही प्रचलित रहा।

मम्राट से संबंध - प्राप्त प्रसंगों के ऋाधार पर यह कहा जा सकता है कि राजा क्रीर मंत्रिपरिषद् का संबंध घनिष्ठ तो था ही, किन्तु मंत्रियों की अत्यधिक प्रतिष्ठा की जाती थी। महाभारत में यह कहा गया है कि राजा मंत्रिमण्डल पर उसी तरह आश्रित रहता है जैसे पशु बादलों पर, ब्रह्माण वेदों पर, एवं पत्नी पति पर ब्राक्षित रहती है। वास्तव मं प्राचीन हिन्दू राजनीति का यह एक स्वीकृत सिद्धान्त एवं नियम था कि अपने मंत्रिमएडल के परामर्श के अभाव में सम्राट कोई कार्य नहीं कर सकता था। प्रत्येक निर्णय और कार्य के लिए मंत्रिपरिषद का सहयोग व स्वीकृति त्रानिवार्य समभी जाती थी। राजा की सफलता योग्य मंत्रियों पर ही निर्भर करती थी। राजा श्रीर मंत्री एक ही गाड़ी के दो पहिये लमके जाते थे। जैसे एक पहिये से गाड़ी चल ही नहीं सकती, उसी प्रकार अकेला राजा भी प्रशासन नहीं चला सकता । प्राचीन भारत की सभी रमृतियाँ, पूराण ह्यौर राजनीति पर प्राप्त प्रनथ तथा सह इस विषय में एकमत है। मनुस्मृति में यह लिखा है कि मंत्री, पूरोहित आदि की सहायता से हीन. राजा मूर्ल होता है तथा वह न्यायपूर्वक दगड देने के अयोग्य होता है। शास्त्रानुसार व्यव-हार करने वालो श्रीर बुद्धिमान् राजा मंत्री श्रादि की सहायता से दण्डविधान कर सकता है। इ ऐसे सम्राट को मनु त्रायोग्य मानता है जो स्वयं शासन संचालित करना चाहे । त्रान्यथा सम्राट के लिए परामर्शदाता श्रानिवार्य हैं जिनसे वह समय पर सम्पर्क स्थापित करता हुआ पथप्रदर्शन प्राप्त कर सके। मनु यहां तक भी लिखते हैं कि सम्राट अरयन्त सरल कार्य भी अपने मन से न करे। इसलिए राज्य के संचालन के कार्य के संबंध में सबसे सलाह लेना श्रिनिवार्य था। राजतंत्र का प्रचल समर्थक कौटिल्य भी यह त्रादेश देता है कि छोटे से छोटा श्रिभियोग भी सम्राट को स्वयंनिर्णात नहीं करना चाहिए श्रीर ऐसी छोटी-छोटी वाते भो

१ अशोक के शिलालेखों में 'राज्का' राष्ट्र काम में आया है। जिनका अर्थ उन मंत्रियों से हैं जिन्हें राज्य की सम्पूर्ण शक्तियां दो हुई हों।

२ अयोध्याकाराड श्रध्याय ६६

मनुरमृति श्रध्याय सप्तम, पृष्ठ २=६ (श्लोक ३० एवं २१) सोऽसहायेन मृढेनालुट्धनाकृतवुद्धिना । न शक्यो न्यायतो नेतुं सक्तेन विषयेषु च ॥३:। शुनिना सत्यसंधन यथा शास्त्रानुसारिणा । प्रणेतुं शक्यते दण्डः सुसहायेन धीमता ॥३१॥

श्रपनी परिषद् के परामर्श से करनी चाहिए। राज्य के सब प्रकार के प्रश्न मंत्रिपरिषद् में प्रस्तुत होने चाहिए श्रीर विचार-विमर्श के बाद बहुमत से जो निर्णय किया जाय, सम्राट की उसी का पालन करना चाहिए। अर्थशास्त्र में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि मंत्रिमण्डल श्रीर मंत्रिपरिषद् दोनों हों तो सबको एक साथ श्रामंत्रित कर स्चित करना चाहिए श्रीर पूर्ण विचार के पश्चात् निर्णय लेकर कार्यान्वित करना चाहिए। १ कौटिल्य मंत्रिपरिषद् का महत्व बढ़ाते हुए इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि इन्द्र के केवल दो नेत्र थे, परन्तु फिर भी उन्हें 'सहस्राच' अर्थात् सहस्रनेत्र वाला इसलिए कहा जाता है कि उसकी मंत्रिपरिषद् में सहस्र बुद्धिमान् पुरुष थे जो उसके नेत्र माने जाते थे ।२ इसी प्रकार शुक्र नीति सार में भी यह लिखा गया है कि मंत्रियों के परामर्श के जिना राज्य का कोई भी विषय अनेले राजा के द्वारा निर्णीत नहीं होना चाहिए, चाहे वह राजा सब प्रकार के विद्वानों एवं नीतियों में निपुण ही क्यों न हो। बुद्धिमान राजा को सदैव ही मंत्रियों की सम्मति का अनुसरण करना चाहिए। मंत्रिपरिषद् के समज्ञ सम्राट का कोई व्यक्तिगत ऋधिकार ऋथवा विशेषाधिकार रहा हो ऐसा प्रसंग नहीं मिलता। इसलिए राजा को मंत्रपिरिषद् के निर्णय के विरुद्ध निपेधाधिकार भी नहीं था। बृहस्पति सूत्र के अनुसार सम्राट के लिए यह आदेश दिया गया है कि उचित कार्य (धर्मः भी सम्राट को बुद्धिमानों की सम्मति से ही करना चाहिए।३ सम्राट को राज्य की ऋोर से प्रत्येक कार्य मंत्रिपरिषद् की सम्मति श्रोर स्वीकृति से ही करना पड़ता था। उसकी स्वीकृति विना सम्राट न कोई भेंट दे सकता था और न कोई दान। आपस्तम्म के **त्र्रमुसार मंत्रिपरिषद् के द्वारा विरोध करने पर** सम्राट मैंट देने का अधिकारी नहीं रहता था। ४ सम्राट अशोक ने बौद्ध लोगों के लिए कुछ भेंट देने का आदेश किया था, किन्तु उनके वित्त मंत्री श्री राधागुप्त ने यह भेंट देना अस्वीकार कर दिया था। इसी प्रकार कद्रदमन के समय में जब सुदर्शन भील के सुधार का प्रस्ताव रक्खा गया तो उस समय मंत्री परिषद् द्वारा आपत्ति की गई। फलवस्हप धुधार का सम्पूर्ण व्यय रुद्रदमन को स्वये देना पड़ा। इन प्रकार यह सिद्ध होता है कि सम्राट ऋौर मं त्रिपरिषद् में घनिष्ठ संबंध था ऋौर मं त्रिपरिषद् वास्तविक सार्वभीम सत्ता की अधिकारिणी थी। आपस्तम्भ के अनुसार सम्राट और मंत्रि-परिषद् के संबंध भी नियमों पर आधारित थे और ये नियम सर्वोपरि ये। प्राचीन काल के नियमों की यह प्रतिष्ठा बौद्धकांत के प्रन्थों से स्पष्ट है। सम्राट अशोक के संबंध में दिन्या-वधान में वर्णित सम्पूर्ण घटना हमारी धारणा को स्पष्ट करती है। प्र

१ अर्थाशास्त्र माग प्रथम-अनुच्छेद १५ "श्रात्यायिके कार्य मन्त्रियो मन्त्रिपरिषद चाहूय न वात । तत्र यद मृथिष्ठाः कार्य सिद्धिकर वा मृथुस्तत् कुर्यात् ।

२ श्रथ शास्त्र-भाग प्रथम-श्रनुक्लेद १४ "इन्द्रस्य हि मन्त्रपरिषद्धपीणां सहस्रं । तन्त्रज्ञुः ।

३ धर्ममिष लोकविक प्टंन कुर्यात्। तस्मादिमं द्वयत्तं सहस्रात्तमाहुः ॥ "
करोति चेदाशास्येनं वृद्धिमद्भि" वृहस्पति सूत्र I 4-5-

४ श्रपस्तम्भ, II. १०-२६.

५ दिव्यावधान पृष्ठ ४३०.

मंत्रिपरिषद् का संगठन वैदिककालीन रातिन के उत्तराधिकारी मंत्रिया को शुक्र-नीति में "राष्ट्रभृत्" कहा गया है ।१ जिसका तात्पर्य है कि मन्त्री राष्ट्र के लिए उत्तरदायी हैं। भारतीय परम्पराश्रों में मन्त्री की नियुक्ति राजा द्वारा की जाती थी। इस दृष्टि से मन्त्री राजा के प्रति भी उत्तरदायी बन जाते थे। परन्तु फिर भी राष्ट्र के स्वार्थ सर्वोपिर होते थे। वे लोग राजा को प्रजातन्त्रात्मक और वैधानिक ढंग से शासन करने के लिए सम्मति देते थे । सम्राट इसीलिये राज्य का सुप्रवन्ध तथा ध्यवस्था रखने के लिए श्रावश्यकतानुसार मंत्रियों की नियुक्ति करते थे। मन्त्रिपरिषद् की सदस्यसंख्या समय समय पर न्यूनाधिक होती रही है। साधाररातया राज्य के आकार, आवश्यकता एवं समस्याओं के आधार पर परिवद की .सदस्यसंख्या निर्धारित की जाती थी। चृहस्पति के ऋनुसार मन्त्रिपरिषट के सदस्यों की संख्या सौलह थी।२ अर्थशास्त्र के अनुसार आदर्श मन्त्रिपरिषद् में बारह सदस्य होने चाहिए । उपनाश के अनुसार यह सदस्य संख्या बीस बताई गई है । इससे पूर्व मन्त्रिपरिषद् ्में सदस्थों की संख्या ख्रीर भी ऋधिक होती थी। महाभारत में ३२ सदस्यों वाली मंत्रि-परिषद् का भी वर्णन है। यह तो प्रतीत होता है कि साधारणतया छोटी संस्था की श्रीर ही अधिक भुकाव था। मनुस्मृति में मन्त्रिपरिषद् के लिए केवल सात या आठ सदस्यों की ही स्वीकृति दी है। ३ इसी धारणा का समर्थन शुक्र-नीति में भी किया गया है। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि शिवाजी का मन्त्रिमण्डल जिसे 'श्रष्टप्रधान' कहते थे, एक सर्वमान्य परम्परा बन गई थी त्रौर मन्त्रिपरिषद् में साधारणतया त्राठ सदस्य होते. थे। शुक्र-नीति के श्राधार इन श्राठ सदस्यों के पद एवं विभाग निम्निश्चित होते ये :-

- (१) सुमन्त्र (Minister of Finance)
- (२) पिंडतामात्य (Minister of Law)
- (३) मन्त्री (Home Minister)
- (४) प्रधान (President of the Connoil)
- (५) सचिव (Minister of War)
- (६) अमस्य (Minister of Revenue and Agriculture)
 - (৬) সাত্ৰিৰাক (Minister of Justice and Chief Justice)
 - (८) प्रतिनिधि (Representative)

कुछ अन्य विचारकों के अनुसार दो और मन्त्री मी सिमलित होते थे।

- (६) प्रोहित (Minister of Religion)
- (१०) द्त (Minister of Diplomacy)४.

श्क नीति सार २।७६.

२ टॉ॰ जायसवाल-Hindu Polity Page 292.

३ मनुस्पृति-अनुच्छेद सप्तम, श्लोक ४४. (सचिवानसप्त चाण्टी वा)

४ ग्रुक नीति सार-Age quoted by Jayaswal-Hindu Polity Page 293.

इनके अतिरिक्त युवराज भी मन्त्रिमण्डल में सम्मिलित होता था सम्भवतः परिषद् में नहीं। यद्यपि इस पद पर राजा का भाई, भतीजा, पुत्र, चाचा अथवा दत्तक पुत्र या पीत्र ही होता था और अन्य मन्त्रियों की भाँति वह भी सम्राट को सहायता देता था। युवराज की मुहर अलग होती थी और अलग ही वह हस्तान्तर करता था। सम्राट अशोक के समय में उनके पुत्र जन तक्षशिला के राज्यपाल थे, उन्हीं का पीत्र (कुणाल का पुत्र) उस समय युवराज के पद पर त्रासीन था। मह भारकर के अनुसार युवराज मन्त्री की कुमाराध्यत भी कहा जाता था । अशोक ने अपने प्रस्तर-लेखों में भी 'महामात्रा' और 'कुमार' शब्द का प्रयोग किया है।

मंत्रियों के पद और विभाग समय समय पर विभिन्न प्र कार से प्रयुक्त हुए हैं। मनुस्मृति के अनुसार सचिव शब्द का अर्थ सहायक के रूप में तथा आम तौर पर मन्त्रपद के लिए ंपयुक्त हुआ है। अर्थशास्त्र में 'अमात्य' शब्द का प्रयोग संब मन्त्रियों के लिए आया है और उसका अर्थ है 'सम्मिलित रहना'। रामायण में भी अमात्य शब्द ही मिन्त्रवर्ग के लिए प्रयोग में आया है। 'अजातशतु' में प्रधान मन्त्री के लिए 'अग्रमहाम त्र' तथा 'दिव्यावधान' में प्रधान मंत्री के लिए 'ग्रमात्य' शब्द ग्राया है। त्रशोक का गुख्यमंत्री राधागुष्त 'ग्रामत्य' राष्ट्र द्वारा ही संबोधित किया जाता था। ेंगुप्तकाल में इसी पद की 'महाद्गडनायक' के नाम से पुकारा गया है। 🦥 👵

भारति में पुरोहित का उल्लेख नहीं है। जातक-प्रत्य और धर्म सूत्र के अनुसार पुरोहित धर्मशास्त्र एवं राजनीतिशास्त्र का विद्वान् समभा जाता था श्रीर 'श्रापस्तम्ब' के मतानुसार पुरोहित उन अभियोगों का निर्णिय करता था, जिनमें प्रायश्चित अथवा इसी प्रकार के अन्य कोई आत्मा को पवित्र करने वाले दर्गड का विधान हो। सम्राट या राजा अधिकांश चत्रिय कुल से संबंधित होते थे, इसलिए वे बाह्मणों का न्याय करने योग्य नहीं माने जाते थे। यह पुरोहित ही ब्राहाणों का, राजा की स्त्रोर से, न्याय-सम्पादन करते थे। अर्थशास्त्र के अनुसार ब्राह्मण से यह अमेचा की जाती थी कि वह वेद-वेदान्तों का जाता-ज्योतिषी, नीतिज्ञ एवं अथर्वण पढितयों का मर्मज्ञ होना चाहिए ११ शुक्रनीति सार पुरोहित की नीतिशास्त्र के अतिरिक्त न्यूह आदि का पूर्ण ज्ञान (सैनिक ज्ञान) चाहिए था। र

इसी प्रकार दूत अर्थात् विदेश मंत्री के लिए भी कई प्रकार के नाम प्रयोग होते थे। साधारणतया दूत की श्रर्थ राजदूत (Diplomate) से लिया जाता है। किन्तु प्राचीन काल में दूत का अर्थ क्टनीति सचिव (Minister of Diplomacy) से लिया जाता था।३ वास्तव में दूत का काम संधि और युद्ध के होत्र में सीमित होता था। ४ रामायण एवं शुक-

श्रर्थशास्त्र भाग १--श्रनुच्छेद ८ एष्ठ-१५

शुक्तनीतिसार-नीतिशस्त्रास्त्रन्यूहादिकुशलस्तुं पुरोहितः। ५० 🗥

मनुस्मृति-श्रनुच्छेद सप्तम श्रीर श्लोक ६५-६६ विकास स्थाप स्याप स्थाप स्याप स्थाप स्याप स्थाप स्याप स्थाप स

नीतिसार में भी रूत शब्द का प्रयोग हुआ है, परन्तु कुछ समय पश्चात् दूत को 'संधि-वैप्रहिक भी कहा गया है। ऐसी स्थिति में दूत श्रीर संधि वैप्रहिक एक ही पद के दो नाम हैं, यह सिद्ध होता है।

सुमंत्र के लिए मनुस्मृति में यह प्रसंग मिलता है कि नृप स्वयं ही राष्ट्रीय कीष का अधिकारी होता था। "नृपती कोषराष्ट्रे च" अर्थात् स्वयं राजा ही कीष संबंधी कार्य करता था। अर्थशास्त्र में वित्तमंत्री की समाहती कहा गया है। शुक्र-नीतिसार में सुमंत्र ही प्रशुक्त हुआ है। कही वित्त मंत्री की 'अर्थसंचयक्तत्' भी कहा गया है।

सेनापित का पद भी समय समय पर विभिन्न प्रकार से पुकारा गया है। शुक्र-नीतिसार में उसे 'सचिव' कहा गया है। दूसरे स्थानों पर 'महाद्गडनायक' 'सेनाध्यच्' तथा महा-बलाधिकृत शब्द का भी प्रयोग हुन्ना है। यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सेना के ग्रध्यच् का पद बहुत 'महत्वपूर्ण होता था और साधारणतया मन्त्रिपरिषद् में भी प्रतिष्टित स्थान रखता था।

मंत्रिमण्डल एवं मंत्रिपरिषद् — श्राधुनिक समय में मंत्रिमण्डल श्रीर मंत्रिपरिषद (Ministry and Cabinet का मेद बहुत स्पष्ट ख्रीर महत्वपूर्ण माना जाता है । प्राचीन भारत की राजनीतिक व्यवस्था में परिपद् प्रणाली का बहुत महत्व रहा है। उस सपय भी परिषद् श्रीर सूद्म परिषद् (Cabinet and Inner Cabinet) की रचना की जाती थी श्रीर श्रपने श्रपने कार्य के चेत्र मर्यादित होते थे। साधारणतया (१) श्रमात्य (प्रधान मंत्री), (२) पुरोहित (विधि मंत्री , (३) दूत (विदेश मंत्री), (४) सुमंत्र (वित्त मंत्री) एवं (५) सेना-पति (सुरज्ञा मंत्री) परिषद् के सदस्य होते थे और युवराज भी इनकी औं शी में गिना जाता था। जन अन्य विभागों के अध्यन् सम्मिलित होते थे तो मंत्रिमगडल का रूप हो जाता था। इसी ऋवस्था में म त्रिमण्डल के सदस्यों की संख्या बीस और बत्तीस होती थी। (महा-भारत) किन्तु मंत्रिपरिषद् में सदस्यों की संख्या आठ या दस से अधिक होना सम्भव नहीं था श्रीर इस मंत्रिपरिषद् में भी एक सूच्म परिषद् होती थी, जिसमें केवल तीन या चार सदस्य होते थे। १ इन्हीं लोगों से सम्राट विचार-विमर्श किया करते थे। इस ब्रान्तरिक संस्था से सम्राट निरन्तर सम्पर्क रखते थे। ऋर्थशास्त्र रामायण, ऋौर महामारत में इस सूचम संस्था के सदस्यों को मंत्री की संज्ञा दी गई है। अर्थात् वे लोग जिनके साथ मंत्रणा की जाय श्रीर मंत्रणा सदैव गुप्त एवं गम्भीर होती है, इसलिए मन्त्री शन्द के साथ यह परिहियति बहुत उपयुक्त प्रतीत होती है। संस्कृत भाषा में मंत्र (Policy) का अर्थ एक सिद्ध एवं शुद्ध विचार होता है, जो कल्याणकारी भी होता है। राजनीति में राज्य की नीति को भी मंत्र कहा जाता था। इसलिए मंत्री का ऋर्य उस व्यक्ति से लिया जाता था जो राज्य के मंत्र का सम्पादन करे । इसलिए रामायण श्रयोध्याकाण्ड में 'मंत्रघर' तथा महाभारत में 'मंत्रगृह' शब्दों का प्रयोग हुआ है। २ महाभारत में सुद्दम परिषद् के सदस्यों की संख्या कम से कम

१ अर्थशास्त्र एष्ठ २=

२ महाभारत श्रोर रामायण-(As quoted by Dr. Jayaswal-Hindu Polity-Page 298.

तीन और सम्भवतः पांच स्वीकार को गई है। अर्थशास्त्र में यह स ख्या तीन अथवा चार प्रस्तावित की गई है। अर्थशास्त्र में ही यह भी प्रसंग है कि बहुत अधिक छोटी परिषद् भी प्रयात एक व्यक्ति की परिषद् लाभदायक नहीं हो सकती। रामायण में तो स्पष्ट है कि परिषद में भन तो एक ही व्यक्ति हो और न अनेक?'। नीतिवाक्यामृत के अनुसार परिषद के सदस्यों की संख्या सदेव विषम ही होनी चाहिए। १ इसका अर्थ है कि परिषद में भी पूर्ण विचार विमर्श के पश्चात तिर्णय बहुमत के हारा सरल बनाने के हेत यह विधि के छप में स्वीकार किया गया था। परिषद के सदस्यों की संख्या सदेव न्यूनाधिक होती रहती थी। इससे यह सिद्ध होता है कि परिषद प्रणाली एक विक्रित्त संख्या थी, जो प्राचीन भारत में एक व्यक्ति के शासन के स्थात पर अनेक विश्वहत और चतुर व्यक्तियों के शासन के रूपात पर अनेक विश्वहत और चतुर व्यक्तियों के शासन के रूपात पर अनेक विश्वहत और चतुर व्यक्तियों के शासन के रूपात पर अनेक विश्वहत और चतुर व्यक्तियों के शासन के रूपा में प्रकट हुई। एक व्यक्ति का शासन भारतीय समाज में कमी। भी नहीं रहा और परम्परा यह सिद्ध करती है कि सदेव समाज के न्यायिय चतुर लोगों हारा शासन संचालित होता था।

मंत्रियों की श्रे णियाँ—प्राचीन भारत में भी सारे मंत्रिगण एक ही श्रेणी के नहीं होते थे। रामायण, शुक्रनीति-सार तथा पाली प्रत्यों के अनुमार मंत्रियों की तीन श्रे णियाँ होती श्री-रामायण में सुख्य (Superior), मध्यमः (Intermediaries), श्रीर जवन्य (Inferior) श्रीणियां मानी गई है। शुक्र-नितसार भी इसी का समर्थ न करता है। इसके श्रितिरक्त श्रन्य प्रसंगों से यह प्रकट होता है कि मंत्री चार प्रकार के होते थे—

(१), मंत्रधर अर्थात् वे मंत्रिगण जो सदम परिवद् (Inner Cabinet) में सम्मिलितः होते थे ।

(२) परिषद-सदस्य अर्थात् जो विभन्न विभागों के अध्यक्त होते ये और मंत्रि परिषद में सिक्तय रहते, थे।

(३) सहायकः मंत्री अर्थात् वे लोगः जिनके पासः कोई निश्चित विभागः नहीं होता था (Ministers with: out-Portfolios)

(४): अन्यः मंत्रिगणः अर्थात् वे लोगः चीः पदेनः (Ex-officio)ः मंत्रिमण्डलः केः सदस्य होते थे । जैसे प्रामणी अथनाः पौर-जनपदः के अध्यत्, पूर्ग-निगमः आदि के अध्यत् अपि

इस। प्रकार अने के अ ियाँ के सदस्यों से मंत्रिमण्डन का निर्माण होता था। यहें मंत्रिमण्डलों में इनकी संख्या साधारणतथा आनुपातिक होती थी और इसी के अनुसार मंत्रियों का वेतन भी निर्मित होता था। प्रथम अर्जा के मंत्रियों का वेतन ४०००० पण ने श्रितवर्ष होता था। और इस अर्जा के मंत्रियों को संख्या चार या पांच होती थी। दितीय अर्जी के मंत्रियों का वेतन २४००० पण प्रतिवर्ष होता था और उनकी संख्या पांच से लेकर नी तक होती थी। त्रितीय अर्जी के मंत्रियों का वेतन १२००० पण प्रतिवर्ष होता था। उनकी संख्या ग्यारह से लेकर अटारह तक हो। सकती थी। आवश्यक वातुसार यह गहिमा

१ नीतिवालयामृत-त्रयः पत्न सन्त वा मन्त्रियः कार्या । अनु ध्वेद दराम

^{🛨 ्}तत्कालीन हजतमुद्रा, जिसका मृत्य नर्तमान सुद्रानुसार लगमग प्रनास अवे पैसे हो सबता है। ः

न्यूनाधिक होती रहती थी। इस हिन्द से यदि हम आधुनिक प्रजातंत्रात्मक राज्यों के मंति-मण्डलों का अध्ययन करे तो हमें कोई नवीनता नहीं मिलेगी। आज भी परिषद्-मंत्री, राज्य-मंत्री, उपमंत्री, एवं अतिरिक्त मंत्री आदि की श्रेणियां होती हैं और उनके पद. वेतन एवं प्रतिन्ठा का भी लगभग उसी प्रकार का कम है मंत्रियों की संख्या का अनुपात भी देश, काल और स्थिति के अनुसार लगभग वही होता है, जो प्राचीन भारतवर्ष में होता रहा है।

मंत्रिपरिषद् के कार्य पाचीन काल में राज्य का सम्पूर्ण शासनपत्रन्थ मंत्रि-परिषद् के द्वारा ही संचालित होता था। तत्कालीन समस्त ग्रन्थ इस विषय में कुछ न कुछ प्रकारा अवस्य डालते हैं और उन सबका तात्पर्य यह है कि म त्रिपरिषद् के कार्य राज्य का सब प्रकार से हित करने के लिए अत्यन्त विंस्तृत और व्यापक माने गए थे। शुक्र-नीति के. श्रनुसार मन्त्रियो।को ऐसी नीति का निर्धारण करना चाहिए था, जिससे राज्य, प्रजा, कोष तथा सुनृपत्व की निरन्तर बृद्धि होती रहे यदि यह सन सम्भव नहीं हो तो उस मन्त्रिमण्डल का श्रास्तित्व ही प्रयोजनहीन हैं। १ यह सच हैं कि यदि मन्त्रि-परिषद् राज्य की संमृद्धि में लिए सचेष्ट न हो, प्रजा को प्रगति के पंथ पर अप्रसर न' कर' संकें, राज्यकीय को सम्पन्न न रख सके तथा रूप में सुरूपत्व की न बढ़ा सके तो ऐसा मिन्त्रिमएडल निर्धिक हैं। इसका तात्पर्य है कि राजा पर नियंत्रण रखने और उसे प्रजा का शुभचिन्तक वेनाये रखने का कार्य मन्त्रिपरिषद् का था । राज्य का शासन-सचालन पूर्णरूपेख इसीं परिषद् के उत्तरदायित्व का विषय था। राज्य की ऋार्थिक व्यवस्था द्वारा सम्पन्न कोष् की स्थापना करना था। राज्य के मुसंगठित वल अर्थात् सेमा द्वारा भीतरी शान्ति व बाह्य सुरचा अर्थात् विदेशी आक्रमणी से बन्नाव की व्यवस्था करना भी मन्त्रिपेखिंद् का ही कार्य था । इमेलिए मन्त्री को राज-राष्ट्र-भृत् अर्थात् राज्यात्रौरः राष्ट्रके उत्तरदायित्व का वहन करने वाला कहा गया है। महाभारत में इसी परिस्थिति एवं कर्ताव्यपरायणता के कारण राजा की संदेव 'परतंत्र' कहा गया है, जो कभी स्वतंत्र नहीं रहता। वास्तव में राजा पर मिन्त्रमण्डल को पूर्ण नियंत्रेण रहता था। महाभारत के ऋनुतार तथा कौटिल्य द्वारा समर्थित मन्त्रिपरिषद् के निम्नेलिखित पुंख्य कर्ता व्य माने गये हैं :-

- (१): मन्त्र निर्धारण (Delibration on the policy of State)
- (२)। मन्त्र। फल-प्राप्ति (Realization of the result of that policy)
- (३) कर्म अनुष्ठान अर्थात् राज्य के कार्यों को व्यावहारिक रूप देना (Execution of business)
- (४) आयं क्या क्या (The business concerning income and expenditure)
- (u) दण्ड अर्थात् सेना का नियंत्रण (Army)

राज्य प्रजा वस्त्र कोषः सुनृपत्व न विद्धितम् ।
 यन्मन्त्रतोऽरिनारास्तेम न्त्रिभिः कि प्रयोदानम् ॥ श्कनीतिसार २ =३

(६) दण्डप्रणयन ऋर्थात् सेना का नेतृत्व (Leading the army)

(७) अमित्र एवं आटविक प्रतिशोध अर्थात् शत्रु एवं बर्बर या जंगली लोगों के विरुद्ध व्यवस्था करना ।

(=) राज्यरच्रण ऋथीत् सरकार की व्यवस्था (Maintenance of Government) |

(६) व्यसन-प्रतिकार अर्थात् राज्य की दुर्व्यसन आदि के प्रचार से रत्ना (Providing against national degeneration)

(१०) कुमार रक्षा एवं ग्रिभिषेक व्यवस्था ग्रार्थात् राजाग्रीं की रक्षा एवं उनके राज्याभिषेक की रज्ञा करना (Protection of the princess and their Consecration (Coronation)?

इस प्रकार सम्पूर्ण प्रशासन मंत्रिपरिषद् के अधिकार में रहता था और वे ही लोग सब विभागों के कार्य के लिए उत्तरदायी होते थे।

कामन्दक के अनुसार मंत्रिमण्डल के कार्य बहुत विस्तृत थे। मुख्यतः उस चित्र में मंत्रिपरिषद की पांच विशेषताएँ मानी जाती थीं :--

प्रत्येक सदस्य का क्या कर्तव्य था, विस्तार से बताया गया है। कीटिल्यं के

- (२) विचार-विमर्श । (३) समय का विभाजन
- (४) प्रादेशिक सीमा निर्घारण एवं
- (५) श्रापत्तियों के निवारण की योजना । श्रीर इसके बाद मंत्रिपरिषद के

(१) राज्य की नीति का निर्धारण

मतानुसार मंत्रिपरिषद् मुख्य रूप से चार प्रकार के काम करती थीं :--

- , (१) नये कार्य का आयोजन 🐇 🕟 👾
 - (२) पूर्व संचालित कार्यों की पूर्णता कार व (३) वर्तमान कार्यों में सुधार तथा
 - (४) प्रस्तावित विधेयकों का अन्तरशः पालन ।

शुक्तीति के अनुसार मंत्रिपरिषद् उन सब कार्यों के लिये उत्तरदायी थी जिनके द्वारा राज्य या प्रजा के जीवन पर किसी भी प्रकार का प्रभाव हो सकता या। इसके ग्रातिरिक्त प्रत्येक विमागीय मंत्री का विशिष्ट कार्य होता या वो ग्राक-नीतिसार में बहुत विस्तार के साव धर्मान किया गया है।

विदेशी यात्री शैगस्थनीज के द्वारा भारतवर्ष की तत्कालीन स्थिति का वर्णन किया गया है। उससे भी यह स्पष्ट है कि राज्य की समस्त शक्तियाँ मेत्रिपरिपद के द्वारा प्रयुक्त होती

मन्द्रभः लावान्तिः कर्मानुष्ठानमायन्ययकमं दर्ग्यमण्यनमभियादवीप्रतिवंशी राज्यस्यस्य स्यसन-प्रतीकारः कुमाररकणमनिषेकस्य कुमाराखामावराममात्वेषु (महागारत और कीटिल्य) As, quoted by Dr. Jayaswal-Hindu Polity-Page 311.

थीं और सम्राट स्वयं अकेला कुछ नहीं कर सकता था। मैगस्थनीज लिखता है: "मंत्रिपरि-पद् का बहुत सम्मान होता था! बुद्धिमानी और चरित्र का उच्च ग्रादर्श इस संस्था के सम्ब-न्वित था। परिषद् महत्वपूर्ण विषयों पर विचार करती थी। राज्यपालों की नियुक्ति करती थी तथा श्रन्य अधिकारियां (अध्यच्) श्रादि की भी। मंत्रिपरिषद् एक श्रलग जाति ही थी जो संख्या में न्यूनतम, किन्तु उसके सदस्यों के चरित्र श्रीर बुद्धिमानी के कारण श्रत्यन्त सम्मा-नित थीं।" १

उपर्युक्त समस्त वर्णन से यह सिद्ध होता है कि प्राचीन भारतवर्ष में मंत्रिपरिषट् के कार्य समय, स्थिति एवं राज्य के आकार के अनुसार बहुत विस्तृत और व्यापक होते थे। यह भी स्पष्ट है कि तत्कालीन भारत विश्व के वर्जमान प्रजातंत्र देश की शासन पद्धित का बड़ी सफलता से व्यवहार कर चुका था। प्रत्येक मन्त्री के अलग अलग विभागीय कार्य के वर्णन से यह भी प्रकट है कि अपने चेत्र में किताना जागरूक एवं कर्ज व्यविष्ठ रहना आव-श्यक था। जिसके द्वारा वह सफल होता था। यह वास्तव में गर्व का विषय है कि तत्कालीन भारत का राजनैतिक स्वरूप बहुत विकसित एवं व्यवस्थित था और प्रजातंत्रात्मक भी।

कार्य पद्धति—(Procedure of Deliberation)—समिति की उत्तराधिका-रिणी होने के नाते परिषद् एक शिक्तिशाली प्रजातंत्रात्मक संस्था के रूप में प्राचीन भारतीय राजनीति को प्रभावित करती रही। राजा केवल एक सर्वोच्च वैधानिक अध्यन् होता था स्रोर सत्ता का प्रयोग राजा के नाम पर परिषद् व्यवस्थापिका और सर्वोच्च न्यायालय के रूप में तथा मन्त्री कार्यकारिए। के रूप में करते थे। ये परम्पराए सुदृढ़ शी श्रीर इनकी अवहेलना सम्भव नहीं थी। इसलिए मन्त्रिपरिषद् की कायपद्धति भी सुनिश्चित थी। मन्त्रिपरिषद् की इस नियामक शक्ति का पूर्ण परिचय, हमें नियमों के पारित होने, आजाओं और घोषणाओं के प्रेषित किये जाने स्त्रादि की प्रणाली से, मिल सकेगा। प्राचीन भारत की राजनीति में मौखिक त्राज्ञात्रों का कोई महत्व नहीं था। शुक्रनीति के त्रानुसार त्रालिखित रूप से त्राज्ञा देने वाला राजा तथा उस आजा का पालन करने वाला अधिकारी दोनों ही चोर समके गये हैं। २ इस नियम की पुष्टि ऋशोक के शिलाभिलेख से भी हो जाती है। उसने खुदवाया है कि यदि "मैं स्वयं अपने मुख से कोई आजा दूँ कि (अमुक) दान दिया जाय या (अमुक) काम किया जाय या महामात्रों को कोई आवश्यक आजा दी जाय और यदि इस विषय में कोई विवाद उपस्थित हो या मन्त्रिपरिषद् उसे अस्वीकार करे तो भेने आजा दी है कि तुरन्त ही हर घड़ी श्रीर हर जगह मुक्ते सूचना दी जाय।''३ इससे यह सिद्ध होता है कि मीखिक श्राजाश्रों का मूल्य नहीं था श्रीर राजकीय श्राज्ञा परिषद् द्वारा स्वीकृति के उपरान्त ही प्रेषित की जाती थी। इसीलिए मौखिक त्राजात्रों का विरोध मन्त्रिपरिपद द्वारा सम्भव था। विखित

१ Strabo अन्डिद ४=, McCrinadle, Megasthenese, पृष्ठ ६५, As quoted by Dr. Jayaswal—Hindu Polity Page 310.

२ श्रतेख्यमाशापयित ग्रतेख्य यस्तरोति यः। राजकृत्यमुभी चौरौ तो भृत्यनृपती सदा ॥ शुक्रनीतिसार २।२६१ ३ शिलाभिलेख ६.

नियम, त्राज्ञात्रों एवं घोषणात्रों के पारण की पद्धति पर शुक्र-नीतिसार में भी विस्तृत वर्णन मिलता है। तद्नुसार लेख सर्वप्रथम विभिन्न मन्त्रियों की स्वीकृति के लिए जाता था और प्रत्येक मन्त्री अपने पद के अनुसार निश्चित शब्दावली द्वारा अन्ती सम्मति अयवा असम्मति प्रकट करता था। मन्त्रियों की स्वीकृति के उपरान्त राजा अपनी स्त्रीकृति देता था तत्-पश्चात् लेख द्वितीय चरण में प्रवेश करता था इस बार समस्त मन्त्री सामूहिक रूप से परिषद् में विचार करते थे और स्वीकृति देते थे। इसके बाद परिषद् की मुहर से अ कित हो लेख राजा के पास जाता था। राजा विना विलम्ब किये लेख पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर देता था। उसे लेख की आलोचना का अधिकार नहीं था। शुक्रनीति में वर्णित इसी कार्य-पद्धति के श्राचीर पर यह स्वीकार किया जा सकता है कि परिषद् द्वारा पारित प्रस्ताव पर राजा को स्वीकृति देनी ही पड़ती थी। वर्तमान प्रजातंत्रात्मक भारत को राजनीति में भी यही पर-म्परा प्रचलित है। मनु एवं कौटिल्य के मतानुसार भी प्रस्ताव श्रुथवा लेख की पारण प्रक्रिया छुछ छुछ इसी प्रकार की है। इन विचारकों के अनुसार राजा को प्रथम मन्त्रियों से प्रवक् पृथक विचार-विमर्श करना चाहिए। तत्पश्चात् परिषद् में सामूहिक रूप से। सामूहिक रूप से विचार करने से पूर्व राजा द्वारा मन्त्रिया से 2यक पृथक विचार करने का आदेश महत्व का है। १ इसका यह अर्थ हो सकता है कि प्रस्ताव के प्रारम्भ में ही राजा अपनी इच्छानुसार संशोधन या परिवर्तन करा सके। ऋपने व्यक्तित्व से प्रभावित कर ऋपने विचारों का समर्थन प्राप्त कर सके । इसी आदेश से यह भी प्रकट होता है कि सामूहिक रूप से परिषद् में प्रस्ताव स्वीकृत हो जाने पर न तो राजा अपने व्यक्तित्व का प्रभाव डाल सकता तथा और न पारित प्रस्ताव की अवहेलना ही की जा सकती थी उसमें संशोधन भी मंत्रियों की अनुमृति से ही संभव होता था।

डाँ० जायसवाल ने इस सम्पूर्ण पद्धित का संचिप्त वर्णन इस प्रकार किया है कि सर्वप्रम एह मन्त्री, मुख्य न्यायाधीश, विधि मन्त्री एवं विदेश मन्त्री निश्चित प्रणाली के अनुसार ''मुक्ते कोई आपित नहीं है।'' इस प्रकार प्रस्ताव पर अपनी सम्मित प्रकट करते थे। अर्थात उनके विभागों को उस प्रस्ताव के प्रति कोई विरोध नहीं है। राजस्व एवं कृषि मन्त्री लिखते थे ''पूर्ण विचारानुसार'' है। किर परिषद का प्रधान स्वयं लिखता था ''सत्य एवं यथार्थ है।'' प्रतिनिधि लिखता था अंगीकृत योग्य) ''स्वीकार योग्य है।'' युवराज लिखता था — ''स्वीकृति के उपयुक्त है।" पुरोहित लिखता था ''में सहमत हूँ।'' प्रत्येक मन्त्री अपने इस्ताचरों के साथ अपनी मुहर लगाता था। अन्त में सम्राट "स्वीकृत" लिखकर अपनी मुहर लगाता था। इस प्रकार प्रथम चरण के प्रचात दूसरे चरण में यह सारी कार्यवाही परिषद् के सम्मुख उपरिथत होती थी। जहां परिषद (गण) की ओर से स्वीकृति होती थी और परिषद की मुहर लगाई जाती थी। अन्त में एक बार फिर वह प्रस्ताव सम्राट के सामने प्रस्तुत होता था और निर्वेलम्ब 'इष्टिमिति''

१ तेपां स्व स्वमिष्रायमुपलस्य पृथक् -पृथक् । विकास करिया

समस्तानां च कार्येषु विदध्याद्धिवतमात्मनः ॥ मनुस्मृति ७४७ ।तानेक्षेत्रराः पृच्छेत् समस्तां च ॥ अर्थशास्त्र पृष्ठ २ =

त्रार्थात् (Seen) देख लिया ''के साथ उसे त्रान्तिम रूप मिलता था त्रीर उसके परचात् किसी प्रकार की त्रालोचना सम्भव नहीं थी। १

परिषद् द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव सर्वमान्य होता था और सम्राट भी उसकी त्रालीचना के लिए अन्तम था। इस प्रकार के प्रस्ताव ही, जिन्हें सबकी स्वीकृति प्राप्त होती थी, संवैधानिक हिंद से 'सम्राट' थे। शुक्रनीति के अनुसार ''तृपसंचिन्हितं लेख्यं तृपस्तन्त तृपो तृपः।'' (शुक्र॰ द्वितीय २६२) अर्थात् ऐसे लेख जिन पर सब लोगों को मुहर सहित हस्तान्तर हैं वे ही वास्तव में तृप हैं। व्यक्तिगत रूप में राजा तृप नहीं है। इसलिए लिखित आजाओं के पालन करने वाले स्वामिमक्त, किन्तु राजा के व्यक्तिगत मौखिक आदेशों का पालन करने वाले, वैधानिक हिंद से विदेशी आजाओं के पालन करने वाले अथवा चोर की आजा पालन करने वाले चोर माने जाते थे। र अतः यह सिद्ध होता है कि मंत्रिपरिषद् वास्तव में वैधानिक संगठन था और इसी संस्था द्वारा शासन संचालित होता था। इसकी कार्य गद्धित भी सुनि-श्चित थी, जिसका अन्तरशः पालन होता था।

मंत्रियों की छाईताएँ (योग्यताएँ):—मंत्रियों की योग्यताय्रों के लिए विभिन्न यन्यों में सामान्य गुणों को तो आवश्यक बताया ही गया है। मनुस्मृति के अनुसार वंशपर-म्परा के राजसेवक धर्म-नीति पारदर्शी, शूर, लच्यमेदन आदि युद्धविद्या में कुशल, उच्च-कुल के एवं बारम्बार विपत्ति के समय परीचा किये हुए सात या आठ व्यक्ति मंत्री होने चाहिए। यह भी निर्देश है कि पवित्र, बुद्धिमान, स्थिर स्वभाव, सन्मार्ग से धन लाने वाला तथा भली

तेलानुपूर्वं कुर्यादि दृष्ट्वा लेख्यं विचार्यं च ॥३६२॥
मन्त्री च प्राड्विवाकश्च पंडितो द्तसंग्रकः।
स्वाविरुद्धं ं,लेख्यमिदं लिखेयुः प्रथमं रिवमे ॥३६३॥
स्रमात्यः साधु लिखनमस्येनस्प्राग्लिखेदयम्।
सम्यग्वचारितमिति सुमन्त्री विलिखेत्ततः॥३६४॥
सत्यं यथार्थमिति च प्रधानश्च लिखेत्त्वयं।
स्रंगीकत्तुं योग्यमिति ततः प्रतिनिधिलिखेत्॥३६४॥
स्रंगीकर्त्तुं योग्यमिति ततः प्रतिनिधिलिखेत्॥३६४॥
स्रंगीकर्त्तुं व्योग्यमिति ततः प्रतिनिधिलिखेत्॥३६५॥
स्रंगीकर्त्तुं व्योग्यमिति च युवराजो लिखेत्स्वयम्।
लेख्यं स्वामिमतं चेतिद्विलिखेच्च पुरोहितः॥३६६॥
स्वस्वमुद्राचिन्हितं च लेख्यान्ते कुयुरेव हि।
स्रंगीकृतमिति लिखन्मुद्रयेच्य ततो नृष्यः॥३६७॥
सार्यान्तरस्याकुलस्वात्सम्यग्द्रयुं न शक्यते।
युवराजादिभिलेंख्यं तदनेन च दिरीतम्॥३६=॥
समुद्रं विलिखेयुवं सवे ं,मन्त्रिग्यास्ततः।
राजा दृष्टमिति लिखेद् द्वाक् सम्यग्दर्शनाचनः॥३६६॥

१ शुक्रनीतिसार भाग २ रलोक ३६२ से ३६९ तक As quoted by Dr. Jayswal-Hindu Polity Page 307-08.

२ उपरोक्त--१एठ २६१

मनुस्मृति, सप्तम अध्याय, श्लोक ४४. १६० २६०

प्रकार परीचा लिये और भी मंत्रियों को रखे । १ अन्य प्रसंगानुसार सम्राट को चाहिए कि वह ऐसे स्वजाति-बन्धुओं को मंत्रिपद पर नियुक्त करे जिनके पिता स्त्रीर प्रपिता मंत्री रह चुके हों। क्योंकि ऐसे व्यक्ति अपने पूर्व संस्कारानुसार सदैव सम्राट के प्रति भक्त रहेंगे। इसके अतिरिक्त राजधर्म के विशेषज्ञ, जो सम्राट को वास्तव में दण्डधर के रूप में स्वीकार करें, कुलीन हों, शुद्धचित्त तथा कर्ताव्यपरायण हों, मंत्रिषद के योग्य होते हैं। कौटिल्य के मतानुसार मंत्रियों में निम्नलिखित योग्यताएँ एवं गुण होने चाहिए:-राज्य का स्थायी निवासी, कुलीन, प्रभावयुक्त, कलाविज्ञ, दूरदर्शी, बुद्धिमान्, स्मृतिमान्, साहसी, वक्ता, कुशल, उत्साही, प्रखरबुद्धि, सहिष्णु, चरित्रवान्, मधुरस्वभावी, कत्तं व्यनिष्ठ, व्युवहारकुशल. बलिष्ठ, स्वस्थ, शूर, स्फूर्तिमान्, दृढ़चित्त, स्नेही तथा स्वभावतः घृणा एवं शत्रुता की भावना को दूर करने वाला आदि । कामन्दकीयनीतिसार के अनुसार कुलीन, पवित्र, शास्त्रसम्पन्न, दगडनीति के यथायोग्य प्रयोग करने वाले राजा के मंत्री होने चाहिए। र वास्तव में इन गुणों से युक्त व्यक्ति ही मंत्रिपद श्रोर राज्य के शासन के लिये उपयुक्त हो सकता है। ३ कौटिल्य के अनुसार मंत्रियों की नियुक्ति के पहले सम्राट उनकी परीचा करता था। कामन्दक भी इस सिद्धान्त का समर्थन करता है । परीचा के चार मुख्य उपाय थे~धर्म, श्रर्थ, काम श्रीर भय । (इन उपायों का नाम ही उपधा है, ऋषीत् धर्म, ऋर्थ, काम ऋौर भय से परीक्षापूर्वक मंत्रियों त्रादि के त्राशय को दूँ दना उपधा कहाती है। उपधा का ऋर्थ है समीप नःकर भली प्रकार परीचा करना) । ४ इन परीचान्त्रों के बाद जो धार्मिक परीचा में सफल हो उसे न्याय विभाग, जो अर्थ की परीचा में सफल हो उसे राजस्व विभाग, जो काम-परीचा में सफल हो उसे विनोद-विभाग तथा जो भय-परीचा में सफल हो, उसे सुरचा एवं विदेश कार्य विभाग, तथा जो सब परीवाश्रों में सफल हो उसे प्रधान मन्त्री बनाना चाहिए। प्रकामन्दक के मता-नुसार इन परीचात्रों के बाद जिस व्यक्ति में निम्नांकित गुण प्रकट हों उसे मन्त्रिपद पर नियुक्त करना चाहिए:-"ग्रन्छा ज्ञानी, त्रपने देश का, कुलीन, शील-वल से सम्पन, वाचाल, प्रगल्भ, दूरदर्शी. उत्साही, समय पर तत्काल उपाय का ज्ञाता, स्तब्धता श्रीर चपलता से हीन, मित्रता के गुर्गों से युक्त, सहिष्णु, पवित्र, रत्यवादी, बल, घेर्य, स्थिरता, प्रभाव श्रीर श्रारोग्य से संयुक्त, शिल्प विद्या में चतुर, दज्ञ, िविचार-बुद्धिसम्पन, मन्त्रादिधारणा में समर्थ, स्वामी में दृढ़ भिक्त करने वाला तथा वैर का न करने वाला, ऐसा मन्त्री होना

१ मनुस्मृति—श्लोक ६०

२ वामन्द्रकीय नीतिसार—पृष्ट ३६ — "कुलीनाः शुनयः ग्रूराः श्रुतवन्तोऽनुरागिणः । दण्डनीति प्रयोक्तारः सनिवाः स्पूर्महीपतेः ॥ २५॥

२ कौंडिल्व-एष्ठ १४

४ चपेत्य भीवते यस्मादुवभेति नतः रमृता । उपाया उपचा श्रीयास्तयाऽमात्यान् परीक्षवेत् ॥ २७ ॥ । (कामन्द्रकीय नीतिसारे)

५ शतलीतिसार--एण्ड १६**-१७**

चाहिए । १ त्रागे वह यह भी लिखता है कि दूरदर्शिता एवं शिल्पता इन दोनों गुणों की परीक्षा करें । २ प्रगल्भता ग्रीर बुद्धि की चमत्कारिता, इन दोनों गुणों की परीक्षा करें । ३

इसके अतिरिक्त मंत्रियों की नियुक्ति में वर्णों के प्रतिनिधित्व का भी ध्यान रक्खा जाता था। जैसे राज्याभिषेक आदि अनेक अवसरों पर सक्को उचित प्रतिनिधित्व मिलता था. मित्रि परिषद् में भी अपवाद नहीं था, और हिन्दू शासन प्रणाली के अंतिम समय तक यह परम्परा मान्य रही है। महाभारत में ऐसे सैंतीस मंत्रियों की स्वी है जो वर्ण व्यवस्था के आधार पर चुने गये थे। चार बाह्मण, आठ च्त्रिय, इक्कीस वैश्य. तीन श्द्र एवं एक स्त (वर्णकंकर) जनसंख्या के अनुपात से ही यह प्रतिनिधित्व प्राप्त होता था। उस समय वैश्य वर्ण की संख्या अधिक थी, अत: मंत्रिपरिषद् में भी इसे अधिक प्रतिनिधित्व मिला था और फिर इसमें से सात या आठ सदस्यों की वास्तिवक मंत्रिपरिषद् बनती थी, जिसे आज हम ''आंतरीय परिपद्'' कहते हैं। ४

प्रशासन कार्य कुशलतापूर्वक चलाने के लिये मंत्रियां के विभाग भी परिवर्तित होते रहते थे। लगभग प्रति तीसरे वर्ष, अथवा पांच, सात अथवा दस वर्ष में यह परिवर्तन कर ही दिया जाता था। एक ही व्यक्ति के अधिकार में सत्ता निरन्तर नहीं रहनी चाहिए-ऐमा सिद्धान्त स्वीकार किया जाता था। साथ ही यह भी विचार किया जाता था कि योग्य व्यक्ति को अधिक उत्तरदायी-विभाग मिलना चाहिए और इस प्रकार प्रत्येक सदस्य को कमशः उन्नित के पथ पर अप्रसर होने का अवसर मिलता रहना चाहिए। अशोक ने अपने अभिलेखों में भी त्रिवर्षीय या पंचवर्षीय स्यानान्तरण का सिद्धान्त प्रतिपादित किया है। जब कि सम्पूर्ण मंत्रिमण्डल (वर्ग) अपने-अपने विभागों से विदा लेता था। इस पद्धति को "अनुसमयान" (Regular Departure) कहा जाता था जो शुक्रनीति में प्रथुक्त "अनुगत" शब्द का समानार्थी है। अतः यह सिद्ध है कि मन्त्रिपरिषद् स्थायी संस्था नहीं थी। गुणों और योग्यता पर आधारित एक ऐसी उत्तरदायी संस्था थी जो राज्य, राजा और प्रजा के हित में संलग्न रहती थी। मन्त्रियों की सहायता तथा शासन की सुगमता के लिये उन्हें दो सचिव (Secretaries) या कार्य के अनुसार अधिक सचिव नियुक्त करने का अधिकार भी प्रण्त था। ह

मूल्यांकन—उपर्शुक्त वर्णन से मिन्त्रपरिषद् की स्थिति स्पष्ट है। साधारण परि-स्थितियों में राजा, मिन्त्रयों के परामर्श का अनुसरण करता था। परन्तु राजा छोर मिन्त्रपरिषद् के व्यक्तित्व और योग्यता पर यह स्थिति अधिक निर्भर करती थी। यदि राजा टड़निश्चयी, प्रभावशाली और योग्य होता था तो मिन्त्रपरिषद् कुछ गौण स्थान ग्रहण करती थी छोर

१ कामन्दकीय नीतिसार--पृष्ठ ३६--३७ श्लोक र= से ३० तक।

२ उपरोक्त-श्लोक ३४, पृष्ठ ३=

३ . उपरोक्त-रलोक ३६, पृष्ठ ३=

४ महाभारत--शांतिपर्व--श्रनुच्छेद =५,७--११।

१ शुक्रनीतिसार-"त्रिभिर्वा पन्चभिर्वापि सप्तर्भिर्दशभिश्च वा ॥ भाग दूसरा, पृष्ठ ११०

E Dr. Altakar-State & Govt. in Ancient India-Page 168.

यदि इसके विपरीत मन्त्रिपरिषद् अधिक योग्य व्यक्तियों द्वारा संगठित हो जाता था तो सम्राट को भी परिषद् का पूर्ण सम्मान करना पड़ता था। अपनी लोकप्रियता के अतिरिक्त भी मन्त्रियों की नियुक्ति राजा द्वारा होती थी, वह उन्हें त्यागपत्र देने का आदेश दे सकता था, उनका स्थानान्तरण करता था, वे राजा के प्रति उत्तरदायी होते थे इसलिए मन्त्रियों की स्थिति श्रीर प्रतिष्ठा बहुत सीमा तक राजा पर निर्भर करती थी। श्रतः प्राचीन भारत में मन्त्रिपरिषद् पूर्ण रूप से संसदीय प्रकार की नहीं थी। वे लोग राजा के परामर्शदाता थे। परन्त शासन वही चलाता था जो दोनों में से अधिक योग्य और शिक्तशाली होता था। इसलिए राजायत्त-तंत्र (King-centred), सचिवायत्त-तंत्र (Ministry-contr fled) एवं उभयायत्त-तंत्र (Administration by both) शब्दों का प्रयोग होता था। ऐसी स्थिति में उपर्कृत वर्णन कि राजा को निषेधाधिकार भी प्राप्त नहीं था. असंगत प्रतीत होता था। केवल यह कहा जा सकता है कि मन्त्रिपरिषद की प्रतिष्ठा और शक्ति समय समय पर परिवर्तित होती रही है। शक्तनीति के अनुसार राजा चाहे कितना ही कुशल तथा नीतिपट क्यों न हो उसे स्वयं बिना मन्त्रियों की सम्मति के राज्यकार्य नहीं करना चाहिए और स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाला राजा अपने नाश की योजना करता है तथा राज्य एवं प्रजा को खो देता है। १ इससे यह सिद्ध है कि मन्त्रिपरिषद् एक अत्यधिक शक्तिशाली संस्था थी और वह वैदिककालीन समिति के समान ही निर्कुश राजा की पदंच्यत कर सकती थी, तभी तो राज्य श्रीर प्रजा को खो देने का प्रसंग श्राया है। मन्त्रिपरिषद् की इसी स्थिति के कारण राजतंत्र के समर्थक कौटिच्य खादि ने राजा को यह खादेश दिया या कि महत्वपूर्ण कार्यों पर मन्त्रिपरिषद् द्वारा विचार एवं बहमत के द्वारा निर्णिय लिया जाना चाहिए। यही सम्मति बहस्पति, सुक स्रादि ने दी है। स्रतः यह सच है कि मन्त्रियरिषद पाचीन भारत की एक संवैधानिक, शिक्त-शाली और सफल संस्था रही है।

ः शश्ल

- 1. Write a note on the ministry in Ancient India.
- 2. Discuss the composition and powers of Mantri Parishad (Council of ministers) along with the portfolios assigned to each minister.

बारहवाँ अध्याय

प्रशासन (२) राजकीय संगठन

(Administration (II) Governmental)

प्रस्तावान - वर्त्त मान राज्यों की प्रशासन पद्धति की भांति प्राचीन काल में भारत-वर्ष में भी प्रशासन प्रणाली वैज्ञानिक त्राधार पर संगठित थी। सम्पूर्ण राज्य व्यवस्या की दृष्टि से प्रादेशिक त्र्याधार पर विभाजित किया जाता था। परन्तु विभिन्न राज्यों में प्रशासन-संगठन एक ही प्रकार का नहीं था प्रदेश, जिले अथवा अन्य भाग आकार-प्रकार एवं श्रिधिकारों की दृष्टि से भी समान नहीं होते थे। जनसंख्या, उपजाऊ-भूमि अथवा कुछ सीमा तक राजनीतिक कारणों के आधार पर ये भेद होते थे। समयानुसार नये प्रदेशों का राज्य में विलीनीकरण, सीमा प्रदेशों की महता अथवा किसी भाग-विशेष के ख्रीद्योगीकरण आहि से महत्व बढ़ जाया करता था । उदाहरण के तौर पर महाराष्ट्र के करहाटक जिले में सन्७६= ई० में चार हजार प्रामधे, किन्तु सन् १०५४ ई० में दस हजार प्राम ।१ इस प्रकार राज्य की विभिन्न इकाइयों के त्राकार-प्रकार त्रादि में त्रान्तर होता रहता था। ये परिवर्तन समय तथा स्थिति के अनुसार होते ही रहते थे। इन प्रादेशिक भागों को साधारणस्या "विषय" अथवा "राष्ट्र" कहते थे । प्राचीन मौर्य साम्राज्य में प्रशासनीय संगठन इतना सुन्दर श्रीर संगठित था कि उसे किसी भी वर्तमान-उन्नत राज्य के राजकीय संगठन की तुलना में रखा जा सकता हैं। उस समय भी साम्राज्य प्रान्तों में, प्रत्येक प्रान्त डिवीजनों में, प्रत्येक डिवीजन जिलों (विषय) एवं उपजिलों में विभाजित किया जाता था। उपजिलों के लिए "पाटक", "पैठ" त्रथया 'भुक्ति' त्रादि शब्दों का प्रयोग हुन्ना है। उपिक्तों का विभाजन "ग्रामसमृहीं" में किया जाता था और प्रत्येक समृह में दस से लेकर तीस अथवा चालीस ग्राम तक होने ये आधुनिक भारत की तहसीलों की भांति थे और इन समृहों में प्रत्येक ग्राम, अपना स्वायत्त प्रशासन स्थापित करता था । ग्राम प्रशासन अथवा स्थानीय स्वायत्त शासन का अध्ययन हम पूर्ण रूप से आगे के अध्याय में करेंगे।

प्रशासकीय संगठन के सम्बन्ध में प्राचीन ग्रन्थों एवं विभिन्न लेखों से यह सिद्ध है कि तत्कालीन प्रादेशिक एवं प्रशासकीय भागों के नाम अलग-अलग होते ये। उदाहरणार्थ, मध्य प्रदेश एवं दिल्ला भारत में ''भुक्ति'' का अर्थ उस प्रादेशिक भाग से माना नाता था जो वर्तमान तहसील या इसी प्रकार के लेख के समान होता था। परन्तु उत्तर भारत में इसी

[?] Dr. Altekar-State and Government in Ancint India-Page 201.

शब्द का अर्थ इतने बड़े भाग से होता था जो आजकल के किसी भी डिवीजन के समान हो। इसी प्रकार दिल्ला में राष्ट्रक्टों के अधीन "प्रतिष्ठान मुक्ति" के अन्तर्गत बारह ग्राम तथा "कोप्परक मुक्ति" के अन्तर्गत पचास गाँव थे। जब कि गुप्तकाल में "पुन्दरावर्धन मुक्ति" में तीन जिले और 'मगध मुक्ति" में दो जिले थे। १ इसी प्रकार मुक्ति में दो, तीन या अनेक जिलों का सम्मिलित होना सिद्ध होता है। कभी कभी "मुक्ति" और 'विषय" अर्थात डिवीजन और जिला एक ही अर्थ में प्रयुक्त हुआ करते थे। इसलिए इनके नाम, जेत्र या भागविशेष का अर्थ निश्चित कर देना सम्भव नहीं है। परन्तु यह स्पष्ट है कि राज्य का प्रशासनीय संगठन व्यवस्थित था और वे भाग इस प्रकार थे—राज्य, प्रांत, डिवीजन, जिला, उपजिला, तहसील एवं ग्राम। राज्य का प्रशासन मंत्रिपरिषद् की सहायता से राजा द्वारा होता था। इसका अध्ययन हम कर चुके हैं। अब कमशः प्रांत, डिवीजन एवं जिला आदि के प्रशासन संगठन पर विचार करेंगे।

प्रांतीय प्रशासन — साधारणतया प्रांत उन्हीं राज्यों में होते थे जो चेंत्रफल, जन-संख्या तथा अन्य दृष्टियों से विशाल होते थे। जिन राज्यों का स्वयं हो पांत येसा आकार-प्रकार होता था वहां प्रांतीय संगठन की आवश्यकता ही नहीं थी अन्य संगठन अवश्य होते थे। उदाहरणार्थ, मौर्यकाल में साम्राज्य अनेक प्रांतों में विभाजित था। इनमें से कुळ तो अभी तक प्रसिद्ध हैं। उस समय उत्तरापथ की राजधानी तक्षिता, अवन्ति राष्ट्र की राजधानी उप्जयिनी, दिल्लिणापथ की राजधानी सुवर्णिगरी, किलिंग की राजधानी तोशाली, श्रीर प्राच्य की राजधानी पाटिलिपुत्र—इस प्रकार ये पांच प्रमुख प्रांत तो थे ही। डॉ॰ अव्हेकर की तो यह भी है कि संभव है उत्तरापथ और दिल्लिणापथ में हो अनेक प्रांतों का सम्मिनित होना सम्भव मान्यता है। श्रु गकाल में मालवा एक प्रांत की ही भाँति का प्रदेश था और ऐसी सारी प्रतिष्ठा मालवा को प्राप्त थी किनिष्क के राज्यकाल में बनारस, मथुरा और उज्जयिनी के 'महाज्ञन'' और उनका सम्मान प्रांत के राज्यपाल के समान था। गुष्तकाल में भी मालवा, गुजरात और काठियावाड़ का शासन एक प्रकार से प्रांतीय प्रशासन ही था। चील राजाओं के समय में राज्य में दो माग थे—एक 'मण्डल'' और दूसरा 'नाह"। इनमें क्रमशः दो—तीन जिले और दो—तीन तहसील सम्मिलित थीं। ये संगठन उन छोटे राज्यों में होता था जिनका विमा-जन सीधा जिला व तहसील में हो जाता था।

प्रांतीय प्रशासन के अध्यक्त सामान्य रूप से बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति और अधिकांश शाही-परिवार के सदस्य ही होते थे। मौर्यकाल का संगठन इस विषय में आदश है। विन्दु-सार, अशोक और कुणाल राज्यपाल के पद पर कार्य कर चुके थे। शुंगराज्य में भी युवराज अपिनिमत्र मालवा का गवर्नर था और भी ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनमें इस प्रांतीय पद्धित के प्रमाण मिलते हैं और जहां के अधिष्ठाता गवर्नर या राज्यपाल होते थे। यदि युवराज या संबंधी अधिक नहीं होते थे तो इन स्थानों पर विश्वासपात्र और अनुभवी कर्म चारियों को नियुक्त किया जाता था—साधारणतया थे लोग सैनिक अधिकारी भी होते थे। इन

² Dr. Altekar-State and Government in Ancient India-Page 202.

पदाधिकारियों के अधिकार बहुत विस्तृत और व्यापक होते थे । आंतरीय शांति एवं सुरत्ता का पूर्ण उत्तरदायित्व इन्हीं को वहन करना होता था। बाहरी शतुत्रों से सुरचा का भार भी इन्हीं पर होता था। स्रतः उच्च कोटि के शासन के लिए में कौशल एवं नीतिज्ञता स्रपेचित थी। प्रांत के ब्राधार पर प्रत्येक स्थान पर न्यायालय ब्रीर कार्यकारिणियाँ, संगठित होती थीं; परन्तु नीति-संचालन केन्द्र से ही होता था। वर्त्तमान भारत का संगठन कुछ कुछ उसी प्रकार का लगता है। ग्राज भी भारत वर्ष प्रांतों में जिन्हें नए संविधान में 'राज्य' की संज्ञा दी गई है) संगठित है स्त्रौर प्रत्येक स्थान पर (मंत्रिमएडल) कार्यकारिखी, न्यायपालिका, (उच्च न्यायालय), तथा राज्यपाल हैं। उस समय प्रांतों में इसी प्रकार के संगठन के लिए डॉ॰ अल्टेकर का विचार है कि वायसराय या राज्यपाल शाही परिवारों से संबंधित होते थे, इसलिए मन्त्री त्रादि रखे जाते थे। जिनके परामर्श से वे शासन-संचालित करते थे। परंतु नीति सदैव केंद्र के द्वारा नियंत्रित होती थी। १ भारत की वर्तमान स्थिति ग्रीर संगठन देखने से यह साम्य त्रिना कोई विशेष अर्थ लगाए समम में आ जाता है कि राज्यपाल और कार्यकारिस्त्री का क्या ग्रास्तित्व था। इतिहास के ग्राचार पर तच्शिला की जनता के विद्रोह का वर्णन यह उत्सुकता पैदा करता है कि ऐना कैसे हुन्ना १ परन्तु वर्तमान समय में जुलाई सन् ४८ तक केरल के शासन के प्रति जनता का खुला विद्रोह और तदुपरान्त केंद्र द्वारा व्यवस्था स्थापन, इस प्रश्न का भी सुन्दर समाधान कर देता है। श्रतः प्रांतीय शासन के श्रध्यच राज्यपाल होते थे श्रीर उनकी सहायता के लिए कार्यकारिणी का निर्माण होता था, यह सिद्ध है। ये राज्यपाल केंद्र से ग्राज्ञा ग्रीर ग्रादेश प्राप्त करते थे। केंद्र से ये ग्राज्ञाएँ कभी लिखित और कभी संदेशवाहक के साथ मौखिक रूप में ही (जो अधिक महत्व की न हों, केवल प्रक्रिया संबंधी हों) प्रेषित की जाती थीं । त्रावागमन एवं संचार की कठिनाइयाँ इन्हीं स्थानीय राज्यपालों को पूर्ण क्रिविकारी बनाने में सहायता देती थीं। प्राचीन काल में इन प्रांतों में सुरचा स्थापना की दृष्टि से सेना भी रक्ली जाती थी जो कभी त्रावर्यकतानुसार साम्राज्य की सीमादृद्धि के लिए, सुरत्वा के लिए अथवा साम्राज्य के दूसरे भागों की रत्वा के लिए भी उपयोग में त्राती थी। कुशन सम्राट ने, उत्तर राजपूताने में योधिय जाति के विद्रोह को शांत करने के लिए दक्षिण के राज्यपाल कद्रदमन की ग्रामंत्रित किया था।र

राज्यपाल के श्रन्य श्रिषकार भी व्यापक थे। श्रपने प्रदेश के शासन की हर प्रकार सफल बनाना उनका सुख्य कार्य था। श्रतः न्याय, राजस्व तथा श्राचीनस्थ प्रशासकीय भागों में केंद्र की नीति के श्रनुसार शासन चलाना तथा व्यवस्था कायम रखना भी प्रांतीय शासन के कार्य थे। श्रिषीनस्थ भागों के उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति, स्थानान्तरण तथा नये विभाग स्थापित करना, योजना बनाना श्रादि जन-हित के कार्य हसी स्तर पर किये जाते थे। डॉ॰ श्रव्हेकर हन बातों के संबंध में विश्वस्त नहीं है और यह कुछ सीमा तक सच भी है कि जब तक स्वस्य प्रमाण उपलब्ध नहीं हों, निश्चित रूप से कुछ कह सकना साहस ही कहा जा नकता

[?] Dr. Altekar-State & Government in Ancient India-Page 201.

२ जपरोक्त-Page 205.

है। परन्तु कुमारगुष्त प्रथम द्वारा पुन्दरावर्धन के आयुक्त (Divisional Commissioner) की नियुक्ति एवं तदुपरान्त आयुक्त द्वारा उसी के आदेशानुसार कार्य करते रहने का प्रमाण इतिहास में प्रसिद्ध है। १ शासन व्यवस्था एवं राजस्व संग्रह आतिरिक्त उस प्रदेश के नये स्रोतों (Sources) का विकास, कृषि की उन्नति के लिए नहरों का निर्माण, खानों की खुदाई, जनता से सम्पर्क स्थापित करना उनमें आत्मविश्वास तथा राज्य के प्रति भिनत उत्पन्न करना, केंद्र की आजाओं का पालन तथा प्रांतों की स्चना केंद्र को मेजना आदि अनेक कार्य किये जाते थे। वास्तव में केंद्र के सभी कार्य इन प्रांतीय संगठनीं द्वारा सम्पादित होते थे और जो कार्य सारे राज्य के लिए महत्व के होते थे, उनका दायित्व केंद्र वहन करता था। राजस्व-संग्रह के लिए भी प्रांत ही अधिक उत्तरदायी थे। अपना आवश्यक माग, राज्य के कर्मचारियों का वेतन, राजकीय व्यय आदि के बाद जो अवशेष रहता था, वह केंद्र में मेज दिया जाता था। राजस्थान की कुछ सुन्यवस्थित प्राचीन रियासतों में में भी सन् १६४७ तक यही प्रणाली प्रचलित थी।

इस प्रकार प्राचीन काल का प्रांतीय प्रशासन पूर्ण विकसित, व्यवस्थित और बीच का महत्वपूर्ण संगठन था, जो केंद्र और स्थानीय संगठनों के बीच संबंध रखता था। भारत के वर्तामान संगठन से उस समय के प्रांतीय संगठन की तुलना बड़ी सरलता से की जा सकती है।

प्रादेशिक प्रशासन (Divisional Administration)—प्रांतो का विभाजन प्रशासन की दृष्टि से प्रदेशों (Divisions) में होता था। प्रत्येक प्रदेश में लगभग तीन या चार जिले सम्मिलित होते थे। इन प्रदेशों की संज्ञा भिन्न भिन्न समय में भिन्न-भिन्न प्रचलित रही है। गुप्तकाल एवं प्रतिहारयुगा में इन्हें "भुक्ति" कहते थे। राष्ट्र-कृटों के समय में 'राष्ट्र' तथा चौल स्त्रीर चालुक्य राजास्त्रों के समय में इसे "मण्डल" कहा जाता था। कभी प्रदेश के लिए 'देश' शब्द का प्रयोग भी होता था। प्रत्येक प्रदेश का सर्वोच्च अधिकारी "प्रादेशिक" कहा जाता था। मौर्यकाल में ऐसे प्रदेशों के अधिकारियों को "राजुक" भी कहा जाता था। उस समय तो शासन की व्यवस्था भी बहुत सुन्दर थी। अशोक ने तो अपना शासन पूर्ण विकेन्द्रीकरण की नीति के अनुसार बना दिया था। अतः ये प्रादेशिक अधिकारी दीवानी, फीजदारी, राजस्व आदि अधिकारी का प्रयोग करते थे । केवल केन्द्र की नीति का अनुसर्ग करते हुए इन अधिकारों का प्रयोग किया जाता था। श्रतः प्रदेश के चेत्र में इन्हें पूर्ण श्रधिकार प्राप्त थे। परन्तु जैसा समय-समय पर परिवर्तन होता रहता था, इन संगठनों की शक्तियाँ सदैव एक सी रही हों-यह कहना कठिन है। ऐसे भी उदाहरण है, जब कि इन्हीं अधिकारियों के लिए शासन की प्रत्येक महत्वपूर्ण बात के लिए केंद्र की स्वीकृति अनिवार्य होती थी। अमोधवर्ष के राज्यपाल, गाँकेय को, एक ग्राम जैन-मन्दिर के लिए अर्पण करने के लिए, साम्राजीय स्वीकृति लेनी पड़ी थी, यद्यपि वह सम्राट का बहुत विश्वस्त व्यक्ति था। र प्रसंग सभी तरह के हैं, परन्तु भारतवर्ष में विकेन्द्रीकरण

R Dr. Altekar-State & Government in Ancient Iudia-Page 205.

२ उपरोक्त-Page 206.

की नीति का पालन सदा से ही होता रहा है, अतः यह समभाना कि प्रादेशिक अधिकारियों के अधिकार बहुत थे, अप्रासंगिक एवं असंगत है।

पादेशिक ब्रायुक्त ब्रथवा श्रधिकारी अपने ब्रधीनस्य द्वेत्रों एवं कर्मचारियों पर पूर्ण नियंत्रण रखते ये ग्रीर ग्रपने ग्रधिकारों का पूरा प्रयोग कर सकते थे। यदि ग्रधीनस्थ कर्म-चारी कभी भी कर्तव्याधात या गट्दारी (Disloyalty) करते अथवा अमित्रता प्रकट करते तो बन्दी बना लिये जाते थे और उचित कार्यवाही के लिये उन्हें आगे भेज दिया जाता था। श्रपराध के श्रनुसार स्थानीय रूप से भी कार्यवाही की जाती थी। प्रादेशिक स्तर पर कुछ सेना का संगठन भी रखा जाता या जो त्रावश्यकतानुसार स्थानीय सुरज्ञा, त्रधीनस्थ कर्मच।रियों पर नियंत्रण, एवं विभिन्न सामन्तीं पर नियंत्रण रखने के लिये उपयोग में लिया जाता था श्रीर सम्राट द्वारा किसी बड़े श्रायोजन के समय केन्द्र में भी भेज दिया जाता था। वतमान समय की माँति यह प्रादेशिक श्रायुक्त (Divisional Commissioners) राजस्व विभाग के श्रध्यच होते थे। साधारण जनता के भूमि एवं राजस्व संबंधी श्रधिकारों के पूर्ण उपभोग की च्यवस्था करने के लिए इन्हीं अधिकारियों को सम्बोधन किया जाता था। डॉ॰ अल्टेकर के मतानुसार 'राजूका' शब्द के अर्थ से यही प्रकट होता है कि जो भूमि के नाप और तोल से घनिष्ठ रूप से संबंधित होता था १ श्रीर गाँवां में समय-समय पर बन्दोबस्त (Settlement) श्रीर भूमि निर्धारण का काम इन्हीं श्रधिकारियों के निर्देशन के श्रनसार होता था। कुछ न्याय संबंधी अधिकार भी इन अधिकारियों के होते थे। अपने प्रदेश में सम्भवत: वे पुन:-पार्थना (Appeal) से अन्तिम उच्च न्यायालय होते थे। अशोक ने इसी दृष्टि से अपने राजुकान्त्रों को यह निर्देशन किया था कि वे जहां तक सम्भव हो समान दण्ड नीति का पालन करें । प्रान्तों की भाँति प्रदेशों में भी अधिकार-सीमाएँ परिवर्तनशील रही हैं। मौर्यकाल में ये त्रवश्य विस्तृत थीं। गुप्तकाल में भी लगभग वैसी ही रहीं, परन्तु उच्च सत्ताधारियों का हस्तचेप श्रावश्यकतानुसार होता रहना स्वामाविक सा लगता है। ये श्रिधकारी श्रपने श्रधी-नस्य (जिला ऋधिकारी ऋदि) कर्मचारियों की नियक्ति करते थे। इतिहास में ऐसे भी उदा-हरण हैं जत्र राज्य के प्रत्येक कर्मचारी की नियुक्ति सम्राट द्वारा ही की जाती थी। राष्ट्रकूटों के समय में जिला अधिकारी तहसीलदार आदि साधारणतया सम्राट द्वारा ही नियुक्त होते थे ।२ परन्तु फिर भी कुछ स्वतंत्र द्वेत्र प्रादेशिक श्रिधिकारियों के लिए सुरिद्धत था तथा वे केन्द्र की नीति एवं जनहित को ध्यान में रख कर शासन संचालित करते थे।

ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान समय में प्रादेशिक आयुक्तों की भाँति तत्कालीन आधिकारी भी प्रशासन में एक महत्वपूर्ण आंग थे, परन्तु थे केवल एक मध्यस्य की भाँति। वास्तविक शासन था तो इनसे भी उच अधिकारियों के हाथ में अथवा इनके अधीनस्य कमंचारियों के हाथ में । फिर भी इनका अस्तित्व, प्रशासन का विकसित रूप सिद्ध करने के लिए पर्याप्त प्रमाग है।

^{. ?} Dr. Altakar-State & Government in Ancient India-Page 207.

जिला प्रशासनः — प्रत्येक प्रदेश (Division) अनेक जिलों में विभाजित होता था तथा जिलों का प्रशासन राज्य की व्यवस्था का मूलभूत आधार होता था। प्राचीन काल में इन्हें 'विषय' कहा जाता था और प्रत्येक विषय में लगभग एक हजार से दो हजार तक ग्राम होते थे। जिलों के नाम प्राचीन काल में और भी कई तरह के रहे हैं, यह सिद्ध होता है। काठियावाड़ में "अहरणी" मध्य प्रदेश में राष्ट्र तथा आन्ध्र प्रदेश की ओर भी इस "राष्ट्र" शब्द का ही प्रयोग होता था। जब जिलों को 'विषय' कहा जाता था तो यह स्वाभाविक है कि जिला अधिकारियों को 'विषयपित'' या 'विषयाध्यक्ष' कहा जाता हो। अशोक के प्रतर्लेखों में विषयपित का नाम 'राजूका' के साथ ही उिल्लिखत है और उससे 'राजूका' की भाँति ही पर्यटन अथवा यात्रा करने की अपेन्ता की गई है। १ मनुस्मृति में वर्णित 'सहस्पित'' शब्द भी जिला अधिकारों के लिए ही प्रयुक्त हुआ प्रतीत होता है। उसमें ऐसा वर्णन है कि राजा को चाहिए कि एक ग्राम का, दस ग्राम का, बीस ग्राम का, सौ ग्राम का तथा हजार ग्राम का एक एक अधिपित नियुक्त करें 1२ तिमल प्रदेश में इसी प्रकार के एक भाग का नाम 'नाहू'' था। परन्त उसके अध्यन्न की शक्तियाँ विषयपित के समान ही थीं। ३

सम्पूर्ण जिले के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होने के कारण ये अधिकारी बहुत महत्वपूर्ण होते थे। स्थानीय नियम व्यवस्था, शांति एवं सुरत्ना, राजस्व संग्रह, विवाद निर्णय आदि अनेक कार्य करते थे। कार्य का त्तेत्र विस्तृत होने के कारण इन्हें सहायक कर्मचारियों की सहायता भी उपलब्ध थी। युक्त, आयुक्त, नियुत, व्याप्रित, लिपिक आदि अनेक नामों का प्रसंग यह प्रकट करता है कि जिला स्तर पर रहने वाले कर्मचारी इन्हीं पदों पर काम करते थे। अर्थशास्त्र में ऐसे कुछ अधिकारियों के लिए "गोप" शब्द का भी प्रयोग हुआ है। उत्तर गुप्तकाल में गुजरात में कुछ अधिकारियों को "अव" भी कहा जाता था। इस प्रकार नाम कुछ भी कहा जाता रहा हो परन्तु यह पद महत्वपूर्ण अवश्य रहा था। यह भी निश्चित सा है कि अधिकांश जिलों के लिए "विषय" शब्द ही चलन में था।

वर्ता मान जिला प्रशासन की माँति, पाचीन काल में भी "विषयपति" अर्थात् जिला-धीश' ही अपने जिले का (विषय) का स्थानीय सर्वोच्च अधिकारी होता था। शांति स्थापना और सुरत्ता की व्यवस्था रखना, उसका प्रमुख कार्य था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रत्येक जिले में सैनिक दुकड़ियाँ पुलिस आदि के संगठन रहते थे। "द्राडनायक" का वर्णन लगभग तत्कालीन सामग्री में बहुतायत से मिलता है। वह वास्तव में सेनानायक ही हो सकता है। "द्राडपाशिक" या "चोरोद्धरिणक" जो पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे, वे 'विषय-पति' के अनुशासन में रहते थे। इसके अतिरिक्त "विषयपित" का प्रभाव अपने चेत्र में

Page 208.

२ श्रामस्याधिपति कुर्याद्दराश्रामपति तथा । विरातीशं रातेशं च सहस्रपतिमेव च ॥ ११५ सप्तम अध्याय ॥ मनुस्मृति ॥

३ Dr. Altakar जपरोक्त।

४ अर्थशास्त्र—भाग २ अनु० ३६.

निहित समस्त संगठनों पर पूरा ग्राधिकार प्राप्त था। व्यापार, उद्योग, राजस्व, सहकारिता, वन, श्रादि सन स्थानीय रूप से विषयपति के अधीन ही रहते थे, अन्यया उनके केन्द्र के विभागीय अध्यक् के अंतर्गत ही रहते थे। विषयपित की न्यायिक शिक्तयों के संबंध में साधाररातः सन्देह है परन्तु मनुस्मृति के अनुसार यह सिद्ध होता है कि जिलाधीश को न्याय-शिक्तयाँ भी थीं। उसमें लिखा है कि "एक प्राम का अधिपति धीरे से ग्राम में होने वाले श्रपराध को जान ले, उसका निर्माय श्रपने से न हो सके तो दश ग्राम के श्रधिपति से कहे. दश गाम का अधिपति बीस गाम के अधिपति को समाचार दे। बीस गाम का अधिपति सब बात को सौ ग्राम के ऋधिपति से कहे और सो ग्राम का ऋधिपति ऋपने ऋाप सहस्र ग्राम के अधिपति से कहे। १ इससे किसी भी विवाद का 'सहस्रपति' अर्थात् जिलाधीश तक जाना सिद्ध है श्रीर वही ऐसे विवादों में श्रांतिम न्यायालय का काम करता था। वर्त्तमान समय में जैसे जिलाधीश का पद "Collector and District Magistrate" कहलाता है, इसी प्रकार प्राचीन काल में भी हमारे देश के जिलाधिकारी के ऋधिकार और प्रतिष्ठा इसी श्रीणी की थी। जिलाधीश को प्रशासन में सहायता पहुँचाने के लिए एक संस्था भी संगठित होती थी जिसमें अधिकांश लोकप्रिय तत्व होता या और उनका परामर्श मृल्यवान् समका जाता था। गुप्तकाल में ऐसी संस्थाएँ उपलब्ध थीं। साधारणतया जिले के प्रमुख लोग, व्यापारी, सेठ, ग्रामणी, तथा कायस्थ त्रादि इस संस्था में लिये जाते थे। परन्तु किसी एक वर्ग का एकाधिकार नहीं होता था। जातिमेद भी इस संस्था के लिए गीए था। त्राझण, श्रवाहाण भी इसमें होते थे। फरीदपूर (प्लेट) पत्र द्वारा ऐसी संस्था में त्रीस सदस्यां की विद्यमानता प्रकट होती है जिससे बाह्यण-ग्रबाह्यण सभी थे ।२ इन सदस्यों का जुनाव किस प्रकार होता था, इसका स्पष्ट प्रमाण तो अब तक उपलब्ध नहीं है किन्तु यह कहा जा सकता है कि श्रिधकांश सदस्य इस संस्था में पदेन (ex-officio) त्राते थे; जैसे व्यापारी, श्रेष्ठ, श्रादि । श्रपनी संस्थाश्रों के श्रध्यज्ञ या सचिव होने के कारण वे इस जिला परिपद् में भी समिलित हो जाते थे। "प्रथम श्रोदिन" श्रीर "प्रथम कायस्य" श्रादि नाम इसी श्राधार पर प्रचित्ति थे। जो श्रेष्ठ या कायस्य इस परिषद् का सदस्य अनता उसे ही प्रयम गुण लगाकर पुकारा जाता था । इसके अतिरिक्ष चरित्र, अनुभव, योग्यता और कुशलता के आधार पर श्रन्य नागरिकों को भी परिषद् में लिया जा सकता था। यदा-कद। इस परिषद् में के प्रतिनिधि कम श्रीर शहरों के प्रतिनिधि श्रिधिक होते थे। इन्हें "विषयमहत्तर" नाता था।३

इस प्रकार जिला-प्रशासन की सुन्दर रचना करने एवं आदर्श व्यवस्था स्थापन के लिए ही ऐसा संगठन बनाया जाता था। गुप्तकाल में यह संगठन बहुत सुन्दर और सुगठित था। जिले के कार्यालय में एक लेख संग्रहालय होता था और इसका अधिकारी "पुस्तपाल

१ मनुस्मृति—अध्याय सप्तम—श्लोक ११६-११ ७-पृष्ठ ३०२

R Dr. Altakar-State & Government in Ancient India-Page 209-210.

३ उपरोक्त-Page. 210.

कहलाता था। इस श्रिधकारी का मुख्य कार्य (लिखित) श्रिमलेख (Record) रखता था।
भूमि का च्रेत्रफल, उपजाऊ या बीहड़ भूमि का नाप, गाँवों का च्रेत्रफल, जनसंख्या द्वारा
विष्टित भूमि, नगरों की सीमाए श्रादि सब प्रकार की पूर्ण स्चना इस कार्यालय में रहती
थी। भूमि का क्रय-विक्रय नियमानुसार होता था। साधारणतया लोकप्रिय संस्था की स्वीकृति
ऐसे कार्यों के लिए प्राप्त की जाती थी श्रीर क्रय-विक्रय के श्रिमलेखों पर जिला सस्थाश्रों की
सुहर होती थी। ऐसी मुहरों के प्रमाण नालन्दा श्रादि स्थानों की खुदाई से मिल चुके हैं।
इसलिए यह स्पष्ट है कि कार्यालय स्वीकृत प्रणाली के श्रनुसार, सुनिश्चित नियमों का पालन
करता हुश्रा, कार्य करता था। इस पद्धित में श्रपवाद के लिए स्थान नहीं था। यदि स्वयं
'विषयपित' श्रथीत् जिलाधीश भी किसी भूमि को प्राप्त करना चाहता था तो उसे पूरी
श्रीपचारिकता का पालन करना होता था। विशेषाधिकार या उच्च कुलीनता श्रादि कोई
सुख्य बात कार्यालय की कार्यवाही में बाधा बन्कर नहीं श्राती थी, वरन् उनका पालन करते
हुए समाज में श्रच्छी परम्परा स्थापित करते थे। इस प्रकार जिला-शासन का गठन श्राधुनिक
जिला-शासन की श्रपेचा श्रधिक विकेन्द्रित एवं जनप्रिय था श्रीर फिर भी ऊ च-नीच के मेद

उप-जिला प्रशासन (Sub-divisional Administration)—विषय (जिला) प्रशासन एवं स्थानीय छोटी प्रशासनिक इकाई के मध्य में उप-जिला प्रशासन भी संगठित था। यह भिन्न भिन्न स्थानों एवं युगों में भिन्न भिन्न रूप में रहा है। मनु ने एक ग्राम से त्रारम्भ करके फिर दस ग्रामों की दूसरी इकाई त्रीर दस दस ग्रामों की दस इकाइयों से अर्थात १०० ग्रामों की तीसरी इकाई और फिर ऐसी दस इकाइयों की अर्थात् १००० ग्राम की चौथी इकाई का वर्णन किया है। १ इससे १०० ग्रामों वाली इकाई का ग्रर्थ हम वर्तमान समय के उप-जिलों (Sub-Divisions) के समकत्त्र संगठनों से समक सकते हैं। शासन में सुविधा की दृष्टि से मनु ने यहाँ एक सामान्य सिद्धान्त बना दिया था। अतः उप-जिला लगभग १०० ग्रामों के दोत्र तक विस्तृत होता था। महाभारत के त्र्रमुसार दशम प्रणाली का यही रूप प्रस्तावित नहीं किया गया ।२ वहाँ इस प्रकार की संस्थाओं में २० ग्राथवा ३० ग्रामी की इकाई का वर्णन है। डॉ॰ अल्टेकर ने इतिहास में ऐसे उदाहरण लिखे हैं जो इन निचारी की पृष्टि करते हैं। हैदराबाद राज्य में ब्राठवीं ब्रीर नवीं शताब्दी में दस, बारह ब्रीर तीस गाँवों तक के जिले थे। गुजरात श्रीर कर्नाटक में भी तीस गाँवों वाली इकाइयाँ थीं।३ ग्यारह्वीं तथा बारह्वीं सदी में राजस्थान में तनकृप, गुजरात में गडहडिका तथा बुन्देलखण्ड में खटन्डा बारह बारह गाँवों की इकाई के प्रधान कार्यालयों के स्थान (H. Os.) थे। इन्हें विभिन्न स्थानों में पाठक, पेठ, स्थली श्रथवा भुक्ति कहा जाता था। "खर्वटक" एवं ''द्रोण मुख'' भी उप-जिलों के ही नाम थे। इन द्वेत्रों के अधिकारी होते थे और अपने द्वेत्र

१ मनुस्मृति-सप्तम अध्याय-श्लोक ११५.

२ महामारत-XII 87.

[₹] Dr. Altekar—Rashtrakutas—Page 138.

में भृमि विवाद, साधारण न्याय तथा नियम त्र्यौर व्यवस्था सम्बन्धी सभी कार्य करते थे। इनके निकटतम उच्च अधिकारी ''विषयपति'' या जिलाधीश ही होते थे । इनकी नियुक्तियाँ त्रादि अधिकांश केन्द्र द्वारा की जाती थीं। इन अधिकारियों को प्रशासन में सहायता देने के लिए स्थानीय रूप से वंशानुगत राजस्व ऋधिकारी भी होते थे, जो स्थानीय भूमि सम्बन्धी सम्पूर्ण सूचनाप्राप्त होते थे। राजस्थान के कुछ राज्यों में इन्हें "चौधरी" तथा "कानूगो" के नाम से आज भी पुकारा जाता है। दिच्या में भी ये प्रथाएँ थीं। इन्हें कर्नाटक में "नद्गानुन्डा" तथा महाराष्ट्र में 'देशाप्रमाकूट" कहा जाता था। मराठा युग के देशपाण्डेय, सरदेशपाण्डे, देशमुख स्रादि उन्हीं से सम्बन्धित थे। स्रतः यह कहा जा सकता है कि उप-जिला स्तर पर भी व्यवस्था होती थी और राज्य के कम चारियों की सहायता एवं स्वायत्तता के हेत स्थानीय प्रतिनिधि भी उनके साथ सहयोग रखते ये अभिलेखों एवं अन्य आवश्यक सूचनात्रों को स्थानीय रूप से ऋत्एण एवं प्रमाणित बनाने के लिए ही वंशानुगत पद्धति के श्राधार पर स्थानीय सहायक रक्ले जाते ये। यह प्राचीन काल की शासन पद्धति की बड़ी महरवपूर्ण विशेषता थी। उप-जिला स्तर की ऋन्य समस्याऋों का समाधान भी यही संस्था करती थी: जैसे धार्मिक एवं परोपकारी संगठनो की व्यवस्था तथा साधारण विवादों के निर्णाय श्रादि श्रादि । परन्तु उप-जिला प्रशासन सदैव जिला प्रशासन के सहायक के रूप में ही कार्य करता था श्रीर इसके श्रन्तर्गत 'तालुके' श्रथवा तहसील की भाँति छोटी इकाइयाँ होती थीं। उनके सम्बन्ध में अब तक अधिक सूचना प्राप्त नहीं हो पाई। परन्तु इतने विशद संगठन में एक स्थान की कड़ी का अनुपरिथत रहना असंगत लगता है अत: भावी शोध इसी अभाव-पूर्ति करने में सम्भव होगी, ऐसी आशा है। प्राप्त वर्ण न प्राचीन प्रशासन को एक पूर्ण विकसित राज्य श्रीर जागरूक जनता का संगठन सिद्ध करने में पूर्ण सफल है।

प्रश्न

- 1. Give a brief account of the administrative system of the Mauryas.
- 2. "The Arthashastra constitutes the most complete statement of Hindu idias on Government". Discuss.
- 3. Give n brief account of the salient features of the Mauryan system of administration.

तेरहवाँ ग्रध्याय

प्रशासन (३) स्थानीय सरकार

(Administration (III) Local Self Government)

प्रस्तावना - पहले अध्याय में राजकीय प्रशासन का अध्ययन कर लेने के बाद यह स्वाभाविक है कि हम स्थानीय स्वशासन की ऋोर ऋग्रसर हों। प्राचीन काल में प्रजातंत्रात्मक परम्पराएँ स्राद्योपान्त सर्वत्र व्याप्त थीं । इसलिए यह तो निश्चित है कि प्राचीन भारतवर्ष में स्थानीय संस्थाएँ संगठित थीं ग्रौर उन्हीं संस्थाग्रों द्वारा स्थानीय जीवन व्यवस्थित एवं संचालित होता था। उस समय भारतवर्ष ग्राम-प्रधान देश था, परन्तु श्रनेक राजधानियाँ तथा बड़े नगर भी पर्याप्त मात्रा में थे, यह इतिहास से सिद्ध है; परन्तु फिर भी वर्तमान समय के विशाल नगरों की भाँति उस समय इतनी बड़ी जनसंख्या के नगर नहीं से थे। स्थानीय स्वशासन की दृष्टि से उस समय भी ग्राम, नगर एवं राजधानियों के लिये पूर्ण रूप से स्वतन्त्र संगठन स्थापित किये जाते थे। चाहे राजतंत्र रहा हो अथवा प्रजातन्त्र, किन्तु नगरों आदि की स्वायत्त संस्थाएँ सदैव जीवित रहीं। प्राचीन काल के पश्चात् मध्यकाल, मुस्लिम काल तथा श्रांग्ल युग तक भी ये स्थानीय संस्थाएँ किसी न किसी रूप में चलती श्राई है। इन्हीं संस्थाओं के कारण ऋंग्रें जों की यह धारणा बनी थी कि भारतवर्ष का प्रत्येक ग्राम "लघु गणराज्य'' (Little Republics) हैं। वास्तव में तत्कालीन स्वायत्त संस्थाएँ नगरीं को पूर्ण रूप से आदमनिर्भर एवं स्वशासित बनाये रखती थीं। उस समय भी राजधानियों का स्थानीय शासन प्रवन्ध त्राज के बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता त्रादि विशाल नगरों की भाँति विशेष ढंग से होता था तथा साधारण नगरों एव ग्रामों की स्वायत्त प्रणाली त्राजकल की नगरपालिकात्रों तथा ग्राम पंचायतों की भाँति होती थी। इन सब प्रकार की स्वायत संस्थात्रों का ग्रध्ययन भली प्रकार करने के लिए प्रत्येक का विस्तृत वर्णन ग्रावश्यक है। इसलिए अगली पंक्तियों में राजधानी, नगर एवं ग्राम स्वायत्त संस्थाय्रों पर ही क्रमशः विचार किया जाता है।

प्रमुख नगर एवं राजधानियों का स्वायत्त प्रशासनः—वैदिक काल में बहुत बड़े बड़े नगरों की परम्परा रही हो, ऐसा प्रतीत नहीं होता । उस समय की सम्यता अधिकांश प्रामीण वातावरण से आच्छादित थी। इसलिए बड़े नगरों का वर्णन अल्प मात्रा में और यदा-कदा मिलता है। उत्तर वैदिक काल में भी नगरों का वर्णन सामाजिक जीवन की मुख्य विशेषता के रूप में मिलता है वह भी अधिक नहीं। किन्तु उपलब्ध प्रसंग यही सिद्ध करते

हैं कि बड़े बड़े नगरों का भी ऋस्तित्व था श्रौर समाज तथा राज्य में उनका महत्वपूर्ण स्थान था। सिकन्दर महान् के श्राक्रमण के समय पंजात्र में ऐसे विशाल नगरों का त्राहुल्य था। इन नगरों में स्वायत्त प्रशासन था ऋौर ऋपनी परिषदों द्वारा स्थानीय व्यवस्था की जाती थी। सम्भवतः इन संस्थाय्रों का संगठन उन चुनावों के त्राधार पर होता हो जो नगर की कई भागों में विभाजित कर श्रानुपातिक-प्रतिनिधित्व-प्रणाली के श्रनुसार सम्पन्न होते थे। इन परिषदों के सदस्य अनुभव और अवस्था का ध्यान रखते हुए निर्वाचित होते थे। गुप्तकाल के पश्चात् से हमें इस प्रकार के नगरों की व्यवस्था का ग्राच्छा वर्णन मिलता है। उस समय नगरों की सिमिति अथवा परिषद् की अव्यक्तता के लिए केन्द्रीय सरकार की ओर से अधि-कारी नियुक्त किया जाता था, जिसे "पुरपाल" कहते थे। ऋ गे जों के समय में जैसा हिन्दु-स्तान में ज़िलों की स्वायत्त संस्थाओं का ऋध्यत्व जिलाधीश होता था। इसी प्रकार शासन को दृढ़ बनाने एवं नागरिकों के पथ-प्रदर्शन के लिए राज्य के कर्मचारियों को पदेन कार्य करना होता था। इतना अवश्य है कि अंग्रेजों के समय में राजकीय अधिकारियों की भावना 'जन-सेवा' न होकर 'राज्य-सेवा' ऋधिक थी । प्राचीन काल में इस व्यवस्था का उद्देश्य सब प्रकार से लोकहित था। त्र्याज जैसा राजस्थान सरकार ने निश्चय किया है तथा कुछ सीमा तक उत्तर प्रदेश तथा श्रांघ्र प्रदेश भी कर रहे हैं। लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण (Democratic-Decentralization) की योजना में स्थानीय निकायों के साथ राज्य के कर्मचारियों का वर्तमान विकेन्द्रीकरण का चरण हमारी प्राचीन परम्पराश्रों के पूर्ण श्रनुरूप है। यदि ऐसे नगर चाहरदीवारी से बन्द होते थे तो वहाँ एक ''कोष्टपाल'' भी होता था। कई बार कोष्ट्रपाल और पुरपाल दोनों पद एक ही व्यक्ति के द्वारा संचालित होते थे। कभी कोष्ट्रपाल के अधीन अनेक नायक होते थे, जिन्हें 'दण्डनायक' कहा जाता था। पुरपाल और कोहपाल सुयोग्य व्यक्तियों में से चुने जाते थे। इसलिए यह सम्भव है कि उस समय मस्तिष्क श्रीर शरीर के मुन्दर से गुणों का समन्वय ब्रादर्श माना जाता हो।

इन नगरों की व्यवस्था के लिए जो सिमिति या परिपट् होती थी, वही नगर का शासन संचालन करती थी। इस सिमिति को कहीं "गोप्टी", "पंचकुल", "चौकदीका" व्यादि शब्दों से पुकारा जाता था। इस संस्था में नगर के सब प्रमुख भागों के प्रतिनिधि होते थे। इस सम्बन्ध में नगरों को कई भागों में बाँटा जाता था। अभी जी में इन्हें "वार्ड म्" कहते हैं, राजस्थान में कुछ मागों में (जैसे उद्यपुर श्रादि) इन्हें "वाड़ा" तथा कोटा श्रादि स्थानों पर "पाड़ा" कहते हैं। कुछ अन्य स्थानों पर "टोड़ी" (श्रालग बसा हुआ मोहल्ला), "पुरा" श्रादि नामों से भी शहर के भागों को पुकारा जाता था श्रीर प्रत्येक मोहल्ले से कम से कम एक प्रतिनिधि इन संस्थाओं में अवश्य लिया जाता था। डाँ० अल्टेकर के मतानुसार राजस्थान के "व्यवसेप" गाँव में आट भाग थे जिन्हें "वाड़ा" कहते थे श्रीर प्रत्येक वाड़ा से दी प्रतिनिधि लिये जाते थे। १ इन प्रतिनिधियों का चुनाव अनुभव, अवस्था, चरित्र एवं

१ - टॉ॰ अल्टेकर-State and Government in Ancient India-Page-215

लोकप्रियता के आधार पर होता था। किन्तु वर्तमान समय की भाँति चुनाव लड़ना नहीं पड़ता था। लोकमत के अनुसार सर्वसम्मित से बिना संघर्ष सुयोग्य व्यक्तियों का नाम निर्धारित कर लिया जाता था और वे पूर्ण योग्यता के साथ जनहित में संलग्न होते थे। सम्पूर्ण काम के लिए छोटी छोटी समितियों का निर्माण होता था और बारी बारी ते प्रत्येक सदस्य को हर सिमिति में कार्य करने का अवसर मिलता था। बारी बारी से नम्बर करने के कारण ही उन सदस्यों को 'वारिक'' शब्द से सम्बोधित किया गया है। १ अर्थात् वे लोग जो बारी बारी से काम करते हैं। इस स्थान पर हमें वर्तमान समय में कियाशील स्विट्जरलेंड की संघीय परिषद् का स्मरण हो आता है। जहाँ अभी प्रतिवर्ष सदस्य अध्यन्त और उपाध्यन्त के पद पर परिवर्तित होते रहने हैं। प्राचीन काल में भारतवर्ष में बड़े नगरों की व्यवस्था के लिए यही पद्धित अपनाई हुई थी। इन सिमितियों में सदस्यों की संख्या साधारणतया तीन होती थी। यह संख्या कम-ज्यादा भी हो सकती थी। दो (सियादोनी), तीन (खालियर), तथा पांच (राजपूताना) तक सदस्य होने के प्रमाण उपलब्ध हैं। इन सिमितियों के मुख्य मुख्य कार्य निम्नलिखित होते थे:—

परिषद् के निर्णयों को कार्यान्वित करना, त्रावश्यकतानुसार कर, शुल्क श्रादि संकलन, जनहित के लिए नये कार्य त्रारम्भ करना, स्वास्थ्य श्रादि लोकहित के कार्यों की व्यवस्था, न्यासकोष (Trust Funds) का प्रवन्ध, त्रावश्यक धन तथा ऋण चुकाने की व्यवस्था करना त्रादि प्रमुख कार्य थे।

इस संस्था के कार्यों को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए स्थायी कार्यालय एवं कर्मचारी भी होते थे। कार्यालय को 'स्थान' कहते थे, जहाँ से सारा कार्य किया जाता था। कार्यालय का मुख्य अधिकारी 'किंकि' (Secretary) कहलाता था जो स्थायी कर्मचारी होता था। कार्यालय के पत्र-व्यवहार तथा लेखों आदि की सुरत्ता का उत्तरदायित्व इसी अधिकारी का होता था। इसकी सहायता के लिए अनेक छोटी अंगी के कर्मचारी होते थे। नगर के विभिन्न प्रकार के कर, शुल्क, चुंगी, मापा (त्रिक्तो कर) यात्रा कर आदि के संग्रह के लिए कई अधिकारी नियुक्त होते थे और यह इस संस्था की आप का मुख्य साधन होता था। इस प्रकार ये संस्थाएँ अपने सब काम स्वीकृत नियमानुसार विधिवत पद्धित से करती हुई लोकप्रिय एवं सफल रहती थी। ये संस्थाएँ उत्तर भारत में बहुत थीं। महाराब्द्र में इन संस्थाओं को ''निगम सभा'' कहते थे। वहाँ यह सभा सम्पत्ति के आवर्तन परिवर्तन का पंजीकरण (Registration) भी करती थी। उपर्युक्त वर्णन यह सिद्ध करता है कि प्राचीन भारतवर्ण में नगरों की व्यवस्था राज्य कर्मचारियों के सहयोग तथा स्थायो नागरिकों के हारा संचालित होती थी और संभवत: संगठन, शिक्त, अधिकार और कर्त व्य आदि की दिल्द से वस्तुत: उत्तित आर्थ में स्वायत्त संस्थाएँ थीं।

राजधानियों का स्वायत्त प्रशासन: —वर्तमान समय में भारतवर्ष के विभिन्न विशाल नगरों की स्थानीय व्यवस्था निगमों (Corporations) द्वारा ही की जाती है; क्यों कि

१ वर्तमान वर्षवारिक जोगनंह । Bombay. G. (As quoted by Dr. Altakar).

नगरपालिका त्रादि दूसरी संस्थाएँ समुचित च्यवस्था करने में समर्थ नहीं हो पातीं। यह श्रनुभव प्राचीन भारतवर्ष में भी किया जा चुका था। उस समय इतने बड़े-बड़े नगर श्रधिक तो नहीं थे परन्तु राजधानियाँ अवश्य ही बड़े नगरों के समान विस्तृत एवं विशाल थीं इसके श्रितिरिक्त एक बार राजधानी रह चुकने के बाद उस नगर की विशालता में अन्तर नहीं आता था। इसलिए ऐसे नगरों की शासन व्यवस्था विशेष प्रकार से की जाती थी। ईसा से पूर्व तृतीय एवं चतुर्थ शतान्दी में पाटलिएत्र की स्वायत प्रणाली ग्रादर्श मानी जा सकती है। राजधानी होने के कारण यहाँ सब प्रकार के लोग, विभिन्न देशों के दत, प्रतिनिधि एवं नाग-रिक भी रहते थे। परन्त फिर भी स्वायत्त शासन के साधारण सिद्धान्त स्थानीय सरकारों के श्रधीन ही थे। पाटलिपुत्र की व्यवस्था तीस सदस्यों की परिषद् द्वारा की जाती थी श्रीर प्रशासन की सुविधा के लिए इस परिषट् के तत्वावधान में पाँच उप-समितियाँ काम करती थीं। प्रथम समिति का मुख्य कार्य था विदेशियों की देख-रेख, उनकी ग्रावश्यकताएँ पूरी करना तथा उनकी क्रियास्त्रों पर ध्यान रखना । बड़ी राजधानियां तथा व्यावसायिक नगरों में जहां विदेशी ऋधिकांश रहते थे यह समिति महत्वपूर्ण होती थी। द्वितीय समिति का मुख्य काम था ऋंकशास्त्र के ऋनुसार जन्म ऋौर मरण का लेखा रखना तथा इनते संबंधित विशेष सांख्यिकी सूचना प्रस्तुत करना श्रीर मरण के विभिन्न रोग श्रथवा कारणों पर प्रकाश डालना । यह सिमिति बड़ी जनसंख्या के नगरों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती थी। मौर्यकाल के पश्चात् इस प्रकार की समिति का उल्लेख नहीं सा मिलता है। यह कहा जा सकता है कि इस समिति ने बाद में कोई स्त्रीर रूप घारण कर लिया हो स्रथवा किसी स्त्रधिक महत्वरूर्ण सिमिति के साथ एकरूप बन गई हो।

तृतीय सिमित का कार्य मुख्य रूप से विभिन्न वस्तुग्रों के उत्पादन पर ध्यान देना था। कितना माल ग्राता है, कितनी वस्तुण् उत्पन्न होती हैं ग्रादि उत्पादन संगंधी कार्य यह सिमिति करती थी। साधारणतया ग्री होगिक नगर एवं दूसरे प्रगतिशील स्थानों पर यह सिमिति ग्रव-श्यमेव रहती थी। चतुर्थ सिमिति का कार्य था श्रमिकों के लिए उचित श्रम ग्रीर उसकी उचित मात्रा निर्धारित करना, बाजार की गतिविधि को ध्यानपूर्वक देलकर उचित निर्देश करना तथा बाजार में शुद्ध एवं ग्रमिश्रित सामग्री की व्यवस्था करना ग्रादि। पाँचवीं सिमिति का कार्य व्यापारियों तथा ग्रन्य संग्रंधित व्यक्तियों से कर एवं शुक्क एकत्र करना, उनका नियमानुसार लेखा रखना तथा शेष कर ग्रादि के प्राप्त करने की कार्यवाही करना ग्रादि। इसके ग्राति रिक्त एक सिमिति ग्रीर होती थी जिसके मुख्य काम थे लोक-निर्माण के कार्य; यथा-तालाव बनवाना, नहरें खुदवाना, उद्यान लगाना तथा जनता के मनोरंजन के साधन उपलब्ध करना ग्रादि। इसे लोक-निर्माण सिमिति (Public Works Committee) कहते थे। इसके ग्रातिशक्त ग्रर्थशास्त्र के ग्रनुसार जन-हित के कार्य करने के लिए नागरिकों की ग्रन्य भी कई सिमितियाँ ग्रीर छोटी संस्थाएँ होती थी। पाटलियुत्र की स्थिति ग्रन्य राजधानियों की ग्रपेन्न विशेष प्रकार की थी क्योंकि बहुत वड़ी राजधानी होने के कारण स्थानीय स्थायत्त में राज्य की ग्रीर से बहुत सहयोग मिलता था। ग्रार्थशास्त्र के ग्रनुसार को विभिन्न ग्राधिकारी

नगरमण्डल में होते थे; जैसे—बाजार निरीक्तक, कर संग्रहकर्ती, तोल-नाप निरीक्तक श्रादि वे सब पाटिलपुत्र में राज्य के ही विशेषज्ञ कर्मचारी होते थे। श्रेन्य नगरीं में ये सब पद स्वायत्त संस्था के श्राधीन होते थे श्रीर उनकी श्राज्ञाश्रों का श्रेक्रशः पीलने करते थे।

राजधानियों तथा बड़े नगरों की स्थानीय व्यवस्था में राज्य का सदैव सहयोग रहता था। विशेष तौर पर आर्थिक सहायता के लिए इन निर्मम आदि संस्थाओं को राज्य पर ही निर्मर करना पहला था। इसके आतिरिक्त सामाजिक, स्वास्थ्य संबंधी तथा दूसरे सेत्रों में भी ये संस्थाएँ राज्य का सहयोग लेती हुई कार्य करती थीं।

उपर्युक्त वर्णन प्राचीन काल के निगम आदि मण्डलों का पूरा चित्र उपस्थित करने में असमर्थ है विशेषतः इन संस्थाओं का संगठन, उनके अस्तित्व का युग, सदस्यों का निर्वाचन या मनोनयन, आय के मुख्य साधन तथा व्यय के मुख्य स्रोत आदि के संबंध में कोई स्पष्ट प्रमाण अभी तक उपलब्ध नहीं है, किन्तु प्राप्त प्रसंगों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्राचीन काल के नगरों की स्वायत्त व्यवस्था बहुत उन्नत स्थिति की थी। एक प्रगतिशील समाज में तथा प्रजातंत्र के सिद्धान्तों का सम्मान करते हुए विभिन्न समितियों और उप-समितियों का वर्णन प्राचीन भारत की राजनैतिक जागृति का एक सुन्दर प्रमाण है।

मान्य प्रशासन (Village Administration:—ग्राम भारतवर्ष के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जैसे-यूनान के नगर के आधार पर नगर राज्यों का निर्माण हुआ उसी प्रकार भारतवर्ष का जीवन ग्राम से आरम्भ हीकर आज पुनः गाँव तक पहुं च कर पूर्ण होता है। उस युग में जब यातायात के साधन नहीं थे एवं औद्योगीकरण नहीं हुआ। था भारतवर्ष के ग्राम वास्तव में अपना विशिष्ट स्थान रखते थे। वेदों में गाँव का प्रसंग याता है, और उनकी समृद्धि के लिए पार्थनाओं के वर्णन भी। जातक ग्रन्थों में राज्य की समृद्धि की प्रशास करते हुए अनेक प्रगतिशील ग्रामों का उल्लेख किया गया है। जैसा हम पहले कह चुके हैं-भारतवर्ष में पशासन, सम्यता, शिन्ता तथा सामाजिक धार्मिक अदि अनेक उत्थान और पतन हुए, परन्तु भारतवर्ष का ग्रामीण जीवन अन्तुण्ण बना रहा। वास्तव में गांवों का अस्तित्व प्रशासकों के लिए जैसे अनेक समस्याओं का स्वजन करता रहा है, उसी प्रकार उनका अस्तित्व अनेक परिवर्तनों से निरपेन्न रहकर पाचीन भारतीय संस्कृति तथा परम्पराओं का संस्तृक भी बना रहा। प्राचीन काल में राज्य अथवा साम्राज्य का प्रत्येक कार्य ग्राम के अध्यन्तों के समसेलन में स्वीकृत होने पर किया जाता था। वास्तव में राज्य के सामाजिक और आर्थिक एवं राजनैतिक जीवन के केन्द्र ये ग्राम ही थे। जिसके आधार पर आज भी हमारे राज्य का समृद्ध एवं सांस्कृतिक प्रशासनीय भवन सुरन्तित है।

प्रामणी (Village Headman): —गाँवों की व्यवस्था साधारणतथा प्रामणी द्वारा की जाती थी। वेद, जातक प्रत्य तथा अर्थशास्त्र आदि में प्रामणी का प्रसंग मिलता है। विभिन्न कालों में ग्रामणी के लिए विभिन्न शब्द प्रयुक्त हुए हैं। उत्तर भारत में उसे "प्रामीक" या "प्राम्यक", दिल्ला में "मुनन्दा", महाराष्ट्र में 'ग्रामकूट", या "प्रदक्षील", कर्नाटक में

"गुबुण्डा", उत्तरप्रदेश में "मुहट्टक", या "महत्तक" करते थे ।१ राजस्थान के कुछ, राज्यों में "पटेल" शब्द का प्रयोग भी इसी अर्थ में होता है। यह पद साधारणतया वंशानुकम के सिद्धान्त पर श्राधारित होता था, किन्तु राज्य सरकार इस पद पर नये व्यक्ति की स्वीकृति का अधिकार सदैव अपने हाथ में रखती थी। इस पद के लिए किसी जाति विशेष की प्राथमिकता नहीं दी जाती थी: किन्तु साधारणतया चत्रिय लोग ऋधिक उपयुक्त माने जाते थे। कभी ऐसे भी प्रसंग मिलते हैं जब एक ही गाँव में अपनेक ग्रामणी होते थे। अनुमानत: यह कहा जा सकता है कि जब एक परिवार में ऋधिक योग्य व्यक्ति हो जाते थे तो सबको अवसर देने के लिए यह व्यवस्था की जाती होगी। ग्रामणी का पद वैदिक काल से ही महत्वपूर्ण रहा है। जातक ग्रन्थों में भी ग्रामणी को 'ग्राम-सम्राट' की तरह चित्रित किया गया है। सम्राट के राज्याभिषेक-उत्सव तथा अन्य महत्वपूर्ण अवसरों पर राज्य की विधानसभाओं में और मन्त्रि-परिषद् में ग्रामणी का स्थान बहुत महत्वपूर्ण रहता था। उसके कर्तव्य भी अनेक थे। गांव की सुरचा तथा त्रान्तिक शान्ति त्रोर व्यवस्था उनका मुख्य कार्य था। जब जब गाँव पर त्रापत्ति त्राती थी, ग्रामणी की अध्यक्तता में सारे गाँव के निवासी अपना कर्त व्य पालन करते थे ।२ दूसरा कार्य राजस्व संग्रह करना था । यह कार्य ग्राम ग्रध्यच् त्र्यपनी छोटी सो स्थानीय सुमिति के परामर्श से करता था। मामणी इस समिति का पदेन अध्यन्न होता था और आव-श्यक समस्त सूचना एवं लेखों (Records) का संरच्छक होता था। इसके अतिरिक्त गाँव के सामाजिक व आर्थिक जीवन का उचित संचालन ग्रामणी के ही निर्देशन में होता था। उसकी प्रतिष्ठा बनाने के लिए राज्य की ऋोर से कुछ सम्मान दिया जाता था। राजकीय-कुटीर उसे निवास के लिए मिलता था तथा गाँव के लोग भी उसे राज्य का प्रतिनिधि मान कर समय पर् श्रव्पांश-कर त्रादि देते थे। शुक्र-नीति के ब्रनुसार ग्रामणी ग्राम-निवासियों के लिए माता-पिता की भाँति होता था ।३ ग्रामणी राज्य श्रीर प्रजा दोनों का विश्वासपात्र होता था । राज्य की स्रोर से वह भूमि संबंधी सूचनाएँ, पत्र, परिपत्र, शेष शुल्क की स्मृति तथा उसकी प्राप्ति का प्रयत्न, ग्राम परिषद् के निर्णयों को सुरिच्चत रखना तथा राज्य की विभिन्न शाखाओं से पत्र-व्यवहार त्रादि कार्य करता था। कहीं-कहीं ग्रामणी की सहायता के लिए कोषाध्यक्त का अलग पद भी रखा जाता था। तामिल प्रदेश में इस पद की नियुक्ति ग्राम्य परिषद् द्वारा की जाती थी। ४ शुक्रनीति के अनुसार उपर्युक्त दो के साथ चार अन्य अधिकारियों का भी उल्लेख मिलता है । सहसाधिपति (Magistrate), 'मागहार' (Revenue Collector), शुल्कप्रहा (Toll-Collector) श्रीर प्रतिहार (Gate-Keeper) संभवतः बड़े गाँवों में ये अधिकारी रहते थे। हर्षचरित-सार के अनुसार आमान्त-पटलिक (एक अर्थ अधिकारी) तथा करिए (सहायक लेखक), अन्तपटल (राजकीय आय का कार्यालय), पुस्तकृत (माम की

R. Altekar-State & Government in Ancient India-Page. 220

२ यथा स्वसैन्येन सह यामाध्यकादिसैन्यं सर्वाध्यक्तस्य भवति । सांख्यतत्वकीमुदी पृष्ठ ४४.

३ शुक्र-नीतिसार, अनुच्छेद २, १५ठ ३४३.

Y Dr. Altekar--State and Government in Ancient India-Page 222.

भूमि संबंधी स्चनार्श्रों वाला अधिकारी), ग्राममहत्तर (ग्रामणी) भी गाँवों के जीवन में सिक्षय पद एवं पदाधिकारी थे। दामोदरपुर ताम्न-पत्र में ग्राम के अधिपति को ग्राममहत्तर कहा गया है। त्राण ने भी वही शब्द प्रयोग किया है। ग्रामणी ग्राम के लिए उसी प्रकार था; जैसे-माता-पिता परिवार के लिए। माता प्रेम की प्रतीक है और पिता अनुशासन का। अशोक के समय में यह भावना अधिक व्याप्त हो गई थी।

प्राम सभा (Village Assembly):—इसे ग्राम-संघ तथा ग्रामसमूह भी कहते थे। साधारणतया गाँव के समस्त गृहस्थी इस समा में सम्मिलित होते थे। इस समा के अधिवेशन के लिए सब एहस्थ प्रामवासियों को ढोल बजाकर सूचना दी जाती थी। इस सभा के सदस्यों को उत्तर प्रदेश में 'महातमा', महाराष्ट्र में 'महत्तर', कर्नाटक में महाजन', तिमल में "पैरुमकल" कहते थे। ये सब लोग गाँव के बड़े त्र्यादमी होते थे। इनकी संख्या अधिक होने के कारण बाद में कुछ प्रतिनिधियों द्वारा शासन चलाने की योजना स्वीकृत हुई श्रीर तदनुशार ग्राम पंचायत का प्रारम्भ हुन्ना। ग्राम का वास्तविक शासन इस समा द्वारा ही संचालित होता था। ग्रामणी तथा अन्य प्रतिनिधि स्वेच्छानुसार कार्य नहीं करते थे। वैदिक काल से ही गाँव में यही परम्परा थी छोर यह सभा सब प्रकार की समस्याछां का हल करती थी। खेल-कूद, विनोद, सुरत्ता, ऋादि सारी व्यवस्था इसी समा के हाथ थीं प्रामणी के अवांछनीय व्यवहार अथवा कार्य के लिए यह सभा उसे सचेत कर सकती थी। जातक ग्रन्थों में यह कथा है-एक बार ग्रामणी ने अधिक नशीले पेय एवं पशु-वध निविद्ध कर दिया था किन्तु जन सभासदों ने इसे ग्राम की स्थानीय परम्पराश्चों के निरुद्ध होने का कारण नतलाया तो यामगी ने अपनी आजाएँ रह कर दीं। अर्थशास्त्र में याम सभा का अस्तित्व स्वीकार नहीं किया गया है, परन्त ये सभाएँ बाद में अवश्य विद्यमान रही हैं। मध्य भारत में पंच-मगडली, बिहार में 'माम जनपद' त्रादि माम परिषदों के ही विभिन्न नाम ये । इन सभाश्रों के सदस्य कई स्थानों पर गाँव के केवल निर्वाचित सदस्य होते थे। इनकी अवधि एक वर्ष की होती थी श्रीर तत्काल पुनर्निर्वाचन वैध नहीं था। ये सत्र सदस्य अवैतिनिक होते थे। दुराचरण के अपराध पर अवधि-समाप्ति के पहले भी कोई सदस्य पदच्युत किया जा सकता था। ग्राम के सब व्यक्तियों को अवसर देने के लिए कहीं-कहीं यह भी नियम था कि एक त्रार निर्वाचित व्यक्ति अगले तीन वर्ष तक निर्वाचित नहीं हो सकते थे। लोककोष (Public funds) का दुरुपयोग करने के अपराध में केवल अपराधी ही नहीं उसके समस्त बन्धु-बान्धव भी सदैव के लिए निर्वाचन के अयोग्य घोषित कर दिये जाते थे। सभासद् न अधिक युवक और न अधिक वृद्ध होते थे । लगभग ३५ वर्ष से ७० वर्ष की आयु तक के लोग सभासद वन सकते ये । प्रत्याशियों के लिए निजी कुटोर एवं न्यूनतम दो एकड़ भूमि का स्वामित्व अनिवार्य या । परन्तु विद्वान एवं वेदाचार्य, स्मृतिकार तथा दार्शनिक इस सीमा से बाहर थे। साधारणतया प्रत्येक सभा का ऋपना विधान होता था। मूल रूप से विभिन्न समाऋों के विधान में विशेष अन्तर नहीं होता था केवल सदस्यां की अवस्था पैतीस या चालीस पुनर्निर्याचन की तीन, पांच या दस वर्ष बाद, उप-समितियों की संख्या व कार्य कम या अधिक आदि साधारण मेद रहते थे।

कार्य: —ये स्भाएँ स्वयं अपने विधान एवं विधियों को संशोधित करती थीं। विभिन्न समितियों का चुनाव भी अबोध बालक द्वारा नाम उठवा कर (By lot) करवाया जाता था। और ये समितियाँ ग्रामोद्यान, ग्राम-वाटिका, जलवितरण, पुष्करिणी, विवाद निर्णय आदि कार्यों में संलग्न रहती थीं। भूमि सर्वे च्ला समिति, देवालय समिति तथा शिचा समिति भी होती थीं। इन समितियों में वर्ण व्यवस्था का महत्व नहीं था। न तो प्रत्येक समिति में बाहाण का होना अनिवार्य था और न अछ्तों का होना निषद्ध।

इस प्रकार प्राप्त संस्थाओं के मुख्य कार्य कर-संग्रह, भूमि-सुधार, केन्द्र से पत्र-व्यवहार, संकट के समय साधन एकत्र करना आदि थे। कर न देने वालों की भूमि वेचन का अधिकार तथा गांव की पड़त जमीन (Waste Lands) का स्वामित्व एवं क्रय-विक्रय. पंजीकरण आदि भी इसके प्रमुख अधिकार थे। गाँव के निवामियों के परस्पर विवाद निपटाना, आव-श्यकतानुसार दण्ड निर्धारित करना तथा गंभीर अभियोगों को आगे स्थानान्तरित करना इनके अधिकार में था। दिल्लिण भारत के कुछ अभितेख यह भी सिद्ध करते हैं कि थे प्राप्त सभाएँ साहूकारों की तरह (Bank) लेन-देन का काम भी करती थीं। संकट की न्यिति में प्राप्त की सम्पत्ति को गिरवी रखकर अथवा अन्य किसी प्रकार से सहायता प्राप्त करना इसी संस्था का काम था। इसके आतिरिक्त जनहित के कई कार्य करनी थीं। उदाहरणार्थ; वन और बीहड़ जमीनों का उपयोग कर गाँव की सम्पत्ति में बुद्धि करना, सिंचाई-योग्य तालावों का निर्माण, सुधार तथा नहरों की व्यवस्था करना, पेय-जल के कुओं की व्यवस्था, ग्राप्त भवनां का निर्माण, शिल्ला की व्यवस्था तथा अर्थ व्यवस्था आदि इन संस्थाओं के मुख्य कार्य थे।

इन सभाश्रों के श्रर्थ-व्यवस्था के मुख्य साधन निम्नलिखित थे-

- (१) राज्य के संग्रहीत राजस्य का ग्राल्पांश (दस या पनद्रह् प्रतिशात)।
- (२ ग्रपराधियों पर किया हुन्ना ग्रर्थ-द्राड ।
- (३) त्रावश्यकतानुसार लगाया हुत्रा त्रातिरिक्त कर त्राथवा शुल्क ।
- (४) विभिन्न संस्थात्रों से ऋण ।
- (५) स्थानीय रूप में व्यापारिक संस्थाओं द्वारा प्रदत्त अनुदान अथवा विवाह आदि के अवसर पर प्राप्त आर्थिक योग ।
- (६) दानशील नागरिकों द्वारा अनुदान।
- (७) स्थानीय संस्था के उद्योगों से प्राप्त लान।
- (=) मे न्द्रिय सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता

ये समाएँ कहीं मन्दिर पर, कहीं पेड़ के नीचें, मठ अथवा हताई (बेठक) पर या कहीं सभा भवन में एकत्र होती थीं। प्रत्येक ग्राम की स्थिति के अनुसार क्षिविधापूर्वक यह व्यवस्था की जाती थी। उस समय भी पक्ष और विपक्ष की मौति सभा में वाद-विवाद होते ये और उपद्रवी सदस्यों पर नियंत्रण रखने के लिए पांच वास् (तत्कालीन सुद्रा) दण्ड भी रखा गया था। श्राम परिषद् के संबंध की जानकारी बहुत सीमित मिलती है। किर भी तत्कालीन

Page 237. Altekar--State and Government in Ancient India-Page 237.

्रकार्यवाहियों का पूरा विवरण रखा जाता था श्रीर मुख्य निर्णयों को मंदिर या सभा भवन की - भित्तियों पर अ कित करवा दिया जाता था। इसलिए शताब्दियों पश्चात् भी ये प्रमाण उप-लब्ध हो सके हैं। कौटिल्य ने ग्राम-सभा या संगठन का उल्लेख न करके, केवल ग्राम-इद श्रीर मुखिया का वर्णन किया है। साथ ही पाँच श्रथवा दस गाँवों के ऊपर नियुक्त श्रिधिकारी "गोप" श्रीर उसके कार्यों का वर्णन भी। "गोप" के लिए अपने श्रधीन प्रत्येक ग्राम का विस्तृत विवरण रखना ऋनिवार्य था। उसमें निम्निल्लित सूचनाएँ सम्मिलित थीं १--वह भूमि जिस पर कृषि होती है, जिस पर कृषि नहीं होती ऐसी भूमि, मैदान, नम भूमि, आराम (उद्यान), उपवन, वाट, वन, चैत्य, देवालय, सेतु, श्मशान, सत्र (दानालय), प्रपा (बल-शाला या प्याक), तीर्थस्थान, विवीत, चरागाह तथा पथ (सङ्कीं। स्रादि । इसके स्रितिरिक खेतीं, वनीं, सड़कों तथा दान में प्राप्त भूमि (सम्प्रदान) की सीमाश्री तथा चेत्रों के लेख रखे जाते थे श्रीर भूमि के कय-विकय तथा कर-मुक्ति श्रादि की सूचना रखना भी श्रावश्यक था। ग्राम के संबंध में अन्य स्चनाएँ; जैसे कुल मकानों की संख्या, करद हैं अथवा कर मुक्त (अकरद), बाह्मण, वैश्य, चत्रिय एवं शूद्रों की पृथक पृथक संख्या, ग्राम के निवासी क्रषक, ग्वाल (गोरक्षक), व्यापारी (वैदेहक), शिल्पियों (कार्), दास मज़दूर तथा जानुवरों की संख्या, प्रत्येक व्यक्ति का हिरएय, विब्दि, शुल्क, दण्ड स्त्रादि के रूप में राज्य की योग, प्रत्येक कुल में रित्रयों श्रीर पुरुषों की संख्या श्रीर उनकी श्राय, जाति के श्रनुसार प्रत्येक का उद्यम, श्राय, व्यय तथा चरित्र का लेखा आदि भी रखने की व्यवस्था का विधान था।

ग्राम सभा के सदस्यों को सम्मान देने के लिए तथा अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक बनाए रखने के लिए उन्हें "ग्रामबुद्ध" की उपाधि से विभूषित किया जाता था। इस सभा की समितियों में साधारणतः पाँच सदस्य होते थे। बृहस्पित २ ने भी पांच सदस्यों वाली समिति का उल्लेख किया है। पंचमण्डली, पंचकुल, पंचकुली आदि नाम इसी आधार पर प्रच-लित हुए थे।

प्राप्त समितियों का अधिकार त्रेतः — उपर्युक्त कार्यों के श्रातिरिक्त ग्राम संस्थाएँ निम्नलिखित कार्य भी करती थीं — भूमि-कर एकत्रित करना, श्रकाल श्रादि के संकट में करों में छूट का प्रवन्ध, सार्वजनिक भूमि पर जनिहत के लिए ऋग्ण प्राप्त करना, ऊसर भूमि को कृषि योग्य बनवाना, पथ-निर्माण तालाब-कुश्रों श्रादि की देखभाल, सार्वजनिक भूमि का विक्रय, न्याय संपादन (जिसमें दीवानी श्रीर फीजदारी मामले सम्मिलित होते थे), देवालयों की संपत्ति का संरत्त्रण, पंचायत बैंक संबंधी कार्य, शिक्ता की व्यवस्था, शिक्ता प्राप्ति के लिए बृत्तियाँ देना श्रादि । न्याय के त्रेत्र में ग्राम पंचायतों के साधारण श्रधिकार तो सर्वत्र ही मान्य रहे हैं परन्तु कहीं-कहीं; जैते चोल शासकों के समय में, पंचायतों के ऐसे मामलों के निर्णय किये जाने की स्वना प्राप्त होती है जिसमें किसी के द्वारा हत्या का श्रपराध भी किया

Marie of Marie . ..

१ अर्थशास्त्र २।३४.

२ हो त्रयः पंच वा कार्याः समूहहितवादिनः । कर्त्ताच्य वचन तैषां ब्रामश्रे खिगुणादिभिः ॥ वीरमित्रोदय-पृष्ठ ४२७.

गयों हो । १ दूसरी विशेषता इस स्थानीय स्वायत्त शासन की यह थी कि शासक वर्ग इन्हें विजन्म हर्स्तज्ञेप नहीं कर सकते थे। मध्यकालीन भारत में भी इन परम्पराओं का पर्याप्त सम्मान थान शिवाजी, राजारीम ऋादि पंचायतों के त्तेत्र के विषयों संबंधी प्रश्नों की, जो सीधे उनके पास जाते थे, पून: पंचायतों के पास ही मेज देते थे । र मुगल शासक भी इस परिपाटी का निर्वाह करते थे। बीजांपुर सुल्तान इबाहीमं त्र्यादिलशाह के समय की एक घटना इस सम्बन्ध में बहुत सुन्दर उदाहरेण है। बापाजी नामक मुसलमान अपने मुखिया-पद के अधिकार संबंधी विवाद में मसूर ग्राम पंचायत में असफल हो गया। बापाजी ने सुल्तान से निर्णय की प्रार्थना की । सुल्तान ने स्वयं हस्तज्ञेप न कर सारा प्रश्न एक दूसरे याम पैठन की पचायत के समज्ञ भेज दिया। वहाँ पर असंफल हो जाने के बाद पुनः सुल्तान के समज्ञ उपस्थित होने पर सुन्तान ने स्पष्ट यह कहा कि वह पंचायत के निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता।३ स्रातः यह कहा जाना सच है कि प्राचीन भारत की ये स्वायत्त संस्थाएँ वास्तव में यथार्थ स्त्रीर न्त्रादर्श का सुन्दर समन्वय थीं। श्रात्यधिक गिक्तिराली भी थीं श्रीर पूर्ण भी। ग्राम्य-जीवन के लगभग समस्त च्वेत्रों में उनकी सत्ता व्याप्त थी। प्रजा की भावनात्रों की प्रतिनिधि ये संस्थाए अपने चेत्र में पूर्ण सार्वभौम थीं। शासक वर्ग न तो हस्तचेप करते ये और न उनमें इस दुस्साहस की चमता थी। दशकुमारचरित के अनुसार राजा ने एक जनपद अध्यक्त से एक ग्रामणी को सताने की प्रार्थना की थी। इससे प्राप्त की संस्थात्रों के नैतिक, सामाजिक श्रीर राजनैतिक सुंह है श्राधार की भान होता है।

केन्द्र एवं प्राप्त की संस्थाओं का सम्बन्ध:— कुछ स्मृतियों के अनुसार तो ग्राम की समस्त शिक्तयाँ सम्राट अथवा केन्द्रिय सरकार द्वारा प्रदान की जाती थीं, परन्तु यह अयन वाद-सा प्रतीत होता है। वास्तव में ग्रामीण संस्थाए प्रारम्भ से ही आत्मिनिर्भर एवं स्वतंत्र रूप से संगठित रही हैं। इसीलिए सत्ता परिवर्तन के बाद भी वे इसी रूप में बनी रही थीं। सम्राट द्वारा समय समय पर उनसे सम्पर्क करने अथवा उनकी स्वीकृति प्राप्त करने के प्रमाण यह सिद्धं करते हैं कि ग्रामों की संस्थाए स्वतंत्र होती थीं और अपना महत्त्र्यण स्थान रखती थीं। यह कहा जा सकता है कि समस्त राज्य के कार्य में संगात रखने के लिए अथवा केन्द्रिय राजाशाए प्रसारित करने के लिये कुछ निर्देशात्मक नियन्त्रण अवश्य रखा जाता था। विशेष-कर गामों के आय-व्यय का निरीक्ण केंद्र के अ केन्द्रकों द्वारा अवश्य रखा जाता था। इसके श्रातिरक्त दो या प्रधिक ग्रामों के मध्य किसी विवाद की उत्पत्ति पर केन्द्र का निर्णय हो अ तिम होता था। इस प्रकार केन्द्र का निर्यत्रण किसी न किसी रूप में अवश्य रहा। किर भी स्थानीय संस्थाओं की प्रशासनीय रूपनेखा पूर्णतया प्रजातन्त्रात्मक थी, जिसमें समस्त नागरिकों को समानता तथा स्वतन्त्रता के साथ भाग लेने का अवसर प्राप्त होता था। इन्हों समानताओं

साउथ इंग्टियन एपियाफी रिपोर्ट्स १६०० सं० ६४, ७७; १६०३ मं० २२३; १६०६ मं० २५७, ३५२।

२ टॉ॰ श्रहटेकर - Village Communities-Page 45, 46.

३ उपरोक्त-पृष्ठ ४४।४४.



.

सर चार्ल्स मेटकाफ ने ये शब्द कहे थे "भारतीय ग्राम छोटे प्रजातंत्र हैं, जिनमें उनकी ग्राव-श्यकता की प्रत्येक वस्तुए उपलब्ध हैं ग्रीर वे किसी भी प्रकार के बाद्य संबंधों से लगभग स्वतंत्र हैं। वे जहाँ ग्रन्य कोई वस्तु स्थायी नहीं रहती, स्थायी प्रतीत होते हैं"। एक के उप रान्त दूसरे राजवंश नष्ट होते हैं विद्रोह के उपरान्त विद्रोह होते हैं " किन्तु ग्राम्य जीवन जैसा का तैसा बना रहता है " ग्राम्य-जातियों की इस एकता ने ही मेरी धारणा में भारत के लोगों को चनाए रखने में सब कारणों से श्रिधिक योग प्रदान किया है।....यही उनके द्वारा श्रिधकांश में दासता से मुक्ति तथा स्वतन्त्रता के उपभोग का कारण रहा है। १

उपर्युक्त समस्त वर्णन से यह धारणा वन ही जाती है कि इन स्वायत्त संस्थाश्रों पर केन्द्र का प्रभाव केवल पथप्रदर्शन एवं सामान्य निर्देशन की दृष्टि से ही थोड़ा वहुत था। वास्तविक श्रधिकार ग्राम्य संस्थाश्रों को प्राप्त ये श्रीर वहुत विस्तृत चेत्र में उदारतापूर्वक उनका उपयोग किया जाता था। गाँव की सुरचा, कर-संग्रह, राजस्व-संग्रह, विवाद-निर्णय, जनोपयोगी कार्य, श्रापत्ति निवारक शुल्क श्रादि, शिचा, पाठशालाश्रों की व्यवस्था, निर्धन श्राश्रम, श्र्यव्यवस्था, देवालय संरच्या श्रादि सभी श्रावश्यक कार्य ये संस्थाएँ करती थीं श्रात्तः यह सिद्ध होता है कि वर्तमान समय में, किसी भी राष्ट्र की स्थानीय संस्थाश्रों की श्रपेचा प्राचीन भारत की ये स्वायत्त संस्थाएँ श्रधिक शिक्तशाली थीं। श्रम विकेन्द्रीकरण श्रादि की जो योजन।एँ वनाई जा रही हैं, वे वास्तव में भारत के लिए नवीनता नहीं है। तस्कालीन स्थानीय संस्थाएँ ग्राम्य निवासियों की हितरचा में बहुत सफल हुई थी। नैतिक, सांसारिक तथा वीद्विक उन्ति के चेत्र में गांवों की उन्नित का समस्त श्रय इन्हीं संस्थाश्रों को दिया जाता है। इस दृष्टि से श्राज भी भारतवर्ष को श्रपने श्रतीत से शिचा प्राप्त करने का पर्याप्त श्रवसर है।

प्रश्त

- 1. "On the whole, Kautilya gives us a picture of a highly-organised system of administration under a powerful bureaucracy at the centre, though much scope was left for local self-government". Illustrate with reference to the central administrative machinery and local institutions.
- 2. Indicate the broad pattern of Village administration in ancient India. To what extent can it serve as a basis for the organisation of our villages at the present day?

१ रिवोर्ट १=३२. भाग ३, १एठ ३३१,

चौदहवाँ अध्याय

न्यायपालिका

(Judiciary)

प्रस्तावनाः-भारतवर्ष में नियम एवं न्याय का सदैव ही उच्च स्थान रहा है। प्रत्येक स्मृति, शास्त्र, पुराण, वेद, वेदांग आदि नियम को समाज का आधार एवं न्यायपालिका को मानव के सब प्रकार के हितों का संरत्नक मानते हैं। वर्त मान समय में भी न्यायपालिका की नागरिकों के हित एवं राज्य के संविधान का संरक्षक माना जाता है परन्तु यह मान्यता नवीन नहीं है । प्राचीन भारतवर्ष में ये सिद्धान्त इतनी क्रशलता के साथ व्यवहार में लाये जा चुके हैं, जिस सीमा तक स्रभी वर्त्तमान नियम व न्यायपालिकाएँ नहीं पह ँची हैं। स्राजकल धारा सभात्रों एवं व्यवस्थापिकात्रों ने त्राधिनियम बनाने का एकाधिकार सा मान लिया है। प्राचीन परम्पराएँ, अर्वाचीन आवश्यकताएँ तथा सामाजिक जीवन के शाश्वत एवं रेआधारभूत सिद्धान्त नियम-निर्माण में वह स्थान नहीं रखते, जो प्राचीन काल में उन्हें प्राप्त था। तत्कालीन परिस्थितियों से नियमों को धर्म की संज्ञा दी गई थी और ये धर्म लगभग इस प्रकार प्रयक्त होते थे कि समय, स्थान ऋौर परिस्थिति के ऋनुसार इनका उचित प्रयोग सुगमता से सम्भव हो जाता था। धर्म का स्थान बहुत महत्व का था तथा उसका चेत्र भी व्यापक श्रौर विस्तृत माना गया था। समस्त हिन्दू दर्शन में धर्म का स्थान सर्वोच है। साधारणतया धर्म में धार्मिक, नैतिक एवं परम्परात्रों के साधारण नियम सम्मिलित होते हैं। वत्त मान नियम श्रयवा श्रधिनियमों की श्रपेचा प्राचीन धर्म वास्तव में श्रधिक प्रभावशील एवं महत्व का था।

धर्म की व्याख्याः— "धर्म" शब्द की उत्पत्ति "धृ" धातु से हुई है, जिसका अर्थ है "धारण करना" । इस प्रकार धर्म का अर्थ उन सिद्धान्तों से है जो किसी भी उद्देश की धारण कर सके अर्थात् सुरिच्चित रखकर निर्वाह कर सके । ऋग्वेद में धर्म का प्रयोग अधि कांश अधिनियम या नियम के अर्थ में हुआ है । उपनिषदों में धर्म की रचना के संबंध में कहा गया है कि धर्म "शिक्त की भी शिक्त और सत्ता की भी सत्ता" है । धर्म से बढ़कर विश्व में कोई चीज नहीं है । इसीलिए धर्म की सहायता से, निर्वल व्यक्ति भी बलवान् व्यक्ति पर शासन करता है । धर्म और सत्य दोनों समान हैं । इसिलिए जब वह सच बोलता है तो धर्म और जब धर्म की अभिन्यक्ति करता है तो सच बोलता है । १ इसिलिए धर्म का स्थान सम्राट

१. बृहदार्ग्यक उपनिषद्।

या चित्रिय की शारीरिक एवं सैनिक शिक्त से भी ऊपर माना गया है। धर्म की इस मान्यता का प्रभाव प्राचीन हिन्दू राजनैतिक विचारों में बहुत गहरा रहा है। धर्म का एक अर्थ 'कर्त व्य' से, भी लिया जाता था और धर्मशास्त्रों का यह आदेश था कि प्रत्येक वर्ण को अपना-अपना कर्त व्य पालन करना चाहिए। कौटिल्य ने धर्म के चार अर्थ बताये हैं—(१) धर्म अर्थात् चरित्र या सामाजिक कर्त व्य, (२) धर्म अर्थात् सत्य पर आधारित नीति, (३) धर्म अर्थात् राज्य के नियम (राजशासन) एवं (४) धर्म (व्यवहार) प्रमाणों पर आधारित। कौटिल्य के मतानुसार सफल समाट को धर्म का अनुसरण करना चाहिए। सम्राट ही धर्म का संस्थापक होता है और धर्म का उचित पालन उसे स्वर्ग का अधिकारी बनाता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सम्राट को छः प्रकार के व्यसनों, और काम, कोध लोभ, मद आदि पर नियंत्रण रखना चाहिए। कौटिल्य ने शांतिमय व्यवस्था करने के लिए चार साधन भी प्रस्तावित किये हैं, जो धर्म, व्यवहार, चरित्र एवं अभिलेख कहे जाते हैं। अशोक ने इसी धर्म के आधार पर सम्राट के पद के लिए नया सिद्धान्त घोषित किया था जिसमें सम्राट को पिता एवं प्रजा को सन्तान के तुल्य समक्षना धर्म माना था और 'सर्वभृतहिते रताः" का।सिद्धान्त सम्राट के लिए आदर्श स्वीकार किया था। इस प्रकार प्राचीन काल में धर्म बहुत अधिक व्यापक अर्थ में प्रयुक्त होता था।

धर्म का स्थानः — प्राचीन भारतवर्ष में धर्म को समाज में सार्वमीम माना जाता था। धर्म ही राज्य का नियम था और नियम ही राज्य में सर्वोपिर था। डाँ० वेनीप्रसाद के मतानुसार प्राचीन भारतवर्ष में सरकार ग्रास्टिन के अर्थ में सार्वभीम नहीं होती थी, क्योंकि वह
सरकार केवल प्रशासन करती थी और वह भी उन नियमों के ग्राधार पर जिनमें संशोधन
का ग्राधिकार उसे प्राप्त नहीं था। वह सरकार केवल स्वीकृत नियमों का ही समाज के हित
में पालन करती थी। १

डॉ॰ राधाक्वां के मतानुसार भी धर्म का द्रार्थ उन सब स्वीकृत मान्य परम्पराद्रों के योग से हैं, जिससे मानवमात्र का हित सुरित्तत होता है। डॉ॰ धावन का विचार है कि प्राचीन भारत में राज्य का कर्त व्य धर्म का संशोधन या परिवर्तन करना नहीं था वरन् धर्म का पालन करना था। र डॉ॰ जायसवाल के मतानुसार मनु ने धर्म का ही वास्तविक सार्वभीम शासक स्वीकार किया है, सम्राट को नहीं। ३ डॉ॰ राधाकुमुद के मत से हिन्दू दर्शन में धर्म ही राज्य का वास्तविक सार्वभीम था और धर्म का ही शासन था, उसका पालन करने के लिए सम्राट दण्ड का प्रतिनिधि था। ४ इस प्रकार धर्म प्राचीन भारतवर्ष में नियम के स्यान पर बहुत महत्वपूर्ण माना गया है।

उपर्युक्त वर्णन के साथ ही आधुनिक समय में धर्म की प्रतिष्ठा के संबंध में झुछ शंकाएँ भी की जाती हैं। डॉ॰ वो, पी. वर्मा अपनी "Hindu Political Thought"

Pr. B. Prasad-Theory of Government in Ancient India-Page 9.

[?] Dr. Dhawan-The Political Philosophy of Mahatma Gandhi.

[₹] Dr. Jayaswal-Hindu Polity-Page 323.

Y Dr. R. K. Mukerji-Chandragupta Maurya and His Timies. Page 79.

नामक पुस्तक में यह व्यक्त करते हैं कि शुक्र, कीटिल्य आदि ने धर्म की कहीं भी राज्य का तत्व नहीं माना है। धर्म की "शिक्त की मी शिक्त" कहते 'हुए भी यह राजनैतिक दोत्र में केवल नैतिक सिद्धान्त ही रहा। व्यावहारिक जीवन में धर्म का उल्लंबन करने अथवा पालन न करने पर सम्राट पर कोई राजकीय दवाव नहीं था और ऐसी स्थिति में धर्म का पालन भी सम्मव नहीं था। इसलिए धर्म को राज्य की सार्वभीम सत्ता स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस संबंध में डॉ॰ वर्मा ने दो आधार प्रस्तुत किये हैं:-(१) ऐतिहासिक दृष्टि से पाचीन भारत के संबंध में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जब धर्म की आजाए सर्वोपिर मानी गई हों। (२) यदि धर्म सार्वभीम था तो राज्य के सात तत्वों की भाँति यह भी राज्य के तत्वों में सिम्मिलित होना चाहिए था। परन्तु धर्म वास्तव में केवल सम्राट पर एक नैतिक प्रभाव था, कोई वास्तविक प्रतिबन्ध नहीं। १

उपयुक्त दोनों विचारधारात्रों के ऋध्ययन के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि प्राचीन भारतवर्ष में धर्म अथवा नियम वास्तव में सम्राट से ऊपर, सर्वोच शक्ति तथा सम्राटों का सम्राट और सर्वशिक्तमान् था। अर्थशास्त्र में यह संकेत किया है कि स्वेच्छाचारी सम्राट का सर्वनाश होता है ।२ इसका तात्पर्य है कि यदि सम्राट नियमां का पालन नहीं करेगा तो वह स्थिर नहीं रह सकता। दूसरे शब्दों में नियमों की सर्वोच्चता पर हा ध्यान आकर्षित किया है। यदि हम सूच्म हिट से देखें तो भारतवर्ष का सम्पूर्ण संगठन धार्मिक पृष्ठभूम पर त्र्याधारित है। चाहे साधारण स्वास्थ्य के नियम हों ऋथवा व्यक्तिगत जीवन से संबंधित सिद्धान्त अथवा पारिवारिक जीवन के प्रश्न, सब की व्याख्या धर्म की सहायता से, धर्म के के द्वारा ही की गई है। इसलिए धर्म के साथ, समाज की सबसे बड़ी सत्ता, लोकमत का सदैव सहयोग रहता था। स्त्राज बीसवीं शताब्दी में भी विश्व में धर्म का बहुत प्राधान्य है; तो तस्का-लीन भारत में धर्म की मान्यता राज्य, सरकार श्रीर सम्राट से श्रिधिक थी इसमें कोई सन्देह नहीं हो सकता। ऋतः धर्म का स्थान प्राचीन भारतवर्ष में सर्वोत्कृष्ट माना जाना सर्वथा उचित है। इसलिए मनुस्मृति अर्थशास्त्र, महाभारत आदि में धर्म को सम्राट से ऊपर माना गया हैं । सम्राट भी नियम त्रनाता था, परन्तु वह केवल सहायक अथवा प्रक्रिया संबंधी नियमों की स्वीकृति होती थी। ऐसे नियम नहीं बना सकता या जो आधारभूत बन सके अथवा उसे स्वेच्छाचारी वना सर्वे ।३ इस प्रकार धर्म अर्थात् नियम का स्थान वास्तव में सर्वोपरि था ।

न्याय की धारणा (Conception of Justice) :— प्राचीन भारतवर्ष में न्याय की स्थापना करना राज्य का प्रमुख कर्त व्य माना गया था। शुक्रनीति के अनुसार यह भित्तपादित किया गया है कि न्याय की स्थापना करते हुए सम्राट की दुष्टों के लिए दगड की व्यवस्था करना चाहिए।" तथा व्यवहार (अभियोग) आदि का निर्णय सम्राट की लीभ और कीघ से मुक्त रहते हुए मुख्य न्यायावीश, अमात्य एवं ब्राह्मण और पुरोहित के साथ मिलकर

रे Dr. V. P. Varma-Hindu Political Thought, अनु० २, पुत्र =३ से १३=.

२ अर्थशास्त्र, भाग १. श्रनु० ३, १एठ ११

[₹] Dr. Jayaswal-Hindu Polity-Page 324.

धर्मशास्त्रों के अनुसार करना चाहिए।"१ इस प्रकार न्याय सम्पादन सम्राट बहुत सावधानी एवं शास्त्र की आजाओं के अनुसार करते थे। उस समय का न्याय पूर्ण रूप से धर्मशास्त्रों के नियमों पर आधारित था और तत्कालीन नियमों के स्रोत मुख्य रूप से वेद, तथा समस्त धर्मशास्त्र (Codes of Law) थे। धर्मशास्त्रियों ने नियम के आधारों, तत्कालीन परम्पराओं, रीति-रिवाज एवं रूहियों आदि को ध्यान में रखकर नियमों का निर्माण किया था और उनका आधार वेदों को ही माना था। इसीलिए धर्मशास्त्र पवित्र एवं अनुकरणीय माने जाते थे। बहुत समय तक प्राचीन भारत के नियम परम्पराओं द्वारा ही सुरिन्तित रहे। इसके विपरीत यह भी प्रमाण उपलब्ध हैं कि प्राचीन काल में न्यायसम्पादन राज्य का कर्त व्य न माना जाता था। र इसीलिए मनुस्मृति जैसे प्रंथ यह स्वीकार करते हैं कि न्यायालय की स्थापना के पश्चात् भी पीड़ित व्यक्ति शक्तिप्रयोग, कुटिल चाल (छुल) और धरना आदि साथनों का प्रयोग कर सकता है। ३ नारद, प्रसिद्ध स्मृतिकार भी इसी प्रकार के विचारों से सहमत है। यह भी मान्यता दीर्घ काल तक रही थी कि हत्याएँ, राज्य विषद्ध अपराध नहीं था वरन एक साधारण अपराध था जिसके लिए हत्या होने वाले दल को मुआवना (Compensation) दे देना पर्याप्त दण्ड था। परन्तु यह मान्यताएँ सदैव नहीं रहीं। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि प्राचीन भारतवर्ष में न्याय की धारणा बहुत उज्ववल और प्रशस्त थी।

कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के संबंध: — प्राचीन भारतवर्ष में राज्य के इन दोनों प्रमुख ग्रंगों के सम्बन्ध बहुत ग्रन्छे रहे हैं। फिर भी न्याय स्थापना की दृष्टि से न्याय-पालिका को सदैव ही पृथक् समभा गया था। न्यायपालिका रूप, संगठन तथा ग्रास्तित्व में स्वतन्त्र मानी गई थी (Independent in Form and independent in Spirit)। कुछ प्राचीन हिन्दू न्यायशास्त्र न्यायपालिका की इस स्वतन्त्र स्थिति के लिए निम्न लिखित ग्राधार स्वीकार करते हैं:——

- (१) न्यायाधीश के पद पर सामान्यतः श्राभवका (Lawyer) ही नियुक्त होते थे।
- (२) साधारणतया यह नियम ही था कि अभिवक्ता बाह्मण ही होते थे।
- (३) अपराध का दर्गड दो रूपों में दिया जाता था। एक तो दण्ड अपराध के लिए तथा दूसरा उस अपराध के कारण जो दुष्कर्म या पाप हुआ, उसके लिए। इस प्रकार पाप का दर्गड केवल बाह्मण न्यायाधीश ही निर्धारित कर सकते ये।
- (४) ब्राह्मण अपराधियों को दिण्डित करने के लिए राजा समर्थ नहीं माना गया था, ब्राह्मण न्यायाधीश ही आवश्यक था।

१ शुक्रनीतिसार—पृष्ठ १=३.

R Dr. Altakar-State & Government in Ancient India-Page 240.

३ धमें ए व्यवहारेण छतेनाचरितेन च । प्रयुक्त साध्येद्ध पंचमेन बलेन च ॥ मनु० अध्याय =. रलोक ४१.

उपर्युक्त श्राधारों में वे कारण भी सम्मिलित हो गए हैं जो ब्राह्मण न्यायाधीशों की नियुक्ति के श्राधार थे। इसके श्रितिस्त ब्राह्मण लोगों के लिए यह भी मान्यता थी कि वे न्यायिष्य होते हैं तथा किसी प्रकार के श्रनुचित दबाव श्रयवा प्रभाव में नहीं श्राते। इतिहाम में ऐसे पर्याप्त उदाहरण हैं जब ब्राह्मण मन्त्री श्रयवा ब्राह्मण न्यायाधीशों ने विभिन्न श्रवमरों पर, शुद्ध न्यायोचित परामर्श देते हुए श्रयवा निर्णय घोषित करते हुए सहर्ष जनहित के लिए श्रयना पद्त्याग कर दिया था। जातक ब्रंथों में भी ऐसे प्रसंग उपलब्ध हैं जहाँ पुरोहित ये सब कार्य करते थे श्रीर सम्राटों के प्रभाव में श्रनुचित रूप से नहीं श्राते थे। श्रतः यह स्वष्ट है कि न्यायपालिका श्रीर कार्यपालिका के मध्य संबंध तो था किन्तु न्यायपालिका श्रपने कार्यचेत्र में स्वतंत्र थी।

न्याय सम्पाद्न प्रक्रिया: — प्राचीन काल की न्याय व्यवस्था पूर्ण रूप से वैज्ञानिक आधार पर संगठित थी। प्रत्येक साधन और प्रकार जो तत्कालीन समय में न्याय सम्पादन के लिए उपयोग में लाये जाते थे, यह सिद्ध करते हैं कि वह समाज बहुत उन्नत. सम्य और न्यायप्रिय था और वर्ष मान युग की संस्थाओं से सरलता के साथ तुलना योग्य भो। अब हम क्रमशः प्रत्येक प्रणाली का अध्ययन करेंगे।

(१) न्याय समिति पद्धित (Jury System):—प्राचीन वैदिक काल में न्यायाश्वा को को सभा भी कहते थे। वास्तव में न्यायाश्वीशों की सहायता के लिए ये सभाए होती थों जिनमें समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति होते थे। यह सिद्धान्त स्वीकार किया गया था कि न्याय-सम्पादन में समाज को सहयोग करना चाहिए श्रीर इसीलिए यह सभा संगठित होती थी। हाँ जायसवाल के मतानुसार यह सभा श्राष्ट्रीनिक भाषा में न्याय समिति (Jury) थी, जो न्याय वितरण में सहायक होती थी। इस न्याय समिति के सदस्यों की संख्या सदैव विषम होती थी जिससे मतदान में सुविधा रहती थी। न्याय समिति के सदस्यों से धर्म के अनुसार सत्य-भाषण की अपेचा की जाती थी। जो न्याय समिति मीन रहती है अथवा धर्मानुकृत कार्य नहीं करती है, वह अनैतिक है। १ न्याय समिति के कार्य आदि का विशद विवरण शुकनोतिसार में अच्छा दिया है। बृहस्पित सूत्र एवं नारदस्मृति में भी वर्णन मिलता है। इन ग्रंथों के अनुसार इस समिति (Jury) में सात, पांच अथवा तीन सदस्य संख्या होती थी। रे के लोग कार्यपरीक्त (The examiners of the cruse) एवं वक्ताध्यक्त (President Speaker कहे जाते थे। मृच्छक्रिक में न्यायाधीश के मुल से ये वाक्य

ह नार्दरमृति—प्रस्तावना III, 18 तथा Dr. Jayaswal—Hindu Polity-Page 325. (Foot Note)—"Either the Judicial Assembly must not be entered at all, or a fair opinion delivered. That man who, either stands mute or delivers an opinion contrary to justice is siner". Narad-Intro. III 10 (Jolly).

२ शुक्तनीतिसार—श्रनु० ४, ५-२६-६७= "लोक वेदशधर्मशाः सप्त पञ्च त्रयोऽपि वा । तत्रोपविष्टा विप्राः स्युः सा यद्वसदृशी सभा ॥ श्रोतारो विणजस्तत्र कर्त्तव्याः स्रविचनणाः ।

कहलाये गये हैं 'हम ही अपराध का प्रमाणित निर्णय करने योग्य हैं, शेष राजा के हाथ में है ।' १ अर्थात् इस न्याय समिति के निर्णय मान्य होते थे और सम्राट को निर्णय कार्यान्वित करने का अधिकार था। वृहस्पति के मतानुसार यह न्याय समिति का पृथक् चेत्र था (कर्म प्रोक्तम् पृथक् पृथक्) कि वह सत्य पर ध्यान दे अथवा उपस्थित विषय के किसी अन्य पच्च पर । इस प्रकार न्यायाधीशों के निर्णय के पश्चात् भी न्याय-स्थापना की सुरच्चा का पर्याप्त साधन उपस्थित था। यह सिद्ध होता है कि प्राचीन न्याय व्यवस्था में आधुनिक युग के समान न्याय समिति को उचित एवं प्रसुख स्थान प्राप्त था।

- (२) न्याय सम्पादन श्रौर सम्राट (King and Justice):—प्राचीन काल में सम्राट का स्थान प्रत्येक रूप में प्रमुख था श्रीर परिषद में सम्राट-(King-in-council) मुख्य न्यायाधीश माना जाता था । फिर भी सम्राट स्वयं कोई ऋभियोग नहीं सुनता था । परि-षद् में-सम्राट पुनर्पार्थना (ऋपील) के लिए सर्वोच्च न्यायालय होता था। नारदस्मृति, वृह-स्पति तथा याज्ञवल्क्य ऋादि सब इस विचार का समर्थन करते हैं। राजतरंगिणी में ऐसा एक उदाहरण बहुत ही स्पब्ट है। सम्राट यशस्कर के न्यागधीशों द्वारा निर्णय हो जाने के पश्चात् जब प्रार्थी सब जगहों से निराश हो चुका, तब उसने अपना सारा विषय सम्राट यशस्कर के सामने उपस्थित किया श्रीर सम्राट ने उसे सुना । इससे यह भी सिद्ध होता है कि सम्राट द्वारा मौलिक अभियोग सुनने की प्रथा बहुत पहले नष्ट हो चुकी थी और इसीलिए ऐसे प्रसंग एव प्रमाणों का अभाव है। वास्तव में राजा को अकेले न्याय सम्पादन का अधिकार नहीं था। न्याय राजा के नाम से संपादित श्रवश्य होता था। सिद्धान्त रूप में न्यायालय की श्रध्य-क्षता सदैव राजा द्वारा ही की जाती थी चाहे वह उपस्थित हो ऋयवा नहीं। न्यायालय से दिया हुआ निर्णय सम्राट की त्राज्ञा ही समभी जाती थी। जब किसी अपराधी या अभियोगी को त्रामंत्रित किया जाता था तो यही त्रार्थ होता था कि सम्राट ने उसे बुलाया है। इस प्रकार न्यायपालिका स्वतंत्र थी; किन्तु इस स्वतन्त्रता के कारण सम्राट की प्रतिष्ठा में किसी प्रकार की कमी नहीं होती थी।
- (३) न्यायपालिका की विशेषतायँ:—प्राचीन काल में न्यायव्यवस्था में श्रन्य श्रनेक प्रमुख विशेषताएँ थों। उनमें से कतिपय निम्नलिखित हैं—
- क—तत्कालीन न्यायपालिका सम्पूर्ण कार्य विवरण लेखरूप में सुरिक्ति गवती थी, तथा निर्णय भी लेखबद्ध किये जाकर संग्रहीत किये जाते थे। निर्णयों से संबंधित अन्य लेख, पत्र आदि भी सुरिक्ति रखे जाते थे।

ख—न्याय खुले रूप में सम्पादित होता था, गुप्त रूप से नहीं ह्यों कभी एक न्यायाधीश द्वारा भी निर्णय नहीं दिया जाता था। निर्णय की प्रतिलिपियाँ दोनों दलों को दी जाती थी।

१ मृच्द्रकटिक-

श्रार्य चारुदत्त ! निर्णये वयं प्रमार्ण, रोपे तु राजा । Act. IX ।

ग — ग्रिभियोगों की संख्या का न्यूनाधिक होना न्याय की विशेषता एवं निर्वलता से संबंधित समभा जाता थ । यदि न्याय कुशलतापूर्वक प्रदान किया जायगा तो ग्रिभियोग कम होंगे श्रोर इसके विपरीत मुकदमें बढ़ते जायेंगे यह मान्यता प्रचलित थी।

घ - शुद्ध न्याय (Purity of Justice) एवं नियम का शासन (Rule of Law) सर्वोच्च सामाजिक एवं राजनैतिक स्रादर्श स्वीकार किये गये थे। न्याय का वितरण वास्तव में निष्पच रूप में होता था। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण हैं, जहां पूर्ण निष्पच्ता के द्वारा निर्णय दिए गए हैं। सुदत्त के विरुद्ध राजकुमार जेता १ का विवाद एक ऐसी ही घटना है। सुदत्त एक साधारण नागरिक (गृहपित) था। वह अनायों के प्रति बहुत सहानुभूति रखता था, श्रतः सम्मानित समभा जाता था । जेता राजकीय घराने से संबंधित था । राज-कुमार जेता के ऋधिकार में नगर के निकट ही एक उद्यान था। उदार सुदत्त ने इस उद्यान को क्रय करने का विचार किया। यह राजकुमार के पास गया। उसने कहा कि मैं हसे आराम (Rest-House) बनाना चाहता हूं। राजकुमार ने कहा—"श्रार्थपुत्र श्रार्थपुत्र), यह उद्यान उस समय तक नहीं विक्रय किया जा सकता, जन तक एक के पास एक मुद्रा रखकर करोड़ों मुद्रायों से समस्त उद्यान त्राच्छादित नहीं हो जाता ।" इस पर मुदत्त ने उत्तर दिया "यह मूल्य देना स्वीकार है, मैं उद्यान को क्रय करता हूं।" इसके बाद राजकुमार इस विनिमय को ऋस्थीकार करना चाहते थे। तब दोनों निर्णय के लिये न्यायाधीश के सम्मुख उपस्थित हए। न्यायाधीशों ने सारी बातें सुनकर निर्णय किया कि राजकुमार ने जो मूल्य निश्चित किया था, जन नह सुदत्त दे रहा है तो उद्यान दिया जाना ही चाहिए। राजकुमार ने विनम्रतापूर्वक निर्णय स्वीकार किया । इस निर्णय में विनिमय के सिद्धान्त, न्यायाधीश की स्वतन्त्रता त्रथवा प्रिक्रिया की ही प्रधानता नहीं है, किन्तु एक साधारण दानशील नागरिक की अपने गुरु के प्रति समर्पण की भावना भी प्रधान तत्त्र है (सुद्त्त, बुद्ध के आगमन पर उनके विश्राम के लिए यह उद्यान चाहता था) । प्राचीन भारत के न्याय सम्बन्धी अनेक उदाहरणों में से यह भी एक ज्वलन्त उदाहरण है। उस समय राजकीय परिवार स्रोर रण नागरिक, नियमों के समच्च समान समके जाते थे।

ङ—प्राचीन काल में भी न्याय चेत्र में आने वाले दल प्रश्तिन (Plaintiff), आभिप्रश्तिन (Defendant), तथा मध्यमिस (Arbitrator) कहलाते थे। इसका तारपर्य है कि न्यायपद्धति पूर्ण विकसित थी। प्रत्येक दल का तकनीकी नाम स्वीकृत था तथा पंच-फैसला अथवा मध्यमिस के द्वारा भी विवाद सुलमाने की प्रथा भली भाँति प्रचलित थी।

च - न्याय-समिति (Jury System) प्रथा भी पूर्ण रूप से व्यवहार में आती थी, जिसका वर्णन ऊपर किया जा चुका है।

छ—न्याय सम्पादन के समय अपराध का रूप, उद्देश्य (ध्येय), अवस्था (वय) तथा अपराधी की सामाजिक प्रतिष्ठा (Social Status) ध्यान में रखी जाती थी। प्राचीन काल में जाति के अनुसार दण्ड की व्यवस्था थी। ब्राह्मण की हत्या के लिए १००० गाय,

[?] Dr. Jayaswal—Hindu Polity-Page 327.

चित्रय की हत्या के लिए ५०० गाय, वैश्य की हत्या के लिए १०० गाय तथा शूद्र की हत्या के लिए केवल १० गाय का दण्ड दिया जाता था। १

ज—विभिन्न अभियोगों में साची अपर्याप्त होने पर परीचा-प्रणाली (Ordeal system) भी अपनाई जाती थी। स्मृतियों में ऐसे प्रसंग बहुत हैं। अग्नि-परीचा का विवरण अधिकांश पढ़ने-सुनने को मिलता रहता है। इसके अनुसार अभियुक्त को निरपराधी सिद्ध होने के लिए लोहे का गर्म गोला अपने हाथ में लेकर सात कदम चलना पड़ता था। इसके बाद गोला फेंक दिया जाता था और हाथों को कपड़ा आदि लगाकर बाँध दिया जाता था। तीन दिन बाद पुनः प्रस्तुत होने पर यदि हाथ ठीक रहते तो उसे निरपराधी' बोषित कर दिया जाता था, अन्यथा 'दोषी' ठहराया जाकर दिखत किया जाता था। इसी प्रकार जल-परीचा, विष-परीचा, भार-परीचा आदि भी प्रचलित थी। र

क — प्राचीन काल में अभिवक्ता (Fleader) साधारणतया नहीं थे जो विभिन्न दलों की ओर से न्यायालय में प्रस्तुत होते हों; किन्तु कुछ विद्वान यह मानते हैं कि मनु ने 'विप्र' शब्द का प्रयोग अभिवक्ता के लिए ही किया है । नारदस्मृति की असहायकृत मीमांसा में ऐसा उदाहरण अवश्य है जहाँ ग्रुक्त प्राप्त कर एक अभिवक्ता ने दूसरे दल की ओर से न्यायालय में उपिरथत होकर विवाद (Arguments) प्रस्तुत किया था। उस अभिवक्ता का नाम स्मार्त दुर्धर था। उसने एक व्यक्ति को ऋण न चुकाने के लिए प्रोत्साहित कर यह कहा था कि यदि तुम मुक्ते एक सहस्र द्रामा (तत्कालीन मुद्रा का नाम) फीस रूप में दो तो में न्यायालय से तुम्हें मृग्णमुक्त करवा लूँगा। शुक्तनीतिसार में भी न्यायालय में अपना मान्य प्रतिनिधि भेजने की प्रथा का प्रसंग मिलता है और उस प्रतिनिधि का शुक्क भी ६ प्रतिशत से ई प्रतिशत तक स्वीकार किया गया था। विवादग्रस्त सम्पत्ति जितनी अधिक होती, शुक्त उसी अनुपात से कम होता जाता था। ज्यों-ज्यों न्याय अधिक विस्तृत, व्यापक और तकनीकी बनता गया, अभिवक्ताओं का प्रवेश व प्रसार भी बढ़ता गया। परन्तु फिर भी आजकल की भांति अभिवक्ताओं की बहुत बड़ी संख्या उस समय नहीं थी। केवल कुछ लोग, जो स्मृतियों के पूर्ण शाता थे, उन्हें ही यह कार्य सींपा जाता था। राज्य की ग्रोर से उन्हें कोई मान्यता श्रपता स्वीकृति प्राप्त करना श्रनिवार्य नहीं था।

इस प्रकार ये विशेषताएँ प्राचीन भारत की न्याय प्रणाली को एक विकसित प्रणाली सिद्ध करने में सहायक हैं।

न्यायमन्त्री एटां मुख्य न्यायाधीश:--डॉ॰ नायसवाल के मतानुसार न्यायमन्त्री को 'प्राड्विनाक ' कहा नाता था ख्रीर वह दो रूपों में काम करता था। प्रथम तो वह मुख्य न्यायाधीश होता था तथा द्वितीय रूप में वह न्याय-मंत्री भी। ३ न्याय-मंत्री के रूप में वह विधिम् मंत्री (Minister of Law) का कार्य भी करता था ख्रीर मंत्रियों में उसका पद बहुत

R Dr. Altekar-State & Government in Ancient India-Page 251.

२ उपरोक्त-पृष्ठ २५३.

३ टॉ॰ नायसवाल-Hindu Polity पृष्ठ ३२६.

महत्व का माना जाता था। मंत्रि परिषद् में प्रतिनिधि प्रधान, सचिव, मंत्री के पश्चात् विधि एवं न्याय मंत्री का पद होता था। राज्य के सर्वोच्च न्यायाज्ञय की अध्यक्षता न्याय मंत्री मुख्य न्यायाधीश के रूप में करता था। इसीलिए इसे 'प्राइ विवाक' (First Judge) कहा जाता था। न्यायमन्त्री के रूप में यह न्याय समिति के बहुमत से प्रक्रिया के नियम सम्राट की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करता था। शुक्रनीतिसार में यह वर्णन बहुत सुन्दरता से किया गया है। तदनुसार न्यायाज्यों के समच्च साच्ची, प्रलेख, शपथ, परीच्चा तथा अन्य साधनों जैसे प्रत्यच्च साक्षी (Direct evidence), अनुमान (Inference), उपमान (Analogy) आदि का उपयोग किया जाता था।

विधि मंत्री के रूप में उसे "धर्माधिकारी" तथा शुक्र नीति के अनुसार 'पण्डित' मी कहा जाता था। इस रूप में वह नियमों को विश्लेषण तथा उनकी उपयोगिता पर विचार करने के पश्चात् सम्राट की स्वीकृति और अस्वीकृति के लिए प्रस्तुत करता था। १ यह प्रसंग यह सिद्ध करता है कि प्राचीन भारत की नियम प्रणाली अवश्य सुधारों का सदैव स्वागत करती थी। साधारणतया हिन्दुओं के नियम परम्परागत माने जाते थे तथा परिवर्तन को अच्छा नहीं माना जाता था। परन्तु किर भी शुक्रनीति का प्रसंग यह सिद्ध करता है कि भारतीय नियम प्रणाली नियमों को सदैव समयानुकृल बदलने में समर्थ थी। इसलिए समय-समय पर नियम प्रत्यच्व-विधि-निर्माण द्वारा, साधारणतया व्याख्या (Interpretation) द्वारा और यदा कदा प्राचीन ऋषियों के नाम पर रचित कृतियों द्वारा समयानुकृल वने रहते थे। लोकेच्छा का भी नियम परिवर्तन अथवा नियम निर्माण में बहुत प्रभाव रहता था। इस प्रकार न्याय एवं विधि मंत्री अपने पद से संबंधित कार्य जनता के हित के लिए करने में सदैव व्यस्त रहता था।

न्यायालयों के प्रकारः—डॉ राधाकुमुद मुकर्जी के मतानुसार प्राचीन भारतवर्ष में न्यायालयों की एक क्रमिक श्रृंखला थी जिसमें धर्मस्थीय (Civil),करटकरोधन (Criminal), ग्रामन्यायालय एवं न्याय की अन्तिम संस्था सर्वोच्च न्यायालय तथा परिषद्युक्त सम्राट (King in-council मुख्य थे।२ इनमें दीवानी, फौजदारी तथा धर्म न्यायालय भी सम्मिलित थे। डॉ० अल्टेकर के मतानुसार न्यायालयों का संगठन निम्न प्रकार से किया गया था।

१. अधीनस्थ राजकीय न्यायालय Subordinate Royal Courts)-ये न्याया-लय अधिकांश प्रदेशों के मुख्य कार्यालयों के साथ स्थापित होते थे, जैसे स्थान ५०० ग्रामों की संगठन की इकाई, द्रोणमुख (४०० गाँवों का संगठन) एवं खरवाटिका जिसका संगठन द्रोणमुख से आधा होता था। ये न्यायालय राजा की मुद्रा द्वारा राजा के नाम पर न्याय

१ वत्त मानाश्च प्राचीना धर्माः के लोकसंश्रिताः । शास्त्रे पु के समुद्दिप्टा विरुध्यन्ते च केऽध ना ॥ लोकशास्त्रविरुद्धाः के पण्डितस्तान् विचिन्त्य च । नृपं संवोधयेत् तैश्च परत्रेष्ट सुखप्रदैः ॥ शुक्रनीति — पृष्ठ ६६-१००

R. K. Mukrerji-Studies in Ancient Hindu Polity.

सम्पादित करते थे, इसलिए बाद के युग में इन्हें 'मुद्रिता' भी कहा गया है। नारदस्मृति के अनुसार इनके अतिरिक्त मण्डल न्यायालय (Circuit Courts) भी होते थे। मीर्यकाल में इन प्रान्तीय न्यायालयों में तीन न्यायाधीश और तीन सहायक न्यायसदस्य Jurors) होते थे। उस समय राजकीय कम चारी अधिक प्रभावशाली नहीं हो सकते थे। यह न्याय गणाली भारत के प्राचीन समय में लगभग निरन्तर चलती रही।

लोकितय न्यायालय (Popular Courts)—उपर्युक्त न्यायालयों के ऋतिरिक्त प्राचीन भारत में लोकिपिय न्यायालय भी बहुत थे छौर यह प्राचीन न्यायालय प्रणाली की विशेषता थी। वैदिक काल में "सभा" एक ऐमी ही संस्था थी। गाँवों में सीमा-विवाद तथा मन्दिर, ब्राह्मण, साधु, स्त्रियाँ, ब्राह्मप्यस्क, बृद्ध तथा अपंग व्यक्तियां के बाद धर्मस्य (Unofficial Jurors) न्यायालय द्वारा निर्णात होते थे। याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार लोकिपिय न्यायालय तीन प्रकार के थे—

(१) पूग (२) श्रेणी, तथा।(३) कुल ।१

वृहस्पित के मतानुसार कुल न्यायालय की अपील श्रेणी में तथा श्रेणी न्यायालय की अपील पूग न्यायालय में होती थी। कुल न्यायालय में वे ही लोग सिम्मिलित होते थे जो किसी न किसी प्रकार कुल से सम्बन्धित होते थे। र यह न्यायालय एक व्यावहारिक संस्था के रूप में था। जब कुल न्यायालय का निर्णय असन्तोषप्रद होता था, तब वाद श्रेणी न्यायालय के समज्ञ प्रस्तुत होता था। ये श्रेणी न्यायालय व्यावसायिक संगठनों की संस्था थी, जो ईसा से ५०० वर्ष पूर्व से भारतवर्ष में बहुत प्रधान बन गये थे। बौद्ध ग्रंथ तथा महाभारत में भी इनका उल्लेख मिलता है। श्रेणी में चार या पांच सदस्यों की कार्यकारिणी समिति होती थी श्रोर वही न्यायालय का कार्य भी करती थी। ये संस्थायें १५वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में कार्य करती रही हैं, इसके प्रमाण उपलब्ध हैं।

पूरा-न्यायालय ऐसा संगठन था जिसमें विभिन्न जाति एवं व्यवसायों के ऐसे लोग सम्मिलित होते थे जो उसी नगर के निवासी हों। प्राचीन काल की ''सभा' इसी प्रकार की संस्था प्रतीत होती है। तैतिरीय संहिता में उल्लिखित ''ग्राम्यवादी'' संभवतः इसी ग्राम न्यायालय 'पूरा' का सदस्य होता होगा। महाराष्ट्र में कुछ समय पश्चात् यही पूरा न्यायालय गोट न्यायालय के नाम से प्रसिद्ध हो गये। सर हेनरी मेन का मत है कि ये समस्त लोकप्रिय न्यायालय भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना तक कार्य करते रहे ग्रीर इसी कारण ग्राम स्तर पर कोई राजकीय न्यायालय कार्य नहीं कर सके। राजकीय न्यायालय की व्यवस्थित स्थापना होते ही ये पंचायत न्यायालय समाप्त ही हो गए। प्राचीन काल में राज्य की यह स्पष्ट नीति रहती थी कि ये न्यायालय कार्य करते रहें ग्रीर इनके निर्णयों का पालन होता रहे। राज्य का पूर्ण सहयोग इन्हें प्राप्त होता था। याज्ञवल्क्य के मतानुनार ये न्यायालय सम्राट

१ न पेशाभिकृताः पूगाः श्रे खयो यः कुलानि च । II २६ (याइबल्नय)

⁻ २ जातिसम्बन्धिर्वधूनां र्समृहः । मिताचरा । as quoted by Dr. Altekar on Page 247. F. Note.

द्वारा मान्यता प्राप्त होते थे। मध्यकाल में अनेक उदाहरण हैं जब राजाओं ने सीधा कोई भी अभियोग सुनना अस्वीकार कर दिया, शिवाजी, राजाराम, साहू आदि ऐसे ही शासक हुए हैं। बीजापुर का शासक इवाहीम आदिल भी इसी प्रकार सीधा अभियोग नहीं सुनता था। इसका तात्पर्य है कि शासक इन लोकप्रिय ग्राम न्यायालयों की प्रतिष्ठा बनाये रखना चाहते थे।

प्राम न्यायालयों की प्रतिष्ठा बनाये रखना, सैद्धान्तिक रूप में बहुत सुन्दर वस्तु थी। स्वायत्त शासन की भावना प्रेरित करने के लिए, केंद्र का प्रशासनीय भार कम करने के लिए, तथा न्याय की सुगमता व सरल रूप में प्राप्ति की दृष्टि से यह अत्युत्तम सिद्धांत था। इन न्यायालयों के अधिकार (न्याय) त्तेत्र की कोई सीमाएं निर्धारित नहीं थीं। गंभीर अपराधों से लेकर साधारण अपराधों तक का निर्णाय ये ही न्यायालय कर सकते थे। इसके पश्चात् कमशः उच्चतर न्यायालयों में पुनर्पार्थना के लिए त्तेत्र था ही।

हिन्दू न्याय शास्त्र के अनुसार प्राचीन भारत में निम्नलिखित आधारभृत सिद्धांत स्वीकार किये थे थे:—

- (१) न्याय प्रिक्रया सदैव स्वतंत्र वातावरण में हो, गुप्त नहीं।
- (२) ऋभियोग क्रमानुसार लिये जाकर समाप्त किये जायं।
- (३) न्याय प्राप्ति में विलम्ब की निन्दा की गई थी।
- (४) कार्यपालिका न्यायपालिका से पृथक् थी व हस्तच्चेप नहीं कर सकती थी।
- (५) न्यायाधीशों से निष्पच रहने की अपेचा की जाती थी तथा अभियोग काल में वे दोनों पन्नों से कोई भी सम्बन्ध नहीं रखंसकते थे।
- (६) फौजदारी अभियोगों में किया के ध्येय (Intention) पर विचार किया जाता था।
- (७) अपराध के लिए प्रोत्साहन (Abetment), (धन, शस्त्र अथवा भोजनादि की सह।यता द्वारा) देना भी दण्डनीय अपराध माना गया था।
- (=) अभियुक्त दनाव, आत्मरचा तथा अल्पायु को स्वरचा के लिए आवश्यक सिद्ध करता हुआ यत्न कर सकता था। अल्पायु के लिए कुछ लोग = वर्ष, कुछ १५ वर्ष तक की अवस्था मानते थे।
- (६) सन्देह का लाभ सदैव अभियुक्त को प्राप्त होता था।
- (१०) दण्ड विधान समयानुकूल सरल एवं कठिन था। अर्थदण्ड, कारावास, वनवास, अर्गमंग तथा मृत्युदण्ड उस समय प्रचलित थे।

त्र्यर्ष्ट समसे अधिक लोकप्रिय था। कारावासियों से अधिकांश जन-मार्गों पर कार्य कराया जाता था। अंगमंग का दण्ड अधिकांश चोरों को दिया जाता था। वनवास का दण्ड विशेषाधिकारपाप्त लोगों को दिया जाता था और मृत्युदण्ड अधिकतर हत्यारे, देश-द्रोही, डाकू अथवा चरित्रहीनों को दिया जाता था। अपराधी के सम्बन्धियों को अनावश्यक रूप से कोई पीड़ा नहीं पहुँ चाई जाती थी।

न्यायिक प्रक्रिया (Judicial Procedure):—सर्वप्रयम प्रार्था (वारी) प्रार्थनापत्र लिखता था, जिसमें उसे अपने अधिकार एवं वाद को संत्तेप में प्रस्तुत करना पड़ता था।
उसके बाद प्रार्थनापत्र में कोई परिवर्तन सम्मव नहीं होता था। तत्र प्रतिवादी को स्त्रना
द्वारा आमन्त्रित किया जाता था। और तत्सम्बन्धी लिखित प्रलेख आदि भी प्रस्तुत करने को
कहा जाता था। अभियुक्त अपराध स्वीकार या अस्वीकार कर सकता था। अथवा स्थगन
आदेश (estoppel) या निर्णात तथ्य (res judicate) का नहारा (Plead) ले सकता
था। प्रार्थनापत्र तथा लिखित वक्तव्य पर विचार कर लेने के पश्चात् न्यायाधीश दोनों
दलों को साची प्रस्तुत करने के लिए आमन्त्रित करता था। साची मौखिक अथवा प्रलेख
रूप में (Documentary) हो सकती थी। प्रलेखों के रूप में साची अधिक प्रभावशाली
होती थी। दीवानी अभियोगों में आधिपत्य का प्रभाव भी माना जाता था। जब सब प्रकार
की साची खत्म हो जाती थी और निर्णय सम्भव नहीं होता था, तब परीचा प्रणाली (Ordeal
System) का पालन होता था। यह पिक्रया धर्मस्थीय (Civil) और कण्टकशोधन
(Criminal) दोनों प्रकार के न्यायालयों में लगभग समान रूप से कार्यान्वित होती थी।
स्यायालयों के चेत्र पृथक पृथक थे। श्री नरेन्द्रनाथ जा के मतानुसार धर्मस्थीय न्यायालयों के चेत्र पृथक पृथक थे। श्री नरेन्द्रनाथ जा के मतानुसार धर्मस्थीय न्यायालयों के चेत्र पृथक पृथक थे। श्री नरेन्द्रनाथ जा के मतानुसार धर्मस्थीय न्यायालयों के चेत्र में निम्नलिखत विषय सम्मिलत थे—

- (१) संविदा (Contracts)।
- (२) स्वामियों के श्रिधिकार एवं कर्तव्य।
- (३) सेवकों के अधिकार और कर्तव्य।
- (४) दास प्रथा।
- (४) ऋण।
- (६) क्रय एवं प्रथमाधिकार (Pre-emption)।
- (७) भेंट एवं उपहार।
- (८) डकैती ।
- (६) ग्राक्रमण (Assault)।
- (१०) श्रपयश (Defamation)।
- (११) स्वामित्व के अधिकार।
- (१२) सीमा-विवाद ।
- (१३) भवन एवं उनका स्थान निर्धारण।
- (१४) उपज, चरागाह एवं मार्गों की चृति।
- (१५) विवाह एवं दहेज।
- (१६) सहकारिता के कार्य।
- (१७) उत्तराधिकार, श्रादि श्रादि ।१

N. N. Law-Studies in Ancient Hindu Polity-PP. 119, 120.

कण्टकशोधन न्यायालयों के चेत्र में निम्नलिखित विषय सम्मिलित थे:—

- (१) नागरिकों तथा व्यापारियों की रत्ता ।
- (२) अवांछनीय लोगों का दमन।
- (३) गुप्तचरों द्वारा अपराधियों का पता लगाना।
- (४) सन्देहात्मक या वास्तविक भ्रापराधियों को बन्दी बनाना।
- (५ शव परीचा।
- (६) राज्य के विभिन्न विभागों में ऋनुशासन ।
- (७) त्रांगमंग, त्रपराध के लिए दण्ड ।
- (५) मृत्युदण्ड की व्यवस्था।
- (६) बलात्कार, त्रादि ग्रादि।

प्रक्रिया के सम्बन्ध में जो व्यक्ति साची के लिए उपस्थित होते थे, उनके लिए यह धारणा थी कि वे भविष्य में प्रसन्नतापूर्णक जीवन व्यतीत करते हैं और इस संसार में अपार यश के भागी होते हैं। वास्तव में अभियोग में सत्य की खोज की जाती थी। न्यायालय के सम्मान की रचा के लिए कुछ ऐसे व्यवहार भी दण्डनीय माने गये थे जो न्यायालय के समच अनुचित हों। उदाहरणार्थः —

- (१) प्रश्न का उत्तर सीधा और स्पष्ट न देना।
- (२) वक्तव्य में अन्तर होना।
- (३) सम्बन्धित प्रश्नों का निरन्तर उत्तर न देना।
- (४) अप्रासंगिक वक्तव्य।
- (५) अपने ही साची के वक्तव्य को अरवीकार करना।
- (६) गुप्त रूप से त्रिना त्र्याज्ञा साची से वार्तालाप करना ।
- (७) निश्चित समय में अपना अभियोग सिद्ध न कर सकना।
- (६) अवांछनीय वक्तव्य, ग्रादि ग्रादि ।१

निम्नलिखित व्यक्ति साची रूप में उपस्थित नहीं किये जा सकते थे :--

साला, बहनोई, मित्र, बन्दी, साहूकार, ऋणी, शत्रु, पराधीन, दण्डित, सम्राट, श्रीत्रिय, प्राम-सेवक, कोढी, जाति-निष्कासित, चांडाल, घमण्डी, स्त्रियां, राज्य-कर्मचारी, साधु, हस्तसामुद्रिक-विशेषज्ञ, छुटेरे, ठग आदि।

न्यायाधीश के गुगा: — यद्यपि प्राचीन भारतवर्ष में न्यायपालिका स्वतंत्र थी श्रौर उसमें कार्यकारिगी का हस्तच्चेप नहीं था, तथापि शुद्ध न्याय सम्पादन के लिए न्यायाधीश का स्वतन्त्र, निर्भीक तथा स्पष्टवक्ता होना श्रावश्यक माना जाता था। मृच्छकटिक के श्रनुसार न्यायाधीश विद्वान्, बुद्धिमान्, वक्ता, गम्भीर श्रौर निष्पच्च होना चाहिए। उसे पूर्ण जानकारी

१ अर्थशास्त्र—भाग ३-खग्ड १।

प्राप्त कर लेने के पश्चात् विचारपूर्वक निर्णय घोषित करना चाहिए। उसे निर्वल का संरच्य एव दुष्टों के लिए आतंकपूर्ण होना चाहिए। उसे हृदय शांत, मस्तिष्क केवल न्याय और सत्य पर केन्द्रित तथा स्वयं को सम्राट के कोध से परे रखना चाहिए। शुक्रनीति के अनुसार सम्राट का यह कर्च व्य स्वीकार किया गया है कि ऐसे न्यायाधीश, जो भय, लोभ अथवा क्रोध के कारण विना विचारपूर्वक निर्णय करते हैं, उन्हें आदर्श दण्ड मिलना चाहिए। इस प्रकार न्यायाधीशों में उपर्श्वक गुण तथा कर्च व्यपरायणता आवश्यक समभी गई थी और शुद्ध न्याय व्यवस्था के लिए यह अनिवार्य स्थिति थी।

उपसंहार:-उपश्वित वर्णन से यह सिद्ध होता है कि प्राचीन भारतवर्ष में नियम श्रीर न्याय की पूर्ण व्यवस्था था तथा न्याय की धारणा बहुत स्पष्ट एवं व्यापक थो। नियम की पिवतता का सदेव ध्यान रखा जाता था। धर्मशास्त्रों में ये नियम सुरिक्त रहते ये श्रीर समय, रिथित एवं श्रावश्यकतानुसार उनका संशोधन, परिवर्षन भी होता रहता था। न्यायालय श्रावश्यकतानुसार जातिधर्म (rules of castes), जनपदधर्म (local customs), श्रेणीधर्म (bye-laws of guilds), कुलधर्म (family traditions) का भी पालन करते थे। र इसके श्रातिरक्त नियमों को समयानुकृत बनाने के लिए एक सचिव को पूर्ण रूप से उत्तरदायी माना जाता था। रीति-रिवाजों पर श्राधारित होते हुए भी प्राचीन भारत के नियम प्रगतिशील रहते थे। बाह्मणों श्रयवा चित्रयों द्वारा उनके स्वार्थ सुरिक्त नहीं बनाये जाते थे, वरन् जनहित तथा समाज कल्याण की व्यवस्था के लिए सिद्धान्त स्वीकार किये जाते थे। श्रतः भारत की नियम-प्रणाली एवं न्याय व्यवस्था जड़ नहीं, जीवित थी, जो न सम्राट की इच्छा से श्रीर न विधानसभा के प्रस्तावों से, वरन् मन्थर गति से होने वाले समाज के प्रत्यस्त परिवर्ष नों एवं संशोधित रीति-रिवाजों के साथ गम्भीर विचारपूर्व क समयानुकृत रूप धारण करती थी।

प्रश्न

- 1. Describe the organization of the judiciary in ancient India.
- 2. Explain the approach to law and Government as embodied in the Manu-Smriti.

How does it compare with the modern approach?

र शुक्रनीतिसार — (As quoted by Dikshitar-Page 229.

र जातिज्ञानपदान्धर्मान्श्रे खीधर्माश्च धर्मवित् । समीद्य लथर्माश्च स्वधर्भे प्रतिपादयेत् । मनुस्मृति VII, 41.

पन्द्रहर्वा ग्रध्याय

कर-सिद्धान्त

(Principles of Taxation)

प्रस्तावनाः— भारतवर्ष में प्राचीन काल से यह उक्ति लोकप्रिय रही है कि कंचन सब गुणों से युक्त होता है। १ राज्य भी इस सिद्धान्त में अपवाद नहीं है। प्रत्येक राज्य की समृद्धि और स्थिरता उसकी अर्थ-ज्यवस्था पर ही निर्भर करती है। राज्य के प्रशासन का मूल आधार यही अर्थ-ज्यवस्था होती है। प्राचीन भारत में यह सिद्धान्त पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया गया था; किन्तु वास्तविक महत्व भी उस समय इसी को दिया गया था। राज्य की धारणा के सप्तांग सिद्धान्त में कोष' एक महत्वपूर्ण अंग स्वीकार किया गया था। वास्तव में कोष का अभाव अथवा निर्वलता राज्य की स्थिति को निर्वल बना देती है और राज्य की समृद्धि उसको सुह बना देती है। इसलिए प्राचीन काल में सम्राट हर प्रकार से राज्यकोष को पूर्ण रखने का यत्न करता था। उस समय कोष की निर्वलता भयंकर राष्ट्रीय आपत्ति समभी जाती थी। इस विषय में अर्थशास्त्र, र महाभारत ३ तथा कामन्दक अदि सभी एकमत हैं। इसलिए कर देना जनता का प्रमुख कर्त्त व्य समभा जाता था। कर के संबंध की धारणाएँ, प्रकार, सिद्धान्त आदि पर प्राचीन भारतवर्ष में विशद विचार किया गया था और वे सिद्धान्त कुछ सीमा तक आदि पर प्राचीन भारतवर्ष में विशद विचार किया गया था और वे सिद्धान्त कुछ सीमा तक आज भी ज्यवहार्य हैं, अतः उनका अध्ययन परमावश्यक है।

कर का महत्वः—राज्य की दृष्टि से कोष का पूर्ण होना, एक अनिवार्य स्थिति होती थी; किन्तु नागरिक दूरारा कर देने की दार्शनिक पृष्ठभूमि भी पर्याप्त रूप में विकसित थी। प्राचीन भारतीय लेखों के मतानुसार यह मान्यता थी कि जो सम्राट अपनी प्रजा के जीवन और सम्पत्ति की रज्ञा करता था, अपने कर्च व्य के लिए पारिश्रमिक का अधिकारी भी होता था और यह धनांश जो सम्राट को शांति और सुन्यवस्था की स्थापना के लिए मिलता था, उसे 'कर' की संज्ञा दी गई थी। महाभारत में इस संबंध में बहुत सुन्दर वर्णन किया गया है। 'मन्दु' जो प्रथम शासक था, उसे सुरज्ञा के उपलच्य में जनता ने, प्रति ५० गायों के क्रय या विकय पर एक गाय, स्वर्ण का पचासवां भाग, अनाज का दसवां भाग, आदि देना

१ सर्वे गुणाः काञ्चनमाश्रयन्ते।

२ कोशमूलाः कोशपूर्वाः सर्वारम्भाः तस्मात्पूर्व कोशमवेत्रेत । अर्थशास्त्र II 2.

३ कोशम्ला हि राजानः कोशो वृद्धिकरो भवेत । महाभारत XII ११६, १६.

४ कोशमूलो हि राजेति प्रवादः सार्वलौकिकः । कामन्दक XIII, ३३.

स्वीकार किया था । यह द्रव्य पा लेने पर जन-सुरत्ता का भार सम्राट पर होता था, श्रीर इसमें श्रसफल होने पर सम्राट को पदच्युत करना या दूसरे का निर्वाचन संभव माना गया था। शांतिपर्व के श्रनुसार छ: प्रकार के व्यक्तियों को छोड़ देना चाहिए:—

- १. वह अध्यापक जो अध्यापन नहीं करता है,
- २. वह ब्राह्मण जिसे वेदों का ज्ञान नहीं है,
- ३. वह शासक जो सुरत्ता स्थापना में असमर्थ है,
- ४. वह धर्मपत्नी जो स्नेही जीवनसायी न हो।
- ५. वह ग्वाला जो नगर में रहने की ऋभिलाषा करता हो ऋौर
- ६. वह नाई जो जंगल में रहना चाहता हो (अर्थात् जो संसार त्यागकर साधु बनकर जंगल में जाना चाहता हो।

वैदिक साहित्य में कर संबंधी प्रसंग बहुत कम हैं। संभवतः उस समय सम्राट के श्रधि-कार इस चेत्र में बहुत सीमित, यदा-कदा और अनिश्चित रहे होंगे। उस समय 'बलि' शब्द प्रचितित या जिसका अर्थ है स्वेच्छा से दी हुई भेंट या उपहार। यह अधिकांश देवताओं को प्रसन्न करने के लिए दी जाती थी; किन्तु बाद में यही प्रथा सम्राट के संबंध में भी कार्या-न्वित होने लगी। धीरे-धीरे इन प्रयाश्रों में परिवर्तन हुत्रा। वैदिक काल में प्राह्मण वेदों का अध्ययन करते थे, चत्रिय रचा करते थे, और शूद्र निर्धन होते थे। केवल वैश्य वर्ग व्यापार में व्यस्त रहते थे, इसलिए वे लोग कर अधिक देते थे ।१ परन्तु अन्य वर्ग भी सामर्थ्य के अनुसार कर देते थे। कुषक एवं प्रापालक भी कर देते थे। कुषक अपनी उपज का कुछ भाग देते थे श्रीर पशुपालक, जो तत्कालीन समाज में श्रधिक महत्वपूर्ण थे, श्रपनी श्राय का कुछ भाग देते थे । वे मुख्यतया गाय, बैल अथवा घोड़ों के रूप में कर चुकाते थे और उनके पशुस्रों का कुछ भाग राज्य का ही समभा जाता था। २ इसके अतिरिक्त सम्राटों को अपने श्रधीन शासकों से भी कुछ त्रार्थिक योग (Tribute) प्राप्त होता था। राज्य का कीप परि-पूर्ण करने के लिए ये सारे साधन बहुत नियमित तथा सुगम थे। हॉपिकन्स के मतानुसार ये कर बहुत स्वेच्छाचारी, कुचलने वाले ग्रीर जनता को पीस देने वाले थे।३ किन्तु यह दृष्टि-कोण सर्वथा अनुचित है। अर्थशास्त्र, स्मृतियाँ एवं धर्मस्त्र इस संबंध में पूर्ण दर्शन तथा करों की मान्यता की एष्टभूमि प्रकट करते हैं। उसका अध्ययन करने पर यह अम कि प्राचीन भारत में कर पीस देने वाले थे, दूर हो जाता है। ग्रातः कर संबंधी धारणा का श्रव्ययन श्रनिवार्य है।

कर-संबंधी धारणाएँ:—प्राचीन भारत में कर-संबंधी सिद्धान्त एवं धारणाएँ अत्यन्त महत्व की थीं। वैधानिक दृष्टि से कर नियमों द्वारा निहिचत एवं निर्धारित होते ध

१ श्रन्यस्य विलक्षत । A. B. VII. 29. as quoted by Dr. Altekar--State and Government in Ancient India-Page 257.

२ एनं भज शामे श्रश्वेषु गोषु । A. V., IV-अपरोक्त । पृष्ठ २४=.

Taxation in the Vedic-Period was oppressive and grinding." Hopkins-India Old and New-Page 240.

श्रीर धर्मशास्त्रों में उनका उल्लेख होता था। इस्रिल्ए राज्य का प्रकार श्रयवा राजाश्रों का ज्यिक्तित्व कर-संबंधी विषयों में कोई परिवर्त्तन नहीं कर सकता था। राजा श्रीर प्रजा में करके विषय में कोई विचार-मेद भी उत्पन्न नहीं होता था। इस प्रकार 'कर' के सिद्धान्त संवैधानिक नियमों के रूप में निर्धारित एवं सुरिज्त थे। महाभारत में यह कहा गया है कि धर्मविरुद्ध कर लगाने वाला शासक स्वयं श्रपने नाश के बीज नोता है। इतिहास में ऐसे श्रनेक उदा-हरण भी हैं, जहाँ इन सिद्धान्तों का उल्लंघन करने के प्रयास श्रयक्त रहे हैं। उदाहरणार्थ, चन्द्रगुप्त मीर्य भविष्य में युद्ध करने के लिए कुछ धन संग्रह करना चाहता था, परन्तु श्रपने महासचिव कीटिल्य सिहत यथासंभव प्रयत्न करते हुए भी स्पल्ल नहीं हो सका। चन्द्रगुप्त ने दूसरे साधनों से घन एकत्र किया, मंदिरों से सहायता माँगो, जनता से 'प्रणय' (Token of affection) रूप में घन मांगा, प्रकाड़ हल्के सिक्के चलाए, किन्तु करों में कोई परि-वर्त्तन नहीं कर सका। इससे यह सिद्ध होता है कि नियमों की प्रतिष्ठा थी श्रीर शासक किसी भी परिरिथित में स्वेच्छाचारिता द्वारा करवृद्धि नहीं कर सकता था। इस प्रकार निर्धारित नियमों के विषय में उस समय कुछ प्रमुख सिद्धान्त प्रचितत थे, जो निम्निलिखित हैं:—

- (१) कर-सम्राट का वेतन (वेतन सिद्धान्त)— राज्य के विभिन्न नियमों द्वारा जो कर निर्धारित किये जाते थे, वही सम्राट का वेतन होता था। राजा समाज की सेवा करता था, सुरत्ता की व्यवस्था करता था, इसीलिए वह वेतन का अधिकारो होता था। यह वेतन उसे विभिन्न करों के संग्रह के रूप में प्राप्त होता था। महाभारत के अनुसार बिल का छुठा भाग, शुक्क अपराधियों से आर्थिक दण्ड एवं उनकी सम्पत्ति के राज्यीयकरण (Forfeiture) आदि जो धर्मानुसार संग्रह किये जाते थे, सम्राट का वेतन ही होता था। र नारद स्मृति के अनुसार भी कर, सम्राट का वेतन ही होता था, इसिलए राज्य में सत्र प्रकार के शुक्क तथा उपज का छुठा भाग, सम्राट को वेतन रूप में प्राप्त होता था। वही सिद्धान्त कीटिल्य ने अपने आर्थ- शास्त्र में भी प्रतिपादित किया है।
- (२) कर-सबंधी देवो सिद्धान्त:-प्राचीन भारत में राजनैतिक दार्शनिकों ने उपर्युक्त वेतन-सिद्धान्त को श्रीर भी विकसित किया था श्रीर अन्त में इसे देवी सिद्धान्त का रूप दे दिया था (Divine Theory of Taxation)। शुक्रनीतिसार के अनुसार यह प्रतिपादित किया गया है कि भगवान (ब्रह्मा) ने सम्राट का रहजन इस प्रकार से किया है कि वह स्वामी के रूप में प्रजा के निरन्तर पालन व विकास की व्यवस्था करता रहे श्रीर दास के रूप में करों द्वारा वेतन प्राप्त करता रहे। र अर्थात् इस दाससुक्त स्वामी का वेतन दैविक सत्ता द्वारा निर्धारत किया गया था। वह इससे अधिक नहीं ले सकता था, क्योंकि उसे ऐसा अधिकार नहीं

१ विलपप्ठेन शुल्केन दर्ग्डेनाथापराधिनाम् । शास्त्रानीतेन लिप्तेथा वेतनेन धनागमम् ॥ महामारत, शांतिपव – अध्याय ५१-१०.

२ स्वभागमृत्या दास्यत्वे प्रजानां च नृषः कृतः । ब्रह्मणा स्वामिरूपस्तु पालनार्थं हि सर्वदा ॥ शुक्रनीतिसार I, पृष्ठ १८५

था। साथं ही प्रजा पर, जो वास्तव में स्वामी थी, यह दायित्व था कि वह राजा को 'स्वभाग'-निर्घारित कर देकर उसकी रज्ञा करे।

यहाँ इस प्रसंग पर विचार करना सर्वथा उचित होगा कि मनुस्मृति के अनुसार दैवी-सम्राट के समच् आत्मार्पण की नीति का प्रतिपादन किया गया है। किन्तु प्राचीन भारत में ऐसा सिद्धान्त जो शासक को स्वेच्छाचारी बनने के लिये प्रेरणा दे, कभी सहा नहीं हुआ। अतएव ऐसे अवसर पर मानवां के गुरु मनु के सिद्धान्त अस्वीकार कर, असुरों के गुरु शुक्र के सिद्धान्त स्वीकार किये जाते रहे हैं।

प्रथम सिद्धान्त (वेतन सिद्धान्त) राज्य के सामाजिक जीवन में बहुत प्रभावशाली रहा है। यदि राजा त्रांशिक रूप में भी अपना कार्य करने में असफल होता था तो उसे ज्ञित के अनुपात का द्रव्य लौटाने की बाध्य होना पड़ता था तथा उसे किसी न किसी रूप में ज्ञित पूर्ति करनी ही होती थी। महाभारत में कर्जा व्यपालन में असफल रहने वाले शासक को ज्ञित्यस्त जलयान (Ship which leaks) की उपमा दी गई है, जिसमें रहना भयानक होता है। अथवा जंगल में जाने वाले नाई के समान है, जिस पर विश्वास नहीं किया। जा सकता। इसी प्रकार अपने कर्जा व्यपालन में असफल शासक भी परित्याग के योग्य है। यह धारणा कर-सिद्धान्तानुसार उन्वित ही थी, जहां कर राजा का वेतन होता था और राजा सुरक्षा की व्यवस्था करने के पुरस्कार रूप में वेतन ग्रहण करता था।

कर-संग्रह के सिद्धांत (Canons of Taxation)—प्राचीन भारत में कर-संग्रह के लिए कुछ स्वीकृत एवं मान्य सिद्धांत थे, जिनका पालन अवश्यम्भावी था। जनता से कर लेने का मुख्य उद्देश्य यह था कि संग्रहीत-संपत्ति के बल पर राज्य में ऐसी व्यवस्था की जाय जिससे कुषि, समाज-कल्याण, समृद्धि एवं विकास निरन्तर होता रहे। इसलिए इन करों में मुख्य भाग सम्राट के लिए होता था और भूमि की उपज का निश्चित भाग उसे प्राप्त होता था। इसके श्रतिरिक्त बाजार के व्यापार में जो लाभ होता था, उसका दशांश अथवा परिस्थिति के श्रनुसार निश्चित भाग सम्राट को मिलता था। मनुस्मृति, श्रापस्तम्ब तथा बौद्धायन श्रादि इस विषय में एकमत हैं। १ राज्य का कोष परिपूर्ण करने के लिए शुल्क श्रादि श्रन्य साधन भी प्रचलित थे और इस दोत्र में प्रारम्भ में शासकों को पर्याप्त स्वतंत्रता भी थी, किन्तु बाद के धर्मशास्त्रों में इस दोत्र को भी राजाओं के लिए मर्यादित कर दिया था। फिर भी लालची या त्राकांची शासकों के लिए पूरे बन्धन नहीं लगाये जा सके। उदा-हरणार्थ, नन्द राजाओं ने धन संग्रह के लिए चर्म या बालों वाले चमड़े पर भी कर लगा दिये थे। श्रर्धशास्त्र में यह प्रसंग स्नाता है कि हिमालय के देशों और मगध साम्राज्यों में चर्म व्यापार बहुत विकसित हो गया था। २

कर-संग्रह का कार्य शासक का प्रधान कार्य था, इसलिए जितनी वुद्धिमानी छीर सावधानी से यह कार्य किया जाता था उतना ही राजा छीर प्रजा के लिए श्रेयस्कर माना

Ġ

ĝ

1

१ टॉ॰ नायसवाल-Hindu Polity Foot Notes- Page 336.

२ उपरोक्त।

जाता था। उस समय कर-संग्रह तथा कर-निर्धारण के सम्बन्ध में बहुत सुन्दर एवं उपयोगी सिद्धांत स्वीकृत किये गये थे। उनमें से मुख्य मुख्य निम्नलिखित हैं:—

- (१) महाभारत में यह कहा गया है कि सम्राट को अधिक तृष्णा करके अधिक कर-संग्रह के द्वारा अपनी एवं दूसरों की नींव निर्वल नहीं बनानी चाहिए।१
- (२) जनता पर इस प्रकार कर लगाया जाय कि वह भविष्य का कर-भार वहन करने के लिए और भी हड़ होती जाय और यदि आवश्यकता हो तो उससे भी अधिक कर देने की चमता बढ़ती जाय। महाभारत में यह प्रसंग बड़ी मुन्दर उपमा द्वारा स्पष्ट किया गया है। लिखा है—हे भारत! यदि बळुड़े को दूध पीने दिया जाय तो वह सशक्त बनता जाता है और अधिक पीड़ा और भार सह सकता है। इसलिए शासक को यह सिद्धांत ध्यान में रखकर कर-दोहन करना चाहिए। अधिक दुग्ध-दोहन से बळुड़ा निर्वल हो जाता है और अन्त में स्वयं स्वामी को हानि होती है।?
- (३) महाभारत के अनुसार तीसरा सिद्धांत यह था कि महत्वपूर्ण एवं बड़े कार्य वह राज्य कर सकता है, जहां सामान्य कर-संग्रह किये जाते हों। अत्यधिक कर-संग्रह करने वाले राज्य द्वारा यह सम्भव नहीं होता। जहां देश की सुरत्ता एवं प्रशासनीय संगठन मितव्ययता के आधार पर व्यवस्थित हैं, वहां स्वामाविक रूप से महत्वपूर्ण एवं विशाल कार्य सम्पादित हो सकते हैं। ३ अपव्यय करने वाले शासक का जनता द्वारा भी विरोध किया जाता था। ऐसा राजा अतिलादी अर्थात् अधिक खाने वाला समभा जाता था। (Eating too much).
- (४) महाभारत के अनुसार कर-संग्रह इस प्रकार किया जाना चाहिए कि कर-दाता उसे भार अनुभव न करें। शासक को इस सम्बन्ध में वागवान या मधुमक्खी की तरह से कार्य करना चाहिए जो पौद्यों को जिना पीड़ा पहुंचाये फल, फूल या मधु इकट्ठा करते हैं। ५

१ नोच्छिन्यादात्मनो मूलं परेपां चापि तृष्ण्या । महाभारत, १२वाँ श्रध्याय, ८७-१८ ।

२ वत्सौपम्येन दोग्धव्यं राष्ट्रमचीणवुद्धिना।

भृतो वत्सो जातवलः पीडां सहित भारत ॥

न कर्म कुरुते वत्सो भृशं दुग्धो युधिष्ठिर।

राष्ट्रमध्यतिदुग्धं हि न कम कुरते महत् ॥ महामारत XII, 87, 20, 21. Translated as"If calf is permitted to suck is grows strong, O Bharata, and can bear (heavy weight) and Pain". Overnuilching is to weaken the calf & consequently harms the nuilcher himself—Dr. Jayaswal-Hindu Polity Page 339.

यो राष्ट्रमनुगृह् वाति परिरचन् स्वयं नृपः।
 संजातसुपजीवन्स लभते सुमहत् फलम् ॥ महाभारत XII 41, 22

४ प्रद्विपन्ति परिख्यातं राजानमतिखादिनन् । उपरोक्त XII 87, 19.

४ मधुदोहं दुहेद्राष्ट्रं भ्रमरा दव पादपम् । उपरोक्त XII 88, 4.

- (५) राज्य को जब कर-वृद्धि करनी हो तो मन्थर गति से उस समय करनी चाहिए जब जनता की समृद्धि भी कमशः श्रग्रसर हो रही हो श्रोर मृदु-पद्धित का श्रनुसरण करना चाहिए ताकि किसी प्रकार का विरोध न हो। १
- (६) कर-संग्रह के लिए उचित स्थान, उचित समय और उचित प्रकार आदि वातों का भी ध्यान रखना अत्यावश्यक है। २ कर-संग्रह का कार्य कभी भी दुःखदायक नहीं होना चाहिए। महाभारत में लिखा है कि गाय को दोहना चाहिए किन्तु उसके स्तनों को कव्ट देना उचित नहीं। ३ (Milch the Cow but do not bore the udders)। ४
- (७) राज्य के विभिन्न त्तेत्रों से कर-संग्रह के विभिन्न सिद्धांत थे। श्रीयोगिक त्तेत्र में उद्योग-कर के लिए महाभारत में लिखा है कि उत्पादन, श्रम तथा लाभ की सम्भावनाश्रों को देखकर ही कर निर्धारित किया जाय ।५ श्रम्यथा श्रम, सम्पत्ति तथा श्रम्य श्रावश्यक तत्वों का ध्यान न रखने पर कर की श्रधिकता के कारण व्यवसाय को त्ति हो सकती है श्रीर श्रम्त में सम्राट को भी हानि होने की सम्भावना है। इसके श्रितिरिक्त श्रीयोगिक त्तेत्र में कलाइतियों के सम्बन्ध में कर-नीति का उदार होना श्रमिवार्थ है। कलाकार के जीवन-स्तर, सामग्री-व्यय श्रादि श्रम्य तत्वों पर भी विचार करना श्रावश्यक है। इ
- (=) श्रायात श्रीर निर्यात के सम्बन्ध में महाभारत में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि श्रायात पर उनके मृल्य, प्राप्तिस्थान की दूरी, श्रायात-व्यय श्रादि का ध्यान रखकर कर निर्धारित करना चाहिए। राज्य के लिए हानिकारक या निष्फल वस्तुश्रों का श्रायात कर-नीति द्वारा ही निरुत्साहित करना चाहिए, जिससे राज्य का धन व्यर्थ की वस्तुश्रों पर नष्ट न हो श्रीर उपयोगी वस्तुश्रों के लिए बचत हो सके ।७ यही सिद्धांत मनुस्मृति द्वारा भी इसी प्रकार से उहिलखितं किया गया है। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि प्राचीन भारत में श्रायात नीति तथा कर-नीति का बहुत गहरा सम्बन्ध था श्रीर राज्य पूर्ण विचार-विमर्श के पश्चात् इसे निश्चित करता था।

महाभारत में वर्णित सिद्धांतों के श्रातिरिक्त मनुस्मृति, श्रर्थशास्त्र एवं शुक्रनीतिसार में भी कर-संग्रह के लिए विभिन्न सिद्धांत दिये गये हैं। उनमें से मुख्य इस प्रकार हैं:—

१ श्रल्पेनाल्पेन देयेन वर्धमानं प्रदापयेत् । ततो भूयस्ततो भूयः क्रमवृद्धि समाचरेत् ॥ दमयन्निव दम्यानि शश्वद्मारं विवर्धयेत् । मृदुपूर्वं प्रयत्नेन पाशानभ्यवहारयेत् ॥ महाभारत ७, ६.

२ न चास्थाने न चाकाले करांस्तेश्यो निपातयेत् । श्रानुपूर्व्येण सान्त्वेन यथा कालं यथाविधि ॥ उपरोक्त

३ वत्सापेची दुहेच्चेंव स्तनांश्च न विकुट्टयेत्। उपरोक्त XII 88, 4.

Y Dr. Jayaswal-Hindu Polity-Page 337.

४ फलं कर्म च संप्रे दय ततः सर्वे प्रकल्पयेत्। फलं कर्म च निर्हेतु न करिचत्संप्रवर्तते ॥ महाभारत XII 87, 16,

६ उत्पत्ति दानवृति च शिल्पं संप्रोत्त्य चासकृत्। शिल्पं प्रति करानेवं शिल्पनः प्रति कारयेत्॥ उपरोक्त XII 87, 14,

७ विक्रयं क्रयमध्वानं भवतं च सपरिव्यवम् । योगन्नेमं च संप्रोदयं विश्वजां कारवेत् करान् ॥ उपरोक्त 87, 13 = तथा मनुस्मृति-सन्तम अध्याय पृष्ठ १२७ ।

- (१) व्यावसायिक वस्तुश्रों पर कर निर्धारित करने के लिए उत्पादन से उत्पादक को स्वयं तथा राज्य को क्या लाभ होता है। इस तत्व को ध्यान में रखना चाहिए। यह सिद्धांत समस्त श्रीद्योगिक दोत्र के सम्बन्ध में व्यवहार्य होना चाहिए।१
- (२) मनुस्मृति के अनुसार राजा की चाहिए कि कय, विकय, मार्ग-व्यय, भता, रचा आदि का व्यय, दुकान, मकान आदि का व्यय सब बातों पर विचार कर व्यापारियों से कर प्राप्त करें।२ जैसे जोंक, बछुड़ा और भौरा अपने भच्य पदार्ध में से थोड़ा-थोड़ा खाते हैं तैसे राजा भी देश से थोड़ा-थोड़ा वार्षिक कर प्राप्त करें। पशुओं के और स्वर्ण के व्यापार में जो लाभ हो उसमें से पचासवां माग, अन्न के लाभ में से आठवां, छठा अथवा बारहवां माग कर-रूप में प्राप्त करें। इन्त, मांस, शहद, घी, सुगन्धित पदार्थ, औषध, रस, फूल, मूल, पल पत्र, शाक, तृरा, चर्म तथा बांस के बने हुए पदार्थ और मिट्टी, पत्थर के पात्रों के साथ में से छठा भाग कर प्राप्त करें। राजा की चाहिए कि धन के अभाव में मियमाण होने पर भी वेदपाठी बाह्मण से कर न ले, उसके राज्य में श्रोत्रिय-ब्राह्मण चुधा से पीड़ित भी नहीं होना चाहिए।३ मनुस्मृति में आगे यह भी व्याख्या की गई है कि शिलिपयों से तथा दूसरे लोगों से किस प्रकार कितना कर संग्रह करना चाहिए और इस कार्य में राजा और प्रजा के बीच परस्पर प्रेम का प्रदर्शन होना चाहिए।
- (३) अर्थशास्त्र के अनुसार लाभदायक आयात कर से मुक्त होना चाहिए तथां हानिकारक आयातों को अत्यधिक आयात कर लगाकर रोकना चाहिए। इसके अतिरिक्त को दुर्लभ वस्तुएं हैं तथा भविष्य में जो राष्ट्र के लिए उत्पादक सिद्ध हो सकती हैं; उन्हें बर-मुक्त कर देना चाहिए।४
- (४) अर्थशास्त्र के अनुसार कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनका निर्यात नहीं होना चाहिए, वरन् कर-मुक्ति द्वारा उनके आयात को प्रोत्साहित करना चाहिए। उदाहरणार्थ; शस्त्र, कवच, लौह, रथ, रत्न, धान्य, पशु, आदि। इसके अतिरिक्त कुछ वस्तुएं ऐसी भी थीं; जैसे सुरा, विदेशी वस्तुएँ आदि। जिन पर कर लगाने के बजाय सहायता पहुँ चाने के सिद्धांत का अनुसरण किया जाता था। वास्तव में कर लाभ पर लिया जाता था, मूल सम्पत्ति पर नहीं। आर्थिक व्यवस्था को स्थिर बनाने के लिए यह अनिवार्य था कि उद्योग में वृद्धि करने वाली वस्तुओं का आयात मोत्साहित किया जाय एवं हानिकारक वस्तुओं के आने को सम्भवतः स्थिगत कर दिया जाय।

मनुस्मृति—अध्याय सप्तम, श्लोक १२८, १२६.

२ उपरोक्त-श्लोक १२७।

३ उपरोक्त-श्लोक १२= से १३३।

४—म्रर्थशास्त्र—दितीय भाग-श्लोक २१ व २४ :—

[&]quot;राष्ट्रपीड़ाकरं भाग्डमुन्द्विन्द्वादफलं च यत्। महोपकारमुच्छुत्कं कुर्याद्वीजं तु दुर्लं मम्॥ (२१)।

५ शस्त्र-वर्म-कवच-लौह-रथ-रत्न-धान्य-पश्नामन्यतममनिर्वाणम्--ऋर्थशास्त्र-भाग २, श्लोक २१ ।

(५) शुक्रनीति के अनुसार एक ही वस्तु पर एक से अधिक वार कर नहीं लगाना चाहिए। १

उपर्युक्त वर्णन से यह सिद्ध होता है कि प्राचीन मारत में कर-पद्धित बहुत ही सामान्य, उचित एवं टोस सिद्धांतों पर आधारित थी। वर्तमान अर्थशास्त्रियों की भाषा में उस समय के अर्थ सम्बन्धी नियमों के निर्माताओं के सामने कर-दाताओं की योग्यता तथा उन पर न्यूनतम भार रखने आदि के तत्वों का पूर्ण महत्व होता था। र भूमि-कर सबसे अधिक महत्व का स्रोत था और उत्पादन के अनुपात से निर्धारित किया जाता था। अन्य प्रमुख साधन विशेष तीर पर व्यापार, यातायात, खानें, नमक, शुल्क, नौकाशुल्क, अर्थद्ग्ड, तथा वन-उत्पादन आदि थे। इसके अतिरिक्त जनता द्वारा वैकल्पिक अनुदान, दान तथा स्वामी-विहीन सम्पत्ति भी राज्य की आय के साधन थे। धातुआं और खानों का राज्य एकाधिकारी था। कीटिल्य के मतानुसार निम्निलिखित साधनों से भी राज्य की आय एकत्रित की जा सकती थी:—

कर-संग्रह ऋधिकारी ग्रामीगों तथा नागरिकों से किसी विशेष व्यवसाय के नाम पर जी वास्तव में विद्यमान नहीं हो, धन संग्रह कर सकता है। इस कार्य में कुछ लोगों से जो विश्वस्त हों खुले रूप में बहुत बड़ी धन-राशियां ऋन्नदान के रूप में ली जा सकती हैं, जिससे कि दूसरे प्रजाजन सम्पत्ति-योग देने में संकोच न करें। गुप्तचरों द्वारा यह प्रचार करवाया जाय कि कम सम्पत्ति देने वाले बाद में पश्चाताप करेंगे तथा सम्पत्तिशालियों से सामर्थ्य के श्रनुसार श्रधिक से श्रधिक स्वर्ण देने की प्रार्थना करें। जो लोग सम्राट को सम्पत्ति द्वारा सहयोग देंगे, वे सम्मानित किये जायेंगे । गुप्तचर मन्दिरों त्रादि संस्थात्रों का धन भी राज्य के लिए एकत्रित कर सकते थे। ऐसे मृतकों की सम्पत्ति जिसको बाहाण भी उपयोग में न ला सकें, काम में ली जा सकती थी। धार्मिक संस्थाओं के अधीचक भी राज्य के समस्त बड़े-बड़े नगरों के देवताश्चों की सब प्रकार की सम्पत्ति को राज्य के कीय के लिए एकत्र कर सकते थे। कभी ऋचानक रात्रि को किसी देवता की स्थापना, यज्ञ की वेदी, ऋषवा साधुआं के लिए किसी पवित्र स्थान की स्थापना श्रथवा किसी श्रश्यभ शकुन की निवृत्ति श्रादि के लिए भी भेंट तथा स्त्रापत्ति-निवारण के लिए जनता ते धन एकत्रित किया जा सकता था। कभी यह घोपणा करके कि सम्राट के उद्यान में अचानक एक बृज् के समय से पूर्व फल श्रीर फूल उत्पन्न हए हैं या यह असत्य प्रचार करके कि नगर के किसी वृत्त में किसी दुष्टात्ना का निवास है (जनिक वास्तव में किसी आद्मी को छुपाकर विभिन्न प्रकार के उपद्रव कराये जावें)। गुप्तचरों द्वारा साधुवेश में सम्पत्ति इक्ही कराई जा सकती थी। या यह प्रचार करके कि एक अनेक मुंह वाला सर्प दिखाया जायगा-उसे देखने के हेतु जनता से धन संग्रह किया जा सकता था । श्रथना गुप्तचर, स्वर्णकार एवं न्यापारियों से जनके न्यवनाय में भागीदार बनकर उनकी अनुचित स्राय को राज्य में ला सकते थे। वेश्या-गुप्तचर सती स्त्री के रूप में चरित्रहीन व्यक्तियों को जाल में फंसाकर उनकी सम्पत्ति का अपहरण कर सकते थे, या दो विप्रही दलों में

१ वस्तुजातस्यैकवारं शुल्कं याहां प्रयत्नतः । शुक्र-चतुर्वं प्रध्याय २ ।

२ वनजी-Public Administration in Ancient India. Page 180.

एक की विषयान कराकर दूसरे पर विष देने का अभियोग लगाकर सब की सम्पत्ति राज्य के लिए प्राप्त की वा सकती थी। १ इस प्रकार कोटिन्य द्वारा राज्य का कीप पूर्ण रखने के लिए को साधन प्रतिपादित किये गये हैं वे अनुचित एवं अनैतिक प्रतीत होते हैं। हा॰ जोशी का मत है कि कीटिल्य ने कर संग्रह के लो साधन बताये हैं, वे धर्मशास्त्रों के विरुद्ध, अनैतिक एवं श्रतुचित हैं। किन्तु श्री दीचितार का मत है कि ये कर, यद्यपि धीखे से संग्रह किये जाते प तथापि अनेक कारणों से इन्हें अनुचित नहीं माना जा सकता। उदाहरणार्थ, कीटिल्य का अंथ राजतंत्र पर व्यावदारिक नियमावली के रूप में है। इसलिए श्रावश्यकतानुसार कर संबद्द के प्रकार साधारण स्थिति में अनुचित प्रतीत होते हुए भी श्रत्यन्त श्रावश्यकता की स्थिति में उचित सिद्ध होते हैं। दूसरे दान अनुदान लेना, दानशील संस्थाओं के दुरुपयोग में आने वाले धन को प्राप्त करना, जनता से मनोरंजन द्वारा, दुश्वरित्रों से द्वड द्वारा धन एकाधत करने के साधन अनुचित नहीं हो सकते और वे भी गम्भोर आवश्यकता के समय। तीसरे, यज्ञ, दुष्टातमा की घोषणा त्रादि के द्वारा भी जनता का मनोरंजन ही हाता था। चौथे, स्वर्णकार तथा इसी प्रकार के अन्य व्यवसाय वाले लोग अनुचित एवं अशुद्ध दंग से धनीपा-र्जन करते हैं। मनु ने ऐसे लोगों को दिन के ठग कहा है। कीटिल्य भी इस अनुचित धन से उन व्यक्तियों को वंचित करने के लिए इस प्रकार कि साधन प्रस्तावित करता है, जो उचित ही था। पांचवें कौंटिस्य के समय की परिस्थिति में ये साधन अनुचित नहीं कहे जा सकते । ऐसे लोगों को दण्डित किये निना राज्य में शांति एवं मुरद्या सम्भव नहीं थी । मनु ने भी ऐसे लोगों को राज्य के मार्ग में कांटे चताया है, जिन्हें किसी भी मूल्य पर दूर करना भाहिए ।२

इस प्रकार कीटिल्य द्वारा प्रस्तावित सिद्धांत इस श्राधार पर उचित माने डा सकते हैं कि श्रावश्यकता श्राविष्कार की जननी है, श्रायवा ''श्रापितकाले भयांदा नास्ति।'' किर कीटिल्य ने स्वयं यह लिखा है कि उपाय केवल दुष्ट एवं श्राचारभष्ट लोगों के प्रशि स्थवहार में लाये जायं, दूसरे लोगों के प्रति कदापि भी नहीं। यास्तव में यह उपाय नियम नहीं, श्रापवाद थे।

गज्य ग्रास संग्रहीत सम्पत्ति का व्यय दो हवों में किया जाता था। प्रथम, नित्य की ध्यावश्यकताओं की पूस करने के लिए तथा दूसरे, जनमेवा के दन कार्यों के लिए जी दीर्य- काल में लाकर लामदायक होने वाले हैं। शुक्रनीतिमार के खतुसार यह व्यय दी नामीं के पुरास जा सकता था, एक, लामान्य व्यय तथा इत्या, उत्पादक-व्यव (Ordinary Consumption & Productive Consumption)। पहले प्रकार के व्यय में मसाजित- व्यव, रिनवास का व्यय, मीजनालय, दीधन, पतन, चिहियापर, मेना, मसुसाला खादि अधिनित्त हीते थे। युक्ती प्रकार के व्यय में से कार्य निम्नित हीते थे, जो भीने समय बाद नाव्य के लिए विशेष क्षाय के साथन बाद वीने विनाई खादि।

रे किन शास्त्र-न्यत रेक्ट्रेन्स्बर् ह

z - Alforet - Hinds Administrative Institutions-Pages 191-184.

इस प्रकार प्राचीन भारतीय राजनीति में कर सिद्धांत स्वीकार किये गये थे। यदि सम्राट सुरच्या नहीं कर सकता था तो उसे कर-संग्रह का ग्राधिकार भी नहीं था। कुछ लोग सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक एवं मानवीय ग्राधारों पर कर से मुक्त किये जाते थे। जनता का धन जनता के हित के लिए ही उपयोग में लाने का एक माना हुन्ना सिद्धांत था। इससे यह ज्ञात होता है कि प्राचीन भारत के राज्य वास्तव में लोक-कल्याणकारी राज्य की विशेष-तान्नों से सुक्त थे।

प्रश्त

1. Comment upon the sources of revenue and principles of taxation in ancient India.

सोलहवां ग्रध्याय

अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध

(Inter State Relation)

प्रस्तावना: - यह वर्णन पहले किया जा चुका है कि राज्य की धारणा में सात श्रंग सम्मिलित होते हैं और मित्र उनमें से एक है। अन्य अंगों में स्वामी (Sovereign) भी महत्वपूर्णं अंग हैं। जिस प्रकार आधुनिक राजनीतिक सिद्धान्तों में राज्य की सार्वभौमिकता एक स्वीकृत सिद्धान्त है श्रीर उसके समस्त श्रांतरिक एवं बाह्य रूपों का विश्लेषण किया जाता हैं, उसी प्रकार प्राचीन भारत में भी यह तत्त्र पूर्ण रूप से स्वीकार किया गया था। निकटस्थ एवं दूरस्य देशों में से मित्र राज्यों को राज्य का आवश्यक आंग माना जाता था और राज्य की सार्वभौम सत्ता की मान्यता भी हर प्रकार से पूर्ण थी। प्रत्येक राज्य आंतरिक रूप में तो स्वतन्त्र होता ही था, बाहा रूप में भी उसका स्वतन्त्र होना त्रानिवार्य था। इसी स्थिति का स्पन्टीकरण उस सिद्धान्त से होता है जिसे प्राचीन काल में "मग्डल सिद्धान्त" (Theory of circle of states) कहा जाता था। इसे प्रभाव मण्डल Sphere or Influence) स्वातन्त्र्य सिद्धान्त (Doctrine of Independence, स्वराज्य या श्रपराधीनत्व का सिद्धान्त), अथवा हित-सिद्धान्त (Doctrine of Interst or Enterprize) भी कहा जाता था। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सार्वभौमिकता उस समय तक पूर्ण नहीं मानी जाती थी जब तक भीतरी एवं बाहरी रूप से विद्यमान न हो । साथ ही राष्ट्रीय परिवार में प्रत्येक देश के संबंध भी बहुत महत्वपूर्ण समके जाते थे। उन्हीं को निर्धारित करते हुए यह मण्डल सिद्धान्त-प्रतिपादित हुआ था वास्तव में ऋ तरिष्ट्रीय संबंधों के चेत्र में यह हिन्दुऋों के शक्ति-संतुलन (Balance of Power) के सिद्धान्त का न्यावहारिक रूप था। इस सिद्धांत की व्याख्या श्रर्थशास्त्र, महाभारत, मनुस्मृति, कामन्दक तथा शुक्रनीतिसार श्रादि सभी प्राचीन प्रथों में की गई है। प्राचीन भारत में अनेक स्वतन्त्र राज्य विद्यमान थे और उनके परस्पर संबंध अधिकांश मण्डल सिद्धान्त की दिशा में संचालित होते थे।

प्राचीन द्यांतर्राष्ट्रीय संबंध: -डॉ॰ ब्रल्टेकर के मतानुसार प्राचीन भारत में विभिन्न देशों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन दो भागों में बाँटा जा सकता है: -(१) युद्धकालीन संबंध एवं (२) शांतिकालीन संबंध ।१ वास्तव में युद्ध ख्रीर शांति के समय में विभिन्न राष्ट्रों के बीच संबंधों में परिवर्त्तन तो होता है, परन्तु इस प्रकार का स्पष्ट विभाजन फिर भी संभव नहीं -

१ डॉ॰ अल्टेकर—State and Government in Ancient India-Page 286.

होता। प्राचीन भारत में नैदिक काल में ये संबंध अधिकांश शांतिमय थे; क्योंकि उस समय राज्य अधिकांश प्रारम्भिक रूपों में ही संचालित हो रहे थे। परस्पर प्रतिस्पर्धा के कारण कभी-कभीसंघर्ष हो जाते थे। उत्तरवैदिक काल में भी राज्यों के आकार-प्रकार एवं कार्यसेत्र अधिक विस्तृत नहीं हुए थे। धर्म ऋौर संस्कृति राज्यों के जीवन में प्रधान रहती थीं। वाजपेय ऋौर त्रप्रवमेध यज्ञों की परम्परा प्रचलित हुई, जिससे एक राज्य त्रपना चड़प्पन स्थापित कर त्रप्री-नस्थ चेत्रों की सीमाए निर्धारित करता था। जब किसी सम्राट या राजा की सेनाए हु एवं साम्राज्य समृद्धिशाली होता था तत्र वह ग्रापने विस्तार की योजना बनाता था। युद्धसंत्रंघी वर्णन करते हुए मनुस्मृति में लिखा है कि जब अपनी सेना को मन से प्रसन्न और अन्न से पुष्ट समभे तथा शत्र की सेना को उसके विपरीत समभे; तब शत्रुत्रों के ऊपर चढ़ाई करे। १ इस प्रकार प्राचीन धर्मशास्त्रों में भी समय और स्थिति के अनुसार विस्तार करना न्यायोचित समभा गया था। युद्ध का पूर्ण रूप से त्याग संभव नहीं समभा गया था। यद्यपि अशोक त्रादि हिन्दू सम्राटों ने ऐसे प्रयोग किये हैं; किन्तु राज्य की सुरज्ञा के लिए सैनिक तैयारी सदैव श्रावश्यक रहती थी। इसी दृष्टि से प्राचीन भारत में समस्त ज्ञिय वर्ग को यही कार्य सींपा गया था स्त्रीर वे सदैव युद्ध के लिए सन्नद्ध रहते थे ।२ इस स्थिति का पूर्ण स्त्रनुभव करने के पश्चात् ही प्राचीन भारतीय दार्शनिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि पूर्ण रूप से युद्ध का परि-त्याग तो नहीं किया जा सकता, पर उसकी संभावना को न्यूनतम बनाया जा सकता है। इस उद्देश्य से विभिन्न राज्यों के बीच न्यायिक शिक्त-संतुलन की दृष्टि से धर्मशास्त्रों ने मण्डल सिद्धान्त प्रतिपादित किया था । प्राचीन भारतीय शासक जैसे त्र्यांतरिक शांति चाहते ये: उसी प्रकार राष्ट्रसंघ या राष्ट्र परिवार में भी शांति की स्थापना चाहते थे शक्त्रों का सहारा न्यूनत म लिया जाय, यह सिद्धान्त स्वीकार किया गया था। महाभारत में लिखा है कि "श्रधार्मिक युद्ध इस जीवन में श्रापयश तथा दूसरे जीवन में नरक देने वाला होता है ।३ इसलिए प्राचीन भारत में युद्ध की श्रीत्साहित न करते हुए यह 'मण्डल सिद्धान्त' स्वीकार किया गया था।

मण्डल सिद्धान्त—इस सिद्धान्त के साथ दो मान्यताएँ स्वीकार की जानी चाहिए। प्रथम—ऐसे शासक की विद्यमानता जो विजय की आकांचा करता हो और द्वितीय यह कि पड़ीसी राष्ट्र से अधिकांश अच्छे संबंध नहीं होते। पहली मान्यता के संबंध में अधिक सन्देह नहीं होता, किन्तु दूसी मान्यता में "पड़ौसी राज्य शत्रु ही होता है' सन्देह है। वास्तव में यह शाश्वत सत्य नहीं हो सकता कि पड़ौसी राष्ट्र शत्रु ही रहें; किन्तु इसकी संभावना अवश्य रहती है। इतिहास का अनुसरण करें तो ऐसे उदाहरण अवश्य उपलब्ध है कि जहाँ पड़ौसी राष्ट्रों में लगभग वैमनस्य ही अधिक रहा है। फ्रांस एवं जर्मनी, रूस एवं पोलैंड, चीन एयं जापान, आदि ऐसे ही उदाहरण हैं जिनके बीच शत्रुता ही अधिक रहा है। अतः दोनों

१ यदा मन्येत भावेन हुप्टं पुष्टं वलं स्वकम् । परस्य विषरीतं च तदा यायाद्रिपुं प्रति ॥१७१॥ मनुरमृति-सप्तम अध्याय ।

२ अवर्मः सनियस्यैष यन्द्रयामर्णं भवेत् । शुक्रनीतिसार, चतुर्धं अध्याय, श्लोक ७ ॥

३ अवर्शयुक्ती विजयोद्धाय बोडस्वर्ग्य एव च ॥ महाभारत, १२ अध्याय ६६ । As quoted by Dr. Altekar—State & Government in Ancient India-Page, 288.

मान्यताएं अनुभव के आधार पर उचित सिद्ध होती है। मण्डल सिद्धांत में विभिन्न गंथों ने बहुत सुन्दर ग्रादर्श उपस्थित किया है। तदनुसार ग्रांतर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के चेत्र में "शिक्त-संतुलन" का यह हिन्दू सिद्धांत वास्तव में "विजिगीयु-सिद्धांत" (Doctrine of Aspirant to conquest) पर त्राधारित हैं। यह एक विकास वृत्ति (cult of expansion) अथवा पुरुषत्व के सिद्धांत (Ethics of manliness) से संबंधित है। महाभारत के ऋतुसार इस सिद्धांत का श्रर्थ निरंतर प्रगति की श्रोर श्रग्रसर होते रहना-बरावर ऊपर चढ़ना, गिरना अथवा सुकना नहीं। जीवन की बाजी लगाकर भी ऐक्वर्य प्राप्त करना ही जीवनका उद्देश्य होना चाहिए।। इस प्रकार यह सिद्धांत अस्तित्व के लिए संघर्ष (Struggle for existence) की आवश्यकता सिद्ध करता है । इसके द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय चेत्र में संतुलन अथवा वस्तुहियति (Equilibrium and abatus-quo) सदैव ही परिवर्तनशील रहनी चाहिए । कौटिल्य के मतानुसार प्रत्येक राज्य की यह आकांचा होती है कि अपनी जनता के लिए शक्ति और मुख का संचय करे। कामंदक भी विजय की त्राकांचा (Aspiration to Conquer) प्रत्येक राज्य के लिए अनिवार्य बताता है। सम्राट की मण्डल का स्वामी अथवा नामि (Centre of gravity) के रूप में स्थापित करना चाहिए और उसके पश्चात् चन्द्रमा की भांति अपने चारों ओर पूर्ण मराडल की स्थापना करना उसका कर्तव्य है। यह मगडल ही अरि (Enemy), सित्र (Ally) मध्यम (Neutral), तथा विजिगीनु (Aspirant) से सम्बन्धित राज्य-मग्डल (Circule of states) है। अपने विस्तार एवं विजय के मार्ग की सब रकावटों को दूर करने के लिए सम्राट को चाहिए कि श्रपने समस्त परिजनों की सहायता प्राप्त करे क्योंकि विप का दमन विष से होता है। हीरे से ही हीरा कटता है एवं हाथी से ही हाथी। वश में आता है। इसलिए मण्डल सिद्धांत का उपयोग वांछनीय है। कामंदक ने स्पष्ट लिखा है कि कोप श्रीर दण्ड से युक्त मण्डल का ऋधिपति महाराजा श्रमात्य श्रीर मंत्रियों के सहित दुर्ग में स्थिति करके अच्छे राजमण्डल के विषय का विचार करे। अखराडमराडल वाले चन्द्रमा के समान वह सन प्राणियों से शोभित होता है (शशीवाखण्डमण्डलः) इस कारण जीतने की इच्छा वाला सम्पूर्ण मण्डल से युक्त रहे ।२ इस सिद्धांत के समर्थन में भीष्म ने कहा है कि श्रधिकार वहीं है जिसे शिक्तशाली व्यक्ति श्रधिकार समभता है और विजय ही अधिकार का श्राधार है । मनुस्मृति के अनुसार मध्यम बलशाली राजा के आचरण, जीतने की इंच्छा वाले राजा श्रीर उदासीन तथा शत्रु राजा के समाचार को प्रयत्नपूर्वक जानते रहना प्रत्येक राजा के लिए ग्रानिवार्य है। ३ शुक्रनीतिसार में किसी भी राज्य के शत्रु-मित्रों की व्याख्या करते हुए भविष्य में संपर्व की दृष्टि से शक्ति-संतुलन तथा परिस्थितियों की उत्पति का बढ़ा सुरदर वर्णन किया है। तदनुसार ज्यों ज्यों शत्रु केन्द्र से दूर होता जाता है उसका महत्व भी कम होता जाता है

Mahabharat Characterizes it as the consisting in seaseless upward striving - "To press only up." "Bend not," "Elect glory even at the cost of life"—Sarkar-Hindu Political Institutions.

२ बामंदक-प्रष्टम सर्ग-श्लोक १, ३ एष्ठ ७=, ७६ ।

३ मन्दरमृति—सप्तम् अध्याय-रलोक १४४।

श्रीर स्थान की दूरी के साथ द्वेष, घृणा तथा प्रतियोगी भावना भी स्वाभाविक रूप से कम हो जाती है। इसलिए कोई भी राज्य शत्रु, उदासीन, या मित्र समका जाय यह दूरी पर निर्भर करता है। शुक्रनीति के अनुसार प्रत्येक राज्य के समीप सर्वप्रथम शत्रु राज्य होते हैं, उसके पश्चात् मित्र राज्य, तत्पश्चात् मध्यम राज्य श्रीर श्रन्त में श्रत्यन्त दूरी पर पुनः शत्रु राज्य होते हैं। कौटिल्य श्रीर कामंदक के श्रनुसार भी श्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध के चित्र में यही सिद्धांत व्यवहार में श्राते हैं। इस सिद्धांतानुसार विजिगीपु एवं श्रीर के मध्य में निरन्तर संवर्ष पिष्ठ of war) चलता रहता है। उपर्युक्त (मण्डलचतुष्क) चतुर्वर्ग निम्नलिखित रूप में स्वीकार किया गया थाः—

- (१) विजिगीपु:-सप्तप्रकृतिक राज्य से युक्त उत्साहवान् श्रमी राजा निरन्तर जीतने की इच्छा करने वाला विजेता अथवा विजिगीपु कहलाता है ।१
- (२ श्रिरि:-विजिगीपु के राज्य की सीमा पर कहीं भी स्थित राज्य का ग्राधिकारी श्रिरि कहा जाता है।
- (३) मध्यम:-वह राज्य होता है जो विजिगीय ख्रौर ख्रिर दोनों के समीप स्थित हो तथा जो इन दोनों को पृथक-पृथक सहायता देने ख्रथवा विरोध करने के योग्य हो ।
- (४) उदासीन:-वह राज्य होता है जो उपर्युक्त तीनों के पश्चात् स्थित हो। साथ ही बहुत शिक्तशाली हो जो विजिगीषु, ऋरि एवं मध्यम को एक साथ या पृथक-पृथक सहायता देने के योग्य हो ऋथवा पृथक-पृथक उनमें से प्रत्येक का विरोध कर सके।

उपर्युक्त चारों राज्य अन्तर्राष्ट्रीय च्लेत्र में प्रथम मगडल की रचना करते हैं। विजिगीपु की दृष्टि से समस्त राज्य या तो उसके मित्र हैं अथवा उसके शत्रु राज्यों के मित्र हैं। ऐसे राज्यों की संख्या आठ हो सकती है और मध्यम और उदासीन के साथ इन राज्यों की संख्या दस हो जाती है। कौटिल्य और काम दक के अनुसार इन राज्यों का क्रम निम्नलिखित होता है—

- (१) विजिगीषु (Aspirant)।
- (२) 羽र (Enemy) 1
- सम्मुल—(Frontward) (३) मित्रम् (Ally of aspirant) ।
- (४) ग्रिर मित्रम् (Enemy's ally)।
- (५) मित्र मित्रम् (Aspirant's ally's ally)।
- (६) श्रिर मित्र मित्रम् (Ally of Enemy's ally)।
- पीछे की स्रोर—(Rearward) (७) पार्विसमाह (rearward enemy)।
- (=) श्राकन्द (Rearward ally)।
- (६) पार्टिणप्राहासार (Ally of Rearward enemy) ।
- (१०) ग्राकन्दासार (Ally of the Rearward ally)।

इस प्रकार उपयुक्ति दस राज्यों का एक पूर्ण दशक-मगडल निर्मित होता है श्रीर मध्यम श्रीर उदासीन की मिलाकर बारह राज्यों का मगडल बनता है। यह शुक्राचार्य का

१ कामंदक-श्रष्टम सर्ग-श्लोक ६ पृष्ठ ७६।

मत है। १ इसमें विजिगीषु सारे मण्डल का केन्द्र होता है। इन बारह राजाओं में ही शत्रु और मित्रों के पृथक-पृथक मेद से मनु ने इसको छुन्बीस राजाओं का मण्डल माना है अर्थात् वारह शत्रु, बारह मित्र, दो उदासीन और मध्यम। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार से विचार करने पर कई प्रकार के मण्डलों का निर्माण होता है। बृहस्पित ने अव्टादशक मण्डल (१० का मण्डल), विशालाज्ञ ने चौत्रन प्रकार का मण्डल, तीन सौ चौबीस का मण्डल आदि का वर्णन किया है। २ शत्रु का चर्छद्शक मण्डल, विजिगीषु के छु; प्रकार के मण्डल-प्रटक तथा छतीस प्रकार संहतीक मंडल, एक विशालक मण्डल (इक्कीस), अव्टक मण्डल, पिटिसंजक मण्डल, त्रिशत्कमण्डल, आदि अनेक प्रकार के मण्डलों का वर्णन मिलता है। ३ कौटित्य के मतानुसार प्रथम चतुष्क मण्डल के प्रत्येक राजा के द्वादश मण्डल के आधार पर क्रमश: ४० राज्यों का मण्डल बनता है, मध्यम और उदासीन के मण्डल को सम्मिलित करने पर ७२ राज्यों का मण्डल बनता है और इसी प्रकार द्वादश मण्डल के प्रत्येक राजा के द्वादशमण्डल को सम्मिलित करने पे १४४ राज्यों का मण्डल भी बन सकता है। जेसे दण्डनीति प्रजा के 'मतस्य न्याय' को समाप्त करती है उसी प्रकार यह 'मण्डल-सिद्धांत' भी मानव समुदाय में निहित 'मतस्य न्याय' अथवा गृहयुद्ध को समाप्त करने में समर्थ होता है।

साधारणतया मण्डल सिद्धांत सत्य होता है किन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि यह सदेव सत्य सिद्ध होगा। साथ ही यह कहना भी कठिन है कि यह हमेशा असत्य सिद्ध होगा। विभिन्न राज्यों के सम्बन्ध अधिकांश परिस्थितियों के अनुसार निर्धारित होते हैं। इसलिए मित्रता एवं शत्रुता के सम्बन्ध में कोई रूढ़िगत नियम स्वीकार नहीं किया जा सकता।

षाड्गुण्यम् (Sixfold incidents):—प्राचीन काल में विभिन्न राज्यों के बीच के सम्बन्ध मुख्य रूप से छ: विभिन्न प्रकारों से निर्धारित होते थे, जिन्हें षाडगुण्यम् कहते थे। कौटिल्य के मतानुसार मण्डल सिद्धांत ही षाडगुण्यम् का मुख्य स्रोत है। ये छ: सिद्धांत निम्नलिखित हैं:—

- (१) संधि (Peace) ।
- (२) विग्रह (War) ।
- (३) श्रासन (Mainting apost against an enemy or observance of neutrality)।
- (४) यान (Marching or Preparedness for attack)।
- (५) समश्रय (Alliance)।
- (६) है तभाव (Double dealing or duplicity)।
- (१) संधि (Pence): काम दंक के अनुसार जन राजा बलवान शत्रु से श्राकांत हो जाय और कोई उपाय न समें, तन विपद्यस्त हो काल व्यतीत करता हुआ संधि कर ले,कपाल,

१ उदासीनो मध्यमश्च विजिगीषोस्तु मण्डलम् । उशना मण्डलमिदं प्राह द्वादशराजकम् ॥ काम दक-श्लोक २२ पृष्ठ ५२ ।

२ काम दक-श्रष्टमसर्ग-पृष्ट = इ से = ५ तके।

इं उपरोक्त।

उपहार, सन्तान, संगत, उपन्यास, प्रतिकार, संयोग, पुरुषांतर, अदृष्टनर, आदिष्ट, आत्मामिश, उपग्रह, परिक्रय, उच्छिन्न, परिभूषण, और स्कन्धोपनेय, कुल सोलह प्रकार की संधि कुशल नीतिज्ञों ने स्वीकार की है। बराबर वाले से मेल करने का नाम कपाल संधि है। द्रव्य से होने वाली उपहार संधि, कन्यादान करने से संतान संधि, अंष्ठों के साथ मित्रता संगत संधि (इसे काञ्चन संधि भी कहते हैं), अंष्ठ कार्य की सिद्ध के लिए उपन्यास संधि, परस्पर उपकार चुकाने के निमित्त प्रतिकार संधि (राम-सुग्रीव की संधि), एक अर्थ के उद्देश्य से गमन करते हुए अचानक होने वाली संयोग संधि, दोनों के मुख्य योद्धाओं से हमारा प्रयोजन सिद्ध हो ऐसा जिसमें प्रण किया जाता है वह पुरुषांतर संधि, जहां किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा शत्रु का विरोध कराया जाय वह अदृष्टपुरुष संधि, पृथ्वी का कुछ आंश देकर आदिष्ट संधि, अपनी सेना से आत्मामिश संधि, प्राणस्क्षा के लिए सर्व स्वदान द्वारा उपग्रह संधि, कोप के आंश या सर्व स्व द्वारा प्रजा की रत्ता के लिए परिक्रय संधि, उपजाऊ भूमि के देने से उच्छिन्न संधि, पृथ्वी से उत्पन्न सब अन्न, फलादि के देने से परिभूषण संधि, तथा जहां थोड़े फलादि थाली में रखकर कंधे पर ले जाकर भृत्य जन देते हैं, उसे स्कन्धोपनेय संधि कहते हैं। इनमें से परस्पर उपकार, मित्रता, सम्बन्ध और भेंट ये चार संधि विशेष रूप से मानी गई हैं। १

कौटिल्य के मतानुसार संधियां मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं:--

(१) काल संधि (Temporary)।

17

(२) स्थावर संधि (Permanent ।

ं संधियों की सूची में कौटिल्य ने भी विशद वर्णन दिया है, किंतु उसने मित्र संधि, हिरएय संधि, भूमि संधि, कर्म संधि, श्रीर श्रन्नविस्त संधि मुख्य बताई हैं। इन संधियों के प्रयोग द्वारा श्रन्तर्शव्द्रीय सम्बन्ध संचालित होते थे।

- (२) विश्रह (War):-शिवतत्व रत्नाकर में विश्रह आठ प्रकार के बताये गये हैं:-
- (१) काम-विग्रह (जहां विग्रह का कारण स्त्रियां होती हैं)।
- (२) लोभज (जो लोभ के कारण उत्पन्न हो)।
- (३) भू-विग्रह (जहां भृमि के कारण निग्रह हो)।
- (४) मान सम्भव (जहां मानभंग होना विग्रह का कारण हो)।
- (५) श्रमय-(जहां मित्र श्रथवा सम्बन्धियों के लिए विश्रह हो) ।
- (६) इच्छुज (जहां त्राकाँचा के कारण विग्रह हो)।
- (७) मदोहिका (जहाँ केवल मूर्खता श्रयवा जिह के कारण विग्रह हो।।
- (प) एकद्रव्यामिलापा (नहां एक विशेष उद्देश्य के कारण विग्रह हो)।

शास्त्रानुसार सम्राट को सोलह प्रकार के विग्रह टाल देने चाहिए। इनका प्रयोग अन्तर्राष्ट्रीय चेत्र में पर्याप्त मात्रा में होता था।

(३) श्रासन—कुछ विद्वानों के श्रनुसार श्रासन का श्रर्थ उदासीनता श्रयवा तटस्थता होती है। किन्तु श्रासन का श्रर्थ शत्रु के विरुद्ध एक निश्चित स्थान प्राप्त करना उपयुक्त पड़ता

१ काम दक-नवमसर्ग-श्लोक १ से २०।

है। आसन भी शास्त्रों में दस प्रकार के माने गये हैं:—स्टस्थान, उपेना, मार्गरोध, दुर्गसाध्य राष्ट्रस्वीकर्ण, रामनीय, निकटसन, दुर्गमार्ग, प्रलोपशन एवं पराधीन। इन विभिन्न प्रकार के आसनों का प्रयोग होता रहता था। पुराणों की कथाओं एवं अनेक ग्रंथों की घटनाओं में इनके प्रसंग यदा-कदा मिल ही जाते हैं।

(४) यान: — उत्कृष्ट, विजयाकां ज्ञी, जयशील, प्रकृति के गुणों में अनुरक्त राजा की यात्रा यान कही जाती थी। युद्ध के लिए मिलकर, एकत्र होकर, प्रसंग से एवं उपे ज्ञा से यह पाँच प्रकार का यान (चढ़ाई) विद्वानों ने स्वीकार किया है। इन्हें कमशः विग्रह्मयान संधायगमन, संभूयगमन, सम्भूययान, प्रसंगयान तथा उपे ज्ञायान भी कहते हैं। १

गरापित शास्त्री के मतानुसार शिक्त, देश श्रीर काल का ध्यान रखते हुए यान निम्न सात प्रकार के माने गये हैं:-संधानज, पार्श्वनिरोध, मित्रविग्रहणी, द्वन्द्वजा, निर्धाल, कुलय एवं शीष्रगामिनी। कौटिल्य ने भी यान की उपयोगिता के संबंध में सुन्दर वर्णन किया है।

- (४) समश्रयः साधारणतया इस शब्द का अर्थ सहायता या समर्थन से होता है किन्तु कुछ विद्वान इसका अर्थ मित्रता रूप में भी लेते हैं। व्यापक हिट से इसका अर्थ अपने मित्रों से सहायता की अपेक्षा करना होता है। इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन उपलब्ध नहीं होता, किन्तु यह उपाय भी प्राचीन काल में प्रचलित अवश्य रहा है। इसमें सन्देह भी नहीं है।
- (६) द्वेतमावः—डा० शामशास्त्री के अनुसार इसका अर्थ है एक से संधि तथा दूसरे से युद्ध करना। श्रीमूलम् मीमांसा के अनुसार इसका अर्थ हैं केवल वाणी द्वारा दो शतुओं में विश्वास उत्पन्न करने की ऐसी नीति जो केवल प्रकट रूप में हो। वास्तव में गुप्त रूप से शतुवत् व्यवहार करते रहना, द्वैतमाव है। कामंदक के मतानुसार बली शत्रुओं के मध्य में वाणी से अपने की समर्पण करता हुआ, काक के नेत्र के समान कभी किसी को कभी किसी को देखता हुआ है धीमाव से बरते कि किसी को प्रतीत न हो। उसे हैं त भाव कहते हैं। यह स्वतन्त्र और परतन्त्र दो प्रकार का होता है। दूसरे शस्त्रों के अनुसार द्वैत भाव पांच प्रकार का माना गया है।
 - (१) मिथ्याचित्त-हृद्य से घृणा किन्तु ऊपर से मित्रवत् व्यवहार ।
 - (२) मिथ्या वचन संजना:-मिरतष्क में अन्य वात होना और उसके विपरीत भाषण करना ।
 - (३) मिथ्याकरण:—ऐसां काम करना जो ऊपर से हितवद्ध क प्रतीत हो किन्तु वास्तव में हानिकारक हो।
- । ४) उभयवेतन:—अपने स्वामी की सेवा में रहते हुए उसके शत्रु से गुप्त रूप से अनुचित वेतन स्वीकार करना।
- (५) युग्मप्रभर्त कः दूसरे व्यक्ति के सहयोग के लिए धन श्रौर जन एकत्रित करने का बहाना करते हुए अपने उद्देश्यों की पूर्ति करना।

१ काम दक-एकादश सर्ग. श्लोक •१।

२ उपरोक्त-श्लोक २४,२७।

सम्राट उस नीति का पालन करता था जो उमके एवं राज्य के लिए ऋत्यन्त लाभ-दायक होती थी, राज्य को विनाश एवं पतन से बचाती थी। राज्य की रज्ञा करना शासक का परम धर्म था और इसीलिये युद्ध तक भी करना पड़ता था, किन्तु युद्ध सदैव ऋन्तिम साधन के रूप में काम ग्राता था। कौटिल्य का मत है कि यदि शांति एवं विग्रह का प्रभाव समान हो तो शांति मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। युद्ध तभो करना चाहिए जब कूट-नीति के चारों (साम, दाम. भेद एवं दण्ड) साधन श्रासकल हो जायें। इस प्रकार ये युद्ध-कालीन ग्रांतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध का च्लेत्र माना जाता था और उपर्युक्त साधन एवं प्रणालियां व्यवहार में श्राती थीं।

इसके अतिरिक्त शांतिकालीन अंतरीष्ट्रीय संबंधों के विषय में भी बहुत सामग्री प्राप्त होती है। वास्तव में राज्य की समृद्धि एवं प्रगति के लिए शांति स्थापना अनिवार्य है ग्रीर शांति के समय में विभिन्न राज्यों के परस्पर व्यवहार भी अधिक मुक्त रूप से होते हैं। ये संबंध अधिकांश राज्यों के प्रतिनिधियों को परस्पर एक दूसरे राज्य में भेजकर व्यवस्थित किये जाते थे। इन प्रतिनिधियों अर्थात् राजदूतों आदि का विस्तृत विवेचन हम अगले अध्याय में करेंगे।

प्राचीन काल में राजा लोग अपने सामन्तों के प्रति भी एक निश्चित नीति का पालन करते थे। सामन्तों को पालकी, हाथी रखने आदि की कुछ सुविधाएँ मिल जाती थीं श्रीर पाँच प्रकार का वाद्य-यंत्रों (शृंग (Horn), शांख, भेरी (Drum) जयत्रएट, एवं टमटा) की रखने का अधिकार भी दिया जाता था और इसीलिए इन्हें महाराजा, सामन्त, महासामन्त, मगडलेश्वर ग्रादि की उपाधियों से विभूषित किया जाता था। मध्यकाल में सामन्त वर्ग सम्राट को सम्राज्ञिय श्रिभयानों में सैनिक सहायता देने थे। श्रन्य उत्सवीं श्रादि पर साम्राज्य की शोभा बढाने में हर प्रकार से सहयोग देते थे। अपने-अपने चेत्रों में ये सामन्त लगभग श्रांतरिक-स्वतन्त्रता का उपभोग करते थे। छोटे सामन्त स्वाभाविक रूप से कम स्वतंत्र होते थे। बहुत ऋहल्प संख्या में ऐसे सामन्त होते थे जिन पर कठोर नियन्त्रण होता था ऋीर समय-समय पर हस्तत्त्रेप भी किया जाता था। सामन्ती विद्रोह की घटनाएँ भी हुआ करती थीं किन्तु परास्त हो जाने पर उन्हें बहुत अप्रमान सहने पड़ते थे। कभी-कभी ती, विजेता की घुड़शाला की सफाई का कार्य पराजित सामन्तों को करना होता था और कीप, अश्व, हायी. आदि सब साधन समर्पण कर देने होते थे। यदि सम्राट दुर्बल होता तो सामन्त लोग स्वतंत्र भी हो जाते थे। केवल नाम के लिए सम्राट के प्रति श्रौपचारिक कार्यवाही करते रहते थे, श्रपना त्रार्थिक योग (Tribute) अनियमित रूप में देने लगते थे, श्रीर धीरे-धीरे वे पूर्ण स्वतंत्र वन जाते थे। सामन्ती युग का यह इतिहास बहुत विचित्र सा रहा है। इसी ग्रस्थिर व्यवस्था के कारण उस समय फोई निश्चित संस्था. नियम या व्यवस्था नहीं पनप पाई ।

इस प्रकार ऋन्तदे शीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों के चेत्र में प्राचीन भारतवर्ष बहुत श्रागे बड़ा हुआ था श्रीर विदेशों संबंधों के विषय में विभिन्न प्रकार के बैशानिक सिद्धान्त एवं व्यवहार के नियम प्रचलित हो चुके थे। जिनका विवेचन त्राज के युग में भी कुछ सीमा तक उपयोगी तथा पूर्ण रूप से ग्रध्ययन के लिए रुचिकर सामग्री उपस्थित करता है।

प्रश्न

- Discuss the doctrine of Mandala (Circle of states) and add a short 1. note of appreciation.
- Discuss the basis and principles of Inter-State relations in ancient India. 2.

सतरहवाँ ग्रध्याय

कृटनीतिक सिद्धान्त और व्यवहार

(Diplomacy-Theory and Practice)

प्रस्तावनाः—ऋधिनिक समय में विभिन्न देशों के पारस्परिक संबंध एक अनिवार्य स्थिति है। इसलिए प्रत्येक राष्ट्र को अन्य राष्ट्रों से अपने संबंध स्थापित करने होते हैं। इन संबंधों को निरन्तर समयानुकूल परिवर्तित एवं परिवर्द्धित करना आवश्यक होता है। इसलिए इस कार्य के संबंध में कुछ निश्चित सिद्धान्त स्वीकार कर लिये गये हैं, जिनका अनुसरण प्रत्येक राष्ट्र अपने ढंग से करता है। इसे कुटनीति (Diplomacy) कहते हैं। और राष्ट्र के जो प्रतिनिधि दूसरे देशों में भेजे जाते हैं, उन्हें कूटनीतिक प्रतिनिधि (Diplomacy) कंट के जो प्रतिनिधि दूसरे देशों में भेजे जाते हैं, उन्हें कूटनीतिक प्रतिनिधि (Diplomacy) कंट के जो प्रतिनिधि दूसरे देशों में भेजे जाते हैं, उन्हें कूटनीतिक प्रतिनिधि (Diplomacy) कंट के जो प्रतिनिधि दूसरे देशों में भेजे जाते हैं, उन्हें कूटनीतिक प्रतिनिधि (Diplomacy) कंट के जो प्रतिनिधि दूसरे देशों में भेजे जाते हैं। प्राचीन भारतवर्ण में भी यह विज्ञान बहुत उन्नत था। कूटनीति के सिद्धान्त बहुत प्रचलित थे एवं प्रत्येक प्रभावशाली राज्य उनके पालन में तत्पर रहता था। कई सिद्धान्त तो ऐसे मूल्यवान एवं महत्वपूर्ण थे, जो आह भी एस्य हैं एवं साधन-सिद्धि के लिए उपयोग में लाये जा सकते हैं।

कूटनीति का श्रर्थ: — वर्षमान समय में शांति श्रीर युद्ध का मेट् इस प्रकार वताया जाता है कि "शांति के समय संतान श्रपने पूर्व जों का दफन करती है किन्तु युद्ध काल में पूर्व श्रपनी संतान का दफन करते हैं।" किन्तु फिर भी युगों से युद्ध ऐसी श्रावश्यकता रहा है जो कियाशीलता के लिए प्ररेखा, श्रात्मोत्सर्ग के लिए प्रवसर तथा प्रसन्नता का स्रोत माना जाता है। राजनीति के मंच पर दो पड़ोसी राष्ट्र उस समय मित्र बनते हैं जब तीसरी शिक्त से भयभीत हों श्रन्यथा पड़ोसी राष्ट्र मण्डल सिद्धान्त के श्रनुसार सदेव ही शत्रु राज्य ही होते हैं। इसलिए क्टनीति द्वारा युद्ध (War by Diplomacy) श्रथवा श्रथवा युद्ध द्वारा क्टनीति (Diplomacy by War) दोनों में से एक सिद्धान्त का पालन करना श्रनिवार्य हो जाता है। श्री पनिकर के शब्दों में कूटनीतिज्ञ को उपाधियां, विशेष श्रधकार मताधिकार, तथा श्रपव्यय की श्राड में कटिन एवं भयंकर काम करते रहने पड़ते हैं। इसलिए विशेष जन-सेवा के सदस्य ही इस कार्य के लिए चुने जाते हैं। प्राचीन काल में राजदूत विशेष रूप की सुन्दर वेशभूपा, सितारे श्रादि से सजे हुए रहने थे। वह समय तो श्रव नहीं है। कूटनीतिक विचार-विमर्श भी श्रत्यन्त गोपनीय होते हैं। प्राचीन काल में ये सब कार्य होते वे श्रीर कूटनीतिक निद्धान्त बहुत महत्वपूर्ण मान गये थे। कीटिल्य ने इस सम्बन्ध में विस्तृत वर्णन किया है। उसका मत है कि कूटनीतिक पद्धित के किटिल्य ने इस सम्बन्ध में विस्तृत वर्णन किया है। उसका मत है कि कूटनीतिक पद्धित के

विना युद्ध अधिक होंगे। कूटनीतिक पद्धित की पृष्ठभूमि युद्ध को तैयारी में हो निहित होती है। इसलिए कूटनीति के कुछ स्वरूप युद्ध की धमकी के रूप में ही काम में आते हैं और वड़े उपयुक्त साधन सिद्ध होते हैं। प्राचीन काल में भी ऐसे कूटनीतिक साधन प्रचलित थे जिन्हें आज का विश्व उपयोग में ला रहा है। जैसे-साम (Negotiation), दाम (Persuation) मेद (Conciliation) और दण्ड (Threat & War) मनुस्मृति के अनुसार ये चार सिद्धान्त प्राचीन भारतीय कूटनीतिक पद्धित के आधारस्तम्म थे। उस समय कूटनीतिक के लिए "नय" शब्द का प्रयोग होता था। कौटित्य ने भी लिखा है कि जो समाट 'नय' अर्थात् कूटनीति की वास्तविकता को सममता है वह समस्त पृथ्वी को विजय कर सकता है। ('नयज्ञ: पृथ्वीं जयति') इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि प्राचीन भारत में कूटनीतिक सिद्धान्त भली प्रकार समक्ते गये थे एवं उनका व्यवहार भी पर्यान्त मात्रा में होता रहता था।

प्राचीन कृटनीति:—साधारणतया कृटनीति का प्रादुर्भाव वैदिक काल से ही स्वीकार किया जाता है। ऋग्वेद संहिता में ऐसे अनेक प्रसंग उपलब्ध हैं। शतु पर विजय प्राप्त करने के लिए अग्नि देवता से पार्थना की जाती थी; क्योंकि अग्नि देवता शत्रुओं के लिए घातक माना गया था। इसी के साथ अपने उद्देश्य की पूर्ति के हेतु गुप्तचरों (Spies) का उपयोग करने का उल्लेख भी भिलता है। सम्राट, जो कूटनीति-संचालन के लिए केन्द्र रहता था, वह पूर्ण रूप से पुरोहित के अनुशासन में रहता था, क्योंकि पुरोहित कूटनीति का विशेवज्ञ होता था श्रीर निष्पत्त परामर्श के लिए श्रत्यन्त उपयोगी माना जाता था। श्रथर्ववेद में प्राप्त प्रसंगानुसार भी शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए अधिकांश कृत्रिमता (Artifice), छल (Strategem), माया (Spell and incantation) ग्रादि का ही उपयोग उचित बताया है। इसी प्रकार रामायण, महाभारत के युग में भी ये पद्मतियाँ पयोग्त रूप में विक्रित रही हैं और यही कारण है कि इन युगों में पड्यन्त्र (Intrigues) तथा वार्तालाप के प्रयत्न एवं प्रकार एक विशेष वातावरण बनाते रहे हैं। महाभारत में प्राप्त प्रसंग तत्कालीन कूटनीति के बहुत सुन्दर विश्लेषण उपस्थित करते हैं। अत्यन्त विख्यात कुटनीतिज्ञ कनिक ने कुटनीति पर ही धृतराष्ट्र की पूरा भाषण दिया था। उसका तथ्य इस प्रकार है — 'कूटनीति के चेत्र में सम्राट की कश्यप (कछुए) की भाँति व्यवहार करना चाहिए, ताकि दूसरों के दोप तो वह देख सके किंन्तु स्वयं के दोष प्रकट न होने दे । काँटे (करटक) की भाँति शत्रु का यदि प्राणान्त न भी कर सके तो मर्मान्तक पीड़ा अवश्य पहुंचा सके, हानिकारक शतुंका विनास सदैय ही प्रशासनीय होता है, क्योंकि अग्नि की छोटी सी चिनगारी भी बृहद् वन की भस्म कर मकते में समर्थ होती है, उसी प्रकार शत्रु को कमी निर्वल या छोटा नहीं समकता चाहिए। सम्राट की कभी-कभी बहरा श्रीर श्रम्धा हो जाने का स्वांग करना चाहिएं: परन्तु साथ हो इतना सतर्क श्रीर जागरूक रहना चाहिए जैसे सीये हुए हरिगों का सनूह रहता है । जब कभी शयु हाव में था जाए तो उस पर किसी भी परिस्थिति में दया नहीं करनी चाहिए, उसे गुप्त अयथा प्रकट साधनों से नष्ट कर देना ही उचित हैं। यहाँ तह उसके मित्र तथा श्रस्य सहयोगियों को भी नष्ट ं कर देना चाहिए। रात्रु के विनास के लिए योजना बनाकर आगे बढ़ना चाहिए। एदंशयम

शत्रु के सहायकों का विश्वास प्राप्त करना चाहिए और उसके पश्चात् उस पर आक्रमण करने के लिए अचानक मेडिये की भाँति भपटना चाहिए ताकि वह संभल भी न सके और उसके सहयोगी भी निरपेद्ध रह जायें। छल (Hypocracy) इस द्वीत में बहुत लामदायक होता है। जिस प्रकार भुके हुए भुँह के बाँस से फलदार बृद्ध की शाखाएँ सरलता से भुका कर फल चुने जा सकते हैं, उसी प्रकार इस प्रयोग द्वारा शत्रु को भी सरलता से नष्ट किया जा सकता है। अपने शत्रु को उस समय तक कन्धों पर ऊँचा चढ़ाये रहना चाहिए, जब तक कि उसे नीचे फैंककर कच्ची मिट्टी के वर्षन के समान दुकड़े-दुकड़े न कर सको। किसी भी परिस्थिति में शत्रु को पलायन का अप्रवसर नहीं देना चाहिए। जहाँ तक संभव हो तत्काल शत्रु का वध कर देना चाहिये। शत्रु चाहे पुत्र, पिता अथवा गुरु ही क्यों न हो, साम, दाम, विष अथवा छल द्वारा नष्ट कर देना ही श्रेयस्कर है। इस चेत्र में गुप्तचरों का अधिक उप-योग किया जाय । गुप्तचर मछवाहों की भाँति अपने कार्य में कुशल होते हैं । सम्राट को उस्तरे की भांति (Razor-like) पैना एवं चमकदार होना चाहिए।" इस प्रकार सम्राट को कुट-नीतिक च्रेत्र में कैसा, किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए, बड़ा रोचक वर्णन किया गया है। इससे यह भास होता है; जैसे महाभारत-काल में कुटनीति के सिद्धान्त उस समय के मेके-यावली के सिद्धान्तों के समान हों। परन्तु वास्त्रव में यह बात ठीक नहीं थी। महाभारत के शांतिपर्व में ही दूसरे स्थान पर भारद्वाज ने कूटनीति के सिद्धान्तों की व्याख्या शत्रुजीत के लिए की है: इस स्थान पर वर्णित व्याख्या पहली से भिन्न है किन्तु आधारभूत सिद्धान्त तो समान ही हैं। महाभारत-काल में, जहाँ सुई की नोक के बरावर भूमि भी उचित होते हुए विना युद्ध के दिया जाना स्वीकार नहीं किया गया था, नैतिकता की न्यूनता अथवा अभाव आहत्रर्य-जनक नहीं कहा जा सकता। त्रातः उपरोक्त क्रूटनीतिक सिद्धान्त तस्कालीन प्रसंगानुसार महत्व-पूर्ण ही स्वीकार किये गये थे।

नारदस्मृति के ऋनुसार क्टनीतिक च्लेत्र में पाड्गुण्य-विधि (Six-fold policy) का प्रयोग ऋनिवार्य माना गया । तदनुसार सम्राट में निम्नलिखित छः गुणों की विद्यमानता एवं उनका व्यवहार ऋगवश्यक है:—

- (१) वाक्-पद्धता (Cleverness of speech)
- (२) तत्परता (Readiness)
- (३) বুরি (Intelligence)
- (४) स्मृति (Memory)
- (४) परिचय (Acquaintance)
- (६) दण्डनीति का व्यवहार (Politics)

उपर्युक्त गुणों के सफल व्यवहार के लिए निम्नलिखित सात साधनों का उपयोग करना चाहिए:—

- (१) वैपम्य का बीजारोपण या भेद (Sowing dissension)
- (२) दण्ड (Chartizement)

- (३) साम (Conciliation)
- (४) दान (Gift)
- (५) माया (Incantation)
- (६) श्रौषधि (Medicine)
- (७) जादू (Magic)

कौटिल्य के मतानुसार भी कूटनीतिक च्लेत्र में राज्य को नैतिक दृष्टि से उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता। यहां कौटिल्य, आधुनिक पाश्चात्य विद्वान् हान्स, मेकेयावली आदि की माँति, राज्य की स्वतन्त्रता और उनके लिए नैतिक मर्यादाओं की अव्यावहारिकता को और लच्य करता है। राज्य की बहुच्चेत्रीय कियाओं में नैतिकता का बन्धन कार्य को कठिन ही बनाता है और कूटनीति का उद्देश्य टीक इसके विपरीत कठिनाइयों का सरल करना होता है। कौटिल्य ने कूटनीति के मुख्य सिद्धान्त चार ही स्वीकार किये हैं:—साम, दान, मेद एवं दण्ड कामन्दक के मतानुसार उक्त चार के साथ तीन सिद्धान्त और सम्मिलित करने पर पूर्ण होते हीते हैं; जो इस प्रकार हैं —माया, उपेचा, और इन्द्रजाल ।१ ये सात उपाय विजय के लिए आवश्यक माने गये हैं। प्राचीन कूटनीति का वास्तविक ज्ञान इन विभिन्न उपायों के विशेष अध्ययन से ही हो सकता है। अतः अब हम इन साधनों का संदिग्त वर्णन आरम्भ करते हैं।

क्टनीति के विभिन्न साधन (Instruments of Diplomicy or the seven expedients of Anci at Diplomacy): - प्राचीन काल में क्टनीतिक व्यवहार के सम्बन्ध में अनेक साधनों का प्रतिपादन किया गया था। उनकी प्रकृति प्रभाव एवं प्रकार की विशद व्याख्या अनेक ग्रंथों में प्राप्य है!। उपर्युक्त सात साधनों में से प्रत्येक के सबंध में निम्निलिखत वर्णन संभव होता है: —

(१) साम:—मत्त्यपुराण के अनुसार यह सिद्धान्त माना गया है कि सब व्यक्तियों के प्रति तथा प्रत्येक समय अथवा सदैव एक ही नीति का अनुसरण सम्भव नहीं हो सकता। संसार में धर्मात्मा (Righteous) या अधर्मी (Unrighteous) दो ही प्रकार के व्यक्ति होते हैं। इसिलए नीति का व्यवहार भी व्यक्तियों के अनुसार मिन्न-भिन्न होता है। उपर्युक्त वर्गीकरण के अनुसार साम भी दो प्रकार का माना गया है। प्रथम-सत्यसाम-नो धर्मात्मा लोगों के प्रति और दूसरा-असत्यसाम-नो अधर्मी लोगों के प्रति व्यवहार में लाया जाय। कोटिल्य भी इसी नीति का समर्थन करते हुए इस प्रकार पुष्टि करता है कि पराजित सम्मार्ट के प्रति यही नीति अपनानी चाहिए जिससे अधीनस्य सम्मार स्वामिमक बना रहे। प्राचीन धर्म शास्त्र तथा अर्थशास्त्र में सामनीति की अन्छी व्याख्या की गई थी। निर्वल सम्नाटों पर अधिकार स्थापित करने के लिए यह बहुत सुन्दर उपाय था। यदि इस नीति द्वारा निर्वल सम्माट वश में नहीं आ सके तब दान (gift) नीति का उपयोग किया जाय। 'शिवतत्व-रत्नाहर' के अनुसार साम पांच प्रकार ने प्रयोग में लाया जाता था। किन्तु समय के साय-साथ

१ सामो दानश दराइश्च भेदश्चेति चतुष्टयम्। मायोपेनेन्द्रजालं च सप्तोपायाः प्रकीत्तिताः॥ कामन्दक—सप्तदरा सर्ग-रजीक ३।

अन्य प्रकार लुप्त होते गये। कामन्दक ने भी निम्न पांच प्रकार के साम बताये हैं -गुण और कर्मों में परस्पर उपकारों का कीर्त्तन, संबंध का आख्यान, आगामी समय में कार्य प्रकाश करना मनोहर मीठी वाणी से भी तुम्हारा हूँ इस प्रकार अपने की अर्पण कर देना आदि साम के पांच प्रकार माने हैं।

- (२) दान:--क्रूटनीतिक चेत्र में दूषरा उपाय दान (gift) माना जता था सान एवं दान की नीति का अनुसरण अपने से हीन राजाओं के प्रति करना चाहिए। कोटिल्य का मत है कि यदि शुद्ध साम की नीति वांछित प्रभाव नहीं दिखा सके, तब दान को नीति का प्रयोग होना चाहिए। मत्स्यपुराण के अनुसार दान की नीति बहुत प्रमात्रशाली हांती है। मनुष्य तो क्या संपत्तिदान तथा दूसरे उपहारों के द्वारा देवता भी वश में हो जाते हैं। इसिनये विद्रोही एवं उच्छ खल व्यक्तियों को वश में करने के लिए ऋत्यन्त लालची दान उपयुक्त होता है। कौटिल्य का मत है कि जन कभी स्थानीय नेता एवं अधिकारी विदेशियां से मिल जायं तन असंतुष्ट प्रजा के प्रति साम एवं दान की नीति प्रयोग में लानी चाहिए, जिससे वे विदेशियों से अपना संबंध-विच्छेद कर लें। जब अपने राज्य में पूर्ण शांति स्थापित हो, तब विजेता को विदेशियों के प्रति भेद एवं दण्ड नीति का अनुसरण करना चाहिए। इस संवध में यह एक स्वीकृत सिद्धान्त था कि बाहरी आपत्ति दूर करने से पूर्व आन्तरिक आपत्ति दूर होनी चाहिए। मनु ने भी यही सिद्धान्त स्वीकार किया है और दान नीति को माम के पश्चात् महत्व की दृष्टि से दूसरा स्थान दिया है। 'शिवतत्व रत्नाकर' में दान सीलह प्रकार का वर्णित है, परन्तु प्रधानता केवल चार प्रकार के दान को ही दी गई है। जो उपकार, मित्रता, संबंध एवं भेंट कहे जाते हैं। कामन्दक के मतानुसार दान पाँच प्रकार का होता था; जैसे राजनैतिक विवाह, संधि आदि।२
- (३) भेद:—क्टनीति चेत्र में भेद तीक्षरा उपाय माना जाता है। मस्यपुराण के अनुसार अधर्मी राजाओं के प्रति भेद नीति का व्यवहार होना चाहिए। यह नीति वर्तमान समय को "विभाजन कर, शासन करे" (Divide and Rule) नीति के समान ही है। जैसा ऊपर कहा जा जुका है कि सुरचा अथवा आक्रमण के लिए आंतरिक शांति अनिवार्य है। इसलिए अपने शत्रु को जीतने के लिए उसके परिजनों अथवा प्रजा में भेद की भागना का प्रसार बहुत प्रभावशाली होता था। जब भेद व्याप्त हो जाय, तब उन पर आक्रमण करना सर्वश्र छ हो सकता है। मनु इस नीति को अधिक महत्व नहीं देता, किन्तु कीटिल्य बलवान से बलवान सम्राट को भुकाने के लिए भी इस नीति को अत्यन्त प्रभावशालां शस्त्र मानता है। अपने अर्थशास्त्र में उसने भेद उत्पन्न करने के अनेक उपायों को व्याख्या को है। 'शिवनतत्वरत्नाकर' के अनुसार भेद निम्न छ: प्रकार का माना गया है:—
 - (१) प्राणहानि (निसमें जीवन-मरण का प्रश्न उत्पन्न हो जाय) !
 - (२) मानमंग (बहां सम्मान की बाबी लग बाय)।

१ वामन्दव-सर्ग १७, इलोक ४ एवं ४।

२ कामंदक।

- (३) धनहानि (जहां लालची शासक को धनहानि की सम्भावना हो)।
- (४) वंधक (जहां शत्रु के मित्र के मित्रक में कारावास का मय हो जाय)।
- (५ दाराविलास (जहां मित्र की धर्मपत्नी को शत्रु द्वारा ले जाने का भय हो)।
- , ६) अ गमंग । जहां शत्रु द्वारा मित्र से राज्य का कोई भाग छीनने का भय हो) । कामंदक के अनुसार भेद तीन प्रकार के हैं: —
- (१) स्नेह-राग का दूर कर देना, (२) हर्ष उत्पन्न कराना, एवं (३) फिड़कना ।१ मेद को साधारण शब्दों में 'फूट डालना' भी कहते हैं। यह नीति बहुत प्रभावशाली होती है। वर्तमान समय में भी यह नीति महत्वपूर्ण समभी जाती है।
- (४) द्राड:—प्राचीन काल के चार प्रधान उपायों में से श्रन्तिम साधन 'दण्ड' या 'युद्ध की धमकी' था। द्राड का अर्थ वास्तव में द्राड देना अथवा संघर्ष आरम्भ करना नहीं है, किन्तु एक क्टनीतिक विरोध है जिसमें शस्त्राशस्त्र का प्रयोग नहीं होता। अधिक से अधिक दण्ड का अर्थ यह होता था कि प्रत्यच्च युद्ध आरम्म होने के पूर्व अन्तिम साधन के रूप में युद्ध की आशंका अथवा धमकी प्रकट कर दी जाय। इस साधन का प्रयोग उस समय किया जाता था, जब प्रथम तीन साधन साम, दान एवं मेद अलग-अलग तथा सम्मिलित रूप में व्यवहार में लाने पर भी अपने उद्देश्य की पूर्ति करने में अनक्त रहे हों। अर्थशास्त्र में दण्ड के विभिन्न प्रकारों का वर्णन किया गया है। जैसे शत्रु को युद्धचेत्र में बन्दी बना लेना, छल-प्रयोग द्वारा युद्ध में अधीन कर लेना, गुप्त षड्यंत्र द्वारा शत्रु पर आधात करना, भयभीत करने के लिए उसके किले पर घेरा डालना, अन्यवस्था के समय शासक की बन्दी बना लेना आदि। कामंदक के मतानुसार दण्ड मुख्य रूप में तीन प्रकार का है:-(१) वध कर देना, (२) धन हर लेना, एवं (३) विशेष कायाक्ट देना।२ (प्रकट दण्ड गुप्त दण्ड आदि इन्हीं के प्रकार हैं)।
- (५) उपेत्ता (Indifference): प्राचीन समय के राजनीतिक दार्शनिकों ने यह अनुभव कर लिया था कि दण्ड-नीति का व्यवहार समस्त सम्राटों अथवा राजाओं द्वारा सम्भव नहीं हो सकता। यह सच भी है कि एक साधारण सम्राट या शासक, नड़े सम्राट या शासक से युद्धत्तेत्र में सामना नहीं कर सकता; बिल्क द्वे तमाव अथवा धोखेबाजी से भी वह सफल नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में यह स्वाभाविक समस्या उत्पन्न होती है कि निर्वल शासक क्या उपाय करे, मत्स्यपुराण में ऐसी ही स्थिति की कल्पना की गई है और तब 'उपेत्ना' की नीति का प्रतिपादन किया गया है। जब बड़ी शिक्तियों से विर जाय, तब साधारण शिक्त या शासक की 'उपेत्ना' नीति का अनुसरण करना चाहिए। कौटिन्य ने भी उपेत्ना का प्रसंग दिया है, किन्तु भिन्न रूप में न देकर उदासीन व्यवहार का ही एक पन्न बताया है। उसका

२ वधोऽर्थबहर्ण चैव परिवलेशस्त्रधैव च । इति इएड विधानकेंद्र एडोऽपि विविधः स्मृतः ॥ कामन्दक, सर्ग १७, पृष्ठ १६३ ।

मत है कि तटस्थ राज्य को पड़ोसी राज्यों के प्रति चाहे रात्रु हो या मित्र, उदासीन व्यवहार करने की पृति विकसित करनी चाहिए। तत्कालीन ग्रन्तर्राष्ट्रीय नियम द्वारा भी तटस्य राज्यों की निरपेच्ता का सम्मान किया जाता था। कोई ग्राक्षामक राज्य ऐसे उदासीन राज्य की कियात्रों पर ध्यान नहीं देता था। कूटनीतिक विज्ञान के चेत्र में 'उपेचा' का सम्मिलित होना यह सिद्ध करता है कि यह प्रगतिशील विज्ञान था। इसीलिए उपेच्ता भी साधन रूप में स्वीकार हुग्रा। इस प्रकार उपेच्ता निर्वल राष्ट्र के विशेषाधिकार के रूप में स्वीकार हुग्रा था। कामदक ने उपेच्ता तीन प्रकार की लिखी है:—

- (१) श्रान्याय में (कीचक जब द्रीपदी की इच्छा करता था, तब भीमसेन ने उसकी (Immoral) द्रीपदी का रूप धर कर मार डाला श्रीर राजा विराट उसके वध से चुप रहे)।
- (२) व्यसन में भीमसेन को सिंडजत देखकर अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए निर्भय (Addiction) हिडिम्बा राज्सी ने अपने भ्राता वक के मारे बाने में उपेजा की थी)।
- (३) युद्ध में (श्रर्थात् युद्ध में प्रवृत्त हुए के निवारण की कोई चेष्टा न करना)। १ इस (War) प्रकार उपेन्ना क्टनीतिक न्नेत्र का महत्वपूर्ण साधन था।
- (६) माया (Illusion):- कृटनीति के उपर्युक्त पांच प्राचीन सिद्धांतों में ये दो (माया एवं इन्द्रजाल) सिढांत श्रीर जोड़े गये थे। इसीलिए श्रर्थशास्त्र में भी माया श्रीर इंद्रजाल का प्रसंग मिलता है। ये दोनों सिद्धांत वस्तुत: निम्न श्रेणी की कुटनीति (Base Deplomacy) में सम्मिलित होते हैं। माया का अर्थ है भ्रम उत्पन्न करना। इस पद्धति के श्रनुसार श्राकामक शत्रु को भ्रम में, या माया में डालने के लिए हर प्रकार का प्रयत्न किया जाता है तथा जब शत्रु अत्यधिक निर्वल प्रतीत हो तब उस पर आघात करने का निर्देश हैं। इस पद्धति में धूर्तता एवं पड्यंत्र प्रधान होते हैं श्रीर श्रनेक प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है। कौटिल्य के मतानुसार तो यह पद्धति मुख्य रूप से 'दण्ड' का ही प्रकार है, जिसे भ्रमयुद्ध (Treacherous Warfare) कहा जा सकता है। परन्तु यहां माया का श्रर्थ किसी वास्तिविक युद्ध से नहीं है । केवल पड्यंत्रीं श्रीर प्रति-पड्यंत्रीं (Intrigues & Counter-intrigues) द्वारा ही शत्रु पर विजय प्राप्त कर लेना इस उपाय की सफलता है। कामंदक ने 'माया' पद्धति का वर्णन बहुत विस्तार से किया है। तदनुसार विजेता की श्राज्ञा दी गई है कि वह देवता या स्तम्भ की भांति वेप बनाकर स्थापित हो जाय श्रीर जब शत्रु पूजा के हेतु समीप स्रावे, तत्र उसकी जीवनलीला समाप्त कर दी जाय। श्रथवा सन्नाट को चाहिए कि शत्रु के पास स्त्री रूप में, शैतान के रूप में अथवा भृत-प्रेत के रूप में जाकर उसकी हत्या कर दें। मुख्य रूप से 'माया' के दो रूप माने गए है:- (१) मानुपी एवं (२) श्रमात्पी या देवी । मात्रपी माया भी तीन प्रकार की मानी गई है-

१ कामंदक, सर्व १७, वृष्ठ २०२।

श्र-ग्रन्धकार में लीन होना।

ब---जल बरसाना 🏥

स-इच्छानुसार रूप धारण कर लेना।

महाभारत में वर्णित भीमसेन द्वारा द्रौपदी के रूप में कीचक का वध इसी नीति का उदाहरण है। यह सच है कि कट्टनीति के चेत्र में इन सिद्धांतों से नैतिक स्तर अवश्य निम्न अंगी का बन गया परन्तु संभवत: यह पतन मौर्यकाल के बाद हुआ। क्योंकि अर्थशास्त्र में इनकी स्पष्ट व्याख्या नहीं की गई। यदि उसी समय ये स्वीकृत सिद्धांत होते तो कौटिल्य द्वारा इसका विवेचन अवश्य ही किया जाता।

(७) इन्द्रजाल (Camouflage)—शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए इन्द्रजाल एक प्रभावशाली पद्धति थी। शांतिकाल एवं युद्धकाल दोनों समय में इसका उपयोग किया जाता था । इन सिद्धांतों की लोकिभियता का अधिकांश, अथर्व वेद की लोकिप्रियता से माना ज्ञाता है। श्रथर्व वेद में कई प्रकार के जादू, टोने एवं तंत्रों का वर्णन मिलता है, जिनका उद्देश्य केवल अपने लच्य की पूर्ति के लिए प्रयोग में लाना होता था। ये निस्सन्देह निम्न-स्तर के थे। परन्तु फिर भी क्रमशः इनका प्रयोग बढ़ता ही गया। विशेष तौर पर विद्रोही एवं उपद्रवी शासकों को वशीभूत करने के लिए यह साधन उपयुक्त माने जाते थे। बीद्धकालीन मंथ, जो उच्च नैतिक स्तरीय कृतियां है, इस मकार के षड्यंत्रकारी एवं अन्धविश्वासी उपायों का उल्लेख करते हैं। कामंदक ने इन्द्रजाल के विभिन्न प्रकारों का वर्णन इस प्रकार किया है-मेघ, अन्धकार, दृष्टि, अग्नि, पर्वत तथा अद्भुत-दर्शन और दूरस्थित ध्वजा-पताका, संयुक्त सेना का दर्शन होना, छिन्न-भिन्न पाटित ,विदारण) श्रीर संस्कृत वस्तु का दिखाना; यह इन्द्र-जाल-विद्या शत्रुत्रों को भय दिखाने के लिए कल्पना करें ।१ इसके अतिरिक्त शत्रु की सेना को इन्द्रजाल द्वारा अपने शिविर से बाहर ले आना, चरागाहों में ग्राम व प्रासादों की विद्यमानता पकट करना (जैसे महाभारत में लावागृह की रचना की गई था), एक स्रोर थोड़े से सैनिक पकट कर सेना का भ्रम करा देना तथा उस श्रोर शत्रु के श्रग्रसर होने पर पीछे से श्राक्रमण कर शत्रु को नष्ट कर देना, बच्चों की टहनियों ब्रादि से सिनजत होकर सैनिक का बच्च की भाँति खड़े रहकर रात्र की समस्त गतिविधि को देखना आदि इन्द्रजाल के ही प्रकार थे। वर्तमान समय में भी इन्द्रजाल सैनिक कियाओं का मुख्य अंग माना जाता है।

उपयु ति समस्त कट्टनीतिक साधनों में प्रथम चार प्रधान तथा तीन गौगा साधन हैं। कामन्दक ने भी यह स्वीकार किया है कि अन्तिम तीन उपाय, प्रथम चार उपायों के ही रूप हैं। माया, दण्ड का रूप है और उपेचा तथा इन्द्रवाल, भेद के रूप माने जाते हैं। कामन्दक का मत है कि वह कट्टनीतिज्ञ जो नीति के उपर्यु के प्रकारों का प्रयोग स्थान, काल और साधनों का ध्यान रखते हुए और अपनी शक्ति का प्रयोग शत्रु के विषद्ध करता है वह अवश्य सफल होता है तथा जो एह नीति एवं विदेश नीति में इन सिद्धान्तों का प्रयोग नहीं करता, वह

१ वित्रपाटितभिन्नानां संस्कृतानाञ्च दर्शनम् । इतीन्द्रजालं द्विपतो भीत्यर्थमुपकलपयेत् ॥ कामन्दक, १७ सर्गे, श्लोक ५६ ।

केवल नेत्रहीन की भाँति समभा जाता है। छः प्रकार की नीति पर आधारित इन सात उपायों का प्रयोग करने से विजयी सम्राट 'सार्वभौम' की उपाधि का अधिकारी होता है। इस प्रकार कूटनीति के सिद्धान्त प्राचीन भारतवर्ष में बहुत महत्वपूर्ण माने गये ये और उनका व्यवहार भी पर्याप्त रूप में होता था।

राजदूत (Diplomatic Agents):—विदेशों में राजदूत भेजने की प्रथा एवं यह संस्था त्राधुनिक समय में ही प्रचलित हुई हो ऐसा नहीं है। प्राचीन भारतवर्ष में भी क्ट्रनीतिक नियमावली बहुत प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त कर चुकी थी। राजदूतों के कार्य एवं उनका प्रतिष्ठित स्थान समाज में सदैव ही गौरवपूर्ण रहा है। साधारखतया राजदूतों का पद क चा एवं प्रतिस्पर्धा के योग्य माना जाता था। वैदिक साहित्य से लेकर वर्तमान समय तक के समस्त प्रन्थों में दूत का स्थान बहुत महत्वपूर्ण रहा है। वेदों में ऋग्नि को देवदूत माना गया है। ऋग्वेद के अनुसार राजदूत दो प्रकार के माने गये थे - (१) दूत, और (२) चर। तैतिरीय संहिता में तीसरा शब्द 'प्रहित' (Envoy) भी काम में त्राया है जो दूत से भिन्न है। प्रसिद्ध विद्वान् सायण द्वारा इन शब्दों की बहुत सुन्दर व्याख्या की गई है। उनके मतानुसार 'दूत' वह व्यिक्त होता है जो शत्रु की स्थिति एवं सैनिक शिक्त ग्रादि के सम्बन्ध में वास्तविक सूचना प्राप्त करने में कुशल हो। 'प्रहित' वह व्यक्ति होता है जो ग्रपने स्वामी द्वारा किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए मेजा जाय। अथर्व संहिता में भी इन्हों शब्दों का प्रयोग हुआ है। डॉ॰ अल्टेकर का मत है कि यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि प्राचीन काल में स्थायी निवास करने वाले राजदूत होते थे; किन्तु फिर भी इतिहास में ऐसे उदाहरण हैं जहाँ स्थायी निवास करने वाले राजदूतों का प्रमाण मिलता है । चन्द्रगुप्त मौर्य के राज्य में मेगास्थनीज तथा बिन्दुसार के राज्य में डिमाकस रहता था। इसी प्रकार यह भी सम्भव है कि इन भारतीय राजायों ने भी अपने राजदूत उन देशों में भेजे हों। बीद धर्म के प्रचार के लिए 'शांति-सन्देश' पहुंचाने तो कुछ लोग गये ही थे। यह भी सन्देह किया जाता है कि यूनानी दूत कुछ समय के लिए ही यहाँ रहे थे, विशेष काल तक नहीं। इतिहास से यह भी पता चलता है कि समुद्रगुप्त के द्रशार में लंका श्रादि देशों ने दूत आये थे और पुलकेशिन (चालुक्य) के राज्य में ईरान (Persia) से । भारतवर्ष से चीन श्रीर रोम में दूत भेजे जाने का प्रसंग भी मिलता है। तत्कालीन संस्कृत भाषा में दूत शब्द का प्रयोग ही राजदूत (Ambassador) के ऋर्घ में हुआ है। १ इस प्रकार राजदूत प्राचीन भारत में बहुत महत्वपूर्ण पद माना गया था श्रौर श्रत्यधिक महत्व के वैदेशिक कार्य करना इस पट् का दायित्व होता था।

राजदूत की योग्यताएँ (Qualifications of the Ambassador):— राजदूत का पद बहुत प्राचीन होने के कारण श्रधिकांश प्राचीन मंथों ने इस पद पर श्राहीन होने के लिए कुछ निश्चित योग्यताश्रों का उल्लेख किया है। मानवधर्म-शास्त्र के अनुसार राजदूत में निम्नलिखित योग्यता होनी चाहिए:—

१ टॉ॰ शहरेकर-State & Government in Ancient India-Page 295.

(१) वह उच्चकुलीन हो, (२) सकल शास्त्रों में प्रवीण, (३) श्रामिप्रायस चक-वचन स्वर श्रादि को जानने वाला, (४) प्रेम-हे बमाव के स्चक श्राकार को जानने वाला, (५) क्रोधादि स्चक हाथ चलाने श्रादि को समफने वाला, (६) श्रन्याय से धन न लेने वाला श्रीर कार्यकुशल हो; ऐसा पुरुष दूत बनाया जाय।१ इसके श्रातिरिक्त शत्रु का भी प्रेमपात्र बनने वाले, धन श्रीर स्त्री के विषय में पवित्र, कार्यकुशल, पूर्वापर बात को याद रखने वाले, देशकाल को समफने वाले, दर्शनीय शरीर वाले, निर्भय, वाचाल, दूत प्रशंसा प्राप्त करते हैं।२ राजदूतों में उपर्युक्त योग्यताश्रों के साथ सुन्दर, मनोहर वाणी, वक्तुत्वकला, स्वामिमिक्त, परिश्रमशीलता श्रादि गुण भी श्रानिवार्य समफ्ते गये थे। वास्तव में विदेशी राज्य में जाकर श्रपने देश का हित साधन करने के लिए उपर्युक्त योग्यताएँ श्रानिवार्य ही होनी चाहिए। श्राधुनिक काल में भी हमारे देश में इस कार्य के लिए पृथक् सेवा संगठित की गई है श्रीर उसमें सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों को ही जुना जाता है। इस प्रकार प्राचीन भारतवर्ष में राजदूतों से सम्बन्धित गुणों का वर्णन यह सिद्ध करता है कि उस समय भी क्टनीति एवं राजदूतों का स्तर बहुत के जा एवं श्रेष्ठ था। महाभारत में भीवम ने भी राजदूत के लिए सात योग्यताएँ श्रावश्यक बताई है:—उच्चवंशज, कुलीन, कुशल, वक्ता, श्रच्छा संदेशवाहक, तीव स्मृति एवं ईमानदार।

राजदूतों की श्रेणियाँ (Classes of Ambassadors):—उस समय कौटिल्य के मतानुसार राजदूत मुख्य रूप से निम्नांकित तीन श्रेणियों में विभाजित किये जाते थे :—

(१) नि:स्नृष्टार्थ —वह कूटनीतिज्ञ जो अनेक प्रकार के कार्य संपादित करता था। उसके लिए मन्त्रियों की भाँति विभिन्न योग्यताएँ आवश्यक होती थीं तथा जो विनिमय या विचारों के आदान-प्रदान के लिए राज्य की ओर से पूर्ण अधिकारों से युक्त रहता था। मन्त्रियों की भाँति यह दूत भी उच्चकुलीन, सकल शास्त्रविशारद, आत्मत्यागी, राज्य एवं राजा के प्रति स्वामिभक्त, शुद्धहृदयं तथा चतुर होता था।

(२) परिमितार्थ—यह राजदूतों की दूसरी श्रेणी होती थी। इस श्रेणी के दूत वे लोग होते ये जिन्हें एक निश्चित कार्य को पूर्ण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता था। इसलिए उपर्युक्त योग्यताश्रों में कुछ कम योग्यता वाला व्यक्ति भी इस पद पर श्रामीन किया जा सकता था। यह दूत श्रंपने निश्चित उद्देश्य से विचलित नहीं हो सकता था।

(३) शासनाहार दूत — यह राजदूतों में साधारण श्रेणी का पद था। इस पद पर श्रासीन दूत केवल राज्य के संदेशवाहक का कार्य करते थे। सम्राट के द्वारा दिया हुन्ना संदेश यथास्थान पहुंचा देना तथा उसका उत्तर पुनः सम्राट तक पहुंचा देना मात्र ही इस श्रेणी के दूत का मुख्य कार्य था। प्रतिनिधि के रूप में किसी प्रकार का वार्तालाप या विचार-विनिमय (Negotiations: इसके श्रिधकार में नहीं होता था।

१ दूतं चैव प्रकुर्वीत सर्वेशास्त्रविशारदम् । इङ्गिताकारचेष्टशं शुचि दचं कुलोद्गतम् ॥६३॥ सप्तम अध्याय—मनुस्तृति ।

२ श्रनुरक्तः शुचिद्चः स्मृतिमान् देशकालवित् । वपुष्मान् वीतभीर्वाग्मी दूतो राशः प्रशस्यते ॥ उपरोक्त ६४।

रामायण में भी दूतों के प्रकार तीन ही माने गए हैं, किन्तु तत्कालीन शब्दावली ऋछ श्रौर ढंग की हैं। उस समय निम्नांकित तीन प्रकार के राजदूत होते थे:—

- (१) पुरुषोत्तम—वह व्यक्ति होता था, जो अवांछनीय एवं अत्यन्त कठिन कार्य भो, राज्य के प्रति अपने स्नेह एवं स्वामिभक्ति के कारण, करता था।
- (२) मध्यम-तर-वह व्यक्ति होता था, जिसके ऊपर कोई निश्चित कार्य का भार रख दिया जाता था श्रीर फिर वह अपने ढंग से उस कार्य को संपादित करता था।
- (३) पुरुष-श्रधम—जो नागरिकों में श्रत्यन्त निम्न कोटि का व्यक्ति हो तथा जो कार्य उसे सोंपा जाय, वह भी उचित ढंग से सम्पादित न किया जा सके, ऐसा दूत पुरुप-श्रधम की श्रेणी में श्राता है।

अग्निपुराण के अनुसार भी राजदूतों की अंणियाँ कौटिल्य द्वारा दिये गए वर्गाकरण के अनुरूप ही थी। परन्तु विशेष रूप से यह और कहा है कि दूत एक प्रकार से प्रकट रूप में गुप्तचर है तथा आवश्यकतानुसार वह सत्य का पता चलाने के लिए व्यापारी, वैद्य आदि का स्वांग भी बना सकता है। कामन्दक द्वारा भी यही तीन अंणियाँ बताई गई हैं।१ शुक्रनीतिसार में दूत मंत्रिमण्डल में प्रथम दस मंत्रियों में से एक माना गया है।

विशेपाधिकार:--राजद्त, एक राज्य का प्रतिनिधि वनकर दूसरे राज्य में जाता है तथा अपने राज्य के हितसाधन में तत्पर रहता है, इसलिए विभिन्न रीति-रिवाज एवं परम्पराओं के होते हुए भी उसे विशेषाधिकार होना अनिवार्य होता है। यही प्रथा प्राचीन भारत में भी थी। किसी भी परिस्थिति में उसकी जीवनरचा का भार सदैव ही उस राज्य के सम्राट पर होता था जहाँ राजदूत निवास करता था। उसे कभी भी दिख्डत नहीं करना चाहिए श्रीर मृखुदण्ड भी नहीं देना चाहिए श्रन्थया दण्ड देने वाला गासक नरक का श्रिधकारी होता है। राजदृत की हत्या करने वाला शासक नरक का ऋधिकारी होता है। राजदृत की हत्या करने वाला श्रिधिकारी स्वयं तथा उसकी अनेक आने वाली पीढियाँ अक्यनीय पाप की भागी होती हैं।२ चाहे दूत का व्यवहार अनुचित हो, अथवा उसके राज्य से शत्रुता आरम्भ हो जाय तो भी राजद्त तथा उसके सहायक कर्मचारियों के प्रति ग्राशिष्ट ग्रथवा ग्रवांछनीय व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए था। यदि दूत का व्यवहार बहुत अनुचित हो तो उसे समुचित दण्ड दिया जा सकता था । उदाहरणार्थ-रावण ने हनुमानजी को लंकादहन के पहले द्रिडत किया था। डॉ॰ ग्रहटेकर के मतानुसार प्राचीन काल में भी प्रवेश-ग्रनुमति-पत्र (Passports) ग्रान-वार्य होता था; परन्तु निरन्तर श्राने-जाने वाले व्यापारियों के लिए यह वन्धन शिथिल होता था। श्रन्यपा सन्देहात्मक व्यक्तियों का विचरण स्थगित कर दिया जाता था। विदेशियों की कियात्रीं पर ध्यान रक्ला जाता था, ताकि यदि कोई गुप्तचर बनकर छाया हो तो उसे रोहा जा सके। इस प्रकार राजवृतीं तथा उनके सहायकों को कुछ विशेषाधिकार व नुविधाएँ प्राप्त थीं और निश्चित जेन में वे अपना कार्य करने के लिए स्वतन्त्र ये ।

१ कामन्दक-पृष्ठ १३१।

र दूतस्य एन्ता निर्यमाविरोत्सिनिकैः सह ॥ As quoted by Dr. Altekar—State and Government in Ancient India-Page 296.

राजदूत के कत्त वय-साधारण रूप में राजदूत के कर्त व्य अनेक प्रकार से कई चेत्रों में व्याप्त होते थे। मनुस्मृति में ये कार्य बहुत विस्तार से वर्णित है। सर्वप्रथम युद्ध एवं शांति (संघि) की घोषणा करने का कार्य राजदूत का होता था। दूसरे, मित्रता स्थापित करना श्रथवा मित्रता भंग करने का कार्य भी राजदूत करता था। जो लोग कुछ सहातुभृतिपूर्ण ज्ञात हों, उनसे मित्रता स्थापित करना तथा विरोधी लगने वाले लोगों से मित्रता भंग करना उसी का कार्य होता था। तीसरे, अपने शत्रु के सम्बन्ध में, उसकी शक्ति, सामर्घ्य एवं सीमा तथा उसके शत्रु, मित्र, एवं अनुयायी आदि का पूरा निश्चय करना भी राजदूत का कार्य होता था। चौथ, विदेश में राजदूत को अपने सम्पूर्ण कार्य इस प्रकार करने चाहिए थे कि वह व्यक्तिगत रूप में कभी कोई संकट न उठाए। कोटिस्य भी उपर्युक्त कार्य ही राजदूत के लिए डांचत बताता है त्रीर इस बात पर बल देता है कि राजदूत को अपने शत्रु राज्य के ग्राधिकारियों से मित्रता बनानी चाहिए, उसकी सैनिक शांकि का ग्राध्ययन करना चाहिए, दुर्ग, शस्त्रागार, सेना त्रादि सब ऋच्छी एवं बुरी बातों का पूरा ज्ञान करना चाहिए, शत्रु गज्य को जाने वाले मार्ग का तत्काल पूर्णारूपेण सर्वेज्ञण करना चाहिए, शिविरयोग्य मुख्य स्थलां की चुन लेना चाहिए ताकि युद्ध के समय, पीछे हटने या आगे बढ़ने अथवा खाद्य सामग्री एकत्रित करने के लिए, उनका उपयोग सुविधापूर्वक किया जा सके, उसे शत्रु गज्य में प्रवेश करने से पूर्व ग्राज्ञा प्राप्त कर लेनी चाहिए, राज्य द्वारा प्रेषित संदेश राजदूत की उसी रूप में पहुंचा देना चाहिए, जैसा उसे पहुंचाने के लिए दिया गया है चाहे उसके जीवन की ही बाजी क्यों न लग जाय ख्रीर यह भी ध्यान रक्खे कि शत्रु ने उसे किस प्रकार तथा किस स्पर्ध में स्वीकार किया है इसके अतिरिक्त राजदूत का कर्ता वय यह भी था कि वह विश्वसनीय प्राप्त स्चना शीव्रातिशीव्र अपने देश में पहुंचा दे। इस कार्य के लिए प्राचीन काल में "गृढु-लेख" (Cipher Code) का प्रयोग किया जाता था। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि प्राचीन भारतवर्ष में भी राजदूतों के कार्य विस्तृत, महत्वपूर्ण एवं व्यापक होते थे। उनके स्वयं के व्यवहार के लिए अनेक प्रकार के नियम थे तथा वर्तमान समय की भाँति, उस समय भी 'कूटनीति', एक शांत पड्यंत्र (Silent Conspiracy) तथा 'राजदूत' एक प्रतिष्ठित गुप्तचर था (an honourable Spy)। प्राचीन भारतवर्ष में यह पद बहुत महस्वपूर्ण था।

शुप्तचर प्रणाली (The Institution of Spies):—श्रन्तर्राष्ट्रीय रांवंघों के चेत्र में गुष्तचर प्रणाली श्रपना विशेष स्थान रखती थी श्रीर गुष्तचर समय समय पर राज्य की श्रद्भुत सेवा करते थे। इसलिए इस प्रणाली का ज्ञान प्राप्त करना श्रानियार्थ लगता है। प्राचीन काल में भारतवर्ष में गुष्तचर श्रत्यावश्यक समके जाते थे श्रीर उनके फार्व की प्रधानता सर्वात्र स्वीकार की जाती थी। गुष्तचरों की सहायता विना शशु पर विजय प्राप्त करना सम्राट के लिए लगभग श्रम्भव नहीं तो कठिन श्रवश्य माना जाता था। वास्तव में गुष्तचर शशु की सेना शादि की पूर्ण स्चना देकर सम्राट को व्यत्तिस्थित ने श्रवगत कराते थे जिसके श्राधार पर भावी योजनाए बनाकर शशु परास्त किया जाता था। इंगलिए गुष्तचर

प्रणाली बहुत अधिक प्रचलित थी। तत्कालीन प्रत्येक लेखक ने इस सम्बन्ध में अच्छा वर्णन किया है। गुप्तचर प्रणाली के विषय में निश्चित नियम एवं परम्पराएँ थीं। तटनुसार गुप्तचर शत्रुदेश में सूचना प्राप्त करने के लिए मेजे जाते थे। कामन्दक के अनुसार दूत दो प्रकार के होते थे; एक प्रकट (राजदूत अथवा Ambassadors, जिनका वर्णन हम कर चुके) श्रीर एक गुप्त (जो चर या गुप्तचर कहे जाते थे) 1१ उसके मतानुसार त्रालक, किसान, वनचारी, भित्तुक, अध्यापक यह दूतों के वेष की मर्यादा है ।२ जड़, मृक, अत्घे, बहरे, पराह, किरात, बौने, कुबड़े तथा श्रौर जो इस प्रकार के कार्य करने वाले, भिक्तुक, चारण, दास, श्रनेक कार्य व कला के जानने वाले, श्रन्तःपुर की बातें बिना किसी के जाने सुन श्रावें, छत्र, चंवर, भारी, यान, वाहन (सवारी) के धारण करने वाले महामात्र यह सत्र वाहर के समा-चारों को जाने, तथा इसी प्रकार अच्छी रसोई करने वाला, शय्या करने में चतुर, थोड़ा व्यय करने वाले, भूगार करने वाले, भोजन कराने वाले, शरीर दावने वाले, जल, ताम्बूल, फूल, गंध श्रीर भूषणों के देने वाले श्रादि द्वारा चर लोग स्थिर चित्त से परस्पर दौत्य कार्य करते हुए विचरण करें ।३ सम्पूर्ण जगत् की इच्छा को जानते हुए जैसे स्र्य की किरणें जलों को ग्रहण करती है, उसी प्रकार सबकी व्यवस्था ग्रहण करते हुए अनेक शिल्पविद्या और अध्यापन विद्या में चतुर दूतगण त्रानेक प्रकार के रूप धारण किये हुए विचरण करें।४ महाभारत के त्रमुसार गुप्तचर साधु, त्रादि ऐसे वेष में जायँ जिसमें पहुँचाने न जा सकें तथा उद्यान, मन्दिर, व्यापारस्थल, व्यायामशाला, सभा-भवन, सचिवालय त्रादि स्थानी पर उन्हें विचरण कर सूचना प्राप्त करनी चाहिए।

कौटिल्य ने भी गुप्तचर प्रणाली का विशद वर्णन किया है। ए तदनुसार सम्राट की यह म्रादेश दिया गया है कि मन्त्रिपरिपद् का संगठन कर लेने के पश्चात् गुप्तचरों की रचना करेगा। म्राधीत् मन्त्रिपरिपद् के पश्चात् महत्व की दृष्टि से दूसरा ही स्थान गुप्तचर प्रणाली की दिया गया था। म्राधीशास्त्र के म्रानसर गुप्तचर, शिष्य सामु, गृहस्य, व्यापारी, तपस्वी, सहपाठी तीक्णप्रकृति, विप देने वाला, मिन्नुणी स्नादि के वेश में भेजे जाने चाहिए। ये गुप्तचर हर प्रकार की पूर्ण स्चना सम्राट को देते रहते थे। म्रापने पद पर कार्य करने से पूर्व इन्हें भी सम्राट को सत्य स्चना देने के लिए शपथ महण्य करनी होती थी। गुप्तचरों की म्रानेक विशिष्ट श्रीणियाँ तथा तदनुसार उनके गुणों की व्याख्या भी स्र्र्थशास्त्र में बहुत सुन्दर ढंग से वर्णित है। शमु के राज्य में भेद का बीज वपन करने का

१ कामन्दव-पृष्ठ १३६, श्लोक ३२।

^{&#}x27;२ उपरोक्त—पृष्ठ १३७, श्लोक ३६।

३ उपरोक्त-पृष्ठ १३=-१३६, श्लोक ४२ से ४७ तक।

४ उपरोक्त-पृष्ठ १३६, रलोक ४=।

एक्षचर चार मुख्य कार्य करते थे-(१) सब घटनाओं, विचारभाराओं तथा जनमत का अध्ययन कर उद्याधिकारियों को च्चित करना । (२) विदेशी राज्यों में अमरण कर पूरी जानकारी देना । (३) राज्य में अष्टाचार एवं चरित्रहीनता का अध्ययन करना । (४) राज्य के कर्मचारियों पर सक्सेनाजी का वष्टुत प्रभाव है । ग्रुप्तचर दोनों लिगों के होते थे । उपरोक्त ।

कार्य भी इन्हें ही दिया जाता था। जनता के संतोष या श्रसन्तोष, का पता भी ये ही लोग लगाते थे। साथ ही सम्राट स्चना के केवल एक स्रोत पर विश्वास नहीं करता था। जब श्रनेक साथनों से एक ही बात की पुष्टि होती थी, तब उस पर विश्वास किया जाता था। भूठी स्चना देने वाला ग्रुप्तचर दिख्त भी किया जा सकता था। इसिलए ग्रुप्तचरों का पूर्ण स्वामिभक्त होना श्रत्यावश्यक होता था। यदि वे बन्दी बना लिये जाते थे तो उनके साथ यद्ध के बन्दियों का सा व्यवहार होता था। उन्हें मृत्युद्रण्ड नहीं दिया जाता था। साथ ही उनकी सफलता उन्हें गौरवपूर्ण ढंग से सम्मानित एवं पुरस्कृत भी किया जाता था। १ इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि प्राचीन भारत में शासन व्यवस्था एवं सुरक्ता की दृष्टि से गुप्तचर विभाग बहुत उन्नत एवं महत्वपूर्ण था। जैसे वर्तमान समय में गुप्त स्चना विभाग (Intelligence Deptt.) श्रत्यधिक महत्वपूर्ण बना हुश्रा है, प्राचीन भारतवर्ष में भी समाज की ऐसी ही उन्नत एवं विकसित स्थिति थी यह सिद्ध होता है।

युद्ध-नियम (Laws of War):— ऋ तर्राष्ट्रीय संबंधों के चेत्र में यदि कूटनीति, राजदूत एवं गुप्तचर विभाग ऋपने उद्देश्य की पूर्ति करने में ऋसफल हो जाते थे तब विभिन्न देशों के बीच उत्पन्न विवादों का निर्णय, ऋ तिम साधन युद्ध द्वारा होता था। इसलिए यह मान्यता बहुत स्पष्ट थी कि युद्ध की ऋावश्यकता कभी भी हो सकती है। प्राचीन भारत में युद्ध के संबंध में भी ऋनेक सिद्धान्त, नियम, एवं प्रकारों का वर्णन किया गया है। साधारणत्या युद्ध के कारण नीचे लिखे थे:—

- (१) साम्राज्ञीय प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए।
- (२) श्रात्म रचा के लिए।
- (३) अधिक भूमि या सम्पत्ति प्राप्त करने के लिए।
- (४) शक्ति संतुलन प्राप्त करने के लिए।
- (५) आक्रमणों के प्रतिकार के लिए।
- (६) पीड़ित जनता की मुिक के लिए।

युद्ध-प्रणाली के सम्बन्ध में भी आदर्शयुक्त नियम थे। कौटिल्य के मतानुसार युद्ध भी दो प्रकार के होते थे:—(१) धर्म युद्ध (प्रकाशयुद्ध) एवं (२) क्टयुद्ध (शकटयुद्ध)। जब युद्ध के साधारण नियमों का पालन किया जाता था, धर्मयुद्ध होता था ग्रीर जब उच्चित-अनुचित नियमों का भेद न रखकर युद्ध किया जाता था, तब कूटयुद्ध होता था। तत्कालीन युद्ध के नियम इस प्रकार थे:—

- (१) युद्ध-त्तेत्र में योद्धा को श्रन्त समय तक डटे रहना चाहिए, पीठ कभी नहीं दिखाना चाहिए।
- (२) युद्ध में प्राण लेना तथा प्राण देना श्रीयस्कर माना जाता था।
- (३) युद्ध सदैव समान लोगों के बीच होना चाहिए था।
- (४) शस्त्रविहीन सैनिक पर श्राक्रमण नहीं किया जाता था।

१ अर्थशास्त्र—भाग १-अध्याय ११ से १४ तक वहुत सुन्द्र वर्णन हैं।

- ४) निम्निलिखित व्यिक्तयों को नहीं मारा जाता था:— पैदल सैनिक (जब दूसरा दल सवारी युक्त हो), शिलण्डी, शरणागत, जो शत्रुता समाप्त कर चुका है, सोता हुआ व्यिक्त, आदि।
- (६। एक व्यक्ति एक बार में एक ही व्यक्ति से युद्ध करेगा।
- (७) सम्राट को केवल विजय के लिए अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अपयशदायक होते हैं।
- (म) कृषि, कृषक एवं साधारण जनता को पीड़ित न बनाया जाय तथा उपज सुरिच्ति रहे।
- (६) शत्रु की भूमि पर भी श्राग नहीं लगाई जायगी, न वृत्त नष्ट किये जायंगे।
- (१०) घायल सैनिकों को, चाहे वे शत्रु पद्म के हों, चिकित्सा की सुविधा दी जायगी।
- (११) अनुचित युद्ध नहीं किया जायगा तथा शक्ति-प्रयोग केवल उस सीमा तक किया जायगा; जब तक शत्रु आत्मसपर्णाण न कर दे।
- (१२) वृद्ध, स्त्री पुरुष, बालक तथा शरणागतों को नष्ट नहीं किया जायगा।
- (१३) विषाक्त बाखों का प्रयोग (वेदों में किया जाय, स्मृतियों में न किया जाय) निषिद्ध था।
- (१४) शत्रु पर अचानक, शस्त्रविहीन अथवा असमान अवस्था में आक्रमण नहीं करना चाहिए।
- (१५) युद्ध-वित्यों के साथ व्यवहार अच्छा तथा उपचार की मुविधा देनी चाहिए ।१ उपयुक्त नियमादि के पालन के लिए प्रत्येक चृत्रिय को उत्तरदायी समभा जाता था, और इन्हीं नियमों के अनुसार युद्ध संचालित होता था। इसके अतिरिक्त तस्कालीन जनमत भी बहुत संगठित एवं प्रभावशाली होता था। इन कारणों से युद्ध सम्वन्धी नियमों का पालन सुचार रूप से होता रहता था। धर्मयुद्धों में तो इन नियमों का पालन बड़ी तत्परता से होता ही था, क्टयुद्धों में भी ऐसे अनाचार या स्वेच्छाचार नहीं होते थे, जैसे आधुनिक समय सामान्यतः हो जाते हैं। नर-मुण्डों का ढेर लगाने का दम्भ या अन्य राज्ञसी वृत्तियों को संनुष्ट करने वाली धारणाएँ, प्राचीन भारतवर्ष की युद्ध नियमावली में नहीं थीं। आत्मसमपंग्र किये हुए, घायल और भागने शत्रु के प्रति उदारता का व्यवहार किया जाता था। युद्ध-समान्ति के बाद शरणागत शत्रु पुन: स्वदेश मेज दिये जाते थे। उन्हें दास नहीं बनाया जाता था। ऐसी उदारता सचमुच अन अलभ्य है। युद्ध के फलस्वरूप जो कीप, बहुमृत्य पदार्थ, शस्त्र खाद्य-सामग्री आदि मिलती थी, वह भी नियमानुसार विजेता राजा हारा ले ली जाती था। नागरिकों की अचल सम्पत्ति पर भी कुछ समय के लिए अस्थायी अधिकार कर लिया जाना

भग्नशस्त्री विषत्रश्च कृतशो हतवाहनः ।
 चिकित्स्यः स्यात्स्वविषये प्राप्यो वा स्वगृहं भवेत् ।
 निम[°]याश्च स भोक्तन्य एप धर्मः सनातनः ॥ महानारत XII 95. 13-14.

था। इस प्रकार युद्धसम्बन्धी बहुत प्रशस्त नियम विद्यमान थे है, र उसका नायन जन्मवतः भली भाति किया जाता था।

युद्ध-प्रणाली--दूसरे देशों से सम्बन्ध रखने के लिए दण्डनीति, कूटनीति श्रादि उपायों का पूरी तरह प्रयोग करते रहने पर भी युद्ध आवश्यक हो जाते थे। अतः युद्ध-प्रणाली का संचिप्त वर्णन कर देना वृथा न होगा। प्राचीन काल में युद्ध-प्रणाली में समय समय पर संशोधन एवं परिवर्तन होता रहा है; परन्तु तत्कालीन कुछ पद्धतियाँ ग्रत्यन्त महत्वपूर्ण थी। व्युहरचना द्वारा युद्ध करना उनमें से एक है। महाभारत में अभिमन्यु के युद्ध में चक्रव्यूह का प्रसंग सर्वविदित है। मनुस्मृति में लिखा है कि राजा को चाहिए कि दण्डाकार, शकटाकार, वराहाकार, मकराकार, सुई के आकार का, अथवा गरुड़ के आकार का व्यूह रचकर शत्रु पर आक्रमण करे और स्वयं पद्माकार व्यूह में रहकर संदेह की दिशा से सेना की आगे बढ़ाये।१ त्राक्रमण के लिए कैसा समय, स्थिति तथा मार्ग अनुकूल होता है, आदि वातों पर भी वहुत ध्यान दिया जाता था। सम्राट की प्रजा, मन्त्रिवर्ग तथा सेना जब तुष्ट एवं पुष्ट हो, तब युद्ध करना उचित माना जाता था। युद्ध के समय नगर की रच्चा का प्रबंध, युद्ध की समस्त सामग्री का साथ रखना, जलमार्ग, जंगलमार्ग आदि की सफाई करवा लेना तथा छहों प्रकार की सेना (पहले राज्य के 'बल' तत्व के प्रसंग में वर्णन किया जा चुका है) को मुसज्जित करने के पश्चात् युद्ध करना हित्साधक माना जाता था। इसके अतिरिक्त मित्र यदि छपकर शत्र से मिला है श्रीर जो सेवक किसी कारण से चला जाकर फिर श्रा गया है तो इन दोनों से बहुत सावधान रहना चाहिए; क्योंकि ये दोनों परम कष्टदायक शत्रु होते हैं। २ इस प्रकार पर्याप्त रूप से विस्तृत वर्णन मिलता है।

उपर्शुक्त वर्णन यह सिद्ध करने में समर्थ है कि प्राचीन भारत में कूटनीति शास्त्र, राजदूतों का आदान-प्रदान, उनके किन कार्य, गुन्तचर प्रथा तथा युद्ध-शास्त्र एवं युद्ध-प्रणालियाँ पूरी तरह से अपनाया हुआ शुद्ध ज्ञान. था। यह सम्पूर्ण संस्थाएँ भारत के तत्कालीन समाज एवं राज्य को उत्कृष्ट रूप से समुन्नत एवं सभ्य राष्ट्र सिद्ध करती हैं। सबसे अधिक महत्व की बात यह थी कि इन सब शास्त्रों एवं विद्याओं का मृल आधार नैतिकता थी। युद्ध जैसी भयंकर परिस्थित में फँस जाने पर भी तत्कालीन समाज अपने नैतिक दायित्वों को नहीं सुलाता था। भौतिक मूल्य कभी भी नैतिक मूल्यों पर विजय प्राप्त नहीं कर सके थे। महाभारत-काल में जाकर कूटनीति और युद्ध-नीति अवश्य अधिक कुटिल होने लगी थी, जब "अश्वत्थामा हतो नरो वा कुं बरो वा" अथवा "स्वयं न दास्वािम" की बाते

दराडव्यूहेन तन्मार्ग यायात् रावटेन वा ।
 वराहमकराभ्यां वा स्त्या वा गरहेन वा ॥
 यतक्ष भयमाराद्वे ततो विस्तारयेद्वलम् ।
 पद्मैन चैव व्यूहेन निविशेत सदा स्वयम् ॥ मनुस्मृति — सप्तम अध्याय-१८७, १८८ ॥

२ मनुस्मृति-सप्तम अध्याय-श्लोक १८३-१८६।

चलने लगीं; किन्तु तो भी युद्ध के अधिकांश नियंमीं का पालन होता था। युद्ध के पश्चात् सायंकाल प्रस्पर मिलने-जुलने की प्रथा निरन्तर प्रचलित रही। अतः यदि यह कहा लाय कि प्राचीन भारत की कूटनीति आधुनिक काल की कूटनीति के समद्ध रखी लाय तो अधिक नीतिमय एवं सफल सिद्ध होगी, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी।

प्रश्त

- 1. Give the qualifications, duties & privileges of a Duta (envoy) in ancient India.
- 2. "The doctrine of Sadgunya (Six-fold Policy) was the corner stone of Diplomacy in ancient India"—Discuss.
- 3. State & Comment upon the main principles of diplomacy accepted in ancient India.

अठारहवाँ अध्याय

पाचीन भारत में साम्राज्यवाद

(Imperialism in Ancient India)

प्रस्तावना—राज्यों के सम्बन्ध में वर्णन करते समय उनका वर्गीकरण तथा स्वह्य के विषय में पर्याप्त विवरण पहले के अध्यायों में दिया जा चुका है। परन्तु फिर भी साम्राज्यवाद का पृथक् वर्णन एक आवश्यकता सी अनुभव होती है। प्राचीन भारत में वैदिक काल से साम्राज्यों की स्थापना होती आई है और लगभग प्रत्येक काल में एक न एक साम्राज्य अवश्य रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। इन साम्राज्यों के रूप, गुण, आकार आदि के अनुसार नामावली में भी भेद रहा करता था और तदनुसार ही उनकी प्रतिष्ठा और प्रमाव रहता था। इन्हीं प्रश्नों का अधिक स्पष्ट अध्ययन करना अनिवार्य है।

प्रकार - वैदिक काल में नृपतंत्र (Monarchy) मुख्य रूप से चार प्रकार का माना . जाता था—(१) नृपतंत्र या राज्य (Monarchy)

- (२) महाराज्य (Great & High Monarchy)
- (३) त्राधिपत्य (Over-Lordship)
- (४) सार्वभौम (Pan-Country-Sovereignty) १

जहाँ तक नृपतन्त्र का प्रश्न है इसकी मान्यता के सम्बन्ध में विशेष व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। महाराज्य के सम्बन्ध में विशेष विवरण प्राप्त नहीं है; किन्तु उपलब्ध सामग्री के आधार पर यह कहा जा सकता है कि तुलनात्मक दृष्टि से समान राज्यों में आंशिक प्रधानता अथवा प्राथमिकता लिये हुए राज्यों को यह संज्ञा दी जाती थी। अपने समीपस्थ राज्यों की अपेन्ना यह राज्य बड़ा होता था। सम्भवतः शासन प्रणाली की दृष्टि से भी महाराज्य अपेन्नाकृत उन्नत होता था। आधिपत्य अवश्य ही ऐसा राज्य था जो अन्य समीपस्थ प्रदेशों पर स्वामित्व के अधिकारों का प्रयोग करता था तथा संरन्नक के रूप में ऐसे प्रदेशों को अपने आधिपत्य में रखता था। प्राप्त प्रसंग में "समन्त पर्यायी स्थात्"र का उल्लेख है। इसके द्वारा पड़ीसियों के संरन्नण के लिए व्यवस्था करने की इच्छा प्रकट होती है। इसका तात्पर्य है कि एक राज्य अपनी सीमाओं से पर दूसरे राज्यों पर भी अधिकार रखता था जीर प्रभाव-

१ आनेव माम्रण—As quoted by Dr. Jayaswal-Hinda Polity-Page 359.

२ ं उपरोक्त ।

पूर्ण ढंग से उनका प्रयोग करता था। समाट खारवेल, अपनी विजयों के कारण अधिपति एवं चक्रवर्ती आदि विशेषणों से सम्बोधित किया गया है। श सार्वभौम बनने की आकांदा प्रत्येक शासक की होती थी। सार्वभौम का साधारण अर्थ यह होता था कि वह अपनी स्वाभा- विक भौगोलिक सीमा तक, समुद्री तट तक तथा उस दोत्र के निवासी समस्त मानव मात्र पर शासन करता था। यह उपतन्त्र का ही बृहत् रूप तथा एक महत्वपूर्ण प्रकार था। शतपथ में वर्णित जन-राज्य (Nation State) से यह बिल्कुल भिन्न था। सार्वभौम का साहित्यक अर्थ यह भी होता है कि जो सार्व (समस्त + भौम (भूमि) समस्त भूमि तथा उससे संबंधित समस्त प्राणियों का अधिष्ठाता हो। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में चतुरान्त साम्राज्य की सीमाएं चारों दिशाओं में निर्धारत होना आवश्यक बताया है। र तत्कालीन भारतीय साम्राज्य की सीमाएं कन्याकुमारो से हिमालय तक वर्णित हैं। इस प्रकार साम्राज्यीय प्रणाली में दो प्रकार अधिक प्रयोग में आते थे, एक तो आधिपत्य प्रणाली और दूसरी सार्वभौम प्रणाली। किन्तु हिन्दू दार्शनिकों ने इन एकच्छत्र राज्यों की निन्दा की है।

हा० जायसवाल के मतानुसार 'समराज्य प्रणाली' भी साम्राज्यीय प्रणाली का ही प्रकार था श्रीर सम्भवत: सार्वभीम प्रणाली से भी पहले प्रचलित था। इस प्रकार की प्रणाली में श्रनेक राज्य एक उत्तम राज्य के नेतृत्व में संगठित हो जाते थे। श्राजकल जिसे 'हम 'संघ-प्रणाली' कहते हैं यह लगभग उसी प्रकार का संगठन था। इसमें राजतंत्र के दोप नहीं होते थे। महाभारत में यह प्रसंग है कि जरासंघ ने 'समरत' की उपाधि प्राप्त की थी श्रीर शिशुपाल इसी संघराज्य का मुख्य सेनापित था। इ उस समय संघ-प्रणाली प्रचलित हो जिसी थी। श्रनेक शासक एकत्रित होकर निर्वाचन करते थे श्रीर उसे सम्राट के पद पर श्रासीन करते थे। यह प्रणाली शासक स्वयं श्रपने हित के लिए, राज्य की मुरज्ञा के लिए श्रपनाते थे। कभी कभी कोई सम्राट श्रपनी सत्ता का दुरुपयोग कर श्रन्य शासकों का शोपण या उन्हें पीड़ित भी करने लगता था, जरासन्थ ऐमे ही शासकों में से एक उदाहरण है। इस पद का निर्वाचन यह सिद्ध करता है कि मुयोग्य व्यक्ति की खोज होती थी तथा शासक वर्ग स्वतन्त्रतापूर्वक श्रपने मत का प्रयोग करते थे। इसीलिए विदेह का शासक जनक 'समरत' का पद प्राप्त कर सका था। प्रभावशाली व्यक्तित्व, चरित्र एवं ख्यांत श्राद्व के श्राधार पर श्राच्यन्त जुना जाता था।

उक्त प्रणाली का विकास बाद में "सार्वभीम" राज्यों के रूप में हुआ। ईसा से लगभग ७०० वर्ष पूर्व यह प्रथा प्रारम्भ हुई थी। जब राष्ट्रीय राज्य, नृपतन्त्र तथा पौराणिक राज्य अस्त होने लगे, तब इस प्रथा का विकास आरम्भ हुआ। मगध, कौसल और अवस्ति ऐसे ही राज्यों में से थे। इसी समय राजनैतिक ज्ञेत्र में यह सिद्धान्त भी प्रचारित हुआ कि पतित राजवंशों से सत्ता छीन लेनी चाहिए। जो शासक अपने उचित कर्ताव्यों का पालन

१ त्रात्रेय नावाण-As quoted by Dr. Jayaswal-Hindu Polity-Page 359.

R Dr. Jayaswal-Hindu Polity-Page 360.

३ उपरोक्त-Page 361.

न करे तथा केवल उपभोग में व्यस्त हो जायं-ऐसे लोगों को पदच्युत करना, नागरिकों का श्राधिकार हो नहीं कर्तव्य भी माना जाने लगा। यह व्यवहार 'कुटिल-नीति' के नाम से विख्यात हुआ। इसी व्यवस्था को ''चक्रवर्त्तां-पद्धित'' भी कहा जाता था। इसका तात्पर्य उस राज्य से होता था जिसके सम्पूर्ण चेत्र में सम्राजीय चक्र-निर्वाध गित से प्रचिलत होता रहे। महात्मा बुद्ध ने राजनीति की शब्दावली से ही 'चक्र' शब्द लेकर 'धर्मचक्र' द्वारा धार्मिक साम्राज्य की धारणा व्यक्त की थी। उसके पश्चात् शताब्दियों तक राजनीतिक एवं धार्मिक चेत्रों में साम्राज्य स्थापित करने की परिपाटी चलती रही। इस परिपाटी का मुख्य उद्देश्य केवल एकता स्थापन था। प्रारम्भ में अत्यधिक उत्साह के कारण यह प्रथा बहुत लोकप्रिय रही; किन्तु बाद में लुप्त सी होने लगी। यहाँ तक कि राज्यों के मान्यताप्राप्त स्वरूप में गिना जाना भी रुक गया। पुनः संघात्मक राज्य की परम्परा विकसित होने लगी। यह विश्वास हव हुआ कि प्रत्येक राज्य को स्वतन्त्रतापूर्वक रहने का मौजिक श्रिधकार है।

तत्कालीन साम्राज्यों में शासन की प्रचलित प्रथाश्रों में श्रनेकरूपता होते हुए भी कुछ सामान्य विशेषताएँ थीं । सत्ता का केन्द्रीयकरण सबसे प्रमुख विशेषता मानी जा सकती है। नियम एवं न्याय व्यवस्था शासनानुक्ल होने लगी थी, राज्य के कर्मचारी सम्राट की श्राज्ञा ही सब कुछ समक्षने लगे तथा ग्रामों की व्यवस्था भी ऊपर से नियंत्रित होने लगी। समुद्री तथा स्थलीय व्यापार, उद्योग श्रादि राज्य के श्रधीन हो गए। गुणों के विकास के साथ कुछ श्रवगुण भी विकसित हुए। वेश्यावृत्ति, जुन्ना, विश्रान्तिग्रह, मधुशालाएँ (मिदरालय) श्रादि के विभाग भी राज्य ने संगठित किये। खानों श्रादि पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण हुश्रा। इस प्रकार राज्य ने (एकमुख) सारा काम केन्द्रित कर दिया था। जहाँ श्रधिक केन्द्रित शासन हुन्ना, श्रसफलता रही, जैसे मगध में श्रन्यथा उदारवृत्तिमय साम्राज्य केन्द्रित होते हुए भी, सफल रहे, जैसे बौद्धसंघ श्रादि।

उपर्कृत विभिन्न पद्धतियों का समय बीत जाने पर प्राचीन भारत में साम्राज्ञीय प्रणाली का नवीन रूप विकसित हुआ, जिसे संवुलन पद्धति (Compromise) कह सकते हैं। यह ऐसा तन्त्र था जिसमें नृपतन्त्र, संघतंत्र तथा आधिपत्य का थोड़ा थोड़ा अंश सम्मिलित था। उत्तर वैदिक काल में ऐसे राज्य अवश्य सफल रहे थे। इस प्रकार ये साम्राज्य संत्तेप में राजतंत्र के ही बृहद् रूप थे। वैधानिक दृष्टि से ये शिक्तयाँ, शांति और युद्धकाल में विभिन्न रूप से प्रकट होती थीं।

सम्राट का स्थान एवं महत्व—राज्यों की शासन व्यवस्था में ग्रन्तर होते हुए भी सम्राट का स्थान तथा उसके साथ सम्बन्धित कर्च व्यभावना प्राचीन काल में सदैव ही प्रधान रही। वास्तव में सर्वे सर्वा रहते हुए भी संवेधानिक दृष्टि से सम्राट सदैव ही प्रजा का सेवक रहता था। डा० जायसवाल ने लिखा है कि सम्राट 'संवेधानिक दास' की स्थिति में रहता था। को किसे डा० जायसवाल ने हिन्दू हाब्स श्रीर नृपतन्त्र का समर्थक कहा है, लिखा है कि सम्राट को सदैव प्रजा की इच्छानुसार व्यवहार करके ही श्रानन्दित होना

[&]quot;Constitutional Slave"—Dr. Jayaswal-Hindu Polity-Page 353.

चाहिए । १ इसी त्याग एवं सेवामाव के कारण सम्राट का स्थान ऋत्यन्त प्रतिष्टित वन जाता था । नैतिक बल उसका आधार था । महाभारत में सम्राट का जन्म ही दूसरों की सेवा के लिए (परिहतार्थ) बताया गया है । जैसे अरव अथवा अन्य समाजीपयोगी जीवधारी परोपकार के लिए ही जीवन व्यतीत करते हैं । इसी प्रकार सम्राट का जीवन भी दूसरों के लिए ही होता था । इसी दृष्टि से वह सम्पूर्ण साम्राज्य की व्यवस्था करता था, जिसमें व्यक्तिगत भावनाएं प्रधान न रहकर, 'जनहित', सामान्य-हित आदि के उच्च आदशों से प्रेरणा मिलती थी । अन्य मन्त्रिगण तथा प्रशासकीय अधिकारी परिवर्तित होते रहते थे, किन्तु सम्राट सदेव दीर्घ काल तक समस्त उत्तरदायित्व का केन्द्र रहता था । वह निर्वल होते हुए भी राज्य का प्रतीक माना जाता था । र शुक्रनीति के अनुसार राज्य रूपी वृत्त का मूल सम्राट ही होता था । तदनुसार मन्त्रिपिष्ट् स्कन्ध (Trunk), सेनाध्यक्त शाखाएँ, सेना पर्वलव, प्रजा कुसुम, फल जन-समृद्धि, तथा बीज समस्त भूमि ही था । र महाभारत-काल में भी सम्राट का पद तथा कार्य सर्व अवन के समस्त कर्मों में प्रशासकीय कार्य उत्कृष्ट समभने की भावना व्याप्त थी । र जीवन के समस्त कर्मों में प्रशासकीय कार्य उत्कृष्ट समभने की भावना व्याप्त थी । र जीवन के समस्त कर्मों में प्रशासकीय कार्य उत्कृष्ट समभन जाता था । इस प्रकार प्राचीन भारतवर्ष में सम्राट का स्थान समाज में सर्वोच्च एवं राज्य में अत्यन्त महत्वपूर्ण था ।

प्रश्त

- 1. Is it true that the social organization in ancient India. Was based secularism? Discuss.
- 2. Discuss that there was a welfare state in ancient Hindu India.

र प्रजासुखे सुखं राग्नः प्रजानाञ्च हिते हितम् । नात्मप्रियं हितं राग्नः प्रजानां तु प्रियं हितम् ॥ श्रर्थशास्त्र भाग १, श्रनुच्देद १६ (१६) ।

२ ध्वजमात्रीऽयम् । ऋर्धशास्त्र-माग ४, श्रनु० ६।६५ ।

राज्यवृत्तस्य नृपतिम् लं स्कन्धाश्च मिन्त्रसः।
 शाखाः सेनाधिषाः सेनाः पह्नवाः कुतुमानि च ।
 प्रजाः फलानि भूभागा बीनं भृभिः प्रकल्पिता । शुक्रनीतिसार/४।१२ ॥

४ सर्द-धर्मपरं हात्र लोकश्रेष्ठ सनातनम् । (Of all dharmas tulership is the hig hest Society, for all times) Dr. Javaswal—Hinda Polity-Page 354.

उन्नोसवां ग्रध्याय

प्राचीन भारत में समाजवा

(Socialism in Ancient India)

प्रस्तावना — समाज की प्रत्येक संस्था वहाँ की भूमि के अनुसार स्वयं उत्पन्न होती रहती है। साधारणतया दूसरे स्थानों की व्यवस्था का अनुकरण संमाज में प्रचिलत है, किन्तु त्रमनुकरण के पश्चात् भी वे संस्थाएँ उस समय तक सफल नहीं हो सकतीं; जब तक वे स्थानीय वातावरण के अनुकूल नहीं हो पातीं। प्राचीन भारत में विभिन्न संस्थाओं एवं प्रणालियों का इतिहास अत्यधिक गौरवमय रहा है। शताब्दियों का इतिहास यह सिद्ध करता है कि विदेशी स्राक्रमण एवं स्रांतरिक संवर्षों द्वारा सामाजिक एवं राजनीतिक विकास-क्रम कभी श्रवरुद्धं श्रीर कभी दिशा परिवंत्त^रन की कठिंनाइयों का सामना करता रहा है। किन्तु भारतीय जीवन का गुप्त स्रोत सदैव शिक्तशाली रहा है। उसी का फल है कि अनेक विदेशी प्रभाव एवं संस्थात्रों के सम्पर्क में रहकर, विदेशी जीवन की भौतिक बृत्तियों को निकट से देखकर तथा जीवन को सुखमय बनाने के साधनों की उपलब्धि होने पर भी भारतवर्ष सामाजिक जीवन के मूल्यों को वास्तविक, एवं न्यायिक दृष्टि से ही समभता रहा है। वास्तव में सच यह है कि प्राचीन भारत के समस्त संगठन की पृष्ठभूमि हमारे ग्राम थे। उनका सामाजिक, श्रार्थिक एवं राजनैतिक जीवन इस प्रकार संगठित था कि साम्राज्य का उत्थान-पतन, युद्धों में विजय-पराजय, स्नाकामकों का स्नावागमन स्नादि उन्हें प्रभावित नहीं कर सकते थे। सत्र प्रकार की श्रापत्तियों के समय भी भारतीय ग्राम चट्टान की भाँति श्रविचल तथा समुद्र की भांति शांत रहते थे। ग्रामों की इस स्थिति का मुख्य कारण था तत्कालीन समाजवाद। राज्य का इस स्रोर कितना योग था, यह हमें देखना है।

प्राचीन भारत में समाजवाद — वर्त मान युग में समाजवाद का मूल अभिप्राय यह है कि सम्पत्ति व्यक्तिगत न होकर समाज या समुदाय के अधिकार में रहे, जिससे सभी को आवश्यकतानुसार उसके उपयोग की समान मुविधा रहे और धनी-निर्धन की विषम समस्या उत्पन्न न हो। साथ ही समाज के उत्पादन के साधन आदि भी किसी एक अथवा कुछ व्यक्तियों के आधिपत्य में न होकर समाज द्वारा नियंत्रित हों, जिससे उत्पादन, वितरण, उपभोग आदि में अन्याय न हो। इस दृष्टि से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीन काल में भारत में मी समाजवादी व्यवस्था थी। प्राचीन भारत की राजनैतिक व्यवस्था के संबंध में

कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक अत्यन्त महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस ग्रंथ के विख्यात टोकाकार श्री महस्वामी का मत है कि प्राचीन काल में जल और स्थल का स्वामी सम्राट ही होता था; इन दो के अतिरिक्त अन्य सब चीजों के स्वामी प्रजा के लोग हो सकते थे। यद्यपि कौटिल्य ने स्वयं यह कहीं स्पष्ट नहीं किया है कि भूमि का स्वामित्व व्यक्तिगत भी हो सकता है अथवा नहीं; तथापि इस बात का समर्थन किया है कि राज्य को अपने नागरिकों का बाहर जाना तथा विदेशियों का अपने यहां आना प्रोत्माहित करना चाहिए, नवीन नगरों की स्थापना करनी चाहिए। राजकीय भूमि (Crown Lands) जीवन मर के लिए कुपकों को दे देनी चाहिए; किन्तु यदि वे उचित रूप से कृषि करने में असमर्थ हों तो भूमि अन्य लोगों को दे देनी चाहिए। इस प्रकार भूमि का स्वामित्व, व्यक्तिगत न होकर, राज्य अथवा समाज का होना सिद्ध होता है।

इसके अतिरिक्त कीटिल्य के अनुसार राज्य के अन्य बहुत से कार्यों का नियंत्रण एव निर्देशन भी अधीक्कों (Supeirntendents) के अधीन होना चाहिए था। तदनुसार देश के बनों का स्वामित्त्र तथा प्रशासन भी राज्य का होना चाहिए और वन की समस्त उपयोगी वस्तुए; जैसे ईंधन, घास, लकड़ी आदि पर भी राज्य का आधिपत्य रहना चाहिए। इसी प्रकार कीटिल्य ने खानों तथा खनिज वस्तुओं पर राज्य के एकाधिकार का समर्थन किया है। राज्य के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति केवल विशेष आज्ञानुसार ही खानों आदि का उपयोग कर सकते थे। कीटिल्य ने तो यह भी लिखा है कि अन्य उद्योग-धन्यों: जैसे तेल, आटा, शक्तर आदि पर भी राज्य का नियन्त्रण अनिवार्य है। सम्राट की मत्त्य केत्र (Fisheries), नौकाविहार तथा पुष्कारिणी एव भोलों आदि में शाक आदि वस्तुओं के व्यापार पर भी स्वामित्व के अधिकार का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार जल और स्थल की समस्त महत्वपूर्ण वस्तुओं और उनके उत्पादन पर राज्य का स्वामित्व होता था, व्यिक्त का नहीं। यही प्राचीन समाजवाद का शुद्ध रूप है।

इसके श्रातिरिक्त राजकीय व्यवस्था भी पूँ जीपित रूप में न होकर लोककल्याएकारी राज्य की भाँति थी। यह निम्नलिखित वर्णन से सिद्ध हो जायगा:-कौटिल्य का मत है "जल-यान एवं नौकाएँ राज्य को हो होनी चाहिए तथा निश्चित मृल्यों पर उनका प्रयोग संभय रखना चाहिए। खिनज वस्तुश्रों का व्यापार राज्य द्वारा केन्द्रित किया जाय श्रीर इन वस्तुश्रों को निश्चित चेत्र से बाहर उत्पन्न करने, क्रय एवं विक्रय करने वालों के लिए दण्ड विधान भी करना चाहिए। राज्य के हित के लिए तथा अनुचित लाभ रोकने के लिए मृल्य एवं लाभ भी निर्धारित किये जाने चाहिए। साधारणतया एह उत्पादन की वस्तुश्रों पर ५ प्रतिशत तथा श्रायात वस्तुश्रों पर १० प्रतिशत का लाभ उचित मानना चाहिए। विशेष परिश्चितयों में (जैसे वस्तुएँ न विकें, हानि हो जाय श्रादि) मृल्य बढ़ाये भी जा सकते थे। परन्तु मिश्रण (Adulteration) श्रादि करने के श्रपराध में पूँ बीपितयों के लिए कटिन दण्ड की व्यवस्था भी होनी चाहिए। श्रमिको के हितों की रखा का नार भी राज्य पर स्वीकार किया गया था। यदि बिना पारिश्रमिक निश्चय किये कोई व्यक्ति अम करता था रो

कृषक या ग्वाले को कमशः उपन या घी का वित वाँ भाग मिलना चाहिए। दास प्रथा नियंत्रित एनं नियमित बनानी चाहिए थी श्रीर मुदे घसीटना, मल-मूत्र अथवा जूठन साफ करना आदि कार्य लेकर अथवा अन्य प्रकार से दासों के साथ दुर्व्यवहार करना चाहिए।"

समाजवादी दृष्टिकीण के अनुसार तथा जन-हित की दृष्टि से राज्य पर यह दायित्व भी रखा गया था कि निर्धन, गर्भत्रती स्त्रियाँ तथा उनके नवजात शिशु, अथवा नालक, वृद्ध भी रखा गया था कि निर्धन, गर्भत्रती स्त्रियाँ तथा उनके नवजात शिशु, अथवा नालक, वृद्ध पुरुष, पागल, अपंग तथा निरसहाय आदि लोगों की सहायता की जाय। वेकारों को काम दिलाना तथा विधवाओं, लीण अग स्त्रियों, कन्याओं, भिन्तुणियों आदि को कर्ताई केन्द्र में स्त्र कातने के कार्य पर लगाना भी राज्य का ही उत्तरदायित्व होता था। महामारी के समय उपचार की व्यवस्था तथा अन्य आपत्तियों के समय जनता की सहायता करना भी सम्राट का उपचार की व्यवस्था तथा अन्य आपत्तियों के समय जनता की सहायता करना भी सम्राट का कर्ता था। नाइपीड़ितों के लिए सहायता कार्य का विधान तथा अग्नि के प्रकार से बनाने के लिए जलयुक्त घट, कुल्हाड़े, सीढ़ी (Ladder) आदि की व्यवस्था भी राज्य करता था। इन व्यवस्थाओं के लिए व्यावहारिक तथा दैविक सब प्रकार के साधन काम में लिये जाते थे। इन व्यवस्थाओं के लिए व्यावहारिक तथा दैविक सब प्रकार के साधन काम में लिये जाते थे। अमेक प्रकार की आपत्तियों को देवी सहायता से दूर करने के लिए प्रदान की गई थीं। र संकट-अमेक प्रकार की आपत्तियों को देवी सहायता से दूर करने के लिए प्रदान की गई थीं। र संकट-आने सम्राट हर प्रकार की सहायता का प्रयत्न करता था, चाहे स्वयं के साधनों से, मित्र शासकों की सहायता से, सम्पत्तिशालियों के सहयोग से, किसी भी तरह व्यवस्था करना उसका शासकों की सहायता से, सम्पत्तिशालियों के सहयोग से, किसी भी तरह व्यवस्था करना उसका धर्म माना गया था।

इस प्रकार कीटिल्य के अर्थशास्त्र में समाजवाद का चित्र दृष्टिगत होता है। जहाँ उत्पादन के साधन समाज के अधिकार में थे, अभिकों का हित, राज्य की परिस्थितियों का नियंत्रण, संकटकाल में सब प्रकार की व्यवस्था आदि के कार्य राज्य के ही अधीन थे। अतः यह कहा जा सकता है कि वर्ष मान समय में भारत सरकार द्वारा स्टीकृत समाजवादी व्यवस्था यह कहा जा सकता है कि वर्ष मान समय में भारत सरकार द्वारा स्टीकृत समाजवादी व्यवस्था संबंधी नीति न नई है और न विदेशों से ली हुई, वरन हमारे स्वयं के अतीत की अद्घट संबंधी नीति न नई है और न विदेशों से ली हुई, वरन हमारे स्वयं के अतीत की अद्घट संबंधी नीति न नई है और न विदेशों से ली हों और वे इतनी मीलिक, जितनी यूरोप विचार-परम्पराएं उत्तराधिकार में प्राप्त की हैं और वे इतनी मीलिक, जितनी यूरोप की कोई भी अन्य संस्थाएँ। राजनैतिक, प्रशासकीय तथा आर्थिक समस्याओं का राज्य से कैंसा अपेर क्या संबंध है, ऐसे गम्भीर प्रश्नों का विवेचन जिस स्वतंत्रता से किया जाता था, वह और क्या संबंध है, ऐसे गम्भीर प्रश्नों का विवेचन जिस स्वतंत्रता से किया जाता था, वह सतर कम से कम १६वीं शताब्दी तक तो यूरोप में प्रचित्त नहीं था। इस प्रकार प्राचीन स्तर कम से कम १६वीं शताब्दी तक तो यूरोप में प्रचित्त नहीं था। इस प्रकार प्राचीन सारत का समाजवाद बहुत सुन्दर, संगठित एवं संवैधानिक सा प्रतीत होता है।

उदाहरणार्थ, 'टिड्डीटाल' की जागीर इसलिए दो जाती थी कि जब कभी उस भाग में टिड्डी दल का प्रकोप हो, तो वह व्यक्ति (अधिकांश नाथ, भारती, गोसाई वैरागी लोग होते थे) जो उस चेत्र की प्रकोप हो, तो वह व्यक्ति (अधिकांश नाथ, भारती, गोसाई वैरागी लोग होते थे) जो उस चेत्र की टिड्डी दल से रचा करने के लिए आगीर का उपभोग करता था, अपनी मंत्र अथवा तंत्र शक्ति से उस टिड्डी दल को विना नुकसान पहुं चाये चेत्र से वाहर निकाल देता था। यह कहावत है कि वह घट का केवल मुंह लेकर खड़ा हो जाता था और फिर ऐसा थोग करता था कि सारी टिड्डियाँ उस घटना केवल मुंह लेकर खड़ा हो जाता था और फिर ऐसा थोग करता था कि सारी टिड्डियाँ उस घटना केवल मुंह लेकर खड़ा हो जाता था थी। इस कथन में कोई सत्य नहीं प्रतीत होता, परंतु 'टिड्डी-मुख में होकर कहीं दर निकल जाती थीं। इस कथन में कोई सत्य नहीं प्रतीत होता, परंतु 'टिड्डी-

सामाजिक सेवाएँ (Social Services): - जैसा ऊपर समाजवाद के संबंध में में कहा गया है। लगभग उसी प्रकार यह भी सच है कि प्राचीन भारत में सामाजिक सेवार्झों की व्यवस्था थी। यह तो स्वीकृत मत है कि भारत में सदा से धर्म का प्राधान्य रहा है। इस-लिए प्रत्येक कार्य का महत्व धर्म की भाषा में समभाया गया है। सम्राट के अधिकार, प्रजा . के कर्ताव्य तथा परिवार त्रादि इकाइयों में भी पिता-पुत्र के परस्पर कर्ताव्यों त्रादि की व्याख्या धर्म द्वारा ही हुई है। इसी प्रथा के अनुसार प्राचीन हिन्दू शासकों के द्वारा अपना कर्त्तव्य पालन करने के लिए समय-समय पर अनेक सामाजिक कार्य किये जाते थे। वास्तव में इन कार्यों को व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य जनता के मुख एवं कल्याण की वृद्धि करना होता था । सङ्कों बनाना, विश्रामगृह बनाना, कुएँ खुदवाना, मार्गों पर बुझ लगवाना, परीपकारी कार्य करना आदि सेवाएँ लगभग प्रत्येक शासक द्वारा की जाती थीं। उस समय इन कार्यों में राज्य ही अप्रणी होता था, जनता का भाग नहीं के बरावर था। इसलिए विभिन्न शासकों पर निर्भर होने के कारण सामाजिक सेवाओं का प्रारम्भ या स्वगन समय तथा शासक के अनुसार चलता रहा। परन्तु सम्राट श्रशोक के समय में तो सामाजिक सेवाश्रां का कार्य राज्य का प्रधान कर्त्त व्य माना जाने लगा। उसके प्रस्तर-लेख, स्तम्भ-लेख ग्रादि इस स्थिति की बहुत स्पष्ट करते हैं। इन्हीं प्रमाणों से यह भी प्रकट होता है कि सामाजिक सेवाय्रों का श्रीगणेश करने वाला प्रथम शासक अशोक नहीं है। एक लेख में अशोक ने लिखा है कि "मैं वही कार्य कर रहा हूं, जी मेरे पूर्वज कर चुके हैं।" अत: यह सिद्ध होता है कि सामाजिक सेवा का प्रचलन भारतवर्ष में बहुत प्राचीन है।

तत्कालीन सामाजिक सेवाश्रों का उद्देश्य मानवमात्र की उन्नति करना होता या, इसलिए धर्म का उपयोग किया जाता था। धर्म के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति, श्रिष्कारी तथा संबंधित
नागरिकों को कर्त व्यपरायणता की शिक्ता दी जाती थो श्रोर दूसरी श्रोर राज्य द्वारा लोकसेवाश्रों की व्यवस्था की जाती थी। इस दृष्टि से प्राचीन श्रीर श्रवांचीन सेवाश्रों में वड़ा भेद
मालूम होता है। उदाहरण के रूप में श्राजकल सेवाश्रों का उद्देश्य सामाजिक शिक्ता का
प्रसार एवं ग्राम विकास योजनाश्रों को सफल बनाना तथा जनता को संगठित कर उन्नति के
मार्ग पर उन्मुख करना होता है; परन्तु प्राचीन समय में जनता में ऐसी जागरूकता पदा
करने की श्रोर ध्यान न देकर उनकी सामृहिक उन्नति की व्यवस्था की जाती थी। सामाजिक
सेवा से श्रन्य दूरस्थ संबंध नहीं से थे। केवल धर्म श्रवांत् कर्त व्ययरायणता जागत की जाती
थी, भौतिक वैभव श्रौर समृद्धि की श्रोर सीधा लच्च नहीं किया जाता था। वास्तव में तो
कर्त व्यपरायणता से समृद्धि उत्पन्न होती ही थो श्रोर यह श्रिषक श्रीयकर होती थी। गीता
में 'कर्मग्येवाधिकारस्ते' का नाद इसी श्रोर इंगित करता है। परन्तु वर्त्तमान समय में समृद्धि
श्रोर वैभव का श्रांकर्वण दिखाकर कर्त व्य भावना को भीरित करने का प्रयान किया जाता है,
जिसमें सफलता नहीं मिलती।

प्राचीन समय के राज्य प्राणिमात्र का हित करना अपना कर्ताच्य समभते थे। सम्राट अशोक ने मानव के लिए ही सहकें, विश्रान्तिग्रह, कुए, कृत्वारोपण आदि नहीं किया परन्तु पशु-पित्यों के शुस के लिए भी व्यवस्था की यी। मेगास्थनीज की डायरी में ऐसी अनेक आकर्षक बातें हैं जो इस पत्त पर प्रकाश डालती हैं। हाथी और घोड़े केवल राज्य ही रख सकता था; क्योंकि इन उच्चजातीय पशुओं का पालन साधारण व्यक्ति की त्त्मता के बाहर था। बन्दर, श्वान, तोते, केला, केरिकयाँ (ये दोनों प्रकार के पत्ती अब शायद नहीं मिलते), मछिलियां, कश्यप आदि की भी व्यवस्था की जाती थी। मेगास्थनीज का मत है कि उस समय पंख वाले बिच्छू, पंख वाले सर्प तथा समुद्री सर्प भी भारतवर्ष में होते थे। एक ऐसे जानवर का भी वर्णन है जो आकार में घोड़े से दुगुना बड़ा और गहरे बालों वाली पूँछदार हीता था; परन्तु किसी की डिट्ट में नहीं आना चाहता था इसिलए संकोचशील वृत्ति के कारण पलायनवादी प्राणी था। इस प्रकार अनेक प्रकार के पशु उस समय थे। राज्य की और से पशु-चिकित्सालयों की स्थापना की जाती थो।

समाट अशोक के राज्यकाल में मानवी मूल्य अपने प्रतिष्ठित स्थान पर थे। वयोद्देख नागरिकों का सम्मान तथा अंगहीन लोगों के प्रति दया-भाव रखना वह आवश्यक सम्भता था और यह केवल उपदेश की हष्टि से नहीं, किंतु स्वयं भी ऐसे आदशों का पालन करता था। वह स्वयं कहता था कि मैं चाहे स्वयं भोजनालय में होऊ, चाहे शयन एह अथवा अश्वपीठ पर, चर एवं दूर्ता को चाहिए कि जनता का विष्रह. कष्ट आदि की स्चना मुभे तत्काल दें। सामाजिक कल्याण की हष्टि से हो अशोक ने ''धममहामात्र'' की संस्था स्थापित की। इन लोगों का कर्व व्य था कि वे जनता की भौतिक समृद्धि एवं आध्यात्मिक उन्नति के हेतु हर सम्भव सहायता करें। इस प्रकार ये लोग शरीर, ज्ञान और विज्ञान, (दैहिक, भौतिक एवं दैविक) आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए ही नियुक्त किये गये थे।

दूसरी शेगी के कर्मचारी "राजुक" कहे जाते थे। इसका मुख्य कार्य अन्य राज्य कर्मचारियों को पुरस्कृत एवं दिएडत करने के लिए जानकारी प्राप्त करना। इससे कर्मचारी विश्वास एवं इड़तापूर्वक अपने कार्य में संलग्न रहते थे। 'राजुक' लोगों को जन-सम्पर्क द्वारा जनता के हित एवं सुख का पूर्ण ज्ञान होता था। अशोक के शासन-काल में तो अपराधियों तक को पर्याप्त स्वतंत्रता मिलती थी। उदाहरण के रूप में मृत्युद्गड पाने वाले अपराधियों तक को पर्याप्त स्वतंत्रता मिलती थी। उदाहरण के रूप में मृत्युद्गड पाने वाले अपराधि को दण्ड से पूर्व तीन दिन का समय दिया जाता था, जिसमें वह अपनी भौतिक (संसारिक) व्यवस्था कर सके तथा दूसरे लोक में जाने की दृष्टि से प्रार्थना या उपवास आदि द्वारा तैयारी कर सके। यह अपराधियों का मूल अधिकार स्वीकार किया गया था। इस प्रकार उस समय राज्य प्रशासन द्वारा अनेक सिद्धान्त स्वीकार किये गए थे। विशेष रूप में नागरिकों द्वारा राज्य की सेवा प्राप्त करने तथा नियम के समच पूर्ण रूपेण समानता के अधिकार अत्यन्त ही महत्वपूर्ण थे।

उपर्युक्त सम्पूर्ण वर्णन का श्रध्ययन करने के पश्चात् यह एक स्वामाविक प्रश्न उत्पन्न होता है कि प्राचीन भारतवर्ष की व्यवस्था क्या लोककल्याणकारी राज्य की थी ? बहुत श्रधिक मात्रा में इस प्रश्न का उत्तर उपर्युक्त वर्णन के श्राधार पर स्वीकारात्मक रूप में मिल जाता है: परन्तु वर्ष्त मान समय का यह एक महत्वपूर्ण विषय होने के कारण हम पुन: द्वस द्वाटर से संदिग्त वर्णन करना श्रच्छा समभते हैं।

प्राचीन भारत में लोककल्याणकारी राज्य (Welfare State Ancient India):— श्राधुनिक समय में राज्य को एक कत्यारणकारी समुदाय के रूप समभा जाने लगा है प्राचीन समय की व्यक्तिवादी विचारधारा के अनुसार केवल सुरज्ञा, शांति एवं न्याय के कार्य सम्पादित कर, वाग्रिज्य, शिचा, स्वास्थ्य, गरीबी ब्रादि की समस्यास्रों को छोड़कर वर्त्तमान राज्य संतुष्ट नहीं रह सकता और न समाजवादी की भाँति अत्यधिक नियंत्रण ही संभव हो सकता है। इसलिए वर्तामान समय में राज्य को सेवा-राज्य स्वीकार किया जाने लगा है। वास्तव में लोकतन्त्रात्मक राज्य का मुख्य उद्देश्य लोक-सेवा ही है। त्रात: राज्य श्रशिचा, वेकारी, निर्धनता, श्रह्वास्थ्य, शरावखोरी इत्यादि बुराइयों को दूर करना भी श्रपना कर्त्त वय समभता है। यही नहीं, राज्य प्रत्येक चेत्र का नियमन (Regulation) करता है श्रर्थात्ं व्यापार एवं वाणिज्य के नियम बनाना, नए कर निर्धारित करना, उत्पादन एवं वित-रण स्रादि पर नियंत्रण रखता है । विवाह, छूत्राछूत, जायदाद इत्यादि के संबंध में भी राज्य कानून बनाता है। यह लोककल्यागाकारी राज्य का चित्र है। इस दृष्टि से देखने पर प्राचीन भारतवर्ष के राज्य पूर्ण रूप से कल्याणकारी राज्य की परिसीमा में सम्मिलित होते हैं। तत्का-लीन राज्य सामानिक, त्रार्थिक, परोपकार, स्वास्थ्य तथा औद्योगिक एवं विकास के च्लेत्र में भली प्रकार नियंत्रण करते थे। इन सब चेत्रों में राज्य की कार्य प्रणाली का वर्णन हम क्रमशः करेंगे।

सामाजिक कार्यः — साधारणतया प्राचीन भारत के राज्य स्वयं की जनता के संरच्यक समभते थे। इसिलए जनता के विरोधी स्वार्थों का समन्वय करना, शांति स्थापित रखना, दास एवं स्वामी के मध्य मधुर संबंधों की स्थापना करना आदि कार्य किये जाते थे। इन कार्यों से संबंधित नियम बनाये जाते थे और उनका पालन दृढ़तापूर्विक किया जाता था। स्वामी और सेवक के संबंध में सम्राट अशांक के समय में यह नियम था कि यदि सेवक का अपराध न होते हुए कार्य बन्द रहता है तो भी स्वामी द्वारा वेतन देना अनिवार्य था। साथ ही यदि सेवक कर्ज व्यव्यव्यत होता, चोरी करता अथवा सम्पत्ति आदि को च्वित पहुँचाता तो उसे दिख्डत किये जाने की व्यवस्था भी थी। इस प्रकार सामाजिक चेत्र में संतुत्तित व्यवस्था की जाती थी।

श्रार्थिक कार्यः—इस त्तेत्र में उपभोक्ताश्रों की रत्ता का दायित्व गाय पर था। साधारण श्रानिवार्यताश्रों की वस्तुश्रों का मृत्य सामान्य स्तर पर रहना श्रावश्यक था। राज्य यह ध्यान रखता था कि व्यापारिक लोग ऐसी वस्तुश्रों का मृत्य बढ़ाकर कै ना न कर दें नी जनता के लिए श्रानिवार्य हैं, श्रावश्यकतानुसार मृत्यों का निर्धारण भी जनहित की दृष्टि है गाय द्वारा कर दिया जाता था। परन्तु इसका श्रार्थ यह नहीं था कि उत्पादकों श्रायया व्यापारी वृर्ग के हितों का ध्यान नहीं रहता था। उत्पादन की श्रावश्यक सामग्री, श्रामकों का वेतन, कर-गुल्क श्रादि, यातायात व्यय श्रादि की ध्यान में रखकर ही मृत्य निर्धारित किये जाते थे। इसके श्राविरिक्त श्रार्थिक त्त्रेत्र में राज्य सदैव कियाशील तथा जागहक रहता था। तील के लिए सर्वत्र एक से बाट प्रयोग में लाये जाते थे। जिन पर राज्योंक होता था, वे ही बाट कान

में लाये की सकते थे, इसके विरुद्ध व्यवहार करने वाले दण्डित होते थे खाद्य तथा अन्य कर्तिओं में मिश्रण करने वाले तथा अन्य किसी भी प्रकार का घोखा या छल करने वाले व्यापारी दण्ड के भागी होते थे। इस प्रकार आर्थिक चेत्र में राज्य का पर्याप्त नियन्त्रण था।

परोपकारी कार्यः — जनता का कल्ट-निद्यारण करना राज्य का धर्म समभा जाता था। इसलिए अपाहिज, अस्वस्थ एवं निस्सहाय व्यक्तियों की सहायता के लिए व्यवस्था की जाती थी। अनाथों के लिए, बृद्ध एवं विचलित मस्तिष्क वाले पुरुष एवं स्त्रियों के लिए सदावत की व्यवस्था की जाती थो। जैसा अपर कहा गया है — निर्धन गर्भवती स्त्रियों के लिए सहायता का प्रवन्ध होता था। बेकारी के कारण अन्द में होने वाले परिवारों के लिए कर्ताई विभाग में कार्य दिया जाता था। समाज में साधु अथवा सन्यासी बनना भी राज्य द्वारा नियं त्रित था। अपने अपर निर्भर रहने वाले परिवार के सदस्यों की व्यवस्था किये विना कोई व्यक्ति साधु नहीं बन सकता था। इसी प्रकार समर्थ नागरिकों का यह उत्तरदायित्व स्वीकार किया गया था कि वे अपने अल्पवयस्क माई-बहिन तथा अपनी संतान का पोषण करे। इस कार्य में त्रुटि होने पर ऐसे नागरिक दण्ड के भागी होते थे। इस प्रकार परोपकार के जेत्र में राज्य बहुत सावधान एवं कर्त्त व्यारूढ था।

स्वास्थ्य संबंधी कार्यः — जन-स्वास्थ्य प्राचीन काल में राज्य द्वारा महत्वपूर्ण विषय सममा जाता था। अशोक के समय में जिस प्रकार स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्य किये जाते थे, उनसे यह सिद्ध होता है कि राज्य इस च्रेत्र में बहुत कियाशील था। प्रत्येक परिवार के निवासस्थान में नालियों की व्यवस्था होती थी और कूड़ा-करकट आदि गन्दगी एक निश्चित स्थान पर फैंकने का विधान था। इस नियम का उल्लंघन करने वाले दण्ड पाते थे। स्वास्थ्य की हिंदि से अनाज, तेल, घृत, औषधि आदि में किसी भी प्रकार का मिश्रण वर्जित था एवं मिश्रण करने वाले के लिए कठिन दण्ड की व्यवस्था थी। बीमारी, महामारी आदि आपत्तियों के समय राज्य द्वारा स्वास्थ्य की सुरत्वा तथा बीमारियों को रोकने के लिए अथक परिश्रम किया जाता था। अकाल के समय राज्य के अन्न-भएडारों को उपयोग करते हुए जनता की सहायता को जाती थी। निर्धन नागरिकों का भार कम करने के लिए सम्पत्तिशालियों से अधिक कर संग्रह किया जाता था। इसी प्रकार अन्य आपत्तियों (बाढ़, अग्न आदि) के समय भी राज्य जनता की सहायता के लिए प्रत्येक संभव प्रयत्न करता था। इस प्रकार स्वास्थ्य एवं जन-कल्याण के विभिन्न कार्य राज्य द्वारा सम्पन्न किये जाते थे।

श्रीद्योगिक कार्यः—प्राचीन मारत में राज्य के सात प्रमुख श्रंग माने गये थे श्रीर कीष उनमें से एक प्रमुख तत्व था। कोष की पूर्णता पर राज्य की सफलता श्रीर समृद्धि निर्भर करती था। वर्त्त मान समय की माँति उस समय भी राज्य उद्योग के चेत्र में कियाशील रहता था। खिनज श्रादि साधनों का विकास करना राज्य का ही कर्त्त व्य था। वंजर भूमि को उपज्ञाऊ ननाना, वनों का विकास करना, विभिन्न प्रकार के उद्योगों की स्थापना करना श्रादि राज्य के ही कार्य होते थे। धातु की खानों का पता लगाना तथा उन्हें विकसित करना केवल राज्य द्वारा ही संभव होता था, किन्तु श्रन्य उद्योग-धन्धों में राज्य का एकाधिकार नहीं था।

राज्य के नागरिक भी श्रीद्योगीकरण में सहायता देते थे। केवल यह कहा जा सक्ता है कि श्रीद्योगिक चेत्र में न तो राज्य का ही एकाधिकार था, न केवल पूँ जीपति। नागरिकों का वर्ष-मान भारतीय श्रर्थनीति की भाँति प्राचीन भारतवर्ष में भी श्रिधिकांश संयुक्त श्रर्थव्यवस्था (Mixed Economy) श्रपनाई जातो थी। इस प्रकार श्रीद्योगिक चेत्र में राज्य विभिन्न प्रकार के विधि-विधानों द्वारा जनहित के लिए व्यवस्था करता था।

विकास कार्य:—प्राचीन समय में जन्-जीवन के प्रत्येक च्लेत्र का विकास करना राज्य का कर्त्तं व्य माना गया था। त्रावागमन के साधनों की सुविधा देकर व्यापारियों एवं उद्योगपितयों को व्यापार के विकास में सहायता देना, यात्रियों तथा व्यापारियों के लिए मार्ग की सुरज्ञा का प्रवन्ध कर उन्हें पर्यटन के लिए प्रोत्साहित करना तथा व्यापार केन्द्रों को स्थापना द्वारा व्यापार का विकास करना राज्य के मुख्य कार्य थे। सम्राट ऋशोक के समय में तो राज्य का व्यापार की क्रोर बहुत ध्यान था। यदि व्यापारियों को मार्ग में किसी भी प्रकार की हानि होती तो यह राज्य द्वारा पूरी की जाती थी। भारत सदैव से कृषिपधान देश रहा है, इसलिए कृषि का विकास सिंचाई के साधनों का विकास क्रादि कार्य राज्यों द्वारा निरन्तर किये जाते थे। स्थान-स्थान पर सिंचाई के लिए कुए, बाँध तथा उनमे नहरें क्रादि बनाने के लिये राज्य संभवतः प्रत्येक संभव प्रयत्न करता था: कृपकों को भी इन कार्यों के लिये प्रोत्साहन दिया जाता था। वर्त्त मान समय के विकास खराडा की माँति उस समय भी जनहित के लिए जनता के सहयोग से महत्वपूर्ण कार्य किये जाते थे क्रीर उनमें राज्य का पूर्ण सहयोग होता था। मार्ग एवं सड़कें बनाना, छोटे पुल बनाना, तालाव बनाना क्रादि कार्य इसी ढंग से पूरे किये जाते थे।

भौतिक जीवन को समृद्ध चनाकर ही राज्य संतुष्ट नहीं होता था। नागरिकों के नैतिक जीवन का विकास भी राज्य से संबंधित रहता था। इसिलए शरात्र पीना, जुल्ला लेलना तथा वेश्यावृत्ति ल्लादे व्यवसाय पर राज्य का कठोर नियंत्रण होता था। शिचा, साहित्य एवं ज्ञान के साधनों को प्रोत्साहित किया जाता या। देवग्रह, यज्ञ तथा ल्लान्य नागरिक जीवन को सुली बनाने के कार्य में जो सामित्रयाँ ल्लावश्यक होती थीं, वे राज्य की ल्लोर से कर-शुक्क ल्लादि से मुक्त होती थीं। इस प्रकार सांसारिक समृद्धि एवं विकास के साथ नागरिकां के चारित्रक एवं नैतिक विकास का दायित्व भी राज्य द्वारा सफलतापूर्वक वहन किया जाता था।

उपर्युक्त वर्णन से यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि प्राचीन भारतीय शासन प्रणाली शुद्ध रूप से लोककल्याणकारी व्यवस्था थी। यह तो सच है कि प्राचीन भारत वर्ष में सदैव ऐसी व्यवस्था नहीं रही और न रह सकना संभव था, परन्तु अधिकांश समय में राज्य के कर्त्त व्य संबंधी सिद्धान्त इसी रूप में रहे और ऐसे विधान पर आवरण करने के लिए राज्य तत्पर बने रहे—यह सच है। उस समय राज्य अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होता था। किन्तु धर्म के ऐसे प्रतिवन्ध कर्त्त व्यविष्टा में वंध जाते थे. जिनका संबंध केवल इसी च्याक सांसारिक जीवन से न होकर अनेक जन्म-जन्मान्तरों तक तथा दूसरे लोकों तक सुधारने और विगाइने का प्रश्न सर्वधित था। इसलिए वर्त्तमान समय के

विद्यानिक श्रेष्टिकों की अपेचा प्राचीन समय के शासक अधिक कर्त व्यपरायण एवं जागरूक होते थे और जनता की सेवा करना व लोककल्याणकारी दृष्टि से शासन संचालित करना लोक और परलोक को सुधारने का सर्वोत्तम साधन समभते थे। वैसे तो प्राचीन भारत की सभी संस्थाओं की पृष्ठभूमि धर्म पर आधारित है, किंतु दण्ड-नीति उन सबका भी आधार है। इसलिए प्राचीन भारत में राज्य एवं राजा दोनों में कोई मेद नहीं समभा गया था और इसी प्रकार राजा और प्रजा को संबंध पिता-पुत्र की भांति दैहिक, दैविक एवं भौतिक रूप में स्वीकार किया गया था। इसलिए लोककल्याण सम्राट का कल्याण था और लोकहित की उपेचा सम्राट के लोक एवं परलोक की उपेचा था। इसलिए प्राचीन भारत में लगभग सदैव ही प्रशासन का आधार लोककल्याणकारी वृत्तियाँ बनी रहीं।

प्रश्न

- 1. Discuss the principles of Imperialism in Ancient India.
- 2. "Even Imperialistic system in Ancient India was highly efficient and advantageous to all." Explain this statement fully.

वीसवा अध्याय

प्राचीन भारत के राजनैतिक सिद्धान्तों का मूल्यांकन

(An Estimate of the Ancient Indian Political Thought)

प्राचीन भारतवर्ष में प्रचलित राजनैतिक सिद्धान्त एहां संस्थायां का पर्याचा शाणागन कर लेने के पश्चात् यह लगभग श्रावश्यक जान पड़ता है कि भारतयामी होते हुए भी निस्पेज दृष्टि से उसका उचित मूल्यांकन किया जाय । उपयुक्ति समस्त यर्गान के प्रापार पर एक यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि सामान्यतः पाश्चात्य विद्वानी की भारणाएँ, की प्राचीन भारत की राजनैतिक स्थिति एवं संस्थायां के संबंध में बनी एई थी अवधा गुरु लोगों को अब भी हैं पूर्ण रूप से अमात्मक हैं। पहले तो ये लोग राजनीति जैगी जीज भागत में थी-इसे ही नहीं मानते थे: परन्तु प्राचीन राजनीति से संबंधित कुछ शारत प्रादि के प्रकाश में ज्याने पर वे दूसरी शंकाएँ करने लगे थे। वे भी ज्यसस्य मिक्स ही रही हैं। पारकारय दार्शनिक प्राचीन भारतीय धर्म को श्रन्धविश्वाम तथा राजनीति को शासको की निरंगुण इच्छा मानते हैं। वे तत्कालीन धर्म श्रीर राजनीति में निहित पानगीयता, लीकक्याणकारी सिद्धान्त तथा चेतनता को पहचानने में श्रासमर्थ रहते हैं। इसीलिए समस्य परिचारी विद्वान प्राचीन भारत की राजनीतिक ज्ञान से शुन्य मानते रहे हैं। युनांग्य यह है कि कुछ भारतीय विद्वानों ने भी इस धारणा को मान लेने का श्रवराध किया है। यास्यय में एक श्रीम प्राचीन भारत की सम्यता को श्रेष्ठ एवं श्रद्धितीय स्वीकार करना श्रीर वसरी श्रीर राजनीतिक क्षेत्र में नितान्त श्रविकसित समभाना, श्रत्यधिक श्रसंगत हो बाता है; नयोकि किया भी अप्रू की सभ्यता एवं संस्कृति की उच्चता देश की राजनीतिक प्रगति विना सम्मय ही गरी है। सपती । इसलिए समस्त भारतीय एवं श्रमारतीय विद्वानी की यह विरोधी धारणा रवयं विद्या करती है कि प्राचीन भारत में राजनैतिक प्रगति भी सर्वोच्च सीमा पर पहुँची हुई सी। 'सर्वेशक हिते रताः' तथा 'कृगवन्ता विश्वमार्थम्' के सिद्धान्त यह प्रकट फर्मा है कि सभागित में स्वतन्त्रता, समान ता एवं बंधुस्व के सिद्धान्त से लेकर विश्ववस्थान कर के प्राहरी निहित ये जो छात भी किवल भारत का नहीं, विश्व का मार्ग-इशंन करने में सार्थ हो सकते हैं। गांधीजी का मत्य और प्यहिंसा, पंठ नेहरू का पंचारील और महन्त्रीमान तथा संत विनोश की शांति-क्षांति श्रीर दय-दगत् उभी प्राचीन हदः प्रस्थि पर श्रामारित है।

वैसा जपर कहा हा बुका है-भारत का कामभग प्रलेक मिद्राम्य पूर्व संस्था धर्म स्ट ब्रामारभूमि पर स्थापित हैं, परन्तु उस धर्म का स्यस्य क्या चा, यह कानमा क्रीमवार्य स्ट के श्राडम्बर श्रथवा श्रम्धवश्वास से था। तत्कालीन धर्म श्रपने विशुद्ध रूप में मानवता, जनिहत तथा विश्वकत्थाण की वृत्तियों से परिपूर्ण था। व्यक्ति, समुदाय, समाज एवं प्राणिमात्र के हित के लिए व्यवस्था करना धर्म का मुख्य उद्देश्य था। यही धर्म तत्कालीन राजनीति का श्राधार था। परन्तु पारचात्य देशों में धर्म का श्रर्थ श्रधकांश सम्प्रदाय से लिया गया श्रीर इसीलिए वहाँ ऐसे संघर्ष मी बहुत हुए। भारतवर्ष में धर्म के साथ सहिब्सुता का बहुत शिक्तशाली तत्व सदैव विद्यमान रहा है। प्राचीन काल के श्रितिरक्त, सत्तरहवीं शताब्दी में भी हम देखें तो स्पष्ट है कि वैब्याव धर्म ने मानवमात्र की समानता घोषित की श्रीर सुद्ध तथा बाहाण एक साथ मिलकर श्रागे बढ़े। मुस्लिम मक्त-कि रसखान के सवैयों हारा हिन्दु श्रों के भगवान की पूजा श्रारम्भ हुई श्रीर गालिब ने यह क्टपना की कि वह हिन्दू को कावा में दफ्ताना तथा मुसलमान की काशी में श्रन्त्येष्टि किया करना चाहता है। प्रपत्तु पाश्चात्य देशों में यह दुर्लभ था। वहाँ सम्प्रदायों के संघर्ष रक्तरंजित रहे हैं। इसीलिए भारतीय धर्म का शुद्ध श्रर्थ वे नहीं समक्त सके। वास्तव में धर्म का सम्प्रदाय के रूप में व्यक्तिगत सम्बन्ध ही होता था। शासक के राज्य सम्बन्ध चेत्र में यह धर्म कोई हस्तन्तिण नहीं करता था। इसीलिए प्राचीन भारत में धर्म-निरपेन्त राजनीति रही।

प्राचीन भारत के राजनैतिक सिद्धान्तों का समय-निर्धारण करना आवश्यक भी है श्रीर समस्या भी, परन्तु वर्तमान समय में कुछ साधनी के उपन्तन्ध हो जाने के कारण काल-निर्धारण कुछ सुगम अवश्य हो गया है। डा० बायसवाल का मत है कि पाचीन भारत की राजनीति न्यूनतम तीस शताब्दी पूर्व से चली आ रही है। यह विश्व के किसी भी इतिहास पर आधारित राजनीति के इतिहास से अधिक लम्बा समय है। र उदाहरणार्थ, कुछ ऐसी मुद्राएँ प्राप्त हुई हैं जिनको हिन्दू मुद्राशांस्त्र के प्रमुख विद्वान् सर कनिंधम ने १००० वर्ष ईसा से पूर्व की होना घोषित किया है। पुराण तथा खारवेल का लेख महाभारत का समय १४२५ वर्ष ईसा से पूर्व सिद्ध करते हैं तथा मेगास्थनीज, जो ३१० वर्ष ईसा से पूर्व आया था; चन्द्रगुप्त मौर्य को प्रथम सम्राट से १५४ वां सम्राट वर्णित करता है ।३ इस प्रकार यह निर्वि-वाद सत्य है कि प्राचीन भारत पश्चिम से बहुत पहले ही अपनी राजनीति का विकास कर चुका था। उस समय तक जब यूनान में मुकरात तथा प्लेटो का जन्म हुआ, भारत शासन-पद्धतियों के अनेक प्रयोग कर विकसित एवं प्रगतिशील शासन व्यवस्था जमा चुका था श्रीर यहां प्रजातंत्र राज्य स्थापित हो गये थे। कुछ विचारकों का यह विश्वास है कि भारतीय राज-नीति का प्रारम्भ ही प्रजातन्त्र राज्यों की स्थापना के साथ हुआ है। प्रारंभिक वैदिक काल से ही स्वतंत्रता, समानता एवं वंधुत्व के ग्राधार पर समाज की सत्ता शासन चलाती थी ग्रीर राजा प्रजा का शुभिचतक-सेवकमात्र था, राजा शब्द का सावारण ग्रर्थ यही होता है। धीरे-धीरे-

[?] Dr. Jayaswal-Hindu Polity-Page 366.

२ उपरोक्त।

३ उपरोक्त (Foot Note).

धीरे यही आधारभूत तत्व दृढ़ परम्पराओं द्वारा स्थायी वन गये, जिनका विरोध या उल्लंघन असम्भव होता था एवं अपराधी शासक को समाज दण्डित भी कर सकता था। जनता सदैव शिक्तशाली वनी रही। राजा का निर्वाचन, निष्कासन एवं नियंत्रण जनता के हाथ में रहा। अधिनायक तत्व के लिए राजनीति में स्थान नहीं था। दैवी सिद्धान्त एवं सामाजिक समभौते के सिद्धान्त भी प्रचलित हो चुके थे, किन्तु प्रजातंत्रात्मक परम्पराओं के समस्तं, वे सफल न हो सके। फलस्वरूप भारतीय राजनीति लोकतन्त्रात्मक ही वनी रही।

प्रायः शासन शास्त्र की परीचा इस बात से होती है कि उसमें अपना अस्तित्व बनाये रखने एवं विकास करने की चमता किस मात्रा में है तथा मानव की संस्कृति एवं प्रसन्नता की वृद्धि में कितना योगदान देने की सामर्थ्य है। इस दृष्टि से भारतीय राजनीति शास्त्र पूर्ण रूप से सफल होता है। तुलनात्मक दृष्टि से संभवतः वेवीलोन की सम्यता व व्यवस्था श्रीर भी अधिक प्राचीन सिद्ध हो; किन्तु दुर्मांग्य से अब वह लुप्त ही हो चुकी है। दूसरी सम्यता श्रीर व्यवस्था चीन की है जो लगमग भारतवर्ष के समान है। भारत का शासन-शास्त्र, जं। प्राचीन काल से अब तक अनेक उत्यान-पतन, आरोह-अवरोह देखकर भी जीवित रहा, यह अद्भुत विशेषता रखता है। सिद्धान्त रूप में यह सत्य है कि किसी भी राष्ट्र की राजनीतिक एवं वैधानिक प्रगति कुछ निश्चित परिस्थितियों तथा मानवीय तत्वों द्वारा संयोजित होती है। यही कारण है प्राचीन भारत का राजनीति-शास्त्र विकसित हुआ और समाज की सब प्रकार से उन्नति संभव हो सकी।

व्यावहारिक राजनीति की दृष्टि से भी पाचीन भारतवर्ष बहुत आगे बढ़ा हुआ था। शासत-तंत्र के अनेक प्रकार अनुभव के आधार पर प्रचलित थे। गणराज्य, नृपतंत्र, एकराज, द्विराज, सार्वभौम, चक्रवर्ती त्यादि त्रानेक प्रकार के तत्र समाज में प्रचलित थे। तत्कालीन गगुराज्यों की उन्नति श्रवस्था, संगैधानिक प्रक्रिया तथा प्रजातं। निक व्यवस्था श्राज के उन्नत युग में भी ब्राश्चर्यान्वित करने में समर्थ है। साथ ही उनमें परस्पर संघर्ष की भावना का विकास तथा मेदनीति द्वारा राष्ट्रों के भोतर बैमनस्य के बीज का वपन करवाया, जाना कृट-नीति के द्वारा उनका नाश करवाना त्राज भी शीत-युद्ध से पीड़ित विश्व के राष्ट्रों को मार्ग-दर्शन की चुमता रखता है। यद्यपि राजतन्त्र श्रात्यन्त लोकप्रिय प्रचलित श्रावस्था थी तथापि जनता का नियंत्रण पूर्णरूपेण प्रभावशाली चना रहा। संवैधानिक दृष्टि से राजा स्वयं अपनी प्रतिज्ञात्रों ग्रादि द्वारा जनता की सेवा के लिए कटिबद्ध रहने की चेष्टा करते थे श्रीर यदि किर भी कुछ लोग निरकुश वनने का प्रयत्न करते ये तो केवल असफलता ही निश्चित परिग्णाम होता था । सामाजिक, त्रार्थिक, राडनैतिक एवं धार्मिक त्रेत्रों में राज्य की शक्तियाँ ऐसे नियमी द्वारा मर्यादित थीं जिन पर उसका कोई अधिकार नहीं था। बैदिक काल से ही हमें अनेक समा, समिति, विदय, सेना, पूग, श्रेणी, गण त्यादि, लोकसभात्रों का प्रमंग मिलता है। चाद में पीर, जनपद, ग्रामसभा त्रादि दृष्टिगत होती हैं। इसका तालर्थ है कि प्राचीन भारत का राज-नैतिक जीवन निरन्तर प्रजातांत्रिक ग्राधार पर चलता रहा है ग्रीर उसका यह फल है कि वपों तक विदेशी सत्ता के श्रधीन रहने पर भी भारत निष्पाण नहीं हुआ; वरन् इस हट पृष्ठभूमि के बल पर संघर्ष कर पुनः स्वतंत्र राष्ट्रके रूप में उठ खड़ा हुन्ना।

वर्ते मान युग में चरम उन्नति के प्रतीक कहे जाने वाले साधन; जैसे निर्वाचन, मत-दात, सर्णपूरक, मतपत्र, नियम संबंधी प्रक्रिया, भाषण का अधिकार, स्वतंत्रता आदि प्राचीन भारत के गणराज्यों में पूर्ण रूप से विद्यमान थे। अनेक छोटे राज्यों द्वारा समानता के आधार पर संघों की स्थापना भी प्रचलित थी। आज जिसे बीसवीं सदी की विकसित राजनीति का अथवा प्रजातंत्र का युग कहा जाता है, वह युग यही भारतवर्ष सैकड़ों वर्ष पूर्व अनुभव कर चुका है। अ तर्राष्ट्रीय चेत्र में 'मण्डल सिद्धान्त' आज भी सच है। कूटनीति के शाशवत सिद्धान्त आज भी महत्वपूर्ण हैं। जिस हुलोककल्याणकारी राज्य की धारणा वर्त मान युग में अत्यन्त लोकप्रिय बनी हुई है, महान् सम्राट अशोक ऐसी व्यवस्था पहले ही स्थापित कर चुका था। इसलिए कुछ-कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि अंग्रेजी की कहावत "इतिहास की पुनरावृत्ति होती है" सत्य सिद्ध होने जा रही है। वे ही पुराने अनुभूत थोग पुनः प्रयोग में लाये जा रहे हैं। पहले केवल भारत में प्रयुक्त हुए, अब समस्त विश्व में उनका अनुभव किया जा रहा है।

व्यक्तिगत स्वतंत्रता की धारणा प्राचीन राजनीति में किस प्रकार थी. इस संबंध में विचा-रकों में मतमेद है। जहाँ तक स्वतंत्रता का प्रश्न है, प्राचीन समय में भी मयादित स्वतंत्रता का सिद्धान्त ही माना गया था और व्यक्तिगत प्रारंभ (Personal Initiation) की पर्याप्त स्थान प्राप्त था। परंतु व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सीमा के संबंध में मतैक्य नहीं है। श्री गोखले के मतानुसार प्राचीन भारतीय राज्य पूर्ण शिक्तशाली संस्था थे छीर अपनी जनता के जीवन का पूर्ण नियंत्रण उनके हाथ में होता था। राज्य के विरुद्ध नागरिकों की कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे। परन्तु सम्राट फिर भी धर्मशास्त्र के नियमीं द्वारा बँधा हुन्ना था। उसे कुछ विशेष श्रिधिकार होते थे परंतु ये धर्मशास्त्रों के नियमों का उल्लंपन करने योग्य नहीं बना एकते ।१ दूसरे लेखक का मत है कि न्यिक्त, राज्य का स्वतंत्र छांग समक्ता जाता था और अपने विकास के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र था। जीवन की रचा, सम्पत्ति का उपार्जन. परिवार का श्रिधिकार, तथा बैद्धिकविकास आदि, के अधिकार नागरिकों की प्राप्त होते थे। व्यक्ति के ऊपर लगये गए सामाजिक ग्रथवा बौद्धिक प्रतिबन्धों का वर्णन "पुरुपार्थ" श्रथवा "चतुर्वर्ग" में किया गया है। इसका तालर्य है कि कुछ मर्यादायों एवं प्रतिबन्धों के साथ व्यक्ति की पर्यान्त स्वतंत्रता थी, जिसके द्वारा वह अपना भाग्यसुवार अववा सुकिपादि के अयत्न कर सकता था था। २ डा॰ छल्टेकर का मत है कि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पर कोई बन्धन नहीं था। माचीन भारतवासियों ने राज्य का कार्यचेत्र बहुत ब्यापक बनाया था, किन्द्र उसका सात्पर्य यह नहीं था कि वे व्यक्ति का मृत्य नहीं समभते थे, वरन् इसलिए कि उनके संपर्यात्मक हिताँ का श्रॅंट संतुनन एवं संगठन करने के लिए राज्य को उपयुक्त समक्ता गया था।३ सचसुच प्राचीन

³ B. G. Gokhale - Ancient India-Page 100.

R. C. Bundyopadhyay—Development of Hindu Polity and Political Theories. Page 403-4.

^{2.} Dr. Altekar-Page 60.

समय में व्यिक्तिगत स्वतंत्रता सुरिक्ति रही श्रीर उसके दो प्रमुख कारण थे-पहला, राज्य स्वायत्त संस्थाश्रों के साथ सहयोग से कार्य करता था श्रीर इन संस्थाश्रों में नागरिकों की प्रधानता थी। दूसरा, राज्य की शिक्तयों के विकेन्द्रीकरण का सिद्धान्त स्वीकार किया गया था, जिसके द्वारा स्थानीय संस्थाश्रों को व्यापक एवं विस्तृत श्रीधकार दिये जाते थे। इसलिए यह सत्य है कि प्राचीन भारत में व्यक्तिगत स्वतंत्रता श्रक्तुण्ण रूप में व्यवस्थित थी। उस पर किसी प्रकार का श्रनुचित प्रतिबन्ध या श्रंकुश नहीं था।

प्रत्येक प्रजातंत्र की सफलता का आधार वहाँ की स्वायत्त संस्थाएँ मानी जाती हैं। तदनुसार प्राचीन भारतवर्ष में भी पंचायतें तथा ग्राम सभाएँ पूर्ण रूप से प्रभावशाली एवं सफल रही हैं। न्याय संबंधी अधिकार, कर संग्रह 'के कार्य, विवादों का निर्णय, जनहित के कार्य, चिकित्सालयों की स्थापना, शिच्चालय तथा अनावाश्रमों की व्यवस्था आदि अनेक कार्य इन स्थानीय संस्थाओं द्वारा किये जाते थे। इस प्रकार वर्त्त मान समय में अपनाये जाने वाले आदर्श प्राचीन भारतवर्ष में सकार रूप में उपस्थित थे।

कर-संग्रह के संबंध में प्राचीन राज्य केवल कोषवर्द्ध इकाई के रूप में ही नहीं थे, वरन् राष्ट्र के निर्माता श्रीर जनता के संरक्षक भी थे। न तो वे स्वेच्छा से कर लगा सकते थे श्रीर न उनमें वृद्धि कर सकते थे। न स्वेच्छापूर्वक संग्रह कर सकते थे श्रीर न स्वेच्छापूर्वक उनका व्यय कर सकते थे। ऐसी स्थिति में केवल धर्मशास्त्रों द्वारा स्वीकृत नियम ही उनके लिए एकमात्र पथप्रदर्शक थे। इसलिए जनता बहुत प्रसन्त तथा कर-भार से दबी हुई नहीं रहती थी। इस दृष्टि से श्राज का समाज किसी भी रूप में स्वस्थ नहीं दिखाई देता। हर चेत्र में श्रनेक प्रकार के कर एवं शुल्कों का भार इतना श्रिधिक होता जा रहा है कि मानव की कमर ही तोड़ देता है। इस चेत्र में प्राचीन भारत का राजनैतिक स्वरूप बहुत सुन्दर, व्यव-स्थित एवं श्राकर्षक रहा है।

श्रतः यह निष्कर्ष निकलना उचित प्रतीत होता है कि प्राचीन भारत के राजनैतिक सिद्धान्त श्रीर संस्थाएँ उन्नति की प्रेसी सीमा पर पहुंची हुई थीं, जिन्हें वर्ष मान समय (बीसवीं शतान्दीं) की विश्व की राजनैतिक प्रगति के समन्न तुलना के हेतु प्रस्तुत की जा सकती है। यद्यपि यह निस्संकोच स्वीकार किया जाना चाहिए कि कुछ नेत्रों में उस समय श्रिषक विकास नहीं हुआ था तथापि यह भी सत्य है कि कुछ नेत्र में यह विकास बहुत श्रिषक हो गया था। इस प्रकार प्राचीन भारत का राजनैतिक दर्शन बहुत गौरवपूर्ण, ये ज्ञानिक तथा पर्याप्त रूप से विस्तृत आकार में उपलब्ध है तथा वर्ष मान भारत को अपने नवर्ण निर्माण के लिए कई नेत्रों में पथप्रदर्शन के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। राजस्थान में २ अबह्वर, सन् १६५६ से अपनाया गया लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण प्राचीन भारत की स्वायत्त संस्थाओं के संगठन के अनुरूप ही है। यदि हमारी सरकार इसी प्रकार अन्य नेत्रों में भी शोधकार्य द्वारा विकास की योजना बना सके तो यह संभव है कि पुनः इस विशाल एवं विस्तृत देश में प्राचीन सफल प्रवातंत्र का और अधिक वैज्ञानिक रूप मुन्तरित होने में

सहायता निर्हा धकती है श्रीर विश्वशांति के उपासक, श्रांतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जागरूक एवं तिटिस्ये प्राप्ट्र तथा पंचशील के प्रधान योग देने वाले भारत का स्थान श्रीर भी श्रधिक के चा एवं प्रतिष्ठित बनाया जा सकता है।

प्रश्न

- 1. Is it true to say that Hindu religion and ethics supplied the fundamental principles of ancient Indian polity? Give your own views.
- 2. "Hindu political ideas are a be-product of the Hindu view of life." Elucidate.
- 3. How far and in what directions can the ancient Hindu Polity be said to provide a basis for the reconstruction of our Political institutions today?

प्रथम चार ग्रध्यायों पर

अध्यास के लिए प्रश्न

- 1. What are the various sources of the Ancient Hindu Political Thought? Explain fully.
 - 2. Describe the scope and sources of the Hindu Political Thought in ancient times and analyse them.
 - 3. What were the elements of State in ancient times? Describe the ancient Hindu Conception of State & compare it with the conception of a modern State.
 - 4. What were the various types of states found in ancient India? Also add possible classifications of them?
 - 5. What were the different theories about the origin of State in Ancient India? Describe fully.
 - 6. Describe the Bhishma's theory about the origin of State in ancient India and compare it with the modern theory of Social Contract by Hoffis & Locke.

यन्थ-सूची

हिन्दी एवं संस्कृत (प्राचीन)

- १. कौटिल्य--- ग्रर्थशास्त्र (Shastri)
- २. महाभारत--सभापर्व
 - --शांतिपर्व
 - -–वनपर्व
- ३. मनुस्मृति
- ४. शुक्रनीतिसार
- ५. जातक प्र'थ (Cowell)
- ६. कामन्दकीय नीतिसार
- ७. वशिष्ठसूत्र
- ८. गौतमसूत्र
- ६. बृहस्पतिसूत्र
- १०. कल्पसूत्र
- ११. अछरंग सूत्र
- १२, बोधायन
- १३. अपस्तम्भ
- १४. ऋग्वेद
- १५. ग्राथर्ववेद
- १६. ऐतरेय बाह्मण
- १७. शतपथ ब्राह्मण
- १८. याजवल्क्य स्मृति ।

- १६. नारदस्मृति
- २०. विष्णुंपुराण
- २१. मत्स्यपुराण
- २२. बृहदारंग्यकोपनिषद्
- २३. कठोपनिषद
- २४. शिवतत्त्वरत्नाकर
- २४. रामायण
- २६. समराङ्गण सूत्रधार
- २७. चुल्लवग्ग
- २८. महावग्ग
- २६. वीरमित्रोदय
- ३०. नीतिवाक्यामृत
- ३१. दिव्यावधान
- ३२. पािशानि पर पतझालि का भाष्य
- ३३. मुद्राराच्स
- ३४. राजतरंगिणी (कल्हण)
- ३५. दशकुमारचरित
- ३६. सांख्य तत्त्वकौमुदी
- ३७. मृच्छुकटिक

आधुनिक यन्थ-सूची

1.	Dr. Jayaswal	-Hindu Polity.
2.	Mc Crindle	-Megasthnes.
3.	1*	-Alexander The Great.
4.	,,	-Ancient India as described in Classical
		Literature.
5.	,,	-Invasion of India by Alexander the
		Great.
6.	Rockhill	Life of Buddha.
7.	Fick .	—Social Organisation
		(Trans. by S. K. Maitra).
8.	Fleet	-Gupta Inscriptions.
9.	Conninghum	-Coins of Ancient India.
10.	Cowell	—Jatakas.
11.	Fansball	—Jatakas.
12.	V. A. Smith	-Early History of India.
13.	Jacobi	-Kalpasutra.
14.	Rhys Davids	—Buddhist India.
15.	Cambridge History of India	Vol-I
16.	Digha Nikaya	_
17.	Dr. Altekar	-State & Govt. in Ancient India,
18.	Dr. Altekar	-Village Communities.
	Ghosal	—Hindu Political Theories.
20.	Sir Subrahmnya Aiyar	
	or 1914	- Some Aspects of Ancient Indian Polity.
		9)—Some Aspects of Ancient Indian Polity.
	B. R. Sarkar	-Political Institutions Theories of Hindus.
23.	Yadunandan Kapoor	-Dharma Nirpeksha Prachin Bharat Ki Praja, Tantratmak Paramparayen,
24.	Strabo	-
25.	Curtius	Book IX
26.	Dr. Beni Prasad	-State in Ancient India.
27.	"	-Theory of Govt. in Ancient India.
28.	K. M. Panikkar	-Theories About the Origin of State in Ancient India.
20	R. C. Majumdar	Corporate life.
43.	r. o majamaa	Corporate me.

	(*)
30 X & Bandyopadhyaya	-Development of Hindu Polity & Politi- cal Theories.
31. Dr. Dhawan	-The Political Philosophy of M. Gandhi.
32. Dr. R. K. Mukherjee	-Chandra Gupta Maurya & his Times.
33. ,, ,, ,,	Studies in Ancient Hindu Polity.
34. N. N. Law	-Studies in Ancient Hindu Polity.
35, Dr. V. P. Varma	Hindu Political Thought.
36. Hopkins	-India Old & New.
37. Bancrice	-Public Administration In Ancient India.
38. Dikshitar	Hindu Administrative institutions.
39. Dikshitar	War in Ancient India.
40. B. G. Gokhle	Ancient India.
41. S. K. Vidyalankar	Prachin Bhartiya Shasan Vyavastha aur Rajshastra.
42. S. R. Sharma	Ancient Hindu Political Thought.
43. C. P. Bhambhari	-Substance of Hindu Polity.
44. Vishwanath	-International Law In Ancient India.

JOURNALS,

-Hindu Public Life.

1. Epigraphica Indica--Vol. III & VIII

45. Ghosal

- 2. A Journal of R. A. S. 1916 (Dr. A. B. Keith)
- 3. A Journal of the Bengal Asiatic Society Vol. 52 (1883)
- 4. Some Indian Epigraphic Reports-1900.

